

बैंकिंग

BANKING

लेखक

शंकर सहाय सक्सेना एम० ए०, एम० काम०

प्रिन्सिपल महाराष्ट्रा कालेज उदयपुर

ग्राम्य अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, प्रारम्भिक

अर्थशास्त्र, भारतीय मज़दूर, भारतीय

सहकारिता आन्दोलन आदि ग्रन्थों

के रचयिता

प्रकाशक

रामनारायण लाल

प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

प्रयाग

मुद्रक—

महादेव प्रसाद

आज़ाद प्रेस, प्रयाग

बैंकिंग

THIS BOOK BELONGS TO MAHARANA BHUPAL
COLLEGE - UDHAIPUR - LIBRARY
(RAJASTHAN)

1950/51

श्री भगवान दास केला

अध्यक्ष भारतीय ग्रन्थमाला

को

समर्पित

जिन्होंने आत्म निर्धनता को स्वीकार कर मातृभाषा
हिन्दी में अर्थशास्त्र तथा राजनीति साहित्य का
निर्माण किया, जिन्होंने एक साहित्यिक
तपस्वी का जीवन व्यतीत किया है
और जिनके स्नेह ने लेखक
को धार्ध लिया है ।

निवेदन

लेखक उन व्यक्तियों में से है जिनका विश्वास और मान्यता रही है कि उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर वह पिछले २० वर्षों से हिन्दी में अर्थशास्त्र और व्यापार सम्बन्धी साहित्य निर्माण करने में प्रयत्नशील है।

आज लेखक का स्वप्न सत्य होने जा रहा है। राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के उपरान्त देश अपने मस्तिष्क को भी विदेशी भाषा की दासता से मुक्त कर लेना चाहता है—यह शुभ लक्षण है। एक के बाद दूसरा विश्वविद्यालय हिन्दी को परीक्षा और शिक्षा का माध्यम स्वीकार करता जा रहा है; किन्तु हिन्दी में ऊँची परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक ग्रन्थों का अभाव है। हिन्दी के प्रत्येक विद्वान् का यह कर्तव्य है कि वह मातृ-भाषा की इस कमी को पूरा करे।


प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई थी। हिन्दी में बैंकिंग पर कोई पुस्तक न होने के कारण इस विषय के विद्यार्थियों को इसके अध्ययन में कठिनाई हो रही थी अस्तु इस पुस्तक को लेकर उपस्थित हुआ यद्यपि यह पुस्तक बैंकिंग के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई थी परन्तु लेखक ने इसे लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखवा कि वह साधारण पाठक को बैंकिंग का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त हो।

पुस्तक में बैंकिंग के सिद्धान्तों और भारतीय बैंकिंग के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश कर दिया गया है। पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी में देकर साथ ही कोष्टक में अंग्रेजी शब्द भी दे दिये गये हैं क्योंकि सम्भव है कि कुछ दिनों तक अध्यापकगण कालेजों में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त अभी कुछ हिन्दी पारिभाषिक शब्दों का अन्तिम रूप भी निर्धारित और सर्वप्रचलित नहीं हो पाया है।

पुस्तक का हिन्दी संसार में अच्छा स्वागत हुआ। अर्थशास्त्र के विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कालेजों में इसका उपयोग किया गया अतएव पुस्तक का प्रथम संस्करण शीघ्र समाप्त हो गया।

पुस्तक के दूसरे संस्करण को लेकर उपस्थित होते हुए लेखक को इर्ष है। नवीन संस्करण में पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है। भारत में बैंकों की असफलता अन्तराष्ट्रीय बैंक तथा भारत, ग्रामीण कृषि सार्व कारपोरेशन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर वृथक् परिच्छेद जोड़ दिए गए हैं। अन्य परिच्छेदों में भी दृष्टेय सशोधन और परिवर्धन किया गया है। पुस्तक पहले से अधिक उपयोगी बनाने की पूरी चेष्टा की गई है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तक हिन्दी में बैंकिंग विषय के सम्मीर अध्ययन करने में सहायक होगी।


शंकर सहाय सक्सेना

विषय-सची

निवेदन

बैंकिंग के सिद्धान्त (Principles of Banking)

विषय	पृष्ठ
अध्याय—१ बैंकिंग सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द	१
२ द्रव्य (Money) और बैंकिंग	२५
३ भिन्न प्रकार के बैंक	३६
४ बैंक के कार्य (Functions of a Bank)	४६
५ बैंक की लेनी देनी का लेखा (Balance Sheet of a Bank)	५६
६ विनियोग नीति तथा लेनी (Investment Policy and Asssts)	६७
७ केन्द्रीय बैंक (Central Bank)	८८
८ केन्द्रीय बैंक द्वारा साख (Credit) तथा द्रव्य (Money) का नियंत्रण	१०२
९ क्लियरिंग हाउस (Clearing House)	११६
१० द्रव्य बाज़ार (Money Market)	१२२
११ अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष (International Monetary Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank of Reconstruction and Development)	१२६

दूसरा भाग

भारतीय बैंकिंग

अध्याय—१२ गाँवों के लिये साख की आवश्यकता तथा महाजन और साहूकार	१४२
---	-----

(२)

७३	देशी बैंकर (Indigenous Bankers)	...	१५६
७४	सहकारी साख्त समितियाँ और सहकारी बैंक (Co-operative Credit Societies and Co-operative Banks)	...	१७४
१५	मिश्रित पूँजी वाले बैंक या व्यापारिक बैंक (Joint-Stock Banks or Commercial Banks)	...	२२०
१६	विनिमय बैंक या एक्चेंज बैंक (Exchange Banks)		२४०
१७	इम्पोरियल बैंक ऑफ इण्डिया N	...	२५६
१८	रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया N	...	२६६
१९	पोस्ट ऑफिस, ग्रन्थ कार्यालय, निधि, तथा चिट फंड		२६५
२०	उद्योग-बन्धों के लिए पूँजी का प्रवन्ध N	...	३०२
२१	भारतीय समाशोधन ग्रह या क्लियरिंग हाउस	...	३१८
२२	भारतीय द्रव्य-बाजार N	...	३२३
२३	भारत में बैंकिंग सम्बन्धी कानून N	...	३३८
२४	द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन को भारतीय बैंकों पर प्रभाव	...	३४८

तीसरा भाग

२५	बैंकों की कार्य पद्धति और उनके नियम	...	३५१
२६	बैंकों की प्रसफलता	...	३६४

अध्याय—१

बैंकिंग सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द

बैंक (अधिकोष) :—बैंक लेन-देन करने वाली संस्था को कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यापारी वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता है ठीक उसी प्रकार बैंक द्रव्य (money) के उपयोग का लेन-देन करते हैं। वे सर्व साधारण से कम सूद पर रुपया लेते हैं और ऊँची दर पर उसे उधार दे देते हैं। लेन-देन ही वास्तव में इनका मुख्य धंधा है और इसी से उनको अधिकांश लाभ मिलता है। यह समाज के लिए और बहुत तरह से उपयोगी है जैसे आगे के अध्यायों में प्रकट होगा। आज बिना सुव्यवस्थित बैंकों के कोई भी देश व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता। सब तो यह है कि औद्युनिक व्यापार साख (Credit) पर निर्भर है। माल तैयार करने वाला (Manufacturer) थोक व्यापारी (Wholesaler) को साख देता है और थोक व्यापारी खुदराफरोश (Retailer) को साख देता है। खुदराफरोश उपभोक्ताओं (Consumers) अर्थात् ग्राहकों को साख देता है। ये सब बिना बैंकों तथा अन्य लेन-देन करने वाली संस्थाओं के नहीं हो सकते। बैंक जनता के द्रव्य (money) का रक्षक है और जनता उससे ही साख पाने की आशा करती है।

जमा (Deposit):—जमा बैंक को दिया हुआ ऋण है जो उसने जमा करने वाले व्यक्तियों से एक निश्चित सूद पर और अदायगी सम्बन्धी कुछ शर्तों पर लिया है। जब कोई व्यक्ति अपना रुपया किसी बैंक में जमा करता है तो बैंक एक निश्चित सूद की दर पर और रुपया निकालने की कुछ शर्तों पर उसे स्वीकार करता है। जमा तीन प्रकार की होती हैं। (१) सेविंग बैंक हिसाब (Savings Bank Account) (२) मुहती जमा (Fixed-Deposit Account) (३) चालू खाता (Current Deposit Account)।

सेविंग बैंक खाता (Savings Bank Account) :—यह वह हिसाब है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी बचत को बैंक में जमा कर सकता है। इस प्रकार का हिसाब सर्व साधारण में मितव्ययिता की आदत

डालने के लिए खोला जाता है। इस खाते में कोई भी व्यक्ति अपना, अपनी स्त्री के नाम का या बच्चा के नाम का हिसाब जिनका वह अधिभारक (Guardian) है, खोल सकता है। इस हिसाब की विशेष बात यह है कि एक निश्चित रकम से अधिक दफ्तर इसमें जमा नहीं किया जा सकता तथा सप्ताह में एक या किसी किसी बैंक में दो बार से अधिक नहीं निकाला जा सकता। अब कुछ बैंक सेविंग बैंक खाते वालों को ची चेक (Cheque) द्वारा दफ्तर निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हिसाब में मुल पॉच हजार रुपये से अधिक जमा नहीं किये जा सकते और सप्ताह में एक बार से अधिक दफ्तर नहीं निकाला जा सकता। परन्तु व्यापारिक बैंकों की जमा करने का रकम मात्र मिला जाती है।

सुदती जमा (Fixed Deposit) :—वह जमा होती है जिसमें बैंक के पास दफ्तर एक निश्चित समय के लिए रख दिया जाता है और उस निश्चित अवधि के समाप्त हुए बिना निकाला नहीं जा सकता। बैंक इस प्रकार की जमा पर कितना सूद देगा—यह जितने समय के लिए रकम जमा की गई है तथा बैंक की स्थिति पर निर्भर रहता है। साधारणतः सुदती जमा ६ महीने से लेकर तीन वर्षों तक के लिए होता है। दफ्तर जमा कर देने पर बैंक एक रसीद देता है। इस हिसाब की कोई बात कुछ नहीं होती। यह रसीद हस्तांतरित (Transfer) नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति दफ्तर जमा करता है उसी समय वह दफ्तर निकालने का नोटिस भी दे देता है क्योंकि जितनी अवधि के लिये दफ्तर जमा किया जाता है उतने समय पूर्व नोटिस दिये बिना दफ्तर नहीं निकाला जा सकता। बैंक की विशेष आज्ञा बिना निश्चित तारीख के पूर्व दफ्तर नहीं निकाला जा सकता। यदि रुपये की फिर जमा करना हा तो रसीद को निश्चित तारीख पर बैंक भेज देना चाहिए जिससे सूद की हानि न हो।

सुदती जमा की रसीद का नमूना

Due 20th March, 1949.

Imperial Bank of India—Fixed Deposit Receipt
No. 54/23 Bareilly 20th March, 1948.

Received from Professor Bhola Nath Sharma Rupees Five thousand only as Fixed Deposit repayable

twelve months after date with interest at the rate of three per cent per annum.

For the Imperial Bank of India,

P. Nixan,

Agent.

Entd.

Atma Ram,

Accountant.

B. O 12672

N. B.—Interest will cease at the expiration of the above period of 12 months, when this receipt must be sent in for renewal or payment endorsed by the depositor.

चालू खाता (Current Account) :— चालू खाता एक खुला हिसाब होता है। इसमें रुपया जमा करने वाला किसी भी समय रुपया जमा कर सकता है और निकाल सकता है। इस हिसाब पर अच्छे बैंक कोई सूद नहीं देते। यदि चालू खाता में एक निश्चित रकम से रुपया कम हो जाता है तो जमा करने वाले को कुछ खर्च देना होता है। इम्पीरियल बैंक और इण्डिया में कम से कम ५०० रुपये की रकम रहनी चाहिए।

जो भी व्यक्ति किसी बैंक में चालू खाता खोलना चाहता है उसे बैंक के किसी पुराने ग्राहक से बैंक को अपना परिचय करवा देना चाहिए। बैंक अजनबियों को अपना ग्राहक नहीं बनाता। पहली बार रुपया जमा करने पर ग्राहक को पास बुक, पे-इन बुक (रुपया जमा करने वाली किताब) तथा चेक बुक मिलती है।

पास बुक :— बैंक के लेजर में लिखे हुए हिसाब की नकल होती है। कम से कम उसे महीने में एक बार बैंक भेजकर मिलवा लेना चाहिए। इम्पीरियल बैंक प्रत्येक ग्राहक को महीने के आरम्भ में उसका हिसाब एक पृथक् कागज पर भेजता है और यह हिसाब के पृथक् कागज एक फोल्डर में रखे जाते हैं।

Pay in Book - इस किताब में कारा धुआ हुई स्लिप होती है। जिन्हें पे इन स्लिप कहते हैं। जब चालू खाते में करपा जमा करने के लिए बैंक भेजा जाता है तो वह पहले पे इन स्लिप पर दर्ज कर दिया जाता है। यदि कभी इस बात पर भ्रम होता उठ सके है कि कितना करपा जमा किया गया है तो इन स्लिपों से पता चल सकता है। यही इनका उपयोग है। जब करपा जमा करने के लिए भेजा जाय तो साथ में पे इन स्लिप टीक तरह से भर कर भेजना आवश्यक है। कुछ बैंक में दो प्रकार का मिले होती है। एक नकदी के लिए और दूसरी चेक ड्राफ्ट इत्यादि के लिए।

स्लिप की प्रतिनिधि (Counterfoil) पर बैंक का सचाची हस्ताक्षर भर देता है और करपा जमा करने वाले का लौटा देता है।

चेक (Cheque) धुका:—इसमें १० से १०० चेक तक होते हैं। यह एक ही दिशाइन, साइज और रंग के होते हैं। चालू खाते में करपा चेक के द्वारा ही निकाला जाता है। बैंक इसका मूल्य के ग्राहकों को चेक धुका देता है।

विनिमयसाध्यता (Negotiability)

विनिमयसाध्यता क्या है इसको एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। कल्पना करो कि कोई चार आपसी नदी, ॥ १ ॥ किन, दोबारा और पुस्तकें खुरा लेता है और उन वस्तुओं को किसी व्यक्ति को बँच देता है। या व्यक्ति इन चीजों का मूल्य देकर खरीदता है उसको यह मालूम नहीं होता कि यह चीजों का बाजें हैं और वह धनपाने में उन चीजों को मूल्य देकर खरीद लेता है। अब यदि आपको उन चीजों का पता लग जाता है तो उन चीजों का सरादार बिलने कि अनपाने में मूल्य देकर उन चीजों को संपाद है उनका लौटाने से इनकार नहीं कर सकता। उसे कानून के अनुसार उन चीजों को वापस लौटाना होगा। लेकिन करसी नाट, चेक या बिज या हुडा के बारे में यह बात नहीं है। यदि येरा १०० रुपए का नाट चोरा चला जाता है और चार उस नाट को देकर किसी दुकानदार से १०० रुपए का सामान ले लेता है तो यदि मुझे मालूम हो जावे कि अमुक दुकानदार के पास मेरा जो गहुँच गया है, मैं उस नाट को नहीं पा सकता। हाँ चार के खिलाफ मैं कानून का कार्यवाही कर सकता हूँ। इसी प्रकार यदि मान लो कि मुझे कहाँ से एक हजार रुपए का चेक मिला है। वह चोरी

चला जाता है। चोर किसी से एक हजार रुपये लेकर उसके पक्ष में तुम्हारे नाम से वेचान (Endorsement) कर देता है। बैंक के पास तुम्हारे हस्ताक्षर तो हैं नहीं, उसके पास अपने आह्वक अर्थात् रुपया जमा करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसी दशा में वह तुम्हारे नाम के जाली हस्ताक्षरों को न पहचान कर एक हजार रुपये उस चेक को खरीदने वाले को दे देता है तो फिर तुम उस व्यक्ति (चेक खरीदने वाले) से अपना रुपया वसूल नहीं कर सकते। कारण यह है कि करंसी नोट, तथा चेक विनिमय-साध्य पुर्जों (Negotiable instrument) हैं। इस प्रकार बिल और हुंडी भी विनिमयसाध्य पुर्जें हैं। इनका कारबार विनिमय साध्य पुर्जा कानून द्वारा निश्चित होता है। इस कानून के अनुसार जब तक कि उस पुर्जे पर किसी का नाम नहीं है वह न तो मुकदमा चला सकता है और न उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

चेक (Cheque) या धनादेश :—वह शर्त-रहित आज्ञा है जो किसी बैंक को दी जाती है जिसके द्वारा बैंक की एक निश्चित रकम किसी व्यक्ति विशेष अथवा उसकी आज्ञानुसार किसी व्यक्ति को अथवा आज्ञा (चेक) को ले जाने वाले को माँगने पर देनी होती है।

ऊपर लिखी हुई चेक की परिभाषा का विश्लेषण करने पर चेक के नीचे लिखे गुण मालूम पड़ते हैं :—(१) वह शर्त रहित आज्ञा है। (२) वह एक लिखित पुर्जा होता है। (३) उस पर लिखने वाला हस्ताक्षर करता है। (४) वह किसी बैंक विशेष पर ही काटा जाता है। (५) उसकी रकम निश्चित होती है। (६) उसका भुगतान माँगने पर तुरन्त किया जाता है। (७) उसका भुगतान उस व्यक्ति को जिसका नाम लिखा है अथवा उसकी आज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसे ले जाने वाले (Bearer) को किया जाता है। कोई भी हुंडी पुर्जा जिसमें ऊपर लिखी हुई कोई एक बात न हो चेक नहीं कहा जावेगा।

चेक में तीन पक्ष होते हैं :—(१) चेक काटने वाला (Drawer) अर्थात् जो चेक लिखता है और जिसका बैंक में हिसाब होता है। (२) जिस बैंक पर चेक काटा जाता है उसे Drawee कहते हैं। (३) और जिसके पक्ष में चेक काटा जाता है अर्थात् जिसे रकम मिलती है उसे Payee कहते हैं। कभी-कभी चेक काटने वाला (Drawer) स्वयं रकम पाने वाला (Payee) बन जाता है जब वह स्वयं अपने पक्ष में (To Self) चेक काटता है।

चेक फार्म :—इसके दो भाग होते हैं । चेक और उसकी प्रतिलिपि (Counterfoil) । प्रतिलिपि आगे के हवाले के लिए चेक बुक में ही रहती है और चेक फाड़कर रकम पाने वाले को दे दिया जाता है ।

सब चेकों पर तथा उनकी प्रतिलिपियों पर नम्बर पड़े होते हैं । बैंक तथा उसकी ब्रांच का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में छपा रहता है । तारीख के लिए जगह छुटी होती है । चेक काटने वाले को नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिए ।

तारीख :—जिस तारीख को चेक लिखा गया हो ठीक वही तारीख चेक पर डालनी चाहिए । अगली तारीख वाले अर्थात् उत्तरतिथीय चेक (Postdated cheque) को बैंक उस तारीख के आने तक भुगतान नहीं करेगा । परन्तु पूर्वतिथीय चेक (Ante-dated cheque) अर्थात् पिछली तारीख पड़े हुए चेक का भुगतान करने में बैंक को कोई भी आपत्ति न होगी यदि वह ६ महीने पुराना न हो । ६ महीने पुराने चेक को पुराना चेक (Stale cheque) कहते हैं । यदि चेक पर कोई तारीख न पड़ी हो तो बैंक उस पर ठीक तारीख डाल सकता है । किन्तु व्यवहार में बैंक ऐसे चेक को अधूरा (Incomplete) कह कर लौटा देता है ।

रकम :—रकम साफ-साफ अक्षरों और अंकों दोनों में ही देना चाहिए जिससे इस सम्बन्ध में कोई संदेह न रहे और न जालसाजी की सम्भावना रहे । चेक में रकम बढ़ाने के लिये लिखते समय तनिक भी स्थान न छोड़ना चाहिए । अंकों और अक्षरों में लिखी हुई रकम में कोई अन्तर न रहना चाहिए नहीं तो बैंक उसका भुगतान करने से इन्कार कर देगा और उस चेक पर लिख देगा कि “शब्द और अंक नहीं मिलते” ।

हस्ताक्षर :—हस्ताक्षर करते समय भी चेक काटने वाले को सावधानी से हस्ताक्षर करना चाहिए । हस्ताक्षर उस हस्ताक्षर से भिन्न नहीं होना चाहिए जो उसने हिसाब खोलते समय बैंक की हस्ताक्षर बही (Autograph Book) में किये थे । यदि हस्ताक्षर की लिखावट में तनिक भी अंतर हुआ तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा ।

प्रतिलिपि :—चेक बुक में से चेक फाड़ने से पहले उसकी प्रतिलिपि (Counterfoil) भर लेनी चाहिये । तारीख, पाने वाले का नाम, जिस हिसाब के सम्बन्ध में भुगतान किया जा रहा है उसका उल्लेख, रकम, उसमें अवश्य लिखनी चाहिये । चेक काटनेवाले को प्रतिलिपि पर भी हस्ताक्षर करना चाहिये ।

चेक की किस्में :—चेक विनिमयसाध्यता (Negotiability) की दृष्टि से दो तरह के होते हैं। (१) धनी जोग या वाहक चेक (Bearer cheque) (२) या शाह जोग चेक (Order cheque)

धनी जोग चेक (Bearer cheque)—जो बिना बेचान (Endorsement) किये ही विनिमय साध्य (Negotiable) बनाया जा सके। बेयरर चेक या धनी जोग चेक रखने वाला बैंक में जाकर उसका भुगतान माँग सकता है। इस चेक को चलाने के लिए उसे किसी आदमी को दे देना ही काफी है। जिसके पास बेयरर चेक होगा उसी को बैंक भुगतान दे देगा। यद्यपि कानूनके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास चेक है उसका भुगतान लेते समय भुगतान लेने वाला हस्ताक्षर करे किन्तु व्यवहार में बैंक बिना हस्ताक्षर कराये कपया नहीं देता।

आर्डर चेक या शाह जोग चेक—(Order cheque) यह है जिसे चलाने के लिए बेचान (Endorsement) करना पड़ता है। जिसको यह चेक दिया जाता है वह उसका मालिक तब तक नहीं होता जब तक कि देने वाला हस्ताक्षर करके उसके पक्ष में बेचान (Endorsement) नहीं कर देता। अतएव आर्डर चेक को चलाने के लिये केवल चेक को किसी को दे देना ही काफी नहीं है बल्कि उसके पक्ष में बेचान करना भी आवश्यक है। यदि कोई चेक किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में काटा गया हो लेकिन उसके आगे (or bearer या or order) न लिखा हो—उदाहरण के लिए "Pay to Mr. Rama Krishna" तो वह आर्डर या शाह जोग चेक माना जावेगा। आर्डर चेक को बेयरर चेक केवल चेक काटने वाला (Drawer) ही बना सकता है। उसे इस परिवर्तन पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

बेचान करना (Endorsement) :—किसी विनिमयसाध्य पुर्जे (Negotiable Instrument) अर्थात् चेक, हुन्दी, तथा प्रामिठरी नोट की पीठ पर हस्ताक्षर करने को बेचान करना (Endorsement) कहते हैं। पुर्जे की पीठ पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य उसका स्वामित्व अन्य किसी को हस्तांतरित कर देना है। जो व्यक्ति पुर्जे की पीठ पर हस्ताक्षर करता है उसे बेचान करने वाला (Endorser) और जिसके पक्ष में बेचान किया जाता है उसे (Endorsee) कहते हैं। पक्षला हस्ताक्षर रुपये पाने वाले (Payee) का होता है।

वेचान का रूप :—रकम पाने वाले (Payee) को चेक पर उसी तरह अपने हस्ताक्षर करना चाहिये जिस तरह चेक काटने वाले ने उसका नाम लिखा हो। यदि लिखने वाले ने उसका नाम गलत लिखा हो तो भी उसे अपने हस्ताक्षर उसी तरह से करना चाहिए जैसा कि उसने लिखा हो। ऐसी दशा में यह अधिक अच्छा होगा कि हस्ताक्षर करने वाला पहले तो जैसा उसका नाम लिखा हो वैसे ही हस्ताक्षर करे और उसके नीचे जिस प्रकार वह हस्ताक्षर करता है वैसे हस्ताक्षर कर दे। यदि चेक पर वेचान (Endorsement) ठीक नहीं होगा तो जिस बैंक पर वह काटा गया है उसका भुगतान करने से इन्कार कर देगा। नीचे ठीक वेचान के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :—

रकम पाने वाला (Payee)	गलत वेचान (Irregular Endorsement)	ठीक वेचान (Regular Endorsement)
व्यक्ति Individuals महात्मा गांधी सेठ चिरंजी लाल डाक्टर गिरवर सहाय सक्सेना देशरत्न बा० राजेन्द्रप्रसाद स्त्रियां— श्रीमती दस्तूर (Mrs. Dastur)	महात्मा गांधी सेठ चिरंजी लाल डाक्टर गिरवर सहाय सक्सेना देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद श्रीमती दस्तूर (Mrs. Dastur)	मोहन दास कर्मचंद गांधी चिरंजी लाल गिरवर सहाय सक्सेना डी. लिट. राजेन्द्र प्रसाद मोहनी दस्तूर श्री होरालाल दस्तूर की पत्नी (Mohini Dastur wife of H. Dastur)
कुमारी बोस (Miss Bose) कुमारी दिनेशनन्दनी चोरडिया (अब विवाहित हो गई)	कुमारी बोस (Miss Bose)	कमला बोस (Kamla Bose) दिनेशनन्दनी ^{डालिया} (अविवाहित समय का नाम) दिनेशनन्दनी चोरडिया Dinesh Nan Dalmia (Vice-Chordia)

रकम देने वाला (Payee)	गलत बेचान (Irregular En- dorsement)	ठीक बेचान (Regular Endose ment)
संस्थाएँ— बरेली कालेज, बरेली हिन्दी साहित्य सम्मे- लन प्रयाग अशिक्षित व्यक्ति— बनवारी लाल	भद्रन मोहन, प्रिंसिपल, बरेली कालेज, बरेली मौलिवन्धु शुक्ल, मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन	बरेली कालेज के लिए भद्रन मोहन प्रिंसिपल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए मौलिवन्धु शुक्ल, मंत्री बनवारी लाल के अग्रगृहे का निशान..... गवाही..
फर्म (सामेवारी)— सक्सेना भद्रसं...	जगदम्बा सहाय सक्सेना	सक्सेना भद्रसं या सक्सेना भद्रसं के लिए जगदम्बा सहाय सक्सेना
मेवर्स भीराम मेहरा संपनियों— जगत बैंक लिमिटेड	भी राम मेहरा जीवन् लाल सेक्रेटरी, जगत बैंक लि०	भी राममेहरा एन्ड क० जगत बैंक लि० के लिए और उसके बदले जीवन् लाल सेक्रेटरी
इटिका कपनी लि०..	निमलचन्द्र दास एन्ड कपनी, मैनेजिंग एजेंट	इन्डिया कंपनी लि० के लिए निमल चन्द्र दास एन्ड कंपनी— मैनेजिंग एजेंट
मिनिस्टर्स (Execu- tors) तथा प्रबंधकर्ता Administrators) १० सी. राय (स्वर्गनाथ १ गवा)	ए० एन राय	स्वयं अपने लिए तथा स्वर्गीय बी० सी० राय

रकम पाने वाला (Payee)	गलत बेचान (Irregular Endorsement)	ठीक बेचान (Regular Endorsement)
<p>B. C. Roy (Now deceased)</p> <p>ट्रस्टी (Trustees) रामनारायण तथा भजन- लाल स्वर्गीय बालमुकुन्द की जायदाद के ट्रस्टी (Ram Narain and Bhajan Lal Trust- tees of the es- tate of the late Bal-Mukand)</p>	<p>A. N. Roy.</p> <p>रामनारायण भजनलाल</p>	<p>की जायदाद का सह- एग्जिक्यूटर (Co-exec- utor) ए० एन० राय (For self and (Co-executor of the estate of late B. C. Roy- A. N. Roy)</p> <p>राम नारायण लाल भजन लाल स्वर्गीय बाल मुकुन्द की जायदाद के ट्रस्टी । Ram Narain Lal and Bhajan Lal Trustees of the estate of late Bal-Mukand.</p>

बेचान की किस्में :—बेचो पर साधारणतः चार तरह के बेचान होते हैं ।

(१) कोरा या साधारण बेचान (Blank or General Endorsement)

(२) पूर्ण या विशेष बेचान (Full or Special Endorsement)

(३) प्रतिबन्ध युक्त बेचान (Restrictive Endorsement)

(४) बिना हिम्मेदारी के बेचान (Sans Recourse Endorsement)

कोरा या साधारण चेचान :—वह होता है जिसमें हस्ताक्षर करने वाला केवल अपने हस्ताक्षर कर देता है और किसी व्यक्ति का नाम लिखकर उसको चेक हस्तान्तरित नहीं करता। इस प्रकार के चेचान का प्रभाव यह पड़ता है कि चेक बेयरर बन जाता है और उसको चलाने के लिए उस पर फिर हस्ताक्षर नहीं करने पड़ते। आर्डर चेक पर कोरा चेचान कर देने से वह बेयरर चेक बन जाता है।

पूरा या विशेष चेचान :—वह है जिसमें हस्ताक्षर करने वाला अपने हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त व्यक्ति का नाम भी लिख देता है जिसे वह चेक देना चाहता है।

उदाहरण के लिये .—Pay to Ram Lal or order
Shankar Sahai Saxena.

अब इस चेक पर फिर रामलाल के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी जब वह इसका भुगतान लेना चाहेंगे या और किसी को देना चाहेंगे।

प्रतिबध्नुक्त चेचान : यदि शर्कर सदाय सम्भेना इस चेक पर "केवल रामलाल को भुगतान कीजिए Pay to Ram Lal only" लिख दें तो फिर रामलाल उसको आगे हस्ताक्षर करके नहीं चला सकते। इसे प्रतिबध्नुक्त चेचान कहते हैं।

बिना ज़िम्मेदारी के चेचान :—जब चेचान करने वाला चेक के अस्वीकृत (Dishonour) हो जाने पर उसकी ज़िम्मेदारी या दायित्व (Liability) अपने ऊपर नहीं लेना चाहता तो वह बिना ज़िम्मेदारी के चेचान करता है। उदाहरण के लिए :—

बिना ज़िम्मेदारी के
प्रेमनारायण

Sans Recourse
Prem Narain

या

Without Recourse to me
Prem Narain

रेखांकित चेक (Crossed cheques) :—रेखांकित चेक वह होता है जिस पर दो समानांतर तिरछी रेखाएँ खिंची हों। उसमें चाहे कुछ लिखा हो (& Co.) या कुछ भी न लिखा हो। इसका अर्थ यह होता है कि इस चेक का भुगतान केवल किसी बैंक को ही मिल सकता है। अर्थात् यदि किसी को रेखांकित चेक मिले तो उसे उस चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए उस चेक को किसी बैंक को देना होगा। अर्थात् रेखांकित चेक का भुगतान किसी

बैंक के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। रेखांकन (Crossing) दो प्रकार की होती है (१) साधारण (General) (२) विशेष (Special)

साधारण रेखांकन (General Crossing) :— यह होता है कि जिसमें चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएँ लिखी हों और उनके श्रन्दर या तो कुछ नहीं लिखा जाता या “& Co” इत्यादि शब्द लिखे जाते हैं। इस तरह के रेखांकन का अर्थ यह होता है कि उस चेक का भुगतान किसी बैंक को ही दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को उसका भुगतान नहीं किया जावेगा। पाने वाला (Payee) उस बैंक का भुगतान बैंक जाकर स्वयं नहीं पा सकता। उसे इस प्रकार का चेक किसी बैंक को देना होगा वही उसका भुगतान पा सकेगा। क्योंकि चेक कानूनन मातृ (Legal Tender) नहीं है इस कारण पाने वाला (Payee) रेखांकित चेक लेना अस्वीकार कर सकता है।

रेखांकन के उदाहरण

साधारण रेखांकन

विशेष रेखांकन

& Co

Not Negotiable

A/C Payee only

Not Negotiable

& Co

United Commercial Bank, Ltd.

The Bharat Bank, Ltd.

Not Negotiable Jaipur Bank, Ltd.

A/C Payee only

The Imperial Bank of India

Barclay's Corporation Bank, Ltd A/C
New Standard Bank, Ltd.

विशेष रेखांकन (Special Crossing) :—वह होता है जिसमें दो तिरछी रेखाओं के बीच में किसी बैंक विशेष का नाम दे दिया गया हो। इसका अर्थ यह है कि चेक का भुगतान नामांकित बैंक के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जिस बैंक पर चेक काटा गया है वह इस प्रकार के चेक का भुगतान केवल उसी बैंक को करेगा जिसका नाम रेखाओं के बीच में दिया गया है। अधिकतर इस प्रकार का रेखांकन पाने वाले के अनुरोध पर किया जाता है जिसमें बैंक अधिक सुरक्षित हो जावे।

(& Co) :—रेखाओं के बीच में इन शब्दों के लिखने का कोई महत्त्व नहीं है। यह केवल एक पुरानी परिपाटी है जो आज भी प्रचलित है।

अविनिमय साध्य (Not Negotiable) :—“Not Negotiable” शब्द साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन दोनों में ही काम आता है। इनके लिख देने से बैंक की विनिमय साध्यता की सीमा निर्धारित हो जाती है। जिस चेक पर अविनिमय साध्य रेखांकन (Not Negotiable Crossing) हो वह केवल उन्हीं के हस्ताक्षरों से हस्तांतर किया जा सकता है जो जाने चुके हों। इस रेखांकन का अर्थ यह है कि जिसके नाम यह बैंक हस्तांतर किया जायेगा उसका अधिकार (Title) हस्तांतर करने वाले (Transferor) से किसी भी प्रकार अस्था नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में यदि हस्ताक्षर करने वाले का अधिकार दूषित है तो जिसे बैंक हस्तांतर किया जायेगा उसका भी अधिकार दूषित होगा। इसके विपरीत साधारणतः यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति से विनिमय साध्य पुर्जा (Negotiable Instrument) नेकनियती से मूल्य देकर ले लेता है तो उसका उस बैंक पर दोषरहित अधिकार (Good title) होगा फिर चाहे जिस व्यक्ति से उसने बैंक लिया हो।

केवल पाने वाले के हिसाब में जमा करो (Account Payee

only) :—यह भुगतान वसूल करने वाले बैंक को आज्ञा है कि वह इस चैक का रुपया वसूल करके पाने वाले के हिसाब में ही जमा करे उसे नकद रुपया न दे दे।

खुला चैक (Open Cheque) :—जो चैक रेखांकित नहीं होता उसे खुला चैक कहते हैं। चैक को रेखांकित करने का उद्देश्य यह होता है कि यथार्थ पाने वाले (Payee) को ही रुपये का भुगतान हो। खुला चैक बैंक में ले जाने पर उसका भुगतान दिया जाता है। इसलिए यदि खुला चैक चोरी चला जावे तो उस पर कोई रोक-थाम नहीं होता। जब चैक ड्राक से भेजा जावे तो उसे अवश्य रेखांकित कर देना चाहिए।

रेखांकन कौन कर सकता है :—चैक काटने वाला (Drawer) अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसने वह चैक मिले उसे साधारणतः अथवा विशेष रेखांकित कर सकता है। यदि कोई चैक साधारणतः रेखांकित (Crossed Generally) हो तो अगला व्यक्ति उस पर विशेष रेखांकन (Special Crossing) कर सकता है। यदि चैक पर विशेष रेखांकन हो तो अगला व्यक्ति उसमें "Not Negotiable" शब्द जोड़ सकता है। परन्तु यदि चैक पर विशेष रेखांकन किया गया हो तो वह बैंक जिसके पक्ष में रेखांकित किया गया है अपने एजेंट दूसरे बैंक के नाम उस चैक को विशेष रूप से रेखांकित कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कानून के द्वारा विशेष रेखांकन (Special Crossing) द्वारा केवल उस दशा में हो सकता है जब कि एक बैंक अपने एजेंट दूसरे बैंक के पक्ष में उसे करता है।

यदि बैंक रेखांकन की परवाह न करे, रेखांकित चैक का रुपया गलती से किसी अन्य पुरुष को दे दे, तो वह चैक के असली स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि रेखांकित चैक पाने वाले का बैंक में कोई हिसाब नहीं है तो चैक की रकम प्राप्त करने के लिए उसे चाहिए कि वह अपने हस्ताक्षर द्वारा उसके स्वामित्व को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दे जिसका हिसाब किसी बैंक में हो।

बैंक का चैक पर चिह्न (Bankers mark on cheques) :—जब कोई चैक जो भुगतान के लिए बैंक में लाया गया हो लेकिन बैंक उसका

भुगतान करना अस्वीकार कर दे तो उस चैक पर अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख कर दिया जाता है। इस प्रकार के चिह्न वापस किये जाने वाले चैक के धिरे पर दाईं तरफ लिखे जाते हैं। मिला-मिला चिह्नों के विषय में यहाँ कुछ लिखना आवश्यक है।

(१) R/D चैक काटने वाले से पूछिये (Refer to Drawer):—यह चिह्न तब लिखा जाता है जब कि चैक काटने वाले के हिसाब में यथेष्ट रकमा नहीं होता।

(२) भुगतान रोक दिया (Payment Stopped):—यदि चैक काटने वाला चैक काटने के उद्देश्य चैक को यह सूचित कर दे कि उक्त चैक का भुगतान न किया जाय तब तब उस चैक पर यह चिह्न लगा कर वापस कर देगा।

(३) (Effects not cleared):—उस समय लिखा जाता है जब कि वापस किये जाने वाले चैक के काटने वाले ने जो चैक इत्यादि जमा किए हैं उनका रकमा अभी तक बैंक ने वसूल नहीं कर पाया है और चैक काटने वाले के हिसाब में चैक का भुगतान करने के लिए यथेष्ट रकमा नहीं है।

(४) अगली तारीख वाले चैक (Post dated cheque):—जिस चैक पर अगली तारीख पड़ी है उस पर Post dated cheque लिख कर वापस कर दिया जाता है।

(५) पुराना चैक (Out of date):—जो चैक ६ महीने से अधिक पुराना है उस पर पुराना चैक (Out of date) लिख कर वापस कर दिया जाता है।

(६) चैक लिखने वाले के हस्ताक्षर नहीं मिलते : यदि चैक काटने वाले के हस्ताक्षर नहीं मिलते तो चैक "Drawer's Signatures differ" लिख कर वापस कर दिया जाता है।

(७) वेचान की प्रामाणिकता की आवश्यकता है (Endorsement requires confirmation):—जब कि किसी चैक पर वेचान ठीक न हो तो बैंक उस पर ऊपर लिखा चिह्न लगाकर वापस भेज देता है।

(८) परिवर्तन की प्रामाणिकता की आवश्यकता है (Alteration requires confirmation):—यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन चैक में किया जाय और उस पर हस्ताक्षर न हो तो बैंक उस पर ऊपर लिखा चिह्न लगाकर वापस भेज देता है।

सुपुर्दगीदार के नाम अदालत का हुक्म (Garnishee order) :—यदि बैंक के ग्राहक पर डिगरी हो गई हो और डिगरी से देनदार (Judgment debtor) हो तो अदालत उसके बैंक एकाउंट पर कानूनी रोक लगा सकती है और बैंक को आज्ञा दे सकती है कि वह उसके द्वारा कटे हुए चैकों का भुगतान रोक दे। इस प्रकार की आज्ञा को अदालत की आज्ञा या (Garnishee order) कहते हैं।

पुराना चैक (Stale cheque) :—जो चैक ६ महीने से अधिक पुराना हो उसे पुराना चैक (Stale cheque) कहते हैं। इस प्रकार के चैक का बैंक बिना चैक काटने वाले (Drawer) से पूछे भुगतान नहीं करेगा।

चिह्नित या प्रमाणित चैक (Marked cheque) :—वह होता है जिस पर बैंक हस्ताक्षर कर देता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि जिस दिन चैक बैंक के हस्ताक्षरों के लिए उपस्थित किया गया था उस दिन चैक काटने वाले के हिसाब में यथेष्ट रुपया था। चैक काटने वाले (Drawer), दूसरे बैंक, या चैक जिसके पास है (Holder) उसकी प्रार्थना पर चिह्नित (Mark) किया जा सकता है। यह निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यदि इस प्रकार का चिह्नित या प्रमाणित चैक उचित समय के अन्दर भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया जाता तो बैंक उस चैक के भुगतान के लिए रुपया अलग रख लेने के लिए विवश है।

फटा या विकृत चैक (Mutilated cheque) :—फटा या विकृत चैक वह होता है जो कि फट गया हो। इस प्रकार का चैक बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता; जब तक कि उसके सिरे पर “अकस्मात् फट गया” “Accidentally Torn” न लिख लिया जावे और उस पर हस्ताक्षर न कर दिये जावें।

बैंक का खर्चा (Bank charge) :—बैंक के खर्चों में जमा से अधिक निकाले गए रुपये पर सूद, चैक, बिल, तथा डिवीडेंड वारंट पर बैंक का कमीशन तथा अन्य सम्बन्धित खर्चें सम्मिलित होते हैं। हिन्दोस्तान में बैंक अधिकतर उन चैकों पर जो दूसरे शहरों में स्थित बैंकों पर काटे गए हैं से ६ आना सैकड़ा कमीशन लेते हैं। बैंक ड्राफ्ट और तार की हुंडी (Telegraphic Transfer) देने पर भी बैंक अपना कमीशन लेता है।

बैंक ड्राफ्ट (Bank-Draft) :—बैंक ड्राफ्ट एक चैक है जो बैंक अपनी शाखाओं अथवा अन्य बैंकों पर काटता है। उस चैक में अर्थात् बैंक ड्राफ्ट में उल्लिखित व्यक्तिको एक निश्चित रकम देने की प्रार्थना करता है।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से भेजा जा सकता है। उसका उपयोग वे लोग भी करते हैं जिनका बैंक में हिस्सा नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को पटना में बलकला कुछ रुपया भेजना हो तो वह उतना रकम तथा बैंक का कमीशन देकर बलकला से किसी बैंक पर बैंक ड्राफ्ट ले सकता है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट में जानसाला की भी कोई संभावना नहीं होता क्योंकि जिस बैंक पर ड्राफ्ट भिजा जाता है उसको रकम में परते ही सूचित कर दिया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति जिसका बैंक एकाउंट हो अपने किसी लेनदार (Creditor) को कदा कदा करना चाहे तो वह बैंक काट कर उसके पास भेज सकता है। लेकिन जिसका बैंक एकाउंट नहीं है वह ऐसा नहीं कर सकता लेकिन वह बैंक ड्राफ्ट खरीद कर अपने लेनदार के पास भेज सकता है। वह देश के अन्दर बैंक ड्राफ्ट खरीदा जाता है तो प्रति सैकड़ा थोड़ा सा कमीशन (२ आने) बैंक को देना पड़ते हैं। लेकिन विदेशों के लिए बैंक ड्राफ्ट खरीदते समय कमीशन विनिमय दर (Exchange Rate) में ही सम्मिलित कर लिया जाता है।

तार की हुंड़ी (Telegraphic Transfer) :—बैंकों के द्वारा द्रव्य टेलीग्राफिक ट्रांसफर अर्थात् तार की हुंड़ी के जरिये भी विदेशों को भेजा जाता है। द्रव्य भेजने वाला रकम, कमीशन, और भेजने का व्यय बैंक के पास जमा कर देता है, और बैंक अपनी शाखा अथवा दूसरे किसी बैंक को बिल द्वारा सूचित कर देता है कि उतनी रकम रुपया जमा करने वाले द्वारा बतलाये हुए व्यक्ति को दे दी जाय।

बैंक श्रृण और ओवर ड्राफ्ट (Bank loans and over Draft) :—व्यापार में व्यापारी को किसी विशेष सीढ़े के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर अपने बढ़ते हुये व्यापार को समालने के लिए उसे अधिक पूँजी की आवश्यकता हो सकती है। यदि उसके पास अधिक द्रव्य न हो तो उसे श्रृण लेना पड़ सकता है। वह उस दशा में अपने बैंक से श्रृण ले सकता है। यदि वह श्रृण के लिये यथेष्ट जमानत दे सके तो उसे श्रृण मिलने में तनिक भी कठिनाई न होगी।

बैंक से श्रृण लेने के दो तरीके हैं :—

(१) एक तरीका यह है कि बैंक व्यापारी के चालू खाते (Current Account) में उतनी रकम जमा कर दे और उसके नाम से एक श्रृण खाता (Loan Account) खोल कर उसमें उतनी रकम

नामें माह दे (Debit) । ऐसी दशा में पूरे ऋण पर सूद लिया जाता है ।

(२) दूसरा तरीका यह है कि व्यापारी बैंक से यह तय कर ले कि व्यापारी अपने चालू खाते पर उतनी रकम तक बैंक काट सकेगा जितनी तय हो चुकी है (यह रकम उसके रुपये जो कि चालू खाते में जमा हो उसके ऊपर होगी) सूद प्रति दिन के बैलेंस पर लगाया जाता है । यह बैंक ओवर ड्राफ्ट कहलाता है । ओवर ड्राफ्ट का अर्थ यह है कि व्यापारी ने जितनी रकम के बैंक (अपनी जमा की हुई रकम के ऊपर) काटे हैं और बैंक ने उसका भुगतान किया है उतनी रकम के लिए व्यापारी बैंक का ऋणी है ।

साख पत्र (Letter of credit) :—यह एक पत्र होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक अथवा एक से अधिक बैंकों को लिखता है जिसमें बताये हुए व्यक्ति को एक निश्चित रकम देने की प्रार्थना होती है । जब कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान को जाये और साथ में रुपया न रखना चाहे तो वह किसी भी स्थानीय बैंक को उतनी रकम तथा कमीशन देकर उस स्थान के किसी बैंक के नाम एक साख पत्र ले सकता है जहाँ कि वह जा रहा है । जब कि साख पत्र कई बैंकों के नाम होता है जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर हों तो जो भी बैंक जितना रुपया देता है उस साख पत्र पर लिख देता है और जब वह व्यक्ति अन्य स्थान के बैंक के पास जाता है तो जितना रुपया वह बैंक देता है उस पर लिख देता है । इस प्रकार जब तक वह रकम जो कि साख पत्र में लिखी है पूरी नहीं हो जाती तब तक वे बैंक जिनके नाम साख पत्र लिखा गया है उस व्यक्ति को रुपया देते रहेंगे । साख पत्र का अधिकतर उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति देश में अथवा विदेशों में भ्रमण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ।

बिल (Bill) :—“बिल एक लिखित पुर्जा होता है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को शर्त रहित आज्ञा होती है कि वह एक निश्चित रकम उल्लिखित व्यक्ति या उसकी आज्ञानुसार किसी दूसरे व्यक्ति या उस पुर्जे के धारक (Bearer) को दे दे । उस पुर्जे पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं” ।

बिल से सम्बन्धित चार पक्ष होते हैं :—(१) लिखने वाला (Drawer) जो व्यक्ति ड्राफ्ट लिखता है अर्थात् लेनदार (Creditor) अथवा विक्रेता । (२) जिस पर बिल लिखा जाय (Drawee) जिस व्यक्ति को भुगतान करने की आज्ञा दी जावे अर्थात् देनदार (Debtor) या खरीदार । (३) पाने वाला (Payee) जिस व्यक्ति के पक्ष में बिल लिखा जाय या जिसे

मुग्तान मिलने वाला हो (अर्थात् निम्नलिखित वाले का लेनदार), या स्वयं निम्नलिखित वाला जब कि वह बिल पर "बिल का मुग्तान भुक्त किया जाय" ऐसा लिख देता है । (४) रखने वाला (Holder) वह या तो पाने वाला (Payee) हो सकता है अथवा जिसके नाम बिल बनाया गया हो ।

विस्मै :—बिल दो प्रकार के होते हैं, देशी (Inland) और विदेशी (Foreign) । देशी बिल वह है जो किसी एक देश में ही लिखा जाय और उसी देश के रहने वाले किसी व्यक्ति पर किया जाय । जो बिल किसी अन्य देश के रहने वाले पर किया जाता है वह विदेशी बिल (Foreign Bill) कहलाता है ।

देशी बिल का नमूना

Rs. 275-00

Calcutta,

6 annas

1 st. January, 1948.

Three months after date, pay to our order a sum of Rupees two hundred and seventy five only, value received.

Mr. Bhola Dutta,
Harding Road,
Delhi

Per Pro. Bengal Paper Mills Co. Ltd.
Edward Jaies,
Director.

विदेशी बिल का नमूना (First of Exchange)

£ 55-3-2

Parker Street, Kingsway,

9 d.

London, the 9 th Jan., 1947.

Ninety days after sight of the First of Exchange (Second and third of the same tenure and date unpaid) pay to the National Bank of India Ltd, the sum of fifty five pounds, three shillings, and two pence, value received.

Per Pro. Longmans & Co. Ltd.,
Henry Anderson,
Manager.

In case of need apply to Messrs Martin & Co.,
London, for honour of Longmans & Co. Ltd.

To

Messrs Ram Narain Lal,
2, Katra Road,
Allahabad.

हुण्डी :—बिल के समान ही होती है। उसका उपयोग बालार के व्यापारी तथा सर्राफ बहुत करते हैं। इनका चलन व्यापारिक रीति-रिवाज के अनुसार होता है। हुण्डी दो प्रकार की होती है :— (१) दर्शनी हुण्डी जिसका भुगतान मांगने पर किया जाता है। (२) मिती हुण्डी जिसका भुगतान देखने के उपरान्त कुछ दिनों बाद या निश्चित तारीख के बाद होता है। मिती हुण्डी अधिकतर देखने से ६१ दिन के बाद भुगतान के लिए दी जाती है। मिती हुण्डी पर रियायती दिन (Days of Grace) उस स्थान के रिवाज के अनुसार दिए जाते हैं। हुण्डी अधिकतर मुद्रिया में लिखी जाती है।

दर्शनी हुण्डी का नमूना

सिद्ध श्री कानपुर शुभस्थान श्री पत्नी भाई हर प्रसाद बाल मुकुन्द जोग लिखा प्रयाग जी से वंशीधर हरिशचन्द्र की राम राम वंचना। आगे हुण्डी कीनी आप ऊपर दिया रुपया ५०० आंकड़े पाँच सौ के निमा दो सौ पचास के दुने पुरै देना। यहां राखा भाई दी सैन्ट्रल बैंक आव इण्डिया लिमिटेड, इलाहाबाद वाले के मिती फागुन बदी २ से पहुँचे दाम धनी-जोग बिना जब्ता बाजार चलन हुण्डी की रीति ठिकाने लगाय दाम चौकस कर देना। फागुन बदी २, १९६८।

अर्थ :—यह हुण्डी इलाहाबाद (प्रयाग जी) के वंशीधर हरिशचन्द्र ने कानपुर के हर प्रसाद बालमुकुन्द पर ५०० रु० के लिए की है। सैन्ट्रल बैंक आव इण्डिया लि० के मांगने पर फागुन बदी २, सम्बत् १९६८ के बाद इसका भुगतान कर देना होगा।

मिती हुण्डी का नमूना

रु० ५-५-०
स्टाम्प

सिद्ध श्री बरेली शुभ स्थान रामचन्द्र शिवचरण लाल लिखी देहली से जगजीवनराम की राम राम वंचना। अपरंच हुण्डी एक रुपया ५ ५०० आंकड़े

पचपन सौ जिसका निम्न रूपया सत्ताइस सौ पचास का दूनो पुरा देना । अठे रास्ता दि इलाहाबाद बैंक लिमिटेड पास मित्ती सावन सुदी दसमी (१०) से दिन इकसठ पीछे नामे साह जोग हुशदी चलन कल्दर दीओ मित्ती सावन सुदी दसमी (१०) सम्बत् १९६८ ।

अर्थ :—यह हुहा देहली क जगजावन राम ने बरेली के रामचन्द्र शिव-चरण लाल पर ५, ५०० रुपये के लिए की है । हुदी का भुगतान इलाहाबाद बैंक लिमिटेड को सावन सुदी १० सम्बत् १९६८ से ६१ दिन बाद करना होगा ।

बैंकिंग सम्बन्धी अन्य ज्ञातव्य बातें

बैंक को उपस्थित करना :—जिसके पास चेक हो उसे या तो स्वयं बैंक को उस बैंक पर जिस पर वह काटा गया है ले जाना चाहिए अथवा अन्य किसी बैंक के द्वारा उचित समय के अन्दर उपस्थित करना चाहिए । नहीं तो यदि वह बैंक जिस पर कि चेक काटा गया है इस बीच में दिवालिया हो जाय तो जिसके पास चेक है वह बैंक काटने वाले से रुपये के भुगतान का दावा नहीं कर सकता । वह केवल बैंक का लेनदार (Creditor) मात्र रह जावेगा और बैंक काटने वाले से भुगतान का दावा करने का अधिकारी नहीं रहेगा, यदि बैंक काटने वाले के हितान में उस समय यथेष्ट करया हो ।

बैंक अपने ग्राहक का एजेंट है और यदि उस ग्राहक के हितान में यथेष्ट रूपया है तो बैंक को उसके बैंकों को स्वीकार करना होगा । यदि बैंक ठीक तरह से काटे गए और उपस्थित किए गए हो तो निम्नलिखित दशाओं में बैंक अपने ग्राहक के बैंक को स्वीकार नहीं करेगा :—

- (१) जब ग्राहक स्वयं उसके भुगतान को रोक दे ।
- (२) जब बैंक को ग्राहक के दिवालिया हो जाने की सूचना मिल जाय ।
- (३) जब उसे ग्राहक की मृत्यु या पागल हो जाने की सूचना मिल जाय ।
- (४) जब अदालती आज्ञा (Garnishee Order) मिल जाय ।
- (५) जब जमा किए हुए बैंकों का दूसरे बैंकों से भुगतान न हो चुका हो ।
- (६) जब अकों और अक्षरों में दो हुई रकम मिल हो ।
- (७) रेखांकित चेक (Crossed cheque) किसी बैंक के ही द्वारा उपस्थित करना चाहिए ।

- (८) जब चैक (क) फटा हो, (ख) अगली तारीख का हो अथवा
 (ग) ६ महीने से अधिक पुराना हो ।
 (९) प्रत्येक संशोधन पर पूरे हस्ताक्षर होना चाहिए ।
 (१०) यदि पाने वाले के हस्ताक्षर अधूरे हों, बैंक में रखते हुए
 हस्ताक्षरों से न मिलने वाले हों अथवा हस्ताक्षर न हों ।
 (११) जब कि चैक में कोई परिवर्तन किया गया हो किन्तु उस पर
 हस्ताक्षर न किए गए हों ।

जाली चैक के सम्बन्ध में बैंक का उत्तरदायित्व :—(१) जो
 बैंक कि ऐसे चैक का भुगतान कर देता है जिसकी रकम बढ़ा दी गई हो, या
 ऐसे चैक का भुगतान कर देता है कि जिस पर हस्ताक्षर जाली हैं तो बैंक
 अपने हिसाबदार के हिसाब से वह रकम वसूल नहीं कर सकता, जब तक कि
 (अ) परिवर्तन पर उसके हस्ताक्षर न हों, (ब) अथवा चैक काटने वाले
 ने ऐसी लापरवाही की हो जिसके कारण वह जालसाजी सम्भव हो सकी ।

(२) यदि वेचान (Endorsement) जाली हो और
 बैंक उसका भुगतान कर दे तो वह उस हानि के लिए जिम्मेदार न होगा ।
 बैंक को प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर की जानकारी नहीं हो सकती । इसलिए
 यदि वेचान जाली हो और बैंक उसे बिना जाने भुगतान कर दे तो वह उतना
 रुपया हिसाबदार के हिसाब से ले सकता है ।

चैक का अत्यन्त सुरक्षित रूप :—यदि कोई व्यक्ति ऐसा चैक काटना
 चाहता है कि जिससे रकम पाने वाले को ही दया मिले तो उस पर विशेष
 रेखांकन कर देना चाहिए और उस पर “Not Negotiable” और
 “Account Payee only” शब्द लिख देना चाहिए। उदाहरण के लिए
 यदि हम रामसहाय अग्रवाल के नाम चैक काटना चाहते हैं जिनका कि हिसाब
 “इलाहाबाद बैंक लिमिटेड” में है तो चैक का सबसे सुरक्षित रूप नीचे
 लिखा होगा :—

Not Negotiable
 Account Payee only
 The Allahabad Bank Ltd.

यह चैक रामसहाय अग्रवाल के अतिरिक्त और किसी के काम का नहीं है ।
 चैक द्वारा भुगतान करने से लाभ :—चैक देश भर में एक स्थान से
 दूसरे स्थान को रुपया भेजने का सस्ता साधन है । जिस भुगतान के सम्बन्ध में

कोई झगडा उठ खड़ा हो तो यह एक गवाही का काम देता है। क्योंकि उसका भुगतान बैंक के द्वारा होता है। इससे द्वारा आसानी लेन-देन तय हो जाता है और नकद रुपया लेना-देना नहीं पड़ता। इसका अधिक प्रचार करने के लिए इस पर से ड्यूटी हटा दी गई है।

बैंक में हिसाब रखने से लाभः—कारखाने वालों, व्यापारियों, तथा दूसरे पेशों में लगे हुये लोगों का बैंक में हिसाब रखने से बहुत से लाभ होते हैं। उनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं :—

बैंक में रुपया जमा करने से सुरक्षित रहता है और दैनिक चिकी की रकम को जमा करने की सुविधा रहती है। साथ ही अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी बैंक में रखने से अधिक सुरक्षित रहती हैं। बैंक के द्वारा दूसरों को आसानी से भुगतान किया जा सकता है। अपने पास अधिक रुपया रखने की आवश्यकता नहीं होती। बैंक अपने ग्राहक के काटे हुए चेकों का भुगतान करता है और उसे मिले हुए चेकों का रुपया वसूल करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ग्राहकों को हुण्डी बिल को स्वीकार (Honour) करता है और उनका रुपया वसूल करता है। बैंक कुछ एजेंट के भा कार्य करता है, जैसे वह कम्पनियों के हिस्सों पर लाभ (Dividend) वसूल करता है जीवन तथा अन्य बीमा की प्रीमियम लेता है। बैंक व्यापारिक मामलों की सूचना देता है। बैंक अपने ग्राहक का खाता (Credit) सम्बन्धी आच-पड़ताल का हवाला देने वाले होते हैं और इस तरह वे उसकी खाता और प्रसिद्धि बढ़ाते हैं। वे अपने ग्राहकों को स्वीकृत जमानत पर नकद खाता (Cash Credit) और ओवर ड्राफ्ट के रूप में रुपया उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक में हिसाब रखने के और भी लाभ हैं।

नये ग्राहकों का हिसाब खोलनाः—बैंक नये ग्राहकों का चालू खाता (Current Account) उस समय तक नहीं खोलता जब तक उस ग्राहक के सम्बन्ध में संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं कर लेता। यदि बैंक इतनी सावधानी न रखे तो वह कठिनाई में पड़ सकता है। नये ग्राहक के सम्बन्ध में सतोष हो जाने के उपरान्त उसके हस्ताक्षर के नमूने ले लिए जाते हैं और हिसाब खोल दिया जाता है।

अध्याय २

द्रव्य (Money) और वैकिंग

द्रव्य और वैकिंग हमारे आर्थिक जीवन के आधार हैं जिनके द्वारा हम अपने आर्थिक प्रयत्नों को भली प्रकार पूरा कर सकते हैं। यदि आज द्रव्य (Money) और वैकिंग की सुविधायें हटा ली जावें तो धन (Wealth) का उत्पादन, व्यापार, उद्योग-धंधे सभी असम्भव हो जायें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक उन्नति के लिए द्रव्य और वैकिंग का संतोषजनक व्यवस्था आवश्यक है।

द्रव्य के तीन मुख्य कार्य हैं :—(१) वह विनिमय (Exchange) का माध्यम होता है, (२) वह मूल्य (Value) का मापदण्ड होता है, (३) और द्रव्य के रूप में हो धन या सम्पत्ति (Wealth) को जमा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बटुई अपनी बनाई हुई मेज को बेच कर उसके बदले में गेहूँ, कपड़ा और अपनी बीमार स्त्री के लिए दवा लेना चाहता है तो वह अपनी मेज को ४० रु० में बेच कर उस ४० रुपये से गेहूँ, कपड़ा और दवा खरीद लेता है। यदि द्रव्य अर्थात् वस्तु चलन में न हो तो उसे मेज के बदले में गेहूँ, कपड़ा और दवा मिलने में बहुत कठिनाई हो और समय को नष्ट करना पड़े। इसी प्रकार यदि द्रव्य न हो तो मेज के मूल्य निर्धारण में भी बहुत कठिनाई पड़े। वह मेज के बदले कितना गेहूँ या कपड़ा ले इसका निश्चय करना कठिन हो जावे। और यदि बटुई ने अधिक में बेच कर दस हजार रुपये जमा कर लिए हैं तो वह मविष्य में उन दस हजार रुपये का जिस प्रकार चाहे उपयोग कर सकता है।

ऊपर लिखे विवरण से यह स्पष्ट है कि बिना द्रव्य के आधुनिक आर्थिक संगठन चल ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि यदि द्रव्य चलन में न हो तो बटुई क्या करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति मिलना तो असम्भव है कि जो गेहूँ, कपड़ा

और दवा तीनों ही वस्तुएँ उसे दे सके और बदले में मेज लेने की तैयार हो । व्यवहार में यह होगा कि बटई किसी किसान को दूँ देगा जो कि गेहूँ बेचना चाहता हो परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसे मेज की आवश्यकता हो । सम्भवतः वह हल अधिक पसंद करे । ऐसी दशा में जब तक दो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता हो तब तक अदल बदल (Barter) हो ही नहीं सकता । वस्तुओं के अदल-बदल में एक कठिनाई यह भी है कि बहुत सी वस्तुओं का विभाजन नहीं हो सकता । उनके बदले में बेचने वाले को उस वस्तु के मूल्य (Value) के बराबर ही किसी दूसरी वस्तु को लेना होगा । फिर चाहे बेचने वाले को बदले में ली जाने वाली वस्तु की उसनी माना की आवश्यकता न हो । अपने ऊपर के उदाहरण को लें तो बटई का यदि १० सेर गेहूँ या ५ गज कपड़ा चाहिए तो उसे कठिनाई होगी क्योंकि मेज के टुकड़े तो हो नहीं सकते ; उसे ही मेज के बदले ४ मन गेहूँ अथवा १०० गज कपड़ा जो उस मेज का गेहूँ या कपड़े में मूल्य है सब का सब लेना होगा अन्यथा अदल बदल नहीं हो सकता । द्रव्य के चलन से यह कठिनाई दूर हो जाती है । बटई ४० रुपये में मेज बेचकर सब चीज़ें उस मात्रा में खरीद सकता है जितनी की उसको आवश्यकता है ।

द्रव्य के न होने पर केवल वस्तुओं के विनिमय (Exchange) में ही कठिनाई नहीं होगी बल्कि उनके आपसी मूल्य निर्धारण में भी बहुत कठिनाई होगी । पुराने समय में जब गाँवों में मनुष्य अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न कर लेता था और उसकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं और शिनी चुनी ही होती थीं तो बहुत थोड़ी सी वस्तुओं का कय विक्रय होता था । उस समय उनका आपसी मूल्य निर्धारण कुछ सीमा तक सम्भव भी था । उदाहरण के लिए सन्नी और गेहूँ बराबर मूल्य के मान लिए जाते थे । किन्तु आज तो समय जगत में अगणित वस्तुएँ हैं । उन सब का एक दूसरे में मूल्य निर्धारण असम्भव है । अतएव उन सबका मूल्य निर्धारित करने के लिए समान मूल्य मापदण्ड (Common Standard of Value) आवश्यक है । द्रव्य इसी काम को करता है ।

यही नहीं, आवश्यकता से अधिक धन (Wealth) को जमा करने का भी द्रव्य सर्वोत्तम साधन है, जिससे कि मविष्य में धन जमा करने वाला सुगमता से जिस प्रकार चाहे उसका उपयोग कर सके । उदाहरण के लिए यदि बटई ने दस हजार रुपये जमा कर लिए हैं तो वह उस द्रव्य का उपयोग जिस कार्य में चाहे बिना कठिनाई के कर सकता है । किन्तु यदि उसने अपनी

वस्तु को गेहूँ, लकड़ी अथवा अन्य किसी वस्तु के रूप में जमा किया है तो उसे कठिनाई होगी ।

अस्तु ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि आधुनिक समय में जब कि धन या सम्पत्ति (Wealth) का उत्पादन (Production) बड़े-बड़े कारखानों द्वारा होता है, संसार के सब देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गई हैं जिनको पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी तब बिना द्रव्य (money) के यह धंधे और व्यापार सम्भव ही नहीं हो सकता । यही कारण है कि आधुनिक जगत को द्रव्य की इतनी अधिक आवश्यकता पड़ती है ।

यही कारण है कि आज प्रत्येक सम्य सम्राज में यदेष्ट द्रव्य की आवश्यकता होती है जिससे व्यापार और धंधे सुगमता से चल सकें । चलन में द्रव्य के तीन रूप होते हैं एक तो प्रामाणिक सिक्का (Standard coin) दूसरे संचैतिक सिक्का (Token coin) तीसरा कागज़ी मुद्रा (Paper currency) अथवा कागज़ी नोट । अधिकतर आजकल कागज़ी नोट और संचैतिक सिक्कों का ही चलन होता है प्रामाणिक सिक्के नहीं निकाले जाते हैं । और कागज़ी नोट राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय बैंक (Central Bank) द्वारा निकाले जाते हैं । किन्तु प्रत्येक देश में एक ही परिपाटी नहीं है ।

किन्तु केवल कागज़ी नोट (Paper currency) और संचैतिक सिक्कों (Token coins) से ही आधुनिक समाज की द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो जाती । कागज़ी नोट और संचैतिक सिक्कों के अतिरिक्त चेक, बिल तथा हुण्डी इत्यादि विनिमय साध्य पुर्जा (Negotiable Instrument) का भी उपयोग होता है । जो देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र हैं वहाँ कागज़ी मुद्रा (Paper currency) से १० से १५ गुने तक चेकों का उपयोग होता है । अर्थात् लोग चेकों के द्वारा अपनी देन-दारी को भुगतान करते हैं । चेक बैंकों पर काटे जाते हैं और वही व्यक्ति चेक काट सकता है जिसका बैंक में हिसाब है अर्थात् जिसका रुपया चालू खाते (Current Account) में जमा होता है । इस प्रकार की जमा (Deposit) दो प्रकार उत्पन्न होती है । किसी व्यक्ति के अपनी आमदनी से बचत करके रुपया बैंक में जमा करने अथवा बैंक से ऋण लेने से । बैंक ऋण देकर किस प्रकार जमा (Deposit) का निर्माण करता है इसके सम्बन्ध में हम आगे लिखेंगे ।

बैंक का मुख्य कार्य जनता का अपनी बचत का धरणा जमा करने की सुविधा देना है। बैंक जनता के द्रव्य को जमा (Deposit) के रूप में सुरक्षित रखता है। यह उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जब मनुष्य की आय उसके व्यय से अधिक होती है तो उससे पास जो द्रव्य बचता है उसको सुरक्षित रखने का समस्या उठ खड़ी होती है। किसी व्यक्ति अपना संस्था की बचत की रकम भित्तनी ही अधिक होती है उसकी सुरक्षित रखने की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बैंक जनता को अपनी बचत की सुरक्षित रखने की चिन्ता से मुक्त कर देते हैं। बैंक जनता की बचत की वेबल सुरक्षित रखने का ॥ जिम्मा नहीं लेते वरन् उसको जमा करने वाले के माँगने पर देने का बचन भी देते हैं।

सत्रहवीं शताब्दी में पंजीय में सार्वकार लोग धनी व्यक्तियों का धन, जेवर, सोना, चाँदी इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएँ अपने पास सुरक्षित रखते थे और उस सेवा के लिए वे कर्मचान लेते थे। किन्तु कुछ समय के उपरान्त सुनारों ने देखा कि उनके धना भाइयों को बरपा पैसा और सोना चाँदी जमा करते थे वह अधिकतर निकालते नहीं थे। सुनारों ने देखा कि बीरुपवा जमा किया जाता है उसका बहुत थोड़ा अंश भाइयों निकालते हैं। अतएव वे भाइयों के जमा किए हुए धन्य को चाल के रूप में दूसरों को उठाने लगे और सूद प्राप्त करने लगे। अब वे सुनारों को दोहरा लाभ होने लगा। जमा करने वालों से वे उनके धन की सुरक्षित रखने के लिए कमीशन लेते और उसको व्यापारियों को कर्ज देकर सूद कमाते थे। अतएव सुनारों ने जमा को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने को सुरक्षित रखने के लिये कर्मचान लेना बन्द कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि डिपॉजिट बहुत बढ़ गए और इन सुनारों को बहुत लाभ होने लगा। अपने व्यापार का बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने डिपॉजिट पर थोड़ा सूद देना भी आरम्भ कर दिया और वे सर्वसाधारण में सितम्पयिता की भावना को जाग्रत करके अविक्रमिक डिपॉजिट आकर्षित करने लगे। वे लोग विवना सूद बरपा जमा करने वालों को देते थे उससे कहीं अधिक सूद भ्रष्ट पर वसूल करते थे। इस सिद्धान्त पर आधुनिक बैंकिंग का निर्माण हुआ। अनुभव से ज्ञात हुआ कि यदि देश की मुद्रा मौखिक के प्रति जनता का किसी कारण निरुपेक्ष नष्ट अविश्वस्य न हो गया हो और न बैंकों के प्रति अविश्वस्य हो तो साधारण समय में जो डिपॉजिट बैंकों में रखी जाती है उसका केवल बहुत थोड़ा भाग किसी समय निकाला जाता है। यही कारण है कि बैंक जमा

किये हुए रुपये का बहुत बड़ा भाग (६० प्रतिशत) ऋण के रूप में लोगों को दे देता है और उस पर सूद लेता है।

बैंक डिपॉजिट का निर्माण करते हैं :—जमा किए हुए रुपये का अधिकांश भाग ऋण के रूप में उठाने का कार्य एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि जिसके कारण बैंकिंग का आधुनिक जगत में इतना अधिक महत्व है। “बैंक केवल लोगों की वचत को जमा करने वाले ही नहीं हैं वरन् वे द्रव्य (money) का निर्माण करने वाले भी हैं”। बैंक जो द्रव्य (money) का निर्माण करते हैं वह केवल डिपॉजिट किये हुये रुपये का ऋण स्वरूप अन्य व्यक्तियों को देने से ही सम्भव हो सकता है। जहाँ कपया कि बैंक के ग्राहक बैंक में जमा करते हैं उसको बैंक व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों का कर्ज देकर नई डिपॉजिट निर्माण करते हैं और वह डिपॉजिट ही द्रव्य (money) के सदृश्य बैंक से ऋण लेने वालों के द्वारा काम में लाई जाती है। उदाहरण के लिए जब बैंक किसी व्यापारी को ऋण देता है तो वह कपया उसको दे नहीं दिया जाता वरन् उसके नाम जमा कर दिया जाता है। कर्ज लेने वाला ग्राहक आवश्यकतानुसार उसको चेक द्वारा निकाल सकता है। चेक का उपयोग वह इसी प्रकार करता है जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति वस्तुओं के क्रय-विक्रय में द्रव्य का उपयोग करता है। जिस प्रकार द्रव्य (money) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) है ठीक वही कार्य डिपॉजिट करती है। बैंक इन डिपॉजिटों का निर्माण करते हैं अस्तु बैंक एक प्रकार से विनिमय के माध्यम अर्थात् द्रव्य का निर्माण करते हैं। यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि आधुनिक काल में व्यापार में जितना उपयोग कागजी नोट अथवा सिक्कों का होता है उससे दस पंद्रह गुना उपयोग चेकों का होता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जितना द्रव्य सरकार अथवा राष्ट्रीय सेंट्रल बैंक (देश का केन्द्रीय बैंक) सिक्कों और कागजी नोटों के रूप में निकालती है उसका कई गुना द्रव्य डिपॉजिटों के रूप में बैंक उत्पन्न करते हैं। अतएव देश को जितने द्रव्य की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग बैंक उत्पन्न करते हैं।

द्रव्य के निर्माणकर्ता होने के कारण बैंक जनता की क्रय-शक्ति (Purchasing Power) को निर्धारित करते हैं और द्रव्य परिमाण सिद्धान्त (Quantity theory of money) के अनुसार मूल्य स्तर (Price Level) को भी निर्धारित करते हैं। बैंकों के हाथ में जो इतनी शक्ति है वह केवल इसलिए कि वे ग्राहकों के द्वारा जमा किए हुए रुपये को दूसरों को

श्रृणु स्वरूप दे सकते हैं। अब हम विस्तारपूर्वक इस बात का अध्ययन करेंगे कि बैंक किस प्रकार श्रृणु देकर नवीन डिपॉजिटों का निर्माण करते हैं।

बैंकों द्वारा डिपॉजिट या द्रव्य (money) निर्माण करने की क्रिया :—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक के पास जो कुछ भी द्रव्य डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाता है वह सब का सब अपने पास नकद रूप में नहीं रखता बल्कि उसका अधिकांश भाग वह कर्ज के रूप में दे देता है। जब कोई श्रृणु लेने वाला बैंक को अपनी साख के सम्बन्ध में भरोसा दिला देता है और बैंक उसको दस हजार रुपये श्रृणु देना स्वीकार कर लेता है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो श्रृणु लेने वाला उन दस हजार रुपये को निकाल ले अथवा उन दस हजार रुपये को अपने हिसाब में जमा कर दे। यदि श्रृणु लेने वाला दस हजार रुपये को निकाल लेता है तो जहाँ तक बैंक के हिसाब का प्रश्न है नीचे लिखा परिवर्तन होगा :—

डिपॉजिट तो श्रृणु लेने के पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी उसमें कोई परि-
बैंक की वर्तन न होगा। हाँ बैंक के पास जितना नकद रुपया (cash) था उसमें दस हजार की कमी हो जावेगी और दूसरी देनी (Asset) अर्थात् कर्ज-
दारों (Debtors) में दस हजार की वृद्धि हो जावेगी। इसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ हुआ कि बैंक ने नकद देनी (Cash Asset) को एक दूसरी देनी में बदल लिया। यदि श्रृणु लेने वाला दस हजार रुपया न निकाल कर उसे अपने हिसाब में बैंक ने पास जमा कर देता है कि जिससे उसे जब आवश्यकता हो वह आगे निकाल सके तो बैंक के हिसाब में नीचे लिखा परिवर्तन होगा :—

देना करने से बैंक की डिपॉजिट दस हजार रुपये से बढ़ जावेगी रोकड़ या नकदी रुपयों की त्यों रहेगी उसमें कोई परिवर्तन न होगा और दूसरी देनी (Asset) अर्थात् कर्जदारों (Debtors) में दस हजार रुपये की वृद्धि हो जावेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि बैंक की लेनी (Liability) अर्थात् डिपॉजिट में दस हजार रुपये की वृद्धि हुई और बैंक की देनी (Asset) अर्थात् कर्जदारों में भी दस हजार रुपये की वृद्धि हुई। यदि बैंक किसी व्यक्ति से कोई सिक्कुरिटी (प्रतिभूति) खरीदे तो भी यही परिणाम होगा। बैंक सिक्कुरिटी के मूल्य स्वस्थ बेचने वाले का चेक देगा। बेचने वाला या तो चेक को भुना कर रुपया निकाल लेगा अथवा चेक को अपने हिसाब में जमा कर देगा। यदि सिक्कुरिटी बेचने वाला रुपया निकाल लेता है तब तो बैंक की रोकड़ या

नकदी कम हो जावेगी और सिक्क्यूरिटी उतने ही मूल्य की बढ़ जावेगी और यदि सिक्क्यूरिटी बेचने वाला उस बैंक को अपने हिसाब में जमा कर देता है तो डिपॉजिट में वृद्धि होती है और उधर सिक्क्यूरिटी में वृद्धि होती है।

ऊपर लिखे विवरण में हमने यह भी मान लिया है कि जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो वह उतना रुपया बैंक से तुरन्त निकाल लेता है किन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। ऋण लेने वाला अधिकतर उस रुपये को अपने हिसाब में जमा कर देता है वह तुरन्त रुपया नहीं चाहता। जब उसको आवश्यकता पड़े वह रुपया निकाल सके यह अधिकतर चाहता है। बैंक अधिकतर अपने उन्हीं स्थायी ग्राहकों को ऋण देते हैं जिनका उनके साथ हिसाब होता है और जिनके बारे में बैंकों को पूरी जानकारी होती है। व्यापारी बैंक के द्वारा ही मुग्तान करता है रुपया अपने पास अधिक नहीं रखता। अतएव जब किसी व्यापारी को अपने कारबार के लिए कुछ पूँजी की आवश्यकता होती है तो वह बैंक से ऋण लेकर अपने हिसाब में जमा कर देता है। यही कारण है कि यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि “ऋण डिपॉजिट का निर्माण करते हैं” जब बैंक सिक्क्यूरिटी खरीदते हैं उसका भी यही परिणाम होता है अर्थात् सिक्क्यूरिटी खरीदने से डिपॉजिट की वृद्धि होती है क्योंकि बेचने वाला रुपया न निकाल कर उसे अपने हिसाब में जमा कर देता है। आज जो बैंकों की डिपॉजिट में इतनी अधिक वृद्धि हुई है वह अधिकतर ऋण देने और सिक्क्यूरिटी खरीदने से ही सम्भव हो सकी है।

यद्यपि बैंक ऋण देकर डिपॉजिट निर्माण करते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि डिपॉजिट निर्माण करने की कोई सोचा नहीं है और बैंक जितनी चाहें उतनी डिपॉजिट निर्माण कर सकते हैं। वह तो स्पष्ट ही है कि बैंक जिस डिपॉजिट अर्थात् द्रव्य (money) का निर्माण करते हैं वह उनकी देनी (Liability) है और उन्हें उसको नकदी में चुकाना पड़ सकता है। बैंक जो डिपॉजिट अर्थात् द्रव्य का निर्माण कर सकते हैं वह केवल इस कारण कि उसकी सब देनी (Liabilities) का मुग्तान उसको नकदी में नहीं करना पड़ता। दूसरे अर्थों में बैंक की डिपॉजिट का बहुत थोड़ा अंश ही किसी समय बैंक से निकाला जाता है। किन्तु बैंक में डिपॉजिट करने वालों को कुछ नकदी की तो आवश्यकता पड़ती ही है जो कि बैंक को देनी होगी। जनता को अपने दैनिक कारबार के लिए कुछ नकदी की आवश्यकता होती है जो कि बैंकों को देनी पड़ती है और जो कि वह बैंकों से निकालते हैं। अस्तु बैंकों को डिपॉजिट के रुपये में से कुछ रुपया ग्राहकों के मभिने पर उन्हें नकदी के रूप में

रख सकता है और यदि वह बीस प्रतिशत लाभ ले ले तो उसको २ हजार रुपये लाभ मिलेंगे। परन्तु यदि उसे साल मिलती है और उसकी दुकान में २० हजार का माल है तो वह वस्तुओं पर १० प्रतिशत लाभ लेकर भी २ हजार रुपये कमा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक घरे या व्यवसाय में फल प्राप्त करने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करना पड़ती है और यदि व्यवसायी या व्यापारी केवल अपनी निजी पूँजी से कारबार करे तो कारबार बहुत योर्डाँ मात्रा में होगा और उपभोक्ताओं (Consumers) अर्थात् प्रादको को वस्तुओं का अधिक मूल्य देना होगा और सम्पत्ति का उत्पादन (Wealth Production) कम होगा। अतएव साल (Credit) के द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है।

अध्याय ३

भिन्न प्रकार के बैंक

बैंक कितने प्रकार के होते हैं इसका ठीक-ठीक उत्तर देना कठिन है क्योंकि बैंकों का स्वरूप किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा वहाँ की परम्पराओं पर निर्भर होता है। फिर एक ही देश में आर्थिक संगठन में परिवर्तन होने के साथ बैंकों के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, उदाहरण के लिए जर्मनी में व्यापारी बैंक (Commercial Banks) उद्योग-धन्धों को भी पूँजी देते हैं किन्तु इंग्लैंड के व्यापारी बैंक ऐसा नहीं करते। अस्तु बैंकों का ठीक-ठीक वर्गीकरण करना कठिन है परन्तु फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए उनका वर्गीकरण कर लेना आवश्यक है।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि बैंक का मुख्य कार्य यह है कि वह देशवासियों द्वारा बचाये हुए धन को आकर्षित कर और एकत्रित पूँजी को देश के आर्थिक लाभ के लिए उत्पादन कार्य में लगाये। जब बैंक एक और देश की धन को एकत्रित करता है वहाँ दूसरी ओर वह उत्पादन कार्य के लिए पूँजी देने की व्यवस्था करता है। किन्तु सम्पत्ति या धन (Wealth) का उत्पादन बहुत प्रकार से होता है। किसान भूमि पर खेती करके सम्पत्ति का उत्पादन करता है। यह उद्योग-धन्धों में (Cottage Industries) में लगा हुआ कारीगर कपड़ा, जूता या पीतल के बर्तन बनाकर सम्पत्ति का उत्पादन करता है। बड़े पूँजीपति पुतली घर या कारखाने स्थापित करके सम्पत्ति का निर्माण करते हैं और सौदागर या व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको कुछ समय अपने गोदाम में सुरक्षित रख कर और अनुकूल समय पर उसे बेच कर सम्पत्ति का उत्पादन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि खेती के द्वारा, धंधों के द्वारा, और व्यापार के द्वारा, सम्पत्ति का उत्पादन होता है। और इस उत्पादन कार्य को भली-भाँति चलाने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसे बैंक देते हैं। किन्तु प्रत्येक धन्धे की साख की आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं तथा जितने समय के लिये साख की आवश्यकता होती है उसकी अवधि भी भिन्न होती है। किसी धन्धे में लम्बे समय के लिए साख की आवश्यकता होती है तो किसी में कम समय के लिए, फिर प्रत्येक धन्धे के लिए

साख का स्वरूप क्या होगा इसमें भी भेद होता है। उदाहरण के लिए किसान को फसल उत्पन्न करने के लिये ६ महीने के लिए साख (Credit) चाहिए क्योंकि वह ६ महीने में फसल उत्पन्न करके उसे बाज़ार में बेचकर दाम वसूल कर लेगा। किन्तु यदि वह पैसों की ज़ाद्री लेने के लिए, मूल्यमान बेतरी के यंत्र या औज़ार लेने के लिए या कुर्बानियाँ बनवाने के लिए ऋण लेता है तो वह उसे एक फसल के बाद न चुका सकेगा, उस तीन से पाँच वर्ष तक के लिए ऋण चाहिए कि जिसमें वह धीरे-धीरे प्रत्येक फसल के उपरान्त थोड़ा थोड़ा चुका सके। इसी प्रकार ग़रीब पुराना ऋण चुकाने के लिए तथा भूमि इत्यादि मोल लेने के लिए उसे २० से ३० वर्षों के लिए ऋण चाहिए। यहाँ नहीं कि किसान को भिन्न-भिन्न समय के लिए ऋण चाहिए वरन् उसका धन अनिश्चित होता है कभी फसल अच्छी होती है तो कभी फसल नष्ट हो जाती है। अतएव जो भी बैंक किसानों को खेती के लिए पूँजी उधार देगा उसका इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि फसल के नष्ट हो जाने पर ऋण की अदायगी के समय का वह बड़ा दे। यही नहीं किसान छद्म भाषा में ऋण लेता है और उसकी फसल को छोड़ कर अथवा कुछ दशाश्री में (जब कि किसान का भूमि पर स्वाभिर होता है) भूमि के अतिरिक्त उसके पास ऋण की जमानत (Security) के रूप में देने के लिए कुछ नहीं होता है। अधिकांश किसान इतने निधन होते हैं कि वे ऋण के लिए प्रायः कोई जमानत नहीं दे सकते। फिर उनकी पूँजी का आवश्यकता इतनी कम होता है कि कोई बड़ा बैंक उस कारबार को करने पसंद नहीं करेगा। किसानों से साख सम्बन्ध निम्नका न हो उस संस्था को किसानों का साख (Credit) देना कठिन हो जाता है।

इस प्रकार उद्योग धंधों में दो प्रकार की साख चाहिए एक लम्बे समय के लिए और एक थोड़े समय के लिए। एक कारखाने का स्थापित करने के लिए यंत्र, इमारत तथा अन्य आवश्यक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और इन साधनों को उपलब्ध करने में जो पूँजी (Capital) आवश्यक होती है वह थोड़े समय में धंधे से वसूल नहीं की जा सकती। कई वर्षों में तो कारखाना बन कर खड़ा होता है। फिर यंत्रों और इमारत इत्यादि में जो पचास लाख रुपये व्यय होते हैं यह दो-चार वर्षों में तो वसूल हो नहीं सकते। अतएव इन सामग्रियों को उपलब्ध करने के लिए लम्बे समय के लिए पूँजी चाहिए। किन्तु दसक साथ ही मजदूरों की मजदूरी देना और बच्चे माल का खरीदने के लिए थोड़े समय के लिए पूँजी का आवश्यकता होती है।

धन्धों को केवल लम्बे समय और थोड़े समय के लिए ही पूँजी नहीं चाहिए वग्न धन्धों को साख (Credit) देने का कार्य एक विशेष प्रकार का है और व्यापारिक साख (Commercial Credit) से सर्वथा भिन्न है जो सदैव केवल थोड़े समय के लिए दी जाती है। उद्योग-धन्धों की साख उनकी मशीनों, इमारतों तथा कच्चे माल और तैयार माल की जमानत पर दी जाती है और व्यापारिक साख माल की जमानत पर दी जाती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि खेती, चन्ने और व्यापार के लिए जो साख (Credit) आवश्यक है उसकी अवधि और रूप भिन्न है और एक ही बैंक सब प्रकार की साख का प्रबंध कर सके यह सम्भन नहीं है। इसलिए सभी प्रकार की साख का प्रबंध करने के लिए विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता होती है और एक प्रकार के बैंक बचल एक प्रकार की ही साख देते हैं। उदाहरण के लिए खेती के लिए थोड़े समय के लिए साख का प्रबंध सहकारी साख समितियाँ तथा सहकारी बैंक (Co-operative Credit-Societies and Co-operative Banks) करते हैं। लम्बे समय के लिए खेती को साख देने का प्रबंध भूमि बंधन बैंक (Land Mortgage Banks) करते हैं। उद्योग-धन्धों को औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) पूँजी देते हैं तथा व्यापारियों को व्यापार के लिए थोड़े समय के लिए व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) साख देते हैं। संक्षेप में प्रत्येक प्रकार की साख देने का कार्य एक विशेष प्रकार का बैंक करता है। अब हम यहाँ प्रत्येक प्रकार के बैंक के संबंध में कुछ लिखेंगे।

(१) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) :—वस्तु के उत्पादन के उपरान्त और उसके उपभोक्ता (Consumer) के हाथ में पहुँचने तक जो समय लगता है उस समय के लिये साख देने का कार्य व्यापारिक बैंक करते हैं। यह तो मानी हुई बात है कि उत्पादन के उपरान्त उपभोक्ता (Consumer) के पास पहुँचने तक अधिक समय नहीं लगता। इस कारण व्यापारिक बैंकों को थोड़े समय के लिये अधिकतर कुछ महीने के लिये ही साख देनी पड़ती है। उत्पादन के उपरान्त माल थोक व्यापारियों (Wholesale dealers) के हाथ में पहुँचता है फिर वह चाहे कामखानों में तैयार हुआ माल हो या खेतों की पैदावार हो या खानों से निकला हुआ खनिज पदार्थ हो। थोक व्यापारी उस माल को लम्बे समय के लिये अपने पास रखने के लिये नहीं लेता, वह जो शीघ्र ही अनुकूल अवसर देखकर थोड़े लाभ से उसको फुटकर निम्नेताओं (Retailers) को बेच देता है अस्तु उसको

कुछ महानों (३ महीने) के लिए ही साख की आवश्यकता होती है जिसे वह हँडा या बिल को स्वीकार करके प्राप्त करता है और उन बिलों या हँडियों को भुना कर बैंक व्यापारियों का पूँजी देते हैं। विदेशों से माल मँगवाने वाले व्यापारियों का भी थोड़े दिनों के लिये ही साख की आवश्यकता होती है। अरब व्यापारिक बैंक थोड़े समय के लिये ही साख देने का कार्य करते हैं, हाँ कुछ बैंक विशेषकर विदेशी व्यापार (Foreign Trade) का ही कारबार करते हैं। उन्हें भारतवर्ष में (Foreign Exchange Banks) कहते हैं और कुछ केवल देश के आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) तक ही अपने कारबार को सीमित रखते हैं, वे व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। किन्तु अब अधिकतर बड़े व्यापारिक बैंक विदेशी तथा देशी व्यापार के कारबार को करते हैं।

औद्योगिक बैंक : (Industrial Banks) जहाँ तक उद्योग-धन्धों को थोड़े समय के लिए साख की आवश्यकता होती है (मजदूरी देने तथा बच्चा माल इत्यादि खरीदने के लिये) वह तो व्यापारिक बैंक आसानी से दे सकते हैं और देते हैं, उनके लिये विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु धन्धों के लिये जो लम्बे समय के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है उसके लिये विशेष प्रकार के बैंकों अर्थात् औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता होती है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि जहाँ व्यापारिक बैंकों का सभा देशों में आश्चर्यजनक उत्पत्ति हुई है वहाँ औद्योगिक बैंकों की सब जगह एक सी उत्पत्ति नहीं हुई। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में औद्योगिक बैंक प्रायः नहीं हैं वहाँ धन्धों का अधिक समय के लिए पूँजी हिस्से को बेच कर इरॉ, हाउस तथा फाइनेन्स कंपनियों के द्वारा इकट्ठी की जाती है। जापान में औद्योगिक बैंक यह कार्य करते हैं। जर्मनी, आस्ट्रिया, स्वीटजरलैंड तथा इटली में एक प्रकार के मिश्रित बैंक (Mixed Banks) होते हैं जो व्यापारिक बैंकों तथा औद्योगिक बैंकों का काम करते हैं। भारत में अभी तक औद्योगिक बैंक नहीं थे किन्तु अब भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल फारमैन्स फारपेरेशन की स्थापना की है जो लम्बे समय के लिये धन्धों को पूँजी देने का प्रबन्ध करेगी। ब्रिटेन में भी इस प्रकार की एक संस्था स्थापित की जा चुकी है।

सहकारी बैंक तथा भूमि बन्धक बैंक (Co-operative and Land Banks) जो कार्य धन्धों के लिए व्यापारिक बैंक और

औद्योगिक बैंक करते हैं वही कार्य खेती के लिए क्रमशः सहकारी बैंक और भूमि बन्धक बैंक करते हैं। कुछ देशों में जहाँ खेती बहुत बड़े-बड़े फार्मों पर होती है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा इत्यादि वहाँ खेती के लिये थोड़े समय के लिये पूँजी व्यापारिक बैंक ही देते हैं। किन्तु अधिकांश दूसरे देशों में खेती के लिये थोड़े समय के लिये साख देने का प्रबन्ध एक विशेष प्रकार की संस्था जिसे हम सहकारी बैंक (Co-operative Bank) कहते हैं करती है और लम्बे समय के लिए साख का प्रबन्ध भूमि बन्धक बैंक करते हैं। उदाहरण के लिए भूमि मोल लेने के लिए, भूमि का ढुधार करने के लिये, मूल्यवान खेती के यन्त्र खरीदने के लिए या पुराना ऋण चुकाने के लिए।

सेविंग्स बैंक :—व्यापारिक बैंकों से भिन्न होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य साधारण आय वाले व्यक्तियों में मितव्ययिता का भाव जागृत करने और उनकी डिपॉजिट (जमा) को आकर्षित करना होता है। यही कारण है इनमें जमा किया हुआ रुपया जब चाहे सभी नहीं निकाला जा सकता है वरन् सप्ताह में एक या दो बार ही निकाला जा सकता है। जब कि व्यापारिक बैंकों के चालू-खाते (Current Account) में जमा करने वाला जब चाहे अपना रुपया निकाल सकता है। लगभग सभी देशों में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक होते हैं। किन्हीं-किन्हीं देशों में उदाहरण के लिये संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा में स्वतन्त्र सेविंग्स बैंक भी हैं। परन्तु आजकल सेविंग्स बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का यह भेद प्रायः लुप्त होता जा रहा है क्योंकि सभी देशों में व्यापारिक बैंक भी सेविंग्स बैंक का काम करने लगे हैं।

राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (Central Bank) :—आज लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (Central Bank) स्थापित हो चुके हैं। इन राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों का रूप संगठन तथा कार्यपद्धति में थोड़ा-थोड़ा भेद सभी देशों में पाया जाता है किन्तु उनका उद्देश्य और मुख्य कार्य सब देशों में एक समान हैं। राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है देश में सब प्रकार की साख (Credit) और द्रव्य (Money) का नियन्त्रण करना जिससे देश के आर्थिक हितों की रक्षा हो और देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक रहे। यही कारण है कि सब बैंकों को राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (Central Bank) में अपना सुरक्षित-कोष (Reserve) रखना पड़ता है और केन्द्रीय बैंक का संचालन

अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करके लाभ कमाने के लिये नहीं होता वरन् अन्य बैंकों का वे कदम कर उनका नेतृत्व करने के लिये किया जाता है। राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक राज्य को द्रव्य सम्बन्धी नीति (State Monetary Policy) को कार्य रूप में परिणत करता है। राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की तरह अपने हिस्सेदारों के लिये अधिकतम लाभ कमाने का प्रयत्न नहीं करता वरन् उसका मुख्य लक्ष्य देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक बनाये रखना होता है। वह देश की अर्थ नीति को बहुत दूर तक चलाता है और उसका निर्माण करता है।

भारत में मिश्र मिश्र प्रकार के बैंक :—भारत में ऊपर लिखे सभी प्रकार के बैंक पाये जाते हैं। सब से ऊपर सर्वोपरि बैंक रिज़र्व बैंक आया हुआ है जो भारत का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) है। रिज़र्व बैंक की स्थापना १९३५ में हुई उससे पूर्व यहाँ कोई केन्द्रीय बैंक नहीं था। इम्पीरियल बैंक जिसकी स्थापना १९२० में एक विशेष एक्ट के अनुसार हुई मूलतः एक व्यापारिक बैंक था किन्तु यह १९३५ तक केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के कतिपय कार्य करता था। आज व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में इम्पीरियल बैंक के अतिरिक्त बहुसंख्यक मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंक (Joint Stock Commercial Banks) हैं। भारतवर्ष के द्रव्य बाज़ार में (Money Market) एक विशेष प्रकार के व्यापारिक बैंक भी हैं जिन्हें हम ऐक्सचेंज बैंक (विनिमय बैंक) कहते हैं जो मुख्यतः विदेशी व्यापार का कारबार करते हैं। वे सभी विदेशी बैंक हैं। पिछले दिनों में यह ऐक्सचेंज बैंक (विनिमय बैंक) देशीय व्यापार में भी हिस्सा लेने लगे हैं किन्तु उनका मुख्य कार्य विदेशी व्यापार ही है। इससे विपरीत भारतीय व्यापारिक बैंक जो पहले केवल देश के आन्तरिक व्यापार तक ही अपना कारबार सीमित रखते थे अब विदेशी व्यापार में भी भाग लेने लगे हैं। अभी तक भारत में धन्धों को लम्बे समय के लिये पूँजी देने के लिये कोई औद्योगिक बैंक नहीं था किन्तु अब भारत सरकार एक इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना करने जा रहा है। अभी तक यहाँ धन्धों को लम्बे समय के लिए पूँजी देनेवाला एजेंट तथा पूँजीपति ही देते हैं। खेती के लिये साहूकार और महाजन तथा सहकारी साख्त समितियाँ, सहकारी बैंक (Co-operative Banks) तथा ग्रामीण बचक बैंक हैं जो दमस्त छोटे समय तथा लम्बे समय लिये पूँजी का प्रयत्न करते हैं।

इनके अतिरिक्त व्यापार के लिये थोड़े समय के लिये पूँजी का प्रवन्ध करने का कार्य सराफ, मुलतानी, चेटी, साहूकार तथा महाजन भी करते हैं। ये लोग भारतीय प्राचीन पद्धति के अनुसार थोड़े समय के लिये साख्त (Credit) का प्रवन्ध करते हैं। भारतवर्ष की छोटी-छोटी मंडियों, व्यापारिक केन्द्रों में सब स्थानों पर इन देशी बैंकरो (Indigenous Bankers) का कारवार चलता है। यह आधुनिक बैंकों के समान संगठित मिश्रित पूँजा वाले बैंक नहीं होते वरन् वे व्यक्ति या फर्म होती हैं जो व्यापारिक बैंक का कार्य करते हैं। भारत के द्रव्य बाजार (Money Market) में इन देशी बैंकरो का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

बैंक के कार्य (Functions of a Bank)

बैंक के कार्यों की व्याख्या करने का अर्थ यह है कि उसकी परिभाषा की जावे किन्तु बैंक की परिभाषा करना सरल नहीं है क्योंकि समय-समय पर तथा भिन्न भिन्न देशों में बैंक जो कार्य करते रहे हैं उनमें बहुत भिन्नता रही है और आज भी वह भिन्नता विद्यमान है। अस्तु हम बैंक की परिभाषा की विस्तृत प्रालोचना करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हमारे लिए इतना ज्ञान लेना ही पर्याप्त है कि बैंक (व्यापारिक बैंक) यह सस्था है जो जनता से जमा (Deposit) इस शर्त पर स्वीकार करता है कि जमा करने वाला जब चाहे चेक द्वारा रुपये को निकाल सके।

बैंकों के मुख्य कार्य : बैंकों का मुख्य कार्य जनता की जमा को स्वीकार करना है जो जमा करने वाले की इच्छा पर चेक द्वारा निकालो जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैंकों का मुख्य कार्य चालू खाता (Current Account) रखना है। किन्तु चालू खाते के अतिरिक्त बैंक मुदती जमा (Fixed Deposit) भी स्वीकार करते हैं। मुदती जमा करने वाले उस रुपये को सभी निकाल सकते हैं जब एक निश्चित समय के नोटिस (सूचना) की अवधि समाप्त हो जावे। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए मुदती जमा (Fixed Deposit) की है तो एक वर्ष के नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर ही वह उस रुपये को निकाल सकता है। किसी-किसी देश में एक महीने, दो महीने, तीन महीने तक के लिए मुदती जमा स्वीकार की जाता है किन्तु भारतवर्ष में बैंक ६ महीने से कम मुदती जमा स्वीकार नहीं करते। इंग्लैंड तथा अन्य देशों में मुदती जमा की अवधि समाप्त होते ही जमा करने वाले को अपना निकाल लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारतवर्ष में जब मुदती जमा की जाती है सभी जमा करने वाला निकालने का नोटिस दे देता है अस्तु व्यवहार में जमा करने वाले को मुदती जमा की अवधि समाप्त होते ही अपना निकालने का अधिकार मिल जाता है। मुदती जमा के अतिरिक्त बैंक सेविंग्स खाता (Savings Account) भी खोलते हैं और मध्यम भेरी के व्यक्तियों की बचत को

जमा करते हैं। सेविंग्स खाते में अधिक से अधिक कितना जमा किया जा सकता है यह निश्चित कर दिया जाता है और सप्ताह में एक या दो बार से अधिक नहीं निकाला जा सकता। कोई-कोई बैंक यह भी निश्चित कर देते हैं कि एक बार में एक निश्चित रकम से अधिक नहीं निकाली जा सकती। अथवा बैंक चेक द्वारा सेविंग्स खाते में से भी रकमा निकालने की सुविधा प्रदान करने लगे हैं। इन खातों के अतिरिक्त बैंक कैश सर्टिफिकेट (Cash Certificate) भी बेचते हैं जो कि १ या ५ वर्षों के लिये होते हैं।

जनता की जमा आकर्षित करने के अतिरिक्त बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य विश्वसनीय व्यक्तियों को उनके कारबार के लिये ऋण देना है। बैंक दो तरह से ऋण देता है। एक ढंग तो यह है कि बैंक एक निश्चित रकम ऋण स्वरूप दे दे अथवा चालू खाते (Current Account) पर एक निश्चित रकम तक अधिविक्रय (Overdraft) देकर ऋण दे। दूसरा ढंग यह है कि बैंक अपने ग्राहकों के बिल, हुंडी, अथवा प्रानोट भुना कर ऋण दे। बिल, हुंडी या प्रामिसरी नोट को भुनाकर बैंक अपने ग्राहक से उस बिल अथवा हुंडी की रकम को प्राप्त करने का अधिकार खरीद लेता है और जब यह बिल या हुंडी पक जाती है तो बैंक उस बिल या हुंडी का रकम उस व्यक्ति से वसूल कर लेता है जिस पर बिल या हुंडी की गई थी। बैंक बिल या हुंडी को भुनाते समय ग्राहक को उस समय के लिये सूद काट कर शेष रकम अर्थात् तत्कालीन मूल्य (Present Worth) दे देता है।

पहले बैंकों का एक दूसरा भी मुख्य कार्य होता था अर्थात् कागज़ी नोट निकालना। व्यापारिक बैंकों के लिये कागज़ी नोट निकालना बड़ा लाभदायक कारबार था किन्तु अब लगभग सभी देशों में कागज़ी नोट निकालने का एकाधिकार राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों (Central Bank) को दे दिया गया है और व्यापारिक बैंकों से यह अधिकार छीन लिया गया है। भारतवर्ष में यह अधिकार रिजर्व बैंक को है और रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व सरकार कागज़ी नोट निकालती थी।

अस्तु व्यापारिक बैंकों के तीन मुख्य कार्य थे, अर्थात् जमा (Deposit) स्वीकार करना, ऋण देना और हुंडी और बिलों को भुनाना तथा कागज़ी नोट निकालना। किन्तु अब वे कागज़ी नोट निकालने का कार्य नहीं करते इस प्रकार अब उनके केवल दो कार्य ही रह जाते हैं, अर्थात्

वटपाइज स्वीकार करना तथा अर्थ देना अथवा बिल और टुंडियों का मुनाना (Discounting) ।

बैंकों के अन्य पूरक कार्य — यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक नद स्थान या सस्था है जो पूँजी बनाने वाला तथा पूँजी उधार देने वाला का मिलाता है। परन्तु इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त बैंक ऐसे बहुत से अन्य कार्य भी करता है जो बहुत महत्व के होते हैं और समाज तथा बैंक के ग्राहकों के लिये विशेष लाभ के होते हैं। आरम्भ में बैंकों ने यह कार्य अपने ग्राहकों की सुविधा के लिये करना आरम्भ किया था किंतु बाद की बैंकों के लिये भी वे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए और इस कारण वे बैंकों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए। यह पूरक कार्य दो भेदों में बाँटे जा सकते हैं। (१) एजेंसी सेवाएँ (२) साधारण उपयोगिता की सेवाएँ।

एजेंसी सेवाएँ (Agency Services) — (१) बैंकों, बिलों, टुंडियों तथा प्रामिसरी नोटों का कृपया अपने ग्राहकों के लिये वसूल करना तथा अपने ग्राहकों द्वारा लिखे या काटे गए बैंकों, बिलों, टुंडियों या प्रामिसरी नोटों का मुनाना करना।

(२) ग्राहक की स्थायी आवासीय का पालन करना। कोई भी ग्राहक अपने बैंक की यह आशा दे सकता है कि बैंक उसके हितों में से किसी सस्था अथवा व्यक्ति को नियमित रूप से एक निश्चित रकम का भुगतान करता रहे। बहुधा ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्ति अपने बैंक को सूचित कर देते हैं कि वह उसके हितों में से रा बीमा कम्पनी का प्रीमियम, बच्चों का खर्चा तथा अन्य ऐसे खर्चों का जो नियमित रूप से ग्राहक को चुकाने पड़ते हैं चुकावा रहे। बैंक इस प्रकार की सेवाओं के लिये थोड़ा सा कमीशन लेता है।

(३) बैंक अपने ग्राहकों से हिस्सी का लाभ (Dividend) तथा सिक्यूरिटी शिअरों पर सूद का वसूल करता है और ग्राहक के हितों में जमा कर देता है। ग्राहक यह माँ कर सकता है कि वह कम्पनियों तथा सिक्यूरिटी निकालने वाला सस्था को सूचित कर दे कि वह उसके हिस्स का डिवाइडेंड (लाभ) या सूद उसके बैंक का दे दे। ऐसा दशा में ग्राहक को उन डिवाइडेंड वारंट (Dividend Warrants) पर बेचान करना और बैंक का उन्हें देने का भरोसा भी नहीं करना पड़ेगा। बैंक ग्राहक का डिवाइडेंड तथा सूद वसूल करने के लिये बहुत थोड़ा सा कमीशन लेते हैं।

(४) कम्पनियों के शेयर (हिस्से) या स्टॉक और सिन्डूरिटियाँ ग्राहकों के लिये खरीदना । अधिकांश बैंक ग्राहकों को यह राय नहीं देते कि उन्हें अपना रुपया कहाँ लगाना चाहिये किन्तु वे भिन्न-भिन्न कम्पनियों के सम्बन्ध में सभी जानने योग्य बातें अपने ग्राहकों को बतलाते हैं और उनके सम्बन्ध में अपने ग्राहकों को पूरी जानकारी देते हैं । परन्तु प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कम्पनियों के हिस्से तथा सिन्डूरिटि खरीदता है । इस कार्य के लिये बैंक अपने ग्राहक से कुछ भी नहीं लेता वह शेयर ब्रोकर से उसके कमीशन में से अपना हिस्सा लेता है ।

(५) बैंक रुपये को एक बैंक से दूसरे बैंक अथवा अपनी एक शांघ से दूसरी शांघ को भेजता है । उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति आगरे से कुछ रुपया कलकत्ता भेजना चाहता है तो वह आगरे के किसी बैंक में रुपया जमा करके उस बैंक से एक बैंक ड्राफ्ट कलकत्ता में उसकी शांघ पर अथवा अन्य किसी बैंक पर ले लेगा और उस बैंक ड्राफ्ट को वह कलकत्ते में उस व्यक्ति के पास भेज देगा जिसे वह रुपया भेजना चाहता है । कलकत्ते वाला व्यक्ति उस बैंक ड्राफ्ट को बैंक में देकर रुपया वसूल कर लेगा । ग्राहक अपने बैंक से विशेष प्रयत्न करके यह सुविधा प्राप्त कर सकता है कि वह बैंक की एक शांघ पर तो चेक काटे और दूसरी शांघ उसका शुगतान कर दे ।

(६) बैंक अपने ग्राहकों का ट्रस्टी या ऐक्जीक्यूटर (Trustee or executor) भी बनता है । यदि कोई ग्राहक वसीयत करता है और चाहता है कि बैंक उस वसीयत की व्यवस्था करे या वह अन्य किसी आर्थिक समझौते का प्रबंध बैंक को सौंपता है तो बैंक अपनी फीस लेकर उस महत्वपूर्ण और सम्पन्न के काम को अपने ऊपर लेते हैं ।

(७) बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट, प्रतिनिधि और सलाहकार का काम करते हैं, यही नहीं वे देशी अथवा विदेशी बैंकों और अन्य व्यापारी संस्थाओं के एजेंट, प्रतिनिधि और आर्थिक सलाहकार का भी काम करते हैं ।

साधारण उपयोगिता की सेवायें (General Utility Services) :—आधुनिक बैंक अन्य बहुत सी उपयोगी सेवायें करते हैं जो आज के व्यस्त कारवारियों और सर्वसाधारण के लिये बहुत सुविधाजनक और लाभदायक सिद्ध होती हैं । उनमें से नीचे लिखी सेवायें महत्वपूर्ण हैं :—

(१) बैंक व्यक्तिगत तथा व्यापारिक साख प्रत्र (Letters of Credit) देते हैं । बैंक के ग्राहकों को इन साख

पत्रों (Letters of Credit) से यह लाभ होता है कि वे बैंक की ऊंची साख्त से लाभ उठा सकते हैं। माल पत्र (Letters of Credit) एक प्रकार का पत्र होता है जो एक बैंक अपनी साख्त अथवा अन्य दूसरे बैंक को लिख देता है, जिसमें बताये हुए व्यक्ति को हरया उधार देने या साख्त देने की प्रार्थना होती है। इस प्रकार यदि कोई ग्राहक अन्य स्थान पर जाकर कुछ कारबार करना चाहे तो वह अपने बैंक से उस स्थान पर स्थित उस बैंक की शाखा अथवा अन्य किसी दूसरे बैंक के नाम साख्त पत्र (Letter of Credit) ले जा सकता है। वहाँ उस व्यक्ति को साख्त पत्र (Letter of Credit) दिखाने पर सुरन्त रुपया मिल सकता है अथवा उस बैंक की शाखा या अन्य बैंक उस व्यक्ति पर उसके लेनदारों (Creditors) द्वारा लिखे गए बिलों को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने बैंक से साख्त पत्र की सहायता से अन्य स्थान पर भी साख्त (Credit) पा सकता है।

(२) आधुनिक बैंक विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का कारबार भी करते हैं। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदता है तो उसके दूसरे देश के द्रव्य में मूल्य चुकाना पड़ता है। बैंक एक देश के द्रव्य (money) को दूसरे देश के द्रव्य में बदलने का काम करते हैं। यदि भारतवर्ष का व्यापारी लक्काशायर से सूती कपड़ा अथवा संयुक्तराज्य अमेरिका से मशीनें मँगाता है तो अपने बैंक को जो भी विनिमय दर (Foreign Exchange Rate) हो उस हिसाब से रुपये दे देगा और बैंक उसको स्टर्लिंग और डालर दे देगा। बैंकों के विदेशी विनिमय के कारबार से ही यह सम्भव होता है कि एक देश के व्यापारी अन्य देशों से व्यापार कर सकते हैं अथवा विदेशी व्यापार असम्भव हो जावे। प्रश्न यह हो सकता है कि बैंक डालर या स्टर्लिंग कहाँ से लावेगा। वास्तव में होता यह है कि प्रत्येक देश अन्य देशों को कुछ माल भेजता है अर्थात् निर्यात (Export) करता है और कुछ माल उन देशों से मँगाता है। कल्पना कीजिए कि भारत के एक व्यापारी ने कुछ कपास लक्काशायर को भेजी है ता भारतीय व्यापारी अपनी कपास के मूल्य का विदेशी बिल (Foreign Bill) लक्काशायर के व्यापारी पर स्टर्लिंग में काटेगा और उसे लेकर अपने बैंक में पाग जावेगा। बैंक उस बिल को भुना देगा अर्थात् उसका तात्कालिक मूल्य (Present worth) देकर उस बिल को (स्टर्लिंग) खरीद लेगा। अब यदि कोई व्यापारी इंग्लैंड से माल मँगाया है और उसका मूल्य चुकाना चाहता

है तो वह बैंक के पास जावेगा और बैंक उसी बिल (स्टॉलिंग) को वेंच देगा। इसी प्रकार विदेशी बिलों को भुनाकर यह बैंक विदेशी व्यापार के लिये सुविधा प्रदान करते हैं। विदेशी बिलों को भुना कर विदेशी व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करने में बैंकों को बहुत माल का समुद्री बीमा कराना पड़ता है, उसको जहाज द्वारा भेजने का प्रबंध करना पड़ता है, और उसको कुछ समय तक अपने गोदामों में रखना पड़ता है। अतएव बैंक इस कार्य के लिये एक बांसा विभाग और एक भाड़ा विभाग (Freight Department) भी रखते हैं। अन्य देशों में विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) कार्य व्यापारिक बैंक ही करते हैं किन्तु भारत में यह कार्य एक विशेष प्रकार के व्यापारिक बैंक करते हैं जिन्हें-विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Bank) कहते हैं।

(३) ये बैंक अपने ग्राहकों के बदले उन पर लिखे गए बिलों को स्वीकार करते हैं या कर सकते हैं। इस प्रकार बैंक अपने नाम और ऊँची साख को थोड़ा सा कमीशन लेकर अपने ग्राहकों के लाभ के लिए दे देते हैं। उदाहरण के लिए यदि बैंक का कोई ग्राहक किसी व्यापारी से साख (Credit) पर माल खरीदना चाहता है, व्यापारी उसे साख देने को तैयार भी है किन्तु वह माल खरीदने वाले को और उसकी साख (Credit) के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता ऐसी दशा में माल खरीदने वाला अपने बैंक से उस पर लिखे गए बिल को स्वीकार कर लेने के लिए कहता है। बैंक अपने ग्राहक की साख के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखता है, अस्तु वह माल वेंचने वाले व्यापारी के बिल या हुंडी को अपने ग्राहक के स्थान पर स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार माल खरीदने वाले बैंक के ग्राहक को साख (Credit) मिल जाती है।

(४) बैंक बहुमूल्य वस्तुओं, सिक्कुरिटी और अन्य आवश्यक कागज़ पत्रों को थोड़ा सा कमीशन लेकर सुरक्षित रखने का भार ले लेते हैं। उदाहरण के लिए सर्व साधारण सोना, चांदी, बहुमूल्य आभूषण, महत्वपूर्ण कागज़-पत्र, तथा सिक्कुरिटी बैंक के हवाले कर देते हैं और इस प्रकार उनके चोरी जाने आर अग्नि से नष्ट हो जाने का भय जाता रहता है। इन वस्तुओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए बैंक विशेष प्रकार के कमरे और तिजोरियाँ बनवाते हैं, जिससे उनके चोरी जाने और अग्नि इत्यादि से नष्ट हो जाने का भय नहीं रहता। इस प्रकार थोड़ा सा कमीशन लेकर बैंक इन बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित अमानत के रूप में रखने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं।

(५) बैंक अपने ग्राहकों की ईमानदारी और उनका साल और आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में दूसरों को ठीक-ठीक जानकारी कराते हैं। यह कार्य व्यापारों के समान के लिए बहुत महत्त्व का और आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार बैंकों के द्वारा व्यापारियों का सहज में ही अन्य व्यापारियों को साल तथा आर्थिक स्थिति के बारे में ठीक-ठीक जानकारी हो जाती है और उनसे कारव्दार करने में तथा उन्हें सत्य देने में हानि की सम्भावना नहीं रहती। उदाहरण के लिए यदि किसी कपड़े के बड़े व्यापारी के पास अन्य स्थान का व्यापारी आर्डर देता है और तब महाने की सत्य पर भूल खरीदना चाहता है तो यदि बैंकने वाला व्यापारी खरीदने वाले व्यापारी का नहीं जानता अथवा वह नहीं जानता कि उसको साल देना उचित होगा अथवा नहीं, तो वह खरीदने वाला व्यापारी से बैंक रिफरेंस माँगेगा। खरीदने वाला व्यापारी अपने बैंक का नाम लिख भेजेगा और बैंकने वाला व्यापारी गुप्त रूप से उससे बैंक से पूछेगा कि उस व्यापारी को साल (Credit) पर भूल देना उचित है अथवा नहीं। बैंक उस व्यापारी को साल और ईमानदारी तथा आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी छमाँत मिल भेजेगा। बैंक यह सूचना गोपनीय रखते हैं और व्यापारियों के सम्बन्ध में सारा ठीक-ठीक जानकारी रखते हैं।

(६) बड़े-बड़े बैंक व्यापार सम्बन्धी जानकारी तथा व्यापार सम्बन्धी आकड़ों की इकट्ठा करके व्यापारियों को देते हैं। व्यापारिक दृष्टि से उन्नतिशील राज्यों में बड़े-बड़े बैंक एक पृथक् सूचना विभाग तथा व्यापारिक आकड़ों का विभाग रखते हैं। यह बैंक अपनी शाखों का तहायता से देश-विदेश की व्यापार सम्बन्धी सूचनाएँ तथा आकड़े इकट्ठा करते हैं और उसे अपने ग्राहकों को उनके लाभ के लिए देते हैं। कोई-कोई व्यापार सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री को अपने ग्राहकों के पास पहुँचाने के लिए मासिक पत्र निकालते हैं जो व्यापारियों के लिए बड़े काम की वस्तु होता है।

ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिक बैंक व्यापारिक जनता तथा व्यापार और धर्मों की बहुमूल्य सेवा करते हैं। सच तो यह है कि बिना अन्धे बैंकों के किसी देश का भी व्यापार तथा उद्योग धंध उन्नति नहीं कर सकते। बैंकों की सब से महत्वपूर्ण सेवा तो यह है कि वह देश भर में बिखरा हुआ व्यक्तियों का थोड़ा थोड़ा बचत का इकट्ठा करके उत्पादन कार्य (Productive Work) के लिए दे देते हैं। इससे धंधे और व्यापार की

उत्पत्ति होती है। व्यापारी जिस सरलता से बैंकों से ऋण पा जाते हैं उससे उद्योग-धंधों तथा व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यही नहीं व्यापारियों को बैंक का मूल्यवान परामर्श और उनकी जानकारी का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। बैंक इस बात का निर्णय करते हैं कि किन व्यक्तियों को पूँजी या साख दी जावे। इस प्रकार से परोक्ष रूप से बैंक राष्ट्र की पूँजी को उस दिशा में बहने देने में सहायक होते हैं जिस दिशा में राष्ट्र की पूँजी को जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुदृढ़ बैंकों को स्थापना से जनता में बचत करने, अल्पधिक व्यय न करने और मितव्ययिता की भावना जागृत होती है क्योंकि बचाने वालों को अपनी बचत को सुरक्षित तथा लाभदायक रूप से बैंकों में रखने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इस सुरक्षा को पाकर वे बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

श्री गिल्बर्ट महोदय के शब्दों में "बैंक व्यापारिक शुणों के सार्वजनिक शक्त हैं, वे परिश्रमी, बुद्धिमान, नियत समय पर ऋण चुकाने वाले तथा ईमानदार व्यापारियों को प्रोत्साहन देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो जुआरी, अपव्ययी, झूठे और बेईमान होते हैं कभी आर्थिक सहायता नहीं देते। ऐसे व्यापारियों को बैंक अपने से दूर ही रखते हैं। आज के व्यापारिक जगत् में बैंक की सहायता के बिना किसी भी व्यापारी का काम नहीं चल सकता। अस्तु कोई भी व्यापारी बैंक को असंतुष्ट करने से डरता है। बैंकों के कारण व्यापारियों को ईमानदार होना पड़ता है। सब तो यह है कि आज किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि बहुत कुछ बैंक पर निर्भर है। यदि किसी देश में अच्छे सुदृढ़ बैंकों की योग्य संख्या में स्थापना नहीं हुई है तो उस देश की आर्थिक उत्पत्ति नहीं हो सकती।

व्यापारिक बैंकों के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्त

आज इस बात पर बैंकिंग जगत् में एक वाद-विवाद चल रहा है कि व्यापारिक बैंकों का कारबार किस प्रकार का होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आज दो मत प्रचलित हैं। एक मत पुरातनवादियों का है। उनका मत है कि व्यापारिक बैंकों को केवल थोड़े समय के लिए शुद्ध व्यापारिक कार्यों के लिए ही ऋण देना चाहिए। एक दूसरा मत यह है कि व्यापारिक बैंकों को मिश्रित कारबार करना चाहिए अर्थात् थोड़े समय के लिए तथा धन्धों के लिए लम्बे समय के लिए भी ऋण देना चाहिए। अब हम इन दोनों मतों के सम्बन्ध में निस्तुत विवेचना करेंगे।

पुरातन मत :—पुरातन मत वादियों का कहना है व्यापारिक बैंक का केवल थोड़े समय के लिए ही धन देना चाहिए जो कि सरलता से स्वतः प्रयुक्त होत जावे। इस सिद्धान्त का आधार यह है कि व्यापारिक बैंकों का काम (उपाय) यह है समय के लिए होती है अस्तु व्यापारिक बैंक लम्बे समय के लिए धन दे सकते। ब्रिटिश बैंकों का यहो कहना है क्योंकि हम जमा किए हुए धन को जमा करने वालों के मांगने पर देना पड़ता है अस्तु हम उस रुपये का लम्बे समय के लिए नहीं देता सकते।

बैंक जिस प्रकार अपने रुपये को लगाते हैं उससे देश के आर्थिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बैंक अपने पास जमा किए हुए रुपये से लाभ कमाने के लिए उस रुपये को विलों, सरकारी सिक्योरिटी (प्रतिभूत) तथा अन्य स्थानों में लगाते हैं। बैंक कमी व्यापारिक बिल में अपना धन लगाते हैं तो कभी सरकारी सिक्योरिटियों में तो कभी कम्पनियों के हिस्सों में धन लगाते हैं। बैंक जिस काम में अपना धन अधिक लगाते हैं उसी आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यदि वे व्यापारिक विलों में अधिक धन लगाते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वे व्यापार को अधिक आर्थिक सुविधा देकर प्रोत्साहन देते हैं। यदि वे कम्पनियों के हिस्सों में धन लगाते हैं तो वे उद्योग धंधों को अधिक सहायता प्रदान करते हैं इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक की विनियोग नीति (Investment Policy) का आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि बैंक कितना धन (money) व्यय किया जा सकता है उसका निर्णय करते हैं और उसका निर्माण करने हैं और जनता उसका वास्तव में उपयोग किस प्रकार होगा यह निर्णय करती है। ऊपर दिया हुआ मत बिल्कुल सही नहीं है। यह ठीक है कि अन्ततः धन का किस प्रकार उपयोग होगा यह बैंक के अधिकार के बाहर की बात है। हो सकता है कि बैंक अपने रुपये को एक जगह लगावे और व्यापारी उनको वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दें। परन्तु यदि बैंक यह देखें कि उनके रुपये को अनुचित स्थान पर लगाया जा रहा है तो वे तुरन्त अपनी विनियोग नीति (धन लगाने की नीति) पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

अस्तु यह स्पष्ट है कि बैंक अपनी विनियोग नीति (Investment Policy) के द्वारा आर्थिक कारगर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वे जिस प्रकार के काम में अपना धन लगाते हैं वही कारगर अधिक चमकता

है और उसकी उन्नति होती है। अब प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार इन कागज़ों को, जिनमें वे अपना रुपया लगाना चाहते हैं, चुनते हैं। कागज़ चुनने का उनका आधार क्या है। बैंक यह निर्धारित करने में कि उनको अपना रुपया कहाँ लगाना चाहिए दो बातों को ध्यान में रखते हैं (१) तरलता (Liquidity) और लाभदायकता (Profitability) बैंक के लिए तरलता को अपनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जमा करने वाले जब चाहें अपना रुपया माँग सकते हैं। अस्तु उनको उनका जमा किया हुआ हरया वापस दे सकने तथा जनता का अपने में विश्वास पैदा करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे तरलता (Liquidity) को न छोड़ें। किन्तु यदि वे जमा किए हुए सब रुपये को बिलकुल तरल (Liquid) अवस्था अर्थात् नकदी रोकड़ के रूप में अपने पास रखें तो फिर वे उससे लाभ बिलकुल नहीं कमा सकते। यदि बैंक ग्राहकों द्वारा जमा किये हुए सारे के सारे रुपये को तरल अर्थात् नकदी रोकड़ के रूप में अपने पास ही रखे तो फिर वह हाया जमा करने वालों को मूँद कहाँ से देगा। इसके विपरीत यदि बैंक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहे तो उसे उस रुपये को बहुत लम्बे समय के लिए लगाना पड़ेगा जो बैंक के लिए खतरनाक हो सकता है। पहली बात तो यह है कि बैंक को कुछ नकदी तो इसलिए अपने पास रखना आवश्यक है क्योंकि जमा करने वाले समय-समय पर अपना रुपया वापस माँगेंगे और दूसरे थोड़े समय की जमा (डिपॉजिट) में आये हुए रुपये को लम्बे समय के लिए फँसा देना बहुत खतरनाक है। अतएव बैंक की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह इन दोनों विरोधी बातों का समन्वय स्थापित करे। जितना ही बढ़ यह समन्वय स्थापित कर सकेगा उतना ही वह बैंकिंग के कार्य में सफल होगा।

तरलता दो बातों पर निर्भर रहती है, एक तो इस बात पर कि लगा हुआ रुपया शीघ्रता से निकाला जा सके और दूसरे इस बात पर कि उसमें जोखिम तनिक भी न हो। यही कारण है कि यदि ये दोनों शर्तें पूरी हों तो लम्बे समय का कागज़ भी तरल लेनी (Liquid Asset) कही जावेगी। उदाहरण के लिए, सरकारी मिक्यूरिटी (प्रतिभूत) को लीजिए। बैंक जब चाहे तब उसको बाज़ार में बेचकर रुपया प्राप्त कर सकता है और उसमें जोखिम भी बहुत कम होती है। इसी प्रकार कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध कम्पनियों के हिस्से भी तरल लेनी कही जा सकती है। परन्तु साधारण कम्पनियों के हिस्से न तो बहुत आसानी से बिक ही सकते हैं और उनमें जोखिम भी

होती है कि कहीं उनके भाव बहुत अधिक गिर न जावे। इसी प्रकार जो श्रृणु बैंक ने व्यापारियों को उनकी व्यक्तिगत जमानत पर या किसी वस्तु को बंधक रखकर उसकी जमानत पर दिया वह तुरन्त नकदी रोड में परिणत नहीं किया जा सकता और उसमें जोखिम भी होता है।

अतः यह हो सकता है कि बैंक ने किसी पर्स या व्यक्ति को श्रृणु दिया। उस पर्स अथवा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और उस पर्स की लेनी (Assets) देनी (Liabilities) को चुकाने के लिए पर्याप्त है। परन्तु हो सकता है कि बैंक पर यदि कोई संकट आवे तो वह श्रृणु तुरन्त चुकाया न जा सके। परन्तु यदि किसी देश का केन्द्रीय बैंक ऐसे समय में उस बैंक को आर्थिक सहायता दे तो संकट टल सकता है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि संकट के समय किसी एक बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी है अथवा नहीं यह इतना महत्व नहीं रखती जितना कि केन्द्रीय बैंक की नीति। क्योंकि यदि किसी बैंक से लोग भयभीत हो कर अपना रुपया निकालने लगें तो अच्छे बैंक को भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है। यही कारण है कि ऐसे अवसर पर केन्द्रीय बैंक (Central Bank) बैंकों की सहायता कर सकता है क्योंकि वह अन्तिम श्रृणुदाता होता है। ऐसी दशा में जब केन्द्रीय बैंक अन्तिम श्रृणुदाता होता है और संकट के समय बैंकों को श्रृणु देकर सहायता देना उसका कर्तव्य है तब यह इस बात की भी देखभाल करता है कि बैंक उस प्रकार के कागज में अपना रुपया न फँसावे जिनको केन्द्रीय बैंक ठीक नहीं समझता। अस्तु केन्द्रीय बैंक इस प्रकार के नियम बना कर कि वह अमुक प्रकार के कागज पर ही किसी बैंक को श्रृणु देना स्वीकार करेगा बैंकों ने एक प्रकार से विवश कर देता है कि वह उसी प्रकार का श्रृणु दे जिसे केन्द्रीय बैंक पसंद करता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का विनियोग नीति को निर्धारित करता है। इस प्रकार एक ओर व्यापारिक बैंकों की देनी (Assets) तरल (Liquid) बन जाती है और दूसरा ओर केन्द्रीय बैंक द्रव्य बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है।

अस्तु पुरातन मत वालों का बैंकिंग सिद्धान्त यही है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी देनी (Assets) को जहाँ तक हा सके तरल रखना चाहिए अर्थात् थोड़े समय के ही लिए श्रृणु देना चाहिए और उन्हीं कागजों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें केन्द्रीय बैंक ठाढ़ समझता है। ब्रिटेन इस मत

का प्रधान गढ़ है। ब्रिटेन में व्यापारिक बैंक उद्योग धन्धों को चालू व्यय की व्यवस्था के लिए थोड़े समय के लिए ऋण अवश्य दे देते हैं किन्तु धन्धों में लम्बे समय के लिए अपना रुपया कभी नहीं फँसाते। भारत के व्यापारिक बैंक भी इसी नीति के अनुयायी हैं।

जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका

जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक तथा औद्योगिक बैंकिंग का मिश्रण है। वे थोड़े समय के लिए भी ऋण देते हैं और उद्योग-धन्धों को लम्बे समय के लिए भी ऋण देते हैं।

जर्मनी में आरम्भ में जो बैंक थे वे वास्तव में औद्योगिक बैंक थे। वे अधिकतर अपनी पूँजी पर ही निर्भर रहते थे। डिपॉजिट बहुत कम होती थी। परन्तु बीसवीं शताब्दी में डिपॉजिट बहुत अधिक बढ़ गई और जर्मन बैंक बहुत अधिक राशि में डिपॉजिट आकर्षित करने लगे। किन्तु वे अपने पुराने कारबार अर्थात् उद्योग-धन्धों को लम्बे समय के लिए ऋण देना नहीं बन्द कर सके, अस्तु वहाँ मिश्रित बैंकिंग पद्धति प्रचलित हुई। वहाँ के बैंक दोनों प्रकार के ऋण देते हैं, व्यापार के लिये थोड़े समय का ऋण तथा उद्योग-धन्धों के लिए लम्बे समय का ऋण।

मिश्रित बैंकिंग के गुण-दोष

मिश्रित बैंकिंग के कुछ गुण हैं। मिश्रित बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उद्योग-धन्धों को उससे प्रोत्साहन मिलता है। जर्मनी इसका उदाहरण है। जर्मनी में जो तेजी से उद्योग-धन्धों की उन्नति हुई वह इसी बात का परिणाम था कि वहाँ उद्योग-धन्धों को व्यापारिक बैंक आर्थिक सहायता देते थे। जर्मनी का उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि मिश्रित बैंकिंग को अपना कर भी बैंकों की आर्थिक स्थिति ठीक रह सकती है।

मिश्रित बैंकिंग में जो खतरा उपस्थित होता है वह साधारण समय में उपस्थित नहीं होता वरन् आर्थिक मंदी के समय उपस्थित होता है। उस समय कम्पनियों के हिस्सों का भाव तेज़ी से गिरने लगता है और बैंकों को बहुत भारी हानि उठानी पड़ती है। जब आर्थिक धूम (Boom) होता है तो धन्धे बहुत लाभदायक होते हैं और बैंक धन्धों में उनकी शक्ति के बाहर रुपया फँसा देते हैं और जब संकट आता है और आर्थिक मंदी होती है तो

बैंकों में उनका रुपया डूबने लगता है, उनके कागजों का मूल्य गिरने लगता है और बैंकों की स्थिति संकटमय हो जाती है ।

अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मिश्रित बैंकिंग आर्थिक मदी का सामना नहीं कर सकता । अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि व्यापारिक बैंकिंग और औद्योगिक बैंकिंग को वृत्त रक्खा जावे और मिलाया न जावे । भारत के बैंकों ने इसी नीति को स्वीकार किया है । 4.3.57

अध्याय ५

बैंक की लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet of a Bank)

बैंक की लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet of a Bank) बैंक की तत्कालीन आर्थिक स्थिति को प्रगट करता है। बैंक के कारवार के सम्बन्ध में इस लेखे का अध्ययन करने से पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस लेख को देखने से यह भी ज्ञात हो सकता है कि बैंक किस प्रकार अपने कोष (Funds) को इकट्ठा करता है और किस प्रकार उस कोष का उपयोग करता है।

दुर्भाग्यवश बैंकों की लेनी-देनी के लेखे (Balance Sheet) का कोई ऐसा सर्वमान्य रूप प्रचलित नहीं हुआ है जिसको सब ने अपनाया हो। इंग्लैंड में बड़े-बड़े बैंकों ने आपसी समझौते से लेनी-देनी के लेखे के एक रूप को स्वीकार कर लिया है। संयुक्तराज्य अमेरिका में बैंकिंग सम्बन्धी कानून के अनुसार बैंकों को अपने लेखे में कुछ मदों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट देनी पड़ती है, इस कारण विवश होकर एक सा लेखा बनाना पड़ता है। परन्तु भारतवर्ष में बैंकों के लेनी देनी के लेखों में विभिन्नता पाई जाती है इस कारण बैंकों की तुलनात्मक आलोचना करना कठिन हो जाता है। फिर भी बैंकों का कारवार इस प्रकार का है कि मोटे रूप से ऐसा लेनी-देनी का लेखा तैयार किया जा सकता है जो कि सब बैंकों के लिए एक समान हो, यद्यपि उसमें जो भेद होंगे वे इस प्रकार के नहीं होंगे कि उनसे विस्तृत जानकारी हो सके।

साधारणतः बैंकों का लेनी-देनी का लेखा (Balance-Sheet) इस प्रकार होगा :—

<u>देनी (Liabilities)</u>	<u>लेनी (Assets)</u>
<u>पूँजी (Capitals)</u>	
१. अधिकृत पूँजी (<u>Authorised Capital</u>)	१. नकदी, तथा अन्य बैंकों और रिज़र्व बैंक में जमा किया हुआ रुपया
२. विक्रित पूँजी (<u>Subscribed Capital</u>)	२. याचना-द्रव्य (<u>Call money</u>) तथा बहुत थोड़े समय के लिये दिया हुआ पण (<u>Money at short notice</u>)

३. परिदत्त पूँजी या चुकता पूँजी (Paid up Capital)	३. खरीदे तथा मुनाये हुए बिल (Bills discounted and purchased)
४ सुरक्षित कोष (Reserve Fund)	४. निवेश (Investments)
५. चालू खाता तथा मुदती जमा तथा अन्य खाते (Current Deposits, Fixed Deposit and other accounts)	५. ग्राहकों को दिया हुआ ऋण
६. बिलों का स्वीकार करने तथा उन पर बैचान करने से उत्पन्न होने वाला दायित्व Liabilities for Acceptance and Endorsements, etc.)	६. बिलों को स्वीकार करने तथा उन पर बैचान करने के सम्बन्ध में ग्राहकों का दायित्व (Liabilities of Customers for acceptances, endorsements, etc.)
	७. बैंक की इमारतें तथा अन्य अचल सम्पत्ति

लेनी देनी के लेखे का अध्ययन करते समय हम पहले देनी (Liabilities) का अध्ययन करेंगे क्योंकि इससे हमें यह ज्ञात होगा कि बैंक को कोष (Fund) कहाँ से प्राप्त होता है जिसे वह ऋण स्वरूप अपने ग्राहकों को देकर अपना कारबार करता है।

१. पूँजी (Capital) :—अधिकृत या निर्धारित पूँजी (Authorised Capital) उस रकम को कहते हैं जिसे बैंक का स्मारक पत्र या अधि-कार पत्र (Memorandum of Association) में निर्धारित कर दिया गया हो। जब कोई मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी (Joint Stock Company) स्थापित की जाती है तो एक स्मारक पत्र तैयार किया जाता है। उसमें उस कम्पनी के उद्देश्य आदि के अनिवार्य अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) की रकम भी दी जाती है। उससे अधिक के हिस्से नहीं भेजे जा सकते। प्रचलित पूँजी (Issued Capital) उस रकम को कहते हैं जितने मूल्य के हिस्से (Shares) जनता को बैंकने की बैंक ने घोषणा की हो। निश्चित पूँजी (Subscribed Capital) उसे कहते हैं जितने मूल्य के हिस्से जनता ने स्वीकृत किए हो। और परिदत्त या चुकता पूँजी (Paid up Capital) उस राशि को कहते हैं जितनी हिस्से खरीदने वालों अध्यात हिस्सेदारों से प्राप्त हो चुकी हो। एक उदाहरण से यह भेद भली भाँति समझा जा सकता है।

कल्पना कीजिए कि हम एक बैंक स्थापित करते हैं। जब हम बैंक की रजिस्ट्री करावेंगे तो एक स्मारक पत्र या अधिकार पत्र (Memorandum of Association) तैयार करना होगा। उसमें हम जितनी पूँजी निर्धारित कर देंगे उससे अधिक के हिस्से नहीं बँचे जा सकते। इस पूँजी को अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कहेंगे। हमारे कल्पित बैंक की अधिकृत पूँजी ४ करोड़ रुपया है जो ४ लाख साधारण हिस्सों में (प्रत्येक हिस्सा १०० रु० का है) बँटी हुई है। आरम्भ में बैंक के डायरेक्टर ४ लाख हिस्सों का न बँच कर केवल २ लाख हिस्से बेचने की घोषणा करते हैं। इस हम प्रचारित पूँजी (Issued Capital) कहेंगे। मान लीजिये कि जनता सभी हिस्सों को खरीद लेती है तो २ करोड़ रुपये की पूँजी विक्रित पूँजी (Subscribed Capital) कहलावेगी। इन २ लाख हिस्सों पर डायरेक्टर पूरा मूल्य अर्थात् १०० रु० न माँग कर केवल ५० रु० प्रति हिस्सा माँगते हैं और शेष ५० रु० आगे वसूल करने के लिए छोड़ देते हैं। जो २ लाख हिस्सों पर ५० रु० प्रति हिस्से के हिसाब से हिस्सेदार चुकावेंगे उस १ करोड़ रुपये को परिदत्त या चुकता पूँजी (Paid up Capital) कहा जावेगा। बहुत से बैंक हिस्सों का पूरा मूल्य वसूल न करके उसका आधा या एक भाग ही वसूल करते हैं। प्रति हिस्से पीछे जो शेष रहता है उसे हिस्सेदार देने के लिए उत्तर दायी रहते हैं और वह बैंक में रुपया जमा करने वालों के लिए विशेष प्रकार की सुरक्षा का काम देता है।

किन्तु इस सम्बन्ध में सब बैंकों की एक ही नीति नहीं है। भारत में बहुत से बैंकों ने अपने हिस्सों के मूल्य का केवल पचास प्रतिशत ही वसूल किया है और ५० प्रतिशत हिस्सेदारों का सुरक्षित दायित्व (Reserve Liability) है जो उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बेसा हो सकता है। परन्तु कोई भी बड़ा और पुराना बैंक उस शेष पूँजी का कभी व्यवहार में वसूल नहीं करता। यह शेष पूँजी केवल बैंक के दिवालिया होने पर ही वसूल की जाती है। अन्य देशों में भी बैंक अपने हिस्सों के पूरे मूल्य को वसूल नहीं करते और सुरक्षित पूँजी (Reserve Capital) छोड़ रखते हैं जो बैंक के दिवालिया होने की दशा में ही वसूल की जाती है।

1/ सुरक्षित कोष (Reserve Fund) :—प्रति वर्ष बैंक अपने लाभ का एक भाग सुरक्षित कोष में जमा करते हैं। प्रत्येक अच्छा बैंक अपने लाभ का एक अंश सुरक्षित कोष में अवश्य ही जमा करता है क्योंकि उससे बैंक की

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है बैंक का प्रतिष्ठा उदता है, और बैंक की निजी पूँजी में वृद्धि होती है। यह ध्यान में रखने का बात है कि मुद्रास्वत कोष (Reserve Fund) और न वसूल का हृद पूँजी या मुद्रास्वत दायित्व (Reserve Liability) में उद्भूत अन्तर है। मुद्रास्वत कोष को हिस्सेदारों नहीं देता है वरन् वह वार्षिक लाभ में से एक भाग अभ्यग निकाल कर रखने से बनता है। मुद्रास्वत कोष प्रथम भली का निष्पत्ति में लगाया जाता है। पंक्ति पूँजी (Paid up Capital) और मुद्रास्वत कोष मिलकर बैंक की कार्यशील पूँजी (Working Capital) बनता है। यदि कभी बैंक को भाग हानि हो जाय तो यह अपने मुद्रास्वत कोष में से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हम प्र. १ मुद्रास्वत कोष माहका क निर मुद्रास्वत का काम देता है। यद्यपि मुद्रास्वत कोष हिस्सेदारों का सम्पत्ति होता है और उन का उपयोग हिस्सेदारों को बोनस शेअर्स (Bonus Shares) देने तथा लाभ की दर का समान करने (Equalization of Dividend) में किया जा सकता है।

लेखा देनी व लेखे (Balance Sheet) में जो मुद्रास्वत कोष (Reserve Fund) प्रकट रूप से लिखाया जाता है उसके अतिरिक्त बहुत से एक गुप्त मुद्रास्वत कोष (Secret Reserves) का भी निर्माण करते हैं जिन्हें लेना देना व लेखे (Balance Sheet) में नहीं लिखाया जाता। गुप्त मुद्रास्वत कोष से बैंक का आर्थिक स्थिति और भी दृढ़ होता है और उसका मुद्रास्वत तथा प्रतिष्ठा उदता है। गुप्त मुद्रास्वत कोष का निर्माण सम्पत्ति या लेनी (Assets) का मूल्य कम निधारित करके किया जाता है। उदाहरण के लिए एक बैंक की इमारतों का टाक मूल्य ६५० लाख रुपये है और लेनी देना व लेखे में केवल ५० लाख रुपये ही दिखलाया जाता है तो ५ लाख रुपये का गुप्त मुद्रास्वत कोष निर्माण हो जायेगा।

उदाहरण के लिए यदि बैंक की प्रतिभूति (Security) का मूल्य ऊँचा हो गया है तो बैंक लेना देना व लेखे में प्रतिभूति (Security) को ऊँचे मूल्य पर न दिखा कर पूर्व मूल्य पर दिखा कर गुप्त मुद्रास्वत कोष निर्माण कर सकता है। इस प्रकार के गुप्त मुद्रास्वत कोष का उपयोग ऐसे समय पर किया जा सकता है जब कि बैंक का विशय हानि उठाना पड़े या आर्थिक मंदी (Economic Depression) का समय हो।

चालू खाता तथा अन्य खाते (Current Account and other Accounts) — यह रुपये बैंक में सर्व साधारण जमा करते हैं वह

इस शीर्षक में दिखलाया जाता है। यह बैंक की सबसे महत्वपूर्ण देनी (Liability) होती है। बैंक जमा रूप में पाई हुई इस धन राशि को अधिक सूद पर लगा देता है और इससे लाभ कमाता है। किन्तु इस जमा किये रुपये को लाभदायक ढंग से लगाने में बैंक को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जमा करने वालों ने जो धन राशि बैंक के पास अमानत के रूप में रखी है वह सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा को खतरा न पहुँचे।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक चालू खाते (Current Account) में रुपया लेते हैं। जमा करने वाला जब चाहे चेक काट कर इत्र खाते में से रुपया निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त मुहती जमा (Fixed Deposit) भी बैंक स्वीकार करते हैं। मुहती जमा एक निश्चित समय का नोटिस देने के उपरान्त ही निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में बैंक सेविंग्स डिपॉजिट लेते हैं और कैश सर्टिफिकेट भी बेचते हैं। सेविंग्स डिपॉजिट में से रुपया सप्ताह में एक या दो बार ही निकाला जा सकता है। कुछ बैंक सेविंग्स खाते पर भी चेक काटने की सुविधा देते हैं परन्तु कुछ बैंक यह सुविधा नहीं देते। यहाँ नहीं सेविंग्स खाते में से एक बार में अधिक से अधिक कितना रुपया निकाला जा सकता है यह भी निर्धारित कर दिया जाता है। सेविंग्स खाते में कुल अधिक से अधिक कितना रुपया जमा किया जा सकता है यह भी निश्चित होता है। कैश सर्टिफिकेट २ वर्षों के लिए या ५ वर्षों के लिये होते हैं।

Liability for acceptance & endorsement etc.

6 बिलों को स्वीकार करने तथा उन पर वेचान करने के सम्बन्ध में बैंक का दायित्व :—बैंक अपने ग्राहकों को श्रृणु देने तथा थोड़े समय के लिये साख देने के उद्देश्य से बिलों को स्वीकार करते हैं अथवा उन पर वेचान (Endorsement) करते हैं। किन्तु बैंक के बिलों पर हस्ताक्षर होने के कारण यदि बैंक का ग्राहक उस बिल के पकने पर उसका भुगतान न करे तो बैंक को उस बिल का भुगतान करना पड़ सकता है। वास्तव में इन बिलों का भुगतान बैंक के ग्राहक ही करते हैं और वे ही उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। परन्तु यदि वे समय पर बिलों का भुगतान न करें तो बैंक को उनका भुगतान करना पड़ता है और बाद को बैंक अपने ग्राहक से उतनी रकम वसूल करते हैं। किन्तु इस देनी (Liability) के विपक्ष में लेनी (Assets) की ओर भी इतनी ही रकम दिखलाई जाती है क्योंकि उतनी रकम के लिए ग्राहक बैंक के लिये जिम्मेदार हैं।

बैंक की लेनी (Assets of a Bank) :—लेनी-देनी के लेख (Balance Sheet) के दाहिनी ओर की मदों तथा उनके आंकड़ों से हमें यह ज्ञात होता है कि जो रुपया बैंक ने अपने ग्राहकों से डिपॉजिट (जमा) के रूप में लिया है और हिस्सेदारों से पूँजी के रूप में प्राप्त किया है उसका किस प्रकार उपयोग किया गया है। बैंक की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि बैंक के संचालक अपने कोष (Fund) को भिन्न प्रकार की विनियोग (Investments) में इस प्रकार लगायें कि बैंक अपनी कार्यशाला पूँजी (Working Capital) पर अधिक से अधिक मूद्र कमा सकें, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर विनियोग (Investment) को रोकड़ (Cash) में परिवर्तित किया जा सके। बैंक की लेनी (Assets) को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है (१) चल लेनी (Liquid Assets) और (२) देखी लेनी जो सीधे ही रोकड़ में परिवर्तित नहीं की जा सकती। पहले श्रेणी अर्थात् चल लेनी में हम रोकड़ (Cash) तथा उस विनियोग (Investment) को रखते हैं जो तुरन्त रोकड़ में परिवर्तित हो सकें।

बैंक की लेनी देनी के लेखे (Balance Sheet) में लेनी (Assets) को इस प्रकार विरत जाता है कि जो सत्र से अधिक चल लेनी (Liquid Asset) होती है वह सबसे पहले रक्खा जाती है और सबसे अधिक अचल लेनी (Fixed Asset) सबसे अन्त में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए रोकड़ (Cash) सबसे पहल और हमारतें इत्यादि सबसे अन्त में लिखी जाती हैं।

बैंक के लेखे में लेनी की ओर रोकड़ (Cash), रिजर्व बैंक में कोष (Balance with Reserve Bank) ग्राहकों को ऋण, विनियोग (Investment) तथा भुगतान हुए बिना के सम्बन्ध में हम विस्तार पूर्वक आगे लायेंगे। विलों की स्वीकार करने तथा उन पर बेचान (Endorsement) करने के सम्बन्ध में ग्राहकों का आ दापित्व है उसके सम्बन्ध में हम ऊपर लिख चुके हैं। यह वह राशि (रकम) है जिसके मूल्य के बिल बैंक ने अपने ग्राहकों को बदले में स्वीकार किये हैं। वस्तु देनी (Liability) और लेनी (Asset) दोनों ओर ही यह रकम दिखलाई जाती है। दोनों ओर यह रकम बराबर होती है।

बैंक की इमारतें तथा अन्य अचल सम्पत्ति एक प्रकार का अचल विनि-

योग (Fixed Investment) होता है जो शीघ्र ही रोकड़ में परिणत नहीं किया जा सकता। अधिकतर अच्छे बैंक प्रति वर्ष मूल्य ह्रास (Depreciation) के द्वारा इमारतों और अन्य सम्पत्ति के मूल्य को बहुत घटा देते हैं। इनका जो मूल्य लेनी (Asset) की ओर लिखा जाता है वह इनके वास्तविक मूल्य से कहीं बहुत कम होता है और इस प्रकार यह बैंक गुप्त सुरक्षित कोष का निर्माण करते हैं।

अब हम यहाँ संक्षेप में उन बातों पर विचार करेंगे जिनका हमें किसी बैंक की लेनी-देनी के लेखे (Balance Sheet) का अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिए। बैंक के लेनी-देनी के लेखे में हमें तीन बातों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। (१) बैंक के लाभ देने की शक्ति, (२) सुरक्षा, (३) बैंक के कारबार का स्वरूप। इन तीन बातों का अध्ययन करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा।

(१) बैंक के लाभ देने की शक्ति :—बैंक के लाभ देने की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने कितना लाभ (Dividend) बांटा है इसको जानना होगा तथा उसका सुरक्षित कोष (Reserve Fund) लाभ समकारी कोष (Dividend Equalisation Fund) तथा अविभाजित लाभ (Undivided Profits) पहले से बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। यदि पिछले वर्षों में लाभ एक समान दिया गया है तथा सुरक्षित कोष, लाभ समकारी कोष, तथा अविभाजित लाभ की रकम प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि बैंक की लाभ देने की शक्ति अच्छी है। इसके अतिरिक्त बैंक की हिस्सा पूँजी (Capital) तथा डिपाजिट का क्या अनुपात है इससे भी बैंक की लाभ देने की शक्ति का पता लगता है। यदि जमा (डिपाजिट) हिस्सा पूँजी को देखते बहुत अधिक है तो बैंक की लाभ देने की शक्ति अधिक होगी।

(२) सुरक्षा तथा तरलता (Safety and Liquidity) बैंक की सुरक्षा (Safety) तथा तरलता (Liquidity) को जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि डिपाजिट और विनियोग (Investments) तथा दिए हुए ऋण का क्या सम्बन्ध है। अर्थात् विनियोग इस प्रकार के हैं कि जो शीघ्रता पूर्वक रोकड़ में परिणत किये जा सकते हैं अथवा नहीं, और ऋण डिपाजिटों की तुलना में बहुत अधिक तो नहीं हैं। बैंक का सुरक्षित कोष (Reserve Fund) समुचित है अथवा नहीं, इसके अतिरिक्त बैंक की

मुद्रा को जानने के लिए उसकी हिस्सा पूँजी (Share Capital) और जमा (डिपॉजिट) का क्या सम्बन्ध है। यदि पूँजी डिपॉजिट को देखते यथेष्ट है तो मुद्रा अच्छी है।

(३) बैंक के कारबार का रूप :—यह जानने के लिए कि बैंक का कारबार ठीक ढंग से चल रहा है अथवा नहीं हमें देखना होगा कि डिपॉजिट और दिए हुए ऋण का क्या सम्बन्ध है, विनियोग और डिपॉजिट का क्या सम्बन्ध है। यदि डिपॉजिट पहले से बढ़ रहे हों और विनियोग तथा दिया हुआ ऋण भी पहले से बढ़ रहा हो तो यह सम्झना चाहिये कि बैंक का कारबार बढ़ रहा है।

ऊपर की बातें तो केवल सबत मात्र है जिनका हमें किसी बैंक का अध्ययन करते समय ध्यान रखना चाहिये किन्तु उसके लिये कोई एक नियम नहीं चलाया जा सकता। किन्तु एक बैंक का दृढ़ता का अनुमान करने के लिये हमें ऊपर की बातों का ध्यान रखते हुए उसकी तुलना उस देश के प्रथम श्रेणी के बैंकों से करनी चाहिए। इसके अनिश्चित हमें यह भी देखना चाहिए कि बैंक डिपॉजिट पर कितना सूद देता है। यह जमा अर्थात् डिपॉजिटों की रकम तथा सूद के रूप में कितनी रकम दी गई है उसको मालूम करने से हाथ हो सकता है। कितनी ही डिपॉजिटों पर कम सूद की दर दी गई हो उतना ही बैंक की अच्छा सम्झना चाहिए। इसके अनिश्चित दिये हुए ऋण पर तथा विनियोग (Investment) पर कितनी ही कम शीघ्रत सूद का दर होगी उतना ही बैंक की अच्छा सम्झना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बैंक ने अपना क्या सुरक्षित स्थान पर लगाया है और बैंक की ऐसी तरल है।

अध्याय ६

विनियोग नीति तथा लेनी (Investment Policy and Assets)

इससे पहले हम बैंक की लेनी (Assets) के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक लिखें यह आवश्यक है कि बैंक की विनियोग नीति का अध्ययन कर लें। क्योंकि बैंक जिस प्रकार अपने रुपये को लगावेगा उस पर ही यह निर्भर होगा कि बैंक की लेनी या सम्पत्ति किस प्रकार की होगी। बैंक के लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी पूँजी (Capital) तथा जमा (Deposit) को इस प्रकार लगावे कि वह अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें, साथ ही उसके विनियोग (Investments) ऐसे हों जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किए जा सकें। दूसरे अर्थों में उसकी लेनी तरल हों।

विनियोग नीति के मुख्य आधार :—सभी देशों में बैंक एक ही नीति नहीं बतते। जिस देश की जैसी आर्थिक दशा होती है उसी प्रकार की नीति बैंक अपनाते हैं। प्रत्येक देश में डिपॉजिट तथा ऋण सम्बन्धी नीति एक ही नहीं हो सकती। यहाँ तक एक देश के भिन्न भागों में डिपॉजिट का रूप तथा ऋण का रूप भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण के लिए भारत और ब्रिटेन की स्थिति में बहुत अन्तर है। भारत में चेक (Cheque) तथा बिल का व्यवहार ब्रिटेन की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त एक ही देश में गाँवों तथा व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों में बैंकों को भिन्न-भिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाँवों में ऋण अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए और कुछ छोड़ी सी आवश्यकताओं के ही लिए दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ सबों का एक ही धंधा (अर्थात् खेती) होता है। किन्तु औद्योगिक केन्द्रों तथा व्यापारिक केन्द्रों में ऋण बहुत से कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इन सब बातों का प्रभाव बैंक की विनियोग नीति (Investment Policy) पर पड़ता है।

जब कोई बैंक अपने रुपये को कहीं लगाता है तो उसको तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, (१) सूद की आमदनी, (२) रुपया सुरक्षित रहे, (३) रुपया बहुत लम्बे समय के लिए अटक न जाय। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बैंक को अपना रुपया लगाते समय आय, सुरक्षा और तरलता (Liquidity) का ध्यान रखना पड़ता है।

हमें यह न भूल जाना चाहिए कि बैंक एक व्यापारिक संस्था है अतएव वह अपने हिस्सेदारी के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। उनका मुख्य ध्येय अधिकतर लाभ कमाना है। किन्तु बैंक के पास जो कोष (Fund) होता है उसका अधिकांश भाग उसका न होकर जमा करने वालों का होता है जिसे वे बैंक के पास धरोहर के रूप में रख देते हैं। अस्तु बैंक उस राश का ऐसी जगह नहीं लगा सकता जहां उसके मारे जाने का खतरा हो। बैंक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि उसका लगाया हुआ धन सुरक्षित रहे। अतएव बैंक द्वारा लगाने में अनायश्यक और अधिक खतरा नहीं उठा सकता। इसके अतिरिक्त क्योंकि बैंक की अधिकतर विपणित इन्धानुसार जब चाहे निकाली जा सकती है इस कारण बैंक को अपनी यथेष्ट लेनी (Assets) तरल (Liquid) रखनी पड़ती है जिससे जरा आवश्यकता पड़े उन्हें रोकड़ (Cash) में परिणत करके जमा करने वालों को उनका रुपया वापस किया जा सके।

बैंकिंग के कारबार में ये तीन आधारभूत सिद्धान्त हैं और इन तानों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक बैंक इन तीनों आधारभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता तब तक कभी सफल नहीं हो सकता। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है और बैंक दूसरों के जमा किये हुये रुपये को व्यापारियों को श्रेष्ठ स्वरूप देकर लाभ कमाता है। इस कारण यह नितान्त आवश्यक है कि बैंक में रुपया जमा करने वालों को बैंक पर पूरा भरोसा तथा विश्वास हो। बैंक रुपया जमा करने वाले से अपने प्रति विश्वास तभी उत्पन्न कर सकता है जब रुपया जमा करने वाले के माँगने पर उनका रुपया द्रुत देने में समर्थ हो। जमा करने वालों को माँगने पर नकद रुपया देने की क्षमता तभी हो सकती है जब बैंक की लेनी (Assets) तरल (Liquid) हो। बैंक ने अपना रुपया इस प्रकार बहुत लम्बे समय के लिए न अटका दिया हो कि आवश्यकता पड़ने पर उसके पास नकद रुपया देने की न रहे।

किन्तु तरलता (Liquidity) का अर्थ केवल यह नहीं है कि लेनी (Asset) को जब चाहे तब नकद रुपये में परिणत किया जा सके। इसके साथ ही तरलता का अर्थ यह भी है कि लेनी को बैंक वर अथवा दूसरे बैंको अथवा व्यक्तियों को देकर नकद रुपये परिणत करने में घाटा न उठाना पड़े। अस्तु तरलता (Liquidity) का अर्थ यह है कि लेनी शीघ्रता

पूर्वक नकद रुपये में परिणत की जा सके, साथ ही उसको नकद रुपये में बदलने में कोई धाया भी न हो। इसको हम एक उदाहरण से अच्छे प्रकार समझ सकते हैं। सरकार की लम्बे समय की प्रतिभूति (Security) को जब चाहें हम बाज़ार में बेच सकते हैं क्योंकि सरकारी सिक्कुरिटी के लिए बाज़ार में ग्राहक सदैव मिल सकते हैं अतएव सरकारी सिक्कुरिटी को सरलता से रोकड़ में परिणत किया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जिस मूल्य पर सिक्कुरिटी खरीदी गई थी उसी मूल्य पर वह बेची जा सकेगी। हो सकता है कि यह अधिक मूल्य पर बिके अथवा कम मूल्य पर बिके। यदि वह कम मूल्य पर बिकती है तो बैंक को हानि होगी और यदि वह अधिक मूल्य पर बिकी तो बैंक को लाभ होगा। हाँ यदि बैंक अन्त तक ठहरे जब सरकार उस ऋण को चुकावेगी तब अवश्य बैंक को हानि नहीं हो सकती। अस्तु सरकारी सिक्कुरिटी यद्यपि रोकड़ में शीघ्र ही परिवर्तित की जा सकती है किन्तु उसमें भी हानि की सम्भावना बनी रहती है। इस दृष्टि से तो सरकारी सिक्कुरिटी भी आदर्श लेनी (Asset) नहीं है परन्तु फिर भी सरकारी सिक्कुरिटी एक उत्तम लेनी है। केवल रोकड़ (Cash) ही आदर्श तरल लेनी (Liquid Asset) है। जब बैंक किसी व्यक्ति की सलाह पर उसे ऋण देता है यदि वह व्यक्ति अत्यन्त विश्वसनीय, भरोसे वाला और ईमानदार है और इस जोखिम को कि उसके मर जाने से बैंक को हानि होगी उसका जीवन बीमा कराकर दूर कर दिया गया है तो उसको ऋण देने से जो लेनी (Asset) उत्पन्न हुई उसमें हानि की जोखिम तो नहीं रहती किन्तु उस लेनी को आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त रोकड़ में परिणत नहीं किया जा सकता।

जहां तक लेनीको रोकड़ में परिणत करने का प्रश्न है हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ लेनी (Asset) ऐसी होती हैं कि साधारण समय में तो वे सरलता पूर्वक रोकड़ में परिणत की जा सकती हैं, वे बाज़ार में आसानी से बिक जाती हैं, किन्तु असाधारण समय में, उदाहरण के लिये जब घोर आर्थिक मंदी (Economic Depression) हो अथवा जब सर्व साधारण बैंकों से अपना रुपया निकालने के लिए दौड़ रहे हों, तब ये लेनी भी आसानी से नहीं बिकती। और यदि सभी बैंक अपनी लेनी (Asset) बाज़ार में एक साथ बेचना चाहेंगे तो उनका मूल्य बहुत गिर जावेगा। जब बैंकों पर इस प्रकार का संकट आता है तो राष्ट्र का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) उनकी सहायता के लिए आगे आता है। केन्द्रीय बैंक इन बैंकों की

लेनी की जमानत पर उन्हें कपया देता है और इस प्रकार बैंकों में रखा जमा करने वाला की घबराहट को दूर कर देता है और सन्धान स्थिति को वापस लाने का प्रयत्न करता है। किन्तु केन्द्रीय बैंक केवल कुछ विशेष प्रकार की लेनी (Assets) की जमानत पर ही बैंकों को ऋण देता है और कुछ विशेष प्रकार का लेनी को हा भुनाता है। केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के इस सम्बन्ध में निश्चित नियम होते हैं कि वह किस प्रकार की लेनी को स्वीकार करेगा। अतः बैंकों का अपना इश्या लगाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि केन्द्रीय बैंक (Central Bank) किस प्रकार की लेनी को स्वीकार करेगा। क्योंकि जब बैंक पर सन्धानात्मक संकट आयेगा तो वही लेनी काम आयेगी जो केन्द्रीय बैंक का स्वीकार होगी क्योंकि उस समय बैंक का अन्य लेनी बाजार में नहीं बिक सकेगी। अतः बैंक की विनियोग नीति (Investment Policy) अर्थात् कपया लगाने की नीति पर केन्द्रीय बैंक का बहुत प्रभाव पड़ता है।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि बैंक अपने कपया लगाते समय लाभ, सुरक्षा और तरलता का ध्यान रखता है किन्तु लाभ की अपेक्षा सुरक्षा और तरलता अधिक महत्वपूर्ण है। किमी ने ठीक ही कहा है कि सुरक्षा के पीछे पड़ने से बैंक को कोई खतरा नहीं होता बल्कि अधिक लाभ के पीछे पड़ने से खतरा उत्पन्न हो जाता है। जब सुरक्षा और तरलता का पूरी तरह प्रयत्न हो ले तभी लाभ की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक अपने कपया (Fund) को इस प्रकार लगाता है कि कुछ कपया तात्काली में रहे जिसमें प्राइमरी की दैनिक माँग पूरी हो सके। नकदी या राकड़ सबसे तरल लेनी (Liquid Asset) होती है और क्रमशः बैंक कम तरल लेनी में अपना कपया लगाता है। कुछ लेनी ऐसी होती है कि जो शुभ ही नकदी में परिणत हो जा सकती है और अन्त में कुछ लेनी अचल सम्पत्ति के रूप में होती है। बैंक को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कितना कोष किस प्रकार की लेनी में लगाया जावे। इसको बैंक की "विभागीय नीति (Portfolio Policy)" भी कहते हैं। अब हम यहाँ बैंक की मुख्य लेनी के सम्बन्ध में लिखेंगे।

(१) मुख्य कोष (Primary Reserve) :— इसमें नकदी (Cash) को बैंक में रखा है, अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के पास जो रोक (Balance) है अर्थात् कपया जमा है और जो चेक

इत्यादि समाशोधन (Clearing) या वसूली के लिए गए हैं—सम्मिलित होते हैं ।

(२) गौण कोष (Secondary Reserve) :—इसमें याचना द्रव्य (Call-money) वह ऋण जो बहुत थोड़े दिनों (एक सप्ताह से कम) के लिए दिया गया हो अर्थात् अल्प सूचनाया द्रव्य (Money at short notice) तथा खरीदे हुए तथा भुनाये हुए विल सम्मिलित होते हैं ।

(३) विनियोग (Investments)

(४) ऋण (Loans) तथा अग्रिम (Advances) ऋण, सुरक्षित (Secured) भी होता है और अरक्षित (Unsecured) भी होता है ।

(५) स्थायी अचल सम्पत्ति (Fixed Assets) इमारत, फरनीचर, सेफ तथा अन्य अचल सम्पत्ति ।

(६) वे लेनी जिनके विरुद्ध बैंक का दायित्व है । उदाहरण के लिये ग्राहकों के बिलों पर बेचान करना अथवा उनको स्वीकार करना ।

हम पहले चार के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे । किन्तु इनके बारे में विचार करने से पूर्व हमें बैंक के कारबार में किन बातों का मुख्य रूप से विचार करना पड़ता है उसका वर्णन करेंगे ।

बैंक का मुख्य कार्य साख (Credit) देना अर्थात् ऋण देना है, अस्तु बैंक का कारबार साख देने तथा साख सम्बन्धी अन्य बातों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । साख देने का कार्य ठीक ढंग से करने के लिए बैंक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह सम्भावित ऋण लेने वालों की ईमानदारी, विश्वसनीयता, व्यापारिक कुशलता तथा आर्थिक स्थिति का ठीक पता लगावे जिससे ऋण देने में घाटा न हो । यदि बैंक ऊपर लिखी बातों की जाँच किए बिना ही ऋण दे दे तो रुपये के मारे जाने का भय रहता है और बैंक को हानि उठानी पड़ती है । बैंक का ऋण देने के सम्बन्ध में मुख्य कार्य यह है कि वह साख की जोखिम (Credit risk) को कम से कम कर दे ।

यह सभी जानते हैं कि बैंक को अपना रुपया लगाने में उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए । परन्तु सच तो यह है कि कोई भी ऐसा विनियोग (Investment) नहीं होता जिसमें थोड़ी बहुत जोखिम न उठानी पड़े । यह ठीक है कि सुरक्षित विनियोग (Secured Investments) में अरक्षित विनियोग (Unsecured Investments) से कम

जोरिम होती है। किन्तु कभी कभी सुरक्षित ऋण की सुरक्षा भी कर्जदार की ईमानदारी पर निर्भर होती है। किन्तु बैंक ने अरक्षित ऋण (Un-secured loans) भी बहुत अधिक होने हैं इस कारण बैंक के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन कर्जदारों की साख की जाँच पड़ताल कर ली जावे। किसी किसी देश में अरक्षित ऋण बहुत अधिक दिये जाते हैं क्योंकि वे व्यापारिक कार्यों के लिये होते हैं अतएव वे शीघ्र ही चुका दिये जाते हैं इस कारण व्यापारिक बैंक उन्हें अच्छा समझते हैं। समुद्रराज्य अमेरिका तथा अन्य उद्यत राष्ट्रों में आधे से अधिक ऋण अरक्षित होते हैं इस कारण उन्हें एक ऐसा विभाग रखना पड़ता है जो ऋण लेने वालों की साख की जाँच पड़ताल कर सके।

साख के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के साधनः—बैंक किसी भी कर्जदार की साख को जानने के लिए दो साधनों पर निर्भर रहते हैं। (१) आन्तरिक। (२) बाहरी।

१. आन्तरिक साधन — (अ) ग्राहक के कारबार का लेखा अर्थात् उसका लाभ हानि खाता (Profit and loss account) लेनी देनी का लेखा (Balance Sheet) देखने से।

(क) यदि ग्राहक बैंक का पुराना ग्राहक है तो उसका पुराना इतिहास जो बैंक अपने रिकार्ड से मालूम कर सकता है।

(ख) बैंक के कर्मचारी ग्राहक के कारबार के स्थान पर जाकर उसके कारबार का जाँच करके तथा उसके कारबार को देख कर उसकी साख के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) ग्राहक से बात करके अथवा उससे पत्र द्वारा पूछ लें।

बाहरी साधनः—(अ) अन्य बैंक से उन ग्राहक के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करके उसकी साख के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(क) उन पत्रों से पूछ लें जिनसे ग्राहक ने कारबार किया हो।

(ख) उन व्यापारिक स्मृतियों से पूछ लें करने से जो व्यापारियों की साख के सम्बन्ध में मूलवान खासगी जमा करती हैं ग्राहक की साख का पता लगाया जा सकता है।

(ग) साख विनियम ब्यूरो से पूछने पर।

(घ) अदालती रिकार्ड, समाचार पत्रों, तथा प्रकाशित रिपोर्टों से जो व्यापारियों की साख के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है।

इन सब में कर्जदार के कारबार का आर्थिक लेखा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक लेखे में लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) और लाभ-हानि खाता दोनों ही सम्मिलित हैं। यदि वह लेखा किसी अधिकारी आय-व्यय निरीक्षक (Auditor) द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो और भी अच्छा है। जहां तक हो बैंक को दो-चार वर्षों का आर्थिक लेखा मांगना चाहिए क्योंकि उनके देखने से यह पता चल सकता है कि यह व्यक्ति अपने व्यापार में उन्नति कर रहा है अथवा नहीं। यदि कर्ज लेने वाला बैंक का पुराना ग्राहक हो तो पिछले रेकार्ड से उसकी आर्थिक स्थिति, ईमानदारी, उसकी साख और उसके कारबार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है।

भावी कर्जदार की साख की जानकारी प्राप्त करने के बाहरी साधनों में पहले दो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। बैंक एक दूसरे को आपस में साख सम्बन्धी सूचनाएँ देते हैं। परन्तु प्रत्येक बैंक इस प्रकार की सूचनाओं को गुप्त रखता है। इस प्रकार बैंक कम व्यय में और सरलतापूर्वक साख की जानकारी प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह यह भी जान जाता है कि उस ग्राहक (जो कर्ज लेना चाहता है) ने किसी अन्य बैंक से भी कर्ज ले रखा है या नहीं। बैंक किसी व्यापारी की साख के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारिक संस्थाओं की भी सहायता ले सकते हैं। संयुक्तराज्य अमेरिका तथा अन्य योरोपीय देशों में कुछ ऐसी व्यापारिक एजेंसियाँ होती हैं जिनका एक मात्र कार्य यह होता है कि वे प्रमुख व्यापारियों, कम्पनियों, इत्यादि की आर्थिक दशा, उनके कारबार और धन के सम्बन्ध में तथा उनकी साख (Credit) के सम्बन्ध में पूरी जानकारी एकत्रित करती हैं और थोड़ी फीस लेकर बैंक इत्यादि को उस जानकारी को दे देती हैं।

बैंक की लेनी (Bank Assets) :—रोकड़ या नकदी (Cash) बैंक की सबसे तरल लेनी (Liquid Asset) होती है और बैंक उसको अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए रखते हैं। रोकड़ के अंदर वह नकद रुपया जो बैंक अपने पास रखता है अथवा जो उसने अन्य बैंकों तथा केन्द्रीय बैंकों में जमा कर रखा है सभी आ जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय व्यापारिक बैंक जो रुपया या कागजी नोट अपने पास रखते हैं, और जो रुपया उन्होंने अन्य बैंकों तथा रिजर्व बैंक में जमा कर रखा है सभी सम्मिलित होता है।

लेकिन नकदी वह लेनी है जिससे कुछ भी आया नहीं होती। एक व्यापारिक बैंक का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इस कारण वह स्वभावतः यह चाहेगा कि उसकी अधिक से अधिक लेनी ऐसा हो जिससे कुछ आमदनी हो। अतएव वह नकद रुपये का रकम का जितना भी कम कर सकता है उतना कम करेगा। कुछ नकद रुपया तो बैंक को रखना ही पड़ता है क्योंकि बिना नकद रुपया रखते बैंक का काम ही नहीं चल सकता। प्रातःदिन बैंक का जमा करने वालों के निकालने पर उन्हें नकद रुपया देना पड़ता है, उसका लिए बैंक का थोड़ी नकदी रखनी ही पड़ती है। फिर यदि समाशोधन घर (Clearing House) में बैंक का जमा दिन अधिक देना हो जाता है तो उस नकद देकर चुकाना पड़ता है। होता यह है कि केन्द्रीय बैंक में जो उस बैंक का रुपया शेष (Balance) है उसमें से जितना क्लियरिंग हाउस को देना होता है उतना कम कर दिया जाता है। इस प्रकार बैंक का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) में जमा शेष है उसमें कमी हो जाती है और हम यह पहले ही कह आये हैं कि जो राष्ट्रीय बैंक में जमा होता है उसे भांटा (Cash) माना जाता है। यह तो साधारण दैनिक नकदी की आवश्यकता है जो बैंक के गैरजाना कारबार में काम आती है, किन्तु कुछ नकदी इसलिए भी रखना आवश्यक होती है कि जिससे असाधारण नकदी की मांग को पूरा किया जा सके। कुछ असाधारण "कृत्रिम" की मांग को तो पहले से ही अनुमान किया जा सकता है। उदाहरण के लिये जब बैंक की छुट्टियाँ होने की होती हैं उसमें पूर्व नकद रुपये की असाधारण मांग होती है। परन्तु जब ऐसे कारणों से नकदी की असाधारण मांग होती है जिनके बारे में पहले से कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता तब बैंक अपनी रक्षा का दूसरीपक्ष अर्थात् वाचनाद्रव्य (Call money) बहुत थोड़े समय के लिए दिए हुए श्रृणु, और बिलों पर निर्भर होता है। जैसे ही नकदी की असाधारण मांग हुई कि बैंक वाचनाद्रव्य तब अल्पकालीन श्रृणु को बट्टन कर लेता है नये बिलों को भुनाना या खरीदना कर देता है, पुराने बिल पकने जाते हैं और प्रतिदिन बैंक को बहुत अधिक नकद रुपया प्राप्त होता जाता है।

बैंक कितनी रोकड़ रखेगा यह बहुत सी बातों पर निर्भर है। उनका उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है जो बैंक जिस स्थान में काम कर रहा है वहाँ की स्थानीय स्थिति तथा उसका ग्राहकों के स्वभाव का इस बात पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि बैंक को कितनी रोकड़ या नकदी रखना चाहिए।

(१) जिस देश में विनिमय (Exchange) बहुत अधिक होता हो और द्रव्य के द्वारा होता हो वहाँ बैंकों को उन स्थानों की अपेक्षा अधिक नकदी या रोकड़ रखनी होगी जहाँ द्रव्य का चलन कम है अथवा द्रव्य (Money) की सहायता से कम विनिमय होता है। (२) जिस समाज में चेक (cheque) का चलन बहुत अधिक होता है अर्थात् जहाँ के व्यक्ति अपना लेन-देन सिक्कों या कागजी नोटों द्वारा नहीं चुकाते किन्तु चेक के द्वारा करते हैं वहाँ बैंकों को कम नकदी रखनी पड़ती है। किन्तु जहाँ चेक का चलन कम होता है और लेना-देना सिक्कों या कागजी नोटों के द्वारा अधिकतर चुकाया जाता है वहाँ बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक नकदी रखनी पड़ती है। (३) जहाँ समाशोधन गृह अर्थात् क्लियरिंग हाउस (Clearing House) मौजूद होता है वहाँ बैंकों का काम नकदी से चल जाता है। क्योंकि क्लियरिंग हाउस में प्रत्येक बैंक पर काटे गये चेक अन्य दूसरे बैंकों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। बैंकों के सारे चेकों को जो उस पर काटे गए हैं मूल्य न चुका कर केवल अन्तर को लेना या देना पड़ता है जो उस दिन उसके पक्ष या विपक्ष में हों। उदाहरण के लिए एक बैंक को किसी दिन अन्य बैंकों से १२ लाख रुपये लेना है और १२½ लाख रुपये देना है तो वह केन्द्रीय बैंक (Central Bank) पर जिसमें सभी बैंकों का हिसाब रहता है चेक काट कर चुका देता है। अर्थात् उस दिन केवल उससे केन्द्रीय बैंक के हिसाब में ५० हजार रुपये कम हो जावेंगे। यदि दूसरे दिन उसको देना कम हो और लेना अधिक हो तो केन्द्रीय बैंक में उसके हिसाब में उतना ही अधिक जमा हो जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी बैंक में थोड़े से ही जमा करने वाले होते हैं और विशेष रूप से जब वे एक प्रकार का कार-बार करते हैं तो बैंक को अधिक नकदी रखनी पड़ती है क्योंकि विशेष अवसरों पर बैंक को अपने जमा करने वाले को बहुत अधिक रुपये देना पड़ सकता है जब उन जमा करने वालों के कारबार का समय आता है। किसी एक स्थान में जितनी नकदी और बैंक रखते हैं उसका भी प्रभाव प्रत्येक बैंक पर पड़ता है, उसको भी उसी अनुपात में नकदी रखना पड़ती है क्योंकि साधारण जनता का ऐसा विश्वास है कि जो बैंक जितनी ज्यादा नकदी रखता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित और अच्छा है। यदि कोई बैंक किसी स्थान में अधिक नकद कोष (Cash Reserve) रखता है तो अन्य बैंकों को भी अपने नकद कोष को बढ़ाना पड़ता है जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुँचे। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि वास्तव में नकद कोष (Cash Rese-

rove) ही किसी बैंक की अच्छाई का सातक नहीं है। बैंक की मुरत्ला इस बात पर निर्भर होती है कि बैंक ने अपना धन्य सुरक्षित स्थान पर लगाया है अथवा नहीं। यदि किसी बैंक ने अपना अधिकांश धन्य ऐसी लेनी (Assets) में लगाया है जो शीघ्र ही नफ़्दों में बदली जा सकती है तो उसको अधिक नफ़्द कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अधिक नफ़्द कोष इस बात का सातक हो सकता है कि बैंक का अधिक कोष कम तरल लेनी (Less Liquid Assets) में लगा हुआ है।

नफ़्द कोष (Cash Reserve) का अनुपात :—अब प्रश्न यह है कि बैंकों को नफ़्द कोष कितना रखना चाहिए। जमा के अनुपात में जितना नफ़्द कोष रक्खा जाता है उसी को नफ़्द कोष का अनुपात कहते हैं। क्योंकि नफ़्द कोष की आवश्यकता केवल धन्य जमा करने वालों की मांग पूरी करने के लिए होती है। उदाहारक बैंक जमा की तुलना में कितना नफ़्द कोष रखते हैं उसका अनुपात भिन्न देशों में भिन्न है। ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में यह सबसे कम अर्थात् डिपॉजिट (जमा) का ६ प्रतिशत होता है किन्तु भारतवर्ष में १५ से २० प्रतिशत नफ़्द कोष रक्खा जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में चेक का चलन बहुत अधिक है और भारत में उसका चलन कम है।

कुछ देशों में कानून द्वारा कम से कम एक निश्चित अनुपात में नफ़्द कोष रखना पड़ता है। इसे कानूनी नफ़्द कोष (Statutory Cash Reserve) कहते हैं। कानून नफ़्द कोष का अनुपात बहुत थोड़ा निर्धारित करता है। भारतवर्ष में कानून के अनुसार बैंकों को अभिधाचन जमा (Demand Deposit) का ५ प्रतिशत तथा मुहूर्ती जमा (Fixed Deposit) का २ प्रतिशत नफ़्द कोष रखना पड़ता है। परन्तु भिन्न देशों में कानून द्वारा नफ़्द कोष का न्यूनतम अनुपात निर्धारित कर दिया गया है वहाँ बैंक बहुधा उससे कहीं अधिक नफ़्द कोष रखते हैं।

याचना द्रव्य (Call-money) तथा अल्पकालीन ऋण (Money at short notice) :—नफ़्द कोष के बाद द्रव्य बाजार को जो बहुत अल्प काल के लिए ऋण दिया जाता है वह सबसे अधिक तरल लेनी होती है। नफ़्द कोष की अपेक्षा उनका एक लाभ यह है कि उस रुपये

पर कुछ सूद मिल जाता है। द्रव्य बाज़ार (Money Market) को जो ऋण दिये जाते हैं उन्हें हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक प्रकार का ऋण तो वह होता है जो बिल बाज़ार (Bill Market) को दिया जाता है। ब्रिटेन में बिल ब्रोकर तथा डिस्काउन्ट हाउस (जो बिल मुनाने का काम करते हैं) बिल खरीद लेते हैं। उन्हें कभी-कभी थोड़े दिनों के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ जाती है। वे बैंकों से रुपया उधार लेते हैं। इसके अतिरिक्त स्टॉक ऐक्सचेंज (जहाँ कम्पनियों के हिस्से का क्रय-विक्रय होता है) के ब्रोकरों को भी बहुधा कुछ दिनों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। यह दूसरे प्रकार का ऋण होता है। इस प्रकार के ऋण एक या दो सप्ताह से अधिक के लिए नहीं दिये जाते। तीसरे प्रकार का ऋण वह होता है जो बैंक एक दूसरे को देते हैं और उसको जब चाहे तो मांगा जा सकता है। भारतवर्ष में बिल बाज़ार नहीं है, और स्टॉक ऐक्सचेंज के ब्रोकरों को जो ऋण दिया जाता है वह याचना-द्रव्य (Call-money) के रूप में नहीं दिया जाता है। वह साधारण ऋण के रूप में दिया जाता है। अस्तु वह साधारण ऋण माना जाता है। भारत में इस श्रेणी में केवल वह ऋण आते हैं जो बैंक एक दूसरे को थोड़े समय के लिये देते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में ही केवल याचना-द्रव्य बाज़ार (Call money Market) है जहाँ बैंक एक दूसरे बैंकों से क्षणिक आवश्यकताओं के लिए ऋण लेते हैं। यदि कारवार बहुत अधिक है और इस प्रकार के ऋण की बहुत अधिक मांग है तो सूद की दर कुछ अधिक होती है और यदि कारवार मंदा है तो सूद की दर कम होती है। मई, जून से सूद की दर कम होने लगती है और नवम्बर और दिसम्बर से सूद की दर ऊँची उठने लगती है। साधारण तौर पर सूद की दर १ प्रतिशत से १ प्रतिशत तक बढ़ती है।

भुनाये हुए तथा खरीदे हुए बिल (Bills Discounted and Purchased) :—इसमें प्रामिसरी नोट, बिल (व्यापारिक) तथा सरकारी ट्रेजरी बिल (Treasury Bill) सभी सम्मिलित होते हैं। प्रामिसरी नोट तो बैंक कम हो मुनाते या खरीदते हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बिल (International Bills), देशीय बिल (Inland Bill) तथा सरकारी ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) ही अधिकतर भुनाते या खरीदते हैं। ब्रिटेन में इनका और जमा (Deposit) का अनुपात १२ प्रतिशत से २० प्रतिशत तक होता है। नक़द कोष (Cash Reserve) याचना-द्रव्य, तथा अल्प कालीन ऋण (Call money and at short notice) तथा बिल, बैंक की तरफ

लेनी (Liquid Assets) होती है। ब्रिटेन में इनका अनुपात जमा (Deposit) की तुलना में ३० से ३३ प्रतिशत होता है।

भारतवर्ष में बैंक बिलों में अधिक रुपया नहीं लगाते। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अभी तक बिल बाजार (Bill Market) का निर्माण नहीं हुआ। इसी वजह से एक्सचेंज बैंक अवश्य विदेशी बिल बहुत अधिक रखते हैं। भारतीय बैंक व्यापारिक बिलों में बहुत कम रुपया लगाते हैं। भारतीय बैंकों द्वारा भुनाये गये खासरी दे हुए बिलों का डिपॉजिट की तुलना में अनुपात ५ से ६ प्रतिशत तक लगभग ही होता है।

विनियोग (Investments) :—विनियोग (Investments) बैंकों का चौथा रत्ना पात्र होता है। विनियोग से याचना द्रव्य तथा बिलों की अपेक्षा अधिक सूर का आय होती है। यद्यपि ऋण पर जितना सूर मिलता है उससे तो इस पर कम हा सूर मिलता है। किन्तु साधारणतः उचित सूर पड़ जाता है। जब ऋण की मांग कम हो जाती है तो बैंक अपने कोष को परम प्रतिभूति (Gild Edged Securities) या सरकारी सिक्कुरिटी में लगाता है, और जब ऋण की मांग अधिक होती है तो इन सिक्कुरिटीयों को बैंचकर रुपया ऋण के रूप में दे दिया जाता है। संयुक्तराज्य और ब्रिटेन में अधिकतर बैंक सरकारी प्रतिभूति सिक्कुरिटी, में ही अपना रुपया लगाते हैं यद्यपि थोड़ा रुपया अन्य परम प्रतिभूति (Gild Edged Securities) में भी लगाते हैं। ब्रिटेन में इनका जमा की तुलना में अनुपात २७ प्रतिशत, संयुक्तराज्य अमेरिका में १० प्रतिशत से भी अधिक है। भारतवर्ष में भी बैंक इसमें अपने कोष का बहुत बड़ा भाग लगाते हैं। भारतवर्ष में बैंक अपनी जमा का ४० प्रतिशत इसमें लगाते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में बिल बाजार (Bill Market) तथा याचना-द्रव्य (Call Money Market) का अभाव है। इन कारण परम प्रतिभूति (Gild Edged Security) ही अधिक उपयुक्त और तरल लेनी (Liquid Asset) मानी जाती है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक इनको नकदी में परिणत करने का प्रश्न है इनको सरलतापूर्वक नकदी में बदला जा सकता है किन्तु इन पर हानि होने की जोखिम रहती है। क्योंकि जिस समय बैंक इनको बैंचना चाहता है हो सकता है कि बाजार में उनका मूल्य गिर गया हो। अधिकतर भारतीय बैंक सरकारी सिक्कुरिटी, स्टॉक एंड ट्रस्ट तथा पाब्लिक तथा म्यूनिस्पैलिटीयों के बॉण्ड में रुपया लगाते

हैं किन्तु पिछले दिनों में बैंकों ने मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों (Joint Stock Companies) के हिस्सों और डिबेंचरों (ऋण पत्र) में भी रुपया लगाना आरम्भ कर दिया है ।

ऋण (Loans) :—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि ऋण देना बैंक का मुख्य कार्य है और इस कार्य के द्वारा ही बैंक का सीधा सम्बन्ध जनता से स्थापित होता है । जनता तथा व्यापार के लिए बैंक की उपयोगिता उसके इस कार्य से ही नापी जाती है । यदि बैंक घरोघर के रूप में उसके पास जमा किया हुआ रुपया बुद्धिमानों से ऋण के रूप में देता है तो वह समाज की बहुमूल्य सेवा करता है । ऋण बैंक की मय से लाम-दायक लेनी (Asset) है क्योंकि ऋण पर बैंक को सबसे अधिक सूद मिलता है । यही कारण है कि बैंक जितना अधिक हो तब उतना कोष (Fund) ऋण के रूप में लगा देना चाहता है । साथ ही उसको इन ऋणों की सुरक्षा के लिए सावधानी करना पड़ती है । वह ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी प्रतिभूति (Security) के आधार पर ऋण देता है जिससे रुपये के मारे जाने का तनिक भी भय न रहे । यदि बैंक ऋण देने में बहुत उदारता में काम लेता है तो बड़े खाते (Bad debts) के कारण उसको बहुत हानि उठानी पड़ सकती है और यदि बैंक ऋण देने में अत्यधिक भयभीत रहता है तो उसका कोष (Fund) बेकार पड़ा रहेगा वह यथेष्ट आय प्राप्त नहीं कर सकेगा । अपने कोष को सावधानी से ऋण के रूप में छोड़े कर्जदारों को उठाने का योग्यता ही बैंक के संचालकों की सफलता का कारण बनती है । यदि किसी बैंक की ऋण देने की नीति ठीक है तो बैंक की सफलता में तनिक भी संदेह नहीं हो सकता ।

यद्यपि ग्राहकों को दिये हुए ऋण से बैंक को सबसे अधिक लाभ होता है किन्तु यह लेनी (Asset) सबसे कम तरल है अर्थात् आवश्यकतानुसार नकदी में परिणत नहीं की जा सकती । यद्यपि नाम के लिए बैंक ऋण देते समय यह शर्त रख सकता है कि मांगने पर कर्ज लेने वाले को रुपया देना होगा परन्तु व्यवहार में यह कठिन होता है कि बैंक की सूचना मिलते ही कर्जदार रुपया देने का प्रवण कर सके । उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि किसी व्यापारी ने कपास खरीदने के लिये ऋण लिया है तो वह बैंक के मांगने पर उस ऋण को नहीं चुका सकता क्योंकि जब तक वह कपास को बेच कर रुपया वसूल न कर ले तब तक वह बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ

होगा। अस्तु कोई भी बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपने कर्जदारों से रुपया नहीं पा सकता और न वह कर्जदारों पर निर्भर ही रह सकता है। यदि सभी बैंक अपने-अपने कर्जदारों से श्रृणु को चुकाने के लिये दबाव डालने लगें तो और भी अधिक आर्थिक संकट (Economic Crisis) उत्पन्न हो जावे और जनता का बैंकों पर से विश्वास उठ जावे। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी दशा में अपना जमा किया हुआ रुपया निकालने के लिये और भी उत्सुक और आतुर हो उठे और बैंकों से अपना रुपया निकालने के लिए दौड़ पड़े। उस दशा में बैंकों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

श्रृणु बहुत से रूपों में दिये जाते हैं। किन्तु बिना प्रतिभूति या जमानत (Security) के कोई श्रृणु नहीं दिया जाता। जमानत या प्रतिभूति भी कई प्रकार की होती है। श्रृणु के स्वरूप और जमानत में चाहे कितनी भिन्नता हो किन्तु व्यापारिक बैंक थोड़े ही समय के लिए श्रृणु देते हैं। कोई भी श्रृणु अधिक लम्बे समय के लिए नहीं दिया जा सकता। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य में बैंक थोड़े ही समय के लिए श्रृणु देते हैं और भारतीय बैंक भी उसी नीति को अपनाये हुए हैं। भारतवर्ष, ब्रिटेन तथा संयुक्तराज्य में इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है कि व्यापारिक बैंकों का यह कार्य नहीं है कि वे अपने ग्राहकों को अधिक लम्बे समय के लिए या अचल पूंजी (Fixed Capital) की व्यवस्था करें। उनका काम तो केवल इतना है कि वे जनता को थोड़े समय के लिए पूंजी दें अथवा कार्यशील पूंजी (Working Capital) की व्यवस्था करें। जब कोई व्यक्ति बैंक से श्रृणु लेने का प्रस्ताव करता है तो बैंक पहली बात यह देखता है कि श्रृणु कितने समय के लिए चाहिये, और दूसरी बात यह देखता है कि उस समय के व्यतीत हो जाने पर उसकी अदायगी की क्या सम्भावना है। बैंक को इस बात का अधिक महत्व होना चाहिए कि समय व्यतीत होने पर श्रृणु के चुकाये जाने का कितनी सम्भावना है। बैंक के लिए श्रृणु की तरलता (Liquidity) अधिक महत्वपूर्ण है उसे अच्छा जमानत और अच्छे सूद के लालच में न पड़ना चाहिये और लम्बे समय के लिए रुपया न पसाना चाहिये। इसके अतिरिक्त बैंक इस बात को भी जांच करता है कि श्रृणु किस लिए लिया जा रहा है। बैंक जोखिम के व्यापारों तथा सट्टे के लिए रुपया देने से हिचकता है। वह इस प्रकार के श्रृणु लेने वालों का उत्साहित नहीं करता। संसार के सभी मुख्य देशों में व्यापारिक बैंक जमा

(Deposit) किये हुए कोष का ५० प्रतिशत ऋण के रूप में दे देते हैं । भारत में ५० प्रतिशत से भी अधिक ऋणों के रूप में दे दिया जाता है ।

ऋण का स्वरूप :—बैंक अपने ग्राहकों को तीन प्रकार से ऋण देते हैं । पहला साधारण कर्ज के रूप में, दूसरा नकद साख (Cash Credit) के रूप में, तीसरा अधिविकर्ष (Over Draft) के रूप में । पिछले दो प्रकार के ऋण चालू खाते (Current Account) के द्वारा दिये जाते हैं और साधारण ऋण का हिसाब बिलकुल अलग रहता है । यदि किसी व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं है वह भी बैंक से साधारण ऋण ले सकता है । यद्यपि व्यवहार में बैंक साधारणतः उन लोगों को ऋण नहीं देते जो उसके ग्राहक नहीं होते अर्थात् उनका बैंक में खाता नहीं होता । नकद साख (Cash Credit) अथवा अधिविकर्ष (Over Draft) लेने के लिए बैंक के साथ चालू खाता होना आवश्यक है । यदि देखा जाये तो व्यवहार में नकद साख और ओवर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) एक से होते हैं । दोनों में ही ग्राहक को यह सुविधा दी जाती है कि वह जितना रुपया उसके हिसाब में है उससे अधिक निकाल सके । वह कितना रुपया अधिक निकाल सकेगा यह पहले निश्चित हो जाता है । जब किसी को बैंक साधारण ऋण देता है तो ऋण का हिसाब अलग खोला जाता है और जितना रुपया कर्ज देना तय हुआ है उतना बैंक कर्ज लेने वाले के ऋण खाते में उसके नाम (Debit) कर देगा । और या तो कर्ज लेने वाला उतना रुपया नकद बैंक से ले लेगा अथवा उतना रुपया उसके चालू खाते में उसके नाम जमा कर दिया जावेगा । कर्ज लेने वाला जब जितना चाहे उसमें से निकाल सकेगा । ऋण के पहले दो स्वरूप अर्थात् नकद साख और ओवर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) अधिक सुविधा जनक और प्रचलित हैं क्योंकि इनमें ग्राहक को उतनी ही रकम पर सूद देना पड़ता है जितनी कि वह निकालता है । पूरी रकम पर (जितने तक वह निकाल सकता है) सूद नहीं देना पड़ता । साधारण ऋण में कर्ज लेने वाले को पूरी रकम पर सूद देना पड़ता है । उदाहरण के लिए मान लें कि एक व्यापारी को कुछ खरीद करनी है और उसके चालू खाते में केवल दस हजार रुपया है वह बैंक के पास जाता है और पुराना ग्राहक होने के कारण बैंक उसको दस हजार रुपये की नकद साख अथवा ओवर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) दे देता है अर्थात् वह अब अपने चालू खाते में से २० हजार रुपये तक निकाल सकता है । किन्तु आगे चलकर ग्राहक ने अपने रुपये से केवल पाँच हजार रुपये ही अधिक निकाले तो उसको केवल

पाँच हजार रुपये ही पर सूद देना होगा। परन्तु यह भी हो सकता है कि ग्राहक दस हजार रुपये (जो उसके चालू खाते में जमा था) से अधिक निकाले ही नहीं और बैंक ने जो उसको नकद साख (Cash Credit) या ओवर ड्राफ्ट (अधिकिकर्य) दिया है उसके लिए नकद कोष (Cash Reserve) रखना पड़े और उस प्रकार बैंक की उस रुपये पर सूद की हानि हो। इस हानि से बचने के लिए बैंक नकद साख या ओवर ड्राफ्ट देते समय एक न्यूनतम रकम रख देते हैं जिस पर ग्राहक को सूद हर हालत में देना होगा चाहे वह उसको निकाले या न निकाले। यह कुल रकम (जिसके लिए नकद साख या ओवर ड्राफ्ट दिया गया है) की एक तिहाई या एक चौथाई होती है।

साधारण ऋण तथा नकद साख और ओवर ड्राफ्ट में एक भेद यह है कि साधारण ऋण अधिकतर लम्बे समय के लिए (अधिक लम्बे समय के लिए नहीं) लिए जाते हैं और नकद साख तथा ओवर ड्राफ्ट अपेक्षाकृत कम समय के लिए। साधारण ऋण अपने निज व्यव के लिए अथवा धंधों के लिए उसकी मशीनों इत्यादि की जमानत पर लिए जाते हैं। ओवर ड्राफ्ट कम्पनियों के हिस्सों, सेना, कपास जूट इत्यादि की जमानत पर अथवा कर्जदार के प्रोमोट पर बिना किसी गारंटी करने वाले के हस्ताक्षर के ही दे दिया जाता है। परन्तु बिना आनुसंगिक जमानत (Collateral Security) के प्रोमोट पर ओवर ड्राफ्ट नहीं दिया जाता। नकद साख, सेती की पैदावार, अन्य वस्तुओं तथा सैयार माल की जमानत पर दी जाती है। नकद साख लेने वाले को अपना माल बैंक के मोदारो में रख देना पड़ता है।

जमानत या प्रतिभूति (Security) का स्वरूपः—ग्राहक की व्यक्तिगत जमानत पर भी उसे ओवर ड्राफ्ट या नकद साख दे दी जाती है और उससे प्रोमोट लिखा लिया जाता है। यह अरक्षित कर्ज (Unsecured) कहलाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बैंक अपने रुपये की सुरक्षा का ध्यान किये बिना ही ऋण दे देता है। इस प्रकार के ऋण की जमानत कर्जदार की वस्तुस्थिति तथा भविष्य में कर्जदार के व्यापार या कारबार की बेसी सम्भावना है इस पर निर्भर होती है। इस प्रकार का ऋण देने से पूर्व बैंक कर्जदार से मिलने कुछ वर्षों का उसका लाभ हानि खाता (Profit & Loss Account) तथा लेनी देनी का लेखा (Balance Sheet) मांगता है। इनका एक विश्वसनीय आय-व्यय-निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। बैंक इनका अध्ययन करता है और कर्ज लेने वाले की आर्थिक स्थिति का

अनुमान लगाता है। इसके अतिरिक्त उस कर्जदार की बाज़ार में कैसी साख है तथा उसका चरित्र कैसा है इसकी जानकारी प्राप्त करता है। यदि कर्ज लेने वाला बैंक का ग्राहक रहा है तो उसकी ईमानदारी उसके कारबार की स्थिति तथा आर्थिक अवस्था का बैंक को ज्ञान होता ही है इन पर अवलम्बित होकर बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देना स्वीकार करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऋण देते समय बैंक कर्ज लेने वाले के चरित्र, योग्यता तथा पूँजी इन तीन बातों की जानकारी प्राप्त करता है।

यदि बैंक कर्ज लेने वाले की व्यक्तिगत जमानत को यथेष्ट नहीं समझता और कर्ज माँगने वाला कोई अन्य आनुसंगिक जमानत (Collateral Security) भी नहीं दे सकता तो बैंक गारंटी माँगता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी साख में बैंक का विश्वास हो कर्ज माँगने वाले की गारंटी दे अर्थात् यदि कर्ज माँगने वाला रुपया न चुकावे तो गारंटी देने वाला व्यक्ति बैंक के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात् उस रुपये को स्वयं चुकावेगा। गारंटी कर्ज माँगने वाले के लिए भी सुविधाजनक है और बैंक के लिए भी एक अच्छी जमानत होती है। इसका एक दुर्गुण भी है; यदि गारंटी का लेख अच्छे प्रकार से ठीक-ठीक नहीं तैयार किया गया है तो आगे चल कर बहुत झगड़ खड़ी हो सकती है और इस जमानत की उपयोगिता जमानत करने वाले की आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर होती है। यदि गारंटी देने वाला दिवालिया हो जावे तो वह बेकार हो जाती है। बैंक को गारंटी देने वाले के चरित्र, उसकी योग्यता तथा साख का पता भी लगाना पड़ता है। बैंक को जब गारंटी पत्र पर गारंटी करने वाले से हस्ताक्षर कराने हों तब उसे उसकी शर्तों को बता देना चाहिये जिससे वह आगे चल कर यह न कह सके उसे शर्तों का पता न था अथवा गारंटी पत्र में क्या लिखा है यह न मालूम था। साथ ही गारंटी पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि कर्ज की राशि चाहे बढ़ती बढ़ती रहे किन्तु गारंटी पूरे ऋण के बराबर रहेगी।

व्यक्तिगत जमानत तथा गारंटी के अतिरिक्त अन्य आनुसंगिक जमानत (Collateral Security) भी ली जाती है। कर्ज लेने वाला कंपनियों के हिस्से, डिबेंचर, तथा बांड इत्यादि कच्चा माल तथा तैयार माल अथवा उस माल सम्बन्धी फाइल-पत्र (जिनसे माल का स्वामित्व हस्तांतरित होता है) तथा अचल सम्पत्ति हमारा इत्यादि जमानत के रूप में बैंक के पास रखता है। हम आगे चल कर जमानत के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

बैंकों का संगठन —संगठन की दृष्टि से बैंक दो प्रकार के होते हैं (१) यूनिट बैंकिंग (२) ब्रांच बैंकिंग। संयुक्तराज्य अमेरिका में यूनिट बैंकिंग की प्रधानता है। वहाँ प्रत्येक बैंक का एक ही आफिस होता है। बैंक जहाँ स्थापित होता है केवल वहीं कारबार करता है ब्रांच स्थापित नहीं करता। यद्यपि संयुक्त राज् अमेरिका में कुछ बैंकों को बहुत अनुचित क्षेत्र में कतिपय ब्रांचें खोलने की आज्ञा दे दी गई है किन्तु अधिकांश बैंकों की वहाँ कोई भी ब्रांच नहीं है। इसके विपरीत अन्य उन्नत राष्ट्रों में बहुत बड़े बैंक होते हैं और उनकी हजारों शाखाएँ दूर-दूर भरे भरे फैली हुई होती हैं। इंग्लैण्ड के बड़े पाँच बैंकों की ६,५०० से अधिक ब्रांचें हैं और देश की तीन चौथाई डिपॉजिट उनके पास रहती है। कनाडा में चार बड़े बैंकों में देश की ८० प्रतिशत डिपॉजिट है। यही दशा जर्मनी में है।

बहुत से लेखक भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए कहते हैं कि भारत में भी यूनिट बैंक हैं। पहले इस कथन में कुछ सत्यता रही हो किन्तु अब यह सत्य नहीं है। पिछले युद्ध में भारत में ब्रांच बैंकिंग का अभूत पूर्व विस्तार हुआ है। पुराने बैंकों ने सामान्य पूर्वक अपनी ब्रांचों को देशभर में फैला दिया है और अनेक नये बैंक स्थापित हो गए हैं जिन्होंने अपनी ब्रांचों को पैमाना प्रारम्भ कर दिया है। अतएव अब यह कहना कि भारत में यूनिट बैंकिंग है ठीक नहीं है।

यूनिट और ब्रांच बैंकिंग की तुलना —यूनिट बैंक और ब्रांच बैंकिंग की तुलना ठीक वैसी ही है जैसी बड़ी मात्रा की उत्पत्ति (Large Scale Production) और छोटी मात्रा की उत्पत्ति। ब्रांच बैंकों की बड़ी मात्रा में काम करने के लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रांच बैंक में श्रम विभाजन (Division of Labour) का पूरा उपयोग किया जा सकता है जो यूनिट बैंक में सम्भव नहीं है। ब्रांच बैंक में श्रेष्ठ कर्मचारी बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं और उसकी नीति को निर्धारित करते हैं। जैसे एक श्रेष्ठ कर्मचारी केवल इस बात पर अपना सारा समय लगावेगा कि बैंक का शेष ठीक चगढ़ लगाया जा रहा है। कृपा ऐसी चगढ़ तो नहीं लगाया जा रहा है कि जहाँ जोखिम हो। एक दूसरा श्रेष्ठ कर्मचारी उन नियमों का निर्धारण करेगा और लागू करने के लिए नियुक्तियाँ जाँचता है जो किसी कर्मदार को श्रम देने पर जमानत स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। एक

सीसरा, कर्मचारियों को मरती करने के लिए रक्खा जा सकता है। किन्तु एक यूनिट बैंक में यह सम्भव नहीं होता, उसका कारबार सीमित होता है, इस कारण एक ही व्यक्ति को सारा काम करना पड़ता है। ब्रांच बैंक कम नकद कोष रखकर भी काम चला सकता है क्योंकि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से आवश्यकता पड़ने पर नकद रुपया ले सकती है किन्तु यूनिट बैंक को अपेक्षा कृत अधिक नकद कोष रखना पड़ता है। ब्रांच बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को कोष (Fund) भेजने का काम कम व्यय में और सरलता पूर्वक कर सकता है। यद्यपि यूनिट बैंक यह कार्य अन्य बैंकों के द्वारा करते हैं परन्तु उसमें ब्रांच बैंक के समान सरलता और कम व्यय नहीं होता। यही नहीं ब्रांच बैंक को एक बड़ा लाभ यह भी है कि उसकी जोखिम एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली होती है जहाँ उद्योग-धंधे और व्यापार भिन्न-भिन्न होते हैं। अतएव यदि एक व्यापार या धंधा मंदा है अर्थात् उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस क्षेत्र की ब्रांच का रुपया झूबने या अटकने की सम्भावना हो सकती है। किन्तु अन्य ब्रांचों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरन् सम्भव है कि उनकी दशा अच्छी रहे क्योंकि बहुत सम्भव है कि उनके क्षेत्र के धंधे या व्यापार खूब सफल हो रहे हों। किन्तु यूनिट बैंक का कारबार तो एक ही केन्द्र में सीमित होने से यदि वहाँ के धंधे की आर्थिक स्थिति खराब हो जावे तो यूनिट बैंक को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। हाँ यदि सभी धंधों और व्यापार में आर्थिक मंदी एक समान हो तो दोनों प्रकार के बैंकों की स्थिति एक सी ही होगी। उदाहरण के लिए १९२९ की आर्थिक मंदी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में खेती की पैदावार का मूल्य बहुत घट गया इस कारण बहुत से (सैकड़ों) छोटे यूनिट बैंक दिवालिया हो गए। किन्तु उस समय लंकाशायर के सूती कपड़े के धंधे की दशा अत्यन्त ही दयनीय थी। इंग्लैंड के बड़े बैंकों का बहुत रुपया उस धंधे में झूब चुका था, उन्हें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी, किन्तु उनका कारबार अन्य स्थानों में भी फैला हुआ था और वहाँ के धंधे पनर रहे थे इस कारण वे इस हानि को सहन कर सके। अब तक हमने ब्रांच बैंकों के लाभों का वर्णन किया। किन्तु एक बात ध्यान रखने की है कि श्रम विभाजन (Division of Labour) की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को पार करने पर लाभ नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रांच बैंकिंग के लाभ तब तक तो बहुत अधिक होते हैं जब तक ब्रांच एक ही देश के अन्दर खोली जाती है। किन्तु जब ब्रांच विदेशों में खोली जाने लगती है तो कठिनाई बढ़ जाती है और लाभ नष्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि व्यापार

सम्बन्धी कानून व्यापारिक रीति रिवाज, तथा आर्थिक स्थिति प्रत्येक देश की भिन्न होती है। फिर प्रत्येक देश का लक्ष्य भिन्न होता है और भाषा भी भिन्न होती है। इस कारण अधिकतर बैंक विदेशों में जांच नहीं खोलते। यदि वे विदेशों में कारबार करते हैं तो एक पृथक् सहायक बैंक (Subsidiary Bank) उस देश के लिए स्थापित करते हैं। वह सहायक बैंक लगभग स्वतंत्र तरफा होते हैं।

अब हम तनिक यूनिट बैंकों के साथों पर भी दृष्टि डाल लें। भिन्न भिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में स्थानीय भिन्नता इतनी अधिक होती है कि यूनिट बैंक उसके लिए अधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए मान लें कि एक यूनिट बैंक एक बड़ी कपास की मंडी में स्थापित है तो उसको कपास के व्यापारियों से ही कारबार करना होगा। अस्तु यूनिट बैंक कपास के सम्बन्ध में बैंकिंग सम्बन्धी जितनी भी समस्याएँ उठेंगी उनका जांच बैंक की अपेक्षा सुगमता से हल कर सकेगा और कपास के व्यापारियों से बराबर कारबार करने के कारण वह जांच बैंक से इस कार्य में अधिक कुशल हो जावेगा। यूनिट बैंक के संचालक स्थानीय व्यापारियों की साथ, उनकी ईमानदारी तथा उनके धन की आर्थिक स्थिति का बहुत नजदीक से देखते हैं और वे उनको व्यक्तिगत रूप से माली भांति जानते हैं। अतएव श्रृंखला देने में उन्हें आश्विन कम रहता है और उन्हें यह जानकारी प्राप्त करने में जांच बैंकों की तरह व्यय नहीं करना पड़ता। किंतु उसके साथ ही एक भय भी रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यापारी बैंक से कारबार करता चला आता है। वह व्यावहारिक ही है कि उस व्यापारिक परिवार और बैंक के सच्चा लक्ष्य का प्रतिष्ठ सामाजिक संबंध भी स्थापित हो जाये और उस दशा में बैंक वह समझते हुए भी कि व्यापारी के कारबार की स्थिति अच्छी नहीं है शिष्ट-चार तथा संबंध के नाते कभी कभी श्रृंखला देना अस्वीकार नहीं कर सकता। किंतु जांच मैनेजर अपने ग्राहकों से क्लेशों तथा अन्य स्थानों में लूट मिल जुल कर तथा उस स्थान के सामाजिक जीवन में खूब धूल मिला कर एक ओर तो बैंक के कारबार को मरता है और अपने ग्राहकों की साथ, उनके कारबार, तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी ओर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे जांच मैनेजर की पवित्रता है और उसको श्रृंखला देना उचित नहीं है, यदि बैंक से श्रृंखला चाहता है तो जांच मैनेजर हेड आफिस की आड़ लेकर श्रृंखला अस्वीकार कर सकता है और उसके सामाजिक सम्बन्ध पर भी आघात नहीं पहुँचता।

ऊपर लिखी सारी बातों को ध्यान में रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रांच वैकिंग के गुण अधिक हैं और दोष कम हैं तथा थूनिट वैक की अपेक्षा ब्रांच वैकिंग के गुण कहीं अधिक हैं। यही कारण है कि आधुनिक समय में सर्वत्र ब्रांच वैकिंग का प्रचार है।

अध्याय ७

केन्द्रीय बैंक (Central Bank)

यह तो हम पहले परिच्छेद में पढ़ चुके हैं कि द्रव्य (Money) और साख (Credit) का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार की द्रव्य सम्बन्धी नीति देश में अपनाई जावेगी उसका साख पर प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार धन के उत्पादन अर्थात् उद्योग धंधों तथा व्यापार सभी को वह प्रभावित करेगी। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि बैंक साख (Credit) का निर्माण करते हैं और द्रव्य का बहुत सा कार्य साख पर (Credit Instruments) ही करते हैं। आज उन्नतिशील देशों में चेक और बिल इत्यादि का जितना उपयोग होता है मुद्रा तथा कागज़ी मुद्रा का दसवां हिस्सा भी नहीं होता। अतएव यह बात स्पष्ट हो गई कि द्रव्य (Money) और साख (Credit) का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और इन दोनों का देश के आर्थिक संगठन को बनाने या बिगाड़ने में बहुत हाथ रहता है। अतः द्रव्य सम्बन्धी नीति और साख सम्बन्धी नीति का देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए संचालन और नियंत्रण होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त देश में निम्न निम्न प्रकार के उत्पादन कार्य होते हैं और उनमें प्रत्येक प्रकार के उत्पादन कार्य अर्थात् खेती, उद्योग धंधे, व्यापार इत्यादि की पूँजी और साख सम्बन्धी विशेष आवश्यकताएँ होती हैं इस कारण बहुत प्रकार के बैंक स्थापित हो गए हैं। कृषि बैंक, सहकारी (Co operative Bank) मृत्ति ऋणक बैंक (Land Mortgage Banks) खेती के लिए, औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) अधिक लम्बे समय के लिए उद्योग धंधों को तथा व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) थोड़े समय के लिए व्यापारियों तथा व्यवसायियों को पूँजी (Capital) देने का प्रबंध करते हैं। राष्ट्र की बचत (Savings) यह बैंक अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और उस पूँजी को साख निर्माण करने की पद्धति के अनुसार कई गुना करके उत्पादन कार्य (Production of wealth) को सहायता पहुँचाते हैं। परन्तु यदि इन बैंकों का आपस में कोई सम्बन्ध न हो तो यह

राष्ट्रीय पूँजी (National Capital) छोटे छोटे भागों में बंटी रहे और देश को पूरा पूरा उपयोग न मिल सके। उदाहरण के लिए हम सहकारी बैंकों को लें। जब बीज बोने का समय होता है तब खेती के धंधे की पूँजी की बहुत आवश्यकता रहती है और यह बैंक पूँजी किसानों को उधार देते हैं। किन्तु जब फसल तैयार हो जाती है और किसान उसको मंडी में बेच कर श्रृण लुका देता है तो इन बैंकों के पास बहुत कोष जमा हो जाता है और वे उसको खेती के धंधे में नहीं लगा सकते क्योंकि खेती को उस समय पूँजी की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु सहकारी बैंक (Co-operative Banks) उस कोष को व्यापार तथा उद्योग-धन्धों में लगाने की योग्यता नहीं रखते क्योंकि वे उस कार्य को करते ही नहीं हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वह कोष राष्ट्र के उत्पादन कार्य (Production of Wealth) में सहायक न होगा और बेकार रहेगा। इसी प्रकार व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) के पास वर्ष में कुछ दिनों कोष बेकार रहता है उसकी अधिक मांग नहीं होती, और कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यापार को बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। यदि इन सभी प्रकार के बैंकों का आपसी सम्बन्ध स्थापित किया जा सके तो राष्ट्र की पूँजी को सरलता से एक धन्धे से दूसरे धन्धे में भेजा जा सकता है। इस प्रकार जिस धन्धे में पूँजी की अधिक आवश्यकता होगी वहीं पूँजी प्रवाहित कर दी जा सकेगी और उत्पादन कार्य के लिये उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

अतएव द्रव्य और साख का देश के हित में ठीक-ठीक नियन्त्रण करने तथा द्रव्य बाजार (Money Market) अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों में आपसी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता होती है ①केन्द्रीय बैंक की विशेषता यह है कि वह अन्य बैंकों का इस प्रकार नियन्त्रण करता है ②जिससे राज्य की द्रव्य नीति (Monetary policy) देश में लागू हो सके और द्रव्य का मूल्य जल्दी-जल्दी न बदले। अन्य बैंकों की भाँति लाभ कमाना केन्द्रीय बैंक का लक्ष्य नहीं होता वरन् देश के द्रव्य परिमाण (Monetary Standard) को स्थायित्व प्रदान करना और साख का इस प्रकार नियन्त्रण करना उसका लक्ष्य होता है जिससे देश के आर्थिक हितों की रक्षा और उन्नति हो। भारत के रिजर्व बैंक ऐक्ट में रिजर्व बैंक का लक्ष्य इस प्रकार बताया गया है। “रिजर्व बैंक आर इंडिया को स्थापित करना इसलिये आवश्यक है कि जिससे कागजी नोटों को

निकालने का कार्य भली भाँति हो सके और वह देश के सुरक्षित कोष (Reserves) को भारत में द्रव्य का स्थायित्व (Monetary Stability) उत्पन्न करने की दृष्टि से रखे, और भारत के हित के लिये साख तथा करसी का नियन्त्रण करे।”

इस कार्य को करने के लिये बैंक को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए केन्द्रीय बैंक को कागजी नोट (Paper currency) निकालने का एकाधिकार प्राप्त होता है। देश में अन्य कोई बैंक नोट नहीं निकाल सकता किन्तु केन्द्रीय बैंक देश की सरकार का सारा कारबार करता है, वह सरकार का बैंकर होता है। वह राष्ट्र के कोष (Reserves) को रखता है और अन्तिम स्थिति में श्रुण देने वाला होता है (Lender of the last resort)। अर्थात् जब व्यापारिक बैंक भी साख देने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो वे केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से अन्त में श्रुण लेते हैं।

किन्तु जहाँ केन्द्रीय बैंक को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है वहाँ कुछ रबत भी उस समय पर लगाना आवश्यक हो जाता है। केन्द्रीय बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कारबार नहीं करने दिया जा सकता क्योंकि उसको तो देश के आर्थिक स्वार्थों की रक्षा करनी होती है। केन्द्रीय बैंक अन्तम स्थिति में श्रुण देने वाला होता है इस कारण उसे अपनी लेनी (Assets) का बहुत तरल (Liquid Form) में रखना पड़ता है। केन्द्रीय बैंक को अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतिस्पर्धा (Competition) करना न तो उचित है और न न्यायपूर्ण। अन्य बैंकों से केन्द्रीय बैंक प्रतिस्पर्धा करे तो वह न्यायपूर्ण न होगा क्योंकि केन्द्रीय बैंक के पास सरकारी कोष (Government Balances) रहते हैं वह उन पर कोई सूद नहीं देता और यदि वह अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करे तो वे उसका सामना नहीं टिक सकते। यह अनुचित भी है क्योंकि यदि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो वे केन्द्रीय बैंक के प्रति द्वेषभाव रखने लगेंगे और केन्द्रीय बैंक का नेतृत्व का वे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक (Central Bank) साख (Credit) का ठीक प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सकेगा। साख का नियंत्रण बिना अन्य बैंकों के सहयोग के सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक के पास कुछ ऐसे साधन भी होने चाहिए कि वह व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण कर सके। इसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ होता है कि केन्द्रीय बैंक जिस प्रकार की नीति निर्धारित करे उसे व्यापारिक बैंकों को स्वीकार करना पड़े। तभी वह साख (Credit) का भली प्रकार नियंत्रण कर सकता है और देश के द्रव्य परिमाण (Monetary Standard) को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। केन्द्रीय बैंक किस प्रकार साख का तथा व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण करता है इस पर हम आगे विचार करेंगे। यहाँ हम केन्द्रीय बैंक तथा उस देश की सरकार का क्या संबंध होता है इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank) और सरकार :—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि केन्द्रीय बैंक सरकार की मुद्रा नीति को प्रचलित करने में सहायक होता है इस कारण केन्द्रीय बैंक फिर चाहे वह हिस्सेदारों का बैंक ही क्यों न हो राज्य के आदेशानुसार और उसकी अधीनता में कार्य करता है और सरकार द्वारा निर्धारित नीति को चलाता है। १९२० के उपरान्त बहुत से लेखकों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि केन्द्रीय बैंक सरकार के प्रभाव से मुक्त होना चाहिये और इसी कारण केन्द्रीय बैंकों को हिस्सेदारों का बैंक बनाया गया। किन्तु फिर भी हमें यह न भूल जाना चाहिये कि कोई भी केन्द्रीय बैंक राज्य के आदेशों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। राज्य की नीति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वास्तव में मुद्रा का नियंत्रण करने का काम सरकार का है। हाँ यह आवश्यक है कि राज्य की अर्थ नीति (Financial Policy) के सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंक की सलाह अवश्य ली जाती है और यदि केन्द्रीय बैंक की देश में अधिक प्रतिष्ठा है तो राज्य उसकी सलाह पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान भी देता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के अधिकारी यदि योग्य व्यक्ति हैं तो वह परोक्ष रूप से सरकार की अर्थ नीति को प्रभावित करता है। परन्तु यदि सरकार और केन्द्रीय बैंक (Central Bank) में किसी प्रश्न पर मतभेद हो तो केन्द्रीय बैंक को सरकार द्वारा निर्धारित नीति को स्वीकार करना ही होगा।

आधुनिक काल में सरकार का द्रव्य बाजार (Money Market) पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। क्योंकि सरकार लम्बे समय के लिये ऋण निकालती है और इस प्रकार लम्बे समय के लिये सूर की दर को प्रभावित करती है और सरकारी हुंडियाँ (Treasury Bills) बेच कर थोड़े समय

लिये सूद की दर को प्रभावित करती है। जहाँ विनिमय सरकारी बोध (Exchange Equalisation Fund) होता है जिसका प्रयुक्त विशेष कर सरकारी विभाग ही करता है वहाँ तो सरकार बहुत तरह से द्रव्य बाजार को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में राज्य के आर्थिक कार्य राष्ट्र के एक चौथाई आर्थिक कार्यों के लगभग होते हैं। इनका देश की करसी और साख (Credit) पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि करसी और साख का नियन्त्रण ही केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। अतएव सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी आर्थिक नाति को निर्धारित करने से पूर्व वह केन्द्रीय बैंक से सदैव परामर्श कर ले। कुछ देशों में तो राज्य का केन्द्रीय बैंक से करसी और साख सम्बन्धी विषयों पर परामर्श करना कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। और जहाँ कानून द्वारा सरकार को केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से परामर्श करने पर विवश किया गया है वहाँ इस प्रकार की एक परिपाटी या परम्परा स्थापित हो गई है। केन्द्रीय बैंक सरकार की नीति पर कितना प्रभाव डाल सकेगा यह उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके अधिकारियों की योग्यता पर निर्भर होता है। परन्तु यह समझना भूल होगी कि यदि सरकार शून्य और विचार गलत नीति स्वीकार करे जिससे उसकी साख गिर जावे तो केन्द्रीय बैंक स्वयं अपने आप स्वतन्त्र रूप से द्रव्य तथा साख को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर सकेगा।

सरकार तथा केन्द्रीय बैंक में नीति के सम्बन्ध में मतभेद भी हो सकता है। सरकार के अर्थ विभाग के स्वार्थों तथा केन्द्रीय बैंक के विचारों में भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिये सरकार यदि एक बड़ा ऋण निकालना चाहती है तो स्वभावतः अर्थविभाग सूद की दर को नीचा रखना चाहेगी। उसके विपरीत केन्द्रीय बैंक का यह मत हो सकता है कि देश के आर्थिक हितों के देखते हुए यह आवश्यक है कि सूद की दर को बढ़ाया जावे या कम से कम तना ही रखा जावे जितना कि उस समय है। या फिर सरकार केन्द्रीय बैंक इतना अधिक ऋण लेना चाहती है जितना कि केन्द्रीय बैंक उचित नहीं समझता। इसी प्रकार अर्थनाति के सम्बन्ध में सरकार तथा केन्द्रीय बैंक में मतभेद हो सकता है। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक के अधिकारी सरकार के अर्थ विभाग (Finance Department) को अपने विचारों से सहमत कराने लिए पूरा प्रयत्न करेंगे किन्तु यदि सरकार ने उनकी बात को स्वीकार नया तो केन्द्रीय बैंक को सरकारी नाति के सामने मुकना होगा।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब सरकार और केन्द्रीय बैंक में इस बात पर मतभेद हो कि देश के हित में कौन सी नीति अच्छी है तो पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि दोनों के बीच में उस प्रश्न को लेकर निर्भीकतापूर्वक विस्तृत विचार और वादविवाद हो और सरकार केन्द्रीय बैंक की बात को ध्यान पूर्वक सुने। परन्तु यदि दोनों एक मत न हो सकें तो केन्द्रीय बैंक को सरकारी नीति को स्वीकार करना होगा। अवश्य ही केन्द्रीय बैंक की उस नीति के लिए जिम्मेदारी न होगी।

‘केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के कार्य :—पिछले २५ वर्षों में केन्द्रीय बैंक का संसार के प्रत्येक देश में विकास हुआ है और नीचे लिखे कार्य केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्य माने जाते हैं :—

(१) देश के व्यापार तथा साधारण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करंसी (Currency) का नियंत्रण करना। बैंक इस कार्य को भली भाँति कर सके इसके लिए उसे कागज़ी नोट निकालने का एकाधिकार दे दिया जाता है।

(२) देश की सरकार को बैंकिंग तथा एजेंसी की सुविधाएँ प्रदान करना अर्थात् सरकार के बैंकर का कार्य करना।

(३) देश के व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) के नक़द कोष (Cash Reserves) को रखना।

(४) राष्ट्र के पास कितनी अंतर्राष्ट्रीय करंसी (International Currency) का कोष (Reserve) है उसको रखना और उसका प्रवन्ध करना।

(५) बैंकों का बैंकर बनना, उन्हें स्वीकृत प्रतिभूति (Approved Securities) के आधार पर ऋण देना तथा उनके भुनाये हुए बिलों, प्रामिसरी नोटों, तथा दूसरे व्यापारिक कागज़ पत्रों (Commercial papers) को पुनः भुनाकर (Re-discount) व्यापारिक बैंकों को आर्थिक सहायता देना, बैंकों के अतिरिक्त बिल ब्रोकर तथा आर्थिक संस्थाओं को भी ऊपर बताये गए तरीके से आर्थिक सहायता देना, और अन्तिम ऋण दाता (Lender of the last resort) होने का साधारण उत्तरदायित्व स्वीकार करना।

(६) क्लियरिंग हाऊस अर्थात् समाशोधन गृह (Clearing House) का काम करना ।

(७) व्यापार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए तथा सरकार द्वारा निर्धारित द्रव्य नीति (Monetary policy) को चलाने के उद्देश्य से साख (Credit) का नियन्त्रण करना ।

अब हम इन कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक निखेंगे ।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank) और कागजी नोट निकालने का कार्य — लगभग प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को अपने देश में कागजी नोट निकालने का एकाधिकार प्राप्त है । या तो करसी निकालने का कार्य राज्य का रहा है । परन्तु अब लगभग सभी देशों में धातु के सिक्के (Metallic Coins) राज्य निकालता है किन्तु कागजी नोट (Paper Currency) निकालने का एक मात्र अधिकार केन्द्रीय बैंकों को सौंप दिया है । यह आवश्यक भी है क्योंकि द्रव्य (Money) और साख (Credit) का घनिष्ठ सम्बन्ध है और क्योंकि केन्द्रीय बैंक को साख (Credit) का नियन्त्रण करना पड़ता है और यदि केन्द्रीय बैंक की नोट निकालने का एकाधिकार न दिया जावे तो वे साख का ठीक प्रकार से नियन्त्रण नहीं कर सकते । उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय बैंक देश में वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने नहीं देना चाहता अथवा मूल्य स्तर (Price Level) को गिराना चाहता है तो आवश्यकता इस बात की है कि साख (Credit) को कम किया जावे और द्रव्य को भी कम किया जावे । अब यदि कागजी नोट निकालने का काम केन्द्रीय बैंक नहीं करता तो हो सकता है कि कागजी नोट निकालने वाले अधिकारी, बैंक की नीति के माध्यम से द्रव्य का उपयोग न करें और इस प्रकार नोट अधिक प्रचलित कर दिए जायें । उस दशामें न तो साख (Credit) ही कम की जा सकती है और न वस्तुओं का मूल्य ही घिर सकता है । क्योंकि लोग चेक इत्यादि का उपयोग न करके नोटों से अपना काम चला लेंगे । किसी भी देश में कागजी नोट तथा चेक इत्यादि ही विनिमय के साधन (Medium of Exchange) होते हैं । अतएव केन्द्रीय बैंक को दोनों के नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिए । पिछड़े देशों में तो बिल इत्यादि का चलन कम होता है इस कारण कागजी नोट ही अधिकतर चलन में रहते हैं । अतः उनको निकालने का एकाधिकार (Monopoly) मिलने से बैंक का द्रव्य की पूर्ति (Supply of money) पर नियन्त्रण करने की बहुत सुविधा

हो जाती है। और जो देश व्यापारिक दृष्टि से उन्नत हैं और जहां चेक इत्यादि का बहुत अधिक चलन है वहां केन्द्रीय बैंक साख (Credit) पर नियंत्रण करके द्रव्य पूर्ति (Supply of Money) पर नियंत्रण स्थापित कर ही लेता है। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि बैंक को विदेशी व्यापार (Foreign Trade) की सुविधा के लिए कुछ नोट तो स्वतः निकालने या चलन में से खींचने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि देश में स्वर्ण मान (Gold Standard) प्रचलित है और कोई व्यापारी जिसने विदेश से माल मंगाया है उसे विदेशी व्यापारी को मूल्य चुकाने के लिए विदेशी बिल (Foreign Bill) नहीं मिलता या अत्यधिक मूल्य पर मिलता है तो वह नोट देकर केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से स्वर्ण ले लेगा और स्वर्ण को बेज कर मूल्य चुका देगा। यदि देश में स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) प्रचलित है तो वह व्यापारी केन्द्रीय बैंक को नोट देकर स्वर्ण ले सकता है। भारतवर्ष में कोई भी व्यापारी रिजर्व बैंक को नोट देकर स्टर्लिंग (Sterling) खरीद सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यापारी को जिसने अपना माल बाहर भेजा है सोना या उस देश की करंसी मूल्य रूप में मिलती है तो वह केन्द्रीय बैंक को बेंचकर उसके मूल्य के नोट ले लेता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक को विदेशी व्यापार के कारण कुछ हद तक नोट निकालने पड़ते हैं और कभी-कभी नोटों को सिकके में भुनाना पड़ता है। किन्तु केन्द्रीय बैंक के पास नोट निकालने के तथा चलन में से नोट खींच लेने के लिए और भी साधन और उपाय हैं। उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय बैंक अधिक नोट चलाना चाहता है तो वह व्यापारिक बैंकों द्वारा भुनाये हुए विलों को पुनः भुना कर, उन्हें ऋण देकर या सरकारी प्रतिभूति या सिक्यूरिटी (Securities) को खरीद कर और मूल्य रूप में नोट देकर अधिक नोटों को चलन में ला सकता है। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक नोटों को चलन में कम करना चाहता है तो अपने ऋण को वापस माँग कर ऋण निकालकर, अर्थात् लेकर या सरकारी सिक्यूरिटी को बेंचकर मूल्य रूप में नोट पाता है और उन्हें अपने पास रोक लेता है। इस प्रकार वह नोटों को चलन में से खींच लेता है।

नोटों के निकालने में तीन मुख्य बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं (१) नोट एक प्रकार के हों, बहुत प्रकार के न हों, अर्थात् नोटों के निकालने वाली एक ही संस्था हो। नहीं तो यदि कल्पना कीजिए कि दस रुपये का नोट कई बैंकों द्वारा निकाला जावे उसका साइज, रंग, इत्यादि भिन्न हो तो सर्व साधारण को

बड़ी कठिनाई होगी। केन्द्राय बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार दे देने से यह बात पूरी हो जाती है। (२) दूसरा गुण जो नोटों के चलन में होना चाहिए वह है लोचन (Elasticity)। अधिकतर देशों में यह कानून है कि केन्द्राय बैंक जो नोट निकाले उसका ४० प्रतिशत स्वर्ण कागजी मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve) में रखे, और शेष व्यापारिक बिल, (Trade Bills) सरकारी सिम्पूरिटि, या अन्य व्यापारिक कागज पत्र (Commercial paper) में हो। इस प्रकार यदि अधिक नोटों की आवश्यकता हो तो केन्द्रीय बैंक उन नोटों के मूल्य का ४० प्रतिशत स्वर्ण कागजी मुद्रा कोष में रखकर भेट छाप सकता है। इस प्रकार नोटों के निकालने में लोचन (Elasticity) उत्पन्न की जा सकती है। (३) तीसरा गुण जो कि नोट के चलन में होना चाहिए वह है सुरक्षा (Security)। इसके लिए ४० प्रतिशत स्वर्ण कागजी मुद्रा कोष में रखा जाता है। (कमी-कमी इस ४० प्रतिशत में स्वर्ण के अतिरिक्त विदेशी करसी भी सम्मिलित होती है) शेष कोष व्यापारिक बिल या सरकारी सिम्पूरिटियों के रूप में रखा जाता है।

२. सरकार के बैंकर तथा आर्थिक एजेंट का काम करना :— सरकार के पास जो भी कोष (Funds) होता है वह केन्द्रीय बैंक के पास जमा रहता है। सरकार जा खर्च करती है उसको केन्द्रीय बैंक ही चुकाता है। जब सरकार कोई ऋण लेती है तो केन्द्रीय बैंक ही उसको निकालता और बेंचता है उस पर निश्चित रूप से सरकार की ओर से सद्देना है। एवरे में वह सरकारी बर्ज का सारा मनब करता है। कमी-कमी जब सरकार को थोड़े समय के लिए रुपये की आवश्यकता होती है तो केन्द्रीय बैंक सरकार को थोड़े समय के लिये ऋण देता है। उदाहरण के लिए कमी कमी सरकार को कुछ रुपये की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि व्यय अधिक हो गया हो और करों (Taxes) से उस समय तक अधिक रुपया वसूल न हो पाया हो। ऐसी दशा में सरकार केन्द्रीय बैंक से थोड़े समय के लिए ऋण ले लेती है और जब करों (Taxes) से रुपया वसूल हो जाता है तो वापस कर देती है। इससे लिए केन्द्रीय बैंक सरकार को सीधे ऋण दे देता है अथवा सरकारी हुजियों (Treasury Bills) को भुना देता है। किन्तु यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि केन्द्रीय बैंक को सरकार को अधिक लम्बे समय के लिए ऋण कर्दारि न देना चाहिए केवल थोड़े समय के लिए देना चाहिए और ऋण की रकम भी बहुत अधिक न होनी चाहिए, सरकार की वार्षिक आय का एक निश्चित अंश ही होना चाहिए।

- देश के व्यापारिक बैंकों के नक़द कोष (Cash Reserve) को रखना :—प्रत्येक देश में व्यापारिक बैंक अपने नक़द कोष (Cash Reserve) का एक भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा कर देते हैं। कुछ देशों में तो वे कानून द्वारा ऐसा करने के लिए विवश हैं और कहीं-कहीं इस प्रकार की परिपाटी बन गई है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने नक़द कोष का एक भाग केन्द्रीय बैंक में जमा करता है। इंग्लैंड तथा योरोप के अन्य देशों में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) निश्चित न्यूनतम नक़द कोष केन्द्रीय बैंक में जमा करें। किन्तु वहाँ ऐसी सुदृढ़ परम्परा है कि प्रत्येक बैंक नक़द कोष का एक भाग केन्द्रीय बैंक के पास अवश्य रखता है। १९२० के उपरान्त जो भिन्न-भिन्न देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना हुई वहाँ यह नियम बना दिया गया कि प्रत्येक बैंक को एक निश्चित न्यूनतम नक़द कोष (Minimum Cash Reserve) केन्द्रीय बैंक के पास रखना ही होगा। केन्द्रीय बैंक के पास नक़द कोष रखने से नीचे लिखे लाभ हैं :—

(अ) व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने नक़द कोष को केन्द्रीय बैंक में जमा करने का परिणाम यह होता है कि बैंकों की तरलता (Liquidity) में वृद्धि होती है और बैंकों पर मांग होने के समय वे इस कोष पर निर्भर हो सकते हैं। देश के सभी बैंकों का नक़द कोष (Cash Reserve) जब एक स्थान पर इकट्ठा होता है तो प्रत्येक बैंक कम नक़द कोष रख कर भी जमा करने वालों की मांग को पूरा कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध हो जाता है।

(ब) केन्द्रीय बैंक के पास सभी बैंकों का नक़द कोष होने से वह उन बैंकों की साख निर्माण (Creation of Credit) शक्ति को प्रभावित कर सकता है। जब बैंक का नक़द कोष बढ़ जाता है तो उससे साख (Credit) के विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है और जब नक़द कोष घट जाता है तो साख को संकुचित करने की आवश्यकता होती है। यही नहीं साख के निर्माण को प्रभावित करने के लिये व्यापारिक बैंकों को जितने प्रतिशत नक़द कोष (Cash Reserve) रखने की आवश्यकता होती है उसमें भी केन्द्रीय बैंक हेर-फेर कर देता है और इस प्रकार साख के निर्माण पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है।

(स) इन लाभों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के नक़द कोष को केन्द्रीय बैंक

बैंक में रखने का एक यह लाभ भी है कि उसके पास अपेक्षाकृत तरल लेनी (Liquid Assets) बहुत अधिक राशि में इकट्ठी हो जाती है।

राष्ट्र के पास जितना अन्तर्राष्ट्रीय करेंसी (International Currency) का कोष है उसको सुरक्षित रखना और उसका प्रयोजन करना :—यह तो हम पहले ॥ कह चुके हैं कि केन्द्रीय बैंक नोट निकालता है और उतनी मुद्रा के लिए स्वर्ण कोष रखता है। यदि देश में स्वर्णमान (Gold Standard) प्रचलित होता है तब तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्रीय बैंक की नोट देकर निश्चित दर पर स्वर्ण ले ले। इस प्रकार चाहे व्यवहार में या व्यापार में कागजी नोटों से ही लेन देन होता रहे किन्तु वास्तव में स्वर्ण ही प्रमाणिक द्रव्य (Standard Money) होता है, क्योंकि देश में जो भी कागजी मुद्रा तथा अन्य धातु के प्रिके होते हैं उनका सम्पूर्ण स्वर्ण से होता है और कोई भी व्यक्ति नोटों के बदले केन्द्रीय बैंक से स्वर्ण पा सकता है। अतएव जब देश में स्वर्ण मान (Gold Standard) होता है तब तो विशेष रूप से केन्द्रीय बैंक को मयेष्ट स्वर्ण कोष (Gold Reserve) रखना पड़ता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर जनता नोट के बदले स्वर्ण मांग सकती है। साधारण स्थिति में जनता नोटों को स्वर्ण में नहीं बदलती किन्तु यदि देश में विदेशों से आयात (Import) अर्थात् माल आधिक आया ॥ और निर्यात (Export) कम हुआ है तो व्यापारी अपनी विदेशी देनदारी (Foreign Debt) को चुकाने के लिये केन्द्रीय बैंक से स्वर्ण लेकर विदेशों को भेज देते हैं। अस्तु स्वर्ण मान (Gold Standard) के होते तो केन्द्रीय बैंक को अपने नोटों को स्वर्ण में बदलने का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिये मयेष्ट स्वर्ण कोष रखना ही पड़ता है। किन्तु जब देश में स्वर्ण मान (Gold Standard) प्रचलित नहीं होता तब भी केन्द्रीय बैंक को नोटों की मुद्रा के लिये कुछ (४० प्रतिशत) स्वर्ण तो रखना ही पड़ता है। —

१९३१ के उपरान्त सत्तर के क़िस्तों देश में भी स्वर्ण मान प्रचलित नहीं है और लगभग सभी देशों में कागजी मुद्रा प्रमाण (Paper Currency Standard) प्रचलित है अर्थात् नोटों का स्वर्ण में नहीं बदला जा सकता। कागजी मुद्रा (Paper Currency) ही प्रमाणिक द्रव्य (Standard Money) होता है। किन्तु विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए प्रत्येक देश अपनी करेंसी और अन्य देशों की करेंसी के आस्पास मूल्य को निर्धारित कर देता है। इसे विदेशी विनिमय दर

(Foreign Exchange Rates) कहते हैं। केन्द्रीय बैंक इस विनियम दर को स्थायी बनाने रखने का प्रयत्न करता है और इस उद्देश्य से अन्य देशों की करेंसी का कोष अपने पास रखता है। जब देश के व्यापार का संतुलन (Balance of Trade) देश के विरुद्ध होता है अर्थात् विदेशों से माल अधिक मँगाया गया और कम माल भेजा गया तो केन्द्रीय बैंक निश्चित दर पर उन देशों की करेंसी व्यापारियों को बेच देगा। व्यापारी नोट देकर विदेशों की करेंसी केन्द्रीय बैंक से निर्धारित दर पर पा सकेंगे। जब देश से निर्यात अधिक होता है अर्थात् अधिक माल बाहर भेजा जाता है और कम मँगाया जाता है तो देश के व्यापारियों के पास विदेशी करेंसी अधिक आ जाती है, किन्तु विदेशी करेंसी तो साधारण कारखानों में देश में चल नहीं सकती। अस्तु वे विदेशी करेंसी को निर्धारित दर पर केन्द्रीय बैंक को बेच देते हैं और नोट ले लेते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक अपने देश की करेंसी की विनियम दर (Exchange Rates) का नियंत्रण करता है और उसको स्थायित्व प्रदान करता है। परन्तु ऐसा करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी (International Currency) का कोष रखना पड़ता है।

बैंकों का बैंकर बनना (To act as Banker's Bank) :—
 केन्द्रीय बैंक बैंकों द्वारा भुनाये हुए या खरीदे हुए बिलों, हुंडियों, प्रामिसरी नोटों या अन्य व्यापारिक कागज़ पत्र को पुनः भुनाता है और इस प्रकार व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर रुपया देता है या फिर स्वीकृति प्रतिभूति (सिफ्यूरिटी) पर उन्हें ऋण देता है। केन्द्रीय बैंक का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा केन्द्रीय बैंक बैंकों को साख (Credit) देता है और अन्तिम ऋणदाता बनाने का कार्य करता है। केन्द्रीय बैंक के इस कार्य से देश की साख पद्धति (Credit System) ठीक प्रकार से चलती है और उसमें कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। अन्यथा यदि बैंकों को साख की आवश्यकता हो और उन्हें साख न मिले तो उन्होंने अपने ग्राहकों को जो साख दे रखी है उसे संकुचित करना पड़े इससे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़े बिना न रहे। यही नहीं केन्द्रीय बैंक की मितीकाटे की दर (Discount Rate) जिस पर वह बैंकों के बिल भुनाता है साख पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय बैंक मितीकाटे की दर (Discount Rate) को ऊँचा कर देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यापारिक बैंकों को केन्द्रीय बैंक से अधिक सूद

पर साख (Credit) मिलेगी । अस्तु उन्हें भी अपने ग्राहकों से अधिक पद लेना होगा । दूसरे शब्दों में द्रव्य बाजार (Money Market) में सूद की दर ऊँची उठ पावेगी और साख समुचित होगी अर्थात् कम मात्रा ही जायगा । इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक मित्रीकाटे की दर घटा देता है तो साख का विस्तार होगा अर्थात् साख का बहुत अधिक निर्माण होगा । इस प्रकार मित्रीकाटे की दर को घटा बढ़ा कर केन्द्रीय बैंक साख के निर्माण पर गहरा प्रभाव डालता है ।

अधिकतर केन्द्रीय बैंक केवल बैंकों से ही कारबार करते हैं व्यक्तियों से नहीं करते । केवल बैंक और इंगलैण्ड बैंकों से कारबार न कर के बट्टा गृह (Discount Houses) से कारबार करता है । अधिकतर केन्द्रीय बैंक प्रथम भेखी के व्यापारिक बिल को गिनकी अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होती स्वीकार करते हैं । किन्तु कृषि बिल (Agricultural Bills) के समय में तनिक छूट दी जाती है । कृषि बिल ६ से ६ महीने तक के लिए स्वीकार कर लिए जाते हैं । भारत का रिजर्व बैंक ६ महीने की अवधि के कृषि बिलों को स्वीकार कर सकता है । यह बात ध्यान में रखने की है केन्द्रीय बैंक उसी व्यापारिक कागज (Commercial paper) को स्वीकार करता है जो कि तरल (Liquid) हो और जो स्वतः अवधि के समाप्त होने पर रोकड़ (Cash) में परिणत हो जावे । क्योंकि यदि ऐसा नहीं होमा तो केन्द्रीय बैंक का कोष (Fund) घटकर जावेगा और यह देश में साख का नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जावेगा । इसी कारण केन्द्रीय बैंक जिस प्रकार का देनी (Assets) के आधार पर बैंकों को ऋण देता है वह देनी (Assets) ऐसी हानी चाहिये कि शीघ्र ही नकदी में परिणत की जा सके । केन्द्रीय बैंक ऐसा देनी के विरुद्ध ऋण नहीं देता है जो शीघ्र ही नकदी में परिणत न की जा सकेगी । केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य व्यापारियों को ऋण देना नहीं है किन्तु साख का नियन्त्रण करना है ।

क्लियरिंग हाऊस अर्थात् समाशोधन गृह (Clearing House) का काम करना — केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिये क्लियरिंग हाऊस का काम करता है । प्रत्येक बैंक केन्द्रीय बैंक पर चेक काट कर अपनी देनदारी को चुकाता है । यदि किसी दिन किसी बैंक को क्लियरिंग हाऊस से रुपया लेना होता है तो क्लियरिंग हाऊस केन्द्रीय बैंक पर उसके पक्ष में चेक काट देता है ।

व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर साख

(Credit) का नियंत्रण करना और सरकार द्वारा निर्धारित द्रव्य को चलाना :—व्यापार की आवश्यकता को पूरा करने के लिये केन्द्रीय बैंक साख (Credit) का नियंत्रण करता है। यदि व्यापार के लिये अधिक साख की आवश्यकता होती है तो वह साख (Credit) का विस्तार करता है और यदि व्यापार को कम साख की आवश्यकता होती है तो साख को संकुचित कर देता है। केन्द्रीय बैंक यह कार्य राष्ट्र के आर्थिक हितों की ध्यान में रख कर करता है। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय बैंक देश में द्रव्य की पूर्ति (Money Supply) का भी नियंत्रण करता है। वह जितने द्रव्य की व्यापार के लिये आवश्यकता समझता है उतना निकालता है। यदि किसी समय अधिक द्रव्य की आवश्यकता होती है तो अधिक द्रव्य जनता को देता है नहीं तो द्रव्य (Money) को चलन में से खींच लेता है। केन्द्रीय बैंक राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ाने के उद्देश्य से करंसी तथा साख (Credit) दोनों का नियंत्रण करता है। परन्तु क्योंकि बैंकों द्वारा निर्माण की हुई साख (Credit) ही विनिमय (Exchange) अर्थात् व्यापार का मुख्य माध्यम है और द्रव्य (Money) का उसकी अपेक्षा बहुत कम उपयोग होता है इस कारण साख का नियंत्रण ही केन्द्रीय बैंक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक किस प्रकार साख (Credit) तथा द्रव्य (Money) का नियंत्रण करता है यह आगे के परिच्छेद में हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे।

अध्याय ८

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख (Credit) तथा द्रव्य (Money) का नियन्त्रण

सब से यह है कि केन्द्रीय बैंक का यह कार्य सग से अधिक महत्वपूर्ण है और उसके अन्य सब कार्य इससे सम्बन्धित हैं। पिछले वर्षों में क्रमशः व्यापार की उन्नति के साथ-साथ सभी देशों में द्रव्य (Money) की अवेक्षा साख (Credit) व्यापार का मुख्य माध्यम बन गया। आज व्यापारी तथा सर्वसाधारण जितने चेक इत्यादि का उपयोग अपने लेन देन में करते हैं उतना सिक्के या कागजी नोटों का नहीं करते। यदि पिछड़े देशों को छोड़ दें तो चेक इत्यादि का उपयोग नोटों तथा सिक्कों से दस गुने से भी अधिक होता है। अब हमें, भारत में भी चेक का उपयोग बढ़ रहा है। और क्योंकि साख (Credit) का वस्तुओं के मूल्य पर तथा व्यापार पर प्रभाव पड़ता है इस कारण उसका नियन्त्रण करना आवश्यक हो जाता है।

साख तथा द्रव्य नियन्त्रण के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। देश की करसी की विनिमय दर (Exchange rates) को स्थायित्व प्रदान करना और देश के अन्दर मूल्य स्तर (Price Level) को स्थायित्व प्रदान करना अर्थात् जल्दी जल्दी मूल्य स्तर को न बदलने देना। १८१७ से १९१४ तक तथा सौमा तक १९२५ से १९३१ तक केन्द्रीय बैंक देश की करसी की विनिमय दर (Exchange rates) को स्थायित्व प्रदान करना अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण समझने में, इस कारण साख का नियन्त्रण इसी उद्देश्य से किया जाता था। उस समय सभी देशों में यह धारणा प्रचलित थी कि विनिमय दर का स्थायित्व अन्तर्ग्राहीय विश्वास को बनाये रखने तथा अन्तर्ग्राहीय व्यापार को बढ़ाने के लिये आवश्यक है, तथा अन्तर्ग्राहीय व्यापार की वृद्धि तथा उन्नति में ही सबी की आर्थिक उन्नति और हित छिपा हुआ है। आज भी बहुत से अग्रगण्य तथा बैंक इसी मत के हैं कि विनिमय दर के स्थायी रहने से प्रत्येक देश को लाभ है और उनकी आर्थिक उन्नति होती है।

१९३१ के उपरान्त सवार के सब देशों ने स्वर्ण मान (Gold

Standard) को छोड़ दिया और सब से एक बहुत बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री तथा बैंकर इस मत को स्वीकार करने लगे हैं कि केन्द्रीय बैंक के साख नियंत्रण का उद्देश्य मुख्यतः देश के भीतर मूल्य-स्तर (Price Level) को स्थायित्व प्रदान करना है। उनका कहना है कि यदि विनिमय दर (Exchange rates) तथा देश के भीतर मूल्य-स्तर (Price-Level) को एक साथ स्थायित्व (Stability) प्रदान करना असम्भव हो तो केन्द्रीय बैंक को मूल्य-स्तर को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि उनका कहना है कि देश के अन्दर मूल्य-स्तर के घटने बढ़ने से देश के अन्दर आर्थिक संबंधों में बड़ी गड़बड़ फैल जाती है। उदाहरण के लिए यदि मूल्य-स्तर (Price-Level) ऊँचा हो जाता है तो उत्पादकों (Producers) को अधिक लाभ होने लगता है तथा उपभोक्ताओं (Consumers) को हानि होती है। जिन्होंने ऋण लिया है उनका ऋण भार बहुत हल्का होता है और लेनदारों (Creditors) जिन्होंने ऋण दिया है उन्हें घाटा होता है। साथ ही निश्चित वेतन वालों का वास्तविक वेतन (Real wages) बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार जब मूल्य-स्तर घटने लगता है तो उत्पादकों को हानि होने लगती है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, ऋण लेने वाले का भार बढ़ जाता है और ऋण देने वाले को लाभ होता है तथा निश्चित वेतन या मज़दूरी वालों की वास्तविक मज़दूरी बढ़ जाती है। इससे उद्योग-धंधों तथा व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन लोगों का यह भी मत है कि जब विनिमय दर (Exchange Rates) को स्थायित्व प्रदान किया जाता है तो देश अन्य देशों की द्रव्य नीति (Monetary Policy) के ऊपर निर्भर हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि संयुक्तराज्य अमेरिका की करेंसी अर्थात् डालर से अन्य देशों ने अपनी विनिमय दर निश्चित कर दी है तो यदि संयुक्तराज्य अमेरिका मुद्रा प्रसार (Currency Inflation) अथवा मुद्रा संकोचन (Currency Deflation) की नीति अपनाता है तो इसका प्रभाव उन देशों पर पड़े बिना नहीं रह सकता जिन्होंने अपनी करेंसी की विनिमय दर (Exchange Rates) को डालर से निश्चित कर दिया है। इस कारण उनका मत है कि केन्द्रीय बैंक की साख नियंत्रण (Control of credit) का उद्देश्य देश के अन्दर मूल्य-स्तर को स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए। देश के अन्दर मूल्य-स्तर (Price-Level) के स्थायी होने से देश अन्य देशों की द्रव्य सम्बंधी नीति के प्रभाव से स्वतंत्र हो जावेगा।

रहा देश की करसी की विनिमय दर का प्रश्न वह आवश्यकता पड़ने पर घटा बढ़ा कर ठीक कर ली जावेगी।

इन दोनों मतों के विरुद्ध एक तीसरा मत भी है। उस मत के लोगों का कहना है कि विनिमय दर का स्थायी होना अथवा मूल्य-स्तर (Price Level) का स्थायी होना आवश्यक है। परन्तु उससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि देश में आर्थिक स्थायित्व (Economic Stabilisation) स्थापित हो और देश के उद्योग धंधे तथा व्यापार में स्थिरता न आवे। यह जो आर्थिक मंदी (Economic Depression) आती है जिससे उत्पादन (Production) को घटा लगता है, उद्योग धंधे और व्यापार ठप्प सा हो जाता है, बेकारी फैल जाती है, अत्यन्त कष्टसाध्य होती है और देश की आर्थिक गति को रोक देती है। इस कारण देश की साख तथा द्रव्य का नियंत्रण इस उद्देश्य को रखा कर किया जावे कि आर्थिक मंदी (Economic Depression) को बचाया जा सके।

दूसरे महायुद्ध के उपरान्त (१९४५) विद्वानों का एक चौथा मत भी इस समय में हमारे सामने आया है। वह मत यह है कि द्रव्य तथा साख संबंधी नीति का नियंत्रण का उद्देश्य अन्तराष्ट्रीय विनिमय दर (International exchange rates) को जहाँ तक हो सके स्थायित्व प्रदान करना, देश में बेकारी को दूर करना तथा देश की वास्तविक आय को बढ़ाना है। एक प्रकार से इस मत के लोग पहले तथा तीसरे उद्देश्यों को एक में मिलाने के पक्ष में हैं। अन्तराष्ट्रीय द्रव्य कोष (International Monetary Fund) जो दूसरे महायुद्ध के उपरान्त बना उसका उद्देश्य यही है। अभी हाल में संयुक्तराज्य अमेरिका इत्यादि देशों ने इस बात की घोषणा की है कि उनकी द्रव्य नीति तथा साख नीति (Monetary and Credit Policy) का उद्देश्य देश की बेकारी को दूर करना तथा देश की आय को बढ़ाना है।

केन्द्रीय बैंक द्रव्य और साख पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करता है :—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी देश में द्रव्य (Money) और बैंकों की डिपॉजिट ही विनिमय (Exchange) का माध्यम होता है। अर्थात् दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार तथा लेन-देन के लिए जो भी विनिमय का साधन या द्रव्य हमें मिलता है वह करसी और डिपॉजिट के द्वारा ही मिलता है और बैंक साख (Credit) देकर डिपॉजिट

निर्माण करते हैं। केन्द्रीय बैंक को कागज़ी नोट निकालने का एकाधिकार प्राप्त होता है, इस कारण भुगतान के इस माध्यम का जहाँ तक प्रश्न है केन्द्रीय बैंक इसका सरलता से नियंत्रण कर सकता है। जहाँ स्वर्ण मान (Gold Standard) होता है वहाँ लोगों को यह छूट रहती है कि वे सोना देकर कागज़ी नोट ले लें। उस दशा में केन्द्रीय बैंक का कागज़ी नोटों के निकालने पर सीधा नियंत्रण तो नहीं रहता किन्तु बैंक अन्य उपायों से उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय बैंक यदि चाहता है कि अधिक नोट निकाले तो वह बाजार में सिक्कूरिटियों को खरीदने लगेगा। उसका परिणाम यह होगा कि सर्व साधारण को सिक्कूरिटियों के मूल्य स्वरूप कागज़ी नोट दिए जावेंगे और नोट चलन में आ जावेंगे। यदि केन्द्रीय बैंक नोटों को चलन में से कप्त करना चाहेगा तो वह सिक्कूरिटियों को बेचने लगेगा और इस प्रकार उसके पास मूल्य रूप में नोट आ जावेंगे जिनको वह चलन से निकाल कर रख लेगा। इसी प्रकार अन्य तरीकों से भी केन्द्रीय बैंक कागज़ी मुद्रा का नियंत्रण करता है।

किन्तु आज के समाज में अपनी देनदारी का भुगतान करने का मुख्य माध्यम व्यापारिक बैंकों की डिपाजिट है। यह तो इस पहले ही कह चुके हैं कि व्यापारिक बैंक धन देकर डिपाजिट निर्माण करते हैं, अस्तु केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित हुई साख (Credit) पर नियंत्रण स्थापित करना है।

यह तो हम ऊपर कह चुके हैं कि व्यापारिक बैंक ही साख (Credit) का निर्माण करते हैं अतएव यदि केन्द्रीय बैंक देश में साख का नियंत्रण करना चाहता है तो उसे व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण करना होगा। बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने में केन्द्रीय बैंक को दो बातों से बड़ी सहायता मिलती है। एक तो यह कि बैंकों की साख निर्माण करने की शक्ति उनके नक़द कोष (Cash Reserves) पर निर्भर होती है और दूसरी यह कि केन्द्रीय बैंक नक़दी को आसानी से घटा-बढ़ा सकता है। इस प्रकार वह बैंकों के साख निर्माण की शक्ति को नियंत्रित कर देता है।

बैंकों का नक़द कोष (Cash Reserve) :—उस नक़दी को कहते हैं जो व्यापारिक बैंकों के पास रहती है तथा उस रुपये को कहते हैं जो केन्द्रीय बैंक में उनके हिसाब में जमा रहता है। अस्तु व्यापारिक बैंकों के नक़द कोष (Cash Reserves) में सिक्के कागज़ी नोट तथा केन्द्रीय बैंक के पास

जमा किये हुए रुपये होते हैं। इसमें सिक्के महत्वहीन हैं और कागज़ी नोट भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। कागज़ी नोट तथा सिक्के व्यापारिक बैंकों के लिए उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार एक बड़े दूकानदार के लिए छोटे सिक्के एक आना, दो आना इत्यादि, जिससे माल बँचने में फ़ायदा न हो। अस्तु बैंकों का नक़द कोष मुख्यतः केन्द्रीय बैंक के पास जमा किया हुआ कोष होता है। ब्रिटेन इत्यादि उन्नतिशील देशों में तो व्यापारिक बैंक मुख्यतः केन्द्रीय बैंक के पास अपने जमा किए हुए रुपये पर ही निर्भर रहते हैं। अपने पास नोट या सिक्के तो केवल काम चलाने के विचार से बहुत थोड़ी मात्रा में रखते हैं। हाँ भारत तथा अन्य देशों में अवश्य व्यापारिक बैंक अपने पास भी यथेष्ट नक़दी रखते हैं। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि व्यापारिक बैंक नक़द कोष (Cash Reserve) को जितना भी कम हो सकता है उतना कम रखते हैं क्योंकि उस पर उन्हें कोई लाभ नहीं होता। परन्तु कानून के अनुसार अथवा परिपाटी के अनुसार उन्हें अपनी डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत नक़द कोष (Cash Reserve) के रूप में अर्थात् केन्द्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। हम यह भी कह चुके हैं कि व्यापारिक बैंक क्रेडिट (Credit) देकर डिपॉजिटों का निर्माण करते हैं। किन्तु उनके डिपॉजिट निर्माण करने की शक्ति उनके नक़द कोष (Cash Reserve) पर निर्भर होती है। दूसरे अर्थों में यदि बैंक अपनी डिपॉजिटों को बढ़ाना चाहता है तो उसके पास अधिक नक़द कोष होना चाहिए। जितना ही अधिक नक़द कोष अर्थात् केन्द्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों का दया जमा होया उतनी ही अधिक डिपॉजिट बैंक निर्माण कर सकेंगे। अस्तु यदि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को विवश कर सके कि वह कितना दया उसके पास जमा रखें तो वह उनके द्वारा निर्माण का जाने वाला डिपॉजिटों पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नक़द कोष का नियंत्रण करके उनका डिपॉजिटों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है।

केन्द्रीय बैंक किस प्रकार नक़दी पर नियंत्रण स्थापित करता है:—
केन्द्रीय बैंक तीन प्रकार से व्यापारिक बैंक के उसके पास जमा किए हुए रुपये पर नियंत्रण स्थापित करता है (१) बाजार में सरकारी सिक्यूरिटियों (प्रतिभूति) तथा सरकारी हुजियों (Treasury Bills) को खरीदकर, (२) बाजार से सोना खरीद कर, (३) और सरकारी खर्च को इस

प्रकार नियंत्रित करके कि सरकार को जो कर रूप में आमदनी हो वह उसके खर्च से कम रहे।

बाज़ार में सरकारी हुंडियों और सरकारी सिक्कूरिटियों को खरीदने का परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय बैंक को उनके मूल्य को जनता, बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को चुकाना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्रीय बैंक जो चेक उन व्यक्तियों, बैंकों तथा संस्थाओं को मूल्य रूप में देगा वे चेक अन्त में व्यापारिक बैंकों के पास आ जावेंगे और वह उतना रुपया केन्द्रीय बैंक से वसूल करेंगे। केन्द्रीय बैंक उतना रुपया उन बैंकों के हिसाब में जमा कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारिक बैंकों की जो केन्द्रीय बैंक के पास डिपोजिट (जमा) है उसमें वृद्धि होगी अर्थात् उनके नकद कोष (Cash Reserves) में वृद्धि हो जावेगी और व्यापारिक बैंक अधिक साख (Credit) देकर अधिक डिपोजिटों का निर्माण करेंगे। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि डिपोजिटों का उपयोग किसी देनदारी का भुगतान करने में द्रव्य (Money) के समान होता है और जहाँ तक विनिमय के माध्यम (Medium of exchange) का प्रश्न है वे कागज़ी नोटों या सिक्कों का वैसा ही कार्य करते हैं। अतएव दूसरे शब्दों में डिपोजिटों की वृद्धि होने से द्रव्य में वृद्धि हो जावेगी।

जब बैंक बाजार में सोना खरीदेगा तो भी वही परिणाम होगा जो सरकारी हुंडियों के खरीदने या सरकारी सिक्कूरिटियों के खरीदने से हुआ। सोना खरीदने पर उसके मूल्य स्वरूप केन्द्रीय बैंक उन व्यापारियों को चेक देगा जो वे अपने बैंकों का केन्द्रीय बैंक से वसूल करने के लिये दे देंगे। व्यापारिक बैंक उन चेकों को केन्द्रीय बैंकों के पास भेजेंगे और केन्द्रीय बैंक उतना रुपया व्यापारिक बैंकों के हिसाब में जमा कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यापारिक बैंकों का नकद कोष बढ़ जावेगा और वे साख (Credit) देकर अधिक डिपोजिट का निर्माण करेंगे, दूसरे शब्दों में द्रव्य (Money) की वृद्धि हो जावेगी।

जब कि केन्द्रीय बैंक सरकार के खर्चों की इस प्रकार व्यवस्था करता है कि जितनी सरकारी कर (Tax) से उन दिनों आमदनी होती है उससे कहीं अधिक सरकारी खर्च होता है तो इसका परिणाम पहले दोनों तरीकों से विलकुल मिलता-जुलता होता है। इसका परिणाम यह होगा कि व्यापारिक बैंकों के ग्राहकों (जनता) को करों (Taxes) के रूप में जितना राया

सरकार को देना पड़ता है वह उससे कहीं कम होता है जो उन्हें सरकार से वेतन तथा सरकार को बैंचे माल के रूप में मिलता है। इसका फल यह होगा कि व्यापारिक बैंकों की केन्द्रीय बैंको के पास जो डिपॉजिट है वह बढ़ जावेगी। क्योंकि जनता अपने करों (Taxes) को चेकों द्वारा देगी और वे चेक व्यापारिक बैंकों के ऊपर काटे गए होंगे। इन चेकों के कारण व्यापारिक बैंकों की केन्द्रीय बैंकों के पास रखी हुई डिपॉजिट (जमा) कम हो जावेगी। किन्तु साथ ही सरकार के अत्यधिक व्यय के फल स्वरूप जनता की केन्द्रीय बैंक पर जो चेक मिलेंगे उनको बसूल करने के लिये वे उन्हें अपने बैंकों को दे देंगे। व्यापारिक बैंक उन चेकों को केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से बसूल करेंगे और केन्द्रीय बैंक उठना हुआ व्यापारिक बैंकों के हिसाब में जमा कर देगा। क्योंकि करों (Taxes) की आमदनी से सर्व अधिक किया गया है इसलिये व्यापारिक बैंकों का केन्द्रीय बैंक के पास डिपॉजिट (जमा) में वृद्धि हो जावेगा अर्थात् उनके नकद कोष (Cash Reserve) में वृद्धि होगी और वे अधिक डिपॉजिटों का निर्माण करेंगे। दूसरे शब्दों में द्रव्य (Money) की वृद्धि हो जावेगी।

इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक सरकारी भिन्सूरिटियों, सरकारी हुजियों (Treasury Bills) को बैंचे, सोने को बैंचे, अथवा सरकारी व्यय की इस प्रकार व्यवस्था करे कि करों (Taxes) इत्यादि से होने वाली आप सरकारी व्यय से कहीं अधिक हो तो ऊपर बतलाये हुए परिणाम के सर्वथा विरुद्ध परिणाम होगा। ऊपर लिखे कार्यों का फल यह होगा कि जनता की केन्द्रीय बैंक की सरकारी भिन्सूरिटियों, सोने अथवा सरकारी हुजियों का मूल्य चुकाने के लिए अपने बैंकों पर चेक (Cheque) देने होंगे। यदि सरकारी व्यय की अपेक्षा करों (Taxes) से होने वाली आमदनी अधिक है तो भी जनता करों (Taxes) की अपने बैंकों पर चेक काट कर और केन्द्रीय बैंक का देकर चुकावेगी। फल यह होगा कि व्यापारिक बैंकों को यह सारा स्पर्श केन्द्रीय बैंक को चुकाना होगा। किन्तु व्यवहार में इसका परिणाम केवल यही होगा कि व्यापारिक बैंकों का केन्द्रीय बैंक में रखा जमा है उसमें कमी हो जावेगी। इस प्रकार जब व्यापारिक बैंकों के नकद कोष (Cash Reserve) में कमी हो जावेगी तो वे अपने नकद कोष को बढ़ाने के लिए दिए हुए ऋणों को वापस माँगेंगे तथा मास देकर नई डिपॉजिटों का निर्माण करना रोक देंगे या बहुत कम कर देंगे। दूसरे शब्दों में द्रव्य (Money) की कमी हो जावेगी।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को जिस प्रकार चाहे घटा बढ़ा कर द्रव्य राशि (Quantity of money) को नियंत्रित कर सकता है। किन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता भी है। व्यापारिक बैंक बढ़ा बाजार (Discount Market) के द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास ऋण लेने के लिए पहुँच सकते हैं और इस प्रकार केन्द्रीय बैंक से अपने भुनाये हुए विलों को पुनः भुना कर (Re-discount) अपने नकद कोष को पूरा कर सकते हैं। व्यापारिक बैंक दो में से एक काम कर सकते हैं। उन देशों में जैसे इंग्लैंड जहाँ बढ़ा बाजार (Discount Market) उन्नत अवस्था में है और जहाँ व्यापारिक बैंक व्यापारिक विलों को सीधे न भुनाकर बढ़ा बाजार के ब्रोकरों (दलालों) को ऋण दे देते हैं और वे व्यापारिक विलों को भुनाते हैं, वहाँ व्यापारिक बैंक बढ़ा बाजार को दिए हुए ऋण को वापस माँग सकते हैं। इसका फल यह होगा कि बढ़ा बाजार उन विलों को बैंक आफ इंग्लैंड से भुनाकर ऋण प्राप्त करेगा और व्यापारिक बैंकों को उनका ऋण वापस कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि व्यापारिक बैंकों की बैंक आफ इंग्लैंड (इंग्लैंड का केन्द्रीय बैंक) में डिपॉजिट बढ़ जावेगी अर्थात् व्यापारिक बैंकों के नकद कोष में वृद्धि होगी। जहाँ बढ़ा बाजार उन्नत अवस्था में नहीं होता है वहाँ व्यापारिक बैंक स्वयं सीधे व्यापारिक विलों को भुनाते हैं। अस्तु यदि केन्द्रीय बैंक उनके नकद कोष को घटाने की युक्ति करे तो वे अपने भुनाए हुए विलों का लेकर केन्द्रीय बैंक के पास पहुँच सकते हैं और उन विलों को केन्द्रीय बैंक से पुनः भुना कर उससे ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने नकद कोष को घटने से बचा सकते हैं। यदि ऐसा हो तब तो केन्द्रीय बैंक (Central Bank) व्यापारिक बैंकों के नकद कोष का नियंत्रण करने में असमर्थ सिद्ध हो और द्रव्य को घटा बढ़ा न सके। परंतु जब व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के पास सीधे या बढ़ा बाजार (Discount Market) के द्वारा ऋण लेने पहुँचते हैं तो केन्द्रीय बैंक की बढ़ा दर (Discount rate) प्रभावशाली हो जाती है। बढ़ा दर (Discount rate) वह दर है जिस पर बैंक विलों को पुनः भुना कर बैंकों को ऋण देता है। यदि बैंक चाहता है कि व्यापारिक बैंक कम साख का निर्माण करें तो वह बढ़ा दर (Discount rate) को ऊँचा कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब व्यापारिक बैंकों को ऋण ऊँची दर पर मिलेगा तो वे अपनी सूद की दर को और ऊँचा उठावेगा इसका फल यह होगा कि ऋण कम लिया जावेगा।

और साख (Credit) का कम निर्माण होगा। यदि बैंक चाहता है कि साख का निर्माण अधिक हो तो वह अपनी दर (Rate) को कम कर देगा। अस्तु केन्द्रीय बैंक उस दशा के जब व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के पास ऋण के लिये पहुँचते हैं तो वह अपनी दर को ऊँचे उठा कर या नीचा गिरा कर देश में साख (Credit) के निर्माण का नियन्त्रण करता है।

साख (Credit) नियन्त्रण के तरीके :—जिन तरीकों से केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण करता है वे नीचे लिखे हैं :—

(१) अपनी बड़ा दर और सूद की दर को घटाना वा बढ़ाना जिससे देश में साधारणतः सूद की दर घटे वा बढ़े और साख का विस्तार वा संकोचन हो।

(२) विक्रयिष्ठियाँ (प्रतिभूति) को तथा विलों को खुले बाजार में इस उद्देश्य से खरीदना या बेचना जिससे बाजार में अधिक द्रव्य दिया जावे अथवा बाजार में से द्रव्य खींचा जा सके और उस प्रकार साख (Credit) को बढ़ाया या कम किया जाता है।

(३) साख का राशनिंग (Rationing of Credit) करके भी साख का नियन्त्रण किया जाता है। कभी कभी केन्द्रीय बैंक बड़ा दर या सूद की दर को बढ़ाने के साथ ही साख का राशनिंग कर देते हैं और कभी स्वतन्त्र रूप से साख के राशनिंग के द्वारा ही उसका नियन्त्रण करते हैं।

(४) उन बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करके जो केन्द्रीय बैंक से अधिक लम्बे समय न लिए तथा अत्यधिक मात्रा में ऋण लेते हैं या जिनके बारे में केन्द्रीय बैंक को वह शिकायत हो कि वे उससे ऋण लेकर सट्टा या पाटका (Speculation) के लिए पूँजी देते हैं अथवा उन धर्मों को साख देते हैं जो आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं हैं अथवा उपभोग के लिए साख (Consumer Credit) देते हैं।

(५) केन्द्रीय बैंक अपना नैतिक प्रभाव डाल कर तथा विज्ञप्ति करके भी साख को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है।

(६) केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के द्वारा उसके पास रखे गये न्यूनतम नकद कथ (Minimum Reserve) को अधिक करके अथवा घटा करके व्यापारिक बैंकों को इन बात के लिए विवश करता है कि वे साख का निर्माण कम करें या अधिक करें।

(८) साख का नियंत्रण करने के ऊपर लिखे तरीकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहले दो तरीके हैं। अर्थात् केन्द्रीय बैंक सूद की दर को घटा बढ़ा कर तथा खुले बाजार में विलों और सिक्क्यूरिटियों को खरीद बेच कर अधिकतर साख (Credit) का नियंत्रण करता है। किन्तु यहाँ एक बात समझ लेने की है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा 'बढ़ा दर' (Discount Rate) को ऊँचा कर देने से स्वतः ही साख का निर्माण कम नहीं हो जावेगा। हाँ यदि केन्द्रीय बैंक की सूद की दर ऊँची होने से द्रव्य बाजार (Money Market) में सूद की दर ऊँची हो जावे तब अवश्य साख का निर्माण कम होगा। और इसी प्रकार बैंक की दर गिरने से यदि द्रव्य बाजार में सूद की दर गिर जावे तो साख का अधिक विस्तार होगा। अस्तु साख का बढ़ना या घटना इस बात पर निर्भर होता है कि द्रव्य बाजार में सूद की दर केन्द्रीय बैंक की दर के साथ साथ घटती बढ़ती है। यदि केन्द्रीय बैंक की दर (Bank Rate) में परिवर्तन होने से द्रव्य बाजार की सूद की दर में कोई परिवर्तन न हो तो साख के निर्माण पर केन्द्रीय बैंक की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अस्तु केन्द्रीय बैंक का दर (Bank rate) केवल इसीलिये साख (Credit) के नियंत्रण में सफल हो पाती है क्योंकि यह एक परिपाटी स्थापित हो गई है कि द्रव्य बाजार में व्यापारिक बैंक अपनी सूद का दर को केन्द्रीय बैंक की दर के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। यदि केन्द्रीय बैंक की दर (Bank Rate) ऊँची चढ़ती है तो व्यापारिक बैंक भी अपनी सूद की दर बढ़ा देते हैं और यदि केन्द्रीय बैंक की दर नीचे गिरती है तो वे भी अपनी सूद की दर नीचे गिरा देते हैं। व्यापारिक बैंक यह भी जानते हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो केन्द्रीय बैंक के पास और भी अस्त्र है जिससे वह अपनी सूद की दर का प्रभावशाली बना सकता है। अस्तु वे केन्द्रीय बैंक के नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सूद की दर को केन्द्रीय बैंक की दर के अनुसार निश्चित करते हैं, फिर चाहे द्रव्य बाजार की स्थिति को देखते हुए सूद की दर में परिवर्तन की आवश्यकता हो या न हो।

(९) केन्द्रीय बैंक अपनी सूद की दर को प्रभावशाली बनाने के लिये अथवा स्वतंत्र रूप से साख का नियंत्रण करने के लिये खुले बाजार में विलों तथा सिक्क्यूरिटियों का विक्रय करता है। इसको 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market Operations) कहते हैं। 'खुले बाजार की क्रिया' नीचे लिखी तरह से होती है। यदि केन्द्रीय बैंक चाहता है कि साख का निर्माण कम हो तो वह अपने पास की सिक्क्यूरिटियों को बाजार में बेच देगा।

सिक्यूरिटी खरीदने वाले व्यापारिक बैंक होंगे या उनके ग्राहक होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि व्यापारिक बैंकों की केन्द्रीय बैंक के पास डिपॉजिट कम हो जावेगा और उनके नकद कोष (Cash Reserve) के कम होने से उन्हें साख (Credit) को कम करना होगा। यदि केन्द्रीय बैंक बाजार में सिक्यूरिटियों की खरीदने लगेगा तो इसका उलटा परिणाम होगा अर्थात् व्यापारिक बैंक अधिक साख का निर्माण करने लगेंगे। 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market Operations) केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये करता है:—

(क) केन्द्रीय बैंक की खुद की दर (Bank Rate) की प्रभावशाली बनाने के लिये खुले बाजार की क्रिया से व्यापारिक बैंकों का नकद कोष घट या बढ़ जाता है। अतः उन्हें केन्द्रीय बैंक की दर के अनुसार अपनी दर को निश्चित करना पड़ता है।

(ख) द्रव्य बाजार में द्रव्य के मौसमी हेर-फेर से तथा सरकारी कोषों (Funds) के हेर फेर से होने वाली गड़बड़ को कम करने के लिए भी 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market Operations) की जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष के कुछ महीनों में व्यापार की तेजी होती है और व्यापार को अधिक द्रव्य की आवश्यकता होती है। उस समय केन्द्रीय बैंक बिल तथा सिक्यूरिटियों को खुले बाजार में खरीद कर बाजार में अधिक द्रव्य दे देता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक भी केन्द्रीय बैंक के ऐसा करने पर अधिक साख का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यदि सरकार 'कर' (Tax) रूप में बहुत अधिक द्रव्य (Money) बाजार में से खींच ले तो भी बाजार में द्रव्य की कमी हो जावे। उस समय भी केन्द्रीय बैंक (Central Bank) बिल तथा सिक्यूरिटी खरीद कर द्रव्य की कमी को पूरा करता है।

(ग) स्वर्ण का आयात (Import) तथा निर्यात (Export) जो देश की करंसी पर प्रभाव पड़ता है उसको रोकने के लिए भी 'खुले बाजार की क्रिया' की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में स्वर्ण-मान (Gold Standard) हो और व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) देश के विरुद्ध हो और स्वर्ण का निर्यात (Export) होने लगे तो जनता कागजी नोट केन्द्रीय बैंक (Central Bank) को देकर उससे स्वर्ण लेकर बाहर भेजेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि बाजार में करंसी की कमी हो जावेगी उस समय केन्द्रीय बैंक 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market

Operation) के द्वारा अर्थात् बिल और सिक्यूरिटी खरीद कर बाज़ार में द्रव्य (Money) की कमी को पूरा करता है। यदि स्वर्ण देश में आ रहा हो तो उसका परिणाम यह होगा कि लोग केन्द्रीय बैंक को स्वर्ण देकर उससे नोट लेंगे। देश में कागज़ी नोट अर्थात् करंसी आवश्यकता से अधिक हो जावेगी उस समय केन्द्रीय बैंक बिल तथा सिक्यूरिटी को बैंचकर अनावश्यक द्रव्य या करंसी को चलन में से खींच लेता है।

(घ) 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market Operations) इसलिए भी की जाती है कि जिससे सूद की दर गिर जावे और सरकार अपने ऋण को कम सूद पर बैंच सके अथवा पुराने ऋण को जो ऊँची दर पर लिया गया था कम सूद के ऋण में बदल सके।

(ङ) खुले बाजार की क्रिया का एक उद्देश्य यह भी होता है कि सूद की दर नीची रहे जिससे व्यापार पनपे और उन्नत हो।

(३) साख का राशनिंग करना :—कभी-कभी केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग करके साख का नियंत्रण करता है। जब व्यापारिक बैंक अथवा बट्टा-गृह (Discount Houses) अपने बिलों को भुनाने के लिए केन्द्रीय बैंक से प्रार्थना करते हैं और उन सब बिलों का कुल मूल्य उस रकम से अधिक होता है जितने मूल्य के बिल किसी एक दिन में केन्द्रीय बैंक भुनाना तय करता है तो प्रत्येक बैंक या बट्टा-गृह के प्रार्थना पत्र में से केन्द्रीय बैंक कुछ कमी कर देता है और भुनाता है, और इस प्रकार साख का नियंत्रण किया जाता है।

(४) सीधी कार्यवाही करके (Direct Action) :—कभी-कभी बट्टा-दर (Discount Rate) या खुले बाजार की क्रिया (Open Market Operations) के स्थान पर केन्द्रीय बैंक सीधी कार्यवाही (Direct Action) करता है, कभी ऊपर लिखे दोनों उपायों के साथ-साथ भी सीधी कार्यवाही की जाती है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि कोई बैंक अपनी पूँजी (Capital) तथा सुरक्षित कोष (Reserve Fund) को देखते हुए केन्द्रीय बैंक से अधिक ऋण लेता है अथवा वह बैंक सट्टा या फटका (Speculation) के लिए ऋण देता है अथवा अनावश्यक धंधों को ऋण देता है अथवा उपभोग के लिए साख देता है, तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक या ऐसे बैंकों के बिलों को भुनाना अस्वीकार कर देता है, और

यदि उनके वित्त सुनाता भा है तो उनसे ऊँची दर लेकर उन्हें दवित करता है।

(२) नैतिक दबाव (Moral Suasion).—उप केन्द्रीय बैंक देलता है कि साल का अधिक विस्तार न होने देना देश के आर्थिक हित में है और व्यापारिक बैंक अधिक साल निर्माण कर रहे हैं तो वह उन्हें अपनी बताई हुई नीति को बरतने के लिए कहता है। इस प्रकार यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि साल (Credit) का विस्तार होना चाहिए तो वह व्यापारिक बैंकों को बैठा ही करने के लिए कहता है। केन्द्रीय बैंक (Central Bank) का द्रव्य-बाजार में इतना अधिक नैतिक प्रभाव होता है कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक उसकी बात को मानता है। इस प्रकार अपने नैतिक दबाव से ही केन्द्रीय बैंक साल की नियंत्रण करने में सफल होता है। कहीं-कहीं केन्द्रीय बैंक साल सम्बन्धी नीति को धमित कर देते हैं और व्यापारिक बैंक उसी के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन कर लेते हैं।

(६) नकद धोप के अनुपात (Cash Ratio) को बदल कर :—यदि मुक्ति उन देशों में विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है जहाँ कानून के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी विपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंक में रखना पड़ता है और केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह उस अनुपात (Ratio) को बदल दे। उदाहरण के लिये यदि किसी देश में कानून के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिये अपनी विपत्तियों की ५ प्रतिशत नकदी केन्द्रीय बैंक में जमा करना आवश्यक है और केन्द्रीय बैंक साल को कम करना चाहता है तो और उसको व्यापारिक बैंकों को नकदी के अनुपात (Cash Ratio) को बढ़ाने का अधिकार है तो वह व्यापारिक बैंकों से अपनी विपत्तियों का १० प्रतिशत जमा करने के लिये कह सकता है। केन्द्रीय बैंक के नकदी के अनुपात (Cash Ratio) को बढ़ाते ही व्यापारिक बैंकों को दिये हुए धन को वापस माँगना होगा और नई साल देना कम करना होगा। केन्द्रीय बैंक के इस कार्य से ही साल (Credit) का निर्माण कम हो जावेगा। इसी प्रकार केन्द्रीय बैंक नकदी के अनुपात को घटा कर साल (Credit) का निर्माण भा कर सकता है।

केन्द्रीय बैंक की सूद मरि दर (Bank Rate) का आर्थिक प्रभाव :—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि केन्द्रीय बैंक अपनी मरि दर या सूद मरि दर (Bank Rate) का ऊँचा कर देता है तो द्रव्य-बाजार में

सूद की दर ऊँची हो जावेगी। यदि सूद की दर इतनी अधिक हो जाती है कि व्यापारी और व्यवसायियों को उधार ली हुई पूँजी पर अधिक सूद देने के कारण लाभ (Profit) कम होने लगता है तो सभ्यता का उत्पादन कम होने लगेगा तथा बेकारी बढ़ जावेगी। बेकारी बढ़ने का परिणाम यह होगा कि लोगों की क्रय शक्ति कम होगी और वस्तुओं का मूल्य नीचे गिरने लगेगा। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक सूद की दर घटा दे तो द्रव्य-बाजार में सूद की दर घट जावेगी, व्यापार तथा व्यवसाय सस्ती पूँजी पा सकेंगे। इससे व्यापार तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

केन्द्रीय बैंक की सूद की दर केवल देश के भीतर ही प्रभाव नहीं डालती बल्कि बाहर भी डालती है। जब केन्द्रीय बैंक को सूद दर (Bank Rate) ऊँचा उठती है अर्थात् द्रव्य महँगा (Dear Money) हो जाता है तो उसका नीचे लिखा प्रभाव होता है :—

(१) महँगे द्रव्य का प्रभाव यह होता है कि देश विदेशों को कम उधार देता है और उनसे अधिक उधार लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश में सोना आने लगता है अथवा जाने वाला सोना रुक जाता है। जब कोई देश स्वर्ण मान (Gold Standard) पद्धति पर होता है और उस देश का आयात (Import) निर्यात (Export) से अधिक होता है तो स्वभावतः उस देश की करेंसी का अन्य देशों की करेंसी की तुलना में मूल्य गिरने लगता है और स्वर्ण बाहर जाने लगता है। उस समय केन्द्रीय बैंक सूद की दर को ऊँचा कर देता है। केन्द्रीय बैंक का सूद की दर ऊँची बढ़ने से देशों में सूद की दर ऊँची उठ जाती है और विदेशी व्यापारी अपने रुपये को स्वर्ण के रूप में न मँगवा कर उसी देश में अधिक सूद का लाभ उठाने के लिए अपना रुपया बैंकों इत्यादि में जमा कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्वर्ण बाहर जाने से रुक जाता है और विनिमय दर (Exchange Rates) नहीं गिरता।

यही नहीं जब देश में सूद की दर ऊँची उठ जाती है तो क्रय शक्ति (Purchasing Power) कम होता है और देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को देश में खपत न होने के कारण उनका निर्यात (Export) होने लगेगा। इससे देश का निर्यात व्यापार (Export Trade) बढ़ेगा और विदेशी व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) देश के पक्ष में होगा और स्वर्ण का बाहर जाना रुक जावेगा।

इसके अतिरिक्त ऊँचे सूद की दर के कारण पशुओं का मूल्य गिरता है क्योंकि सार का निर्माण कम होता है) तो व्ययगारियों को दाम्भवतः अपने उत्पादन व्यय (Cost of production) को कम करना पड़ता है। उससे देश का मा निर्यात व्यापार (Export trade) बढ़ता है और विदेशी व्यापार का अन्तर् देश के पक्ष में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय बैंक की सूद की दर का देश के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

असंगठित द्रव्य बाजार पर केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण :—
ऊपर हमने केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के मात नियंत्रण (Credit Control) का विवरण दिया वह संगठित द्रव्य बाजार (Organised money market) का है। किन्तु सब द्रव्य-बाजार संगठित नहीं होते। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, क्यूबा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में द्रव्य बाजार संगठित है। वहाँ केन्द्रीय बैंक ऊपर लिखे अनुसार दीक्षा का नियंत्रण करते हैं। किन्तु भारत तथा अन्य देशों में वहाँ द्रव्य-बाजार असंगठित है वहाँ केन्द्रीय बैंक इस प्रकार बाजार का नियंत्रण नहीं कर सकता।

इस प्रकार के असंगठित द्रव्य-बाजार की विशेषता यह होती है कि वहाँ बैंकिंग व्यवसाय उन्नत नहीं होता, जनता में बैंकिंग की आदत नहीं होती, अल्पकालीन द्रव्य-बाजार (Short term money market) यह तो होता ही नहीं जबकि उसका संगठन संतोषजनक नहीं होता। केन्द्रीय बैंक नई संस्था होने के कारण अधिक प्रभावशाली नहीं होता। यह व्यापारिक बैंक के ऊपर काबू द्वारा विद्यमान जाता है। उसके पीछे कोई परम्परा नहीं होती इस कारण उसका प्रभाव कम हो जाता है। भारतवर्ष में विद्यमान बैंकों ने बहुत से नये बैंकों की स्थापना की है, बैंक का चलन भी बढ़ता जाता है फिर देश के विस्तार को देखते बैंकिंग की यह उन्नति संशय नहीं, कदा का सकती। भारतवर्ष में और सभी देशों में वहाँ द्रव्य-बाजार असंगठित होता है सबसे यही वही यह होती है कि द्रव्य बाजार में सारे अल्पकालीन कोष (Short term funds) को एकत्रित करने और उसका व्यापार के लिए उपयोग करने की कोई व्यवस्था या संगठन नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि यह धन कोष (Funds) द्रव्य-बाजार (Money Market) के भिन्न-भिन्न विभागों में टूटकर छट से नहीं बंट पाता। किसी भाग में तो पूँजी की कमी प्रतीत होती है और वहाँ कारबार बूझी के कारण रुक जाता है और

दूसरे भाग में आवश्यकता से अधिक पूँजी होती है जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार के असंगठित द्रव्य-बाजार में भिन्न-भिन्न सूद की दरें प्रचलित होती हैं जिनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

असंगठित द्रव्य-बाजार में केन्द्रीय बैंक की सूद की दर (Bank Rate) इतनी अधिक कारगर नहीं होती जितनी संगठित द्रव्य-बाजार में होती है। केन्द्रीय बैंक की सूद की दर तभी कारगर होती है जब व्यापारिक बैंक उसके ऋणी हों। उस दशा में केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सूद की दर के सम्बन्ध में अपना नेतृत्व मानने पर विवश कर सकता है। किन्तु जहाँ केन्द्रीय बैंक पुराने स्थापित व्यापारिक बैंकों पर ऊपर से थोप दिया जाता है तो उसका नेतृत्व प्रभावशाली नहीं होता और अन्य व्यापारिक बैंकों को केन्द्रीय बैंक का शीघ्र ऋणी बनाना आसान नहीं होता। असंगठित द्रव्य-बाजार 'खुले बाजार की क्रिया' (Open Market Operations) का भी क्षेत्र सीमित ही होता है क्योंकि उन देशों में शेयर या स्टॉक एक्सचेंज (शेयर बाजार) इतना उन्नति नहीं होता कि उसमें बहुत बड़ा कारबार हो सके।

ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक सरकारी अर्थ विभाग से सहयोग करके ऐसी व्यवस्था करे कि सरकार की 'कर' (Tax) इत्यादिकी आय उसके तत्कालीन व्यय से अधिक हो। इसका परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय बैंक में सरकारी डिपॉजिट बढ़ जावेगी और व्यापारिक बैंकों का नकद कोष (Cash Reserve) कम हो जावेगा। इस प्रकार उन्हें साख (Credit) को घटाना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे देशों में केन्द्रीय बैंकों को यह अधिकार दे देना चाहिए कि वे व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा किया जाने वाला नकद कोष (Cash-Reserve) का अनुपात घटा बढ़ा सकें। यदि केन्द्रीय बैंक साख (Credit) को घटाना चाहता है तो व्यापारिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक में जमा किये जाने वाले नकद कोष के अनुपात को बढ़ा देगा और यदि साख को बढ़ाना चाहता है तो नकद कोष के अनुपात को घटा देगा।

साथ ही हमें यह न भूल जाना चाहिये कि वद्यपि केन्द्रीय बैंक की वट्टा-दर (Discount Rate) अर्थात् सूद की दर असंगठित द्रव्य-बाजार में बहुत कारगर नहीं होती किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि केन्द्रीय बैंक के सूद की दर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असंगठित-द्रव्य-बाजार में भी केन्द्रीय बैंक की सूद की दर का उपयोग होता है और उसका

प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक बैंक परोक्ष रूप से केन्द्रीय बैंक की सूद की दर से प्रभावित होते हैं। फिर वे यह तो जानते ही हैं कि यदि उन्हें केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना होगा तो उन्हें उस ऋण पर मिलेगा। अतएव वे भी केन्द्रीय बैंक के सूद की दर के अनुसार ही अपनी सूद की दर को घटाते बढ़ाते हैं। सब तो यह है कि केन्द्रीय बैंक की सूद की दर (Bank Rate) प्रभावशाली होगी या नहीं यह इस बात पर निर्भर रहता है कि केन्द्रीय बैंक की द्रव्य बाजार में कितना प्रतिष्ठा है और उसे अन्य व्यापारिक बैंकों का कितना सहयोग प्राप्त है।

समाशोधन गृह या क्लियरिंग हाउस (Clearing House)

प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र में बहुत से व्यापारिक बैंक होते हैं और उन सब बैंकों के भिन्न-भिन्न ग्राहक होते हैं। अतएव प्रत्येक बैंक को दूसरे बैंकों पर चेक, बिल इत्यादि वसूल करने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के लिए कलकत्ता कीजिए कि कलकत्ते में 'अ' भारत बैंक में अपना हिसाब रखता है और 'ब' सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में अपना हिसाब रखता है। 'अ' ने पाँच हजार रुपये का जूट 'ब' के हाथ बेंचा। 'ब' ने अपने बैंक अर्थात् सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया पर पाँच हजार रुपये का चेक काट कर 'अ' को दे दिया। अब 'अ' प्रति दिन जो भी चेक उसे मिलते हैं अपने बैंक अर्थात् भारत बैंक के पास भेज देता है। अस्तु इस चेक को भी वह भारत बैंक के पास सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से वसूल करके उसके हिसाब में जमा करने के लिए भेज देगा। इसी प्रकार प्रत्येक बैंक के ग्राहकों को व्यापार तथा कारबार में प्रति दिन भिन्न-भिन्न बैंकों पर चेक मिलते हैं। वह अपने बैंक के पास वसूल करके उसके हिसाब में जमा करने के लिए भेज देता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक बैंक के पास अन्य बैंकों पर काटे गए चेक इत्यादि वसूल होने के लिए आते हैं।

एक दूसरे पर कटे हुए चेकों को वसूल करने का एक उपाय यह है कि प्रति दिन प्रत्येक बैंक अपने एक क्लर्क और चपरासी को केवल इसीलिए नियुक्त करे कि वह सब चेकों को लेकर प्रत्येक बैंक के दफ्तर जावे और वहाँ उस चेक का रुपया वसूल करे। इस प्रकार प्रत्येक बैंक के कर्मचारियों को बार बार चेक तथा ड्राफ्ट इत्यादि का रुपया वसूल करने के लिए भिन्न-भिन्न बैंकों को जाना पड़ता है। इससे कर्मचारियों का समय तो नष्ट होता ही है, सवारी इत्यादि का व्यय भी होता है और रुपये को लाने और ले जाने में उसके खो जाने या लुट जाने का भी भय रहता है। इसके अतिरिक्त जब प्रत्येक बैंक को अपने ऊपर काटे गये चेकों या ड्राफ्टों का नकद रुपया देना पड़ता है तो उन्हें अपने पास नकदी भी अधिक रखनी पड़ती है। ऊपर का तरीका अवैज्ञानिक, कष्ट साध्य, और जोखिम का है। साथ ही इसमें व्यय अधिक होता है और बैंकों को अपने पास नकदी अधिक रखनी पड़ती है। यही कारण है कि जब बैंकिंग कारबार बढ़ा

और अधिकांश लोग अपना कारबार बैंकों की सहायता से करने लगे तो इस बात की आवश्यकता हुई कि एक दूसरे पर काटे हुए चेकों की वसूली का अधिक सुविधाजनक और सरल तरीका निकाला जावे और क्लियरिंग हाउस अथवा समाशोधन गृह की व्यवस्था की गई। चेकों के निष्कासन (Clearing) में एक बैंक की दूसरे बैंक पर जितनी माँग होती है उसको काट कर शेष (Balance) को चुका दिया जाता है। निष्कासन (Clearing) एक क्लियरिंग हाउस (समाशोधन गृह) के द्वारा होता है। इस ढंग से बहुत से लाभ होते हैं। क्लियरिंग हाउस की व्यवस्था होने से बैंक के कर्मचारियों को चेक इत्यादि को वसूली के लिए बार बार अन्य बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न चेकों तथा ड्राफ्टों को नक़दी में वसूल करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे लाभ यह होता है कि मार्ग में रुपये के लूटे या मारे जाने की जोखिम नहीं रहती। यही नहीं बैंकों को अपने पास अधिक नक़दी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह शक्ति बहुत ही सुविधाजनक, सरल, जोखिम रहित और लाभदायक है।

अब हम यहाँ क्लियरिंग हाउस का एक उदाहरण दे कर यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि क्लियरिंग हाउस किस प्रकार काम करता है। प्रत्येक बैंक जो क्लियरिंग हाउस का सदस्य होता है अपने प्रतिनिधि को क्लियरिंग हाउस में नियुक्त कर देता है। उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वह उन सब चेकों, बिलों, ड्राफ्टों, टेलीग्राफ़िक ट्रांसफ़र (Telegraphic Transfer) का चढ़ा देता है जिन्हें उसे क्लियरिंग हाउस के अन्य सदस्यों से वसूल करना है। प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इनकी एक प्रथम सूची भी बनाता है। वस्तुतः यह सूची रजिस्टर के भिन्न भिन्न कालों को नक़ल होती है। प्रत्येक काल में उन चेकों, बिलों, ड्राफ्टों को चढ़ाया जाता है जो एक बैंक के ऊपर काटे गए हैं। इन सूचियों को जोड़ लिया जाता है और उतनी राशि को रजिस्टर में उस बैंक के नाम चढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इसी प्रकार अपने रजिस्टर में उन चेकों और बिलों इत्यादि को चढ़ा लेता है और अन्य दूसरे बैंकों के नाम चढ़ा देता है। जोड़ने का काम मशीनों द्वारा होता है। क्लियरिंग हाउस में यह मशीनें बराबर यह काम करती हैं क्योंकि करोड़ों, आरबों का जोड़ और घटाना होता है और दिन में चार बार निष्कासन (Clearing) होता है। प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इन सूचियों को क्लियरिंग हाउस के अधिकारी को देता है और साथ ही उन बैंकों, बिलों और ड्राफ्टों के बदल भी उनके सुपुर्द कर देता है। प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि जो भी चेक और बिल दूसरे बैंकों

पर उसे अपने बैंक से वसूल करने के लिए मिलते हैं उनको एक बंडल में अलहदा बांध देता है और उसके साथ उन चेकों की सूची भी क्लियरिंग हाऊस के अधिकारी को दे देता है। क्लियरिंग हाऊस का अधिकारी प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि को उसके नाम के चेकों, बिलों और ड्राफ्टों के बंडल तथा उसकी सूचियाँ उन्हें सुपुर्द कर देता है। प्रत्येक प्रतिनिधि उन सूचियों तथा बंडलों को मिलाकर उन्हें अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता है। अब प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि उनको जोड़ कर और जितने के चेक इत्यादि उसने दूसरों पर दिये हैं उनमें से घटा कर यह मालूम कर लेता है कि उसके बैंक को अन्य बैंकों से कुल मिलाकर कितना लेना है अथवा देना है। और रजिस्टर में यह सारा हिसाब लगाकर वह अपने रजिस्टर को क्लियरिंग हाऊस के अधिकारियों को सौंप देता है। क्लियरिंग हाऊस के अधिकारी उनको मशीनों से फिर जांच लेते हैं और फिर वे यह हिसाब लगाते हैं कि प्रत्येक बैंक को आज सब मिलाकर कितना लेना अथवा देना है।

प्रत्येक बैंक का हिसाब केन्द्रीय बैंक (Central Bank) में होता है और क्लियरिंग हाऊस का हिसाब भी केन्द्रीय बैंक में होता है। जिस बैंक को किसी दिन क्लियरिंग हाऊस के हिसाब में देना निकलता है तो केन्द्रीय बैंक उस बैंक के हिसाब में से उतना रुपया कम करके क्लियरिंग हाऊस के हिसाब में जमा कर देता है। और जिस बैंक को क्लियरिंग हाऊस के हिसाब में लेना होता है उसे क्लियरिंग हाऊस उतने का केन्द्रीय बैंक पर चेक काट देता है। केन्द्रीय बैंक उतना रुपया क्लियरिंग हाऊस के हिसाब में लिख कर उस बैंक के हिसाब में जमा कर देता है। इस प्रकार क्लियरिंग हाऊस का हिसाब प्रति दिन पूरा सन्तुलित (Balance) हो जाता है और प्रत्येक सदस्य बैंक की केन्द्रीय बैंक में जमा (Deposit) बढ़ती बढ़ती रहती है।

अध्याय १०

द्रव्य-बाजार (Money Market)

द्रव्य बाजार में छोटे समय के लिए रुपये का लेन देन होता है। द्रव्य बाजार के द्वारा ही किसी देश के आर्थिक व्यवहार (Financial Transactions) का निष्कायन (Clearing) होता है। द्रव्य-बाजार (Money Market) शब्द का उपयोग दो अर्थों में हो सकता है। विस्तृत अर्थों में इसे अन्तर्गत सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहार का आते हैं किन्तु संकुचित अर्थों में उसके अन्तर्गत केवल अल्पकालीन आर्थिक व्यवहार (Short term financial transactions) ही आते हैं। जब हम द्रव्य बाजार के सम्बन्ध में साधारणतः कहते या लिखते हैं तो हमारा सारण्य इस संकुचित अर्थ से होता है। दूसरे अर्थों में द्रव्य बाजार अल्पकालीन कोष का भंडार है जहाँ से व्यापार इत्यादि को अल्पकालीन समय के लिए कोष (Funds) मिलता है। द्रव्य-बाजार में छोटे समय के लिए कोष की परीद बिक्री होती है।

हमें यह न भूलना चाहिए कि द्रव्य-बाजार (Money Market) पूँजी के बाजार (Capital Market) से भिन्न है। वो इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि बहुत से व्यवहारी (Transaction) का आरम्भ एक बाजार में होता है किन्तु वे दूसरे बाजार में पूरे होते हैं। उदाहरण के लिए एक या कंपनियों के लाभ (डिविडेंड) की अदायगी का आनुपूर्व तो पूँजी के बाजार में होता है और समाप्ति द्रव्य-बाजार में होती है। एक या डिविडेंड की अदायगी का द्रव्य-बाजार पर बड़ी प्रभाव पड़ता है जो हूँडी या बिल इत्यादि का पड़ता है। द्रव्य बाजार और पूँजी के बाजार में शक्ति संबंध तो होता है किन्तु वे दो पूर्णतः कार्य भी करते हैं। द्रव्य बाजार का सबसे अल्पकालीन कोष (Short Term Funds) से होता है जिसका उपयोग व्यापारिक कारगर में होता है अथवा सरकार को यदि अल्पकाल के लिए कोष की आवश्यकता होती है तो उसको पूरा करने में होता है। इसके विपरीत पूँजी के बाजार (Capital Market) का सबसे दीर्घ कालीन (Long Term) कोष (Funds) से होता है जिसकी उपयोग धनो (Industries) या सरकार को आवश्यकता होती है।

कार्यों की भिन्नता के अतिरिक्त इन बाजारों में काम करने वाली संस्थाएँ भी भिन्न होती हैं। प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न संस्थाएँ दोनों बाजारों में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिये पूँजी के बाजार (Capital Market) में औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) विनियोग ट्रस्ट (Investment Trusts) ब्रोकर इत्यादि होते हैं और द्रव्य-बाजार में केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, विल बाजार अथवा विल ब्रोकर होते हैं।

द्रव्य-बाजार का रूप :—द्रव्य-बाजार और वस्तु बाजार (Commodity market) में भेद है। न तो वह इतनी सरल और न वह इतनी अधिक संगठित होती है जितनी कि वस्तु-बाजार। द्रव्य बाजार में कारवार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता जैसा वस्तु बाजार में होता है। उदाहरण के लिए कपास के बाजार (Cotton Exchange) में कपास को खरीदने और बेचने वाले एक निश्चित स्थान पर इकट्ठे होकर कारवार करते हैं। किन्तु जहाँ द्रव्य को खरीदने और बेचने वाला मिलता है और सौदा तय हो जाता है वहीं-द्रव्य बाजार स्थापित हो जाता है। द्रव्य-बाजार में कारवार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। इन दोनों प्रकार की बाजारों में दूसरा भेद यह है कि द्रव्य-बाजार में जो लोग कारवार करते हैं वे बराबर बदलते रहते हैं केवल कुछ ही संस्थाएँ ऐसी होती हैं जो अल्पकालीन कोष (Short term funds) का ही विशेष रूप से कारवार करती हैं; उदाहरण के लिए ब्रोकर या एजेंट। नहीं तो द्रव्य-बाजार में काम करने वाली संस्थाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की साख (Credit) का प्रबंध करती हैं। अस्तु द्रव्य-बाजार एक कम संगठित संस्था है जिसकी कई शाखाएँ और उपशाखाएँ होती हैं और प्रत्येक शाखा अथवा उपशाखा एक विशेष प्रकार की साख (Credit) का प्रबंध करती है। वस्तुतः प्रत्येक शाखा अथवा उपशाखा एक स्वतंत्र बाजार होती है। परन्तु द्रव्य-बाजार की प्रत्येक शाखा अथवा उपशाखा एक दूसरे से सम्बन्धित होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है।

द्रव्य बाजार की वनावट :—विस्तृत अर्थों में द्रव्य-बाजार के अन्तर्गत बहुत सी स्वतंत्र रूप से संगठित बाजारों का समावेश होता है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी के बाजार (Capital Market) से सम्बन्धित होती हैं। इन विस्तृत अर्थों में द्रव्य-बाजार के अन्तर्गत नीचे लिखी स्वतंत्र बाजारें होती हैं :— (१) द्रव्य बाजार (Money Market) खास, (२)

पैसों का बाजार (Capital Market), (३) वस्तुओं का बाजार (Commodities Market), (४) विदेशी विनिमय बाजार (Foreign Exchange Market), सोना चाँदी का बाजार (Bullion Market) बीमा बाजार (Insurance Market) और कुछ हद तक जहाज रानी का बाजार (Shipping Market) ।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि सास द्रव्य बाजार तथा अन्य बाजारों में येद है किन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध है । अन्य दूसरी बाजारों सास द्रव्य बाजार की सहायक होती हैं । इन दूसरे बाजारों के कारबार तथा व्यवहारों (Transactions) के लिए जो अर्थ प्रबंध की आवश्यकता हुना है उसका प्रबंध द्रव्य-बाजार ही करती है । यदि यह अन्य बाजारों न हों तो सम्भवतः द्रव्य-बाजार की आवश्यकता ही न पड़े ।

सास द्रव्य-बाजार भी (Money Market Proper) जिसका समग्र अल्पकालीन कोष (Short Term Funds) से होता है और जिसका अभ्यपन करना हमारा विशेष उद्देश्य है निम्न निम्न विभागों में बांटी जा सकता है । यह विभाग निम्न निम्न देकों में वर्गीकृत किया जा सकता है परन्तु मोटे रूप में हम उन्हें नीचे लिखे अनुसार बांटी सकते हैं । (१) बट्टा बाजार (Discount Market), स्वीकृत बिल बाजार (Acceptance Market), सरकारी प्रतिभूति (Government Security) या विकल्पित बाजार अत्यन्त अल्पकाल के लिए शेयर बाजार के लिए अल्प अर्धे का प्रबंध करने वाला बाजार इत्यादि ।

द्रव्य बाजार की आवश्यकताएँ — द्रव्य बाजार को वहनी आवश्यकता यह है कि बाजार में अतिरिक्त कोष (Surplus Funds) अधिक मात्रा में होना चाहिए । इसकी आवश्यकता इसलिए और भी है क्योंकि 'कोष' आपस में बांटी जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि व्यापारिक बैंकों ने अल्पकालीन अल्प दिया है तो बैंकों के जमा करने वाले — द्वारा अपना जमा (Deposit) का निकालने पर उन को पारस पैसे की अपेक्षा हमारा आपस में बांटी जा सकता है । अतएव द्रव्य बाजार को उ मात देन वाले आपस में अल्प को अधिक समय के लिए पैसा नहीं रखते । कई बैंकों को उस रूप में की बहुध अल्प समय तक आवश्यकता न पड़ पर फिर भी बैंक का कभी एक एक उस रूप में आपस में बांटी जा सकता है ।

1 Surplus funds - 2 fund

सकता है। बैंकों को यह तो मालूम नहीं होता कि जमा करने वाले अपना रुपया कब निकालेंगे। अस्तु द्रव्य-बाजार को उधार दिया हुआ रुपया तभी शीघ्रतापूर्वक और आसानी से वापस मिल सकता है जब अल्पकाल के लिए उधार दिए जाने वाले कोष की मात्रा बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए यदि उधार लिया हुआ रुपया प्रथम श्रेणी के विलों या सरकारी सिक्यूरिटी की जमानत पर दिया गया है और यदि वह ऋण वापस माँगा जाता है धरन उधार लेने वाला ब्रोकर अन्य किसी से उधार लेकर अपने पहले ऋण को चुका देता है। यह तभी सम्भव है कि द्रव्य बाजार में यथेष्ट अतिरिक्त कोष (Surplus Funds) हो। यदि किसी समय द्रव्य-बाजार से जो कोष (Funds) वापस लिया जाता है यदि उसकी मात्रा अधिक नहीं होती तो उसकी कमी उस द्रव्य कोष से पूरी हो जाती है जो द्रव्य-बाजार में बेकार पड़ा होता है अथवा उस कोष से होती है जो नये स्थानों से द्रव्य-बाजार की ओर आता रहता है। ऐसी दशा में सूद की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु यदि द्रव्य-बाजार से वापस लिया जाने वाला द्रव्य कोष मात्रा में बहुत अधिक होता है तो सूद की दर ऊँची हो जाती है। जितनी ही द्रव्य कोष द्रव्य-बाजार में अधिक होता है उतनी ही सूद की दर के बढ़ने की सम्भावना कम रहती है।

अभी तक हमने द्रव्य कोष (Funds) की पूर्ति का अध्ययन किया किन्तु अब हम माँग (Demand) का अध्ययन करेंगे। द्रव्य-बाजार के लिए दूसरी प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि जो व्यापारिक-पत्र (Commercial papers) जिनका द्रव्य-बाजार में कारबार हो वे शीघ्र ही नकदी (Cash) में परिणत हो सकने वाले हों। यदि कोई पत्र (Paper) बहुत अच्छा और सुरक्षित हो किन्तु शीघ्र ही नकदी में परिणत न हो सके तो वह द्रव्य-बाजार के काम का नहीं होगा। यह इसलिए आवश्यक है कि ऋण लेने वाले को कभी-कभी अल्प सूचना पर ही उस पत्र (Paper) को नकदी में परिणत करना पड़ सकता है। अतएव अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति या सिक्यूरिटी प्रथम श्रेणी के बैंक बिल, अथवा वे खेती की पैदावारों जिनकी बाजार में सदैव तेज माँग रहती है द्रव्य-बाजार के लिए उपयुक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य-बाजार के लिए वही पत्र (Paper) उपयुक्त होता है जो अल्पकालीन हो क्योंकि बैंक इत्यादि जो इन पत्रों के आधार पर ऋण देते हैं उन्हें कभी भी अपना रुपया वापस माँगना पड़ सकता है। अस्तु वे उन पत्रों

के मूल्य में सूद का घट बढ़ से होने वाले परिवर्तन की जोखिम नहीं उठा सकते। यह जोखिम तभी दूर की जा सकती है जब द्रव्य बाजार के पत्र (Paper) इतने अल्प समय में ही पत्र आवें और सूद की दर के परिवर्तन से उन पत्रों के मूल्य में अधिक घट बढ़ न हो।

द्रव्य बाजार का संगठन :—द्रव्य बाजार में भिन्न भिन्न संस्थाएँ होती हैं जो अल्पकालीन कोष की खरीद बिक्री का काम करती हैं। ये संस्थाएँ अल्पकालीन कोष को उधार भी लेती हैं और उधार देती भी हैं। परन्तु कुछ संस्थाएँ विशेष रूप से उधार देती हैं और कुछ विशेष रूप से उधार लेती हैं। उधार देने वालों में मुख्य संस्थाएँ नीचे मिली हैं :—

(१) **केन्द्रीय बैंक (Central Bank) :—**केन्द्रीय बैंक अन्तिम श्रृङ्खलाका हाता है। यही-कहीं केन्द्रीय बैंक केवल बैंकों से ही कारबार करता है। इंग्लैंड और अमेरिका में जनता से भी कारबार करता है।

(२) **व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) :—**द्रव्य-बाजार को श्रृङ्खल देने वाली संस्थाओं में व्यापारिक बैंक सब से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये कभी कभी केन्द्रीय बैंक से उधार भी लेते हैं। जो द्रव्य को यह बैंक द्रव्य बाजार को उधार देते हैं यह डिपॉजिटो (जमा) द्वारा प्राप्त करते हैं और यह डिपॉजिट जब चाहें तो जमा करने वाले निकाल सकते हैं। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि बैंक इस जमा क्रिये हुए धन को द्रव्य-बाजार को देते हैं। कहीं कहीं बैंक बिल ओकरों को खरा मर्रा एरों (Discount Houses) को श्रृङ्खल देते हैं और सरकारी हुजियों (Treasury Bills) तथा स्वीकृत बिलों में हरया लगाते हैं तो कहीं स्टॉक बाजार इत्यादि को श्रृङ्खल देते हैं।

(३) **विनियोग (Investment) करने वाले :—**इस श्रेणी में सेविंग बैंक, वाया कर्पोरेशियाँ, विनियोग ट्रस्ट (Investment Trusts) तथा ट्रस्ट कम्पनियों की गणना होती है। इन संस्थाओं का कोष जब चाहें निकाला नहीं जा सकता परन्तु फिर भी ये अपने कोष का कुछ अंश सरल लेनी (Liquid Assets) में लगाते हैं। कोष द्रव्य बाजार में आता है।

(४) **व्यक्ति, कम्पनियाँ या फर्म :—**अधिकतर ये संस्थाएँ द्रव्य-बाजार में अपना रुपया नहीं लगाती क्योंकि द्रव्य बाजार में सूद की दर

बहुत कम होती है। परन्तु यदि कभी द्रव्य-बाजार में सूद की दर ऊँची उठ जाती है तब ये संस्थायें अपना रुपया द्रव्य-बाजार में मेजती हैं।

द्रव्य-बाजार में उधार लेने वाले स्वभावतः थोड़े ही होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कठोर शर्तों को पूरा करना पड़ता है। उनका पत्र (Paper) तरल और थोड़े समय में ही पकने वाला होना चाहिए। ये शर्तें बिल ब्रोकर, बट्टा-गृह (Discount Houses) तथा सरकारी हुडियो तथा स्वीकृत विलों का कारबार करने वाले पूरी करते हैं। अतएव ये लोग मुख्यतः द्रव्य-बाजार में ऋण लेते हैं।

प्रत्येक द्रव्य-बाजार वस्तुतः केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की अधीनता और नियंत्रण में काम करता है। जैसा हम केन्द्रीय बैंक के परिच्छेद में कह चुके हैं कि केन्द्रीय बैंक बहुत तरह से द्रव्य-बाजार का नियन्त्रण करता है।

द्रव्य बाजार के कार्य :- द्रव्य-बाजार का किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और वह राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए एक अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक संस्था है। द्रव्य-बाजार के द्वारा ही देश का आंतरिक कोष एक स्थान पर एकत्रित होता है। द्रव्य-बाजार बैंकों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को अपने अतिरिक्त कोष को लगाने की सुविधा प्रदान करता है तथा साथ ही एक ऐसा द्रव्य भंडार उपस्थित कर देता है जहाँ से आवश्यकता पड़ने पर द्रव्य कोष लिया जा सके। द्रव्य-बाजार की एक देश को बड़ा उपयोगिता है जो एक स्थान के लिए बैंक की होती है। यही नहीं सरकार के लिए भी द्रव्य-बाजार का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जब सरकार को अल्प काल के लिए द्रव्य कोष (Funds) की आवश्यकता होती है तो वह द्रव्य-बाजार से ले लेती है। यदि द्रव्य-बाजार न हो तो सरकार को या तो केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना पड़े अथवा कागजी मुद्रा (Paper Currency) निकाल कर काम चलाना पड़े। इन दोनों तरीकों से मुद्रा प्रसार (Inflation) होता है जो देश को आर्थिक व्यवस्था के लिए हानिकर सिद्ध हो सकता है। एक अच्छे द्रव्य-बाजार में बहुधा विदेशी सरकारें भी अल्प काल के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले लेती हैं। इसके अतिरिक्त यदि द्रव्य-बाजार का संगठन अच्छा है तो उसका पूँजी के बाजार (Capital Market) पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। द्रव्य-बाजार पूँजी के बाजार

का सहायक सिद्ध होना है । द्रव्य बाजार की स्थिति और सूद की दर का प्रभाव पूँजी के बाजार पर पड़े बिना नहीं रह सकता । अतएव देश को आर्थिक सन्नति के लिए एक सुव्यवस्थित द्रव्य बाजार की निरन्तर आवश्यकता होता है ।

अध्याय ११

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Fund) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank)

द्वितीय संसार व्यापी महायुद्ध (१९३९ से १९४५) के समय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि संसार के प्रत्येक देश की ^{मुद्रा} करंसी को स्थायित्व प्रदान करना तथा भिन्न-भिन्न देशों की करंसी की विनिमय दर (Exchange Rates) को अधिक घटने या बढ़ने न देना देशों की आर्थिक उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए आवश्यक है। अतएव जुलाई १९४४ में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्मेलन (International Monetary Conference) हुआ जिसमें एक 'अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष' तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का निश्चय हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष का मुख्य उद्देश्य एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति या द्रव्य पद्धति (Monetary System) की पुनः स्थापना करना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी सहयोग स्थापित हो सके। अर्थशास्त्रियों का यह दृढ़ विचार था कि बिना इसके संसार के भिन्न-भिन्न देशों में उत्पादन को तेजी से बढ़ाया नहीं जा सकता और न बेकारी को ही दूर किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) के साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना आवश्यक समझी गई जो भिन्न-भिन्न देशों की औद्योगिक उन्नति में सहायक होगा। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष सदस्य देशों की अल्पकालीन साख (Short Term Credit) की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों के औद्योगिक विकास के लिये लम्बे समय के लिए पूँजी की व्यवस्था करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वानों का मत था कि संसार व्यापी महायुद्ध से अधिकांश देशों का आर्थिक ढाँचा जर्जर हो गया है। अस्तु यदि प्रत्येक देश युद्ध की समाप्ति के उपरान्त अपनी अपनी करंसी का स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध करेगा तो विनिमय दर (Exchange Rates) में बहुत घट-बढ़ होगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति अवरोध होगी। इसका

प्रभाव उन देशों की आर्थिक स्थिति पर हुआ होगा और उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। अतएव इस बात की आवश्यकता है कि मित्त मित्त देशों की करसी तथा उनकी विनिमय दर (Exchange Rates) को स्थायित्व प्रदान किया जावे।

१९२२ के पूर्व स्वर्ण प्रमाण (Gold Standard) के द्वारा समस्त के मित्त-मित्त देशों की करसी की विनिमय दर को स्थायित्व (Stability) प्रदान होता था। किन्तु एक के बाद दूसरे देश ने स्वर्ण प्रमाण को छोड़ दिया और अब अधिकांश राष्ट्रराष्ट्रियों का मत है कि स्वर्ण प्रमाण (Gold Standard) बहुत ही कम लचीला और अव्यवहार्य है अस्तु इस बात की आवश्यकता हुई कि एक ऐसी अन्तर्गोष्ठीय द्रव्य पद्धति (International Monetary System) को जन्म दिया जावे जो अधिक लचीली हो। इसी उद्देश्य से अन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष तथा अन्तर्गोष्ठीय बैंक की स्थापना की गई है।

अन्तर्गोष्ठीय द्रव्य-कोष और विनिमय दर का स्थायित्व :—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि अन्तर्गोष्ठीय द्रव्य-कोष का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का करसी का विनिमय दरों का स्थायित्व प्रदान करना है। इसके लिए आवश्यक है कि मित्त मित्त देशों की करसी के लिए एक सर्वमान्य आधार हो। अस्तु प्रत्येक सदस्य देश को अपनी करसी का मूल्य सोने में निश्चित कर देना होगा। अस्तु सोने के द्वारा समस्त के प्रत्येक देश की करसी की विनिमय की सममूल्य दर (Parity of Exchange) निर्धारित हो जावेगी। अन्तर्गोष्ठीय द्रव्य-कोष के द्वारा (International Monetary Fund) मित्त मित्त सदस्य देशों की विनिमय दरों को एक सीमा के अन्दर ही रखने का आयोजन किया जावेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि देशों की करसी की विनिमय दर एक निश्चित सीमा से अधिक घट बढ़ न सकेगी।

युद्ध के कारण बहुत से देशों का आर्थिक डाँचा खँजूर हो गया है इस कारण आरम्भ में बहुत से देशों का व्यापार समुतन (Balance of Trade) उनके निष्पक्ष में हुआ अर्थात् वे कितने मूल्य का माल बाहर भेजेंगे उससे बहुत अधिक मूल्य की वस्तुएँ बाहर से म्यांगने ऐसी दशा में उन देशों को विदेशों की करसी का बहुत अधिक आवश्यकता होगी और यदि उनकी

विदेशों की करेंसी को निश्चित विनिमय दर (Exchange Rates) पर देने का प्रबन्ध न किया गया तो उनकी करेंसी की विनिमय दर कभी स्थिर नहीं रह सकती। यदि युद्ध जनित आर्थिक गड़बड़ी को छोड़ भी दें तो भी साधारण व्यापार में भी कभी-कभी व्यापार का संतुलन (Balance of Trade) किसी समय किसी देश के पक्ष में हो सकता है और किसी देश के विपक्ष में। ऐसी अवस्था में उन देशों को जिनका व्यापार संतुलन उनके विपक्ष में है यदि अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से सहायता न मिली तो उनकी करेंसी की विनिमय दर स्थिर नहीं रह सकती।

अस्तु इस अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उन देशों को अन्य देशों की करेंसी श्रृण स्वरूप दे देगा और वे अपनी देनी का भुगतान कर सकेंगे। इस कार्य को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) सफलता पूर्वक कर सके इस उद्देश्य से प्रत्येक सदस्य देश अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में जो उसका भाग निर्धारित है उसका कुछ भाग सेने में और शेष अपनी करेंसी (मुद्रा) में चुकावेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास प्रत्येक सदस्य देश की करेंसी यथेष्ट मात्रा में रहेगी जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देशों को एक दूसरे की करेंसी उधार दी जा सकेगी। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में भिन्न-भिन्न प्रमुख देशों का भाग इस प्रकार है।

ब्रिटेन बुद्ध-द्रव्य-सम्मेलन में जो ४४ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे (शत्रु राष्ट्र उस समय सम्मिलित नहीं हो सके थे) उनके लिए सम्मेलन ने कुल ८,६००,०००,००० डालर का कोटा निर्धारित किया था। और १,२००,०००,००० डालर का कोष शत्रु राष्ट्रों के लिए छोड़ दिया गया था कि युद्ध के उपरान्त वे भी कोष में सम्मिलित हों तो उनको उसमें हिस्सा दिया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में प्रमुख राष्ट्रों का भाग इस प्रकार है:—संयुक्त राज्य अमेरिका २,७५०,०००,००० डालर, यूनाइटेड किंगडम १,३००,०००,००० डालर, सोवियत रूस १,२००,०००,००० डालर, चीन ५५०,०००,००० डालर, फ्रांस ४५०,०००,००० डालर, भारतवर्ष ४००,०००,००० डालर, कनाडा ३००,०००,००० डालर, निदरलैंड २७५,०००,००० डालर, बेलजियम २२५,०००,००० डालर, आस्ट्रेलिया २००,०००,००० डालर, जेकोस्लावाकिया तथा पोलैंड १२५,०००,००० डालर दक्षिण अफ्रीका

यूनिट १००,०००,००० डालर, मैक्सिमम ६०,०००,००० डालर, चाइल
थार कॉन्सिडर ५०,०००,००० डालर इत्यादि ।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने पास का २५ प्रतिशत अथवा सदस्य राष्ट्र के पास कुल जितना सोना होगा उसका १० प्रतिशत सोना देना होगा (जो भी उस समय कम हो) और शेष १५ प्रतिशत सदस्य राष्ट्र अपनी करसी (मुद्रा) में चुकावेगा । इसका परिणाम यह होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास सभी सदस्य राष्ट्रों की करसी (मुद्रा) दृष्टिगत राशि में इकट्ठी हो जावेगी और अब किसी सदस्य राष्ट्र का व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) उसके विपक्ष में होगा और उसके पास अपने विदेशी व्यापार श्रृंखला को चुकाने के कोई साधन नहीं रहेंगे तो वह अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से उसी देश की करसी को खरीद लेगा और अपने व्यापार श्रृंखला को चुका देगा । इस प्रकार उस देश की करसी की विलम्ब दर (Exchange Rates) में विशेष घट बढ़ न होगी । इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आरम्भ से ही अपने विदेशी व्यापार के श्रृंखला को चुकाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष पर निर्भर रहेगा । साधारणतः प्रत्येक देश अपने व्यापारिक र्वैको के द्वारा अपने लेन-देन का भुगतान करते रहेंगे और जब कोई देश विदेशी व्यापार का सन्तुलन (Balance of Foreign Trade) अपने विपक्ष में होने के कारण किसी विदेशी करसी का साधारणतः पाने में असमर्थता अनुभव करे तभी वह अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से करसी को खरीद लेगा ।

साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष (International Monetary Fund) के पास प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की करसी इतनी मात्रा में होती कि उसका काम नहीं चलेगी । अतः विशेष परिस्थितियों में यह सम्भव है कि किसी देश विशेष का व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade) इतना अधिक उसके पक्ष में हो और अन्य सदस्य राष्ट्रों को उस देश विशेष की करसी को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष से इतना अधिक राशि में खरीदना पड़ जावे कि उस देश विशेष की जितनी मा करसी अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास है वह सभी समाप्त हो जावे ऐसी स्थिति में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । उदाहरण के लिये विद्यमान महाकुट में समुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार सन्तुलन उसके इतना अधिक पक्ष में था और संसार के अन्य राष्ट्र उसके इतने अधिक देनदार हो गये कि प्रत्येक देश को अमेरिका की करसी अर्थात् डालर को आवश्यकता

थी और डालर का टोटा पड़ गया था । यदि कमा ऐसी स्थिति खड़ी हो जावे कि किसी देश विशेष की करेंसी का संसार में टोटा पड़ जावे और अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास भी वह करेंसी कम होने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उस करेंसी का टोटा है ऐसी घोषणा कर देगा और जितनी भी उम देश की करेंसी 'कोष' के पास होगी वह प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रख कर बांट देगा । अन्य सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से परामर्श करके थोड़े समय के लिये अस्थायी रूप से उस देश से माल के आयात (Import) पर रोक लगा सकेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि उस देश से अन्य देशों को निर्यात (Export) कम हो जावेगा और उस की करेंसी की माँग कम हो जावेगी । किन्तु व्यापार पर यह रोक केवल उतने समय के लिये लगाई जा सकेगी जितने से करेंसी की यह कमी दूर की जा सके । जब अन्तर्राष्ट्रीय-द्रव्य-कोष इस बात की घोषणा कर देगा कि उक्त देश की करेंसी की अब कमी नहीं है तो फिर इस देश के व्यापार पर कोई बन्धन नहीं लगाया जा सकेगा ।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास किसी देश की करेंसी की कमी को दूर करने के और भी उपाय हैं । एक उपाय तो यह है कि 'कोष' उस देश में जिसकी करेंसी की कमी है अपना सोना वेंचे या उस देश में ऋण ले । ऐसा करने से अन्तर्राष्ट्रीय-द्रव्य-कोष के पास उस देश की करेंसी अधिक मात्रा में आ जावेगी और फिर वह उन सदस्य राष्ट्रों को दी जा सकेगी जिनको उस करेंसी की आवश्यकता हो । ऊपर लिखे उपायों के अतिरिक्त दो उपाय और भी हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank) उन देशों को न्यून करेंसी (Scarce Currency) में ऋण दे सकता है जिन्हें 'न्यून करेंसी' की आवश्यकता हो या फिर वह देश जिसकी करेंसी न्यून है स्वयं ही अन्य देशों को ऋण दे दे नहीं तो उसके निर्यात (Export) पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो जावेगा । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष प्रत्येक देश की विनिमय दर (Exchange Rates) को स्थायी बनाने का प्रयत्न करेगा ।

काँई भी सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से एक सीमा तक अपनी करेंसी देकर अन्य किसी भी राष्ट्र की करेंसी खरीद सकता है और उस सीमा के उपरान्त वह सोना देकर कमी भी किसी देश की करेंसी खरीद सकता है ।

जहाँ तक अपनी करसी देकर किसी अन्य देश की करसी खरीदने का प्रश्न है प्रत्येक देश अपने भाग (कोटा) का केवल २५ प्रतिशत तक एक वर्ष के अन्दर खरीद सकता है। अब कोई देश अपनी करसी देकर दूसरे देश को करसी 'कोप' से खरीदेगा तो 'कोप' के पास खरीदने वाले देश की करसी अधिक बढ़ जावेगा। परन्तु एक वर्ष में उस देश का 'कोप' में जो भाग (कोटा) है उसकी २५ प्रतिशत में अधिक उस देश (खरीदने वाले) की करसी कोप के पास बारह महीने में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और कुल मिला कर २०० प्रतिशत अर्थात् दुगुने से अधिक उस देश (खरीदने वाले) की करसी 'कोप' में कभी भी इकट्ठी न होनी चाहिए।

अब कोई देश अन्य देश की करसी खरीदेगा तो सममूल्य दर (Parity) के अनुसार मूल्य देने के अतिरिक्त उस देश को ३ प्रतिशत लवें का देना होगा। परन्तु यदि किसी देश का करसी उस देश के भाग (कोटा) से अधिक 'कोप' के पास लगातार तीन महीने से अधिक इकट्ठी रही तो सदस्य राष्ट्र को तीन महीने व्यतित हो जाने के उपरान्त जितनी करसी उस देश के भाग से अधिक 'कोप' के पास होगी उस पर सदस्य राष्ट्र को बढ़ती हुई दर से खूद देना होगा।

पहले तीन महीने तक कोई खूद नहीं लिया जावेगा। तीन महीने के उपरान्त रोप ६ महीने के लिए ३ प्रतिशत अतिरिक्त (३ प्रतिशत के ऊपर) खूद लिया जावेगा और उसके उपरान्त प्रतिवर्ष के हिसाब से ३ प्रतिशत अधिक खूद देना होगा। इस प्रकार जितने अधिक समय के लिए करसी ली जावेगी उतनी ही प्रतिवर्ष के हिसाब से खूद की दर ३ प्रतिशत बढ़ती चली जावेगी। यही नहीं यदि किसी देश की करसी उस देश के भाग (कोटा) में २५ प्रतिशत से अधिक इकट्ठी हो जावे किन्तु ५० प्रतिशत से कम रहे तो ३ प्रतिशत अधिक खूद लिया जावेगा और उसके उपरान्त प्रति २५ प्रतिशत के लिए ३ प्रतिशत अधिक खूद देना होगा। इस प्रकार करसी की राशि और जितने अधिक समय के लिए करसी ली जावेगी उती हिसाब से खूद की दर बढ़ती जावेगी। अधिक खूद लेने की व्यवस्था इस कारण की गई है जिससे विदेशों की करसी खरीदने वाले देश जल्दी से जल्दी उस करसी का वापस करने का प्रयत्न करें। अन्य देशों की करसी लेने वाले देश को केवल अधिकतम ६ खूद ही नहीं देना पड़ता बल्कि उसका अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप में जितने बोट (मत)

देने का अधिकार है वह भी क्रमशः कम होता जाता है और जिस देश की करंसी उसने उधार ली है उसकी बोट बढ़ती जाती है ।

सममूल्य परिवर्तन (Changes in Par Values):—प्रत्येक देश को अपनी करंसी की सममूल्य दर (Par of Exchange) में तभी परिवर्तन करने का अधिकार होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उसकी अनुमति दे दे। जब तक कोई सदस्य राष्ट्र अपनी करंसी के सममूल्य (Par of Value) में केवल १० प्रतिशत वृद्धि या कमी करता है तब तक कोष उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा, अर्थात् १० प्रतिशत तक प्रत्येक देश में अपनी करंसी के सममूल्य में परिवर्तन कर सकेगा। किन्तु इसके उपरान्त परिवर्तन तभी हो सकेगा जब अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उसकी अनुमति दे दे।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank):—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति और उनके पुनर्निर्माण में सहायता पहुँचाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए उन्हें ऋण देगा और अन्य देशों द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी देगा। इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों के औद्योगिक विकास के लिए पूँजी (Capital) की व्यवस्था करेगा, यही उसका मुख्य कार्य होगा।

साधारणतः जब कोई सदस्य राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का औद्योगिक उन्नति के लिए उपयोग करना चाहेगा और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए पूँजी चाहेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का अपनी योजनायें बतला कर उससे गारंटी की व्यवस्था करा लेगा। यह सब हो जाने के उपरान्त वह सदस्य राष्ट्र संसार के प्रमुख द्रव्य-बाजारों (Money Markets) में उदाहरण के लिए लंदन या न्यूयार्क के द्रव्य-बाजार में ऋण लेने की व्यवस्था करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस ऋण का गारंटी कर देगा। अब किसी सदस्य राष्ट्र को व्यक्तिगत रूप से द्रव्य-बाजारों में ऋण नहीं मिल सकेगा तब बैंक उस राष्ट्र को सीधा अपने पास से ऋण देगा। जब तक किसी देश को अन्य देशों से साधारणतः ऋण मिल सकेगा तब तक बैंक उसे स्वयं ऋण नहीं देगा। इस व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि पिछड़े और निर्धन राष्ट्र जिनको अपने उद्योग-धंधों के विकास के लिए पूँजी की आवश्यकता होगी पूँजी पा सकेंगे और जिन राष्ट्रों के पास यथेष्ट अतिरिक्त पूँजी (Surplus

Capital) इच्छा हो जायेगी वे बैंक की गारंटी होने के कारण उन राष्ट्रों को श्रृणु स्वरूप दे सकेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उन श्रृणु की अदायगी की गारंटी देगा और अपनी इस सेवा के पारिधमिक स्वरूप वह कर्ज लेने वाले राष्ट्र से गारंटी किये हुये श्रृणु पर कम से कम १ प्रतिशत और अधिक से अधिक २½ प्रतिशत धीम लेगा। कर्ज लेने वाले राष्ट्र को प्रचलित मुद्र की दर अपने श्रृणु दाताओं को देनी होती है। जब कर्ज लेने वाले राष्ट्र को साधारण तौर पर अपनी आर्थिक योजनाओं को पूरा करने के लिए श्रृणु न मिल सके तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उन्हें अपने पास से श्रृणु दे देगा।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक श्रृणु की गारंटी तभी करेगा या स्वयं तभी श्रृणु देगा जब वह उस योजना को देख लेगा और श्रृणु लेने वाले देश की अदायगी की क्षमता की जाँच कर लेगा। साथ ही वह श्रृणु लेने वाले देश के केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से उस श्रृणु की अदायगी की गारंटी ले लेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी—अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) १०,०००,०००,००० है। उसमें से ब्रेटनवुड्स द्रव्य सम्मेलन ने ६, १००,०००,०००, डालर मित्र राष्ट्रों (उन ४४ राष्ट्रों में जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे) में बाँट दा और शेष शत्रु राष्ट्रों के लिए छोड़ दी गई। प्रत्येक राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी में उतना ही भाग मिला जितना उसको अन्तर्राष्ट्रीय कोष में मिला था। केवल सयुक्त राज्य अमेरिका को ४२५, ०००, ००० डालर, चीन को ५०, ०००, ००० डालर, और कनाडा को २५, ०००, ००० डालर की पूँजी अधिक दी गई और दक्षिणी अमेरिका के देशों, यूगोस्लाविया, ग्रीस और मिस्र को कुल मिला कर २००, ०००, ००० डालर की पूँजी कम दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का नही राष्ट्र सदस्य हो सकता है या अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष का भी सदस्य हो।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी का मितल भाग प्रत्येक देश को दिया गया है उसकी प्रचल २० प्रतिशत पूँजी हो सदस्यों ने चुनाई है। शेष ८० प्रतिशत पूँजी बुरस्तित गारंटी के तौर पर है जिसे बैंक सब चाहे माँग सकता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का मुख्य कार्य सदस्य बैंकों द्वारा लिये हुए श्रृणु की गारंटी देना है। अस्तु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को बहुत अधिक पूँजी

इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई देश अपना ऋण न चुका सके तभी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को उस ऋण का मूलधन तथा उसका सुद देना होगा क्योंकि उसने उस ऋण की गारंटी दी है। ऐसी स्थिति बहुत कम उपस्थित होगी। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह प्रत्येक देश से उसके हिस्से की पूरी रकम वसूल कर लेता। अस्तु बैंक ने प्रत्येक देश से उसके हिस्से की २० प्रतिशत रकम ही वसूल की है। शेष ८० प्रतिशत जब बैंक चाहे तो वसूल कर सकता है।

प्रत्येक देश ने अपने हिस्से की २० प्रतिशत रकम को इस प्रकार चुकाया है:—२ प्रतिशत स्वर्ण या अमेरिकन डालर के रूप में और शेष उस देश की अपनी मुद्रा में। यदि कभी बैंक को शेष ८० प्रतिशत पूँजी को माँगना पड़ा तो सदस्य देश की सुविधानुसार स्वर्ण में, अथवा अमेरिकन डालर में अथवा उस मुद्रा में जिसकी बैंक को भुगतान करने के लिए उस समय आवश्यकता हो चुकाया जावेगा।

यह तो हम ऊपर कह आये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने प्रत्येक देश से उसके भाग की केवल २० प्रतिशत रकम ही वसूल की है। यही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कार्यशील पूँजी है। किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इससे ही बैंक की सदस्य देशों को ऋण देने की शक्ति सीमित हो जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण की गारंटी देने अथवा सीधा ऋण देने के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर किसी सदस्य देश के बाजार में अपनी सिक्यूरिटी (ऋण पत्र) बेचकर धन प्राप्त कर सकता है और उस धन को ऋण स्वरूप अन्य देश को दे सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि पाकिस्तान को अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए ऋण चाहिए और उसे अमेरिका से अधिकतर मशीनें मँगाना है तो स्वभावतः पाकिस्तान अमेरिका से ऋण लेना चाहेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पाकिस्तान की योजनाओं को ठीक समझे तो पाकिस्तान को सीधे अपने पास से ऋण दे सकता है, अथवा पाकिस्तान द्वारा अमेरिका में लिए जाने वाले ऋण की अदायगी की गारंटी दे सकता है। यदि इस प्रकार ऋण न मिल सके तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अमेरिका की सहमति से अपने ऋण-पत्र अथवा सिक्यूरिटी अमेरिका के बाजार में बेचेगा और इस प्रकार उसे जो धन प्राप्त होगा वह उसे पाकिस्तान को ऋण के रूप में दे देगा। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ऋण देने की शक्ति केवल उसकी कार्यशील पूँजी से सीमित नहीं है।

किसी भी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक गारंटी के रूप में अथवा श्रृंख के रूप में बैंक की वित्तित पूँजी (Subscribed Capital) सुरक्षित कोष तथा अन्य वस्तु से अधिक श्रृंख नहीं देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों से उस देश के केन्द्रीय बैंक, अथवा सरकारी खजाने (Treasury) के द्वारा ही फास्वाफ करेगा और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र भी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अपने केन्द्रीय बैंक द्वारा ही वारवार करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक नीचे लिखी दशाओं में ही श्रृंख देगा:—

(१) यदि कोई सदस्य राष्ट्र की सरकार स्वयं श्रृंख लेना चाहे तब तो अन्तर्राष्ट्रीय बैंक बिना केन्द्रीय बैंक की गारंटी के ही श्रृंख दे देगा अन्यथा जिस देश में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है उसको श्रृंख देने के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस देश के केन्द्रीय बैंक से श्रृंख की अदायगी की गारंटी लेगा।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उसी दशा में आर्थिक सहायता देगा जब उसको विश्वास है जावे कि वर्तमान स्थिति में उचित रूप पर उस कार्य के निम्ने किसी देश में श्रृंख नहीं मिल सकता।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस योजना की जाँच के लिये विशेषज्ञों की एक समिति विठायेगा और जब उस समिति की सम्मति में वह योजना ठीक होगी तभी वह आर्थिक सहायता देगा। बैंक किसी देश के पुनर्निर्माण अथवा आर्थिक उन्नति के लिये हा श्रृंख देगा।

यदि बैंक स्वयं किसी सदस्य राष्ट्र को श्रृंख देगा तब तो वह उचित रूप लेगा ही। परन्तु यदि बैंक किसी राष्ट्र को दिये गये श्रृंख की अदायगी की गारंटी देगा तो भी वह इस जोखिम के बदले में कुछ गारंटी कमेशन लेगा।

बैंक इस बात की देख बाल रखेगा कि किसी राष्ट्र ने जिस योजना को कार्यान्वित करने के लिये श्रृंख लिखा है वह स्कम उसी योजना पर न्यय होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का प्रबन्ध:—
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष (International Monetary Fund) के १२

संचालक (Directors) होंगे । उनमें से पाँच डायरेक्टर तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के 'प्रतिनिधि' होंगे । इन पाँचों राष्ट्रों को एक-एक स्थायी सदस्य रखने का अधिकार होगा । दो डायरेक्टर अमेरिकन प्रजातंत्रों की ओर से चुने जावेंगे और शेष पाँच डायरेक्टर अन्य सब देशों की ओर से चुने जावेंगे । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि फंड पर बड़े राष्ट्रों का ही प्रभाव रहेगा । भारतवर्ष ने इस योजना का इसी प्रश्न को लेकर विरोध किया था कि भारतवर्ष का व्यापारिक महत्त्व फ्रांस तथा चीन से अधिक है । इन देशों का कोटा राजनैतिक कारणों से अधिक रक्खा गया और भारत का कम रखा गया । फिर भारत-वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य के प्रबन्ध संचालक बोर्ड पर कोई स्थायी जगह भी नहीं दी गई । परन्तु बाद को भारतवर्ष को संचालक बोर्ड में एक जगह मिल गई । परन्तु यह कहना कठिन है कि जब सभी देश उसके सदस्य हो जायेंगे तो भारतवर्ष की चुनाव में क्या स्थिति रहेगी । उसे शेष पाँच जगहों में से एक जगह के लिये चुनाव लड़ना पड़ेगा । होना तो यह चाहिये कि भारत के महत्त्व को देखते हुये उसे एक स्थायी जगह दी जावे । यदि कोई सदस्य चाहे तो नोटिस देकर फंड से पृथक् हो सकता है ।

जो स्वर्ण कोष में इकट्ठा होगा वह संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रांस या चीन में रहेगा । कोष का प्रधान कार्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका में रहेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के भी १२ डायरेक्टर होंगे । उनमें से पाँच डायरेक्टर क्रमशः संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन नियुक्त करेंगे और ७ डायरेक्टर शेष सदस्यों द्वारा चुने जावेंगे । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के बोर्ड आफ़ डायरेक्टर पर भी भारत को कोई स्थाई स्थान नहीं मिला ।

रूस अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य नहीं बना इस कारण भारत पाँच बड़े राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया और उसको बैंक के बोर्ड पर एक स्थायी स्थान मिल गया । अब संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत को स्थायी स्थान प्राप्त है और शेष ७ स्थानों को शेष सदस्यों में से चुनकर भरा जाता है ।

डायरेक्टर एक प्रेसीडेंट का चुनाव करते हैं । प्रेसीडेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है । बोर्ड ही वास्तव में बैंक का संचालन करता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा ३० अक्टूबर १९४६ तक दिए गए ऋण की तालिका
(द्वारा अमेरिकन डॉलरों में)

(२४०)

क्र.सं.	देश	हालिक	डेनमार्क	लक्षम प्राप्त	मिलियन	पिनलैंड	चाइल	मैक्सिको	ब्राजील	कोल म्बिया	भारत	यूरो स्लाविया
१	टुनि	१०,३००	३०,८००	११,५००			२,८००			५,०००	१०,०००	२,७००
२	डोमोन धरे	१८५,५००	११३,१००	२३,७००	१०,३००	१२,३५०			२२,१४०		३४,०००	
३	पातायात	३३,३००	७८,१००	४,८००	५,७००	२,०००	११,८८३	३४,१००	५२,८००			
४	निष्ठुत शक्ति	६००				१५०	१,३०७					
५	अन्य											
	जोड़	२५०,०००	२२२,०००	४०,०००	१६,०००	१६,८००	१६,०००	३४,१००	७५,०००	५,०००	४४,०००	२,७००

बैंक का कार्यः—जैसे ही बैंक स्थापित हुआ डालर ऋण के लिये कई देशों के प्राथना पत्र आये किन्तु मई १९४७ में जाकर कहीं बैंक ने पहला ऋण दिया। शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का ऋण देने के लिये संयुक्तराज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में ऋण लेना होगा। ब्रिटेन बुद्धत सम्मेलन में लोगों का यह विचार था कि प्रत्येक देश जो डालर ऋण लेना चाहेगा वह अपने वांछ संयुक्तराज्य अमेरिका में बेचेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उनकी अदायगी की गारंटी दे देगा। विद्वानों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की गारंटी अमेरिकन पूँजीपतियों को उन देशों के बौद्धों में अपना धन लगाने के लिये प्रोत्साहित करेगी। परन्तु बैंक ने द्रव्य-बाजार की अव्यवस्थित दशा के कारण अन्य देशों के बौद्धों की गारंटी न देकर स्वयं अपने बौद्ध संयुक्तराज्य अमेरिका के द्रव्य-बाजार में बेचकर धन प्राप्त करना आरम्भ किया।

अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने जो ऋण भिन्न-भिन्न देशों को दिये हैं उनकी तालिका पृष्ठ १४० पर दी गई है :—

इस दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अभी तक योरोपीय देशों को ही अधिकतर ऋण दिया है।

भारतवर्ष को पहला ऋण ३१,०००,००० डालर का रेलवे ऍंजिन, वायलर्स, तथा रेलवे ऍंजिन के हिस्सों को खरीदने के लिये दिया गया। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान में रखने की है कि भारत सरकार ने रेलों का सुधार करने के लिये जितना व्यय किया उसका यह ऋण एक अंश मात्र था। भारत सरकार ने रेलों के सुधार में होने वाले भारी व्यय का अधिकांश भाग स्वयं अपने साधनों से प्राप्त किया। सितम्बर १९४६ में भारत सरकार को बैंक ने एक दूसरा ऋण १०,०००,००० डालर का कृषि के लिये ट्रैक्टर तथा अन्य यंत्र खरीदने के लिये दिया। बात यह है कि भारत सरकार खाद्य पदार्थों को अधिक उत्पन्न करने के लिये उस भूमि पर जहाँ आज जंगली वनस्पति, घास इत्यादि उत्पन्न हो रही है साफ करके खेती के योग्य बनाने का प्रयत्न कर रही है। भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिये ट्रैक्टरों इत्यादि की आवश्यकता थी।

अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने दामोदर घाटी योजना के लिए भी भारत को एक ऋण दिया है।

दूसरा भाग

भारतीय बैंकिंग

अध्याय १२

गाँवों के लिये साख की आवश्यकता तथा महाजन

और साहूकार

प्रामोण्य श्रृणुः—यों तो भारत के ग्रामीण श्रृणु के स्वयं में पहले भी कुछ अटकलें लगाई गई थीं किन्तु अब से पहले १९२६ में प्रामोण्य रूप से प्रान्तीय बैंकिंग कमेटियों ने अपने-अपने प्रान्तों में ग्रामीण श्रृणु का जो अनुमान लगाया उसके अनुसार सब प्रान्तों का श्रृणु १०० करोड़ रुपया था। कभी किसी सरकारी बैंच कमिटी ने देशी राज्यों में ग्रामीण श्रृणु का पता नहीं लगाया और न कभी देशी राज्यों ने ही यह जानने का प्रयत्न किया कि उनके किसानों पर कितना श्रृणु है। देशी राज्यों के किसानों की आर्थिक स्थिति प्रान्तों से भी गिरी हुई है। अस्तु देशी राज्यों का ग्रामीण श्रृणु सब प्रान्तों के ग्रामीण श्रृणु का एक तिहाई खराब या खराब है। अतएव १९२६-३० में समस्त भारत (हिन्दुस्तान और पाकिस्तान) का ग्रामीण श्रृणु १२०० करोड़ रुपये के लगभग था। किन्तु १९२६ के उपरान्त घोर आर्थिक मंदी के कारण सेतोकी पैदावार का मूल्य बहुत घट गया अस्तु श्रृणु का भार लगभग दोगुना हो गया। १९३० के उपरान्त घोर आर्थिक मंदी के फल स्वरूप ग्रामीण श्रृणु को वृद्धि का अनुमान लगाते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री रामचन्द्र महादेव का कहना था कि केवल प्रान्तों का ग्रामीण श्रृणु १२०० करोड़ रुपये

के लगभग था ' यदि इसमें देशी राज्यों का भी ग्रामीण ऋण जोड़ दिया जावे तो १९३६ के पूर्व समस्त भारत का ग्रामीण ऋण १८०० करोड़ रुपये के लगभग रहा होगा।

१९३६ के उपरान्त दूसरे महायुद्ध के फल स्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ता गया अतएव ग्रामीण ऋण कुछ कम अवश्य हुआ है। किन्तु अभी तक इस संबंध में प्रामाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। किन्तु यह कहना भी गलत है कि युद्ध काल में खेती की पैदावार की बढ़ी हुई कीमत का लाभ उठा कर किसान ने अपना सारा ऋण चुका दिया है। युद्ध काल में ग्रामीण ऋण कितना घटा इसकी जाँच के लिए केवल मद्रास सरकार ने डाक्टर नायडू को नियुक्त किया था। डाक्टर नायडू ने १६० गाँवों में ग्रामीण ऋण की जाँच की और १९४६ में अपनी रिपोर्ट मद्रास सरकार के सामने उपस्थित कर दी। रिपोर्ट के अनुसार मद्रास प्रान्त का १९३६ में कुल ग्रामीण ऋण २७२ करोड़ रुपये था जो १९४५ में घट कर २१८ करोड़ रुपये रह गया। दूसरे शब्दों में २० प्रतिशत ऋण में कमी हो गई। परन्तु उस रिपोर्ट के देखने से यह सात होता है कि बड़े किसानों के ऋण में अधिक कमी हुई। १९३६ में कुल ग्रामीण ऋण १५.४% बड़े किसानों पर था जो १९४५ में घट कर केवल १०.८ प्रतिशत रह गया। मध्यम श्रेणी के किसानों पर १९३६ में १३.५% ऋण था जो घट कर ४१ प्रतिशत रह गया अर्थात् केवल २.५ प्रतिशत की ही कमी हुई और बहुत छोटे किसानों पर कुल ऋण का १९३६ में ३५.३% ऋण था जो १९४५ में बढ़ कर ३८.७% हो गया अर्थात् जहाँ तक बहुत छोटे किसानों का प्रश्न था उनका ऋण पहले से बढ़ गया।

यदि हम गाँवों के रहने वालों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें तो हमें लगभग यही स्थिति सभी प्रान्तों में मिलेगी। भारतीय गाँवों में मजदूर वर्ग है जिसके पास भूमि नहीं होती वह अपने पड़ोसी किसानों के खेतों पर काम करके मजदूरी प्राप्त करता है। जब खेतों पर काम नहीं मिलता तो वह घास छील कर, लकड़ियाँ बेंच कर, भट्टों में काम करके तथा समीपवर्ती उद्योग-वर्धों वा शहरों में काम करके अपनी गुजर करता है। इन खेत मजदूरों के पास तो खेती की पैदावार बेचने को थी ही नहीं इस कारण खेती की पैदावार का मूल्य ऊँचा उठने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। जो छोटे किसान हैं जिनके पास पाँच दस बीघा भूमि है

उनके पास भी खेती को पैदावार इतनी अधिक नहीं थी कि वे अपनी आवश्यकताओं से बचाकर उसे बेचते और खेती की पैदावार के ऊँचे मूल्य से लाभ उठाते। हाँ यहाँ किसानों को खेती की पैदावार के बड़े हुए मूल्य से बहुत लाभ हुआ किन्तु उन्होंने माँ इस समृद्धि का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया। उन्होंने सोना चाँदी खरीदने में और धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यां पर अनाप शनाप व्यय किया। फिर भी यह मानना होगा कि उनके श्रृंख में बहुत कम हुई है।

ग्रामीण श्रृंख के कारण.—भारतीय ग्रामीण के श्रृंखी होने के नीचे निम्ने मुख्य कारण हैं:—

(१) पैतृक श्रृंख — भारतीय ग्रामीण श्रृंखी जन्म लेता है। अपने जीवन काल में श्रृंख का बढ़ाकर मरते समय उत्तराधिकार में श्रृंख का भार बौक अपने पुत्र के सिर पर छोड़ जाता है। बात यह है कि पैतृक श्रृंख इतना अधिक होता है कि छोटा किसान उसे कभी भा चुका नहीं सकता।

(२) साहूकारी और महाजनी की दूषित पद्धति:—गाँवों में २५ से ३७ प्रतिशत तो साधारणतः सूद लिया जाता है और कहा-कहा तो ७५ से १०० प्रतिशत तक सूद लिया जाता है। भारतीय अदालतों में ऐसे भी मुकदमें आये जिनमें एक हजार प्रतिशत तक सूद लिया गया था। किसान इतना अधिक सूद कभी भी नहीं चुका सकता। फल यह होता है कि एक बार श्रृंख लेने के बाद उसका सूद बढ़ता ही जाता है और श्रृंख इतना अधिक हो जाता है कि उसका सामर्थ्य के बाहर हो जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएँ गाँवों में सुनी जा सकती हैं। यदि किसी किसान ने २५० ६० उधार लिया और वह पाँच सौ दे चुका है किन्तु एक हजार देना शेष है। कभी-कभी महाजन बेई-मानी करके अपने बही खाते में सौ हुई रकम को बढ़ा कर लिख लेता है और उस पर किसान का झगूठा लगवा लेता है।

(३) किसान की निर्धनता — भारतीय किसान अत्यन्त निर्धन है उसके पास लाभदायक खेती के लिए यथेष्ट भूमि नहीं होती। यह उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने से तथा जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने से देश में भूमि का अकाल हो गया है। अतएव अधिकांश किसानों के पास बहुत कम भूमि है जिस पर लाभदायक खेती नहीं हो सकती और जो कुछ छोटी भूमि किसानों के पास है वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इस कारण उग पर गहरी खेती (Intensive cultivation) नहीं हो सकती। अस्तु साधारणतः किसान

को खेती से उतनी आय नहीं होती कि वह अपने परिवार का उचित रूप से पालन-पोषण कर सके, फिर आये दिन फसल नष्ट होती रहती हैं। कभी सूखा पड़ जाने से तो कभी अत्यधिक वर्षा हो जाने से, कभी बाढ़ से कभी टिंडी या फसलों के कीड़ों से और कभी ओले या तुषार से उसकी फसल मारी जाती है और उसे श्रृण लेने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। दोरों की छूत की बीमारियों से अत्यधिक मृत्यु होना भी उसके श्रृणी होने का एक कारण है। जब किसान का पशु मर जाता है तो उसे श्रृण लेकर दूसरा बैल खरीदना पड़ता है।

सामाजिक कारणः—ग्रामीण विवाह, जनेऊ, मृतक संस्कार तथा अन्य धार्मिक और सामाजिक कृत्यों पर अंधाधुंध रुपया व्यय करता है और मुकदमेवाजी में भी उसका बहुत व्यय होता है। कभी-कभी मुकदमेवाजी में वह नष्ट हो जाता है। सामाजिक कृत्य तथा मुकदमेवाजी उसके श्रृणी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है।

लगान और मालगुजारी :—लगान और मालगुजारी जिष्ठ कठोरता से वसूल की जाती है उसके कारण भी किसान को कभी-कभी श्रृण लेने पर विवश होना पड़ता है। विशेष कर जिस वर्ष फसल नष्ट हो जाती है अथवा खेती की पैदावार का मूल्य बहुत गिर जाता है तो लगान को चुकाने के लिए भी किसान को श्रृण लेना पड़ता है।

श्रृण का दुष्परिणाम :—श्रृण का दुष्परिणाम यह होता है कि जहाँ किसान का भूमि पर स्वामित्व है वहाँ भूमि उसके हाथ से निकल कर महाजन के हाथ में चली जाती है और किसान भूमि रहित हो जाता है उससे खेती की अवनति होती है और किसान के रहन-सहन का दर्जा गिरता है। फल स्वरूप खेती की पैदावार प्रति एकड़ गिर जाती है और इससे देश निर्धन होता है। यही नहीं कि श्रृणी होने से खेती पर बुरा प्रभाव पड़ता है किन्तु किसान की अपनी फसल कम मूल्य पर अपने महाजन या साहूकार को बेचने पर विवश होना पड़ता है। उदाहरण के लिए खंडसारी धंधे को ले लीजिये। किसान को कुछ रुपया पेशगी दे दिया जाता है, उस पर सूद नहीं लिया जाता किन्तु उसकी फसल को बाज़ार भाव से बहुत कम पर खरीद लिया जाता है। यही दशा अन्य फसलों की होती है क्योंकि महाजन या साहूकार खेती की पैदावार की खरीद विक्री का काम भी करता है। किसान उसके चंगुल में होता है अस्तु उसको अपनी फसल महाजन को कम मूल्य पर बेच देनी पड़ती है।

अतः श्रृणो होने के कारण किसान की आर्थिक स्वतन्त्रता जाती रहती है। वह अपने साहूकार का एक प्रकार से आर्थिक दास बन जाता है और उसका सारा उत्पाद जाता रहता है। वह खेती के मुभार और उसकी उन्नति के किसी भी मुक्ताव को स्वीकार करने के लिए उत्साहित नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि यदि मैंने अपने खेत में अधिक पैदावार की तो उनके पास न रह कर वह महाजन के पास चला आवेगा। उसका सूद इतना मयकर होता है कि किसान उसको चुका हा नहीं सकता। अस्तु किम वपे वसल श्रच्छी होती है तो महाजन का अधिक देना बढ़ता है और यदि फमल कम हो गई तो महाजन को कम स्वीकार करना पड़ता है। किसान को सों प्रत्येक दशा में ६ या १० महीने का भाजन हो मिलता है अतएव वह खेती की पैदावार को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न नहीं करता। ग्रामीण श्रृण गिछही हुई खेती का एक प्रधान कारण है और जब तक ग्रामीण को श्रृण मुक्त नहीं किया जाता तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती और न किसान के रहन सहन का दर्जा ऊँचा उठ सकता है। क्योंकि वह जो कुछ भूमि पर पैदा करता है उसका अधिकांश भाग महाजन के पास चला जाता है।

श्रृण समझौता बोर्ड (Debt Conciliation Boards) :—

केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने प्रांतीय सरकारों को यह राय दी थी कि इस ग्रामीण श्रृण का समझौता करा कर उसको नुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। पल स्वरूप कुछ प्रान्तों में श्रृण समझौता कानून बन गए हैं। मध्यप्रदेश, बंगाल आसाम, पंजाब तथा कुछ देशी राज्यों में इस प्रकार का कानून बना दिया गया है। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रांतों के कानूनों में कुछ भेद अवश्य है परन्तु मुख्य धारारें एक समान हैं। इस कानून के अन्तर्गत श्रृण समझौता बोर्ड की स्थापना की जाती है। यह बोर्ड किसान के सभी लेनदारों अर्थात् महाजनों से किसान पर उनका कितना लेना है उसका हिाव उपस्थित करने का कहते हैं और जब यह मात्तूम हो जाता है कि किसान पर कितना श्रृण है तो महाजनों से श्रृण की रकम को जितना भी कम हो सके उतना कम करा कर समझौता कराया जाता है और यदि महाजन एक उचित प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करता तो श्रृणी किसान को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र का प्रभाव यह होता है कि वह महाजन यदि अदालत में उस किसान पर डिमरी करावे तो उसे न्यायालय का व्यय नहीं मिलता और एक निरिचत सूद से अधिक नहीं मिल सकता। बंगाल के श्रृण समझौता ऐक्ट के

अनुसार यदि किसान के ४० प्रतिशत महाजन समझौता बोर्ड के फैसले को मान लेते हैं तो समझौता बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसान को एक प्रमाण पत्र इस आशय का दे दे कि जब तक किसान उन महाजनों का ऋण नहीं चुका देता जिन्होंने समझौता बोर्ड के फैसले को स्वीकार कर लिया है तब तक वे महाजन जिन्होंने फैसले को नहीं माना है न्यायालय से भी किसान से रुपया वसूल नहीं कर सकते। इस प्रकार समझौता बोर्ड उन महाजनों को अप्रत्यक्ष रूप से विवश कर सकता है कि वे समझौता बोर्ड के फैसले को स्वीकार करें।

यद्यपि ऋण समझौता बोर्डों से कुछ लाभ अवश्य हुआ किन्तु शीघ्रता पूर्वक ऋण का समझौता नहीं हो सकता क्योंकि इसमें महाजन का राजी होना आवश्यक है। और कभी-कभी सभी महाजन मिलकर एक हो जाते हैं इस कारण इन बोर्डों से अधिक सफलता नहीं मिली। इस कारण बहुत से वद्वानों का विचार था कि बिना कानून द्वारा ऋण को कम किए किसान का ऋण नहीं चुकाया जा सकता।

अभी प्रांतीय तथा भारत सरकार इस समस्या पर विचार कर ही रही थी कि काठियावाड़ की छोटी सी रियासत भावनगर ने जिस प्रकार अपने किसानों को ऋण मुक्त कर दिया उससे सारे देश का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। भावनगर के दीवान स्वर्गीय प्रभार्शकर पट्टानी ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उद्देश्य से एक आशा निकाली कि जिस किसी महाजन का किसी भी किसान पर कर्जा हो वह राज्य को उसका पूरा व्योरा निश्चित तारीख तक दे दे नहीं तो उसका कर्जा गैर कानूनी घोषित कर दिया जावेगा राज्य ने हिसाब लगाकर देखा तो भावनगर राज्य के तमाम किसानों का ऋण ८६,१८,८७४ रु० निकला। स्वर्गीय प्रभार्शकर पट्टानी ने महाजनों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि राज्य उनके समस्त ऋणों के बदले २०,५६,४७३ रु० देकर किसान को ऋण मुक्त कर देना चाहता है। पहले तो महाजन इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि राज्य किसान को ऋण मुक्त कर देने पर तुला हुआ है और हमारे द्वारा इस प्रस्ताव को न मानने का फल यह होगा कि राज्य ऐसा कानून बना देगा कि उन्हें अपना रुपया वसूल करना कठिन हो जावेगा तो वे राजी हो गये। राज्य ने २०,५६,४७३ रु० देकर किसानों को ऋण मुक्त कर दिया। ध्यान रहे कि भावनगर का किसान उस तमाम कर्ज पर साल भर में २५ लाख रुपये केवल

सुर में दे देता था राज्य ने किसान में इस रकम को किसानों में वसूल कर लिया। श्रृंखला मुक्त होने का वचन यह हुआ कि भावनगर में खेती की बहुत उत्पत्ति हुई किसान अच्छे इस बैल और साद का उपयोग करने लगा है, मुझे खेदकर उसने वैज्ञानिक दम की खेती को अपनाया है क्योंकि श्रम उत्पत्ति (प्रदत्त) हो गया कि उसकी पैदावार उसके पास ही रहेगी। मविध में किसान विर महाजन के चणुल में न रेंस जाने इच्छित थे राज्य ने एक कानून बना कर किसान की साख को बहुत सीमित कर दिया है। राज्य ने तहसील देने का अनुचित प्रवण किया है।

व्यक्ति प्रान्तों में अभी तक ग्रामीण श्रृंखला की चुकाने का भावनगर लैला कोई प्रातिकारी बंद नहीं उठाया गया किन्तु सभी प्रान्तों में ग्रामीण श्रृंखला का कानून दम या हलका करने का प्रयत्न किया गया। अधिकतर प्रान्तों में किसानों के श्रृंखला गार को हलका करने के लिए कानून बना दिए गये। इन कानूनों के अंतर्गत यह की दर निर्धारित कर दी गई है उससे अधिक सुद की दर गैर कानूनी होगी। वही नहीं कि मविध में महाजन अधिक से अधिक जितना सुद ले सकता है वरन् पिछले श्रृंखला पर भी सुद की दर क्या होना चाहिये यह निश्चित कर दिया है और कहीं कहीं दाम चुपट का नियम भी लागू कर दिया गया है।

उत्तरप्रदेश में १९४० के कानून के अनुसार श्रृंखला को कम करने के लिए ४६ प्रतिशत सुद सुरक्षित श्रृंखला पर ६ प्रतिशत अर्धित श्रृंखला पर लगाया जावेगा। इसका अंतरित जा सुद नहीं चुकाया गया है उसके समय में बावदुपत का नियम लगाया जावेगा। किसान की भूमि का एक निश्चित अंश श्रृंखला के बदले कुछ नहीं करवाया जा सकता बहुत से प्रान्तों में इसी आधार पर श्रृंखला को कम करने के लिये कानून बने हैं।

मविध के लिए निम्न निम्न प्रान्तों में निश्चित की हुई सुद की दरें इस प्रकार हैं :-

प्रान्त	सुरक्षित श्रृंखला		अर्धित श्रृंखला	
	सादा न्याय	दर सुद	सुद	दर सुद
मद्रास	६.१%	मना है	६.२%	मना है
बम्बई	६	मना है	१२	मना है
बंगाल	१३	१०	२५	१०

पंजाब	१२	६	१८	१४
बिहार	६	मना है	१२	मना है
मध्य प्रदेश	७	५	१०	५
आसाम	१२½	मना है	१८½	मना है
उड़ीसा	६	मना है	१२	मना है

उत्तर प्रदेश में व्याज की दर श्रृण ली हुई रकम पर निर्भर है। जिस दर पर भारत सरकार प्रान्तीय सरकार को श्रृण देगी उससे नीचे लिखी हुई अधिक दर पर श्रृण दिया जा सकेगा :—

(सुरक्षित) सूद दर सूद (अरक्षित) सूद दर सूद

रकम ५०० रु० से कम	क+५½	क+३	क+१०½	क+७½
„ ५०१ से ५,००० रु० तक	क+४½	क+२½	क+८	क+६
„ ५,००१ से २०,००० रु० तक	क+३½	क+२	क+६½	क+४½
„ २०,००० रु० से अधिक	क+२½	क+१½	क+५	क+३½

इनके अतिरिक्त मदरास, बम्बई और मध्य प्रदेश में श्रृण की रकम को भी कानून द्वारा घटाने का प्रयत्न किया गया है।

मदरास किसान रिलीफ ऐक्ट के अनुसार १ अक्टोबर १९३२ के पहले लिए हुए श्रृण पर १ अक्टोबर १९३७ तक का बकाया सूद माफ कर दिया गया है और केवल मूल ही देना होगा। यदि मूल अथवा सूद की अदायगी के रूप में मूल से दुगुनी रकम अदा कर दी गई हो तो सारा श्रृण चुक गया मान लिया जावेगा। और यदि अदा की हुई रकम मूल श्रृण के दुगुने से कम हो तो शेष देकर किसान श्रृण मुक्त हो जावेगा। जो श्रृण १ अक्टोबर १९३२ के उपरांत लिया गया हो उसके मूल पर ५ प्रतिशत सूद लगाकर कुल रकम मालूम करली जाती है और उसमें से जितना श्रृण किसान ने अदा कर दिया है उसको घटा कर जो रकम शेष रहती है वह कर्जदार को देनी पड़ती है। इस रकम पर किसान को भविष्य में केवल ६½ प्रतिशत सूद देना पड़ता है।

मध्य प्रदेश के कानून के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि यदि श्रृण ३१ दिसम्बर १९२५ के पूर्व लिया गया हो तो श्रृण की रकम ३० प्रतिशत कम कर दी जावेगी। यदि श्रृण १ जनवरी १९२६ के उपरांत और १ अक्टोबर १९२६ के पहले लिया गया हो तो २० प्रतिशत और यदि श्रृण १

अक्टोबर १९२६ के बाद और ३२ दिसम्बर १९३० के पहिले लिया गया हो तो १५ प्रतिशत कम कर दिया जावेगा।

अम्बई में १२ प्रतिशत सूद के हिसाब से जो रकम ३१ दिसम्बर १९३० को देना है उसमें ४० प्रतिशत कम कर दा जावेगी और १ जनवरी १९३१ के बाद जो रकम देनी होगी उस पर ३० प्रतिशत कम कर दी जावेगा।

इन कानूनों के अतिरिक्त बहुत से प्रान्तों में महाजन की हिसाब पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाये गये हैं। यह कानून पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा उत्तर प्रदेश, आसाम, मद्रास और मध्य प्रदेश में बन गया है। इन कानूनों के अनुसार महाजन को मूल धन और सूद का पृथक् ठीक ठीक हिसाब रखना होगा और प्रत्येक कर्जदार को उसके कर्ज के व्योरे की एक प्रतिलिपि (नकल) निश्चित समय पर देनी होगी। इन कानूनों द्वारा महाजनों को विवश कर दिया गया है कि जब कर्जदार कुछ रुपया अदा करे तो उसकी रसीद कर्जदार को अवश्य दी जावे। जो महाजन ठीक ठीक हिसाब नहीं रखेंगे उन्हें दण्ड दिया जावेगा। किन्तु इन कानूनों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनके निरीक्षण या जाँच का कोई प्रबंध नहीं किया गया।

इन कानूनों के अतिरिक्त कुछ प्रान्तों में महाजन लायसेंस कानून भी पास कर दिए गए हैं। बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, अम्बई और पंजाब में महाजन कानून (Money Lenders License Act) बन गए हैं। इन कानूनों के अनुसार प्रत्येक महाजन को सरकार से एक लायसेंस लेना होगा। कुछ प्रान्तों में लायसेंस लेना आवश्यक है और शेष प्रान्तों में यह महाजन की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। परन्तु उन प्रान्तों में यदि महाजन ने लायसेंस नहीं लिया तो वह अपने कामों के लिए अदालत में नालिश नहीं कर सकता। प्रत्येक लायसेंसदार महाजन को नियमानुसार हिसाब रखना होगा और प्रत्येक कर्जदार को निश्चित समय पर उसका हिसाब लिखकर देना होगा। जब कभी कर्जदार कुछ रुपया महाजन को दे तो महाजन को उसकी रसीद देनी होगी। यदि कोई महाजन इन नियमों का पालन न करे तो उसे दण्ड मिलेगा।

भारतीय किसानों के ऋण के सम्बन्ध में यह सक्षिप्त विवेचन करने के उपरान्त अब हम कृषि के लिये साख्त (Credit) की आवश्यकता तथा उसके प्रबंध का अध्ययन करेंगे।

खेती की विशेषता:—इससे पहले कि खेती की साख के सम्बन्ध में अध्ययन करें हमें यह जान लेना चाहिए कि खेती और उद्योग-धंधों में बहुत भेद है। इसी कारण खेती के लिए आर्थिक प्रबन्ध करने में कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(१) जहाँ अन्य धंधों में बड़ी मात्रा की उत्पत्ति (Large Scale Production) होती है और बड़े-बड़े कारखाने तथा भीमकाय पुतलीघर होते हैं खेती में बहुधा छोटे-छोटे खेत होते हैं। यह छोटे-छोटे खेत बिखरे हुए एक दूसरे से पृथक् और अलगठित होते हैं। फिर खेती का कार्य एक समान नहीं होता। खेती का धंधा अनिश्चित धंधा है। वह प्रकृति पर इतना अधिक निर्भर है कि किसान के सब कुछ करने पर भी फसल नष्ट हो सकती है। अतएव खेती में जो जोखिम है उसका अनुमान लगाना कठिन है अतएव फसल को ऋण की जमानत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत कारखानों की यदि व्यवस्था ठीक है तो उनके माल की उत्पत्ति निश्चित होती है। यही कारण है कि कारखानों को तो हिस्से तथा दिवेंचर (ऋण पत्र) बैंचकर यथेष्ट पूँजी मिल जाती है और यदि उन्हें अन्य आवश्यकताओं के लिये साख चाहिए तो वह अपने माल की जमानत पर बैंकों से साख पा जाते हैं किन्तु किसान को अपनी पूँजी ही से काम चलाना पड़ता है। व्यापारिक बैंक उसको इसलिए साख देना पसन्द नहीं करते क्योंकि एक तो जितना ऋण वह लेना चाहता है वह बहुत थोड़ा होता है दूसरे उसकी फसल अनिश्चित होती है इस कारण उसकी जमानत (Security) स्वीकार योग्य नहीं होती।

(२) यदि खेती की पैदावार का मूल्य गिर गया है तब भी किसान खेती को छोड़ नहीं सकता। उसे खेतों पर फसल पैदा करना ही होगा नहीं तो भूमि बेकार पड़ी रहेगी और उस पर जंगली पौधे उग आवेंगे। इस कारण यदि खेती लाभदायक न भी हो तो भी किसान को फसल पैदा ही करनी पड़ती है। अतएव उसकी साख की आवश्यकता एकसी बनी रहती है और उसका ऋण बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि मूल्य गिर रहा हो तो अन्य धंधों में पैदावार को कम किया जा सकता है अथवा कुछ समय के लिए रोक जा सकता।

(३) यदि किसी समय उत्पत्ति आवश्यकता से अधिक हो गई हो तो

कारखाने अपने माल की जमानत पर बैंकों से ऋण लेकर उसको अपने गोशायों में रोक रख सकते हैं और पैदावार को कम करके उसके मूल्य को अधिक गिन्ने से बचा सकते हैं। किन्तु खेती में लगा हुआ किसान ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि उसका घरा अस्मगठित है उसकी फसल अनिश्चित है।

(४) खेती तथा द्रव्य बाज़ार में सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है क्योंकि व्यापारिक बैंक किसान को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होने। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान या तो फसल को अथवा भूमि को जमानत रूप में दे सकता है। व्यापारिक बैंकों के लिए ये दोनों प्रकार की जमानतें अनुपयुक्त हैं। फसल अनिश्चित होती है और भूमि लम्बे समय के लिए, लिए हुए ऋण के लिए तो उपयुक्त जमानत हो सकती है किन्तु व्यापारिक बैंकों के लिए उपयुक्त जमानत नहीं है क्योंकि वह शीघ्र ही आवश्यकता पड़ने पर बँची नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त किसान ऋण लेकर समय पर नहीं चुका पाता क्योंकि उसकी फसल का कोई ठीक नहीं रहता। अतएव व्यापारिक बैंक उसे ऋण नहीं देते क्योंकि उनकी डिपॉजिट बहुत थोड़े समय के लिए होता है वे उस रुपये को अनिश्चित काल के लिए नहीं अटक सकते।

(५) खेती के सम्बन्ध में जो ऊपर लिखी कठिनाइयाँ हैं वे भारतवर्ष में और भी अधिक भयंकर रूप में उपस्थित हुई हैं क्योंकि यहाँ का किसान अशिक्षित और निर्धन है तथा भयंकर ऋण के बोझ से दबा हुआ है और उसके पास आर्थिक जात (Economic Holding) न होने के कारण खेती लाभदायक घरा नहीं है। यही कारण है कि खेती के लिए सहकारी साख समितियों (Co-operative Credit Societies) का आयोजन किया गया है।

किसान की साख की आवश्यकता — यह हम पहले ही कह चुके हैं कि खेती के लिए तीन प्रकार की साख की आवश्यकता होती है—(१) थोड़े समय के लिए साख, (२) स्थावरण समय के लिए साख, (३) और लम्बे समय के लिए साख। थोड़े समय के लिए साख की आवश्यकता बाज, खाद, हल तथा अन्य औजारों को खरीदने तथा खेती की पैदावार को मंडी तक ले जाने के लिए तथा खेती की अन्य क्रियाओं के करन के लिए होती है। किसान को खेती के कार्यों के लिए ६ महीने के लिए साख की आवश्यकता

होती है। साधारण समय के लिए साख की आवश्यकता पशुओं की खरीदने, मूल्यवान औजारों को मोल लेने, सिंचाई करने, बाढ़ बनाने तथा अन्य सुधार करने के लिए आवश्यक होती है। लम्बे समय के लिए ऋण की आवश्यकता पुराने पैतृक ऋण को चुकाने, अधिक मूल्यवान खेती के यंत्रों की खरीदने, नई भूमि खरीदने के लिए होती है।

महाजन और साहूकार (पेशेवर और गैर-पेशेवर) देशो बैंकर, सहकारी बैंक, मिथी, और चिट-फंड (Chit Funds) व्यापारिक बैंक, इम्पीरियल बैंक, रिजर्व बैंक और सरकार, ग्रामीण साख का प्रबंध करते हैं अतएव हम अब इनके सम्बन्ध में लिखेंगे।

महाजन अथवा साहूकार (Money Lender) : भारतवर्ष में प्रत्येक गाँव में महाजन या साहूकार होता है जो लेन-देन का काम करता है। इन पेशेवर महाजनों और साहूकारों के अतिरिक्त और बहुत से गैर-पेशेवर लोग जैसे जमींदार, नौकरी करने वाले, चकील, व्यापारी इत्यादि जिसके पास भी कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता है वही लेन-देन करने लगता है।

गाँवों का पेशेवर महाजन या साहूकार छोटी रकम का ऋण केवल अपनी वही में लिख कर दे देता है और न कोई उसकी गवाही होती है। किन्तु जब रकम अधिक होती है तो ग्रामिसरी नोट लिखा लिया जाता है। वे किसान को बिना किसी जमानत के इस आधार पर ऋण दे देते हैं कि कर्जदार किसान अपनी फसल को महाजन को बँच देगा अथवा महाजन के द्वारा बँचेगा। एक प्रकार से वह फसल को गिरवी रख लेता है। किन्तु जब रकम अधिक होती है और बहुत लम्बे समय के लिए होती है तो भूमि, जेवर या मकान बंधक रख दिए जाते हैं। महाजन को इस बात की कोई चिन्ता नहीं होती कि किसान किस कार्य के लिए ऋण ले रहा है। वह खेती के लिए ऋण ले रहा है अथवा विवाह-शादी या अन्य अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेता है इससे महाजन को कोई मतलब नहीं होता। महाजन सूद दर सूद लगाता है और शीघ्र ही यह रकम बढ़ कर एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है।

इन महाजनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी महाजन इस देश में उत्पन्न हो गए हैं जो एक स्थान पर लेन-देन न करके एक विस्तृत क्षेत्र में लेन देन करते हैं वे गाँवों में समय समय पर आते रहते हैं और किसानों से लेन-देन करते हैं। उदाहरण के लिए पठान और काबुली सर्वत्र यह कार्य करते हैं।

विस्तारवाले उत्तरप्रदेश में, रोहिला मध्य प्रदेश में, गोसाईं और नागा बिहार और उड़ीसा में लेन देन का काम करते हैं। ये लोग ऋण देकर कर्ज लेने वाले का अंगूठे का निशान अपनी बंदी पर ले लेते हैं और प्रति मास एक रुपये के हिसाब से वसूल करते रहते हैं। यदि उन्होंने ८५० कर्ज दिये हैं तो वे एक रुपया प्रति मास वसूल करके वर्ष भर में १२ रुपये वसूल कर लेंगे। यह तो हम ऊपर ही कह आये हैं कि भिन्न भिन्न प्रान्तों में सूद की दर भिन्न है। बैंकिंग कमेटियों के अनुसार सुरक्षित ऋण पर १२ प्रतिशत से ३७½ प्रतिशत तक सूद लिया जाता है। काबुली तथा अन्य महाजन पिछड़े प्रदेशों में तथा गरीब आदिमियों से अरक्षित ऋण पर ७५ प्रतिशत से १५० प्रतिशत तक ऋण लेते हैं। कहीं कहीं ३०० प्रतिशत तक सूद लिया जाता है। कहीं-कहीं महाजन के अतिरिक्त और कोई साख देने वाली संस्था नहीं होती इस कारण वह मनमाना सूद लेता है। यही नहीं कभी कभी महाजन किसान को ठग भी लेता है। कोरे कागज पर अंगूठा लगा कर वह उसमें मनमानी रकम लिख लेता है। जब किसान थोड़ा थोड़ा करके रुपया चुकाता है तो उसको नहीं चढ़ाता। कर्जदार से बहुत सी वस्तुयें मुपन लेता है। कहीं-कहीं तो कर्जदार की स्थिति दास की तरह हो जाती है। वह अपने महाजन का दास बनकर उसकी सेवा करता है। महाजनी लेन देन के इन्हीं दोषों के कारण प्रान्तीय सरकारों को उनके कारबार पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कानून बनाने पड़े।

पिछले दिनों महाजनी कारबार कम होता जा रहा है क्योंकि प्रत्येक प्रान्त में किसान की ऋण से रक्षा के लिए कानून बन गए हैं। महाजन को अपना रुपया वसूल करने में कठिनाई होने लगी है अतएव बहुत से महाजनों ने लेन देन का काम बंद कर दिया है। भविष्य में लेन देन का काम और भी कम हो जावेगा।

सरकार द्वारा दिये गए तत्काली ऋण—भारतवर्ष में प्रान्तीय सरकारें किसान का लम्बे समय के लिए तथा थोड़े समय के लिए तक की ऋण देती हैं। लम्बे समय के लिए तत्काली ऋण १८८३ के भूमि सुधार ऋण कानून (Land Improvement Loans Act) के अन्तर्गत दिया जाता है और थोड़े समय के लिए तत्काली ऋण किसान ऋण कानून (Agriculturists Loan Act) के अन्तर्गत दिया जाता है। पहले कानून के अन्तर्गत भूमि का सुधार करने, कुर्चा खोदने

या दान बनाने के लिए लम्बे समय के लिए ऋण दिया जाता है और दूसरे कानून के अन्तर्गत खेती-बारी के लिए उदाहरण के लिए बीज, डल, खाद, धूल इत्यादि खरीदने के लिए थोड़े समय के लिए ऋण दिया जाता है। पहले कानून के अनुसार ऋण अधिक से अधिक ३५ वर्षों के लिए दिया जा सकता है किन्तु व्यवहार में २० वर्षों से अधिक के लिए ऋण नहीं दिया जाता। दूसरे कानून के अन्तर्गत ऋण १ वर्ष या २ वर्ष के लिए दिया जाता है और फसल तैयार होने के उपरान्त वसूल कर लिया जाता है। इन दोनों कानूनों के अन्तर्गत सब प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिए गए ऋण की रकम क्रमशः ३५ लाख और ६० लाख रुपये वार्षिक होनी है। भारत जैसे विशाल देश में इतना कम ऋण लिया जावे यह इस बात को सिद्ध करता है कि वह ऋण अधिक आकर्षक नहीं है और किसान सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का प्रयोग नहीं करते। इसके मुख्य कारण नीचे लिखे हैं:—

(१) किसानों की अभावश्यकता को देखते हुए ऋण बहुत कम दिया जाता है।

(२) जब किसान ऋण के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब कहीं जा कर उसे ऋण मिलता है।

(३) यद्यपि सूद बहुत उचित लिया जाता है (६ प्रतिशत) परन्तु तहसील के कर्मचारी जो ऋण देने का कार्य करते हैं वे किसान से रिश्वत और नज़राना लेकर ही उसके प्रार्थना पत्र पर सिफारिश लिखते हैं। अतएव किसान को ६ प्रतिशत से बहुत अधिक देना पड़ता है।

(४) ऋण को वसूल करने में बड़ी कठोरता का व्यवहार किया जाता है। कभी-कभी किसान को महाजन से ऋण लेकर तकावी का रुपया चुकाना पड़ता है।

(५) इसके अतिरिक्त यह जानकारी कि तकावी किस प्रकार ली जा सकती है अधिकांश किसानों को नहीं है इस कारण भी तकावी ऋण का भारतीय किसान ने अधिक उपयोग नहीं किया।

यदि ऋण का प्रबंध ठीक तरह से हो, ऋण लेने वाले को अधिक समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, उसे तहसील के अधिकारियों को रिश्वत और नज़राना न देना पड़े, यदि फसल नष्ट हो जावे तो वसूली रोक दी जावे, तकावी की वसूली में कम कठोरता बरती जावे, तकावी किस प्रकार

मिल सकती है इसकी जानकारी किसानों को करादी जावे, तथा सरकार यथेष्ट रकम भ्रूण देने के लिए रखे तो इनका अधिक उपयोग हो सकता है। अन्यथा तत्काली भ्रूणों का ग्रामीण साख में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

महायुद्ध और ग्रामीण भ्रूणः— महायुद्ध के पत्र स्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य आकाश छूने लग गया इससे गिद्दानों की तथा मर्ग साधारण की यह धारणा होने लगी कि या तो गाँव वालों का भ्रूण बिक-कुल हानुक गया होगा अथवा बहुत कम शेष रह गया होगा। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रामाणिक आँकड़े प्राप्त नहीं थे जिसके आधार पर कुछ कहा जा सके। हर एक व्यक्ति केवल अटकल से ही काम लेता था। अगस्त १९४१ में रिजर्व बैंक ने सब प्रान्तीय सरकारों को एक पत्र लिख कर ग्रामीण भ्रूण की जाँच की आवश्यकता बतलाई और प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। रिजर्व बैंक का कहना था कि युद्ध के पल स्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ गया है, इस कारण गाँवों के रहने वालों और विशेषकर किसानों के भ्रूण का भार हलका हो गया होगा। अस्तु इस समय किसी योजना के अनुसार इस समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं किया गया तो यह बहुत सम्भव है कि किसान फिर भयंकर भ्रूण में डूब जावे। इसी अभिप्राय से रिजर्व बैंक चाहता था कि ग्रामीण भ्रूण की जाँच की जावे और ऐसे उपाय किए जायें कि किसान फिर १९१९ की स्थिति में न पहुँच जावे। इस पत्र के आधार पर केवल मद्रास प्रान्त की सरकार ने १९४४ में डाक्टर नायडू को ग्रामीण भ्रूण की जाँच के लिए नियुक्त किया। डाक्टर नायडू ने प्रान्त के १६० गाँवों के भ्रूण की जाँच करके प्रान्त सरकार के भ्रूण का अनुमान लगाया। गाँव के परिवारों को पाँच भ्रूणों में बाँटा गया और उनकी जाँच की गई।

भ्रूण सर्वधी जाँच का परिणाम यह निकला कि जहाँ प्रान्त का भ्रूण १९३९ में २०२ करोड़ रुपये था और २२८ करोड़ रुपये है। प्रति मनुष्य पीढ़े वहाँ १९३९ में ५१ रु० भ्रूण था अब ४८ रुपये है। अस्तु मद्रास में कुल भ्रूण तथा प्रति मनुष्य पीढ़े भ्रूण केवल २० प्रतिशत घटा है। भ्रूण में जो कमी हुई है वह भी केवल जमींदारों तथा बड़े और सम्पन्न किसानों के भ्रूण में। छोटे किसानों तथा खेत मजदूरों का पूर्ववत् है। उसमें तनिक सा कमी नहीं हुई वरन् कुछ दशाओं में छोटे किसानों तथा खेत

मज़दूरों के ऋण में वृद्धि ही हुई है। रिज़र्व बैंक आव हन्डिया ने जो फुटकर गाँवों के ऋण की जाँच करवाई तो वह भी इसी निर्या पर पहुँचा कि ज़मींदारों तथा बड़े और सम्पन्न किसानों के ऋण में कुछ कमी अवश्य हुई है परन्तु छोटे किसानों और खेत मज़दूरों की दशा पूर्ववत् है। कहीं-कहीं उनके ऋण में वृद्धि ही हुई। अभी हाल में (१९५० में) बिहार सरकार ने खेत मज़दूरों की आर्थिक स्थिति की जो जाँच करवाई उससे पता चलता है कि वहाँ खेत मज़दूर की वार्षिक आय ४४४ रुपये है और उसका न्यूनतम व्यय ६१६ रुपये है। अतएव उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जाती है और वह अधिकाधिक फर्ज़दार होता जा रहा है। लेखक का भी यही मत है कि बड़े और सम्पन्न किसानों तथा ज़मींदारों के ऋण भार में तो कमी अवश्य हुई है किन्तु साधारण छोटे किसान तथा खेत मज़दूरों के ऋण में कोई कमी नहीं हुई। अब हम इस संबंध में विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

सच तो यह है कि भारत में अधिकांश किसानों के पास भूमि बहुत कम है। उस भूमि पर किसान के परिवार के योग्य अनाज ही उत्पन्न होता है। चार छ गीने में जो पैदावार होती है वह उसके परिवार के लिए ही हो जाती है अस्तु उसके पास बँचने के लिए बहुत कम बचता है। खेती की पैदावार के मूल्य की वृद्धि से लाभ तो उन बड़े और सम्पन्न किसानों को हुआ जिनके पास उनका आवश्यकता से अधिक पैदावार होता है और जो उसको बँचते हैं। अब प्रश्न यह हो सकता है कि छोटा किसान जिसके पास केवल अपने परिवार के पोषण योग्य ही पैदावार होती है वह लगान इत्यादि के खर्च किस प्रकार करता था। बात यह था कि युद्ध के पूर्व वह भूखा रहकर तथा केवल एक समय भोजन करके अपनी कुछ पैदावार को बेच कर आवश्यक खर्च करता था। आज वह उतना भूखा नहीं रहता और दोनों समय रोटी खाता है क्योंकि वह दो चार मन अनाज या थोड़ी सरसो, कपास या गन्ना बँचकर लगान तथा अन्य आवश्यक खर्च चुका देता है। गाँवों में एक वर्ग खेत मज़दूरों का भी है जिनके पास भूमि नहीं होती और जो गाँव के किसानों के खेतों पर मज़दूरी करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। खेती की पैदावार का मूल्य आकाश छूने से इस वर्ग को तो कुछ लाभ हुआ नहीं क्योंकि उनके पास बँचने को कुछ होता ही नहीं। अतएव केवल सम्पन्न किसान तथा ज़मींदारों को ही खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ने से विशेष लाभ हुआ है और उनका ही ऋण घटा है।

इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखने की है और वह यह है कि जो कुछ भी मुद्र के फलस्वरूप गाँव वालों की आर्थिक समृद्धि हुई है उसका ग्रामीण जनसंख्या ने पूरा लाभ नहीं उठाया । किसान ने विवाह, मृतक भोज, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में तथा तीर्थ यात्रा में अनाप रनाप व्यय किया । बहुत से गाँव वालों ने उन आवश्यकताओं को बढ़ा लिया जो शहरों के शौकीन लोगों तक समित थी । इन शौकीनी तथा विलास की वस्तुओं पर भी उनका व्यय बढ़ गया जो भविष्य में उनके लिए कष्ट साध्य होगा । गिन लोगों ने कुछ बचाया भी वह चाँदी खाने के रूप में बचाया जिसका मूल्य बहुत ऊँचा चढ़ गया है और मावस्थ में जब सोने और चाँदी का मूल्य गिरा तो उनका बचत आधी रह जावेगा । उपर व सन्निहित विवरण से यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी समृद्धि मुद्र के कारण ग्रामीण जन संख्या को प्राप्त हुई उसका ठाक उपयोग वह नहीं कर सका ।

आवश्यकता इस बात का थी कि किसान के ऋण का जाँच करवाई जाती तथा उनके महाजनों से ऋण का कम करवा कर एक समझौता करवा दिया जाता और सरकार किसी भी किसान की सहाय या मालगुजारी के साथ ऋण की किरतों का किसान से वसूल करके उनका ऋण चुका देती । किसानों को विश्वास दिला जाता कि वे अपनी पैदावार को बेच कर जो नकद पावे उसका एक अंश सहाकारी सार्व सन्निधि अथवा सरकार के पास जमा किया जावे । निन्तु ऐसा नहीं हुआ नहीं तो ऐसा अवसर था कि किसान को ऋण मुक्त किया जा सकता था और सम्पन्न किसानों के पास कुछ पैसा इकट्ठी की जा सकता थी । अब यदि भविष्य में खेतों का पैदावार का मूल्य गिरा तो किसान की स्थिति दयनीय हो जावेगी, उसका ऋण भार असहनीय हो जावेगा और उसका अनावश्यक खर्चाशील आदतें जो उसने इन दिनों में डाल ली है उस विशेष कष्ट साध्य होगी ।

अध्याय १३

देशी बैंकर (Indigenous Bankers)

भारतवर्ष में बैंकिंग व्यवसाय अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है । वैदिक युग के साहित्य (ईसा से २००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक) में इसका उल्लेख मिलता है किन्तु बैंकिंग के सम्बन्ध में विस्तृत और क्रमबद्ध विवरण ईसा के ५०० वर्ष पूर्व के पहले नहीं मिलता । ईसा के ५०० वर्ष पूर्व से आगे हमें भारतीय प्राचीन बैंकिंग व्यवसाय का पूरा विवरण प्राप्त है । उस समय भारत का बैंकिंग व्यवसाय उन्नति दशा में था । तत्कालीन साहित्य के पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि उस समय के देश के सभी व्यापारिक केन्द्रों में 'भेन्डी या बैंकर' होते थे और उनकी व्यापारिक तथा औद्योगिक संबंधों और व्यापारी समाज में बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान था । ये लोग विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों, बहुमूल्य पदार्थों की खोज में जाने वाले साहसी व्यक्तियों, तथा युद्ध इत्यादि अवसरों पर राजाओं और सम्राटों को ऋण देकर आर्थिक सहायता देते थे ।

मनुस्मृति से यह पता चलता है कि देश में लेन-देन का कार्य बहुत बढ़ गया था । इसी कारण मनुजी को सूद इत्यादि की दर को निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ी । यही नहीं उस समय देशी बैंकर जमा (डिपॉजिट) भी लेने लग गए थे । कौटिल्य अर्थशास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य ने जमानती ऋण पर अधिक से अधिक १५ प्रतिशत और गैर जमानती ऋण पर ६० प्रतिशत सूद की व्यवस्था की थी । किन्तु उस समय सूद की दर भिन्न-भिन्न वर्गों से भिन्न थी । ब्राह्मण को सब से कम सूद पर ऋण मिल जाता था किन्तु नीचे वर्ण के लोगों को अधिक सूद देना पड़ता था ।

हुण्डियों का भारतवर्ष में चलन बारहवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ । प्रारम्भिक मुस्लिम शासन काल में तथा मुगल बादशाहत में देशी बैंकरों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । उस समय वे देश के अन्दरूनी तथा विदेशी व्यापार के लिए साख का प्रबंध करते थे तथा शासकों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण

देते थे। मुगल शासन काल में देश के भिन्न भिन्न भागों में बहुत प्रकार के बाहु के सिक्के प्रचलित थे अतएव देश के अन्दरूनी व्यापार के लिए यह आवश्यक था कि इन सिक्कों का एक दूसरे में विनिमय हो सक। अस्तु इन बैंकों ने सिक्कों के विनिमय का काम भी अपने हाथ में ले लिया। सिक्कों की बदला बदला से इन्हें बहुत लाभ होता था। मुगल शासन काल में प्रमुख बैंकों का राज्य की ओर से टक्काल का अप्युछ, मालगुजारी वसूल करने वाला तथा राज्य का बैंक और सिक्के का विनिमय करने काका नियुक्त कर दिया जाता था। मध्य कालीन भारत में कई ऐसा दरबार नहीं पा जाहीं का प्रमुख बैंक न हो। शासक इन्हें जखत सेठ और नमर सेठ इत्यादि की उपाधियों से विभूषित करते थे और आवश्यकता पड़ने पर वे शासकों की श्रृणु देते थे। इन सेठों का खयाल और दरबार में बहुत मान और शक्ति होती थी।

किन्तु मुगल साम्राज्य के विघ्न भिन्न हावर नष्ट हो जाने से देशी बैंकों के काजार और उनकी प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। मुगल साम्राज्य के विघ्न भिन्न होने के उपरान्त भारतवर्ष में राजनैतिक अस्थिरता और लड़ाइयों का काल आरम्भ हुआ। उसका स्वभावतः बैंकिंग के कारबार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बहुत से शासक अपने श्रृणु को बुझाने में असमर्थ हो गए, राजनैतिक अस्थिरता के कारण देश का व्यापार ठप्प हो गया और उसका बैंकिंग पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का देश में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया तो देशी बैंकों का कारबार और प्रभाव और भी कम हो गया। यद्यपि अंग्रेजों ने आरम्भ में देशी बैंकों से भी श्रृणु लेना आरम्भ किया किन्तु अंग्रेजों ऐबेसी एंडों की स्थापना के उपरान्त बैंकिंग का अधिकतर कारबार उनके द्वारा होने लगा। यही नहीं १८१५ के उपरान्त देश में चितने सिक्के प्रचलित थे गैर कानूनी घोषित कर दिए गए और बाँदा का ठपका सर्व प्राप्ति सिक्का बनाया गया। इस परिवर्तन से देशी बैंकों का लाभदायक धंधा अर्थात् सिक्कों की बदला बदली नष्ट हो गया। इसका भी देशी बैंकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कमशः देश में रेली, पोस्ट आलिस का विस्तार हुआ और जहाजों के द्वारा विदेशों से व्यापार अधिक होने लगा। व्यापार में मूल मूल परिवर्तन हो जाने के कारण भी देशी बैंकों के कारबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। देशी बैंकों की अवन्ति के साथ साथ यहाँ परिबन्धीय देश के व्यापारिक बैंकों की स्थापना होने लगी तथा सरकार ने स्थान-स्थान पर खजाने स्थापित करके मालगुजारी तथा करों की

वसूली का प्रबंध कर दिया। अपने कारबार के कम हो जाने के कारण तथा व्यापारिक बैंकों की प्रतिस्पर्धा के कारण देशी बैंकों को इस देश में अवनति होना आरम्भ हो गई। परन्तु फिर भी वे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आज भी उनका कारबार बहुत विस्तृत और व्यापारिक बैंकों से सर्वथा स्वतंत्र है। आज स्थिति यह है कि एक तो देशी बैंकर हैं जिनके काम करने का ढंग पुराना और सर्वथा अपना है। उन्होंने पश्चिमीय ढंग के व्यापारिक बैंकों से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं समझी। दूसरे प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं जिन्होंने देशी बैंकों की अच्छाईयों को स्वीकार नहीं किया। अस्तु यह दोनों प्रकार की बैंकिंग संस्थायें सर्वथा एक दूसरे से स्वतन्त्र और भिन्न हैं।

देशी बैंकों की परिभाषा :—इससे पहले कि हम देशी बैंकिंग का अध्ययन करें हमें महाजन और बैंकर का भेद जान लेना चाहिये। महाजन तो केवल अपने पूँजी को श्रृणु स्वरूप देता है किन्तु बैंकर श्रृणु देने के अतिरिक्त जमा (डिपोजिट) भी स्वीकार करता है और हुंडी का कारबार भी करता है। किन्तु यह परिभाषा बहुत संतोषजनक नहीं है क्योंकि बहुत से बैंकर उदाहरण के लिए मुलतानी बैंकर डिपोजिट नहीं लेते किन्तु वे मुख्यतः बैंकिंग का ही कारबार करते हैं। कभी-कभी महाजनी और बैंकिंग के कारबार इतने मिले-जुले होते हैं कि उनमें भेद करना कठिन हो जाता है। भिन्न-भिन्न बैंकिंग इनकवायरी कमेटियों के मत के अनुसार डिपोजिट लेना देशी बैंकर का मुख्य लक्ष्य नहीं है वरन् हुंडी का काम करना उसका मुख्य लक्ष्य है। अस्तु हुंडी का कारबार करना देशी बैंकर का मुख्य लक्ष्य है।

साहूकारी और महाजनी का काम (अर्थात् लेन-देन करना) तो सभी जाति के लोग करते हैं किन्तु बैंकिंग का काम कुछ विशेष जातियाँ ही करती हैं। उनमें मारवाड़ी, वैश्य, जैनी, चेष्टी, खत्री और शिकारपुरी मुलतानी मुख्य हैं। मारवाड़ी राजपूताना के मारवाड़ प्रदेश से निकल कर भारत के प्रत्येक प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र में फैल गए हैं। उनका कारबार कलकत्ता, बम्बई के अतिरिक्त सभी केन्द्रों में फैला हुआ है। चेष्टियों का बैंकिंग कारबार मुख्यतः मदरास तथा बर्मा में है। खत्री पंजाब में अपना कारबार करते हैं और शिकारपुरी मुलतानी सिंध और बम्बई प्रान्त में अपना कारबार करते हैं। वोहरे गुजरात और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमीय भाग

में बैंकिंग का कारबार करते हैं। देशी बैंकर कोठेवाला, सॉफ्ट, आफ, तथा चेदी इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं।

इनमें से बड़े बैंकर अपने कार्यालय और एजेंटियाँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, देहली, रंगून, इत्यादि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में भी रखते हैं। इन शाखाओं को उनमें मुनीम या गुमान्ते चलाते हैं। इन मुनीमों को बहुत अधिक अधिकार होते हैं और वे अत्यन्त कुशल, ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। ये लोग अपने प्रधान कार्यालय को कारबार की रिपोर्ट भेजते रहते हैं और वहाँ से आशा लेते रहते हैं। समय-असमय पर बैंकर स्वयं आकर हिसाब की जाँच करता है।

यद्यपि अधिकांश देशी बैंकर स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं किन्तु उनमें से कुछ अब भी गुण्डे (Guilds) के सदस्य हैं जिन्हें 'महाजन' कहते हैं और जो उत्तर और दक्षिण भारत में अब भी पाये जाते हैं। यद्यपि इन 'महाजनों' अर्थात् लक्षों का मुख्य कार्य धार्मिक तथा सामाजिक होता है किन्तु वे दो बैंकों का आपसी झगड़े को निवटाने और विधानिका अदालत का काम भी करते हैं। विछले दिनों में देशी बैंकों ने अपने कुछ परिषद (Associations) स्थापित की हैं। उदाहरण के लिए बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद में आफ एसोसियेशन और मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कामर्स स्थापित हो गई हैं और बम्बई में मुलतानी और शिकारपुरी एसोसियेशन स्थापित है। रंगून में भी एक मारवाड़ी एसोसियेशन है और देहली में बैंकर्स एसोसियेशन है। इन एसोसियेशनों के द्वारा इन बैंकों के आपसी झगड़े तय हो जाते हैं तथा उनका संगठन टूट हो गया है। कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर दो एसोसियेशनों की सम्मिलित सभा होता है क्योंकि एक एसोसियेशन का सदस्य दूसरे एसोसियेशन का सदस्य से कारबार करता है। इसका अतिरिक्त देशी बैंकों का ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके द्वारा उन्हें माहको की खास सम्बन्धी जानकारी का आदान प्रदान हो और वे साल अथवा सुद के सम्बन्ध में एक ही नीति निर्धारित कर सकें। भिल भिन्न बैंकों में कोई सहयोग नहीं होता। दो मारवाड़ी और चेष्टवर बैंकों में आताथ सहयोग अवश्य होता है और वे समय पड़ने पर एक दूसरे को सहायता करते हैं।

इन बैंकों का क रवार पारिवारिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ा चलता रहता है। अतएव इनकी बैंकिंग की व्यावहारिक शिक्षा अनुयायन ही अपनी पंम का काम देखने से प्राप्त हो जाती है। हाँ उन्हें बैंकिंग की सैद्धान्तिक

शिक्षा प्राप्त नहीं होती। देशी बैंकर का कारबार सरल और भ्रष्टों से मुक्त होता है। इस कारण देशी बैंकर से काम करने में देरी नहीं लगती और न कोई विशेष भ्रष्ट ही होती है। ग्राहक हर समय बैंकर के पास जा सकता है। उसके काम का समय कोई निश्चित नहीं होता, वह हर समय काम करता है। उसके काम करने का ढंग बहुत कम खर्चीला और उनके दफ्तर इत्यादि का खर्चा बहुत कम होता है। उसके कार्यालय में कोई विशेष परनिचर या बहुत से क्लर्क नहीं होते। केवल कुछ मुनीम और एक-आध लिजोरी होती है। उनका हिसाब रखने का ढंग सरल और कम खर्चीला होता है किन्तु हिसाब बहुत ठोक रहता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हिसाब की जाँच की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती और न कभी लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) ही तैयार किया जाता है। देशी बैंकर बैंकिंग के साथ और भी व्यापार करता है किन्तु दोनों के हिसाब पृथक् नहीं रहते और न दोनों का रुपया ही अलग रखा जाता है। इन बैंकरों का कारबार भी अधिकतर पुस्तैनी पुराने ग्राहकों से ही होता है। ऐसे व्यापारी अधिक मिलेंगे जिनकी कई पुस्तें एक ही बैंकर की फर्म से कारबार करती रही हों।

बैंकर अपने पुराने ग्राहकों के परिवार से, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके व्यापार की दशा से भली भाँति परिचित होता है। इस कारण उसे इस बात का निश्चय करने में देरी नहीं लगती कि किस ग्राहक को कितना ऋण देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। ऋण देने के उपरान्त भी वह बैंकर अपने कर्जदारों के कारबार का समाप से देखभाल सकते हैं जैसा कि व्यापारिक बैंकों के लिए सम्भव नहीं है। वही कारण है कि उनका रुपया बहुत कम मारा जाता है। देशी बैंकरों से जब भी जमा किया हुआ हुआ वापस मांगा जाता है वे तुरन्त ही वापस कर देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बैंकर मांगने पर तुरन्त जमा किया हुआ रुपया वापस न करे। यही नहीं वे अपनी फर्म की सख और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे यथेष्ट नकद कोष (Cash Reserves) रखते हैं। वे अपने ग्राहकों को उनका लिखित हिसाब समय-समय पर देते हैं। यह बैंकर अपने उत्तरदायित्व को निवाहने और ईमानदारी से कारबार करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यही कारण है कि उनकी सख (Credit) बहुत ऊँची होती है और व्यापारी उन पर विश्वास रखते हैं।

यह बैंक चालू जमा (Current Deposits) और मंजूरी जमा लेते हैं। यह बी दर बीजन, रकम और कितने समय के लिए जमा की जा रहा है इसके अनुसार मिल देती है। परन्तु यहाँ यह न भूल जाना चाहिए कि आधुनिक ढंग के बैंक जितना जमा (रिपोजिटों) पर निर्भर रहते हैं उतने देशों के लिए निर्भर नहीं रहते। वे अपनी पूँजी पर ही अधिक निर्भर रहते हैं। मुलतानी और मारवाड़ी बैंक तो साधारणतः जनता से विपणित स्वीकार ही नहीं करते। वे अपनी पूँजी (Capital) से ही कार-बार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने क रिमाइनों से या सिंकारपुर तथा राकधुतावे में रहते हैं श्रृण से लेते हैं। मुलतानी इम्पीरियल बैंक से भी अधिकतर आवश्यकता पड़ने पर श्रृण से लेते हैं। पिछले दिनों में सहकारी बैंकों (Cooperative Banks), मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों (Joint Stock) तथा सरकार की प्रॉविस्टर्ड के कारण देशी बैंकों को कम विपणित मिलने लगी है। पोस्ट ऑफिस फैसल डिपॉजिट, सरकारी श्रृण, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, तथा सहकारी बैंकों तथा मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों की कार्य पद्धति अधिक आकर्षक है। वे विपणित आकर्षित करने के लिए निष्ठापन का सहाय लेते हैं। इस कारण जनता उनकी ओर अधिक आकर्षित होती है और उन्हें विपणित अधिक मिल जाती है। यह देशी बैंक एनन लोगों की विपणित लेते हैं। उन्हें मांगने पर नकदी में ही सहाय निकालने की सुविधा नहीं देते। कुछ देशी बैंक आवश्यक ही चेक बुक और पास बुक देते हैं किन्तु व्यापारिक बैंक तथा इम्पीरियल बैंक उनके चेकों को स्वीकार नहीं करते इस कारण उन पर कटि गए चेकों का चलन सीमित ही होता है। अब सीजन आने पर इन्हें अधिक रुपये की आवश्यकता होती है तो वे एक दुसरे से उधार ले लेते हैं और मछे मछे चेन्टों और शहरों में वे कुछ हद तक इम्पीरियल बैंक तथा अन्य मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों से प्रामितरी नोट पर श्रृण से लेते हैं या फिर हुडियों को बैंकों से मुमा कर अधिक कोष (Excess) प्राप्त करते हैं।

देशी बैंक किसानों को सीधे श्रृण नहीं देते परन्तु स्थानीय महाजन अथवा साहूकार को आवश्यकता पड़ने पर श्रृण देते हैं। यह महाजन किसानों को श्रृण देते हैं। यही नहीं देशी बैंक व्यापारियों और आदतियों को भी श्रृण देते हैं जो खेती की पैदावार को खरीदते हैं। देशी बैंक व्यापारियों और व्यवसायियों को साख देने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। वे हुडी मुमाते हैं, हुडिया खरीदते हैं, पैदावार पर श्रृण देते हैं और विपणित स्वीकार

करते हैं। कुछ औद्योगिक केन्द्रों में देशी बैंकर मिलों में अपना रुपया जमा कर देते हैं। रुपया मुहती जमा (Fixed Deposit) के रूप में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त देशी बैंकर बड़े-बड़े कारखानों को और कोई आर्थिक सहायक नहीं देते। हाँ आप कारखानों के डिबेंचर खरीद कर, तथा कंपनियों के शेयरों को अपने पास रख कारखानों को अधिक समय के लिए ऋण देते हैं।

देशी बैंकर बहुधा प्रामिसरी नोट पर ऋण दे देते हैं। यदि रकम बहुत अधिक हुई तो प्रामिसरी नोट पर जमानती के हस्ताक्षर ले लेते हैं नहीं तो बहुत अधिक सूद लेते हैं। एक दूसरा तरीका यह है कि ऋण लेने वाला प्रामिसरी नोट लिखने के स्थान पर ऋण को स्वीकार करते हुए एक रसीद लिख देता है जिसमें सूद का दर का भी उल्लेख रहता है। एक तीसरा तरीका स्टाम्प पर मुर्जा लिखाकर ऋण देने का है। इस याद में ऋण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सभी शर्तों का उल्लेख रहता है। एक चौथा तरीका ऋण देने का यह भी है कि ऋण लेने वाला बैंकर की बही में ही हस्ताक्षर करदे और उस पर स्टैम्प लगा दिए जायें। जब बैंकर बहुत बड़ी रकम ऋण देते हैं तो भूमि तथा इमारत इत्यादि को बचक रख लेते हैं किन्तु उस दशा में सूद की दर कम कर दी जाती है।

ऋण देने के अतिरिक्त देशी बैंकर हुंडी का कारबार बहुत अधिक करते हैं। हुंडियाँ कई प्रकार की होती हैं। (१) दर्शनी हुंडी का भुगतान तुरन्त करना पड़ता है। मुहती हुंडी की एक अवधि होती है (११, २१, ३१, ४१ दिन इत्यादि ३६१ दिन तक)। धनोयोग और शाहजोग हुंडियाँ भी होती हैं। उनका भुगतान करने से पूर्व बैंकर को यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि वह जिस व्यक्ति को भुगतान कर रहा है वही उस हुंडी का न्यायोचित स्वामी है। यदि वह गलत व्यक्ति को भुगतान कर देता है तो वह वास्तविक स्वामी के लिए फिर भी देनदार रहेगा। किन्तु दर्शनी हुंडी और मुहती हुंडी को जो भी व्यक्ति उपस्थित करे उसे भुगतान कर देने से बैंकर का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। हुंडियाँ देखनहार (Bearer) और फरमानजोय (Payable to Order) भी होती हैं। कभी-कभी यह लोग हुंडियों को अपने एजेंट तथा अन्य व्यापारियों पर केवल इसलिए लिख देते हैं जिससे उन्हें रुपया प्राप्त हो जावे। उदाहरण के लिए एक व्यापारी को दस हजार रुपये की आवश्यकता है। वह अपने एजेंट तथा किसी अन्य व्यापारी

पर जिससे उसका सम्बन्ध है दस हजार की हुंडी लिख देता है और उसको किसी देशी बैंकर से मुना कर रुपये प्राप्त कर लेता है। जिस सूद की दर पर देशी बैंकर हुंडी मुनाते हैं उसको बाज़ार-दर कहते हैं। यह बाज़ार-दर घटती-बढ़ती रहती है और मिला मिला व्यापारिक केन्द्रों की बाज़ार-दर में बहुत मिलाता रहती है। हुंडियों के द्वारा देशी बैंकर रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं।

बैंकिंग का काम करने के अतिरिक्त देशी बैंकर अन्य व्यापार भी करते हैं। उनकी जो पूँजी बैंकिंग के कारबार में लगी होती है उसमें तथा व्यापार में लगी हुई पूँजी में कोई भेद नहीं किया जा सकता। जब भी आवश्यकता हुई इधर की पूँजी उधर लगा दी जाती है। केरल मद्रास प्रान्त के नटकी-टाई चेन्नी और बम्बई प्रान्त के मुलतानी ही ऐसे देशी बैंकर हैं जो बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार नहीं करते हैं। नहीं तो अधिकांश देशी बैंकर अनाज, कपास, जूट तथा अन्य सेती की पैदावारों, कपड़े और सोना-चाँदी का व्यापार या सहा या पाटका करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ज्वेलर्स मर्चेंट, आदल ग्रांकर, ज्वेलर्स (ज्वेलर का) का भी काम करते हैं। व्यापार के साथ-साथ वे शक्कर, तेल, आटे के कारखानों तथा कपास, जूट, धान, रेशम तथा टीशे के कारखानों को भी जलाते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि देशी बैंकर बैंकिंग के साथ और भी व्यापार तथा व्यवसाय करते हैं और पशुधा उनको अपने व्यापारिक तथा व्यवसायिक कारबार से बैंकिंग की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि पिछले दिनों में देशी बैंकरो का बैंकिंग कारबार कम होता जा रहा है। इस कारण उन्होंने अपना ध्यान व्यापार तथा व्यवसाय की ओर अधिक लगाना आरम्भ कर दिया है।

देशी बैंकरो की अवनति के कारण :—देशी बैंकरो की क्रमशः अवनति हो रही है। उसके नीचे लिखे कारण मुख्य हैं :—

(१) इम्पीरियल बैंको, मिश्रित पूँजी के व्यापारिक बैंको (Joint Stock Banks) तथा सहकारी बैंको (Co-operative Banks) की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। इम्पीरियल बैंक को कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बहुत सुविधा है इस कारण देशी बैंकर रुपये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में उलझे होइ नहीं कर सकते। सहकारी बैंको का सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण वे सरलतापूर्वक डिपॉजिट आकर्षित

कर लेते हैं और मिश्रित पूँजी वाले बैंक ऋण देने में उनसे होड़ करते हैं । इस बदती हुई प्रतिस्पर्धा के होते हुए भी देशी बैंकरो ने अपनी कार्यपद्धति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जिससे वे इस प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते ।

(२) उनकी अवनति का दूसरा कारण यह है कि हुंडियों पर स्टाम्प ट्पूटी बहुत अधिक है इस कारण हुंडियों का चलन और कारबार कम होता है ।

(३) बैंकर्स साक्षी एक्ट (Bankers Evidence Act.) में जो बैंकों को कानूनी सुविधायें प्राप्त हैं वे देशी बैंकरो को प्राप्त नहीं हैं ।

(४) वस्तुओं का निर्यात (Export) करने वाली फर्मों अब प्रमुख मंडियों और व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखायें स्थापित करने लगी हैं । वे अभी तक इनको ही अपना एजेंट बना देती थीं । इस परिवर्तन का फल यह हो रहा है कि देशी बैंकरो का एजेंसी का कारबार भी कम होता जा रहा है ।

(५) देश में व्यापार का विस्तार होने के कारण देशी बैंकरो को व्यापार में अधिक लाभ दिलनाई देने लगा है अतएव वे सट्टा और व्यापार की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं ।

पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऊँचे दर्जे के देशी बैंकर अपनी कार्य पद्धति को बदलने लगे हैं और आधुनिक बैंकिंग के ढंग को अपनाने लगे हैं । वे चेक और पास बुक का उपयोग करते हैं और सेविंग डिपॉजिट भी स्वीकार करते हैं ।

देशी बैंकरो तथा उनके ग्राहकों का सम्बन्ध :—सभी बैंकिंग इन-क्वायरी कमेटियों ने देशी बैंकरो की सच्चाई और ईमानदारी की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उनके ग्राहक उनका बहुत आदर करते हैं और उन्हें अपना हित और मित्र समझते हैं । वे केवल अपने ग्राहकों से बैंकिंग का कारबार ही नहीं करते बरन् उनको व्यापार सम्बन्धी सलाह और परामर्श भी देते हैं । वे अपने ग्राहकों के कारबार पर दृष्टि रखते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे किस प्रकार का कारबार करते हैं । अपने ग्राहकों से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक पता रहता है जिसका वे अपने बैंकिंग कारबार में पूरा लाभ उठाते हैं ।

देशी बैंकों का व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) से सम्बन्ध :—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि साधारणतः देशी बैंक अपनी पूँजी और डिपॉजिटों से ही काम चलाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे एक दूसरे से रकबा ले लेते हैं। किन्तु जब व्यापार की तेजी होती है और उनके मादक अधिक ऋण की माँग करते हैं तो उनके यह साधन पर्याप्त नहीं होते। उन्हें इम्पीरियल बैंक, निमिष बैंक (Exchange Banks) तथा व्यापारिक बैंकों के पास आर्थिक सहायता के लिए विवश होकर जाना पड़ता है। किन्तु यह बैंक उन्हीं बैंकों को ऋण देते हैं जिनका नाम उनकी स्वीकृत सूची में है। इम्पीरियल बैंक तथा प्रायःक व्यापारिक बैंक उन देशी बैंकों की एक स्वीकृत सूची रखता है जिनको वह ऋण देना उचित समझता है। यही नहीं उस सूची में यह भी निर्धारित रहता है कि किस बैंक को अधिक से अधिक कितना ऋण दिया जा सकता है। अधिकतर यह बैंक देशी बैंकों की हुडिबां भुनाकर ही उन्हें ऋण देते हैं।

केन्द्रीय बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी तथा प्रांतीय बैंकिंग कमेटियों के सामने साक्ष्यित हुए देशी बैंकों के प्रतिनिधियों ने बार-बार यह शिकायत की थी कि इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक उनके साथ वैसा सद्दानुभूति का व्यवहार नहीं करते जैसा कि एक बैंक होने के नाते उनसे माय होना चाहिये। जब वे इम्पीरियल बैंक से ऋण लेते हैं तो इम्पीरियल बैंक उनके कारबार की जिम्मेदारी से जाँच पड़ताल करता है यह उनको बहुत असह्य है। फिर भी इम्पीरियल बैंक उन्हें वह सुविधाएँ प्रदान नहीं करता जो व्यापारिक बैंकों को प्रदान करता है। यही स्थिति बड़े व्यापारिक बैंकों की है। कभी-कभी बहुत ऊँचे दर्जे के प्रतिष्ठित देशी बैंकों को भी ऋण देना अस्वीकार कर दिया जाता है। इन आरोपों के उत्तर में इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों का कहना यह है कि देशी बैंक हमारे साथ कोई हिसाब नहीं रखते और वे बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापार तथा सहे में इतने अधिक फसे रहते हैं कि उनको अधिक ऋण देना जोखिम का काम है। उनकी ठीक-ठोक आर्थिक स्थिति को जान सकना कठिन होता है क्योंकि वे कभी अपनी लेनो देनी का लेख (Balance Sheet) वैशर नहीं करते। इस कारण उनका ऋण देने में सावधानी बरतना आवश्यक है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर लिखे आरोपों में बहुत सत्य है। जब इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंक को किसी देशी बैंक का अच्छी आर्थिक

स्थिति के सम्बंध में विश्वास और भरोसा हो जाता है तो वे उसकी सब प्रकार आर्थिक सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए मदरास के खेदियों और बम्बई के मुलतानी बैंकों को इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। बैंकिंग के सिद्धान्त के भी यह सर्वथा विरुद्ध है कि जो देशी बैंक सट्टे तथा अन्य व्यापार में अधिक फँसा हो उसको अधिक ऋण दिया जावे।

देशी बैंकों के संगठन के दोष और गुणः—यदि हम ध्यानपूर्वक देशी बैंकों के कार्यों का अध्ययन करें तो हमें उनके संगठन में निम्नलिखित दोष दिखलाई पड़ेंगेः—

(१) उनमें से अधिकांश दकियानूसी और रूढ़िवादी हैं और आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। उनमें समय के साथ अपनी कार्य पद्धति को बदलने की क्षमता नहीं है और न वे नई दिशाओं में अपने कारबार को बढ़ाने की ही क्षमता रखते हैं। वे अपना कारबार पुराने ढंग से अकेले और बहुधा गुप्त रूप से करने के अभ्यस्त हैं। इस कारण सर्वसाधारण की दृष्टि को वे आकर्षित नहीं कर पाते और न उनका अनता पर अधिक प्रभाव ही पड़ता है। इसका सम्भवतः एक कारण यह है कि देशी बैंकिंग का कारबार केवल कुछ परिवारों में ही सीमित है इस कारण उसमें नया रुधिर नहीं आता। इस कारण उनमें नये विचारों का समावेश नहीं हो पाता। इनके दकियानूसी होने तथा पुराने ढंग से चिपटे रहने का एक कारण यह भी है कि वे आधुनिक बैंकों के सम्पर्क में बहुत कम आते हैं।

(२) उनके संगठन का दूसरा दोष यह है कि वे बहुत कम जमा (डिपॉजिट) लेते हैं जो आधुनिक संगठित बैंकों का मुख्य कार्य है। इसका फल यह होता है कि देशवासियों की वचत डिपॉजिट के रूप में आकर्षित नहीं होती और न उसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए हो पाता है। बहुत सी पूँजी देश में बेकार पड़ी रहती है।

(३) वे व्यापार में हंडियों का उपयोग कम करते हैं। नक़द रुपये का उपयोग अधिक करते हैं।

(४) उनका व्यापारिक बैंकों से कोई सम्बन्ध नहीं होता इस कारण देश में दो द्रव्य-बाज़ार (Money Markets) साथ-साथ एक दूसरे से पृथक् रहकर काम करते हैं और दो सूद की दरें प्रचलित रहती हैं। यही नहीं रिजर्व

बैंक का भी इन पर कोई नियंत्रण नहीं है इस कारण देशी बैंकिंग प्रसरित रहता है ।

यद्यपि देशी बैंकों के संगठन में ऊपर लिखे दोष हैं परन्तु फिर भी उनकी देश की बहुत आवश्यकता है क्योंकि देश में बड़े-बड़े नगरों को छोड़ कर छोटे स्थानों और मंडियों में व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं । वहाँ केवल देशी बैंक ही बैंकिंग सुविधायें प्रदान करते हैं । यद्यपि पिछले वर्षों में देश में निहित पूँजीवाले व्यापारिक बैंकों का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, नये बैंक खोले गए और पुराने बैंकों ने अपनी शाखाओं का खूब ही विस्तार किया, फिर भी देश के विस्तार को देखते हुए बैंकिंग की सुविधा कम है । और भारत जैसे वृद्धि प्रधान देश में इस बात की तो कभी सम्भावना ही नहीं हो सकती कि बड़े गाँवों, कस्बों और छोटे मंडियों में बैंकों की शाखाएँ स्थापित हो सकें । वहाँ तो देशी बैंक ही काम कर सकते हैं ।

उनके पास शताब्दियों का बैंकिंग अनुभव है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनको मिला है । उनके काम करने का ढंग कम खर्चाला है और उनका बैंकिंग अनुभव बहुमूल्य है । अतएव उसको नष्ट न होने देना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सेन्ट्रल बैंकिंग कमेटी ने देशी बैंकों के सुधार के लिए सुझाव रखे थे । सेन्ट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि जब रिज़र्व बैंक की स्थापना हो जावे तो देशी बैंकों का सम्बन्ध रिज़र्व बैंक से स्थापित कर देना चाहिए ।

देशी बैंक और रिज़र्व बैंक का सम्बन्ध — यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि सेन्ट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि रिज़र्व बैंक के स्थापित हो जाने पर देशी बैंकों का उससे सम्बन्ध स्थापित हो जाना चाहिए । अस्तु जब रिज़र्व बैंक की स्थापना हो गई तो रिज़र्व बैंक ने नीचे लिखी शर्तों पर देशी बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने का प्रस्ताव रखता :—

(१) जो भी देशी बैंक रिज़र्व बैंक से सम्बन्धित होना चाहेगा और रिज़र्व बैंक से सुविधायें प्राप्त करना चाहेगा उसे शुद्ध बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापार को छोड़ देना होगा ।

(२) उन्हें अपना हिस्सा, नोट्स, प्रत्येक से. जिस प्रकार रिज़र्व बैंक करे उस प्रकार रखना होगा । अपने हिस्से की नियमित रूप से आय-व्यय परीक्षकों से जाँच (आडिट) करवानी होगी ।

(३) रिज़र्व बैंक आवश्यकता समझने पर उनके हिसाब और कारवार का निरीक्षण कर सकेगा। उन्हें रिज़र्व बैंक को समय-समय पर अपने कारवार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और सूचनार्थ देनी होगी। रिज़र्व बैंक जिस प्रकार जानकारी उनसे चाहेगा उन्हें देनी होगी और रिज़र्व बैंक को उनके बैंकिंग के कारवार का नियंत्रण करने का अधिकार होगा।

(४) प्रत्येक देशी बैंकर की निज की पूँजी कम से कम पाँच लाख रुपये होगी और उनको अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिज़र्व बैंक के पास जमा करना होगा। फिर भी रिज़र्व बैंक उनसे सीधा सम्बन्ध स्थापित न करके अप्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के पक्ष में था।

ऊपर लिखा प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के मत के विरुद्ध था। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी (Central Banking Committee) का यह मत था कि आरम्भ में देशी बैंकों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिए उन पर कड़ी शर्तें न लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए आरम्भ में कुछ वर्षों तक देशी बैंकों को रिज़र्व बैंक में अनिवार्यरूप से जमा (Deposit) रखने पर विवश न करना चाहिए। किन्तु पहली गश्ती चिन्नी में रिज़र्व बैंक ने जो ऊपर लिखी शर्तें लिखकर भेजीं वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशी बैंकर उनको स्वीकार करने के लिए तैयार न था।

इस पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुआ कि रिज़र्व बैंक को २६ अगस्त १९३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ी जो केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप थी और उसमें देशी बैंकों का रिज़र्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाने की व्यवस्था थी। जिन शर्तों पर रिज़र्व बैंक देशी बैंकों को अपने से सम्बन्धित करने के लिए तैयार था वे नीचे लिखी थीं :—जो देशी बैंकर रिज़र्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें अपने कारवार को शुद्ध बैंकिंग तक ही सीमित रखना होगा, वे दूसरे प्रकार का व्यापार न कर सकेंगे। उन्हें अपने हिसाब को ठीक-ठीक रखना होगा और रजिस्टर्ड अकाउन्टेंट से उसकी जाँच करवानी होगी और जब रिज़र्व बैंक चाहेगा तो उनके हिसाब का निरीक्षण कर सकेगा। रिज़र्व बैंक उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी सूचना चाहेगा वह देनी होगी। शिख्यूल बैंक जो भी विवरण-पत्र (Statement) अपने कारवार के सम्बन्ध में समय-समय पर रिज़र्व बैंक को भेजते हैं वे उन्हें भी भेजने होंगे और लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet)

इत्यादि जो कम्पनी एक्ट के अनुसार बैंकों को प्रकाशित करना अनिवार्य है वे उन्हें भी प्रकाशित करने होंगे । जब देशी बैंकों की जमा (Deposit) उनकी पूँजी से पाच गुनी छ अधिक हो जावे तभी उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य जमा (Compulsory Deposit) रखनी होगी अन्यथा उन्हें रिजर्व बैंक में अनिवार्य जमा रखने की कोई आवश्यकता न होगी । प्रत्येक देशी बैंक को कम से कम २ लाख की पूँजी (Capital) रखनी होगी जिसे ५ वर्षों में बढ़ा कर पाच लाख करना होगा । जो देशी बैंक इन शर्तों को पूरा करेंगे रिजर्व बैंक उनकी हुडियाँ और बिलों को भुनावेगा, सरकारी लिक्विडिटी की जमानत पर श्रुत्य देगा और हमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वही सुविधायें देगा जो यह शेड्यूल (Scheduled) बैंकों को देता है ।

इस प्रस्ताव को मो देशी बैंकों ने स्वीकार नहीं किया । वे न तो अन्य व्यापार को छोड़ना ही चाहते हैं और न अपने हिसाब का निरीक्षण ही कराने के लिए तैयार हैं । रिजर्व बैंक का इस प्रस्ताव से उद्देश्य यह था कि देशी बैंक अन्य कारबार को छोड़कर अधिकाधिक डिपॉजिट बैंकिंग की ओर झायें और जिस प्रकार से मिश्रित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) कारबार करते हैं वे भी बारबार करें । किन्तु देशी बैंक अपने पुराने ढंग को छोड़ने को तैयार न थे और न वे वही पसन्द करते थे कि वे किसी को अपना हिसाब दिलावायें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में देशी बैंकों को रिजर्व बैंक के बताये हुए मार्ग पर ही चलना होगा । किन्तु रिजर्व बैंक के अधिकारियों को यह समझना चाहिये था कि देशी बैंक एक रात्रि में अपनी पुरानी पद्धति को छोड़ कर आधुनिक बैंकिंग पद्धति को जिस प्रकार अपना सकते हैं । रिजर्व बैंक को आरम्भ में उन्हें कुछ छूट देनी थी । इस प्रकार अमीतक रिजर्व बैंक और देशी बैंकों का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका । यद्यपि रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से ऊपर बिलों शर्तों पर देशी बैंकों को सम्बन्धित करने का प्रस्ताव वापस नहीं किया है ।

रिजर्व बैंक का कहना यह है कि यदि देशी बैंक रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं करते तो मो भारतीय द्रव्य-बाजार (Indian Money Market) से उनका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है यदि देश में एक खुला बिल बाजार (Open Bill Market) स्थापित हो जावे और उन्नति कर जावे । उक्त बिल बाजार में देशी बैंकों के बिल भी स्वतन्त्रतापूर्वक बिना

रोक-टोक के प्रचलित हो और भुनाये जावें । रिज़र्व बैंक इस स्थिति को लाने के लिये स्वीकृत देशी बैंकों के बिलों तथा हुंडियों को स्वीकार कर लेगा यदि वे किसी शिड्यूल बैंक के द्वारा उपस्थित की जावेगी । किन्तु रिज़र्व बैंक की यह आशा कि इस देश में खुला बिल बाज़ार स्थापित हो जावेगा संदेहात्मक है क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं । हम इस सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे ।

१ अक्टूबर १९४० को रिज़र्व बैंक ने क़य़ा एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने की एक नई योजना निकाली । उस योजना के अनुसार रिज़र्व बैंक क़य़ा एक से दूसरे स्थान को रियायती दर पर भेजने की उन देशी बैंकों और गैर-शिड्यूल (Non-Scheduled) बैंकों को सुविधा देगा जो कुछ शर्तों को पूरा करेंगे, और जो रिज़र्व बैंक की स्वीकृत सूची पर हों । अभी तक जिन देशी बैंकों ने इस सुविधा से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है और जिन्हें रिज़र्व बैंक ने स्वीकृत किया है उनकी संख्या अँगुलियों पर गिनी जाने लायक है ।

अन्त में हमें यह न भूलना चाहिए की देशी बैंकों का भविष्य उन्हीं के हाथ में है । उनके स्वार्थ में यही है कि वे अपने कारबार के ढंग में सुधार करें और व्यापारिक बैंकों के अनुसार ही अपनी कार्यपद्धति बना लें । साथ ही उन्हें अपने कारबार को भी मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों (Joint Stock Companies) के रूप में संगठित करना चाहिये । अथवा जैसा कि रिज़र्व बैंक का मत है उन्हें बट्टा कंपनियों (Discount Companies) में संगठित हो जाना चाहिये और बिलों के भुनाने का कार्य विशेष रूप से करना चाहिए तभी वे पनप सकेंगे ।

देशी बैंकों का देशी व्यापार के लिए बहुत उपयोग है अतएव उनका संगठन उनके लिये तथा देश के व्यापार के लिए हितकर होगा । किन्तु जब तक इस प्रकार का व्यवस्था नहीं होती कि शुद्ध बैंकिंग व्यापार से ही उन्हें यथेष्ट लाभ हो तब तक उनसे यह आशा करना व्यर्थ है कि वे अन्य व्यापार छोड़ देंगे । आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें बड़े व्यापारिक बैंक अपना एजेंट बना लें । हम प्रकार उन स्थानों पर भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जावे जहाँ बैंकों की ब्रांच कभी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती, और देशी बैंक बिलों तथा हुंडियों को भुनाने का अधिकाधिक काम अपने हाथ में लें । यह तभी हो सकता है जब देश में बिल बाज़ार उन्नत हो ।

अध्याय १४

सहकारी साख समितियाँ और सहकारी बैंक

(Co operative Credit Societies and Co operative Banks)

कृषि सहकारी साख समितियाँ (Agricultural Co operative Credit Societies) — भारतीय किसान मजदूर श्रृंखला के पोक से दया रहता है और महाजन ने द्वारा लूटा जाता है। किसान को खेती-गारी के लिए साख की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १९५४ में भारतवर्ष में कृषि सहकारी साख समितियाँ स्थापित की गईं। इन समितियों के सदस्य वे ही हो सकते हैं जो खेती-गारी में लगे हों तथा एक ही गाँव में रहते हों। प्रायेण गाँव के किसानों प॥ दूसरे की आर्थिक स्थिति से भली-भाँति परिचित होते हैं तथा एक दूसरे के व्यक्ति के विषय में भी जानकारी रखते हैं। यह साख समितियाँ असीमित उत्तरदायित्व (Unlimited Liability) वाली होती हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के व्यक्ति तथा आर्थिक स्थिति से भली भाँति परिचित हो। असीमित दायित्व के निदान के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के शुरुआत को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से चुनाने के लिए बाध्य है। यही कारण है कि इन समितियों में नवीन सदस्य तभी लिया जा सकता है जब दूसरे नए सदस्य उसकी सदस्य बनाने के पक्ष में हों। सहकारी साख समिति का निदान यह है कि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के कार्यों का उत्तरदायी बन जाता है। इन कारणों विली नवान सदस्यों की सर्वसम्मति से हो चुना जाता है।

प्रायः एक गाँव में एक ही साख समिति स्थापित की जाती है। समिति का प्रबन्ध करने का अधिकार साधारण सभा (General Meeting) तथा प्रत्येक वर्षीय समिति अर्थात् पंचायत को होता है। साधारण सभा तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अल्पमत दे देती है और पंचायत साधारण सभा की आज्ञा का पालन करती है। वस्तुतः साधारण सभा केवल नीति निर्धारित करती है और पंचायत तथा कार्य करती है।

प्रबन्धकारिणी समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

(१) वह सदस्यों को हिस्से देती है और उन्हें समिति का सदस्य बनाती है ।

(२) वह गाँव में डिपाज़िट (जमा) इकट्ठी करने का प्रयत्न करती है और सेन्ट्रल तथा डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है ।

(३) वह यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को कितने समय के लिए रुपया उधार दिया जावे । साथ ही वह उस अवधि के अन्त में ऋण के रुपये को वसूल करती है ।

(४) वह समिति के आय-व्यय का हिसाब रखती है और सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार से लिखा-पढ़ी करती है ।

(५) वह उन सदस्यों के लिए जो सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं तथा खेतों की पैदावार को बेचना चाहते हैं श्रृंखला का काम करती है ।

(६) वह सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करती है तथा उन्हें अपनी बचत को जमा करने के लिए उत्साहित करती है । वह सरपंच तथा मंत्री का चुनाव करती है । सरपंच समिति के कार्य की देखभाल करता है तथा मंत्री समिति का हिसाब रखता है ।

समिति प्रवेश-फीस, हिस्सों का मूल्य, डिपाज़िट, तथा ऋण के द्वारा कार्यशील पूँजी (Working Capital) इकट्ठा करती है । रक्षित कोष (Reserve Fund) भी समिति की कार्यशील पूँजी को बढ़ाता है । प्रवेश फीस नाम मात्र की होती है जो समिति की स्थापना में होने वाले व्यय के लिए ली जाती है । कुछ प्रान्तों में सदस्यों को समिति के हिस्से (Shares) खरीदने पड़ते हैं और कुछ प्रान्तों में हिस्से होते ही नहीं । पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में साख समितियाँ हिस्से वाली होती हैं । अन्य प्रान्तों में हिस्से तथा गैर हिस्से वाली दोनों तरह की समितियाँ दृष्टिगोचर होती हैं ।

भारतवर्ष में सहकारी साख समितियाँ हिस्से वाली दोनों चाहिए अथवा गैर हिस्से वाली, यह विचारणीय विषय है । कुछ विद्वानों का मत है कि समितियाँ हिस्से वाली होनी चाहिए, क्योंकि हिस्सों को बेचकर, थोड़ी कार्यशील पूँजी (Working Capital) इकट्ठी कर ली जाती है । समिति

अपनी पूँजी सदस्यों को श्रुत रखना देकर उस पर लाभ डठाती है और अग्रतत्त्व रूप से रक्षित कोष (Reserve Fund) की वृद्धि होती है। सदस्य समिति के कार्यों में विशेष रुचि से भाग लेते हैं, क्योंकि ये समिति को अपनी वस्तु समझते हैं। यह उन ठीक है, किन्तु भारतवर्ष के गाँवों में निर्घमना इतनी अधिक है कि ईमानदार परिश्रमी किसान को हिस्से का मूल्य चुकाने में कठिनाई हो सकती है और वह समिति की सदस्यता से वंचित रह सकता है। इस कारण कुछ प्रांतों में तो हिस्से होते ही नहीं और वहाँ हिस्से होते भी हैं और वगैरे से अधिक के नहीं होते किन्तु सदस्य धीरे धीरे किसानों में जुकाता है।

साख समिति का कोई भी सदस्य एक निश्चित रकम से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकता। प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। प्रवेश फल तथा हिस्सों के मूल्य से समिति के पास नाम मात्र की पूँजी (Capital) इकट्ठा होती है। इस कारण समितियाँ अधिकतर सेटल अथवा डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंकों से श्रुत लेकर काम चलावा करती हैं। भारतवर्ष में सहकाय साख समितियाँ अभी तक डिपॉजिट आकर्षित करने में सफल नहीं हुईं। वास्तव में कोई साख समिति बित्तनी ही अधिक डिपॉजिट आकर्षित करे वह ठवनी ही सफल समझी जानी चाहिए; क्योंकि डिपॉजिट सभी जमा होनी जब जनता को समिति का सहोदा होता। भारतवर्ष में कच्चे प्राप्ति को छोड़ और किसी प्रांत में अभी तक साख समितियाँ डिपॉजिट आकर्षित नहीं कर पाई हैं। साख समितियाँ उन लोगों से भी डिपॉजिट स्वीकार करती हैं जो समिति के सदस्य नहीं होते।

समिति के धन की कोई धेवन नहीं मिलता। केवल धनी को यदि वह सदस्य हो तो थोड़ा सा धेवन दिया जाता है।

सहकारी साख समितियों की स्थापना लाभ की दृष्टि से नहीं की जाती। इसलिए अपरिमित दायित्व (Unlimited Liability) वाली समितियों का लाभ हो नहीं जाता और यदि बाँटा भी जाता है तो वह रक्षित कोष (Reserve Fund) पूँजी के बराबर हो जाता है तब प्रांतीय सरकार से आशा लेकर बाँटा जाता है फिर भी यथेष्ट भाग रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है। परिमित दायित्व (Limited Liability) वाली समितियों में लाभ बाँटा जा सकता है किन्तु उनकी भी यथेष्ट धन रक्षित कोष में जमा करना पड़ता है।

सहकारी साख समितियों का प्रबंध-व्यय बहुत कम होने के कारण तथा लाभ न बंटने के कारण रक्षित कोष यथेष्ट जमा हो जाता है। प्रत्येक साख समिति के लिए रक्षित कोष अत्यन्त आवश्यक है। रक्षित कोष किसी भी अवस्था में सदस्यों में बांटा नहीं जा सकता। उसका उपयोग समिति के कार्य में हानि होने पर उसे पूरा करने में होता है। यदि किसी देनदार (Debtor) से रुपया वसूल नहीं होता अथवा किसी वस्तु को बेचने में हानि हो तो उसको रक्षित कोष से पूरा किया जाता है। यदि साख समिति मंग हो जावे तो रक्षित कोष (Reserve Fund) या तो किसी अन्य सहकारी समिति को दे दिया जावेगा या सहकारीता विभाग के रजिस्ट्रार की अनुमति से गाँव के सार्वजनिक हितकर कार्य में व्यय किया जावेगा। अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ रक्षित कोष के धन को अपने निजी कार्य में लगाती हैं बाहर जमा नहीं करती।

यदि किसी समिति को हानि हो जावे तो सर्वप्रथम उस सदस्य से रुपया वसूल किया जावेगा जिसने ऋण लिया है। यदि उससे वसूल न हुआ तो जमानत देने वाले से वसूल किया जावेगा। यदि उससे वसूल न हुआ तो रक्षित कोष से हानि भर दी जावेगी। यदि उससे भी हानि पूरी न हुई तो समिति की पूँजी का उपयोग किया जावेगा। यदि समिति की पूँजी देकर भी हानि पूरी न हो सके तो समिति के सदस्यों को समिति के लेनदारों (Creditors) का रुपया चुकाना होगा। प्रत्येक सदस्य को कितना रुपया देना होगा इसका हिसाब लिक्विडेटर (Liquidator) लगावेगा। व्यावहारिक दृष्टि से अपरिमित दायित्व से यहां अर्थ निकलता है किन्तु सिद्धांत से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से सारे ऋण को चुकाने के लिये बाध्य है। यह उसी दशा में हो सकता है जब और सदस्यों से रुपया वसूल न हो सके।

साधारण सभा (General Meeting) अपनी बैठक में समिति की साख (Credit) निर्धारित कर देती है, पंचायत उससे अधिक ऋण नहीं ले सकता। सामिति की साख को निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है कि सामिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाब लगाया जावे। समिति के सब सदस्यों की सम्पत्ति की एक चौथाई से आधी तक साख निर्धारित की जाती है। समिति इस कार्य के लिए एक हैसियत रजिस्टर रखती है जिसमें प्रत्येक सदस्य की हैसियत का लेखा रहता है। हैसियत रजिस्टर का प्रतिवर्ष संशोधन

होता है और प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथार्थ लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी भी अवस्था में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से अधिक उधार नहीं दिया जा सकता । रुपया उधार देते समय पचायत कर्जा लेने का उद्देश्य तथा सदस्य का चुकाने की शक्ति का अनुमान लगाकर ही कर्ज देना निश्चय करती है । श्रृणु केवल सदस्यों को ही दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त यह भी निश्चय कर दिया जाता है कि प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी भी दशा में सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रतिशत से अधिक श्रृणु नहीं दिया जाता । रुपया उधार देने के समय पचायत कर्जा लेने का उद्देश्य तथा सदस्य का चुकाने की शक्ति का अनुमान लगाकर ही कर्जा देना निश्चय करता है ।

सहकारी साल आन्दोलन का यह सिद्धान्त है कि श्रृणु अनुत्पादक तथा व्यर्थ कार्यों के लिए न दिया जावे । किन्तु भारत में सहकारी समितियाँ अनुत्पादक कार्यों के लिए विशेषकर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए श्रृणु दे देती हैं । पचायत का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह इस बात की जाँच करे कि सदस्य कर्ज किस कार्य के लिए ले रहा है । साथ ही पचायत को इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि सदस्य ने उसी कार्य में धन व्यय किया है या नहीं । यदि सदस्य ने किसी अन्य कार्य में धन व्यय किया है तो पचायत को रुपया वापस ले लेना चाहिये । परन्तु भारतवर्ष में इस ओर पचायत कभी भी ध्यान नहीं देती । खेती के लिए धन लिया जाता है और व्यय होता है अनुत्पादक कार्यों पर, किन्तु पचायत इसमें कभी भी रोक-टोक नहीं करती ।

पचायत श्रृणु देते समय सदस्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी बाध देता है, क्योंकि सदस्यों को विस्तों में रुपया अदा करने में मुश्किल होती है । पचायत का यह मुख्य कार्य है कि वह सदस्य से समय पर किस्त वसूल करे । यदि किसी अनिवार्य कारणवश (फसल नष्ट हो जाने पर) सदस्य किस्त न चुका सक तो उसकी मियाद बढ़ा देनी चाहिए ।

समितियाँ अधिकतर नीचे लिखे कार्यों के लिए श्रृणु देती हैं :— (१) खेती-बारी के लिए, मालगुजारी तथा लगान देने के लिए, (२) मूमि का

सुधार करने के लिए, (३) पुराने ऋण को चुकाने के लिए, (४) गृहस्थी के कार्यों के लिए, (५) व्यापार के लिए, (६) भूमि खरीदने के लिए । यह कह सकना कठिन है कि किन कार्यों के लिए कितना रुपया लिया जाता है । बहुधा सदस्य प्रार्थना पत्र में तो खेती-बारी के लिए रुपया लेने की बात लिखता है और उस रुपये को व्यय करता है किसी सामाजिक कार्य पर । साख्य समितियों ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

खेती में तीन प्रकार का ऋण चाहिए :—(१) थोड़े समय के लिए, (२) साधारण समय के लिए ऋण और (३) लम्बे समय के लिए ऋण । जो ऋण थोड़े समय के लिए लिया जाता है वह बीज, खाद, हल इत्यादि औजार खरीदने, गृहस्था का काम चलाने के लिए लिया जाता है और फसल कटने पर चुकाया जा सकता है । अस्तु अधिक से अधिक एक वर्ष में चुकाया जा सकता है । साधारण समय के लिए ऋण बैल लेने, कुआँ बनाने, अच्छे बंत्र खरीदने के लिए लिया जाता है और दो या तान वर्ष के लिए होता है । लम्बे समय के लिए लिया हुआ ऋण पुराना ऋण चुकाने, भूमि को खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने तथा कर्मती बंत्र इत्यादि खरीदने के लिए लिया जाता है । आरम्भ में तो सभी यह मानते थे कि सहकारी साख्य समितियाँ लम्बे समय के लिए भी ऋण दे सकती हैं और समितियों ने अधिक लम्बे समय के लिए ऋण दिया । किन्तु आज सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित सभी विद्वानों तथा कार्यकर्ताओं का यह निश्चित मत है कि साख्य समितियाँ किसान को तान वर्ष से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकतीं । बात यह है कि साख्य समितियाँ (Co-operative Credit Societies) डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल सहकारी बैंकों से ऋण लेकर सदस्यों को ऋण देती हैं और डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल बैंक एक वर्ष से तीन वर्ष तक के लिए मुहूर्त जमा (Fixed Deposit) स्वीकार करके पूँजी (Capital) इकट्ठी करती हैं । यह बैंकिंग का पहला सिद्धान्त है कि थोड़े समय की डिपॉजिट (जमा) से अधिक समय के लिए ऋण नहीं देना चाहिये । अतएव अब साख्य समितियाँ लम्बे समय के लिए ऋण नहीं देतीं । अधिक दिनों के लिए ऋण देने का कार्य सहकारी भूमि बंधक बैंक ही कर सकते हैं ।

समितियों का आय-व्यय निरीक्षण प्रान्तीय सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की देख-रेख और उसकी अधीनता में होता है । रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आडिटरों से साख्य समितियों के आय-व्यय का निरीक्षण करवाता है । यदि

आय-व्यय निरीक्षण (Auditing) का कार्य प्रांतीय सहकारी यूनियन अथवा किसी अन्य गैर सरकारी यूनियन को सौंप दिया गया हो जैसा बहुधा होता है तो रजिस्ट्रार उस दरखा के आडिटरों को लायसेन्स देता है तभी वे आय-व्यय निरीक्षण का कार्य कर सकते हैं। जो भी हो आय-व्यय निरीक्षण का उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार पर होता है।

१९४० के पूर्व सहकारी साल समितियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ५० प्रतिशत से अधिक श्रृण देना या निसका अदायगी की शिथि कम्पनी की निकल गई थी और सदस्यों ने उसका नहीं दिया था। वास्तव में कहीं कहीं तो स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि सेंट्रल बैंकों को कुर्क समान रखने पड़े, जिन्होंने साल समितियों के सदस्यों की कुर्की की, फिर भी कर्ज का बहुत करना बसूल नहीं हो पाया। जब मूल श्रृण की अदायगी की गई दशा या तब उस पर जो सूद इकट्ठा हो गया था उसका तो कहना ही क्या था। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से प्रान्तों में साल समितियाँ अस्थिर स्थिति में और निष्पाय हो गईं और लोगों को भय होने लगा कि आन्दोलन कहीं मर न जाय। किन्तु दिवाय मदरास के आरम्भ हो जाने तथा सेवा की पैदावार का मूल्य बहुत बढ़ जाने से किसान की आर्थिक दशा सुधरा और साल समितियों का श्रृण भा बसूल हो गया।

भारतवर्ष में लगभग १,२०,००० कृषि साल सहकारी समितियाँ हैं। उनके सदस्यों की संख्या ४९ लाख से ऊपर तथा कार्यशाला पूँजी ३६ करोड़ रुपये से अधिक है। इस पूँजी में ४० प्रतिशत तो समितियों की हिस्सा पूँजी (Share Capital) और राक्षत काय (Reserve Fund) है शेष ६० प्रतिशत उधार ला हुई पूँजी है जिसमें ८ प्रतिशत तो डिपॉजिट और शेष सेंट्रल बैंकों से उधार पर ली हुई पूँजी है। इन आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि साल समितियाँ सफल हो रही हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। साल समितियों की स्थिति भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न है। सहकारी साल समितियों का बम्बई, पंजाब और मदरास में अन्य प्रान्तों की तुलना में अधिक उत्थति हुई है और वहाँ साल समितियाँ सफल भा अधिक हुई हैं।

भारतवर्ष में जब कृषि सहकारी साल समितियों का वार्षिक आय-व्यय निरीक्षण होता है तब आडिटर उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। 'ए' वर्ग की समितियाँ बहुत अच्छी समझी जाती हैं, 'ब' वर्ग की अच्छा, 'सा' वर्ग की साधारण, 'डी' वर्ग की बुरी और 'ई' वर्ग की बहुत

सुरी जिन्हें दिवालिया कर दिया जाता है। ग्रान्तीय सहकारिता विभागों की रिपोर्टों में पता चलता है कि समितियों में से एक बहुत बड़ी संख्या 'डी' और 'ई' वर्ग में है। किसी-किसी प्रान्त में ४० प्रतिशत समितियाँ 'डी' और 'ई' वर्ग में है और २५ प्रतिशत से तो किसी प्रान्त में कम नहीं हैं। ६ प्रान्तों में १० प्रतिशत से भी कम समितियाँ 'ए' और 'बी' वर्ग में हैं। अस्तु रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि सहकारी साख समितियों की दशा संतोषजनक नहीं है। रिपोर्टों से यह भी ज्ञात होता है कि ६ प्रतिशत समितियाँ प्रतिवर्ष दिवालिया होती रहती हैं। समितियों की संख्या घटती नहीं है इसका कारण यह है कि नई समितियों का संगठन होता रहता है।

नगर सहकारी साख समितियाँ (Urban Co-operative Credit Societies) या ज्यूपिह्ल्स बैंक :—हमने ऊपर कृषि साख सहकारी समितियों का वर्णन किया जो गाँवों में होती हैं। नगरों में निर्धन कारीगरों, मज़दूरों, खोमचे वाले तथा दुटपूँजिया दूकानदारों, कारखाने के मज़दूरों और दफ़्तरों के बाधू लोगों के लिए भी सहकारी साख समितियाँ स्थापित की जाती हैं। इनकी संख्या इस देश में अधिक नहीं है। यद्यपि नगर साख समितियों की भी इस देश में अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि कारीगर किसान की ही भाँति महाजन के चंगुल में फँसा होता है। उनके माल को खरीदने वाले ही उनके महाजन होते हैं। यह व्यापारी कारीगर को या तो कच्चा माल उधार देते हैं अथवा चाया नकद उधार देते हैं, किन्तु शर्त यह होती है कि कारीगर को अपना तैयार माल महाजन व्यापारी को ही बेचना पड़ेगा। फल यह होता है कि निर्धन कारीगर महाजन के चिर दास बन जाते हैं। व्यापारी कारीगर को कम से कम मज़दूरी देकर उसका शोषण करता है। छोटे खोमचे वाले तथा दूकानदारों को भी पूँजी की आवश्यकता होती है। मिश्रित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) तो इन्हें ऋण देते नहीं और बिना साख के इनकी दशा शोचनीय रहती है इस कारण इन्हें भी साख की आवश्यकता होती है। कारखाने के मज़दूर भी दूकानदारों, महाजनों तथा काबुलियों के चंगुल में फँसे रहते हैं इस कारण उन्हें भी साख की आवश्यकता है; किन्तु अभी तक इस देश में नगर सहकारी साख समितियों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी कारण देश में नगर साख सहकारी समितियों की संख्या अधिक नहीं है।

नगर सहकारी साख समिति के सदस्यों को उसके हिस्से लेने पड़ते हैं

इस प्रकार समिति की कुछ हिस्सा पूँजी (Share-Capital) जमा हो जाती है । समिति का दायित्व परिमित (Limited Liability) होता है । प्रत्येक सदस्य की फिर उसने चाहे जितने हिस्से क्यों न खरीदे हों एक ही वोट देने का अधिकार होता है । सब सदस्यों की साधारण सभा होती है जो नीति निर्धारित कर देती है और प्रबंधकारिणी समिति अथवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मंजुरी का प्रबंध करता है । नगर साख समिति में वार्षिक लाभ कम से कम २५ प्रतिशत रक्षित कोष (Reserve Fund) में रखा जाता है । शेष सदस्यों में बाँटा जा सकता है । यह समितियाँ डिस्टा पूँजी (Share-Capital) के अतिरिक्त डिपॉजिट भी लेती हैं । अधिकांश समितियाँ केवल मुहूर्ती जमा (Fixed Deposit) लेती हैं । इनके अतिरिक्त रक्षित कोष भी उनकी कार्यशील पूँजी (Working Capital) को बढ़ाता है ।

बंगाल और बम्बई में नगर साख सहकारी समितियाँ सेविंग्स जमा (Savings Bank Deposit) और चालू जमा (Current Deposit) भी लेती हैं तथा हंडी को भुनाने का काम भी करती हैं । यह समितियाँ वास्तव में एक छोटे बैंक हैं और बंगाल तथा बम्बई में विशेष सफल हुए हैं ।

औद्योगिक केन्द्रों में कारखानों के मजदूरों के लिए भी सहकारी साख समितियाँ स्थापित हुई हैं । यदि कारखानों के मालिकों का इन समितियों को सहयोग प्राप्त हो जाता है तो वे अधिक सफल हो जाती हैं । किन्तु इनमें एक दोष शीघ्र ही प्रवेश कर जाता है । यह अपने मुख्य कर्तव्य अर्थात् सदस्यों में मितव्ययिता के भाव प्रचार न करके केवल सदस्यों को भ्रष्ट करने का कार्य करने लगती हैं । इस दोष की ओर ध्यान गया है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि सदस्य समितियों में सभा जमा भी करें ।

भिन्न-भिन्न दफ्तरी तथा कारखानों में कार्य करने वाले बचत भोगी कर्मचारियों की समितियाँ पृथक् होती हैं । इस प्रकार की साख समितियाँ अधिकतर सफल हो जाती हैं । इसका कारण यह है कि सदस्य सिद्धित होते हैं तथा उनमें नियमों को पालन करने का जो अभ्यास होता है उसके कारण समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता है । इसके अतिरिक्त यदि माल समिति को उम दफ्तर के प्रधान अथवा की भी सहायुक्ति प्राप्त हो जाती है तो

फिर कहना ही क्या है। उससे दिये हुए ऋण को वसूल करने में सहायता मिलती है।

नगर साख समितियाँ मदरास, बम्बई, बंगाल और पंजाब में विशेष रूप से हैं। बम्बई और मदरास में तो सभी बड़े-बड़े कस्बों में नगर साख सहकारी समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इन बैंकों की संख्या इस प्रकार है :—आसाम १७०, बंगाल ६१०, बिहार ११०, बम्बई ७००, मदरास १, २००, पंजाब ७५०, सिंध १३१, उत्तर प्रदेश ५००, मैसूर ३०० से अधिक, बड़ौदा २४, काश्मीर २७। सब मिलाकर देश में लगभग ७,००० नगर साख सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं।

नगर साख सहकारी समितियाँ कृषि साख सहकारी समितियों की अपेक्षा इस देश में अधिक सफल हुई हैं। वे अधिक मज़बूत और स्वावलम्बी हैं। नगर साख समितियों के दिये हुए ऋण की किस्तें बहुत कम बकाया रहती हैं। एक विशेष बात इन समितियों के सम्बन्ध में यह है कि वे अपनी हिस्सा पूँजी और डिपॉज़िट से ही इतना कमा पा जाती हैं कि उनका काम अच्छी तरह से चल जाता है। उन्हें सेन्ट्रल सहकारी बैंकों तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत जैसे देश में जहाँ निर्धन नागरिक को बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी बड़ी आवश्यकता है। डाक तथा रेल विभाग के सरकारी कर्मचारियों में यह समितियाँ विशेष सफल हुई हैं।

सरकारी सेन्ट्रल बैंक (Co operative Central Bank) :—

हम ऊपर ग्राम सहकारी साख समितियों तथा नगर साख सहकारी समितियों के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। पहले लोगों का विचार था कि ग्राम समितियाँ डिपॉज़िट आकर्षित करके पूँजी इकट्ठा कर लेंगी और आवश्यकता पड़ने पर नगर साख समितियों से ऋण ले लेंगी किन्तु यह आशा सफल नहीं हुई क्योंकि एक तो किमान ऋणी और निर्धन या दूसरे बैंकों में रुपया रखने का अभ्यस्त नहीं था। अस्तु यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि नगरों में सेन्ट्रल सहकारी बैंक खोले जावें जो ग्राम साख समितियों और गैर साख समितियों (Non-Credit Societies) के लिए पूँजी एकत्रित करें। १९०४ में जब पहला सहकारिता ऐक्ट पास हुआ था उस समय केवल ग्राम तथा नगर सहकारी साख समितियों के स्थापित करने का विधान था। अस्तु १९१२

में दूसरा सहकारी का ऐक्ट पास हुआ और सहकारी सेन्ट्रल बैंकों को स्थापित करने की सुविधा हो गई।

सेन्ट्रल बैंक दो प्रकार के होते हैं (१) ऐसे सेन्ट्रल बैंक जिनके सदस्य उस क्षेत्र की केवल सहकारी साख्त समितियाँ ही हो सकती हैं। इन्हें बैंकिंग यूनियन (Co-operative Banking Union) भी कहते हैं (२) ऐसे सेन्ट्रल बैंक जिनके सदस्य समितियाँ और व्यक्ति दोनों ही हो सकते हैं। देश में दूसरे प्रकार के बैंक ही अधिकतर हैं।

पहले प्रकार के सेन्ट्रल बैंक अर्थात् बैंकिंग यूनियन जिनके सदस्य केवल सहकारी समितियाँ ही हो सकती हैं वास्तव में आदर्श सहकारी सेन्ट्रल बैंक हैं। क्योंकि उससे सम्बन्धित सहकारी समितियाँ ही उसकी नीति निर्धारित करती हैं और बैंक का प्रबंध भी उन्हीं समितियों के हाथ में रहता है। किन्तु भारतीय देश में गाँवों में शिक्षा का अभाव है। ग्राम सहकारी समितियों का प्रबंध करने के लिए योग्य पात्रों का मिलना कठिन होता है। ऐसी दशा में सेन्ट्रल बैंकों के संचालन के लिए उनमें से योग्य डायरेक्टरों का मिलना और भी कठिन हो जाता है। यही कारण है कि देश में अधिकतर मिश्रित सेन्ट्रल बैंक हैं जिनमें से व्यक्ति भी सदस्य होते हैं जिनके सहयोग से बैंक का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

सेन्ट्रल बैंक का क्षेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है। उस क्षेत्र की समस्त समितियाँ उस बैंक से सम्बन्धित होती हैं और उससे श्रृंखला लेती हैं। दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सेन्ट्रल बैंक का क्षेत्र एक जिला होता है किन्तु उत्तर भारत में अधिकांश में एक तहसील में एक सेन्ट्रल बैंक होता है। जब जिले में एक ही सहकारी सेन्ट्रल बैंक होता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं।

साधारण सभा (General Meeting) :—सेन्ट्रल बैंक के हिस्सेदारों की सभा को साधारण सभा कहते हैं। सभा के प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होता है। साधारण सभा ही बैंक के डायरेक्टरों का चुनाव करती है। जिन बैंकों के सदस्य समितियों के प्रतिनिधि व्यक्ति भी होते हैं उनके विधान में समितियों के डायरेक्टरों और व्यक्तियों में से चुने गये डायरेक्टरों की संख्या निश्चित रहती है। समितियों के प्रतिनिधि डायरेक्टरों की संख्या अधिक होती है जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके।

बोर्ड आव डायरेक्टर :—संचालक (डायरेक्टर) बोर्ड बैंक का प्रबंध करता है। साधारणतः सेन्ट्रल बैंक के डायरेक्टर संख्या में अधिक होते हैं क्योंकि उसमें बहुत से स्वार्थी का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है। इससे यह कठिनाई होती है कि बोर्ड की मीटिंग करने में कठिनाई होती है इसलिए बोर्ड अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करता है जो बैंक का कार्य चलाती है। बैंक का दैनिक कार्य मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा चेयरमैन अथवा अचैतनिक मंत्री मैनेजर की सहायता और सलाह से चलाता है। डायरेक्टरों को फीस अथवा वेतन कुछ भी नहीं मिलता। अधिकांश डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु चेयरमैन और मंत्री व्यक्ति ही होते हैं। उत्तर भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में सेन्ट्रल बैंक का चेयरमैन सरकारी कर्मचारी होता है।

पूँजी (Capital) :—सेन्ट्रल बैंक की कार्यशील पूँजी (Working Capital) हिस्सा पूँजी (Share Capital) रक्षित कोष (Reserve Fund) डिपॉजिट तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती है।

वैकिंग यूनियन में केवल सहकारी समितियाँ ही हिस्से खरीद सकती हैं किन्तु मिश्रित सेन्ट्रल सहकारी बैंकों में व्यक्ति भी हिस्सा खरीद सकते हैं। सेन्ट्रल बैंकों के हिस्से ५० रु० से १०० रु० तक के होते हैं। सहकारी साख समितियाँ अपने ऋण के अनुपात में हिस्से लेती हैं। साधारणतः हिस्सेदारों का दायित्व (Liability) हिस्से के मूल्य तक ही सीमित होता है किन्तु कुछ प्रान्तों में हिस्सेदारों का दायित्व चार गुने से दस गुने तक है। प्रत्येक सेन्ट्रल बैंक को लाभ का २५ प्रतिशत रक्षित कोष में जमा करना पड़ता है। सेन्ट्रल बैंक इस २५ प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी विशेष रक्षित कोष जमा करते हैं। हिस्सा पूँजी और रक्षित कोष तो बैंक की निजी पूँजी होती है और डिपॉजिट तथा ऋण उधार ली हुई पूँजी होती है।

किन्तु सदस्यों तथा गैर सदस्यों की डिपॉजिट ही बैंक की कार्यशील पूँजी का बड़ा भाग होती है। सेन्ट्रल बैंक दो प्रकार की डिपॉजिट लेते हैं मुहती (Fixed) तथा सेविंग्स। किसी-किसी प्रान्त में चालू खाता (Current Account) भी रखा जाता है किन्तु चालू खाते में जोखिम अधिक है इस कारण अधिकांश बैंक उसे नहीं रखते। डिपॉजिट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सेन्ट्रल बैंक तथा वैकिंग यूनियन प्रान्तीय सहकारी बैंकों से ऋण लेते हैं। कमी-कमी सेन्ट्रल बैंक इम्पीरियल तथा अन्य बैंकों से

भी ऋण लेते हैं। यह बैंक एक वर्ष से लेकर ३ वर्ष तक के लिए मुदती जमा (Fixed Deposit) लेते हैं और अधिकतर उनकी कार्मशील पूँजी मुदती जमा से ही इकट्ठी होती ।

सेन्ट्रल बैंक अधिकतर सहकारी साख्त समितियों (Co operative Credit Societies) तथा गैर साख्त समितियों को ही ऋण देते हैं। पंजाब, मैसूर, मालियर, तथा मदरास में व्यक्तियों को भी ऋण दिया जाता है किन्तु अब यह रियाज बन्द किया जा रहा है। अपरिमित दायित्व (Unlimited Liability) वाली साख्त समितियों को सेन्ट्रल बैंक प्रो नोट अथवा बाह पर ही ऋण दे देते हैं। अपरिमित दायित्व होने के कारण उनका प्रो-नोट ही यथेष्ट जमानत समझा जाता है। किन्तु अन्य सहकारी समितियों से उसके अतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति भी गिरवी रखवाई जाती है।

यह जानने के लिए कि प्रत्येक सहकारी साख्त समिति को अधिक से अधिक कितना ऋण देना उचित होगा सेन्ट्रल बैंक अपनी सम्बन्धित साख्त समितियों की हैसियत के अनुसार उन साख्त समितियों की अधिकतम साख्त (Maximum Credit) निश्चित कर देते हैं। उससे अधिक ऋण किसी साख्त समिति को नहीं दिया जाता। ऋण की स्वीकृति होने में बहुत सी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है इस कारण ऋण मिलने में देर हो जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए कुछ सेन्ट्रल बैंक एक रकम निश्चित कर देते हैं जिससे समितियों को बिना किसी देरी के ऋण दे दिया जाता है।

सेन्ट्रल बैंक अधिकतर एक दो वर्षों के लिए ऋण देते हैं। कहीं-कहीं अब भी अधिक समय के लिए ऋण दिया जाता है। किन्तु अब अधिक लम्बे समय के लिए ऋण देने का कार्य केवल भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks) ही अधिक सफलता पूर्वक कर सकते हैं। अतएव अब जहाँ जहाँ भूमि बन्धक बैंक स्थापित हो गए हैं वहाँ सेन्ट्रल बैंक लम्बे समय के लिए ऋण बिल्कुल नहीं देते। प्रत्येक प्रान्त में यह धारणा जोर पकड़ रही है कि सेन्ट्रल बैंक अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे सकते। इसके लिए भूमि बन्धक बैंक स्थापित करना चाहिए।

सेन्ट्रल बैंक प्रारम्भिक सहकारी साख्त समितियों से ॥ प्रतिशत सुद लेते हैं और डिपॉजिट पर ३ से ५ प्रतिशत सुद देते हैं। पहले सुद की दर

अधिक भी अब सूद की दर घटा दी गई है। जब सहकारी साख समितियाँ बैंक को ऋण चुकाती हैं तो बैंक के पास आवश्यकता से अधिक रुपया हो जाता है। यह स्थिति वर्ष में दो से चार महीने तक रहती है। उस समय बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों में रुपया जमा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो रुपया स्थायी रूप से अधिक होता है और जो समितियों को ऋण देने में नहीं लगाया जाता उसको अधिक लम्बे समय के लिए जमा कर दिया जाता अथवा ट्रस्टी सिन्डिकेटी में लगा दिया जाता है।

सेन्ट्रल बैंक के वार्षिक लाभ का २५ प्रतिशत रक्षित कोष (Reserve Fund) में जमा कर दिया जाता है। माध्यम रक्षित कोष के अतिरिक्त कोई-कोई बैंक बड़े खाता (Bad debt)-इयागत अथवा लाभ-हानि सन्तुलन (Dividend Equalisation Fund) के लिए विशेष कोष इकट्ठा करते हैं। शेष लाभ हिस्सेदारों में बाँट दिया जाता है। किन्तु इन बैंकों के उपनियमों में लाभ की अधिक से अधिक दर भी निश्चित कर दी जाती है जिससे अधिक लाभ हिस्सेदारों को नहीं बाँटा जा सकता। सेन्ट्रल बैंक ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक लाभ बाँटते हैं। अधिकतर प्रान्तों में ६ प्रतिशत लाभ बाँटा जाता है।

सेन्ट्रल बैंक अपने से सम्बन्धित साख समितियों की देख-भाल करने के अतिरिक्त उन पर अपना नियंत्रण भी रखते हैं। इस कार्य के लिए कुछ कर्मचारी रखे जाते हैं। यह कर्मचारी (सुपरवाइज़र) ऋण के प्रार्थना पत्रों की जाँच करते हैं साख समितियों के सदस्यों की हैसियत का लेखा तैयार करते हैं और साख समितियों को अपने सदस्यों से रुपया वसूल करने में भी सहायक होते हैं। किसी-किसी प्रान्त में यह सुपरवाइज़र समितियों का हिसाब भी रखते हैं। जहाँ नवीन सहकारी साख समितियों को स्थापित करते हैं वह प्रचार कार्य भी करते हैं। किन्तु अब इनमें से बहुत सा कार्य प्रान्तीय सहकारी इन्स्टिट्यूट करने लगी हैं। कुछ प्रान्तों में समितियों की देख-भाल का काम सुपरवाइज़िंग यूनियनों को दे दिया गया है।

सेन्ट्रल बैंकों की आय-व्यय की जाँच सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त ऑडिटर करते हैं। यह सेन्ट्रल बैंक की वार्षिक स्थिति के सम्बन्ध में भी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं। सेन्ट्रल बैंक का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा उसके अधीनस्थ सहकारी विभाग के अन्य कर्मचारी करते हैं। प्रान्तीय बैंक भी उनका निरीक्षण करते हैं।

भारतवर्ष में कुल सिलाकर (ग्रान्ती और देशी राज्यों में) ६०० सहकारी सेन्ट्रल बैंक हैं। पंजाब १२०, बंगाल ११७, उत्तर प्रदेश ७, बिहार उड़ीसा ६८, मध्य प्रदेश ३५, मद्रास ३०, आन्ध्र २०, बम्बई ११, शेष देशी राज्यों में हैं। सब सेन्ट्रल बैंकों में लगभग ८०,००० व्यक्ति और १,५०,००० सहकारी समितियाँ सदस्य हैं। समस्त कार्पोरेट बैंकों ३० करोड़ रुपये के लगभग है, जिसमें हिस्सा बैंकों ६ प्रतिशत, रक्षित कोष १५ प्रतिशत, डिपॉजिट ५६ प्रतिशत, प्रान्तीय बैंकों से लिया हुआ ऋण १५ प्रतिशत और सरकार से लिया हुआ ऋण एक प्रतिशत से कुछ अधिक है।

प्रान्तीय सहकारी बैंक (Provincial Co-operative Banks) या सर्वोपरि बैंक (Apex Banks):— देश में सहकारी सार्व आन्दोलन के समय पैने पर यह अनुभव होने लगा कि यद्यपि सेन्ट्रल बैंक सहकारी समितियों का निरोक्षण तथा उनकी देखभाल करने में रजिस्ट्रार का हाथ बढ़ाते हैं किन्तु जितनी बैंकों की आवश्यकता होती है उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर सकते। १९१५ में मद्रास आन्दोलन की जाँच करने के लिए जो मैकलेगन कमेटी बठाई गई थी। उसने प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय बैंक स्थापित करने की आवश्यकता बतलाई। बाखव में सेन्ट्रल बैंकों का आपस में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ऐसी संस्था की विशेष आवश्यकता थी। प्रान्तीय बैंकों से पूर्व यह कार्य रजिस्ट्रार करता था। यदि किसी सेन्ट्रल बैंक को बैंकों की अधिक आवश्यकता होती तो रजिस्ट्रार को सूचित करने पर वह सब सेन्ट्रल बैंकों के नाम एक गरीबी बिंदी लिख देता और जिस सेन्ट्रल बैंक के पास आवश्यकता से अधिक डिपॉजिट होती वह उस सेन्ट्रल बैंक को ऋण दे देता था। किन्तु एक तो इसमें बहुत सा समय नष्ट हो जाता था दूसरे कभी कभी इस प्रकार बैंकों का प्रबन्ध नहीं हो पाता था। अस्तु प्रान्तीय बैंक की सभी की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। साथ ही द्रव्य बाजार (Money Market) और सहकारी सार्व आन्दोलन (Co-operative Credit Movement) के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए या प्रान्तीय बैंक की स्थापना आवश्यक प्रतीत हुई।

भारतवर्ष में इस समय निम्नलिखित प्रान्तीय सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। मद्रास, बम्बई, पंजाब उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और मगर तथा आसम प्रान्तों में तथा देशी राज्यों में हैदराबाद और मेसूर के सर्वोपरि बैंक (Apex Banks) प्रान्तीय सहकारी बैंकों की भेजी में आते

हैं। यों इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा, काश्मीर तथा भूवाल में भी कोई एक बड़ा सेन्ट्रल बैंक चुन लिया गया है जो सर्वोपरि बैंक का काम करता है। किन्तु प्रान्तीय सहकारी बैंक बैंकों की श्रेणी में नहीं आते।

सदस्यता:—इन बैंकों का संगठन एक सा नहीं है। पंजाब और बंगाल में सहकारी साख समितियाँ और सहकारी सेन्ट्रल बैंक ही उनके हिस्सेदार होते हैं। अन्य प्रान्तों में इनके अतिरिक्त व्यक्ति भी हिस्सेदार होते हैं।

संचालन:—प्रान्तीय सहकारी बैंकों को चलाने के लिए व्यापारिक बुद्धि तथा बैंकिंग की योग्यता चाहिए। इसलिए बैंक के डायरेक्टरों में व्यापारिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी चाहिए। किन्तु अधिकतर डायरेक्टर तो सहकारिता आन्दोलन से सम्बन्धित व्यक्ति ही होने चाहिए। यही कारण है कि दो तीन प्रान्तों को छोड़ कर शेष सभी प्रान्तों में हिस्सेदारों के बाहर से भी डायरेक्टरों को नियुक्त करने की परिपाटी है। इसके अतिरिक्त अधिकतर प्रान्तों में सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार पदेन डायरेक्टर होता है अथवा वह कुछ डायरेक्टर मनोनीत करता है।

कार्यशील पूँजी:—प्रान्तीय बैंकों की कार्यशील पूँजी लगभग १५ करोड़ रुपये है, उसमें १६ प्रतिशत उनकी शेष उधार ली हुई है। उधार ली हुई पूँजी में सहकारी समितियों और सेन्ट्रल बैंकों की डिपॉजिट तथा व्यक्तियों की डिपॉजिट मुख्य हैं। प्रान्तीय सहकारी बैंक चालू (Current), सेविंग्स, तथा मुहती (Fixed) तीनों प्रकार की डिपॉजिट लेते हैं। अधिकांश डिपॉजिट या जमा तीन वर्षों के लिये ली जाती है। प्रान्तीय सहकारी बैंकों की साख (Credit) बहुत अच्छी है। वे सहकारिता आन्दोलन के बाहर से भी जमा आकर्षित करते हैं। वे अन्य व्यापारिक बैंकों से अधिक सूद डिपॉजिट पर नहीं देते और उनको यथेष्ट डिपॉजिट मिल जाती है। द्रव्य-बाजार (Money Market) के अनुसार ही वे भी अपने सूद की दर निर्धारित करते हैं।

पूँजी लगाना (Investment of Funds):—भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों ने कुछ नियम बना दिये हैं, जिनके अनुसार प्रान्तीय सहकारी बैंकों को अपनी देनी (Liability) के एक निश्चित अनुपात में नकदी तथा शीघ्र भेज सकने वाली लेनी (Assets) रखनी पड़ती है। व्यवहार में प्रान्तीय सहकारी बैंक २० से ५० प्रतिशत तक कार्यशील पूँजी सरकारी सिक्यूरिटी में लगाते हैं। कुछ रुपया अन्य व्यापारिक बैंकों और अन्य प्रान्तीय

सहकारी बैंकों में जमा करते हैं और शेष अपने सदस्यों अर्थात् सहकारी सेन्ट्रल बैंकों तथा सहकारी साख समितियों को उधार देते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रान्तीय सहकारी बैंकों को यह सलाह दी थी कि वह अपने सदस्यों को केवल ६ महीने के लिए ही ऋण दिया करें। यद्यपि रिजर्व बैंक की इस सलाह को प्रान्तीय सहकारी बैंक पूरी तरह से नहीं मान सके। पर भा वे अब प्रायः उत्पादन और खेती की पैदावार के क्रय-विक्रय के लिए ही थोड़े समय के लिए ऋण देते हैं। किन्तु किसान को जितनी आवश्यकता कम समय के लिए ऋण की है उतनी ही मध्यम समय अर्थात् दो या तीन वर्षों के लिए है। इस कारण प्रान्तीय सहकारी बैंकों को इन दोनों प्रकार की साख का दाना पड़ता है। प्रान्तीय बैंक लगभग समय के लिए अर्थात् १० या २० वर्षों के लिए ऋण नहीं दे सकते उसके लिए भूमि यथक बैंक ही उपयुक्त संस्था है।

किसी किसी प्रान्त में प्रान्तीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक साख समितियों (Primary Co-operative Credit Societies) को सीधे ऋण दे देते हैं। यह उचित नहीं है। अभिकाश प्रान्तीय बैंक सेन्ट्रल बैंकों को ही ऋण देते हैं और उनके द्वारा ही वे साख समितियों को ऋण देते हैं। जहाँ तक सेन्ट्रल बैंकों का प्रश्न है प्रान्तीय बैंक उनका सतुलन केन्द्र (Balancing Centre) है। यदि उनके पास आवश्यकता से अधिक रुपया हुआ तो वे प्रान्तीय सहकारी बैंक में जमा कर देते हैं और यदि आवश्यकता हुई तो उधार ले लेते हैं। अब प्रान्तीय बैंक क्रय-विक्रय यूनियनों (Marketing Unions) को भी ऋण देती है जो क्रय-विक्रय समितियों (Marketing Societies) को साख देती हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों (Industrial Co-operative Societies) को भी यह बैंक उनके कच्चे माल अथवा तैयार माल की जमानत पर ऋण दे देते हैं। प्रान्तीय सहकारी बैंक तीनों प्रकार की जमा लेने के अतिरिक्त वह सभी बैंकिंग का कारबार करते हैं जो व्यापारिक बैंक करते हैं।

जिन प्रान्तों में केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक (Central Land Mortgage Banks) नहीं हैं वहाँ प्रान्तीय सहकारी बैंक ही भूमि बंधक बैंकों के लिए डिपेंडर बचते हैं और उन्हें लगभग समय के लिए ऋण देते हैं।

प्रान्तीय बैंक और सेन्ट्रल बैंक :—प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा सेन्ट्रल बैंकों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रान्तों में सुदृढ़-सुदृढ़ है। वे सेन्ट्रल बैंकों

पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। सेन्ट्रल बैंक अपना रुपया प्रायः प्रान्तीय बैंकों अथवा सुदृढ़ व्यापारिक बैंकों में जमा कर देते हैं। मदरास तथा मध्यप्रदेश में प्रान्तीय सहकारी बैंक अपने निरीक्षकों के द्वारा सेन्ट्रल बैंकों का निरीक्षण कराते हैं। उन सभी प्रान्तों में जहां प्रान्तीय बैंक हैं सेन्ट्रल बैंक एक दूसरे को सीधे कर्ज नहीं दे सकते। वास्तव में प्रान्तीय बैंकों का कार्य यह है कि वे सेन्ट्रल बैंकों के संतुलन केन्द्र का काम करें, उन्हें बैंकिंग, द्रव्य-वाजार, ऋण देने और सूद की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में परामर्श दें। यद्यपि प्रान्तीय बैंकों का सेन्ट्रल बैंकों पर नियंत्रण वांछनीय नहीं है परन्तु प्रान्तीय बैंकों द्वारा उनका निरीक्षण आवश्यक है।

आय-व्यय निरीक्षण (आडिट) :- प्रान्तीय सहकारी बैंकों का हिसाब सहकारिता विभाग की जांचना चाहिए क्योंकि कानून के अनुसार रजिस्ट्रार का यह मुख्य कार्य है। परन्तु बहुत से प्रान्तों में यह हिसाब पेशेवर आडिटरो द्वारा जांचवाने की आज्ञा दे दी है। आय-व्यय परीक्षा के अतिरिक्त उन बैंकों को अपनी आर्थिक स्थिति का तिमाही लेखा रजिस्ट्रार के द्वारा प्रान्तीय सरकार को भेजना पड़ता है। प्रान्तीय सरकार उस पर अपना मत प्रगट करती है।

प्रान्तीय बैंक और रिज़र्व बैंक :- रिज़र्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों और उससे सम्बन्धित सेट्रल बैंकों को सरकारी सिक्कुरिटी की जमानत पर नक़द साख़ देता है। परन्तु जहां तक सहकारी कागज़ (Co-operative Paper) के भुनाने का प्रश्न है प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा सेट्रल बैंक जब रिज़र्व बैंक की इच्छानुसार अपनी आर्थिक स्थिति तथा कारबार को बना लेंगे तभी वह सहकारी कागज़ को भुनाने की सुविधा देगा। कुछ शर्तें पूरा करने पर रिज़र्व बैंक प्रान्तीय बैंकों को अपना रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधा प्रदान करेगा। इस कार्य के लिए उसने सहकारी सेन्ट्रल बैंकों को प्रान्तीय बैंकों की शाखा मान लिया है। कुछ प्रान्तीय बैंकों ने रिज़र्व बैंक की योजना को स्वीकार कर लिया है और वे उसमें सम्मिलित हो गए हैं। रिज़र्व बैंक ने प्रान्तीय बैंकों को अपना बैलेंसशीट (लेनी देनी का लेखा) एक निश्चित रूप में तैयार करने को कहा है और कुछ बैंक वैसा करने भी लगे हैं। जैसे-जैसे प्रान्तीय बैंक रिज़र्व बैंक की इच्छानुसार सुधार करते जावेंगे वैसे ही वैसे उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ होता जावेगा। यद्यपि रिज़र्व बैंक की स्थापना से सहकारी बैंकों को वे सुविधायें अभी तक नहीं मिलीं जो वे

चाहते थे। किन्तु अब एक अखिल भारतीय सहकारी या सर्वोपरि बैंक की आवश्यकता नहीं रही।

अखिल भारतीय प्रान्तीय सहकारी बैंक वेस्तोशियेसन :—इस संस्था को १९२६ में जन्म दिया गया। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह प्रत्येक सदस्य की कार्यशील पूँजी के वाहुल्य तथा कमी के आँकड़ों को जमा करे और सब सदस्यों को सूचित कर दे जिससे वे एक दूसरे से लेन देन कर सकें और उन्हें मालूम हो जावे कि किस बैंक के पास अधिक पूँजी है और किस बैंक को पूँजी की आवश्यकता है। सदस्य बैंकों को आर्थिक प्रश्नों पर राय देना, उनकी सहायता करना, व प्रान्तीय सहकारी बैंकों का समय-समय पर कामफैल बुझाना और उनमें प्रान्तीय बैंकों तथा साम्प्रदायिक आन्दोलन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना भी इस संस्था के कार्य हैं। जब कभी प्रान्तीय बैंकों को सरकार या रिजर्व बैंक का ध्यान किसी विशेष बात को आकर्षित करना होता है तो यह संस्था उनसे लिखा-पढ़ी करती है।

प्रान्तीय बैंक सहकारी साख्त आन्दोलन के सतुलन चन्द्र हाने ने अतिरिक्त व समी कार्य करते हैं जो व्यापारिक बैंक करते हैं। साधारणतः प्रान्तीय बैंकों का शाखायें नई हानी किन्तु बम्बई प्रान्तीय बैंक ने जहाँ मन्दल बैंक नहीं है अपनी शाखायें खोल दी है जो साख्त समितियों को श्रृंखला देती हैं।

सहकारी भूमि षंयक बैंक (Co operative Land Mortgage Banks) भूमि षंयक बैंकों की आवश्यकता :—पहले बताया जा चुका है कि किसान को साधारण खेती-बारी के कारबार को चलाने के लिए थोड़े समय और मध्यम समय के लिए श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है। इसका अन्तर्गत वह सभी श्रृंखला आ जाता है जो पशु, बीज, खाद, हल तथा अन्य औजार खरीदने के लिए, लगान देने के लिए, तथा अपने कुटुम्ब के पालन के लिए लिया जाता है। इसका अतिरिक्त किसान को पुराने श्रृंखला का चुकाने के लिए, मूल्य की चक्रवन्दी करने तथा उसका उपजाऊ बनाने के लिए अन्य सुधार करने के उद्देश्य से, भूमि खरीदने के लिए, कुआर बनाने के लिए तथा मूल्यवान यंत्र खरीदने के लिए अधिक समय के वास्ते भी श्रृंखला चाहिए।

साम्प्रदायिक सहकारी साख्त समितियाँ किसानों को थोड़े समय और मध्यम समय के लिए श्रृंखला देती हैं। आरम्भ में जब सहकारिता आन्दोलन का भोग्योद्देश्य था, लोगों की यह धारणा थी कि साख्त समितियाँ अधिक समय के

लिए भी ऋण दे सकेंगी। ग्राम्य में ग्राम्य साख समितियों ने अधिक समय के लिए ऋण दिया था। किन्तु न तो साख समितियों के पास इतनी पूँजी थी कि वे सदस्यों के पुगने ऋण को चुका सकें और न यह उनके हित में ही था, इस कारण साख समितियों ने अधिक समय के लिए ऋण देना बंद कर दिया। सभी प्रान्तीय बैंकिंग जांच कमेटियों तथा विशेषज्ञों की यही सम्मति थी कि अधिक समय के लिए ऋण देना साख समितियों के लिए उचित नहीं है। कारण यह है कि सहकारी सेंट्रल बैंकों तथा साख समितियों में डिपॉजिट थोड़े समय के लिए ली जाती है और थोड़े समय के लिए जमा किए हुए रुपये से अधिक समय के लिए ऋण देना जोखिम से खाली नहीं है। यह बैंकिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त अधिक समय के लिए ऋण देने में सम्पत्ति की जमानत लेते समय उसके मूल्य को आकने तथा उससे स्वामित्व की जाँच करने के लिए अनुभवी कार्यकर्ताओं तथा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण समितियों के पास नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि बंधक रखने पर उसके संबंध के कागज ग्राम्य साख समितियों के पास रखने में जोखिम है और अन्तिम सब से बड़ी कठिनाई यह है कि सदस्यों के ऋण न चुकाने पर समिति की पूँजा फँस जावेगी और समिति को सदस्य के विरुद्ध डिगरी करा कर उस भूमि को नीलाम करवाना होगा। यह सब कानूनी काम ग्राम्य साख समिति सफलतापूर्वक नहीं कर सकती। फिर यदि ग्राम्य साख समितियाँ भूमि बंधक रख कर लम्बे समय के लिये ऋण दें तो व्यक्तिगत साख का महत्व कम हो जाने की सम्भावना रहेगी जो सहकारिता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यही कारण था कि सेंट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी, प्रान्तीय बैंकिंग इनक्वायरी कमेटियों, रिजर्व बैंक तथा बैंकिंग के विशेषज्ञों ने एक मत से यह निर्णय किया कि लम्बे समय के लिए ऋण केवल भूमि बंधक बैंक ही दे सकते हैं। साख समितियों को केवल थोड़े समय तथा मध्यम समय के लिये ही ऋण देना चाहिये। अब साख समितियाँ तथा सेंट्रल बैंक लम्बे समय के लिए ऋण बिलकुल नहीं देते।

भूमि बंधक बैंक तीन प्रकार के होते हैं :—(१) सहकारी (Co-operative), (२) गैर सहकारी अर्थात् मिश्रित पूँजीवाले (Joint Stock), (३) अर्ध-सहकारी (Semi-Co-operative)।

सहकारी भूमि बंधक बैंक केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देता है।

बैंक की अपनी निजी पूँजी नहीं होती। जो भूमि रख रख दी जाती है उसी की जमानत पर 'मॉर्गेज बॉन्ड' (Mortgage Bonds) बंधे जाते हैं और उनसे पूँजी प्राप्त की जाती है। सहकारी भूमि व्यवस्था बैंक लाभ को लक्ष्य करके कार्य नहीं करते बल्कि 'स' की दर को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।

गैर सहकारी भूमि व्यवस्था बैंक मिश्रित पूँजी के होते हैं। निम्न प्रकार अन्य व्यापारिक बैंक लाभ की दृष्टि से स्थापित किए जाते हैं वेमे यह बैंक भी निवेशकों को सम्मिलित होते हैं और लाभ की दृष्टि से चलाए जाते हैं। निम्नान तथा अर्थात्कार अपनी भूमि व्यवस्था रख कर उनसे श्रद्धा लेते हैं। इस प्रकार मिश्रित पूँजी वाले भूमि व्यवस्था बैंक योरोप में सर्वत्र पाए जाते हैं किन्तु लक्ष्य उन पर नियन्त्रण रखता है जिससे वे श्रद्धा लेने वालों को मनमाने दम से लूटने न लगे और बूढ़ की दर बहुत अधिक न रहें। अर्ध-सहकारी भूमि व्यवस्था न तो पूर्ण रूप से सहकारी होते हैं और न गैर सहकारी।

भारतवर्ष में जमींदारों के लिए गैर सहकारी बसा किसानों के लिए सहकारी भूमि व्यवस्था उपयुक्त होगी। किन्तु यहाँ जो भूमि व्यवस्था स्थापित किए गए हैं वे अर्ध-सहकारी हैं, कोई भी पूर्ण सहकारी नहीं कहा जा सकता। यह सहकारी भूमि व्यवस्था बैंक परिमित दायित्व (Limited Liability) वाली स्थापनाएँ हैं। उनके सदस्य अधिकतर श्रद्धा लेने वाले ही होते हैं किन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो श्रद्धा लेने वाले नहीं होते। इन सदस्यों को बैंक के प्रत्यक्ष में सहायता पहुँचाने तथा दूसरी आकर्षित करने का उद्देश्य से लिया जाता है। यह लोग प्रान्त के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं। अक्सर ऐसे सदस्यों को दम देने की नीति है जिससे बैंक पूर्ण रूप से सहकारी संस्था बन जावे।

बैंक का उद्देश्य :—(१) किसानों को भूमि तथा मकानों को गिरवी से ढुहाना, (२) खेती की भूमि तथा खेतों आदि के पैसे की उन्नति करना तथा किसानों के मकानों को बनवाना, (३) पुराने श्रद्धा को चुकाना (४) भूमि कापीदने के लिये रुक्का देना, (५) तथा खेतों की चकवन्दी करना। किन्तु व्यवहार में अभी भूमि व्यवस्था बैंक केवल पुराने श्रद्धा को चुकाने के लिए ही श्रद्धा देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भूमि व्यवस्था बैंक खेती की उन्नति करने और भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए भी श्रद्धा दें।

• **कार्य क्षेत्र :—**भूमि बंधक बैंक का कार्य क्षेत्र छोटा होना चाहिये किन्तु इतना छोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रबन्ध ही न हो सके और उसका व्यय न निकल सके । मद्रास में एक भूमि बंधक बैंक एक ताल्लुक में होता है । बम्बई में भी ताल्लुक ही भूमि बंधक बैंक का क्षेत्र है । पंजाब में भूमि बंधक का कार्य क्षेत्र जिला है । उत्तर प्रदेश में भी भूमि बंधक बैंक का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है । भूमि बंधक बैंक का कार्य क्षेत्र एक ताल्लुक या परगना ही ठीक है । ऐसा भूमि बंधक बैंक न तो इतना छोटा होगा कि सफलता पूर्वक चल न सके और न वह इतना बड़ा क्षेत्र हो होगा कि साधारण किसान भूमि बंधक बैंक के लाभ से वंचित रह जावे ।

कार्यशील पूँजी (Working Capital) :—भूमि बंधक बैंकों की कार्यशील पूँजी हिस्सा पूँजी से तथा डिबेंचर (ऋण पत्र) बैंच कर प्राप्त की जाती है । भूमि बंधक बैंक डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते । उनके लिए डिपॉजिट स्वीकार करना उचित भी नहीं है क्योंकि वे १० वर्षों से लेकर ३० वर्षों तक के लिए ऋण देते हैं । कोई भी व्यक्ति इतने लम्बे समय के लिए अपना रुपया भूमि बंधक बैंकों में जमा करना पसंद न करेगा । दो-तीन वर्ष के लिए डिपॉजिट लेकर २० और ३० वर्ष के लिए ऋण देना उचित नहीं होगा अस्तु भूमि बंधक बैंक डिपॉजिट नहीं लेते ।

हिस्सा पूँजी (Share Capital) दो तरह से इकट्ठी की जाती है । एक तो आरम्भ में हिस्सा बैंच कर अथवा ऋण देने समय उस रकम में से कुछ काट कर हिस्से का मूल्य बसूल करने से हिस्सा पूँजी इकट्ठी की जाती है । किन्तु इन बैंकों की अधिकांश पूँजी डिबेंचर बैंच कर प्राप्त की जाती है । जो भूमि सदस्य बैंकों के पास बंधक रखते हैं उनकी जमानत पर बैंक डिबेंचर निकालते हैं और जनता उनको खरीद लेती है । डिबेंचर २० या ३० वर्षों के लिए होते हैं । अन्य देशों में भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचर बहुत अधिक प्रचलित हैं और जनता इनमें प्रसन्नता पूर्वक अपना रुपया लगाती है । परन्तु भारतवर्ष में क्योंकि इस प्रकार के डिबेंचर प्रचलित और सर्वप्रिय नहीं थे इस कारण सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन ने यह माँग रखी थी कि सरकार स्वयं भूमि बंधक बैंकों के डिबेंचर खरीदे और उनको सफलता पूर्वक बैंचने के लिए सरकार डिबेंचर के मूलधन तथा सूद की गारंटी कर दे । साथ ही भूमि बंधक बैंकों के निकाले हुए डिबेंचरों को ट्रस्टी सिन्डिकेटी बना दिया जावे । शाही कृषि कमीशन तथा सेन्ट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी के सामने यह प्रश्न

अस्थित किया गया था। शाही कृषि वयोगत की गण भी कि सरकार को इस प्रकार बोझ गारंटी न देना चाहिए। सेन्ट्रल बैंकिंग इन्सुल्वरी का मत था कि सरकार को मूलधन की गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ खूद की गारंटी सरकार को आवश्यक दे देनी चाहिए। इनमें से ही बनता इन दिवेंचरी को खयदने लगेगी और मूमि बंधक बैंको को बंधेष्ट वृत्ता मिल जावेगी। सेन्ट्रल बैंकिंग इन्सुल्वरी वयेटी का यह भी मत था कि यदि साकार को इस बात का सतोष हो जावे कि बैंको ने दिवेंचरी को बुझाने का प्रयत्न का लिया है तो इन दिवेंचरी का दृष्टी विषयुरिटी बना देना चाहिए। आरम्भ में काम चलाने के लिए जहाँ कहीं भा आवश्यकता हो सरकार मूमि बंधक बैंको को बिना खूद खपवा दे दे और दिवेंचर बिकने पर सरकार का खपवा वापस दे दिया जाये। यह ध्यान में रखने को बात है कि वृत्ता की यह व्यवस्था बैंकी के आरम्भक काल के लिए ही उपयुक्त होगी। विशेषज्ञों का कथन है कि आगे चल कर इन बैंको को बहुत वृत्ता का आवश्यकता होगी। उस समय प्रतीप सरकारों का इन बैंकों के हिसाब नीति कर इनको मददगार देनी चाहिए।

मूमि बंधक बैंको में से यदि प्रत्येक बैंक दिवेंचर बैंकने लगेगा तो उनमें आपस में ही अनिर्वादा उत्पन्न हो जावेगा। जो बैंक अधिक मुख्यस्थित और मजबूत होगा वह कम खूद पर दिवेंचर बैंक लगेगा और दूसरे बैंको को अधिक खूद देना होगा। इस समस्या का हल करने के लिए यह आवश्यक है कि तात्कालिक या जिला मूमि बंधक बैंको का दिवेंचर न बेचने दिए जायें वरन् प्रान्त में एक केन्द्रिय संस्था (प्रान्त मूमि बंधक बैंक या सेन्ट्रल मूमि बंधक बैंक) स्थापित की जाये। यह केन्द्रिय मूमि बंधक बैंक सब सम्बन्धित मूमि बंधक बैंको के लिए दिवेंचर निजाले और जिला या ताल्लुका मूमि बंधक बैंक उनको बेचे। जो मूमि जिला या ताल्लुका बैंक बंधक रखे उसकी जमानत पर वे केन्द्रिय मूमि बंधक बैंक से श्रुत लें लें और प्रान्तीय मूमि बंधक उस जमानत प्रार्थन सहित अपनी मूमि पर निर्भर होकर दिवेंचर निकालें। अन्ती तब केवल सदरा और कबड़े प्रान्तों में केन्द्रिय मूमि बंधक बैंको की स्थापना की गई है। शेष प्रान्तों में या तो प्रान्तीय सहकारी बैंक मूमि बंधक बैंको के लिए दिवेंचर निकालते हैं अथवा मूमि बंधक ही दिवेंचर निजालते हैं। बात यह है कि सदरा का छोड़ कर अन्य प्रान्तों में मूमि बंधक बैंक बहुत कम हैं। इस कारण केन्द्रिय संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसी प्रकार काम चल जाता है। किन्तु अब अधिक संख्या में मूमि बंधक बैंक स्थापित हो जावेगे तो बिना केन्द्रिय मूमि बंधक बैंक के काम नहीं चल सकता।

बैंक का संचालन :—भूमि बंधक बैंक का प्रबंध और संचालन एक बोर्ड आव डायरेक्टर करता है। डायरेक्टरों में अधिकतर उन सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो ऋण लेते हैं। किन्तु कुछ ऐसे व्यक्ति भी बोर्ड में ले लिए जाते हैं जो ऋण नहीं लेते वरन् उन्हें व्यवसायिक पटुता के कारण लिया जाता है जिससे बैंक का काम ठीक चल सके। जब कोई किसान बैंक से ऋण लेना चाहता है तो बैंक के छपे हुए फार्म पर अपनी लेनी और देनी (Assets and Liabilities) का पूरा व्योरा देकर और साथ में अपनी भूमि सम्बन्धी कागज़ नथी करके अपने क्षेत्र के भूमि बन्धक बैंक को प्रार्थना पत्र दे देता है। तब भूमि बंधक बैंक का एक डायरेक्टर तथा सुपरवाइज़र उस किसान के खेतों का मूल्य, उनकी पैदावार, और किसान के ऋण चुका सकने की क्षमता की पूरी जाँच करता है। तदोपरान्त एक सर्टिफिकेट इस आशय का प्राप्त किया जाता है कि उस भूमि पर कोई ऋण लिया हुआ नहीं है। इतना हो चुकने पर बैंक का कानूनी-सलाहकार उन कागज़ों को देख कर किसान का दायित्व ठीक है या नहीं इस पर अपनी रिपोर्ट देता है। बैंक का संचालक बोर्ड आव डायरेक्टर उस रिपोर्ट पर ऋण देना स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है। स्वीकृत प्रार्थना पत्र केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक के पास भेज दिया जाता है। केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक के दफ्तर में सब कागज़ों की जाँच होकर वे बैंक के कार्यकारिणी समिति के सामने रख दिए जाते हैं। जब सेन्ट्रल भूमि बंधक बैंक ऋण देना स्वीकार कर लेता है तो उसकी सूचना उस ताल्लुका अथवा ज़िला भूमि बन्धक बैंक को दे दी जाती है और वह भूमि बंधक बैंक प्रार्थी से बन्धक पत्र लिखा कर सेन्ट्रल भूमि बन्धक बैंक के नाम करा देता है। केन्द्रीय या सेन्ट्रल भूमि बन्धक बैंक बन्धक पत्र पाने पर ताल्लुका या ज़िला भूमि बन्धक बैंक को ऋण दे देता है। जहाँ केन्द्रीय अर्थात् सेन्ट्रल भूमि बन्धक बैंक नहीं होते वहाँ सहकारी विभाग का कोई उच्च कर्मचारी कागज़ों को देखता है और उसकी स्वीकृति मिलने पर प्रान्तीय सहकारी बैंक के नाम बन्धक पत्र लिखा दिया जाता है और वह डिवेंचर निकाल कर भूमि बन्धक बैंक को दे देता है। जहाँ प्रान्तीय बैंक डिवेंचर नहीं निकालते वहाँ ताल्लुका या ज़िला भूमि बन्धक बैंक जिन्हें हम प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक भी कह सकते हैं डिवेंचर निकालते हैं और प्रार्थी को ऋण दे देते हैं।

जब किसान की भूमि बन्धक रखी जाती है तो उसका जो मूल्य कृता जाता है उसका ५० प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता।

मदरास में किसी एक व्यक्ति को ५ हजार रुपए से अधिक और बगई में १० हजार रुपये से अधिक श्रृणु नहीं दिया जाता । किसी भी प्रान्त में १० हजार रुपये से अधिक किसी एक सदस्य को श्रृणु नहीं दिया जाता । श्रृणु अधिक से अधिक ३० वर्षों के लिए दिया जाता है । अधिकतर १० वर्षों से २० वर्षों के लिए श्रृणु दिया जाता है । जब श्रृणु दिया जाता है तब उस पर सूद का हिमाव लगाकर सूद सहित बराबर बराबर वार्षिक किराते में किसान से वसूल कर लिया जाता है जिससे एक निश्चित समय के अन्दर मूलधन और सूद चुक जावे । हमसे यह लाम होता है कि किसान को प्रतिवर्ष मूलधन और सूद के रूप में केवल उतनी ही किस्त देनी पड़ती है जितनी वह महाजन को केवल सूद में ही दे देता है । इस प्रकार यदि किसान को ६ प्रतिशत पर श्रृणु दिया गया है तो उससे दिये हुए श्रृणु पर प्रतिवर्ष ॥ प्रतिशत वसूल करने से २० वर्षों से कम में मारा श्रृणु चुक जावेगा ।

जहां सहकारी साख समिति और भूमि बन्धक बैंक दोनों ही कार्य करते हैं वहां दोनों संस्थाओं को एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहिए । हां दोनों से सहयोग होना आवश्यक है । यदि किसी सहकारी साख समिति का सदस्य भूमि बन्धक बैंक से श्रृणु लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे तो बैंक साख समिति से उसके सम्बन्ध में पूछ-चाछ कर ले बिना सहकारी साख समिति पर श्रृणु की जिम्मेदारी न होगी ।

भूमि बन्धक बैंकों को सुविधाओं की आवश्यकता :— भूमि बन्धक बैंकों की सकलता के लिए सहकारिता आन्दोलन में कार्य करने वाले यह आवश्यक समझते हैं कि भूमि बन्धक बैंकों को यह अधिकार दे दिया जावे कि बिना अदालत में गए अपना रुपया वसूल करने के लिए बंधक रखती हुई जमीन जप्त कर लें और बैंक दें । अधिकतर प्रान्तीय बैंकिंग इनकायरी कमेटीयो ने इस माँग का विरोध किया है । उनका कहना है कि जब इस अधिकार का उपयोग किया जावेगा तब जनता के बैंकों के प्रति विरोध भावना उत्पन्न हो जावेगी । इसके अतिरिक्त यदि भूमि बन्धक बैंकों को यह अधिकार दे दिया जावेगा तो वे श्रृणु देते समय भूमि की अती माँति जाँच पड़ताल नहीं करेंगे । उनके विचार से यदि भूमि बन्धक बैंक साधकानो से काम करें और उनका प्रश्न समझें तो मुन्दरेवाजी की आवश्यकता ही न पड़ेगी । सेन्ट्रल बैंकिंग इनकायरी कमेटी के सामने भी यह प्रश्न उपस्थित किया गया था । जो लोग बैंकों को यह अधिकार देने के पक्ष में हैं,

उनका कथन है कि यदि कोई विशेष कानून बनाकर भूमि बन्धक बैंक को यह अधिकार न दे दिया गया तो फल यह होगा कि बैंकों को अदालत की शरण लेनी होगी अथवा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये पंच के सामने मुकदमा लड़ना होगा। भारत में सम्पत्ति का हस्तांतरण कानून (Transfer of Property Act) तथा जास्ता दीवानी (Civil Procedure Code) इतने पेचीदे हैं कि भूमि बन्धक बैंकों को डिगरी कराने में बहुत समय तथा धन नष्ट करना होगा। इसका फल यह होगा कि बैंकों के कार्य में बहुत सी रुकावटें पड़ेंगी तथा डिबेंचरों की बिक्री पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। योरोपीय देशों में भी भूमिबन्धक बैंकों को विशेष कानून बना कर यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि कर्जदार मृत्यु नहीं चुकाता तो भूमि बन्धक बैंक बिना अदालत में गए भूमि को बेच सकता है। सेन्ट्रल बैंकिंग इनकायरी कमेटी का यह मत है कि बिना यह अधिकार दिए डिबेंचर बैंक कर कार्यशील पूँजी इकट्ठी नहीं की जा सकती, जनता डिबेंचरों को न लेगी। अस्तु कमेटी ने उस माँग का समर्थन किया है। साथ ही यह भी कहा है कि देनदार को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वह समझता है कि बैंक का कार्य अन्यायपूर्ण है तो वह अदालत की शरण में जा सकता है। बैंक के देनदार के हिस्सेदार तथा अन्य किसी लेनदार को, भूमि के बैंक द्वारा जब्त कर लेने पर यदि हानि होती हो तो वह भी अदालत की शरण में जा सकता है।

भारतवर्ष में कुछ प्रान्तों में भूमि हस्तांतरण कानून (Land Alienation Act) लागू है। इस कानून के द्वारा कुछ जातियाँ खेतिहर जातियाँ मान ली गई हैं, उन्हीं जाति के लोग भूमि को मोल ले सकते हैं। यह कानून सारे पंजाब, तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रान्तों के कुछ भागों में लागू हैं। इन प्रान्तों में भूमि बन्धक बैंकों को यह अधिकार मिल जाने पर भी भूमि को बेचने में अड़चन होगी। इसके अतिरिक्त बहुत से प्रान्तों में काश्तकारी कानून (Tenancy Act) के कारण भी भूमि के बेचने में रुकावटें होंगी। प्रान्तीय बैंकिंग इनकायरी कमेटियों तथा सेन्ट्रल बैंकिंग इनकायरी कमेटी का मत है कि इन कानूनों में इस आशय का संशोधन कर देना चाहिए कि भूमि बंधक बैंकों को जब्त की हुई भूमि के बेचने में कोई रुकावट न हो।

भूमि बंधक बैंकों की दशा :—पंजाब-भारतवर्ष में सबसे पहला भूमि बन्धक बैंक पंजाब के मंग ज़िले में १९२० में स्थापित हुआ। इसके उपरान्त

वेजाव में कुल १२ भूमि बन्धक बैंक स्थापित हुए किन्तु वे सफल नहीं हुए। १९२६ के अन्तर्गत खेती की पैदावार का मूल्य बहुत गिर जाने से भूमि के मूल्य में भी भारी उमड़ाई। भूमि हस्तांतरणानुसार (Land Alienation Act) के लागू होने से तथा टायरैक्टरों तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं के अधिक श्रम लेने के कारण यह बैंक अक्षय्य हो गए। दो बैंक कार्य करते हैं। इन्हें प्रान्तीय सहकारी बैंक ही श्रम देता है।

मदरास :—मदरास में भूमि बन्धक बैंकों को बहुत सफलता मिली है। वहाँ लगभग २०० भूमि बन्धक बैंक काम कर रहे हैं। इन बैंकों में ६ करोड़ रुपये से अधिक का श्रम दिया है। प्रतिवर्ष ५० लाख रुपये से अधिक का श्रम दे दिया जाता है। किसानों से केवल ६ प्रतिशत सूद लिया जाता है। मदरास में १९२६ के पहले प्रत्येक भूमि बन्धक बैंक अपने डिपेंडर चयन था किन्तु १९२६ में सेंट्रल भूमि बन्धक बैंक की स्थापना हुई तब से सब प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक के लिए वही डिपेंडर निकालता है। इससे द्रव्य बाजार में भूमि बन्धक बैंकों में आपस में हावा प्रतिस्पर्धा होता था वह बच गई और कम सूद पर पैनी मिल जाती है।

मदरास सरकार ने भूमि बन्धक बैंकों को बहुत सी सुविधायें दी हैं जैसे कानूनात्मक की रजिस्ट्री करने में उन्हें आधी फीस देनी होती है। यह माहूम करने के लिए कि भूमि पर और कोई श्रम लिया हुआ है या नहीं और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी आधी फीस ला जाता है। बैंकों को गौव क नकशे, बदोवस्तन व रजिस्टर और जिल्ह का गज़ट बिना मूल्य दिये जाते हैं।

कानून बनाकर मदरास में कुछ विशेष सुविधायें इन बैंकों को दे दी गई हैं। यदि कोई देनदार भूमि बन्धक का श्रम अदा न करे तो बैंक को यह अधिकार होगा कि बैंक बिना अदालत में गए उस भूमि को और उस पर खड़ी हुई फसल को जन्त कर के बँच दे। इस ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वह भूमि बन्धक बैंकों के डिपेंडरों की आराधना की गारंटी दे दे। ऐक्ट के द्वारा सेंट्रल भूमि बन्धक बैंक प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों को ५ प्रतिशत सूद पर श्रम देता है और ३ प्रतिशत या ३½ प्रतिशत पर डिपेंडर चयन है। मदरास सरकार ने सेंट्रल भूमि बन्धक बैंक के निकाले हुए डिपेंडरों के मूल्यन तथा सूद की गारंटी दे दी है। सेंट्रल भूमि बन्धक बैंक का संचालन बड़ी सतर्कता से किया

जा रहा है । ४० प्रतिशत लाभ रक्षित कोष में प्रतिवर्ष जमा किया जाता है और केवल ४३ प्रतिशत लाभ बाँटा जाता है ।

बम्बई :—बम्बई में २० भूमि बन्धक बैंक हैं जो प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक से सम्बन्धित हैं । ऋण २० वर्षों से अधिक के लिये नहीं दिया जाता और एक व्यक्ति को १० हजार रुपये से अधिक का ऋण नहीं दिया जा सकता । प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक ६३ प्रतिशत पर अपने सदस्यों को ऋण देते हैं । नियम के अनुसार प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक अपने लाभ का ५० प्रतिशत रक्षित कोष में रखता है और सवा छः प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं बाँटा जा सकता । प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक डिबेंचर बैंक कर कार्यालय पूँजी प्राप्त करता है जिनके मूलधन और सूद की अदायगी की गारंटी प्रान्तीय सरकार ने दे रखी है और जो ट्रस्टों सिन्डिकेटी मान लिए गए हैं । यह बैंक रक्षित कोष (Reserve Fund) के अतिरिक्त ऋण परिशोध कोष (Debt Redemption Fund) भी रखता है, जो बम्बई के भूमि बैंकों का संगठन ठीक मदरास जैसा हो है ।

आसाम :—आसाम में ४० भूमिबन्धक बैंक थे वे भी नितान्त असफल रहे । अब वे सदस्यों को ऋण नहीं देते ।

बंगाल :—बंगाल में ५ प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक हैं, वे भी विशेष सफल नहीं हुए ।

मध्य प्रदेश :—मध्य प्रदेश में २१ भूमि बन्धक बैंक हैं । उन्हें प्रान्तीय सहकारी बैंक ऋण देता है जिनका भूमि बन्धक बैंक विभाग डिबेंचर निकालता है । सरकार ने डिबेंचरों के मूलधन तथा सूद की अदायगी की गारंटी दे दी है । सरकार ने काश्तकारी कानून (Tenancy Act) में संशोधन करके मौरूसी और सीर जमीन को भी भूमि बन्धक बैंक के पास बन्धक रखने की सुविधा दे दी है ।

उड़ीसा :—उड़ीसा में एक प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंक है । वह अपनी शाखाओं द्वारा अपने सदस्यों को ऋण देता है ।

उत्तर प्रदेश :—उत्तर प्रदेश में केवल ५ भूमि बन्धक बैंक सहकारी समितियाँ हैं । यह मदरास के प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों की अपेक्षा बहुत छोटी हैं और सहकारी सेन्ट्रल बैंकों से ऋण लेकर सदस्यों को ऋण देती हैं ।

अजमेर :—मेरवाड़ा में ३ भूमि बन्धक बैंक हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है ।

देशी राज्यों में मैसूर, कोचीन और बड़ौदा में मूमि बन्धक बैंकों की स्थापना हुई है। मूमि बन्धक बैंकों के कार्य का सिंहावलोकन करते हुए रिल्वे बैंक ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि उन बैंकों को केवल पुराने ऋण को चुकाने के लिए ही नहीं बल्कि लेनी और मूमि की उत्पत्ति के लिये भी ऋण देना चाहिए। भारतवर्ष में किसानों के पुराने ऋण की समस्या को हल करने के लिए अधिकाधिक मूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की आवश्यकता है।

सहकारी साख आन्दोलन का पुनर्निर्माण : सहकारी साख आन्दोलन की गिरी हुई दशा के कारण तथा युद्ध के पूर्व कुछ प्रांतों में आन्दोलन के लगभग नष्ट हो जाने के कारण इस बात की आवश्यकता हुई कि आन्दोलन का पुनर्निर्माण किया जाय। भिन्न भिन्न प्रांतों में जो पुनर्निर्माण की योजनाएँ बनीं वे इस प्रकार की थीं।

सब से पहले सहकारी साख समिति के दिए हुए ऋण की जाँच की जाती है और उसको इतना कम कर दिया जाता है कि सदस्य उसको चुका सकें। ऐसा करते समय सदस्य को हैसियत और उसकी सम्पत्ति का ध्यान रक्खा जाता है। फिर कम की हुई रकम का किसानों में बाँट दिया जाता है जिन्हें सदस्य धीरे धीरे अदा करता है। किसी भाँति दया में २० वर्षों से अधिक के लिए कितने नहीं बाँची जाती। सदस्यों के ऋण न चुकाने के कारण जो मूमि समितियों के अधिकार में आ गईं हो वह उनके पहले मालिक को 'किराये पर खरीद' (हायर पव्चें) पद्धति से दे दी जाती है और सब कितने चुका देने पर मूमि उसके पहले मालिक को दे दी जाती है।

सदस्यों के ऋण को कम करने में जो घाटा होता है, या जिन सदस्यों से ऋण परसून नहीं होता उनकी रकम बड़े साते में जाल दी जाती है और साख समितियों के रचित काय या हिस्सा पूँजी से उस हानि को पूरा किया जाता है। यदि सहकारी साख समितियाँ उस हानि को सहन करने में असमर्थ होती हैं तो सेन्ट्रल सहकारी बैंक साख समितियों पर जो उसकी रकम उधार होती है उसको उन्नी अनुपात में कम कर देता है और जो साख समितियाँ अपनी देनी को चुकाने में क्लिप्तुन असमर्थ होती हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। सेन्ट्रल बैंकों की लेनी और देनी की भी पूरी जाँच की जाती है और यदि उससे यह बात होना है कि सेन्ट्रल बैंक अपनी देनी को नहीं चुका सकते तो उनके लेनदारों को भी उसी अनुपात में अपनी रकम कम कर देने के लिए कहा जाता है। मध्य प्रदेश और बहार तथा उगाल के सेन्ट्रल बैंकों

ने इस प्रकार अपने लेनदारों (Creditors) की रकम को घटा दिया। बंगाल में लेनदारों की जो रकम शेष रही उतने के उन्हें डिबेंचर दे दिए गए। बिहार के सेन्ट्रल बैंकों के लेनदारों की रकम कुछ तो नकद रूप में दे दी गई कुछ डिपॉजिट में परिणत कर दी गई और कुछ बड़े खाते में डाल दी गई। पुनः निर्माण योजना की एक विशेष बात यह थी कि पुनर्संगठित समितियों के सदस्यों को अणु अनाज के रूप में दिया जाता है जिससे वे खेती इत्यादि करें और यह अणु अनाज के रूप में ही वापस किया जाता है।

बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और बरार में सहकारिता साख आन्दोलन की दशा बहुत गिर गई थी अस्तु प्रान्तीय सरकारों ने भी वहाँ के प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा सेन्ट्रल बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। १९३६ के उपरान्त युद्ध आरम्भ हो गया और क्रमशः खेती की पैदावार का मूल्य ऊँचा बढ़ने लगा। इस समय तो खेती की पैदावार का मूल्य आकाश छू रहा है। किसान की आर्थिक स्थिति इस परिवर्तन से कुछ संभली और साख समितियों का बकाया अणु वसूल हो गया। इस परिवर्तन का प्रभाव यह पड़ा कि सहकारी साख समितियों तथा सेन्ट्रल बैंकों का आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और उनका अणु वसूल हो गया।

प्रारम्भिक साख समितियों का नवनिर्माण

अपरिमित और परिमित दायित्व (United and Limited Liability)

प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों के कई प्रश्नों पर आजकल बहुत विवाद चल रहा है जैसे समितियों का दायित्व, उनका क्षेत्र, उनका निरीक्षण, उनका सेन्ट्रल बैंक से सम्बन्ध आदि। सहकायिता आन्दोलन में लगे हुए कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह इस पक्ष में है कि कृषि सहकारी साख समितियों का दायित्व अपरिमित न होकर परिमित होना चाहिए। १९४० में मदरास सहकारी कमेटी के बहुमत ने भी इसी पक्ष में अपना मत दिया था। उनका कहना था कि अपरिमित दायित्व से अब कोई लाभ नहीं है वरन् हानियाँ अधिक हैं। पिछले वर्षों में साख समितियों को दिवालिया बनाने में अपरिमित दायित्व से उन सदस्यों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी जो साख समिति से अणु नहीं लेते थे और जिन्होंने अपना अणु चुका दिया था। इस कारण आन्दोलन की बहुत बदनामी हुई। उनका

कहना यह है कि अपरिमित दायित्व से अल्पे विमान मरमीत हो जाते हैं और लाख मरिजियों के मरम्मत नहीं बनते। मरम्मत में तो यह और भी अधिक दायता। वास्तव में यह मरम्मत मरिजों में ही होती है तब अपरिमित दायित्व अपरिमित न रह कर अपना-अपना योगदानानुसार मात्र समिति को देता। चुनाव का दायित्व यह जाता है। अपरिमित दायित्व के विशेषियों का यह भी कहना है कि अपरिमित दायित्व का आधार—एक दूसरे के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी, एक दूसरे के कार्यों पर निर्भीकता, तथा पारस्परिक विश्वास आज के समय में अभाव में समाप्त नहीं है। व्यवहार में व्यक्तिगत जमानत पर हैमियत तथा समर्पण का जमानत, श्रद्धा देने में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है।

आज साम्प्रदायिक दायित्व के पक्ष में है उनका कहना है कि आज तक जिसने भी कमायन और कमटियाँ कीं उन्होंने अपरिमित दायित्व के पक्ष में ही अपना मत दिया है। अपरिमित दायित्व सहकारिता का आधारभूत सिद्धान्त है—“प्रत्येक एक के लिए और सब प्रत्येक के लिए” यह सिद्धान्त सामूहिक जिम्मेदारी तथा भाई-भार का भावना को उदय करने के लिए प्रयत्न या गया था। इसका छद्म देने में पारस्परिक विश्वास तथा जानकारी नष्ट हो जायेगी और लाख मरिजियाँ सहकारी न रहकर मेट्रन बैंक की शायद मात्र रह जायेंगी। अपरिमित दायित्व की कठोरता सहकारिता विभाग के नियमों में कम कर दी है। उस पूर्णतया हटा देने में जनता का लाख समितियों पर भी विश्वास ठठ जायगा और उन्हें फिर झिट प्राप्त नहीं होगी। अपरिमित दायित्व निर्धन व्यक्तियों के लिए है। क्योंकि उनके पास कोई समर्पण तो नहीं, ठीक जमानत तो नहीं, उनकी जमानत तो केवल उनके अथवा चरित्र, ईमानदारी और उनके उत्पादन शक्ति ही हो सकती है।

रिजर्व बैंक का भी यही मत है कि कुछ मात्र सहकारी समितियों का दायित्व अपरिमित होना चाहिए। परन्तु दिसम्बर १९३६ में सहकारिता विभागों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव केवल सभापति के निर्णायक मत में गिर गया। ६६ वर्षों के लम्बे सत्रियों का दायित्व परिमित होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि देश में बहुत सख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपरिमित दायित्व को स्वयं समझते हैं।

प्राथम्य सहकारी साख्त समिति का क्षेत्र :—मदरास सहकारी समिति

का मत है कि एक गाँव बहुत छोटा क्षेत्र है और उसकी साख समिति इतनी छोटी होती है कि वह आर्थिक दृष्टि से सफल हो ही नहीं सकती। अतएव बहुत सी छोटी समितियों को मिला कर एक कर दिया जावे और वे एक स आधिक गाँव में कार्य करें। परन्तु ऐसा करने से पारस्परिक विश्वास और जान-कारी जो आन्दोलन का आधार है नष्ट हो सकती है और उस दशा में ग्राम्य साख समितियों को भी परिमित दायित्व स्वीकार करना अनिवार्य हो जावेगा।

बहुत उद्देश्य वाली समितियाँ (Multi-purposes Societies) :—कुछ समय से इस विषय में बड़ा विवाद है कि साख समितियों का कार्य-क्षेत्र क्या होना चाहिए। यह तो सभी मानते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में सर्वांगीण उन्नति न हो। रिज़र्व बैंक ने इसी बात को लेकर बहु-उद्देश्य वाली समितियों की स्थापना का समर्थन किया था। रिज़र्व बैंक का मत है कि बहु-उद्देश्य वाली समिति सदस्य को खेती या अन्य धन्धे के लिए साख दे और अपने अच्छे सदस्यों के पुराने ऋण को भूमि बंधक बैंक के द्वारा अदा करवा दे। किसान सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी पैदावार को बँचे, उनके लिए बढ़िया बीज खरीदे, और उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को ठीक मूल्य पर दिलाने के लिए उनसे आर्डर लेकर उन चीज़ों को खरीद कर उन्हें दे। मुकदमेवाज़ी को कम करने के लिए पंचायत स्थापित करे, भूमि की चकबंदी करके अच्छे बीज और औज़ारों का प्रचार करके खेती की पैदावार को बढ़ावे, खेती के अतिरिक्त बेकार समय में गौश तथा सहायक धंधों के द्वारा उनकी आय को बढ़ाने का प्रयत्न करे। जीवन सुधार कार्य को हाथ में लेकर स्वास्थ्य, औषधि वितरण, उपचार, सामाजिक कृत्यों में अधिक धन व्यय न करने और गाँव में सफाई रखने का प्रबंध करे। कहने का तात्पर्य यह है कि बहु-उद्देश्य वाली समिति गाँव की सभी मुख्य समस्याओं को हल कर के गाँव वालों को सुखी और समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करे। ऐसी समिति गाँव के सार्वजनिक जीवन का केन्द्र बन जावेगी। यह समितियाँ केवल साख ही नहीं देगी वरन् गाँव की आर्थिक दशा को सुधारने और सामाजिक उन्नति करने का प्रयत्न करेंगी।

सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए लोगों का इस विषय में काफी मतभेद है। कुछ बहु-उद्देश्य वाली समितियों के पक्ष में हैं कुछ विपक्ष में। विरोध:

करने वालों का कहना है कि हम प्रकार की समितियों का चलाना कठिन है। यह समितियाँ कुछ शिक्षित व्यक्तियों के हाथ का निर्वहणा मात्र रह जावेंगी जो सहकारिता को मानना व विवक्षित है। यहाँ नहीं उनका यह भी कहना है कि भिन्न विभागों के हिसाब एक दूसरे से मिले रहेंगे जिससे समिति की वास्तविक स्थिति क्षीरी रहेगी और एक विभाग क सहाय होने से दूसरे विभागों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि समिति के उपयोगी कार्य भी असफल हो जावेंगे।

परन्तु यह भी स्वाकार करते हैं कि गाँव की सभी समस्याओं के विरुद्ध एक साथ युद्ध छड़ना चाहिए सभी गाँवों की सहायता उत्पत्ति हो सकती है। सहकारिता आन्दोलन व प्रविष्ट विद्वान भी “के” महाशय ने भी बहुत उद्देश्य वाला समितियों का समर्थन दिया है। रजिस्ट्रारों के सम्मेलन ने भी बहुत उद्देश्य वाला समितियों का ग्मानना करने की सिफारिश की है। मदरास सहकारिता कमेटी ने बहुत उद्देश्य वाला समितियों की स्थापना का समर्थन किया है। १९४८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी (Co-operative Planning Committee) ने भी इसी मत का समर्थन किया है कि राज्य समिति बनल साल १५ न द वरत् किवानों का पैदावार का बँचे तथा उन्हें खेता कलिए हल, बैल, बाग आदि भी वे। किन्तु यह अन्य कारणों व भी साल सामिति व सुपुर्दे करने व पक्ष में नहीं है।

उत्तर प्रदेश, मदरास, बम्बई और बड़ौदा में बहुत उद्देश्य वाली समितियाँ स्थापित हो गई हैं। बम्बई और मदरास में बहुत-उद्देश्य वाली समितियों का कार्य-क्षेत्र बड़ा गाँवों में होता है, किन्तु उत्तर प्रदेश तथा बड़ौदा में एक गाँव में एक समिति होता है। यहाँ यह प्रयोग नहीं हो रहा है इस कारण इनके सम्बन्ध में कुछ कह सकना कठिन है। उत्तर प्रदेश में ही ५००० बहुत उद्देश्य वाली समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

रिजर्व बैंक तथा सहकारी आन्दोलन :—रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने व उपरान्त उसका कृषि साख शाखा (Agricultural Credit Branch) १९३५ में स्थापित हो गई। रिजर्व बैंक की कृषि साख शाखा के निम्नलिखित कार्य हैं :—कृषि साख व निष्पत्तों का नियुक्त करना, वा कृषि साख के सम्बन्ध में भारत सरकार, प्रांतीय सरकारों, देशी एजेंसियों और सहकारी बैंकों का सलाह दे। रिजर्व बैंक तथा सहकारी बैंकों व धारणा सम्बन्ध तथा कृषि साख के सम्बन्ध में जो नीति रिजर्व बैंक निर्धारित करे उसका

संशुद्धीकरण करना। रिज़र्व बैंक ऐक्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक के कृषि साख विभाग ने भारत सरकार को सहकारी साख आन्दोलन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक के कृषि साख विभाग ने सहकारी साख आन्दोलन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता बतलाते हुए नीचे लिखी सिफारिशें की :—

(१) जहां ऋण इतना अधिक हो गया हो कि कर्जदार की सामर्थ्य के बाहर हो, उसे घटा देना चाहिए।

(२) भविष्य में एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे अधिक ऋण न दिया जावे।

(३) सदस्य किसान को एक से अधिक स्थानों से ऋण न लेने दिया जावे।

(४) सहकारी गोदाम तथा विक्रय समितियों की स्थापना की जावे।

(५) प्रान्तीय सहकारी बैंक को कृषि सहकारी साख का नियंत्रण करना चाहिए।

(६) लम्बे समय के लिए दी जाने वाली साख, थोड़े समय के लिए दी जाने वाली साख से पृथक् कर दी जानी चाहिए। अर्थात् अधिक लम्बे समय के लिए भूमि बंधक बैंक ही ऋण दें।

(७) सहकारी सेन्ट्रल बैंकों को अपनी रकम इतनी घटा देनी चाहिए कि सदस्य खेती के लाभ में से उसे २० वर्षों में चुका सके। जो रकम वसूल न हो सके उसे बड़े खाते में डाल देना चाहिए।

(८) साख समितियां को सद की दर कुछ बढ़ानी चाहिए जिससे वे अधिक रक्षित कोष इकट्ठा कर सकें।

(९) सेन्ट्रल बैंकों के बोर्ड्स आब डायरेक्टर्स में बैंकिंग का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अधिक होना चाहिए।

(१०) आवश्यकता से अधिक कर्ज लेने और सदस्यों से कर्ज की रकम वसूल करने में ढिलाई दूर करने के लिए डिपॉजिटर्स के प्रतिनिधि भी सेन्ट्रल बैंक तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में रहना चाहिए।

(११) यदि एक वर्ष से अधिक के लिए ऋण देना ही पड़े तो भी दो-वर्षों से अधिक के लिए न दिया जावे। वेल इत्यादि खरीदने के लिए इस

प्रकार के ऋण को कार्गिज ऋण से पूरक रक्ता जाये। साथ समितिवाँ इस प्रकार के ऋण को अधिक न दें।

(१२) सभी ऋण जो किसान को दिए जावें जैसे-जैसे उसे आवश्यकता हो स्त्रियों में दिये जावें, एक मुश्त रकम न दी जाये।

(१३) यदि ऋण की अदायगी ठीक समय पर न हो तो उसे तुल्य पसल करने का प्रयत्न किया जाये अथवा साथ समिति को तोड़ दिया जावे (यदि पसल नष्ट हो गई हो तो बात दूसरी है।)

(१४) ऋण की अदायगी के समय का पसल नष्ट हो जाने की दशा में ही बढ़ावा जावे।

(१५) प्रारम्भिक साथ समिति का जो सहकारा साथ ग्रान्दोलन की आधार शिला है पुनः संगठन होना चाहिए और उसका क्षेत्र किसान का साथ जीवन होना चाहिए।

(१६) यह समितिवाँ एक छोटी बैंकिंग यूनिपन से सम्बन्धित कर दी जावें।

(१७) प्रान्तीय बैंक का आन्दोलन की देर मास करना चाहिए और उसका नेतृत्व करना चाहिए।

रिजर्व बैंक किसान को सभी ऋण नहीं दे सकता और न रोटी के लिए लम्बे समय के लिए ही सहाय दे सकता है। यह फसलों के लिए लिये गए पशु को भुना (डिस्काउंट) कर प्रान्तीय सहकारी बैंकों की सहायता कर सकता है। निम्न यह बिल ६ महोने से अधिक के लिए नहीं होने चाहिये। थोड़े समय के लिये आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों को ऋण दे सकता है। रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता पाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रान्तीय सहकारी बैंकों को अपनी चाल खाते की जमा प्रतिशत और मुदती जमा की प्रतिशत नफ़्ते रिजर्व बैंकों में जमा करे।

इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने प्रान्तीय सहकारी बैंकों को अपना क्या एक स्थान के दूरे स्थार पर बैठने के लिए कुछ सुविधायें प्रदान की हैं। एक प्रकार से प्रान्तीय सहकारी बैंक भी प्रमाणिक बैंक (Schedule Bank) मान लिए गए हैं। सेन्ट्रल बैंकों को रिजर्व बैंक ने प्रान्तीय सहकारी बैंक की याता आन लिया है अतएव उन्हें भी वह सुविधायें प्राप्त हो जावेंगी।

प्रान्तीय सहकारी बैंक इन सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हैं। अभी सब प्रान्तीय सहकारी बैंकों ने रिज़र्व बैंक से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है। किन्तु भविष्य में जब प्रान्तीय सहकारी बैंकों का रिज़र्व बैंकों से सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा तो सहकारी साख आन्दोलन सबल और दृढ़ हो जावेगा।

उपसंहार—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन को प्रारम्भ हुए ४४ वर्ष हो गए। किन्तु आन्दोलन ने देश के आर्थिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन उपस्थित कर दिया हो ऐसा दिखलाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि सहकारी साख आन्दोलन अभी तक शक्तिहीन है। १९२६ के उपरान्त आर्थिक मंदी का भयंकर प्रभाव पड़ने से आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रान्त में सहकारी साख आन्दोलन जर्जर होकर नष्ट होने लगा। अन्य प्रान्तों में भी आन्दोलन की दशा शोचनीय हो गई। सहकारी साख समितियों के सदस्य अपना धन न चुका सके। सेन्ट्रल बैंकों की स्थिति डावाँडोल हो उठी। यहाँ तक प्रान्तीय सहकारी बैंक भी ढगमगाने लगे। यदि उस समय प्रान्तीय सरकारों ने सहकारी साख आन्दोलन को सहायता न दी होती और पुनः निर्माण की योगनायें न चलाई जाती तो इन प्रान्तों में आन्दोलन की मृत्यु हो जाने में कोई संदेह नहीं था। परन्तु १९३६ के उपरान्त युद्ध के प्रभाव के फल स्वरूप खेती की पैदावार का मूल्य बहुत ऊँचा चढ़ गया किसान की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ सुधर गई। वह अपना धन चुकाने लगा और साख समितियों से सेन्ट्रल बैंक सरलता से अपना धन वसूल कर सके। इस कारण सहकारी साख आन्दोलन की स्थिति पहले से बहुत संभल गई।

पंजाब, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में साधारण रूप से सहकारिता आन्दोलन की स्थिति अच्छी है। बम्बई और मद्रास में गैर सहकारी कार्यकर्ताओं के कारण, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की सतर्कता के कारण आन्दोलन कुछ हद तक सफल हुआ है। अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग तथा देहली में आन्दोलन की दशा साधारण है। यद्यपि पंजाब, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में भी साख समितियों की दशा संतोषजनक नहीं है, प्रतिवर्ष सैकड़ों समितियाँ दिवालिबा हो जाती हैं, फिर भी अन्य प्रान्तों की अपेक्षा वहाँ स्थिति कुछ अच्छी है। देशी राज्यों में भी आन्दोलन की दशा संतोषजनक नहीं है। मृपाल, ग्वालिबर और इन्दौर में आन्दोलन बहुत शक्तिहीन है। हैदराबाद, बड़ीसा, मैसूर, ट्रावनकोर, तथा काश्मीर में स्थिति साधारण है। अधिकतर देशी राज्यों में आन्दोलन अभी आरम्भ ही नहीं हुआ।

समाज का अशिक्षित होना भी है। सहकारिता आन्दोलन की सफलता के लिए तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता है क्योंकि सदस्यों की समिति को स्वयं चनाना पड़ता है, उनके हिसाब का रखना पड़ता है। मारतवर्ष में सहकारी साख सामितियों के लिए लिखे-पढ़े सदस्य नहीं मिलते जो मंत्री का कार्य कर सकें। इस कारण एक वैतनिक कर्मचारी को मंत्री बनाना पड़ता है जो कि सदस्य नहीं होता और उसके निम्ने ८ या १० समितियाँ कर दी जाती हैं। उसका पल यह होता कि वहाँ समितियों का कर्ता-धर्ता बन जाता है और सदस्यों का कार्य करने का कोई शिक्षा नहीं मिलती। इन वैतनिक मंत्रियों के विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं। शिक्षा का प्रचार के साथ ही सहकारिता के विद्वानों का शिक्षा का भी प्रयत्न होना आवश्यक है। तभी सहकारी समितियाँ मंत्री प्रकार चल सकती हैं।

भारत में बहुत से विद्वानों का मत है कि सहकारिता आन्दोलन एक आन्दोलन न होकर एक सरकारी नीति (State policy) के रूप में चलाया जाता है। यहाँ आन्दोलन की निर्यातता है। यदि ऐसा चाहे तो सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रार ही आन्दोलन का सर्वेसर्वा है। रजिस्ट्रार कोई भित्तिनिषेध होता है, उसके नीचे इच्छा रजिस्ट्रार तथा इन्स्पेक्टर होते हैं। काद भी रजिस्ट्रार अधिक दिनों तक उस पद पर नहीं रह पाता क्योंकि वह अपनी उन्नति का आन्दोलन के लिए नहीं छोड़ सकता। जब यह होता है कि रजिस्ट्रार जल्दी जल्दी बदला करते हैं। और एक नीति रचायी रूप से काम में नहीं लाई जाता। अधिकतर सहकारिता विभाग के कार्य कर्ताओं में उत्साह और लगन का अभाव है। अभी तक जो व्यक्ति उसमें गौर सरकारी कार्य कर्ता थे व सरकार का प्रयत्न करने के लिए उसमें आते थे न कि सेवा भाव से प्रेरित होकर आते थे। किन्तु अब राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त यदि सरकार चाहे तो सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य-कर्ता उसमें सम्मिलित होंगे।

इस सबका पल यह होता है साख समिति का सदस्य समिति को अपनी सस्था न समझकर सरकारी बैंक समझता है। वह तो समझता है कि जिस प्रकार सरकार लकावी बाँटती है उसी प्रकार वह सरकारी बैंक श्रम देता है। इसका अर्थ यह है कि समिति का सदस्य सहकारिता के मूल सिद्धान्त से अपरिचित है। यह यह नहीं समझता कि सहकारिता का मूल सिद्धान्त स्वावलम्बन है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि आन्दोलन

पर से सरकारी नियंत्रण कमशः हटा कर गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के हाथ में दे दिया जावे और गैर सरकारी अनैतनिक कार्यकर्ताओं को आन्दोलन में आने के लिए प्रोत्साहित किया जावे ।

अधिकांश साख समितियों की आर्थिक स्थिति खराब है । वह महाजन की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती । महाजन की स्थिति गांव में पहले जैसी ही मजबूत है वह साख समितियों से तनिक भी मजबूत नहीं है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आन्दोलन जीवन रहित है ।

भारतीय सहकारिता आन्दोलन की एक कमी यह है कि वह अभी तक साख समितियों तक ही सीमित रहा । गैर साख समितियों की संख्या बहुत कम है । भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में साख समितियों की आवश्यकता है । उनके महत्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु गैर साख समितियों की भी उतनी ही आवश्यकता है । गांव का महाजन किसान को फेबल ऋण ही नहीं देता वरन उसकी पैदावार को खरीदता भी है और उसकी आवश्यक वस्तुएं बेचता भी है । जब तक कि सहकारी समितियां क्रय-विक्रय को भी अपने हाथ में लेकर महाजन को उसके स्थान से हटा नहीं देती तब तक महाजन का बल नष्ट नहीं होगा और न किसान की आर्थिक दशा में ही सुधार होगा । यह उद्योग बंधो में लगे हुए कारीगरों को भी साख के माध्यम क्रय विक्रय कार्य करने वाली समिति की आवश्यकता है । हर्ष का विषय है कि अब इस ओर विशेष रूप से सहकारिता विभाग का ध्यान गया है और गैर साख समितियों की स्थापना हो रही है ।

एक दोष जो कि आन्दोलन में कुछ आया है वह कागजी लेन-देन है । जब समिति के सदस्य रुपया जमा नहीं करते तो समिति सैन्डल बैंक से उतना ही ऋण ले लेती है जितनी किस्त उन्हें चुकानी होती है । बैंक के खाते में पिछली किस्त चुकता दिखला दी जाती है और उतना ही रुपया ऋण के रूप में दिखला दिया जाता है । उसका अर्थ यह होता है कि रुपया बटूल नहीं होता और अधिकारियों को धोखा दिया जाता है ।

आन्दोलन की निर्वलता का एक कारण यह भी है कि सहकारिता विभाग के कर्मचारी अपनी योग्यता दिखलाने के उद्देश्य से शीघ्रतापूर्वक बिना अधिक ध्यान दिये तथा सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों को सिद्धा दिये समितियां स्थापित कर देते हैं । कुछ समय उपरान्त उस कर्मचारी का तबादला हो जाता

है। जल्दी में सगठित समिति ठीक काम नहीं करती। अन्त में दिवालिया हो जाती है और आन्दोलन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है।

कहीं कहीं पचायत के सदस्य बेईमानी करते हैं, कहीं कहीं महानन हो समिति को हथियाने का प्रयत्न करता है और कहीं कहीं प्रभावशाली सदस्य समिति को हथिया लेते हैं और वे हा उससे अभिन्न लाभ उठाते हैं। वे अन्य व्यक्तियों को उनका सदस्य नहीं बनाते और अधिकांश श्रम स्वयं ही ले लेते हैं। समितियों से श्रम मिलने में देरी होती है और जितना श्रम सदस्य चाहते हैं, उतना नहीं मिल पाता।

प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों का निरीक्षण और आडिट ठीक तरह से नहीं होता इस कारण बहुत से दोष द्विये रहते हैं। साख समितियों की ओर अधिक धमकायी इस कारण भी आकर्षित नहीं होते क्योंकि समिति से श्रम लेने से उसका श्रणी होना प्रकट हो जाता है। यह गुप्त नहीं रह पाता और कभी कभी जब कि वह किस्त नहीं दे पाता तो उसे सभों के सामने अपमानित होना पड़ता है। सेन्ट्रल बैंक के कर्मचारी अथवा सुपरवाइजर मांघ में जाकर सीधे समिति के सदस्य से रुपया बसूल करते हैं। इससे दो हानियां होती हैं एक तो सदस्य की दृष्टि में समिति का कोई मूल्य नहीं रहता। वह समझता है कि बैंक के कर्मचारी ही वास्तव में श्रम दाता हैं, दूसरे जो किसान यह सब देखते हैं वे खुले आम अपमानित होने की अपेक्षा महाजन से चुपचाप श्रम लेना अच्छा समझते हैं। यही कारण है कि सहकारिता आन्दोलन जनता को आकर्षित न कर सका।

सहकारी साख समितियों से लाभ —ऊपर लिखी समालोचना से यह न समझ लेना चाहिए कि सहकारिता आन्दोलन (Co-operative movement) से कोई लाभ हा नहीं हुआ है। यह ठीक है कि आन्दोलन अभी निर्धूल है। दोषपूर्ण सगठन तथा कार्य-कर्ताओं की अकर्मण्यता के कारण वह अभी तक सफल नहीं हो सका है। फिर भी आन्दोलन से देश को लाभ हुआ है। शाही कृषि कमिशन की सम्मति में “सहकारिता आन्दोलन के विषय में जानकारी बढ़ रही है, मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। बैंकिंग के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जा रही है। जहाँ आन्दोलन को नींव दृढ़ है वहाँ महाजन ने खुद की दर घटा दी है और वह अच्छा व्यवहार करता है। उन रातों में महाजन का प्रभुत्व कम हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसान की मनोवृत्ति बदल रही है।”

एक तो लाभ यही हुआ है कि आन्दोलन में लगभग ११० करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी (Working capital) है। वह निर्धन जनता को कम सूद पर मिलती है। सहकारी साख आन्दोलन में सूद की दरें इस प्रकार हैं :—

प्रारम्भिक साख समितियाँ—उदत्यों से ७ से ६ प्रतिशत सूद लेती हैं। डिपाजिट पर ४ या ५ प्रतिशत सूद देती हैं तथा सेंट्रल बैंकों को ५ से ७ प्रतिशत सूद देती हैं।

सैन्ट्रल बैंक—३ या ४ प्रतिशत सूद डिपाजिटों पर देते हैं और प्रान्तीय सहकारी बैंकों से ४ से ५ प्रतिशत सूद लेते हैं।

प्रान्तीय सहकारी बैंक—डिपाजिटों पर २ से ३ प्रतिशत सूद देते हैं और इम्पीरियल बैंक से ३ प्रतिशत पर ऋण लेते हैं।

सहकारी साख समितियों से गाँव वालों में व्यापारिक ज्ञान, स्वावलम्बन, तथा सामूहिक भावना का उदय हुआ है।

महाजन का गाँव में जो एकाधिपत्य था वह क्रमशः नष्ट हो रहा है इस डर से कि उसके ग्राहक समिति के सदस्य न बन जावें अथवा समिति न स्थापित हो जावे वह गाँव वालों के साथ नरमी का व्यवहार करता है।

भविष्य में निर्धन व्यक्तियों तथा गाँवों का आर्थिक उन्नति के लिए सहकारिता आन्दोलन पर ही हमें निर्भर रहना होगा। इर्थ की बात है कि राष्ट्रीय सरकार का इस ओर ध्यान है। बिना सहकारिता आन्दोलन के सफल बनाये हमारे गाँवों का सुधार नहीं हो सकता।

पिछले दिनों से कुछ अर्थशास्त्र के विद्वान यह अनुभव कर रहे थे कि कृषि की अर्थ-व्यवस्था करने के लिए केवल सहकारी साख समितियाँ अथवा सहकारी बैंक ही यथेष्ट नहीं हैं। उन लोगों का कहना था कि जिस प्रकार उद्योग धन्वों के लिए अर्थ व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की गई है उसी प्रकार कृषि की अर्थव्यवस्था करने के लिए ग्राम्य फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की जावे। विशेषकर सारिधा कमेटी ने इस पर अधिक जोर दिया। अस्तु सरकार ने उक्त कारपोरेशन की स्थापना के लिए एक बिल उपस्थित किया है।

ग्राम्य अर्थ (Finance) कारपोरेशन बिल (Rural Finance Corporation)

कारपोरेशन समस्त भारत में कृषि के धन्य को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएँ या एजेंसी स्थापित करेगी। कारपोरेशन सहकारी समितियों को भी अपनी एजेंट बनावेगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय कृषि साख कारपोरेशन भी स्थापित करेगी। कारपोरेशन सभी प्रान्तीय सहकारी बैंकों की केन्द्रीय संस्था का काम भी कर सकती है।

पूँजी :—कारपोरेशन की पूँजी ५ करोड़ रुपये होगी। प्रत्येक हिस्से का मूल्य ५००० रु० होगा। हिस्से का मूल्य कम इस कारण रखा गया कि अधिक से अधिक सहकारी संस्थायें उसके हिस्से ले सकें। यदि कारपोरेशन दियालिया हो जावे तो सरकार हिस्सा पूँजी की अदायगी की गारंटी देगी। सरकार एक न्यूनतम लाभ की दर निर्धारित करेगी और उतने लाभ की गारंटी हिस्सेदारों को देगी। यही नहीं सरकार को चाहिए कि लाभ की अधिकतम दर को निर्धारित कर दे। इस कारपोरेशन के हिस्सों को केवल (१) केन्द्रीय सरकार, (२) रिज़र्व बैंक आव इंडिया, (३) सिविल बैंक, (४) सहकारी बैंक (५) तथा चैम्बर आव कामर्स ही खरीद सकेंगे।

कारपोरेशन के हिस्सों का बंटवारा नीचे लिखे अनुसार होगा :—

(१) केन्द्रीय सरकार १ करोड़ रुपये।

(२) रिज़र्व बैंक एक करोड़ रुपये।

(३) सिविल बैंक एक करोड़ रुपये।

(४) सहकारी बैंक एक करोड़ रुपये।

(५) चैम्बर आव कामर्स, ईस्ट इंडिया काउन्सिल एसोसिएशन तथा बीमा कंपनियाँ इत्यादि—१ करोड़ रुपये।

हिस्सा पूँजी के बंटवारे को ध्यान पूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कारपोरेशन सोलह आने सरकारी सखा नहीं होगी।

कार्यशील पूँजी प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन ऋण पत्र (डिबेंचर) निकास सकेगी जिनकी पूँजी और सुद की अदायगी की गारंटी सरकार देगी। सुद की दर सरकार कारपोरेशन के बोर्ड आव डायरेक्टर्स की सलाह से निश्चित करेगी।

कारपोरेशन अपनी हिस्सा पूँजी के अधिक से अधिक आठ गुने ऋण-पत्र निकाल सकेगी। अर्थात् ४० करोड़ रुपये से अधिक के ऋण पत्र वह नहीं निकाल सकेगी।

कारपोरेशन अपनी हिस्सा पूँजी की दुगुनी रकम अर्थात् दस करोड़ रुपये तक डिपॉजिट ले सकेगी जमा पाँच वर्ष या उससे अधिक समय के लिए ही ली जा सकेंगी।

साख—कारपोरेशन मध्यम काल तथा लम्बे काल के लिए अचल सम्पत्ति, जैसे इमारत, भूमि तथा यंत्रों की जमानत पर उनके ५० प्रतिशत मूल्य तक ऋण दे सकेगी। कारपोरेशन फसलों, गोदाम की रसीद पर तथा अन्य चल जायदाद की जमानत पर ऋण दे सकेगी। अल्पकालीन साख खेती के कार्यों, दूध तथा अंडे के धन्धों को करने के लिए, अथवा खेती की पैदावार की बिक्री के लिए दी जावेगी।

अल्पकालीन साख अधिक से अधिक १८ महीने के लिए दी जावेगी। मध्यमकालीन साख १८ महीने से ७ वर्षों तक के लिए होगी। मध्यमकालीन साख मशीनें खरीदने के लिए, खेती के लिए औज़ार तथा पशुओं को खरीदने के लिए, भूमि का सुधार करने, इमारत बनाने, खेती के लिए मशीन तथा यंत्र खरीदने, या किसी खेती से सम्बन्धित धन्धे को स्थापित करने के लिए दी जावेगी। मध्यमकालीन साख की कम से कम रकम दस हजार रुपये और अधिक से अधिक रकम ५०,००० रु० होगी। अर्थात् किसी एक व्यक्ति को कम से कम दस हजार और अधिक से अधिक पचास हजार रुपये का ऋण दिया जा सकेगा।

लम्बे समय के लिए ऋण नीचे लिखे उद्देश्यों के लिए दिया जावेगा :- भूमि की खरीद के लिए, भूमि में स्थायी सुधार करने के लिए, फार्म गृह को बनाने के लिए, और खेती से सम्बन्धित किसी धन्धे को स्थापित करने के लिए। दीर्घकालीन साख ७ वर्षों से ३० वर्षों तक के लिए दी जावेगी। किसी एक व्यक्ति को लम्बे समय के लिए कम से कम २५ हजार रुपए और अधिक से अधिक एक लाख रुपए दिए जावेंगे। यह न्यूनतम तथा अधिकतम ऋण देने की सीमा सहकारी समितियों तथा “ऋण लेने वाले समूहों” के बारे में लागू नहीं होगी। बहुत कम कर्ज लेने वाले सहकारी साख समितियों से ही कर्ज लेते रहेंगे क्योंकि वे सम्भवतः २५ हजार कर्ज कभी भी नहीं ले सकते।

तक कि नीचे शर्तें पूरी न हों उस समय तक ऋण नहीं दिया जावेगा ।

- (१) अन्नसम्पत्ति को बन्धक रख दिया जाय अथवा
- (२) चर सम्पत्ति को बन्धक रख दिया जाय अथवा
- (३) फसल या पशु इत्यादि को बन्धक रख दिया जावे ।

कारपोरेशन केवल सहकारी समितियों, ऋण लेने वाले समूहों, तथा व्यक्तिगत किसानों तथा खेती के पन्धे को सारा देने वाली संस्थाओं से ही कामबार करेगी ।

सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सहकारी साख समितियों तथा ऋण लेने वाले समूहों के सदस्यों से दीर्घकालीन ऋण पर १ प्रतिशत तथा थोड़े समय और मध्यमकालीन ऋण पर १½ प्रतिशत सूद कम लिया जावेगा ।

इस विधान में एक कमी है । सहकारी साख समिति तथा ऋण लेने वाले समूहों के सदस्यों को एक ही सुविधा दी गई है । इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी व्यक्ति मिलकर एक समूह बनाकर यही सुविधा प्राप्त कर लेंगे जो कि सहकारी समिति को प्राप्त है ।

कारपोरेशन सहकारी समितियों तथा अन्य कृषि सम्बन्धी संस्थाओं के हिस्सों तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन (Under write) करेगी ।

प्रथमः—कारपोरेशन का प्रबन्ध एक बोर्ड आव डायरेक्टर करेगा । बोर्ड एक कार्यकारिणी समिति तथा एक मैनेजिंग डायरेक्टर चुनेगा जो कि कारपोरेशन का संचालन करेंगे ।

बोर्ड में ११ डायरेक्टर होंगे । उनकी नियुक्ति इस प्रकार होगी ।

- (अ) दो डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी ।
- (क) दो डायरेक्टर मित्रवं बैंक मनोनीत करेगा ।
- (ख) दो डायरेक्टर वे शिहूल बैंक चुनेंगे जो कारपोरेशन के हिस्सेदार हैं ।
- (ग) दो डायरेक्टर सहकारी संस्थाओं द्वारा चुने जावेंगे ।

(घ) दो डायरेक्टर अन्य हिस्सेदारों द्वारा चुने जावेंगे ।

(ङ) एक मैनेजिंग डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी । पहली बार मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने में केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक आव इंडिया से राय लेगी और बाद को कारपोरेशन के बोर्ड आव डायरेक्टर से राय लिया करेगी ।

अध्याय १५

मिश्रित पूँजी वाले बैंक या व्यापारिक बैंक

(Joint Stock Banks अथवा Commercial Banks)

एजेंसी गृह (Agency Houses):—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि बैंकिंग व्यवसाय भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है किन्तु आधुनिक ढंग के बैंक अभी थोड़े समय से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। वास्तव में बम्बई और कलकत्ता में या एजेंसी गृह (Agency Houses) में वही इन बैंकों के जनक थे। इन एजेंसी गृहों की स्थापना अँग्रेज व्यापारियों ने की थी। बम्बई और कलकत्ते के यह एजेंसी गृह वास्तव में व्यापार करते थे वही उनका मुख्य कार्य था किन्तु वे व्यापार के साथ बैंकिंग का कारगर भी करते थे। उनके पास निच की पूँजी (Capital) नहीं होती थी। वे जनता से डिपॉजिट (जमा) आकर्षित करके ही कार्यशील पूँजी (Working Capital) इकट्ठा करते थे। यह एजेंसी गृह ईस्ट इंडिया कम्पनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने स्थापित कर लिए थे। जिन कर्मचारियों ने देखा कि भारतीय व्यापार में धनोत्पत्ति का असीम क्षेत्र है उन कर्मचारियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की नौकरी छोड़कर व्यापार करना आरम्भ कर दिया। यों तो यह एजेंसी गृह मुख्यतः व्यापार करते थे किन्तु अँग्रेज व्यापारियों के लिए साख का प्रश्न करने के लिए उन्होंने बैंकिंग विभाग भी खोल रखे थे। देखी बैंकिंग यों ही अवनति की आरंभ थी फिर वे अँग्रेजों द्वारा किये जाने वाले विदेशी व्यापार के लिए साख का प्रश्न कर सकने में असमर्थ थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें अँग्रेजी ढंग के विदेशी व्यापार का न तो कुछ ज्ञान ही था और न अँग्रेज व्यापारी उनकी भाषा को ही समझते थे।

यह एजेंसी गृह दुकानदारी करते थे, जहाजों के मालिक थे, शराब बनाने, चमड़े के कारखानों, कपास, आटा, और लकड़ी की मिलों के स्वामी थे, तथा ईस्ट इंडिया कम्पनी, तथा सरकारी कर्मचारियों और अँग्रेज व्यापारियों के एजेंट तथा बैंकर का काम करते थे। वे अधिकशतः योरोपियन लोगों से डिपॉजिट आकर्षित करते थे। इससे अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी

भी अपनी शक्ति तथा लूट का रूपया इन एजेंसी गृहों के बैंकिंग विभागों में जमा कर देते थे। डिपॉजिट द्वारा प्राप्त रुपये को यह एजेंसी गृह अंग्रेज़ व्यापारियों को फसलों की खरीद के लिए तथा अफीम, नील, कपास तथा रेशम के व्यापार के लिए बहुत ऊँचे सूद पर उधार देते थे। उनमें से कुछ एजेंसी गृह कागज़ी मुद्रा (Paper money) भी निकालते थे। इनमें से कुछ एजेंसी गृहों ने भारत में सर्व प्रथम योरोपियन ढंग के बैंक स्थापित किये। उदाहरण के लिए मेसर्स एलेक्जेंडर एण्ड कंपनी ने १७७० में 'बैंक ऑफ हिन्दोस्तान' स्थापित किया, मेसर्स पाभर एण्ड कंपनी ने 'कलकत्ता बैंक' स्थापित किया और मेसर्स मैकिन्टाश एण्ड कंपनी ने 'बैंक ऑफ कलकत्ता' स्थापित किया। 'बंगाल बैंक' तथा 'जनरल बैंक ऑफ इंडिया' १७८५ के लगभग स्थापित किए गए थे। इन्हें भी कलकत्ते के एजेंसी गृहों ने स्थापित किया था। यह एजेंसी गृह अपने व्यापार के साथ-साथ बैंकिंग का कारबार भी करते थे अतएव उनको व्यापारिक लाभ के अतिरिक्त बैंकिंग विभाग से सूद और कमीशन की आमदनी भी होती थी। अस्तु भारतवर्ष में प्रथम योरोपियन ढंग के बैंक न मिश्रित पूँजी के बैंक थे और न वे केवल शुद्ध बैंकिंग कारबार ही करते थे। काक्स या मिंडले जैसी साधारण व्यापार करने वाली योरोपियन फर्म और पैनिनगुलर और ओरियंटल जैसी जहाज़ी कंपनियाँ भी बैंकिंग कारबार करती थीं। इस बैंकिंग और साधारण व्यापार के मिश्रण का जो परिणाम होना था वही हुआ। इसके अतिरिक्त इन एजेंसी गृहों ने डिपॉजिट किए हुए रुपये से सट्टा (Speculation) करना आरम्भ किया, इमारतों, कोयले की खानों, जहाज़ों, कहवा तथा गरम मसाले के बागों तथा भूमि के खरीदने और आटे कपास और रेशम की मिलों को चलाने में अनाप-शनाप रुपया लगाया। इस सब का परिणाम यह हुआ कि १८२८-३२ में यह एजेंसी गृह डूब गए। एजेंसी गृहों के डूबने के साथ ही उनके बैंकिंग विभाग तथा उनके स्थापित किए हुए बैंक भी डूब गए क्योंकि बैंकों का रुपया उन एजेंसी गृहों के कारबार में लगा था। कलकत्ता बैंक १८२६ में, बैंक ऑफ हिन्दुस्तान १८३२ में, और कमर्शियल बैंक ऑफ कलकत्ता १८३३ में डूब गए।

इन बैंकों ने सर्व प्रथम भारत में कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) का चलन आरम्भ किया। हिन्दुस्तान बैंक के प्रचलित नोटों का मूल्य २५ लाख रुपये था। बंगाल बैंक के नोटों का चलन ८ लाख रुपये के लगभग था। इनमें से प्रत्येक बैंक यह चाहता था कि उनके नोट सरकारी दफ्तरों तथा

खजानों में स्वीकार हों। सरकार ने पहले जनरल बैंक के नोटों को स्वीकार किया किन्तु १७६३ में उनके बढ़ हो जाने पर ' बैंक ऑव कलकत्ता ' के नोटों को स्वीकार किया। १८०० में इस बैंक के ४३ लाख रुपये के नोट प्रचलित थे। इसी प्रकार का एक बैंक मदरास (१६८८) और दूसरा बैंक बम्बई (१७२४) में स्थापित हुआ किन्तु १८२६-३० में एजेंसी गृही के साथ ही यह बैंक भी बंद हुए। इस प्रकार योरोपियन दग के बैंकों की स्थापना का पहला युग समाप्त हुआ।

इस बैंकिंग संकट के उपरान्त १८६० तक बहुत कम बैंक स्थापित हुए। इस काल में १२ बैंक स्थापित हुए जिनमें आधे बैंक बंद हुए। यह सब योरोपियनों द्वारा स्थापित हुए थे। बूझने वाले बैंकों ने जनता को धोखा दिया और डिपॉजिट करने वालों का रुपया मारा गया। किन्तु इस काल में तीन प्रेसीडेंसी बैंक स्थापित हुए जिनका विशेष महत्व था।

प्रेसीडेंसी बैंक—प्रेसीडेंसी बैंक तीन थे जो कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर द्वारा स्थापित हुए थे। बैंक ऑव बंगाल १८०६ में। बैंक ऑव बम्बई १८४० में और बैंक ऑव मदरास १८४३ में स्थापित हुआ। बैंक ऑव बंगाल १८०६ में बैंक ऑव कलकत्ता के नाम से स्थापित हुआ था कि १८०६ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने उसे चार्टर दे दिया। तब से वह बैंक ऑव बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

इन तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूरी करने तथा देश के भीतरी व्यापार को आर्थिक सहायता देने के लिए की गई थी। जब कि बैंक ऑव बंगाल की स्थापना की गई थी तो उससे यह आशा की गई थी कि जब सोने या चांदी की मांग होगी तो यह जनता को उचित मूल्य पर देगा तथा सरकारी विक्रयूरिटियों और सरकारी हुडियों (Treasury Bills) के मूल्य को निराने से बचावेगा तथा कागजी मुद्रा का निकालेगा। उस समय बंगाल में करमी (मुद्रा) की दशा बड़ी खराब थी। इस कारण वहाँ कागजी मुद्रा चलाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आरम्भ में प्रेसीडेंसी बैंक सरकार के कोष (Funds) भी रखते थे किन्तु अद्वारहवीं शताब्दी के अन्त में सरकार ने रिजर्व खजाने (Reserve Treasuries) तथा जिला और तहसील में खजाने स्थापित किए। इस कारण प्रेसीडेंसी बैंकों का सरकारी कारबार से उतना सम्बन्ध नहीं रहा। परन्तु सरकार के इस निश्चय से द्रव्य बाजार

में कोष की कभी-कभी बहुत कमी पड़ जाती थी क्योंकि लगान तथा मालगुजारी के रूप में बहुत सा द्रव्य इन खजानों में जाकर बेकार हो जाता था क्योंकि द्रव्य-बाजार के लिए वह अप्राप्य था और ठीक उसी समय द्रव्य बाजार (Money Market) को द्रव्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी क्योंकि मंडियों में वह समय खरीद विक्री का होता था। फिर भी सरकार ने प्रेसीडेंसी बैंकों के पास एक न्यूनतम द्रव्य राशि रखने का निश्चय कर लिया था। इस न्यूनतम द्रव्य राशि पर प्रेसीडेंसी बैंक कोई भी सूद नहीं देते थे। यदि उस न्यूनतम द्रव्य राशि से कम रुपया सरकार प्रेसीडेंसी बैंकों के पास रखती तो सरकार को उस कमी पर सूद देना पड़ता था। किन्तु व्यवहार में सरकार ने निर्धारित न्यूनतम राशि से सदैव अधिक रुपया प्रेसीडेंसी बैंकों के पास रखा। इसके अतिरिक्त प्रेसीडेंसी बैंक सरकारी ऋण को निकालते तथा उसका प्रबंध करते थे। सरकार ने उन पर कुछ नियंत्रण भी स्थापित कर रखा था। उनके आय-व्यय निरीक्षण पर सरकारी नियंत्रण था, सरकार उनसे समय-समय पर उनके कारबार के सम्बन्ध में पूछताछ करती थी तथा उन्हें अपने हिसाब का साप्ताहिक लेखा निकालना पड़ता था।

१८७६ के प्रेसीडेंसी बैंक ऐक्ट के अन्तर्गत प्रेसीडेंसी बैंकों पर कुछ धन भी लगा दिए गए थे। प्रेसीडेंसी बैंक विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का काम नहीं कर सकते थे, वे भारत के बाहर डिपॉजिट नहीं ले सकते थे। वे ६ महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकते थे और न वे अचल सम्पत्ति की जमानत पर ही ऋण दे सकते थे। ऐसे प्रामिखरी नोटों पर भी वे कर्ज नहीं दे सकते थे जिन पर दो स्वतंत्र व्यक्तियों से कम के हस्ताक्षर हों। व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं दिया जा सकता था और माल की जमानत पर तभी कर्ज दिया जा सकता था कि जय वह माल या उसके स्वामित्व सम्बन्धी कागज़ पत्र (Titles) जमानत के रूप में जमा कर दिये गये हों।

बैंक आव बंगाल की आरम्भ में ५० लाख पूँजी थी जिसमें १० लाख सरकार के हिस्से थे। बाद की बैंक की पूँजी बढ़ा दी गई। करंसी की अस्त-व्यस्त दशा को सुधारने के लिए बैंक आव बंगाल ने कागज़ी मुद्रा निकाली। सरकार केवल बैंक आव बंगाल का ही नोटों को स्वीकार करती थी इस दृष्टि से बैंक आव बंगाल प्रमुख प्रेसीडेंसी बैंक था। बैंक आव बाम्बे का हिस्सा पूँजी ५२, २५००० रु० थी जो कि ५२२५ हिस्सों में बटी हुई थी।

इसमें ३ लाख रुपये के हिस्से बम्बई सरकार ने लिए थे। समुक्त राष्ट्र अमेरिका में गृह-युद्ध होने के कारण ससार में कपास का अकाल पड़ा और भारतीय कपास की मांग और मूल्य बेहद बढ़ गया। उसके कारण बम्बई में नये कारखाने इत्यादि स्थापित हुए और वहाँ शोयरी का सङ्घा बहुत हुआ। बैंक आव बाम्बे का कामा इस सङ्घे में बूब गया। इस कारण यह बैंक १८६८ में बूब गया। किन्तु उसी बष तक एक नया बैंक १ करोड़ रुपये की पूँजी से स्थापित किया गया। बैंक आव मदरास ३० लाख रुपये की पूँजी से स्थापित किया गया। मदरास सरकार ने उसमें ३ लाख रुपये के हिस्से लिए थे। इस बैंक की कार्य-पद्धति बही थी जों अन्य दो प्रेसीडेंसी बैंकों की थी।

आरम्भ से ही सरकार तथा प्रेसीडेंसी बैंकों का पनिष्ठ सम्बन्ध था। सरकार ने इन बैंकों के केवल हिस्से ही नहीं लिए थे किन्तु सरकार इनके सचालक बाड में अपने डायरेक्टर भी नियुक्त करती थी। इन बैंकों को सरकारी बैंकिंग कारबार करने का एकाधिकार प्राप्त था। १८६२ तक उन्हें कागजी मुद्रा (Paper money) निकालने का भी अधिकार था किन्तु १८६२ के उपरान्त उनसे यह अधिकार छीन लिया गया और सरकार ने कागजी मुद्रा निकालना आरम्भ किया। १८६२ में जब प्रेसीडेंसी बैंकों से नोट निकालने का अधिकार ले लिया गया तो उनकी हानि को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रेसीडेंसी नगरी (कलकत्ता, बम्बई, मदरास) में सरकार अपनी सारी रोकड (Cash Balances) प्रेसीडेंसी बैंकों के पास रखेगी। वास्तव में प्रेसीडेंसी बैंक ने कागजी नोट बहुत अधिक जमा भी नहीं निकाले क्योंकि सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेसीडेंसी बैंकों पर कड़े बन्धन लगा दिये थे। उदाहरण के लिए एक प्रतिबन्ध तो यह था कि सब चालू जमा (Current Deposit) तथा कागजी नोट जो चलन में हैं बैंकों के नकद कोष (Cash Reserve) के तीन गुने से अधिक नहीं हो सकते। बाद को इसका बढा कर चारगुना कर दिया गया।

१८७६ में सरकार ने एक प्रेसीडेंसी बैंक ऐक्ट बनाया जिससे इन बैंकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस कानून के अनुसार सरकार ने इन बैंकों से अपनी हिस्सा पूँजी निकाल ली। हिस्सा पूँजी निकालने के साथ ही सरकार ने डायरेक्टरों तथा बैंक के सेक्रेटरी तथा खजांची को नियुक्त करने का भी अधिकार छोड़ दिया। साथ ही बैंकों के पास सरकारी रुपया रखने की सुविधा

भी समाप्त कर दी गई। आगे से यह बैंक जनता से डिपॉजिट ले सकते थे तथा सरकारी सिक्कुरिटियों तथा कुछ अन्य प्रकार की सिक्कुरिटियों में रुपया लगा सकते थे। विलों को खरीद सकते थे उनको मुना सकते थे, स्वीकृति विलों तथा प्रामिसरी नोटों के आधार पर कर्ज दे सकते थे। सिक्कुरिटियों को अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने के लिए स्वीकार कर सकते थे तथा सोने और चांदी की खरीद विक्री का काम कर सकते थे। किन्तु जैसा ऊपर हम बता चुके हैं कि इन बैंकों को भारत के बाहर डिपॉजिट लेने तथा विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का काम करने की मनाही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks) नहीं चाहते थे कि प्रेसीडेंसी बैंक उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें। सरकार ने कुछ प्रतिबन्ध तो बैंकों को ठीक रास्ते पर रखने के लिए लगाये थे किन्तु यह प्रतिबन्ध विशेष कर विदेशी विनिमय बैंकों की ईर्ष्या के कारण लगाये गए थे। प्रेसीडेंसी बैंकों को लंदन द्रव्य बाजार में डिपॉजिट न लेने देने का परिणाम यह होता था कि जहाँ द्रव्य बाजार (Money Market) में द्रव्य की कमी होती थी तो सूद की दर बहुत ही ऊँची हो जाती थी और व्यापार को हानि पहुँचती थी। इस प्रतिबन्ध से प्रेसीडेंसी बैंकों की उपयोगिता तथा कारबार पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

इन सब रूकावटों के होते हुए भी प्रेसीडेंसी बैंकों ने बहुत उन्नति की। उन्होंने देश में बहुत शाखें स्थापित कीं तथा उन शाखों पर सरकारी करंसी नोटों को मुद्राने की सुविधा देकर सरकारी करंसी नोटों के चलन को बहुत अधिक बढ़ाया। यही नहीं उन्होंने डिपॉजिट बैंकिंग की उन्नति की। सरकार से सम्बन्धित होने के कारण देश में उनकी प्रतिष्ठा थी और भारतीय बैंकों में उनका प्रमुख स्थान था। प्रथम महायुद्ध के समय इन बैंकों ने सरकार को सरकारी ऋण निकालने तथा सरकारी हुन्डिया (Treasury Bills) बेचने में बहुत सहायता की। इस प्रकार १९२१ तक यह प्रेसीडेंसी बैंक सफलतापूर्वक बैंकिंग कार्य करते रहे। १९२१ में, इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई और उसने इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को ले लिया। इस प्रकार वे समाप्त हो गए।

मिश्रित पूंजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) :—

वे सभी बैंक जो कि भारत में इंडियन कंपनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर हुए हैं इस श्रेणी में आते हैं। यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि १८६०

तक भारत में बैंकों का प्राप्ति काल था। सीमित उत्तर-दायित्व (Limited Liability) का सिद्धान्त उस समय तक जो भी बैंक यहाँ स्थापित हुए वे अधीमत दायित्व (Unlimited Liability) के आधार पर थे। केवल 'जनरल बैंक ऑफ इंडिया' को १८८६ में स्थापित हुआ इसका अपवाद था। अधिकांश लोगों का विचार है कि अलबर्ट एड कंपनी एजेंसी यह द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिन्दुस्तान, भारत में सबसे पहला बैंक था किन्तु ऐसी बात नहीं है। भारत में सम्भवतः सबसे पहला बैंक मद्रास सरकार ने १६८८ में स्थापित किया। दूसरा बैंक १७२४ में बम्बई प्रान्त में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ हिन्दुस्तान गारो बैंक था। यह तो हम ऊपर लिख चुके हैं कि १८२६ ई० में एजेंसी रहा। कलकत्ते में यह बैंक संकट में आ गया और उसका उपरान्त १८६० तक जो १२ बैंक स्थापित हुए वे भी बंद हुए। जबकि तीन प्रेसीडेंसी बैंक ही इस काल के बैंकों में सफलता पूर्वक कार्य करते रहे। इस काल के बैंकों का केवल एक ही उल्लेखनीय कार्य हुआ अर्थात् उन्होंने भारत में सर्व प्रथम बाराजी मुद्रा को प्रचलित किया।

भारतीय बैंकिंग के विकास का दूसरा काल १८६० से १९०० तक था। इस काल में परिमित दायित्व (Limited Liability) का सिद्धान्त अपना लिया गया था फिर भी इन ४० वर्षों में बैंकों का विकास बहुत धीरे हुआ। उत्तर प्रदेश अमेरिका के यह युद्ध के चलते स्वरूप बम्बई में जो सट्टे का बाजार गरम हुआ उसमें अवश्य बाध पड़े बैंक स्थापित हुए किन्तु वे ठाम ही बंद हुए और अछे कुछ अनुभव छोड़ते गए। १८७० में भारत में कल हो मिश्रित पूँजी वाला बैंक ये जनकी पूँजी (Capital) और रक्षित कोष (Reserve Fund) पाँच लाख से अधिक था। १९०० तक इस प्रकार के बैंकों की संख्या ६ हो गई। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण बैंक नीचे लिखे थे :—इलाहाबाद बैंक (१८६५), एलाह बैंक ऑफ सिमला (१८७४) जो १९२३ में बंद गया, अवध-कर्मचारी बैंक (१८८१), यह पहला बैंक था जो भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक (१८९४), यह बैंक मुख्यतः लाला हर किशन लाल के प्रयत्नों से स्थापित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम २० वर्षों में बैंकों का विकास शीघ्रता पूर्वक हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों में उनकी डिपॉजिट में ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जब कि विनिमय बैंकों (Exchange Banks) की डिपॉजिट में केवल ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और प्रेसीडेंसी बैंकों की

डिपॉजिट में १३ करोड़ की कमी हुई। परन्तु यदि हम इस समस्त काल (४० वर्षों) पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि बैंकों का विकास बहुत धीमी गति से हुआ और उनकी उन्नति संतोषजनक नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि इस काल में देश की आर्थिक उन्नति नहीं हुई साथ ही वस्तुओं का मूल्य गिरता गया। यही कारण था कि बैंकों की उन्नति की गति बहुत धीमी रही।

तीसरा काल १९०० से १९१३ तक कहा जा सकता है। इसके बाद (१९११-१८) के वर्ष भारतीय बैंकों के लिए बहुत ही संकट के थे। इस काल में भारतीय बैंकों की उन्नति की गति सीमरही और उनके मार्ग में कोई बकावट नहीं आई। इस काल में बैंकों की उन्नति का एक कारण स्वदेशी आन्दोलन भी था। १९०५ के उपरान्त स्वदेशी आन्दोलन की लहर के साथ देश में बहुत से धंधे और उनके साथ ही बैंक भी स्थापित हुए। १९०१ में लाला हरकिशन लाल के प्रयत्नों से पीपुल्स बैंक स्थापित हुआ किन्तु उसके उपरान्त स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव से जो बैंक स्थापित हुए उनमें बैंक आव बर्मा (१९०४) सर्व प्रथम था। इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में कई बैंक स्थापित हुए। इनमें बैंक आव बर्मा के अतिरिक्त बैंक आव इंडिया, बैंक आव मैसूर, बैंक आव बड़ौदा, दक्षिण इंडियन स्पेशल बैंक, तथा सेन्ट्रल बैंक आव इंडिया अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ तो आज 'बड़े पाँच' की श्रेणी में हैं। १९०६ तक भारतीय मिश्रित पूँजी के बैंकों का डिपॉजिट में ११ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जब कि विनिमय बैंकों की डिपॉजिट में १३ करोड़ रुपये और प्रसावेंसी बैंकों की डिपॉजिट में ६ करोड़ की वृद्धि हुई। इस काल में (१९००-१३) उन बैंकों की संख्या जिनका पूँजी और रक्षित कोष (Reserve Fund) पाँच लाख रुपये से अधिक था ६ से बढ़ कर १८ हो गई। इनके अतिरिक्त उस काल में छोटे-छोटे बैंकों की संख्या बहुत अधिक हो गई। बहुत से नये छोटे बैंक स्थापित किये गए।

१९१३-१७ के बीच भारतीय बैंकों को भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट काल में ६५ बैंक डूब गए और उनकी २ करोड़ रुपये की पूँजी डूब गई। डूबने वाले बैंकों में अधिकांश छोटे-छोटे बैंक थे किन्तु आधे दर्जन के लगभग बड़े बैंक भी थे जो डूब गए। इसका भारत के बैंकिंग कार-बार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और जनता का उन पर से विश्वास उठ गया। भारत में यह सबसे बड़ा बैंकिंग संकट था। १८२६-३० में एजेंसी गृहों के

डूबने से १८५७ में १८६४ ई० में अमेरिकन गृह-युद्ध के कारण कपास के सट्टे व कारण जो रैकिंग सकट हुए थे इसके सामने नगण्य थे। १७ मितम्बर १९१३ को पीपुल्स बैंक ने अपना कारबार बन्द किया और फिर स्थिति बिगड़ती ही गई। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बम्बई में विशेष रूप से बहुत सारे बैंक डूबे। अबले १९१३-१७ में १५ बैंक डूब गए यद्यपि इस काल में पीपुल्स बैंक, बैंक ऑफ़ अफ़र इंडिया तथा इंडियन स्पीशी बैंक डूब गये किन्तु अधिकांश डूबने वाले बैंक बहुत छोटे थे। यो भारतवर्ष में व्यक्तिगत निर्बलता के कारण कभी कभी एक दो बैंक डूब जाते हैं किन्तु ऐसा बड़ा सकट कभी भी नहीं आया। इस सम्बन्ध में हमें एक बात न भूल जानी चाहिए कि फ़ैसल भारत के ही बैंक डूबे हो ऐसा नहीं था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि सभी देशों में बैंकों पर सकट आये हैं और वे डूबे हैं। अस्तु इस सकट काल को लेकर जो बहुत से पारचात्य विद्वान् इस बात की चोखाना करते हैं कि भारतीयों में आधुनिक ढंग का बैंक चलाने की योग्यता ही नहीं है गलत है। इन बैंकों के डूबने के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं।

बहुत से बैंक नक़द काश (Cash Reserve) कम रखते थे, बहुत से डूबने वाले बैंकों का प्रबन्ध ख़राब था और उनका ख़ासकई ईमानदार नहीं थे, हिस्सदारों ने कभी बैंकों के प्रबन्ध में दिलचस्पी नहीं ली। वे उसकी ओर से उदासीन रहे। इन बैंकों ने अपने रुपये को लगाने में बैंकिंग सिद्धान्तों की नितान्त अवहेलना की। रुपये की उपयोग में लम्बे समय के लिए अटका दिया। यह बैंक जब अपना लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) निकालते थे तो उस समय दिखे हुए ऋण का वापस मुला कर नक़द कोष को अधिक दिखला देते थे किन्तु वास्तव में उनका नक़द काश बहुत कम होता था। यह बैंक लाभ न होते हुए भी लाभ बाँटते थे। इन बातों से जमा करने वाले धोखे में आ जाते थे। सरकार ने भाँवेंको के इन दोषों को दूर करने का कोई प्रयत्न न किया और न देश में कोई केन्द्रीय बैंक (Central Bank) ही था कि जो बैंकों को बैंकिंग के सिद्धान्तों की अवहेलना करने से रोकता और उनका नियंत्रण करता। इसके अतिरिक्त इन बैंकों में आपस में कोई सहयोग नहीं था वरन् एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे और हानि पहुँचाने का प्रयत्न करते थे। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के डूबने का एक और भी कारण था। अधिकारी डूबने वाले बैंकों की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) बहुत अधिक थी किन्तु उनकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) बहुत कम थी। इस कारण उन्हें ऊँची दर

पर सूद देकर डिपॉजिट आकर्षित करनी पड़ती थी और जब वे अपने ग्राहकों को उनकी डिपॉजिट पर अधिक सूद देते थे तो उन्हें अपने रुपये को जोखिम के कारबार में लगाना पड़ता था क्योंकि तभी उस पर अधिक सूद कमा सकते थे और डिपॉजिटों पर अधिक सूद दे सकते थे। ऊपर लिखे कारणों से हो देश में बैंकिंग संकट उपस्थित हुआ था। इस बैंकिंग संकट का एक अच्छा परिणाम भी हुआ। राज्य तथा जनता सभी को एक केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि जो देश में बैंकिंग कारबार का नियंत्रण कर सके और साथ ही इस बात की भी आवश्यकता का अनुभव हुआ कि एक बैंकिंग ऐक्ट बनाया जावे जिससे बैंक सुव्यस्थित और अच्छे ढंग से चल सकें। रिज़र्व बैंक की स्थापना से पहली कमी दूर हो गई और बैंकिंग कानून बनाने से दूसरी कमी दूर हो जावेगी। यही नहीं, मिश्रित पूंजी वाले बैंकों को भी अनुभव ने यह बतला दिया कि आरम्भ में जबकि बैंकों की किसी देश में स्थापना हो तो अधिक द्रव्य कोष (Cash Reserve) रखने की जरूरत है। तब से भारतीय व्यापारिक बैंक सतर्क हो गए और अधिक नकद कोष रखने लगे।

यद्यपि भारतीय बैंकिंग व्यवसाय को १९१३ के संकट से धक्का लगा किन्तु युद्ध के कारण उनकी अवनति और पतन अधिक नहीं हुआ। १९१४ से १९२० तक युद्ध काल में तथा १९२१ की आर्थिक तेज़ी (Boom) में इन बैंकों की संख्या तथा उनकी डिपॉजिट दोनों में ही वृद्धि हुई। १९१८ में ताता औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई तथा अन्य बैंक भी स्थापित हुये किन्तु १९२० से आर्थिक मंदी (Depression) तथा मुद्रा संकोचन (Deflation) दोनों ही आरम्भ हुए और बैंकों को फिर संकट का सामना करना पड़ा। यह आर्थिक संकट १९२४ तक रहा। बैंकों की कुल डिपॉजिट १९२१ में ८० करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, गिरने लगी और १९२४ में केवल ५५ करोड़ रह गई। यद्यपि संकट उतना तीव्र नहीं था फिर भी कुछ बैंक बूब गए। १९१९ से १९२५ के बीच में ८४ बैंक बूब गए जिसमें ४ करोड़ ८० लाख रुपये की पूंजी की हानि हुई। १९२३ सबसे बुरा वर्ष था उस एक वर्ष में २० बैंक जिनकी चुकता पूंजी (Paid up Capital) चार करोड़ ६५ लाख रुपये थी बूब गए। १९२३ में बूबने वाले बैंकों में ताता औद्योगिक बैंक तथा एलाइंस बैंक आव शिमला मुख्य थे। अन्त में ताता औद्योगिक बैंक को सेंट्रल बैंक आव इंडिया ने ले लिया।

१९२३ २४ की आर्थिक मंदी (Depression) के उपरान्त भारत में व्यापारिक बैंकों के इतिहास को तीन कालों में बांटा जा सकता है। पहला काल १९२४ २५ से १९३० तक का है। यद्यपि इस काल में बैंकों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु उन्नति सतोषजनक नहीं हुई। डिपॉजिट १९२१ से (अर्थात् ८० करोड़) बहुत कम रही। १९३० में कुल डिपॉजिट ६८ करोड़ रुपये थी। इस सुधार के घटनात् १९३१ में फिर बैंक डिपॉजिट २ करोड़ कम हो गई और बैंकों की थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ा फिर १९३२ से १९३७ तक दूसरा काल माना जा सकता है। इस काल में बैंकों की स्थिति में पहले की अपेक्षा सेजी से सुधार हुआ। १९३७ में बैंकों की डिपॉजिट बढ़ कर १०८ करोड़ रुपये हो गई। इस काल के उपरान्त १९३८ में फिर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और बैंकों की कुल डिपॉजिट २ करोड़ रुपये घट गई यद्यपि छोटे बैंकों की डिपॉजिट में वृद्धि हुई। इस काल में छोटे-छोटे बैंक बूबे किन्तु ट्रांबंको नेशनल एण्ड मिलन बैंक, बनारस बैंक तथा नगाल नेशनल बैंक उल्लेखनीय हैं। इसके उपरान्त १९३९ के उपरान्त आश्चर्यजनक तेज़ी से बैंकों की संख्या तथा डिपॉजिट में वृद्धि हुई।

नये बैंकों में नीचे लिखे बैंक उल्लेखनीय हैं : भारत बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जयपुर बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ ब्रोकरानेर, जोधपुर बैंक, हरीश बैंक, एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया एण्ड अफ्रीका, हिन्दू बैंक, डिस्काउंट बैंक ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान मर्कैंटाइल बैंक, नेशनल मेबैंक बैंक। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से बैंक स्थापित हुए। यही नहीं कि इस काल में सैकड़ों छोटे बड़े बैंक स्थापित हुए और उन्होंने अपनी शालायें तेज़ी से स्थापित करना आरम्भ कर दिया वरन् पुराने बैंकों ने भी अपनी पूंजी बढ़ाई तथा अपने कारबार के क्षेत्र का विस्तार किया और प्राचीन की वृद्धि करना आरम्भ कर दिया। श्री सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा भारत बैंक की स्थापना होते ही प्रत्येक बड़े व्यवसायी ने अपना अपना बैंक स्थापित करना आरम्भ कर दिया और देश में बैंकों की एक बाढ़ भी आ गई। इनमें छोटे छोटे बैंकों की संख्या ही अधिक थी। जहाँ १९३९ में देश में केवल ५५ सिट्टल बैंक थे वहाँ जून १९४६ में ६६ सिट्टल बैंक हो गये और जहाँ १९३८ में १२७८ ब्रांचें थी वहाँ जून १९४६ में उनकी संख्या ३०६३ हो गई। बैंकों की डिपॉजिट में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। जनवरी १९४१ में बैंकों की कुल डिपॉजिट ८७५ करोड़ हो गई, जनवरी १९४७ में सिट्टल

बैंकों की डिपॉजिट ६५० करोड़ के लगभग हो गई और जनवरी १९४८ में ७२६, ७३७०, ००० रु० थी। २७ दिसम्बर १९४७ को गैर शिड्डल बैंकों की डिपॉजिट ७८,४४,३२,००० रु० थी।

युद्ध काल और उसके उपरान्त बैंकों की यह वाढ़ मुद्राप्रसार (Inflation) का परिणाम थी। सरकार के आदेश पर रिज़र्व बैंक ने जो तेजी से कागजी मुद्रा छापनी आरम्भ कर दी उसके ही परिणाम स्वरूप बैंकों की वाढ़ आ गई और डिपॉजिटों में वृद्धि हुई। परन्तु बहुत से बैंकों ने बिना यह समझे कि उनके पास यथेष्ट योग्य और कुशल कर्मचारी हैं ब्रांच खोलना आरम्भ कर दीं। ब्रांचों के खोलने में उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रक्खा कि कहाँ ब्रांच खोलना लाभदायक होगा और कहाँ ब्रांच खोलना लाभदायक नहीं होगा। बहुत से बैंकों की पूंजी बहुत ही कम थी किन्तु उन्होंने भी बहुत सी ब्रांचें स्थापित कर दीं इस का परिणाम यह हुआ कि १९४६-४७ में बहुत से छोटे-छोटे बैंक जो कि शिड्डल बैंक नहीं थे (विशेषकर बंगाल के) डूब गए। १५ अगस्त १९४७ के उपरान्त जो भारत में पंजाब में भीषण लूट-पाट और नर संहार हुआ उसमें भी पंजाब के बैंकों की बहुत बड़ी हानि हुई। * बैंकों के बहुत अधिक हो जाने के कारण कहीं-कहीं बहुत अनुचित प्रतिस्पर्धा दिखलाई पड़ती है। भविष्य में बहुत से छोटे-छोटे बैंकों को बड़े बैंकों से मिल जाना होगा नहीं तो वे खड़े नहीं रह सकते। फिर भी यह बात उल्लेखनीय है कि इस बीच कोई शिड्डल बैंक नहीं डूबा। यद्यपि लड़ाई के उपरान्त अभी तक आर्थिक मंदी (Depression) का भारतीय बैंकों को सामना नहीं करना पड़ा है फिर भी यह कहा जा सकता है कि रिज़र्व बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंक उन्नति कर रहे हैं और शिड्डल बैंकों की स्थिति अच्छी है।

मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के कार्य :—अब हम मिश्रित पूंजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) के कार्यों का विवेचन करेंगे। यह तो हम

*पंजाब में जो बैंकों की अपार हानि हुई है उसका ठोक-ठोक अनुमान लगाना इस समय कठिन है क्योंकि अभी तो वे बैंक भी नहीं जान सके हैं कि उनकी कितनी हानि हुई है। इस हानि का उन बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह कहना भी कठिन है फिर भी यह तो निश्चित है कि बड़े बैंक इस हानि को सहन कर लेंगे।

पहले ही कह चुके हैं कि मिश्रित पूँजी वाले बैंक व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) होते हैं और वे उन सभी कार्यों को करते हैं जो कि व्यापारिक बैंक करते हैं। इन बैंकों का मुख्य कार्य चालू (Current), मुहती (Fixed) और सेविंग्स डिपॉजिट आकर्षित करना तथा थोड़े समय के लिए ऋण देना है, विलों को भुनाना या खरीदना, (यद्यपि भारतीय बैंक यह कार्य कम करते हैं क्योंकि यहाँ बिल बाज़ार का उदय नहीं हुआ है) सरकारी सिक्कूरिटियों (प्रतिभूति) में अपना रुपया लगाना, नकद साख (Cash Credit) देना, खेती की पैदावार को गाँव से नियत बन्दरगाहों तक और बन्दरगाहों से विदेशों में आए हुए माल को देश के भीतरी बाजारों तक पहुँचाने में आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त यह बैंक और भी छोटे मोटे कार्य करते हैं, उदाहरण के लिये रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना इत्यादि।

यह बैंक कृषि के धंधे को सीधी आर्थिक सहायता नहीं देते। वे केवल बड़े जमीनदारों काय इत्यादि के बागीचों के मालिकों तथा ऐसे व्यक्तियों को ही ऋण देते हैं जो कि बाज़ार में शीघ्र बिक सकने योग्य जमानत (Security) देते हैं। पहले तो यह बैंक मुहती जमा (Fixed Deposits) पर ४ से ५ प्रतिशत वार्षिक सूद देते थे और चालू खाते (Current Account) पर १ से २ प्रतिशत सूद देते थे किन्तु अब अधिकांश बैंक चालू खाते पर कुछ भी सूद नहीं देते और मुहती जमा पर भी २ प्रतिशत से अधिक सूद नहीं देते।

बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्टॉक बाज़ार की सिक्कूरिटि अधिक मिलती है वहाँ यह बैंक उनकी जमानत पर ऋण देते हैं। किन्तु जिन मंडियों तथा बाज़ारों में स्टॉक बाज़ार की सिक्कूरिटि अधिक नहीं मिलती वहाँ खेती की पैदावार को रख कर यह बैंक ऋण दे देते हैं। भारत-वर्ष में सार्वजनिक गोदाम नहीं हैं इस कारण बैंक अपने गोदाम रखते हैं जहाँ ग्राहक का माल रख कर उसकी जमानत पर उसे ऋण दे दिया जाता है। देता भी होता है कि बैंक ग्राहक के गोदाम पर ही अधिकार कर लेते हैं और वहाँ माल बन्द करके ग्राहक को ऋण दे देते हैं। वे सोना चांदी, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं को रखकर भी ग्राहकों को ऋण दे देते हैं। कारखानों को उनके तैयार माल के निरुद्ध तथा अन्य सिक्कूरिटियों के निरुद्ध ऋण देते हैं। कभी-कभी बैंक हमारतों तथा अन्य स्थावा सम्पत्ति को गिरवी रखकर कर्ज दे देते हैं किन्तु इस प्रकार का कर्ज अधिक नहीं दिया जाता। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति शीघ्र ही बेची नहीं जा सकती।

बैंक व्यक्तिगत ज़मानत पर भी कर्ज़ दे देते हैं। ऐसी दशा में कर्ज़दार जो प्रामिसरी नोट लिखता है उस पर दो अच्छे हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं सराफ़ तथा मैनेजिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होने पर बैंक आसानी से कर्ज़ दे देते हैं। हुंदी जो कि आज भी भारतीय बाज़ारों में प्रचलित है यद्यपि पहले से उसका प्रचार कम है वास्तव में दो हस्ताक्षरों वाला पत्र है क्योंकि उस पर देशी बैंकों का वेचान (Endorsement) होता है। किन्तु व्यापार की मात्रा को देखते हुए तथा व्यापारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए जितने दो हस्ताक्षर वाले पत्रों को यह बैंक स्वीकार करके व्यापारियों को कर्ज़ या साख़ देते हैं वे अपेक्षाकृत कम ही होते हैं।

कर्ज़ देने का सबसे अधिक प्रचलित ढंग यह है कि कर्ज़दार बैंक को प्रामिसरी नोट लिख देता है और कंपनियों के हिस्से, माल या ग्रांड अथवा अन्य कोई सिक्यूरिटी बैंक के पास ज़मानत के रूप में रख देता है और बैंक उस कर्ज़दार के नाम नक़द साख़ खाता (Cash Credit Account) खोल देता है। यह ढंग दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक है। कर्ज़दार जितना रुपया वास्तव में निकालता है उस पर ही उसे सूद देना पड़ता है फिर नसे यह भी सुविधा रहती है कि वह जब भी चाहे तो उस खाते में रुपया जमा करदे अर्थात् कुछ कर्ज़ झुका दे। किन्तु कर्ज़दार को जितनी नक़द साख़ दी गई है उसकी आधी रक़म पर अवश्य सूद देना होगा। कर्ज़ देने का यह ढंग भारत में थिल बाज़ार को विकसित नहीं होने देता किन्तु यह अधिक प्रचलित है क्योंकि बैंक और व्यापारी दोनों ही इसे पसंद करते हैं। बैंक को सुविधा यह है कि वह जब चाहे तो नक़द साख़ (Cash Credit) की इस सुविधा को वापस ले सकता है अर्थात् कर्ज़दार को अधिक कर्ज़ या साख़ देना अस्वीकार कर सकता है और कर्ज़ लेने वाले को यह सुविधा होती है कि उसे निश्चित रक़म पर ही सूद देना पड़ता है पूरी रक़म पर सूद नहीं देना पड़ना।

यह बैंक अधिकतर देश के भीतरी व्यापार के लिए अल्पकालीन साख़ (Short Term Credit) का प्रबंध करते हैं। विदेशी व्यापार, उद्योग-धन्धों तथा कृषि को यह बहुत कम साख़ देते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ बड़े बैंकों ने विदेशी निजिमय (Foreign Exchange) का कारबार करना आरम्भ किया है परन्तु अभी तक वह नहीं के बराबर है। उद्योग-धन्धों को यह बैंक थोड़े समय के लिये नक़द साख़ के रूप में या कर्ज़ के रूप में सहायता देते हैं। अधिक समय के लिये स्थायी पूँजी

(Block Capital) के रूप में यह बैंक उद्योग-वन्धों को सहायता नहीं देते ।

भारतीय व्यापारिक बैंकों की कार्यनद्धति की एक विशेषता यह है कि वे विलों की अपेक्षा सरकारी सिक्कुरीटियों में अपना रुपया अधिक लगाते हैं । इसका कारण यह है कि देश में व्यापारी विलों तथा बैंक के स्वीकार योग्य पत्रों (Papers) की कमी या अभाव है । अस्तु बैंक अपना अधिकतर रुपया सरकारी सिक्कुरीटियों में लगाते हैं ।

इनके अतिरिक्त भारतीय बैंक और भी सहायक बैंकिंग कार्य करते हैं । उदाहरण के लिये वे अपने ग्राहकों को अर्थ सम्बन्धी सलाह देते हैं, उन्हें व्यापार सम्बन्धी जानकारी कराते हैं, अपने ग्राहकों के लिए सरकारी सिक्कुरीटी तथा कपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं अपने ग्राहकों के एवज में हस्ताचक्राते हैं और वसूल करते हैं, अपने ग्राहकों के एजेंट या प्रतिनिधि का काम करते हैं । इन कार्यों के अतिरिक्त वे यात्रियों की सुविधा के लिए साक्ष-पत्र (Letter of Credit) देते हैं, रुपये को दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बैंक ड्राफ्ट देते हैं तथा सरकार, कम्पनियों तथा म्यूनिस्पैलिटीयों तथा कारपोरेशनों द्वारा निकाले हुए ऋण का अभिगोचन (Underwriting) करते हैं । वे अपने ग्राहकों की साम्प्रदायिक स्थिति तथा प्रगति के सम्बन्ध में अन्य व्यापारियों को अपना मत देते हैं । वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान् वस्तुओं की सुरक्षित रूप से रखते हैं ।

मविध्य में भारतीय बैंक को अति अधिक विदेशी व्यापार को और ध्यान देना होगा । भारतीय बैंकों ने 'ट्रस्ट' का कारबार भी करना आरम्भ नहीं किया है और ग्राहकों के लिए शेयरों की खरीद बिक्री का भी काम बहुत कम करते हैं । मविध्य में उन्हें इस ओर अधिक ध्यान देना होगा ।

भारतीय व्यापारिक बैंकों के दोष तथा उनकी कठिनाइयाँ :—

(१) भारतीय बैंकों को अभी तक सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला । म्यूनिस्पैलिटिया, विश्वविद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोर्ट आब चाड्स ट्रस्टों इत्यादि का रुपया उनमें नहीं रक्खा जाता । यद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है । १९३५ के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय बैंक न होने के कारण उन्हें कठिनाई के समय टोक नेतृत्व तथा सहायता नहीं मिलती थी और न उनमें आपस में सहयोग ही स्थापित हो पाता था । किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना से अब यह कठिनाई दूर हो गई है ।

(२) विदेशी विनिमय बैंकों (Exchange Banks) तथा इम्पीरियल बैंक की प्रतिस्पर्धा तथा आपसी सहयोग और सहानुभूति का अभाव भी उनकी उन्नति के मार्ग में एक रुकावट है। उनका यह भी विचार है कि भविष्य में सहकारी बैंक (Co-operative Banks) भी उनसे होड़ करेंगे। जहाँ तक इन बैंकों की एक्सचेंज बैंकों तथा इम्पीरियल बैंकों से प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है हम उन बैंकों से सम्बन्धित अध्यायों में लिख चुके हैं। और जहाँ तक उनमें आपस में तथा द्रव्य बाज़ार (Money Market) के अन्य सदस्यों में सहयोग तथा सहभावना उत्पन्न करने का प्रश्न है उसके लिए अखिल भारतीय बैंकर्स एसोशियेशन की स्थापना की आवश्यकता है।

(३) अभी तक बहुत से भारतीय धंधे तथा भारतीय व्यापार विदेशियों के हाथ में हैं और वे स्वभावतः अपने देश के बैंकों को पोसाहन देते हैं इस कारण भी भारतीय बैंकों की उन्नति तेज़ी से नहीं हुई। किन्तु अब भारत स्वतंत्र हो गया है और यह कठिनाई अब कमशः दूर हो जावेगी।

(४) यही नहीं कि विदेशी व्यवसायी तथा विदेशी व्यापारी फर्मों अपने देश के बैंकों से अपना कारबार करती हैं वरन् जो भारतीय व्यापारी इनके ब्रोकर या एजेंट का काम करते हैं अथवा जिनका विदेशी शीमा कंपनियों तथा विदेशी जहाज़ी कंपनियों से कारबार होता है उनको भी यह विदेशी फर्मों और कंपनियों विदेशी विनिमय बैंकों से कारबार पर विवश करते हैं।

(५) पिछले बैंक संकटों के कारण जो बैंक डूब गए उनसे बैंकों की स्थापना में कठिनाई होती थी लोग, बैंकों में हिस्से नहीं लेते थे और उनमें संचय जमा करने से हिचकते थे किन्तु अब यह कठिनाई दूर हो गई है। पिछले वर्षों में बैंकों की संख्या तथा डिपॉज़िट में ज़ेमी तेज़ी से बढ़ि हुई है उसे देखते यह कहना पड़ेगा कि बैंकों के विरुद्ध अब अविश्वास जाता रहा है।

(६) भारत की आर्थिक उन्नति न होने के कारण भी भारतीय बैंकों की उन्नति रुकी रही। अस्तु भारत की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ भारत में बैंकिंग कारबार का विकास होना तथा जनता में बैंकिंग की आदत बढ़ाना अनिवार्य है। अभी तक जनता में बैंकिंग की आदत कम है।

(७) इनके अतिरिक्त बैंकों को कुछ अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हिन्दू तथा मुसलमानों के पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून इतने उलझे हुए हैं कि इस प्रकार की सम्पत्ति की

जमानत पर श्रृणु देना बैंकों के लिए रानरे में खाली नहीं है अस्तु बैंक उस सम्पत्ति की जमानत पर श्रृणु देने से हिचकते हैं।

थोड़े समय के लिए श्रृणु देने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि व्यापारी अपना सम्पत्ति के प्रलेख (Documents) बैंक के पास बिना बंधक पत्र (Mortgage Deeds) लिखे और उनकी रजिस्ट्री कराये रख दें और उन प्रलेखों (Documents) का बैंकों के पास जमा कर देना ही बंधक मान लिया जावे किन्तु भारत में यह सुविधा केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कराँचा नगरों में ही है। अन्य स्थानों में यह सुविधा बैंकों को प्राप्त नहीं है।

(८) व्यापारिक बैंक इस भाषा से सरकारी निस्सुरीटियों में अपना रुपया लगाते हैं कि सकल काल में सरकारी निस्सुरीटियाँ शांति ही नकदी में परिणत की जा सकती हैं किन्तु कभी कभी उसमें कठिनाई पड़ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ कि बैंक इम्पेरियल बैंक से सरकारी निस्सुरीटियों की जमानत पर श्रृणु प्राप्त न कर सके। अभी हाल में रिजर्व बैंक ने भी इसी आशय को घोषणा की है कि यदि किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकार निस्सुरीटियों के आधार पर उन्हें श्रृणु दे ही दिया जावेगा।

(९) भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बैंक हैं कि जिनके पास अपनी निज की संश्लेष पूँजी नहीं है इस कारण उन्हें बहुत कठिनाई पड़ती है। वे डिपॉजिट अधिक आकर्षित करने के लिए सूद अधिक देते हैं और इस कारण उन्हें अपना रुपया आखिरी के कारण में लगाना पड़ता है तभी वे अधिक सूद कमा सकते हैं। डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए यह छोटे-छोटे बैंक दूर दूर अन्य प्रान्तों में शाखें स्थापित करते हैं इस कारण उनकी देख भाल और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और उन्हें बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार के बैंक स्वभावतः निर्बल होते हैं और सकल के समय वे नहीं टहर सकते।

(१०) इसके अतिरिक्त बहुत से बैंकों के डायरेक्टर योग्य और अनुभवी नहीं हैं और योग्य बैंकिंग कर्मचारियों की कमी है। यही नहीं नये बैंकों को समाशोधन गृह अर्थात् क्लियरिंग हाउस (Clearing House) का सदस्य बनने में बड़ा कठिनाई होती है। क्लियरिंग हाउस पर विदेशी बैंकों का बहुत

प्रभाव है और वे नये बैंकों को उसका सदस्य नहीं बनने देना चाहते। किन्तु अब क्रमशः यह कठिनाई दूर हो जावेगी।

(११) भारत के सभी बैंक अंग्रेज़ी में अपना कारबार करते हैं। उनके चेक, रसीदें, तथा हिसाब सभी अंग्रेज़ी में होता है। केवल कुछ ही बैंक ऐसे हैं कि जो हिन्दी में लिखे गए चेकों को तथा हिन्दी में किये गए हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हैं। भारत में व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत भाग अंग्रेज़ी नहीं जानता। भारतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अंग्रेज़ी का महत्त्व अब घटने जा रहा है अतएव अब बैंकों को अपना कारबार हिन्दी में अथवा प्रांतीय भाषा में करना चाहिए।

(१२) भारतीय बैंकों के सामने एक यह भी कठिनाई है कि यहाँ विलों तथा ऐसे पत्रों (Papers) की बहुत कमी है जिन्हें बैंक स्वीकार कर सकें। इस कारण बैंकों का विवश होकर अपना अधिकांश कोष सरकारी सिम्पूरटियों में लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत में बिना किसी सम्पत्ति की जमानत पर अथवा दूसरे हस्ताक्षर लिए हुए व्यांक्तगत साख पर ऋण देने का परिपाटी नहीं है जब कि अन्य देशों में यह बहुत प्रचलित है और अधिकांश ऋण इसी प्रकार दिये जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पश्चिमाय देशों में 'एक व्यक्ति एक बैंक' का चलन है अर्थात् एक व्यक्ति अपना सारा कारबार केवल एक बैंक से ही करता है। दूसरा कारण मैनेजिंग एजेंट हैं। बैंक जब किसी कंपनी को ऋण देते हैं तो वे कंपनी के डायरेक्टर के अतिरिक्त मैनेजिंग एजेंट के हस्ताक्षर अवश्य लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कंपनी के वास्तविक कर्त्ता-धर्त्ता तो मैनेजिंग एजेंट ही हैं। एक तीसरा कारण यह भी है कि अभी तक इस देश में ऐसी व्यापारिक एजेंसियां नहीं हैं जो व्यक्तियों को साख के सम्बन्ध में बैंकों को सारी जानकारी दे सकें।

(१३) भारतीय बैंकों ने अभी तक भारतवर्ष की परिस्थिति के अनुसार अपने संगठन को नहीं बनाया। वे ऐक्सचेंज बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक की नकल मात्र करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रबन्ध व्यय अधिक होता है फिर भी उनके कर्मचारियों में न तो वह कुशलता है और न वह योग्यता। भारतीय बैंकों ने न तो विदेशी ऐक्सचेंज बैंकों की कुशलता ही प्राप्त की और न देशी बैंकों की सादगी और मितव्ययिता ही व अपना सके। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंक भारत के अनुकूल बैंकिंग संगठन

की नवीन पद्धति निकालें जो कि कम खर्चीली हो । क्योंकि भारत में ऐसे स्थान बहुत हैं । कहीं इतना कारबार आरम्भ में तो नहीं मिल सकता कि एक आधुनिक गाँव का खर्च निकल सके परन्तु फिर भी वहाँ बैंकिंग की सुविधा की आवश्यकता है ।

(१४) बहुधा लोग भारतीय बैंकों पर यह दोष लगाते हैं कि वे अपने वास्तविक लाभ का बहुत बड़ा अंश हिस्सेदारों को इस लिये बाँट देते हैं कि जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास बना रहे । क्योंकि भारतीय जनता की यह धारणा है कि जो बैंक अधिक लाभ बाँटता है वह उतना ही अच्छा है । जहाँ तक यह और पुराने बैंकों का प्रश्न है यह आरोप निराधार है किन्तु छोटे बैंक यह करते हैं और इसका मुख्य कारण भारतीय जनता की यह भ्रमपूर्ण धारणा है ।

अब परिस्थिति बदल गई है । यद्यपि भारत के विभाजन से पाकिस्तान में जिन बैंकों की अधिक ज़ाब थी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी है परन्तु फिर भी बैंकों का तेज़ी से विस्तार हुआ है और बड़े बैंक उन क्षेत्रों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

बैंकों का वर्गीकरण:—भारतवर्ष में बैंकों का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है । एक वर्गीकरण सम्पत्ति के आधार पर है और दूसरा रिज़र्व बैंक का है । भारत सरकार को बैंक सम्बन्धी आँकड़े छापती है उसमें दो प्रकार के बैंकों का उल्लेख होता है (१) पहली श्रेणी तो उन बैंकों की होती है कि जिसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) तथा रक्षित कोष Reserve Fund) पाँच लाख रुपये से अधिक है दूसरी श्रेणी उन बैंकों की है जिनकी चुकता पूँजी और रक्षित कोष १ लाख रुपये से अधिक है और पाँच लाख रुपये से कम है । १९३६ के उपरान्त बैंकिंग सम्बन्धी आँकड़े रिज़र्व बैंक छापने लगा है तब से दो अन्य श्रेणियाँ और जोड़ दी गई हैं । तिसरी श्रेणी के बैंक वह हैं जिनकी चुकता पूँजी और रक्षित कोष ५० हजार रुपये से अधिक तथा १ लाख से कम है और चौथी श्रेणी में वे बैंक आते हैं जिनकी पूँजी तथा रक्षित कोष ५० हजार रुपये से कम है ।

रिज़र्व बैंक बैंकों को दो श्रेणियों में बाँटता है :—(१) शिड्यूल बैंक (Schedule Banks) और गैर शिड्यूल बैंक (Non-Schedule Banks) । जिस बैंक का चुकता पूँजी और रक्षित कोष ५ लाख रुपये से

अधिक हो तथा वह कुछ अन्य शर्तें पूरी करे तो वह शिड्यूल बैंक बन सकता है। किन्तु सभी इस प्रकार के बैंक शिड्यूल बैंक नहीं बन गए हैं।

भारतवर्ष में पहली श्रेणी के बैंकों की संख्या १५७ है और दूसरी श्रेणी के बैंकों की संख्या ६४० है। इनमें शिड्यूल बैंकों की संख्या केवल ६१ है और ऐसे बैंकों की संख्या कि जिनकी चुकता पूंजी तथा रक्षित कोष ५ लाख से अधिक है ६६ हैं।

भारतवर्ष में इंग्लैंड के आधार पर बैंकिंग विषय पर लिखने वाले पाँच प्रमुख बैंकों को 'बड़े पाँच' के नाम से पुकारते हैं यद्यपि भारत के बड़े पाँच तथा ब्रिटेन के बड़े पाँच में कोई समानता नहीं है परन्तु फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार का विभाजन किया जाता है। यह 'बड़े पाँच' नीचे लिखे हैं (१) बैंक ऑफ इंडिया, (२) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (३) इलाहाबाद बैंक, (४) पंजाब नेशनल बैंक, (५) बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें इलाहाबाद बैंक तो विदेशी बैंक है और शेष चार भारतीय बैंक हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ इंडिया के साधन बहुत अधिक हैं वे 'दो बड़े' कहलाये जा सकते हैं।

नये बैंक जो कि १९४१ के उपरान्त स्थापित हुए उनमें नीचे लिखे 'बड़े पाँच' हैं (१) भारत बैंक, (२) यूनायटेड कमर्शियल बैंक, (३) इन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, (४) जयपुर बैंक तथा (५) हबीब बैंक।

अध्याय—१६

विनिमय बैंक या एक्सचेंज बैंक (Exchange Banks)

एक्सचेंज बैंक वास्तव में व्यापारिक बैंक हैं किन्तु उनमें तथा भारतीय मिश्रित पूंजी वाले व्यापारिक बैंकों (Indian Joint Stock Banks) में केवल इतना ही अन्तर है कि एक्सचेंज बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं और उनकी शाखाएँ भारतीय बंदरगाहों और मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में हैं तथा वे मुख्यतः विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता और विनिमय (Exchange) की सुविधा प्रदान करते हैं। वास्तव में भारतवर्ष के बैंकिंग संगठन की एक विशिष्ट विशेषता है कि थोड़े से विदेशी बैंकों के एक समूह ने भारत के विदेशी व्यापार पर अपना एकाधिपत्य जमा लिया है। भारतीय व्यापारिक बैंकों का अभी तक इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं हो पाया है। बात यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में अधिकतर भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन से होता था। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि लंदन में ऐसे बैंक स्थापित हो कि जो कि दोनों देशों में विनिमय (Exchange) का काम करें। किन्तु आरम्भ में तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एजेंसी हाऊस जो भारत में व्यापार तथा बैंकिंग का कारबार करते थे इसके विरुद्ध थे कि इस प्रकार के बैंक स्थापित हों। किन्तु १८५३ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार के बैंकों की स्थापना का विरोध करना छोड़ दिया और एजेंसी हाऊसों के समक्ष ही आने से उस प्रकार के बैंकों की स्थापना और भी आवश्यक हो गई।

१८५३ के पूर्व केवल ओरियंटल बैंक विनिमय (Exchange) का काम करता था किन्तु १८५३ में चारटर्ड बैंक ऑफ इंडिया, आस्ट्रेलिया और चीन तथा मरकैंटाइल बैंक इंग्लैंड में स्थापित हुए। १८८५ में ओरियंटल बैंक फेल हो गया। १८८३ में नेशनल बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता बैंकिंग कारपोरेशन के नाम से स्थापित हुआ किन्तु बाद को इसका नाम बदल दिया गया और इसका प्रधान कार्यालय लंदन ले आया गया। इसके उपरान्त फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोर्तुगाल, रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने भी इसी नीति को अपनाया और भारत तथा अन्य एशियाई राष्ट्रों से अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से

अपने बैंकों की शाखाएँ भारतीय वन्दरगाहों में स्थापित कर दी। शीघ्र ही इंग्लैंड के तीन अन्य बैंकों ने भी अपनी शाखाएँ यहां स्थापित कर दीं (लायड, नेशनल प्रोविशियल तथा बामस)। १९१४ में जब प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ जर्मन बैंक (Deutsch Asiatische Bank) तथा रूसी एशियाटिक बैंक की भारतीय शाखाएँ बंद हो गईं और फिर नहीं खुलीं। १९४१ में जब जापान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ तो तीन जापानी बैंकों की शाखाएँ (याकोहामा स्पोडी बैंक, मित्सुई बैंक, तथा तैवान बैंक) बंद हो गईं।

एक्सचेंज बैंकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। एक तो वे बैंक जिनका अधिक कारबार भारत से होता है अर्थात् उनकी डिपॉजिट का २५ प्रतिशत से अधिक भारत में है। दूसरी श्रेणी में वे बैंक आते हैं कि जो बहुत बड़े बैंक हैं और जिनका कारबार अन्य देशों में अधिक फैला हुआ है अर्थात् भारत में उनकी कुल डिपॉजिट का २५ प्रतिशत से कम है। किन्तु यह श्रेणी विभाजन बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि दूसरी श्रेणी के बैंक लायड बैंक, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन तथा अमेरिका का न्यू-यॉर्क बैंक बहुत बड़े बैंक हैं और यद्यपि भारत में उनकी डिपॉजिट उनकी कुल डिपॉजिट की २५ प्रतिशत से कम हैं परन्तु उनको भारतीय डिपॉजिट पहली श्रेणी के बैंकों की डिपॉजिट से नहीं अधिक हैं। १९३९ तक प्रथम श्रेणी में ६ बैंक थे किन्तु १९३९ में चार्टर्ड बैंक ने पी० एच० बैंकिंग कारपोरेशन को खरीद लिया अस्तु अब पहली श्रेणी में केवल पांच बैंक हैं। और १५ बैंक दूसरी श्रेणी में हैं (इनमें जापान के १ बैंक का युद्ध काल में कारबार बंद हो गया)।

नीचे हम मुख्य एक्सचेंज बैंकों की तालिका देते हैं :—

स्थापित होने का वर्ष	नाम	प्रधान कार्यालय
प्रथम श्रेणी १८५३	चार्टर्ड बैंक आफ इंडिया आस्ट्रेलिया और चीन—	लंदन
के बैंक १९०९	इस्टर्न बैंक लिमिटेड	—लंदन
१८५८	मर्कैंटाइल बैंक आव इंडिया—	लंदन
१८६६	नेशनल बैंक आव इंडिया—	लंदन
फा०—१६		

दूसरी श्रेणी १८६६ धामस कुक एण्ड सभ (बैंकर)—सदन
क बैंक

(वह अधिकतर यात्रियों का

कारबार करती है)

लायड बैंक (जिन्होंने क्रिग और

कान्थ का कारबार ले लिया)—सदन

मिडले एण्ड कंपनी

(जिसे नेशनल प्राविशियल बैंक

निश्चित करता है) —सदन

निदर्लैंड ट्रेडिंग सोसायटी —एम्बरडम

निदर्लैंड्स इंडियन

कमर्शियल बैंक —एम्बरडम

होमकांथ रायाई बैंक

कारपारेसन —रामबाग

नेशनल सिटी बैंक आब न्यू यार्क—न्यू यार्क

अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी —न्यू-यार्क

(यह यात्रियों का कारबार करती है)

काम्पटोर नेशनल डी ऐस्काप्टो डी पेरिस—पेरिस

बैंको नेशनल अस्ट्रामैरिनो —लिस्वन

१८५१ के उपरान्त

जापानी बैंकों ने

कारबार बढ़ कर दिया

बाकोहामा स्टीवी बैंक —बाकोहामा

बैंक आब तेशान —तेपेह

मिस्तुई बैंक —टोकियो

बैंक आब चाइना

नाम यह थी कि भारत का व्यापार बढ़ता जा रहा था, बैंकिंग ने अधिक लाभ या और उसी लाभ के लालच से उन देशों के प्रमुख बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित कर दीं कि जिनका भारत से व्यापार होता था। केवल इटली और बेलजियम ही ऐसे देश हैं कि जिनका भारत के साथ बड़े व्यापार होता है किन्तु उनके किसी बैंक ने भारत में अपना कारबार स्थापित नहीं किया।

एकस्वैज बैंक भारत के अत्यन्त प्राचीन बैंक है। जब कि आधुनिक ढंग के मिश्रित ढ़ाँची वाले व्यापारिक बैंकों की भारत में स्थापना भी नहीं हुई थी तब से ही वे भारत में अपना कारबार करते आये हैं। चारटर्ड नेशनल, और भरकै स्टारल तो १८७० के पूर्व ही काम करते थे। वास्तव में भारतीय व्यापारिक

बैंकों का प्रादुर्भाव तो उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में और बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ ।

अतएव 'एक्सचेंज बैंकों' का देश के व्यापार में प्रधान हाथ रहा तो उसमें आश्चर्य ही क्या है । नीचे हम एक्सचेंज बैंकों की तथा भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की भारत में जो डिपॉजिट थी उनकी तालिका देते हैं उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि एक्सचेंज बैंकों का यहां कितना अधिक प्रभाव है ।

वर्ष	एक्सचेंज बैंकों की डिपॉजिट	मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की डिपॉजिट	मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की डिपॉजिट
		'अ' श्रेणी	'ब' श्रेणी
१८७०	५२ लाख रु०	१४ लाख रु०	
१८८०	७५३ " "	२१० " "	
१८९०	१०५० " "	८०७ " "	
१८९०	२८१६ " "	२५६२ " "	
१८९८	७४३६ " "	५८६६ " "	२२८ लाख रु०
१८९०	७४८० " "	७११४ " "	२३३ " "
१८९०	६८११ " "	६३२५ " "	४३६ " "
१८९६	७५०३ " "	६८१४ " "	५४६ " "
१८९७	७३२१ " "	१००९६ " "	८२६ " "
१८९८	६७२० " "	६८०६ " "	८७२ " "
१८९०	८५५७ " "	११३६८ " "	११०४ " "
१८९१	१०६७३ " "		

एक्सचेंज बैंकों का भारतीय द्रव्य बाज़ार में प्रभाव :—इन एक्सचेंज बैंकों का भारतीय द्रव्य बाज़ार पर गहरा प्रभाव रहा है । बहुधा इन बैंकों ने भारतीय आर्थिक हितों के विरुद्ध अपने प्रभाव का प्रयोग किया है । यह इन बैंकों के विरोध का ही परिणाम था कि भारत के प्रेसीडेंसी बैंकों को लंदन के द्रव्य बाज़ार में सीधे ऋण लेने की आज्ञा नहीं मिली

और भारत में केन्द्रीय बैंक (Central Bank) ही स्थापित हो सका । इन बैंकों के प्रधान कार्यालय लंदन में थे इस कारण वे लंदन द्रव्य बाजार के द्राग भारत मंत्री पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाते थे । यही नहीं भारत सरकार को प्रतिवर्ष इंग्लैंड में अपने खर्च (Home Charges) को चुकाने के लिए करोड़ों रुपये के स्टर्लिंग की आवश्यकता होती थी जो कि एक्सचेंज बैंक ही देते थे इस कारण भारत सरकार पर भी उनका प्रभाव रहता था । एक्सचेंज बैंकों को अपने प्रधान कार्यालयों के द्वारा लंदन द्रव्य बाजार में श्रुण लेने की सभी सुविधायें प्राप्त हैं इस कारण वे रिजर्व बैंक पर निर्भर नहीं हैं और इस कारण रिजर्व बैंक का उन पर कभी पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता ।

एक्सचेंज बैंकों के कार्य :—एक्सचेंज बैंकों का मुख्य कार्य भारत के विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है । एक प्रकार से एक्सचेंज बैंकों को भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त है । १८३५ के पूर्व इम्पीरियल बैंक को कानून द्वारा विदेशी बिलों (Foreign Bills) को खरीदने बँचने या मुनाने की मनाही थी । वह केवल अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ही भारत के बाहर रुपया भेज सकता था विदेशी व्यापार का कारबार नहीं कर सकता था । भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (Indian Joint Stock Banks) के ऊपर कोई ऐसा कानूनी प्रतिबन्ध नहीं था परन्तु वे विदेशी व्यापार को अपने हाथ में लेने में असमर्थ थे । क्योंकि एक्सचेंज बैंकों का उस पर एकाधिकार स्थापित था । पहला कारण तो यह है कि भारतीय बैंक इन एक्सचेंज बैंकों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत अधिक मजबूत और साधन सम्पन्न हैं । उनकी पूँजी और सुरक्षित कोष (Reserve Fund) भारतीय बैंकों की अपेक्षा कई गुना अधिक है और उन्हें लंदन के द्रव्य बाजार में बहुत कम सद् पर श्रुण लेने की सुविधा प्राप्त है । भारतीय बैंकों के सामने दूसरी कठिनाई यह है कि उनकी शाखायें अन्य देशों में नहीं हैं इस कारण वे विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का लाभदायक काम सुविधा पूर्वक नहीं कर सकते । तीसरा कारण यह कि भारत में ही भारतीय बैंकों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) की माँग रहती है अतएव उन्हें विदेशी व्यापार में अपने कोष को लगाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती । परन्तु पिछले वर्षों में विशेष कर १९४० के उपरान्त भारत में नये बैंकों की स्थापना इस तेजी से हुई है और पुराने बैंकों ने अपनी पूँजी और शाखाओं का इस तेजी से विस्तार किया है कि बैंकों की प्रतिस्पर्धा बढ गई है और भारतीय बैंकों को

भी विदेशी व्यापार में हाथ डालने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। सेन्ट्रल बैंक आथ इंडिया इत्यादि कुछ बड़े भारतीय बैंकों ने इस कार्य को करना आरम्भ भी कर दिया है। यही नहीं एक भारतीय एक्सचेंज बैंक "एक्सचेंज बैंक आथ इंडिया एण्ड अफ्रिका" भी स्थापित हुआ है जो अफ्रिका के व्यापार का काम करता है। इस बैंक ने अफ्रीका में अपनी शाखाएँ भी स्थापित की हैं। अभी तक जो भारतीय बैंक विदेशों में अपने ब्रांच स्थापित करने में सफल नहीं हुए उसके मुख्य कारण नीचे लिखे हैं :—

(१) भारतीय बैंकों की पूँजी इतनी अधिक न थी कि विदेशों के द्रव्य बाजारों में अपनी साख को सरलता से स्थापित कर सकते।

(२) विदेशों में ब्रांचों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कार्यशील पूँजी (Working Capital) भी अधिक होनी चाहिए।

(३) आरम्भ में कुछ वर्षों तक विदेशों में ब्रांचें घाटे पर चलेंगी अस्तु बैंकों को उस घाटे को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय (International Exchange) के कारबार को करने के लिए बहुत कुशल बैंक कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनकी भारत में कमी है।

(५) आरम्भ में भारतीय बैंकों को विदेशों में अधिक जमा मिलने की सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ के व्यवसायी, व्यापारी और जनता अपने देशीय बैंकों में ही अपना रुपया जमा करते हैं।

(६) भारतीय बैंकों को उन देशों के बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

(७) भारतीय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत में होने के कारण भारतीय बैंकों का संसार की मुख्य द्रव्य बाजारों (न्यू-यार्क और लंदन) से सीधा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता इस कारण वे अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी हलचलों से दूर रहते हैं और निर्यात (Export) और आयात (Import) बिल उन्हें इतने अधिक प्राप्त नहीं हो सकते।

इन्हीं कारणों से भारतीय बैंक विदेशों में अपनी ब्रांचें स्थापित करने में सफल न हो सके। किन्तु अब भारतीय बैंक उस ओर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें भविष्य में परिस्थितिवश अधिकाधिक इस ओर अग्रसर होना पड़ेगा।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक्सचेंज बैंकों का मुख्य कार्य व्यापार को आर्थिक सहायता देना है। किन्तु वे प्रायः सभी उन कार्यों को करते हैं जो कि व्यापारिक बैंक करते हैं। वे चालू (Current), मुहती (Fixed) तथा सेविंग डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, विदेशी विलों को खरीदते हैं, नौ परिवहन प्रलेखों (Shipping Documents) की जमानत पर धन देते हैं और सोना और चांदी के आयात (Import) में सहायता देते हैं। भारत में नेशनल बैंक तथा चारटर्ड बैंक के सोने के पसि बहुत प्रचलित रहे हैं। यही नहीं एक्सचेंज बैंक आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) में भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। जब माल देश के एक भीतरी स्थान से निर्यात (Export) के लिए बन्दरगाहों तक भेजा जाता है अथवा विदेशों से आया हुआ माल बन्दरगाहों से भीतरी केन्द्रों तक भेजा जाता है तब उस व्यापार को भी एक्सचेंज बैंक ही सहायता करते हैं। अब हम यहाँ विदेशी व्यापार का विवेचन विस्तार पूर्वक करेंगे।

जब भारतीय निर्यात (Export) करने वाला व्यापारी विदेशियों को माल बेचता है तो किसी लन्दन बैंक से साख्त (Credit) का प्रवन्ध कर लिया जाता है। माल खरीदने वाला लन्दन के किसी बैंक या पारनैल हाउस (साख्त देने वाले व्यापारी) से साख्त का प्रवन्ध कर लेता है और एक्सचेंज बैंक के जरिये भारतीय व्यापारी को इसकी ख़ुबना दे देता है तब भारतीय व्यापारी उस साख्त (Credit) के विरुद्ध उस लन्दन स्थित बैंक या पारनैल हाउस पर 'बिल' (Bill) लिख देता है। अधिकतर विलों की स्वीकृति हो जाने पर ही प्रलेख (Documents) जहाज की रसीद (Bill of Lading) इत्यादि दे दिए जाते हैं परन्तु कुछ बिल ऐसे भी होते हैं कि इनका भुगतान हो जाने पर ही प्रलेख (Documents) दिए जाते हैं।

ये बिल लन्दन भेज दिए जाते हैं। एक्सचेंज बैंक उन्हें स्वीकृति के लिए पेय करता है। उसकी स्वीकृति हो जाने पर एक्सचेंज बैंक उस पर बेंचान (Endorsement) कर देता है और लन्दन के द्रव्य बाजार में भुजा लेता है। इस प्रकार एक्सचेंज बैंक उस बिल को भारत में खरीद कर जो उसका मूल्य बन्यों में जुटाते हैं वह लन्दन में स्टॉर्लिंग में बतुल्य कर लेते हैं। यदि एक्सचेंज बैंकों के पास मधेष्ट कोष (Funds) होता है और उसका उस समय कोई लाभदायक उपयोग होने की सम्भावना नहीं होती तो वे बिलों को पकने (Maturity) तक अपने पास ही रखते हैं किन्तु यदि द्रव्य की बाजार में

कमी होती है और व्यापार में तेजी होती है तो वे इन विलों को लंदन के द्रव्य बाज़ार में तुरन्त भुना लेते हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उपनिवेशों और भारत के बीच में जो विल होते हैं वे बहुधा स्टालिंग में होते हैं जापान के विल यन (Yen) में होते हैं तथा चीन के विल रुपयों में होते हैं।

भारत के आयात व्यापार (Import Trade) का आर्थिक प्रबन्ध दो प्रकार से किया जाता है। जब भारतीय व्यापारी विदेशों से माल मँगाते हैं अथवा वे योरोपियन व्यापारी माल मँगवाते हैं जिनका लंदन में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है कि जिसकी द्रव्य-बाज़ार में साख हो तो माल भेजने वाला व्यापारी भारतीय व्यापारियों पर जिन्होंने माल मँगवाया है ६० दिन का देखनहार बिल (Sight Bill) काट देते हैं। उसके साथ माल सम्बन्धी सभी प्रलेख (Documents) जहाज़ की रशीद और समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि रहते हैं और वे आवश्यक प्रलेख भारतीय व्यापारी को तभी दिए जाते हैं कि जब वह बिल का भुगतान कर दे। माल भेजने वाला लंदन स्थित व्यापारी इन विलों को लंदन में ही एक्सचेंज बैंक से भुना (Discount) लेता है। इस प्रकार एक्सचेंज बैंक वास्तव में उस माल का स्वामी हो जाता है। जब प्रलेखों (Documents) के साथ एक्सचेंज बैंक की भारतीय शाखा के पास बिल आता है तो भारतीय व्यापारी या तो बिल का भुगतान कर देता है और जहाज़ की बिल्टी (Bill of Lading) तथा समुद्रीय बीमा पालिसी लेकर अपना माल छुड़ा लेता है। परन्तु यदि व्यापारी बिल का भुगतान नहीं करना चाहता तो वह एक्सचेंज बैंक से प्रार्थना करता है कि वह उसे बिना भुगतान किए ही माल लेने दे। ऐसी दशा में माल मँगाने वाला व्यापारी एक्सचेंज बैंक को माल की ट्रस्ट रशीद (Trust Receipt) लिख देता है। अर्थात् वह यह स्वीकार करता है कि जो माल उसने छुड़ाया है वह वास्तव में एक्सचेंज बैंक का है। वह तो उस माल का केवल ट्रस्टी या अमानतदार है। माल लेकर व्यापारी अपने गोदाम में रख लेता है और उसके विक्रि जाने पर बिल का भुगतान कर देता है। इस सुविधा के लिए उसे एक्सचेंज बैंक को सूद देना पड़ता है।

जिन भारतीय योरोपियन फर्मों के कार्यालय लंदन में हैं उनके साथ दूसरा ढंग चलता जाता है। लंदन का कार्यालय उस माल की खरीद करता है जिसकी भारतीय फर्म को आवश्यकता होती है। अब जब लंदन का कार्यालय जहाज़ से माल भारत को भेज देता है तो वह अपनी भारतीय शाखा अर्थात् माल

मँगाने वाली फर्म पर प्रलेख बिल (Documentary Bill) देता है। लंदन का कार्यालय लंदन रियलि एक्सचेंज बैंक के सामने उस बिल को उपस्थित करता है और एक्सचेंज बैंक उसकी स्वीकार कर लेता है। बिल पर एक्सचेंज बैंक की स्वीकृति हो जाने पर लंदन का कार्यालय उस बिल को लंदन के द्रव्य बाजार में भुना कर माल का मूल्य स्टर्लिंग बसूल कर लेता है। बिल को स्वीकार करने वाले एक्सचेंज बैंक जहाजी बिल्टी (Bill of Lading) और समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि आवश्यक प्रलेख अपनी भारतीय शाखा को भेज देता है। एक्सचेंज बैंक की भारतीय शाखा भारतीय फर्म से जितने माल मँगवाया है वप्या बसूल करके लंदन भेज देता है। बिल दोनों ही दशा में स्टर्लिंग में ही लिखे जाते हैं। किन्तु दूसरे ढंग में योरोपीय फर्मों को यह लाभ होना है कि वह बिल लंदन में भुन जाता है अस्तु सूद बहुत कम देना पड़ता है क्योंकि यह बड़ा दर (Discount Rate) बहुत कम होती है किन्तु भारतीय व्यापारियों को बिल कटने के दिन से और उसका भुगतान लंदन पहुँचने के दिन तक ऊँची दर से सूद देना पड़ता है।

बहुधा मातृवर्ष का विदेशी व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) उसके पक्ष में रहता है। अस्तु एक्सचेंज बैंक भारत में सोना चाँदी मँगाकर तथा रिज़र्व बैंक को स्टर्लिंग (जिनका लंदन में भुगतान हो) बेंच कर उस अन्तर को पूरा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक्सचेंज बैंक सभार के प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर तारकी हुद्दी (Telegraphic Transfers) रेंवते हैं।

एक्सचेंज बैंक केवल विदेशी व्यापार का ही कारबार नहीं करते बरन भारत के भीतरी व्यापारिक केन्द्रों से बन्दरगाहों तक और बन्दरगाहों से भीतरी व्यापारिक केन्द्रों तक माल आने जाने का प्रबन्ध भी करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक्सचेंज बैंक भारत के अन्दरूनी व्यापार के कारबार को भी अपने हाथ में लेने के इच्छुक दिखालाई देते हैं। वे मागतीय व्यापारिक बैंकों के हिस्से खरीद कर उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए पी० ओ० बैंकिंग कारपोरेशन ने इलाहाबाद बैंक जैसे प्रतिद और बड़े बैंक को खरीद लिया और इस प्रकार वह भारत के सभी प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में उसकी शाखाओं के द्वारा पहुँच गया। और पी० ओ० बैंकिंग कारपोरेशन को चारटर्ड बैंक ने खरीद लिया अस्तु इलाहाबाद बैंक की भाँचे वास्तव में चारटर्ड बैंक की भाँचे है जो कि एक प्रमुख एक्सचेंज बैंक है। जिन भीतरी व्यापारिक केन्द्रों में एक्सचेंज बैंकों की शाखाएँ होती

हैं वहाँ के व्यापारी एक्सचेंज बैंकों की स्थापित शाखा से ही विदेशों में अपनी देनी (Debt) का भुगतान कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कानपूर का व्यापारी लंदन से माल मँगाता है तो उस पर लंदन के व्यापारी (माल भेजने वाले) ने जो बिल लिखा है कानपूर शाखा को भेज दिया जाता है और कानपूर की शाखा उससे रुपया वसूल करके उसे जहाजी बिल्टी और समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि दे देती है। इसी प्रकार भीतरी केन्द्र से विदेशों को माल भेजने वाला व्यापारी स्थानीय एक्सचेंज बैंक की ब्रांच को अपना बिल जो उसने विदेशी व्यापारी पर लिखा है बैंक देता है।

किन्तु यदि किसी भीतरी व्यापारिक केन्द्र में एक्सचेंज बैंक की शाखा नहीं होती तो वहाँ से बन्दरगाहों तक का कारबार भारतीय व्यापारिक बैंक करते हैं और बन्दरगाहों से विदेशों तक का कारबार एक्सचेंज बैंक करते हैं। जिन भीतरी स्थानों में एक्सचेंज ब्रांच की शाखा होती है वहाँ के व्यापारी एक्सचेंज बैंक से ही दोनों व्यवहार (Transaction) करते हैं क्योंकि वह सरल और कम खर्चोला बैठता है।

विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक प्रबंध करने के अतिरिक्त एक्सचेंज बैंक भीतरी व्यापार के कारबार को भी करते हैं। वे व्यापारियों को ऋण देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजते हैं, तीनों प्रकार की जमा लेते हैं। उनकी साख और प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण वे भारतीय व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा कम सूर देते हैं। वे एजेंसी का काम भी करते हैं और सोना-चाँदी के आयात (Import) व्यापार के लिए भी आर्थिक प्रबंध (Finance) करते हैं।

एक्सचेंज बैंकों के विरुद्ध आरोप :—यह तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि विदेशी व्यापार के लिए जितनी साख की आवश्यकता होती है यह विदेशी बैंक उसको उचित मूल्य पर देने का प्रबंध करते हैं किन्तु भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय व्यापारिक बैंकों को उनसे बहुत सी शिकायतें हैं। जब भारत में केन्द्रीय बैंकिंग जॉइंट कमेटी बैठी थी उस समय भारतीय बैंकों तथा भारतीय व्यापारियों ने उन पर नीचे लिखे आरोप लगाये थे।

(१) एक्सचेंज बैंकों पर भारत का कोई बैंकिंग सम्बन्धी कानून लागू नहीं होता। कानून ने जो दायित्व भारतीय बैंकों पर लगा दिये हैं वे भी एक्सचेंज बैंकों पर लागू नहीं होते। उनके डायरेक्टर और हिस्सेदार सभी विदेशी हैं। अस्तु उनका नियंत्रण विदेशियों के हाथ में है। रिजर्व बैंक का उन पर कोई

नियंत्रण नहीं है। एक्सचेंज बैंकों के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वे भारत में आय-व्यय निरीक्षकों से अपने आय-व्यय की जाँच करावें। वे भारत सम्बन्धी कारबार का पृथक् लेनी देनी का लेखा (Balance-Sheet) तक नहीं छाँटते। भारत सरकार को पाँच वर्षों में वे एक बार अपनी लेनी-देनी का लेखा भेजते हैं उसमें उनके विदेशी और भारतीय कारबार के सम्मिलित आंकड़े रहते हैं जिनसे उनके भारतीय कारबार का कोई पता नहीं चलता। इसका परिणाम यह होता है कि एक्सचेंज बैंकों का कारबार भारतीयों से एक दम गुप्त रहता है। यह बैंक भारत में बहुत अधिक डिपॉजिट आकर्षित करते हैं। उनके कोष का भारतीय डिपॉजिट एक बहुत बड़ा भाग होती है किन्तु भारतीय जमा करने वालों की डिपॉजिटों की सुरक्षा का कोई भी नियम उन पर लागू नहीं होता। यदि कोई एक्सचेंज बैंक किसी बारखुदाश फेल हो जाय (डूट जाय) तो भारतीय जमा करने वालों का अपनी डिपॉजिटों को घसूल करने के लिए एक्सचेंज बैंक की भारतीय सम्पत्ति पर पहला हक भी नहीं है।

(२) दूसरी शिकायत उनके विरुद्ध यह थी कि वे बहुधा भारत में उनकी डिपॉजिटों को देखते हुए यथेष्ट नज़्द कोष (Cash Reserves) भी नहीं रखते। इस कारण भारतीय द्रव्य-बाज़ार के लिए निर्वलता का कारण बनते हैं। प्रथम महायुद्ध के समय इसी कारण एक्सचेंज बैंक कठिनाई में पड़ गए थे और उनकी सहायता करनी पड़ी थी। तब से कुछ वर्षों तक उन्होंने अधिक नकद काय रक्खा किन्तु अब फिर उनका नकद कोष गिरने लगा। अपने पक्ष में एक्सचेंज बैंक कहते हैं कि वे सरकारी प्रतिभूति (सिक्यूरिटियों) और सरकारी हुडियों (Treasury Bills) में अपना यथेष्ट कोष लगाते हैं किन्तु उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(३) एक प्रकार से एक्सचेंज बैंकों को भारत के विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Finance) करने का एकाधिकार प्राप्त है और वे इस कार्य को भारत में प्राप्त का हुई जमा (डिपॉजिट) से ही करते हैं। इस प्रकार भारत को बैंकिंग लाभ और व्यापारिक लाभ से वंचित रहना पड़ता है। एक्सचेंज बैंकों का भारतीय विदेशी व्यापार में बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि भारत का विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा घटता गया और विदेशियों का हिस्सा बढ़ता गया। यहाँ तक कि भारतीयों का विदेशी व्यापार में केवल १५ से २० प्रतिशत भाग ही रह गया। इस प्रकार भारतीयों को करोड़ों रुपये के

वैदेशिक व्यापार से होने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ता है। केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमिटी (Central Banking Enquiry Committee) के सामने गवाही देते हुए बहुत सी व्यापारिक संस्थाओं ने इस बात की शिकायत की थी कि यह विदेशी एक्सचेंज बैंक विदेशी व्यापारियों को अधिकाधिक सुविधायें देकर और भारतीय व्यापारियों को उन सुविधाओं से वंचित रखकर उन्हें बढ़ाते रहे हैं। इसी का परिणाम यह हुआ कि भारत का व्यापार विदेशियों के हाथ में चला गया।

इन एक्सचेंज बैंकों का एक ढंग तो यह है कि जब कोई भारतीय व्यापारी विदेशों से कारवार करना चाहता है तो यह बैंक विदेशों को उनके बारे में बहुधा अच्छी सम्मति नहीं देते। इस सम्बन्ध में एक्सचेंज बैंकों का कहना है कि हम जो इस सम्बन्ध में भारतीय और विदेशी व्यापारियों में भेद करते हैं उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय व्यापारी बैंकों को अपना लेनी-देनी का लेखा (Balance-Sheet) देना नहीं पसंद करते। जब तक हमें उनका आजीवरो द्वारा जांचा हुआ लेनी-देनी का लेखा न मिले तब तक हम उनकी आर्थिक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। भारतीय व्यापारियों का कहना यह है कि एक्सचेंज बैंकों का उससे अर्थ यह है कि जिन आय-व्यय निरीक्षकों (Auditors) को वे स्वीकार करें उनसे हम अपने हिसाब की जांच करवावें तभी वे उसे स्वीकार करेंगे। किन्तु एक्सचेंज बैंकों के प्रतिनिधियों ने इसको अस्वीकार किया। उनका कहना था कि हम सरकार द्वारा स्वीकृत आय-व्यय निरीक्षकों से जांचा हुआ लेनी-देनी का लेखा मांग ही चाहते हैं। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि भारत में एक फर्म और एक बैंक की परिपाटी प्रचलित नहीं है इस कारण एक्सचेंज बैंकों को लेनी-देनी के लेखे को मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सच बात तो यह है कि एक्सचेंज बैंकों के मैनेजर सब विदेशी हैं इस कारण वे भारतीय व्यापारियों के अधिक सम्पर्क में नहीं आते और उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते।

भारत में जो विदेशी व्यापारी हैं उन्हें माल साख (Credit) पर मँगाने की सुविधा दी जाती है जब कि भारतीय व्यापारी को नकद मूल्य देना पड़ता है। भारतीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि विदेशों के व्यापारी भारतीय व्यापारियों को साख इस कारण नहीं देते क्योंकि एक्सचेंज बैंक उनके सम्बन्ध में अच्छी सम्मति नहीं देते। एक्सचेंज बैंकों का कहना था कि हम जो भारतीय व्यापारियों से ट्रस्ट की रसीद (Trust Receipt) लेकर जहाजी

बिल्टो इत्यादि दे देते हैं उससे उन्हें भी ऋण (Credit) की सुविधा मिल जाती है। परन्तु भारतीय व्यापारियों ने इसके उत्तर में यह कहा कि ट्रस्ट-रखीद पर सूद अधिभू देना पड़ता है। अतएव भारतीय व्यापारियों का विदेशी व्यापारियों की अपेक्षा हानि उठानी पड़ती है।

भारतीय व्यापारियों ने इस बात की भी शिकायत की कि पर कोई भारतीय व्यापारी माल बाहर भेजता है तो एक्सचेंज बैंक उनके बिल को बिना अन्तर (Margin) के और बिना जमानत बिना कमी नहीं भुनाते किन्तु जब कोई विदेशी फर्म माल बाहर भेजती है और अपने बिल को भुनाती है तो अन्तर (Margin) या जमानत नहीं माँगी जाती। एक्सचेंज बैंकों का कहना है कि विदेशी फर्मों के प्रधान कार्यालय विदेशों में होते हैं और बिल उन्हीं पर होते हैं अतः उनके भुगतान न होने का कोई भय नहीं होता परन्तु भारतीयों के साथ ऐसी बात नहीं है। इसी कारण एक्सचेंज बैंक उनके बिलों का पूरा मूल्य यहाँ चुका देते हैं। जा भी हो किन्तु यह सत्य है कि भारतीयों को विदेशों फर्मों की तुलना में हानि होती है।

भारत में एक्सचेंज बैंक विदेशों के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में यहाँ के व्यापारियों को कोई जानकारी नहीं देते। संसार के प्रत्येक देश में बैंकों का यह मुख्य कार्य है किन्तु एक्सचेंज बैंक ऐसा नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि भारत में जो विदेशी फर्म काम करती हैं उन्हें तो अपने विदेशी कार्यालयों से विदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है किन्तु भारतीय व्यापारियों को उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती।

पहले तो भारतीय व्यापारी जब विदेशों से माल मगवाते हैं तो उन्हें साफ़ ही नहीं मिलती किन्तु जिन थोड़े से प्रथम श्रेणी के भारतीय व्यापारियों को ऋण मिलती भी है उन्हें भी मँगाने हुए माल के मूल्य का १५ प्रतिशत तक बैंकों के पास जमा कर देना होता है जब कि उन विदेशी फर्मों को जो भारत में हैं कोई डिपॉजिट बैंकों के पास नहीं रखनी पड़ती।

भारत के अधिकांश आयात (Import) और निर्यात (Export) व्यापार में स्टर्लिंग बिल का उपयोग होता है। इसका फल यह होता है कि भारतीय व्यापारी को माल मगाने वाले विदेशी व्यापारी पर स्टर्लिंग में ही बिल काटना पड़ता है अतएव उसका बिल भारतीय द्रव्य बाजार के लिए व्यर्थ की बस्तु हो जाता है। उसे एक्सचेंज बैंकों से ही उसे भुनाना पड़ता है। जिनकी

बट्टा दर (Discount Rate) ऊँची होती है। इसके विरुद्ध भारत में कारवार करने वाली विदेशी फर्मों अपने लंदन स्थित कार्यालयों से माल मंगवाती हैं तो वे लंदन स्थित कार्यालय अपनी भारतीय शाखाओं पर बिल न काट कर लंदन स्थित एक्सचेंज बैंकों के आफिसों पर बिल (Bill) काटते हैं और वे एक्सचेंज बैंक के आफिस उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक्सचेंज बैंक से बिल को स्वीकार कराने के बाद वे उस बिल को लंदन द्रव्य बाजार में भुना लेते हैं। लंदन द्रव्य बाजार में बट्टे की दर (Discount Rate) बहुत कम होती है। इस प्रकार विदेशी फर्मों को भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा एक था डेढ़ प्रतिशत का लाभ हो जाता है।

(४) इन आरोपों के अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों का एक्सचेंज बैंकों के विरुद्ध एक सब से बड़ा आरोप यह है कि वे भारतीय ब्रोकरों, भारतीय बैंकों, भारतीय बीमा कंपनियों और भारतीय जहाजी कंपनियों के विरुद्ध अपने देशों के ब्रोकरों, बैंकों, कंपनियों तथा जहाजी कंपनियों को प्रोत्साहित करते हैं। जब भारतीय व्यापारी विदेशों को माल भेजते हैं तो एक्सचेंज बैंक उन्हें विदेशी जहाजी कंपनियों से माल भेजने तथा विदेशों बांभा कंपनियों से उसका बीमा करवाने पर विवश करते हैं। इस प्रकार भारतीय बीमा कंपनियों तथा भारतीय जहाजी कंपनियों को करोड़ों रुपये की हानि होती है और वे पनप नहीं पाती।

(५) एक्सचेंज बैंक एसोसियेशन बिना भारतीय व्यापारियों से कोई परामर्श किए ही अपने नियमों में जब चाहती है तो परिवर्तन कर देती है और भारतीय व्यापारियों के लिए नियम कठोर रखे जाते हैं। यही नहीं एसोसियेशन किसी भी सदस्य को भारतीय बैंक तथा जावर से कारवार नहीं करने देती जो कि विनिमय (Exchange) का काम करता है। दूसरे शब्दों में एक्सचेंज बैंक भारतीय बैंकों को इस लाभदायक कारवार के क्षेत्र से बाहर ही रखना चाहते हैं।

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि एक्सचेंज बैंक भारत के भीतरी व्यापार को भी करने लगे हैं। इस प्रकार वे भारतीय मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों (Indian Joint Stock Banks) से होड़ करते हैं और उनकी बढ़वार को रोकते हैं। उनकी प्रतिष्ठा और साधन अधिक होने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा में भारतीय बैंकों को कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज बैंकों के कारण भारतीय बैंकों को एक और भी हानि होती है। जब

कोई देश विदेशों से माल मंगवाता है तो वापारखतः होता यह है कि माल मंगाने वाला माल मंगाने वाले के देश की करंसी में बिल लिखता है। यह बिल जहाज़ी बिल्टी इत्यादि के साथ भेज दिए जाते हैं और जब माल मंगाने वाला उस बिल को स्वीकार कर लेता है तो उनकी मुनाया जाता है। क्योंकि बिल उस देश की करंसी में होते हैं इस कारण वहाँ के बैंक उनको भुनाते हैं और उन्हें लाभ होता है। परन्तु भारत के व्यापारी जब माल मंगाते हैं तो आयात बिल (Import Bill) रुपयों में न हो कर स्टर्लिंग में काटे जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों के घर काम के नहीं होते और वेबल एक्सचेंज बैंक ही इस लाभदायक धंधे को कर सकते हैं। एक्सचेंज बैंक इन बिलों को रुपयों में नहीं कटते देते और इस प्रकार भारतीय बैंकों को वे इस लाभदायक कारबार से वंचित रहते हैं।

एक्सचेंज बैंक के पिछे एक कारण यह भी है के जिन देशों कि एक्सचेंज बैंक भारत में नहीं हैं उनकी करंसी यह बैंक बहुत ऊँची कीमत पर देते हैं। यही नहीं यदि किसी अन्य देश का कोई बैंक अपनी शाखा भारत में स्थापित करना चाहता है तो वे उसका विरोध करते हैं। जब कभी कोई विदेशी बैंक अपनी शाख भारत में स्थापित करने में सफल हो गया तो उन देशों की करंसी भारतीयों को कम मूल्य में मिलने लगी जिससे कि भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ। एक्सचेंज बैंकों ने ऐसा कुछ बना लिया है कि यदि किसी देश के बैंक की भारत में शाख भी हो तो भी उन देशों की करंसी (स्टर्लिंग को छोड़ कर) का मूल्य वहाँ ऊँचा ही रहता है। यदि कोई उसी करंसी को लंदन के द्रव्य बाजार में खरीदे तो उसे कम मूल्य देना पड़ता है। उदाहरण के लिए मुद्र के पूर्व यदि कोई बाहर लंदन से खरीदता तो कलकत्ता या बम्बई की अपेक्षा कम मूल्य पर खरीद सकता था।

इसके अतिरिक्त इन एक्सचेंज बैंकों का समाशोधन यह या क्लियरिंग हाऊस (Clearing House) में बहुत प्रभाव है और यह भारतीय बैंकों को क्लियरिंग हाऊस का सदस्य बनने नहीं देते। यहाँ तक हो सकता है पर भारतीय बैंकों को क्लियरिंग हाऊस के बाहर ही रहते हैं। इससे भारतीय बैंकों की प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सचेंज बैंक भारतीय बैंकों से स्वतंत्रता पूर्वक जब चाहते हैं तब याचना द्रव्य (Call Money) लेते रहते हैं किन्तु भारतीय बैंकों को जब आवश्यकता होती है तो वे उन्हें उतनी आसानी से याचना द्रव्य नहीं देते।

यद्यपि एक्सचेंज बैंक भारत के सबसे पुराने बैंको में से है और उनको स्थापित हुए लगभग ८० वर्ष हो गए किन्तु फिर भी कोई भारतीय उनमें ऊँचे पदों पर नहीं रखता गया। इसका परिणाम यह होता है कि बैंको में सभी उच्च कर्मचारी विदेशी व्यक्ति होते हैं। वे न भारतीय भाषा ही जानते हैं और न भारतीय व्यापारियों के घनिष्ट सम्पर्क में ही आ सकते हैं अतएव भारतीय व्यापारियों के साथ उनकी सहानुभूति नहीं होती। यह एक्सचेंज बैंक अपने देशवासियों को ही लाकर उच्च पदों पर रखते हैं। जबकि वे भारतीय व्यापार से इतना अधिक लाभ उठाते हैं तब उनका भारतीयों को ऊँचे पदों पर न लेना उचित नहीं कहा जा सकता।

एक्सचेंज बैंक पिछले वर्षों में इस बात का भी प्रयत्न करते रहे हैं कि भारतीय पूँजी विदेशी धर्मों या विनियमों में न लगे।

एक्सचेंज बैंको ने सदैव ही भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग किया है। यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि यह उन्हीं के विरोध का फल था कि प्रेसीडेंसी बैंको तथा इम्पीरियल बैंक को विदेशी विनिमय (Exchange) का कारबार करने की आज्ञा नहीं दी गई। यही नहीं इन एक्सचेंज बैंको के कारण ही भारत में कोई केन्द्रीय बैंक १९३५ के पूर्व स्थापित न हो सका। इंडिया आफिश के द्वारा यह एक्सचेंज बैंक भारत-सरकार की अर्थनीति पर भी गहरा प्रभाव डालते थे जिससे भारत के आर्थिक हितों की हानि होती थी।

किन्तु अब भारत स्वतंत्र हो गया है। एक्सचेंज बैंको के भारत-विरोधी दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है। भारत सरकार की अर्थनीति पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। रिज़र्व बैंक के नेतृत्व को उन्हें अब स्वीकार करना ही होगा और इस बात की सम्भावना है कि सरकार भविष्य में कोई बैंकिंग कानून बनाकर उनके नियंत्रण का भी प्रयत्न करे। अब हम आगे उन सुझावों का अध्ययन करेंगे कि जो केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के सामने एक्सचेंज बैंको की अनुचित प्रतिस्पर्धा से भारतीय बैंको की रक्षा करने के लिए रखे गए।

केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का मत— इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी (Central Banking Committee) का मत था कि भारत सरकार को विदेशी बैंको को बिना किसी रोक-टोक के भारत में कारबार करने की छूट न

देनी चाहिए। प्रत्येक विदेशी बैंक को जो कि भारत में काम करना चाहे रिजर्व बैंक से एक लायसेंस प्राप्त करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि भारतीयों के हितों की रक्षा हो सकेगी। रिजर्व बैंक का एक्सचेंज बैंकों पर नियंत्रण स्थापित हो सकेगा और भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में बड़ी सुविधायें प्राप्त की जा सकेंगी जो कि भारत में विदेशी बैंक को दी जावेंगी।

कमेटी का बहुमत इस पक्ष में था कि जो एक्सचेंज बैंक भारत में कार-बार कर रहे हैं उनको बिना किसी रोक टोक के लायसेंस दे देना चाहिए। प्रत्येक बैंक को लायसेंस एक निश्चित काल के लिए दिया जाना चाहिए और उस अवधि के समाप्त होने पर यदि रिजर्व बैंक देखे कि लायसेंस की शर्तों का किसी बैंक ने सतोपजनक ढंग से पालन किया है तो उसको फिर लायसेंस दे दे अन्यथा उसका लायसेंस समाप्त कर दिया जा सकता है। एक्सचेंज बैंकों के लायसेंस की यह आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि वे रिजर्व बैंक की अपनी रिपोर्ट 'मेजे' जिसमें भारतीय तथा गैर भारतीय कारबार का लेनी देनी लेखा (Balance Sheet) अलग अलग हो।

कमेटी के बहुमत की यह भी सम्मति थी कि एक्सचेंज बैंकों को अपनी कार्यपद्धति में इस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए कि वे भारतीय आयात करने वाले व्यापारियों (Importers) के विलों की खरीदने के बजाय स्वी-कार (Accept) कर बिपा करे जिससे कि वे बिल लंदन से भुनाये जा सकें। और भारतीय व्यापारी लंदन के द्रव्य बाजार में सस्ते द्रव्य का लाभ उठा सकें।

इसके अतिरिक्त यदि भारतीय आयात व्यापारी (Importers) चाहें कि विदेशी निर्यात व्यापारी (Exporters) उन पर रुपये में बिल लिखें तो एक्सचेंज बैंकों को भारतीय व्यापारियों की सहायता करनी चाहिए।

कमेटी की यह भी राय थी कि जब एक्सचेंज बैंकों की एसोसियेशन अपने नियमों में कोई परिवर्तन करे तो उसे भारतीय व्यापारियों से परामर्श करना चाहिए।

कमेटी की यह भी सम्मति थी कि एक्सचेंज बैंकों को भारतीय बीमा कम्पनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भारतीय युवकों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करना चाहिये और जहाँ एक्सचेंज बैंक की भी शाखा हो वहाँ एक स्थानीय परामर्श दाता बोर्ड (Local Advisory Board) होना चाहिए जो

ऋण देने के सम्बन्ध में बैंक को परामर्श दे। यद्यपि बोर्ड की सलाह बैंक मान ही ले यह आवश्यक नहीं था फिर भी इस प्रकार भारतीय ग्राहकों तथा एक्सचेंज बैंकों में परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं।

यद्यपि केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने ऊपर लिखे सुझाव रखे थे किन्तु एक्सचेंज बैंकों ने उस सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न अपनी कार्य पद्धति में ही कोई अन्तर किया।

कुछ भारतीय विद्वानों (जिनमें श्री सूवेदार और सरकार मुख्य थे) की राय थी कि एक्सचेंज बैंकों पर कड़ा नियंत्रण रक्खा जावे। रिज़र्व बैंक को इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह जिस बैंक को चाहे लाय-सेंस देना अस्वीकार कर दे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि एक्सचेंज बैंकों को भारत में केवल उतनी ही डिपॉजिट लेने देना चाहिए जितनी भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक हों। एक मत यह भी था कि एक्सचेंज बैंक जितनी डिपॉजिट ले उस पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर लगाया जावे। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का यह भी कहना था कि एक्सचेंज बैंकों को भारत में सभी डिपॉजिट लेने का अधिकार होना चाहिए जब उनकी रजिस्ट्री भारत में हुई हो, उनकी पूँजी रुपये में हो और भारतीय उनके डायरेक्टर हों। कोई-कोई इसके मत में थे कि एक्सचेंज बैंकों को भारत में डिपॉजिट लेने की मनाही कर दी जावे। किन्तु ऊपर लिखे मतों को केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने स्वीकार नहीं किया।

भारतीय एक्सचेंज बैंक :—केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का यह भी मत था कि यदि इम्पीरियल बैंक रिज़र्व बैंक की सहायता से विदेशी विनिमय (Foreign Exchange Business) का कारबार न कर सका तो एक भारतीय विनिमय बैंक स्थापित किया जावे। कमेटी का मत था कि वह बैंक सरकार की सहायता से स्थापित हो। किन्तु कमेटी का मत था कि पहले इम्पीरियल बैंक के द्वारा ही यह कार्य करना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो तभी कोई नया बैंक खोलना चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का यह भी मत था कि भारतीय तथा विदेशियों के सम्मिलित एक्सचेंज बैंक स्थापित होने चाहिए जिससे भारत तथा उन देशों का जिनसे भारत व्यापार करता है दोनों का ही लाभ हो। किन्तु कमेटी की एक भाँति सिफारिश कार्य रूप में परिणत नहीं की गई।

सच तो यह है कि विदेशी विनिमय बैंक का एकाधिकार तभी समाप्त
फा०—१७

होगा जब कि भारतीय व्यापारिक बैंक भी विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) के कारबार को अपने हाथ में लें । अभी तक भारतीय बैंक इस ओर से उदासीन रहे हैं । अब कुछ बैंकों (विशेष कर सेन्ट्रल बैंक और इंडिया) ने इधर ध्यान दिया है । आशा है कि भविष्य में वे इस ओर अधिक ध्यान देंगे ।

परन्तु विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा में विदेशों में कारबार करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय बैंक आपस में सहयोग करें और एक दूसरे को सहायता प्रदान करें ।



अध्याय-१७

इम्पीरियल बैंक आर इंडिया

इम्पीरियल बैंक की स्थापना १९२१ में एक स्वतंत्र ऐक्ट इम्पीरियल बैंक ऐक्ट के अन्तर्गत हुई थी। तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिला कर इम्पीरियल बैंक बना था। १९३४ में इम्पीरियल बैंक ऐक्ट को संशोधित कर दिया गया।

इम्पीरियल बैंक की अधिकृत पूंजी (Authorised Capital) ११ करोड़ ७५ लाख रुपये हैं जिसमें से आधी पूंजी चुकता पूंजी (Paid up Capital) है और शेष आधी रक्षित दायित्व (Reserve Liability) है। बैंक का रक्षित फंड है। आरम्भ से १९३१ तक बैंक ने १६ प्रतिशत लाभ बांटा और १९३१ के उपरान्त १२ प्रतिशत लाभ बांटा रहा है इस कारण बैंक के हिस्सों का मूल्य बाजार में बहुत अधिक है।

प्रबन्ध—इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध तीन स्थानीय बोर्ड और एक केन्द्रीय बोर्ड करता है। तीन स्थानीय बोर्ड नीचे लिखे हैं—बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्य उस क्षेत्र के रजिस्टर में दर्ज हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते हैं और यह बोर्ड अपने मंत्री तथा खजांची की सहायता से उस क्षेत्र में बैंक के कारबार को देखते हैं। केन्द्रीय बोर्ड में नीचे लिखे सदस्य होते हैं—(१) प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के प्रेसीडेंट, वाइस-प्रेसीडेंट, तथा मंत्री; (२) प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को केन्द्रीय बोर्ड के लिये चुनते हैं; (३) गवर्नर जनरल अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को केन्द्रीय बोर्ड के लिये मनोनीत कर सकते हैं। वे एक वर्ष के लिये मनोनीत किये जाते हैं किन्तु वे फिर-दूसरे वर्ष के लिये दुबारा भी मनोनीत किये जा सकते हैं; (४) मैनेजिंग डायरेक्टर; (५) डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर; (६) एक सरकारी अधिकारी जिसे गवर्नर जनरल मनोनीत करे। केन्द्रीय बोर्ड की मीटिंग में स्थानीय बोर्डों के मंत्री, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, तथा सरकारी अधिकारी भाग ले सकते हैं किन्तु मत नहीं दे सकते, हां यदि मैनेजिंग डायरेक्टर उपस्थित न हो तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वोट दे सकता है।

बैंक का कार्य संचालन केन्द्रीय बोर्ड करता है। पूरे बोर्ड की मीटिंग जल्दी जल्दी नहीं बुलाई जा सकती इस कारण एक छोटी सी प्रबन्धकारिणी

समिति बना दी गई है जो कि केन्द्रीय बोर्ड के कुछ कार्य सम्पन्न करती है। प्रान्तीय ईंधनों को बचाने के लिए केन्द्रीय बोर्ड का प्रधान कार्यालय किसी एक स्थान पर नहीं है। बोर्ड की मीटिंग कभी कलकत्ते में होती है तो कभी बम्बई में।

१९३४ के पूर्व इम्पीरियल बैंक—१९३४ के पूर्व इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध केन्द्रीय बोर्ड करता था जिसका संगठन नीचे लिखे अनुसार था :—
 (१) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये गए (क) दो मैनेजिंग गवर्नर,
 (ख) ४ गैर-सरकारी अधिकारी जिन्हें भारतीय स्वार्थों की रक्षा के लिये गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। (२) करसी का कंट्रोलर जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधि होता था। (३) स्थानीय बोर्डों (Local Boards) के प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट तथा मंत्री। केन्द्रीय बोर्ड के ऊपर दिये हुए संगठन से यह स्पष्ट था कि यद्यपि इम्पीरियल बैंक हिस्सेदारों का बैंक था किन्तु भारत सरकार का उस पर पूरा नियन्त्रण था। करसी के कंट्रोलर को यह अधिकार था कि वह बोर्ड के किसी भी निर्णय को जो कि सरकारी जमा तथा अर्थनीति से सम्बन्ध रखता हो कार्य रूप में न परिणत होने दे और उसे सरकार के नियंत्रण के लिए भेज दे। (२) वह इम्पीरियल बैंक को उसकी नीति तथा नकद कोष की सुरक्षा के सम्बन्ध में आज्ञा दे सकता था।

(३) सरकार जो भी जानकारी इम्पीरियल बैंक से चाहे उसे देनी होगी तथा बैंक को अपना हिसाब वा लेखा तथा लेनी देनी का लेखा (Balance Sheet) सरकार की इच्छानुसार प्रकाशित करना होगा।

(४) सरकार इम्पीरियल बैंक के हिसाब की जांच के लिए आडिटर नियुक्त कर सकती थी।

१९३४ के उपरान्त अब सरकार ने अपने ऊपर लिखे अधिकार छोड़ दिये क्योंकि बैंक सरकार का बैंक नहीं रहा।

इम्पीरियल बैंक के कार्य—१९३५ तक इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंक था। जितना भी सरकारी कोष (Funds) होता वह इम्पीरियल बैंक में ही रक्ता जाता था। सरकार का खजाना का काम भी इम्पीरियल बैंक ही करता था। इम्पीरियल बैंक इस कार्य के लिए कोई कमीशन न लेता था। सरकार को जितना रुक्या मिलना होता था वह इम्पीरियल बैंक लेता था और सरकार अपने खर्चों के लिए उससे रुपया निकालती थी। भारत सरकार के श्रृंखला का

प्रबन्ध भी इम्पीरियल बैंक ही करता था। सरकार जो नवीन कर्ज निकालती थी वह भी इम्पीरियल बैंक ही निकालता था।

सरकारी कारबार के अतिरिक्त इम्पीरियल बैंक १९३५ के पूर्व केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के भी कुछ कार्य करता था। भारत के अधिकांश बैंक उसके साथ डिपॉजिट रखते थे। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित ११ क्लियरिंग हाउसों का भी प्रबन्ध करता था। इम्पीरियल बैंक जहाँ-जहाँ उसकी ब्रांचें थी वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करता था। बैंक तथा जनता दोनों ही इम्पीरियल बैंक के द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते थे। इम्पीरियल बैंक रुपया भेजने के लिए जो कमीशन लेता था उसको सरकार नियंत्रित करती थी। इसके बदले में इम्पीरियल बैंक को सरकार ने सरकारी खजानों के द्वारा देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना कुछ लिए ही रुपया भेजने की सुविधा दी थी।

जब देश के द्रव्य-बाज़ार में रुपये की कमी पड़े तो उस कमी को पूरा करने के लिये कागज़ी मुद्रा विभाग (Paper Currency Department) बैंक को १२ करोड़ रुपये तक ऋण दे सकता था। किन्तु बैंक को उसके जमानत स्वरूप हुंडी या बिल रखने पड़ते थे। सरकार बैंक से पहले ४ करोड़ रुपये के लिए ६ प्रतिशत और शेष ८ करोड़ रुपये के लिए ७ प्रतिशत सूद लेती थी। देश में बैंकिंग की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक के लिए कानून में ५ वर्षों के अन्दर १०० शाखाएँ स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया था। इम्पीरियल बैंक ने इस शर्त को पूरा कर दिया था। आधी ब्रांचें ऐसे स्थानों पर स्थापित की गई थी कि जहाँ कोई बैंक न था। इसके बदले सरकार इम्पीरियल बैंक के पास अपना रुपया बिना सूद के रखती थी।

एक व्यापारिक बैंक होने के नाते इम्पीरियल बैंक वह सभी कार्य करता था जो कि एक व्यापारिक बैंक करता है। इम्पीरियल बैंक भारतवर्ष में डिपॉजिट ले सकता है और ऋण ले सकता था किन्तु देश के बाहर वह न तो डिपॉजिट ले सकता था और न ऋण ही ले सकता था। केवल लन्दन ब्रांच को यह अधिकार था कि वह प्रेसीडेंसी बैंकों के पुराने ग्राहकों से डिपॉजिट ग्रहण कर सकता था और बैंक की सम्पत्ति या लेनी-देनी (Assets) की जमानत पर बैंक के कारबार के लिए ऋण ले सकता था। इम्पीरियल बैंक अपना रुपया कहीं लगावे इस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए थे। इम्पीरियल बैंक केवल ट्रस्टी सिक्यूरिटियों में रुपया लगा सकता था। उदाहरण के लिए भारत सरकार

तथा ब्रिटिश सरकार की सिक्कूरिटियों में, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सिक्कूरिटियों में, अधिकृत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सिक्कूरिटियों तथा डिपॉजिटो में ही इम्पीरियल बैंक अपना रुपया लगा सकता था। इम्पीरियल बैंक ऊपर लिखी सिक्कूरिटियों की जमानत पर श्रृणु दे सकता था। इम्पीरियल बैंक विलों और प्रामिसरी नोटों को स्वीकार कर सकता था तथा माल अथवा उनके प्रलेखों (Document) को यदि वे बैंक में जमा कर दिये गये हों अथवा बैंक के नाम कर दिये हों तो उन्हें जमानत के रूप में स्वीकार करके श्रृणु दे सकता था। किन्तु ६ महीने से अधिक के लिये श्रृणु नहीं दे सकता था और न किसी ऐसे विनिमय साध्य पुर्जों (Negotiable Instrument) को ही स्वीकार कर सकता था जिस पर दो व्यक्तियों तथा दो फर्मों के हस्ताक्षर न हों (जो आपस में साझेदार न हों) और जिनके पकने की अवधि ६ महीने से अधिक हो। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या फर्म को कितना श्रृणु अधिक से अधिक दिया जा सकता है वह भी निर्धारित कर दिया गया था। इम्पीरियल बैंक केवल उन विलों तथा अन्य विनिमय साध्य पुर्जों को लिख सकता था, भुना सकता था और स्वीकार कर सकता था जिनका कि भारत में या लंका में भुगतान होने वाला हो। किन्तु कानून द्वारा इम्पीरियल बैंक को 'विदेशी विनिमय' (Foreign Exchange) का कार्य करने की मनाही थी। इम्पीरियल बैंक किसी ऐसे विल इत्यादि को भुना भी नहीं सकता था कि जिसकी अवधि ६ महीने से अधिक हो और न किसी ऐसी विनिमय साध्य सिक्कूरिट्री (प्रतिभूति) को ही खरीद सकता था जिसकी अवधि ६ महीने से अधिक हो। बैंक सिक्कूरिट्रियों, जेवर तथा सोना इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए ले सकता था, सोना खरीद और बेच सकता था तथा ग्राहकों के लिए सिक्कूरिट्रियों की खरीद बिक्री कर सकता था तथा उन पर ग्राहकों के लिए लाभ और सूद वसूल कर सकता था।

१९३४ में रिज़र्व बैंक की स्थापना होने के उपरान्त अब इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंक नहीं रहा। ऊपर लिखे प्रतिबन्ध इम्पीरियल बैंक पर इस लिए लगाये गये थे क्योंकि वह सरकार का बैंक था और सरकार का रुपया उसके पास रहता था, किन्तु रिज़र्व बैंक की स्थापना के उपरान्त जब वह सरकार का बैंक नहीं रहा तो इम्पीरियल बैंक पर सरकार का जो नियंत्रण था और उसके कार्यों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे उसको ढीला कर दिया गया।

१९३४ के इम्पीरियल बैंक ऐक्ट के अनुसार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्यों

में से सरकार अब केवल २ सदस्यों को जो गैर-सरकारी कर्मचारी न हो मनोनीत कर सकती है। इनके अतिरिक्त सरकार एक सरकारी अफसर को भी मनोनीत कर सकती है जो कि बोर्ड की मीटिंगों में जा सकता है किन्तु वोट नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को केवल इतना अधिकार और है कि वह चाहे तो आडिटर नियुक्त करे जो बैंक के हिसाब की जाँच करके उसे रिपोर्ट दें।

केन्द्रीय बोर्ड के १६ सदस्य नीचे लिखे अनुसार हैं।

१ मैनेजिंग डायरेक्टर

१ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर

२ सरकार द्वारा मनोनीत किए हुए सदस्य

६ स्थानीय बोर्डों के समापति और उपसमापति

३ स्थानीय बोर्डों के मंत्री

१९३४ के ऐक्ट के अनुसार सरकार का जो इम्पीरियल बैंक के प्रबन्ध पर जो प्रभाव और नियंत्रण था वह दूर कर दिया गया। इसी प्रकार उसके कार्य पर जो प्रतिबन्ध लगाये गए थे वे भी हटा दिए गए। अब इम्पीरियल बैंक भारत के बाहर भी डिपॉजिट ले सकता है तथा ऋण प्राप्त कर सकता है। इम्पीरियल बैंक अब विदेशी विनिमय के काम को कर सकता है तथा विदेशी विलों को खरीद सकता है तथा भुना सकता है और बँच सकता है। पहले इम्पीरियल बैंक ऊपर लिखे कार्य नहीं कर सकता था। पहले इम्पीरियल बैंक ६ महीने से अधिक के लिए न तो ऋण ही दे सकता था और न ६ महीने की अवधि से अधिक की अवधि वाले विलों को भुना या खरीद सकता था किन्तु अब खेती के धन्ये को आर्थिक सहायता देने के लिये ६ महीने तक के लिए ऋण दे सकता है अथवा सहकारी बैंक के पत्र (Co-operative paper) स्वीकार कर सकता है। जिन सिक्यूरिटियों (प्रतिभूति) के विरुद्ध इम्पीरियल बैंक पहले ऋण दे सकता था उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अब बैंक कम्पनियों के डिर्वेचरों की जमानत पर बंधक रखे हुए माल पर, (न कि केवल उस माल पर जो कि बैंक के पास जमा कर दिया जावे) म्युनिस्पैलिटियों द्वारा निकाले हुए डिर्वेचरों या अन्य सिक्यूरिटियों पर तथा रिजर्व बैंक के हिस्सों की जमानत पर भी ऋण दे सकता है। अब भी पहले की कुछ रूकावटें इम्पीरियल बैंक पर लागू हैं। उदाहरण के लिए बैंक अपने हिस्सों की जमानत

पर, अचल सम्पत्ति की जमानत या बन्धक पर अथवा ऐसे विनिमय साध्य पुर्जों (Negotiable Instrument) पर जिस पर कम से कम दो स्वतंत्र व्यक्तियों अथवा पक्षों के हस्ताक्षर न हों, जो कि आपस में साझेदार भी न हों, श्रृण्व नहीं दे सकता। इम्पीरियल बैंक अधिक से अधिक कितना श्रृण्व किसी एक व्यक्ति को अथवा पक्षों को देगा यह अब भी कानून द्वारा सीमित है।

ऊपर लिखे प्रतिबन्धों को लगाने की आवश्यकता इस कारण पड़ी क्योंकि इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक का एकमात्र एजेंट है और जहाँ रिजर्व बैंक की प्रांच नहीं है वहाँ इम्पीरियल बैंक ही सरकारी खजाने का काम करता है तथा कोष को रखता है। इसके अतिरिक्त इम्पीरियल बैंक की यह भी जिम्मेदारी है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इम्पीरियल बैंक की जितनी प्रांचें थी कम से कम उतनी प्रांचें अधश्य बनाये रखें। रिजर्व बैंक के एकमात्र एजेंट का काम करने के लिए १५ वर्ष के लिए इफ्तारनामा किया गया है और इम्पीरियल बैंक को उस कार्य के लिये एक निर्धारित रकम कमीशन के रूप में दी जाती है।

इम्पीरियल बैंक की विशेषता :—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि भारतीय बैंकों में इम्पीरियल बैंक एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। १९३४ तक तो यह कुछ कार्य केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के भी करता था। इसके अतिरिक्त उसके साधन भी अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इम्पीरियल बैंक की डिपॉजिट सभी विनिमय बैंकों (Exchange Banks) तथा भारत के मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) से अधिक थी। नीचे हम भारत के भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों की डिपॉजिट की तालिका देते हैं जिससे इम्पीरियल बैंक का महत्व स्पष्ट है।

बैंकों की डिपॉजिट

००० रु० में

रिजर्व बैंक	इम्पीरियल बैंक	एम्सबैंक बैंक	मिश्रित पूँजी वाले बैंक
१९३३ ..	८०,१६,८८	७०,७८,४२	७६,४२,२७
१९३४ ...	८१,००,१५	७१,३९,९७	८१,८८,३८
१९३६ २२,२८,४४	७८,७९,५०	७५,२२,५५	१०३,६०,६७
१९३७ ३१,१९,१३	८१,०८,०७	७३,२१,०१	१०८,५५,३९

१६३८ २४,२०,३३ . ८१,५०,६५ ६७,२०,४२ १०६,०८,६६
 १६४० ६५,७६,०० ६६,०३,१७ ८५,५७,४७ १२५,०२,४१ .
 १६४८—

वर्तमान स्थिति :—यद्यपि इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंकर नहीं रहा किन्तु फिर भी उसका भारतीय द्रव्य बाजार (Money Market) में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब भी वह बहुत अधिक डिपॉजिट आकर्षित करता है। इम्पीरियल बैंक के ऊपर से प्रतिवन्धों के उठ जाने से वह आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार को अधिकाधिक सहायता प्रदान कर सकेगा। किन्तु भारतीय व्यापारियों को उसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें हैं। इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध भारतीयों का सबसे अधिक गम्भीर आरोप यह है कि उसका संचालन मुख्यतः विदेशियों के हाथ में है और वे भारतीयों के साथ सहानुभूति का व्यवहार नहीं करते। यदि कोई भारतीय व्यापारी या फर्म उनसे आर्थिक सहायता माँगता है तो उसे कठिनाई होती है किन्तु अंग्रेजों को आर्थिक सहायता आसानी से मिल जाती है। इम्पीरियल बैंक के अधिकांश उच्च अधिकारी विदेशी हैं इस कारण भारतीयों को इम्पीरियल बैंक से इस प्रकार की शिकायत रही है। यही नह '१६३४ के पूर्व भारतीय व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) को यह भी शिकायत थी कि इम्पीरियल बैंक यद्यपि एक केन्द्रीय बैंक (Central Banks) है परन्तु वह अन्य बैंकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा करता है। आज भी उनको यह शिकायत है कि रिज़र्व बैंक के एकमात्र एजेंट होने के नाते उसे जो प्रतिष्ठा मिली हुई है उसके कारण वह अन्य बैंकों की उन्नति में एक रुकावट उत्पन्न करता है। भारतीय बैंकों की यह माँग है कि केवल इम्पीरियल बैंक को रिज़र्व बैंक का एकमात्र एजेंट बना देना उचित नहीं है। जितने बड़े और सुदृढ़ बैंक हैं उन सभी को यह प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिये।

इम्पीरियल बैंक की स्थिति को बताने के लिए हम यहाँ उसका लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) देते हैं :—

२ जनवरी को इम्पीरियल बैंक की लेनी-देनी का लेखा
 (Balance Sheet)

देनी (Liabilities)

अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) २२५,००० हिस्से, प्रत्येक
 हिस्सा ५०० रु० का ११,२५,००,०००

दूसरा कारण यह था कि यदि इम्पीरियल बैंक रिज़र्व बैंक बना दिया जाता तो उसके लाभ को कानून के द्वारा सीमित कर दिया जाता जो कि इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदार कभी भी पसंद न करते । पिछले दिनों इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की चर्चा चल रही है । एक बार तो सरकार ने भी ऐसा संकेत किया था कि इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा ।

अध्याय—१८

रिज़र्व बैंक आव इंडिया

भारतवर्ष में एक केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी किन्तु भारत सरकार ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। १९१३ में जब भारत की करंसी के सम्बन्ध में जांच करने के लिए 'चेम्बरलेन कमीशन' बिठाया गया उस समय श्रीयुत कीन्त महोदय ने एक केन्द्रीय बैंक की योजना उपस्थित की जो कि चेम्बरलेन रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुई किन्तु भारत सरकार ने उसकी ओर ध्यान तक न दिया। १९१४-१८ के महायुद्ध में सभी को केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव हुआ। किन्तु जब १९२० में ब्रुसल्स अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सम्मेलन ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि "जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ भी शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होना चाहिए" तब कहीं भारत सरकार का ध्यान उधर गया। अतएव १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। किन्तु इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं करता था इस कारण एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता होने लगी। जब १९२६ में हिल्टन यंग कमीशन बैठा तो यह समस्या उसके सामने भी उपस्थित हुई। देश में कुछ विद्वानों का मत था कि इम्पीरियल बैंक को ही भारत का केन्द्रीय बैंक बना देना चाहिए किन्तु कुछ उसके विरुद्ध थे। हिल्टन यंग कमीशन ने इस प्रश्न का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया और एक स्वतंत्र हिस्तेदारों के केन्द्रीय बैंक की स्थापना का समर्थन किया।

जिन कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने की सम्मति दी वे निम्नलिखित हैं :—

(१) इम्पीरियल बैंक के पास यथेष्ट पूँजी और डिपॉजिट हैं और उसकी सैकड़ों शाखायें भारत भर में फैली हुई हैं। भारत जैसे देश में जहाँ बैंकिंग की सुविधायें नहीं के बराबर हैं यदि इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बना दिया गया तो उसको अपनी शाखाओं को बन्द करना होगा। इससे भारतीय व्यापार को गहरा धक्का लगेगा। आवश्यकता तो इस बात की है कि इम्पीरियल बैंक को बन्धनों से मुक्त कर दिया जावे और उसे एक सुदृढ़ और महान्

व्यापारिक बैंक के रूप में देश की सेवा करने दी जावे। इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक भी बना दिया जावे और व्यापारिक बैंकिंग भी करता रहे यह नहीं हो सकता। क्योंकि यदि इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकिंग करेगा तो अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्द्धा करेगा जो कि अनुचित होगा। क्योंकि केन्द्रीय बैंक के पास राज्य की िना सूद की डिपॉजिट रहेगी और उसके पास इतने विशेष अधिकार रहेंगे कि उसका अन्य बैंकों से होड़ करने देना सर्वथा अन्यायपूर्ण होगा। साथ ही केन्द्रीय बैंक को जायज़ी मुद्रा निकालने का एकाधिकार दिया जावेगा अतएव उसे व्यापारिक बैंकिंग के खतरे से न उठाना चाहिये।

(२) इम्पीरियल बैंक को भारतीय व्यापारिक बैंक अपने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखते रहे हैं क्योंकि यह भारतीय बैंकों से द्रव्य बाज़ार में प्रतिद्वन्द्विता करता रहा है अतएव उसका केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं है। केन्द्रीय बैंक को सभी अन्य बैंकों का नेतृत्व करना होगा। अस्तु किसी ऐसे बैंक को जिसे अन्य बैंक अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते रहे हैं केन्द्रीय बैंक बनाना उचित न होगा।

(३) इम्पीरियल बैंक के प्रति भारतीय व्यापारियों, देशी बैंकों तथा भारतीय व्यापारिक बैंकों की अच्छी धारणा नहीं है। उनका कहना है कि इम्पीरियल बैंक की नीति अभावी है। अंग्रेज व्यापारियों तथा अंग्रेजों द्वारा संचालित बैंक के साथ उसका व्यवहार नरम, सहानुभूतिपूर्ण और उदार होता है और भारतीयों के साथ अनुदारपूर्ण होता है। हिल्टन यंग कमीशन का मत था कि जिस बैंक के प्रति देश में ऐसी धारणा हो वह केन्द्रीय बैंक के उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से न निवाह सकेगा।

(४) कमीशन की यह भी राय थी कि हिस्सेदार भी इस परिवर्तन को पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि यदि इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक बना दिया जावेगा तो सरकार को कानून के द्वारा उसके लाभ को मर्यादित कर देना होगा, हिस्सेदारों को ४ प्रतिशत के लगभग लाभ मिल सरेगा जिसे इम्पीरियल बैंक के हिस्सेदार कभी फसद न करेंगे क्योंकि उन्हें अभी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना का समर्थन किया। कमीशन ने केवल एक स्वतंत्र संस्था के स्थापित किये जाने का ही समर्थन नहीं किया बल्कि उसने इस बात का भी समर्थन किया कि रिज़र्व बैंक राज्य का न होकर हिस्सेदारों का होना चाहिये।

हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने एक बिल

केन्द्रीय धारा सभा (Central Legislative Assembly) में उपस्थित किया। इस बिल में एक हिस्सेदार के रिज़र्व बैंक की स्थापना की व्यवस्था थी और उसके संचालक बोर्ड में हिस्सेदारों द्वारा चुने हुए डायरेक्टरों का बहुमत था और बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर के सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने का विधान था। किन्तु सेलेक्ट कमेटी ने उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। उसमें विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन यह था कि बैंक हिस्सेदारों का न होकर सरकार का होगा। एक स्थिति में सरकार इस परिवर्तन के लिए तैयार हो गई थी किन्तु प्रेसीडेंट ने नये बिल को उपस्थित करने की आज्ञा नहीं दी और सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया। अस्तु उस समय भारत में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित न हो सका। किन्तु जब भारत में नवीन शासन सुधार की योजना तैयार हुई और भारत में संघीय सरकार (Federal Government) की स्थापना का आयोजन होने लगा जो संघीय धारा सभा के लिए उत्तरदायी होती तो एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता हुई जो कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) को निकालने का प्रयत्न करे। अतएव १९३४ में रिज़र्व बैंक ऐक्ट पास हुआ और उसको हिस्सेदारों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया। रिज़र्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक होना चाहिए अथवा राज्य का, इस सम्बन्ध में भारत में बहुत वाद-विवाद चला अस्तु हम यहाँ दोनों पक्षों का मत देंगे।

बैंक हिस्सेदारों का हो अथवा राज्य का हो :—जिन लोगों का कहना था कि बैंक राज्य का होना चाहिए वे नीचे लिखे तर्क उपस्थित करते थे :—

(१) रिज़र्व बैंक को इतने अधिक अधिकार दिये गए हैं कि यदि बैंक पर पूँजीपतियों का प्रभाव हो गया तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे जिससे देश के आर्थिक हितों को धक्का पहुँचेगा। यदि बैंक हिस्सेदारों का रहा तो पूँजीपतियों का उस पर प्रभाव हो जाना स्वाभाविक है अस्तु ऐसा करना खतरनाक है।

(२) क्योंकि बैंक कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) निकालेगा तथा राज्य के कोष (Funds) अपने पास रखेगा अतएव उसको बहुत अधिक लाभ होगा। यह लाभ देश के लाभ के लिए राज्य को मिलना चाहिए न कि हिस्सेदारों को।

(३) भारत में राज्य अधिकांश रेलों, पोस्ट आफिस इत्यादि का प्रबन्ध

करता है। लोगों को राज्य के प्रबन्ध में अधिक विश्वास है और पूँजीपतियों के प्रबन्ध को वे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं।

(४) रिजर्व बैंक के कार्य ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि राज्य को उसे अपने नियन्त्रण में रखना ही होगा अतः उसे राज्य का बैंक ही क्यों न बना दिया जावे।

(५) जिन देशों में केन्द्रीय बैंक हिस्सेदारों की संस्था है वहाँ भी उसका गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर इत्यादि सरकार ही नियुक्त करती तथा बैंक के नीति के निर्धारण में उसका प्रमुख हाथ रहता है। कहना इस प्रकार चाहिए कि राज्य ही बैंक की नीति निर्धारित करता है। देखी दशा में हिस्सेदारों का बैंक स्थापित करने का अर्थ नहीं होता।

(६) इस बात का भय है कि हिस्सेदारों का बैंक योरोपियों के प्रभाव में आ जावेगा और इससे भारतीयों के हितों की उपेक्षा होगी।

तत्कालीन केन्द्रीय धारा सभा का यह भी विचार था कि बैंक केवल राज्य का ही न हो वरन् उसके संचालन बोर्ड में कुछ डायरेक्टर धारा सभा के चुने हुए सदस्य होने चाहिए। क्योंकि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है अतः जनता के चुने हुए डायरेक्टर बोर्ड में होने चाहिये।

इसके विरुद्ध जो विद्वान् हिस्सेदारों के बैंक के पक्ष में थे उनके नीचे लिखे तर्क थे :—

(१) संसार में जितने केन्द्रीय बैंक हैं उनमें से कुछ को छोड़कर सभी हिस्सेदारों के बैंक हैं।

(२) देश के आर्थिक हितों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक पर कोई राजनैतिक प्रभाव न हो और वह अपने कार्यों को बुद्धिपूर्वक रूप से कर सके।

(३) हिस्सेदारों के बैंक में पूँजीपतियों के प्रभाव बढ़ जाने का जो भय है उसको ऐसा नियम बनाकर कि एक व्यक्ति अधिक हिस्से न खरीद सके दूर किया जा सकता है। रहा लाभ का प्रश्न वह तो कानून द्वारा सीमित कर दिया जावेगा और अधिकतर लाभ राज्य को मिलेगा।

ऊपर लिखे कारणों को अधिक महत्व देते हुए रिजर्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक बनाया गया। यद्यपि आज प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों के

राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) की भाँति हो रही है और बैंक आन इंगलैंड जो संसार का सब से पुराना- हिस्सेदारों का बैंक था उसको इंगलैंड की सरकार ने ले लिया। पिछले दिनों भारत में भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सरकार रिज़र्व बैंक को ले ले।

रिज़र्व बैंक का विधान :—यह तो हम ऊपर ही कह चुके हैं कि रिज़र्व बैंक हिस्सेदारों का बैंक है। बैंक की हिस्सा पूँजी (Share-Capital) ५ करोड़ रुपये है। प्रत्येक हिस्सा १०० रु० का है जो कि पूरा चुका दिया गया है। इस उद्देश्य से कि बैंक पर किसी एक प्रवेश का प्रभाव न हो जावे भारत को पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया और हिस्सेदारों के पाँच रजिस्टर खोले गए। भिन्न-भिन्न रजिस्ट्रों को नीचे लीखे अनुसार हिस्सा पूँजी बाँट दी गई।

बम्बई	१४० लाख
कलकत्ता	१४५ लाख
देहली	११५ लाख
मद्रास	७० लाख
रंगून	३० लाख

इसके अतिरिक्त यह नियम भी बना दिया गया कि प्रत्येक हिस्सेदार को पाँच हिस्सों के पीछे एक मत (Vote) देने का अधिकार होगा, और किसी हिस्सेदार को दस मत (वोट) से अधिक देने का अधिकार न होगा। यह नियम इस उद्देश्य से बनाया गया था कि रिज़र्व बैंक के हिस्सों को कुछ लोग न हाथया लें। किन्तु ऊपर लिखे नियमों के रहते हुए भी रिज़र्व बैंक के हिस्से क्रमशः बम्बई रजिस्टर में अधिक बढ़ते गए। यही नहीं कि अन्य रजिस्ट्रों में हिस्से कम होते गए और बम्बई रजिस्टर में हिस्से बढ़ते गए वरन् साथ ही हिस्सेदारों का संख्या भी कम होती गई। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि रिज़र्व बैंक के हिस्से क्रमशः कुछ बड़े से हाथों में इकट्ठा होते गए। नीचे दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जावेगा।

हिस्सों का विवरण

आरम्भ में	जून ३०,	हिस्सेदारों की	जून ३०,
	१९४१	संख्या १	५ मिल, १९४०
			१२३५

बम्बई	१४० लाख रु०	२१३ लाख रु०	२८,०००	१६,०७२
कलकत्ता	१४५ " "	१२२ " "	२३,८६०	१२,२४६
देहली	११५ " "	८० " "	२३,०००	१२,८१३
मद्रास	७० " "	६० " "	१४,०००	७६७३
रंगून	३० " "	१६ " "	३१५७	१३६४

ऊपर लिखी तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि बम्बई रजिस्टर के हिस्से बढ़ते गए और अन्य रजिस्टरों के हिस्से घटते गए। यही नहीं बैंक के हिस्सेदारों की संख्या में ३० जून १९४१ तक ३८ प्रतिशत की कमी हो गई। इस प्रवृत्ति को रोक्ने के लिए मार्च १९४० में रिजर्व बैंक ऐक्ट में इस आशय का संशोधन किया गया कि यदि कोई व्यक्ति २६ मार्च १९४० के उपरान्त रिजर्व बैंक के हिस्से खरीदता है और उन हिस्सों के सहित उसके पास अपने व्यक्तिगत नाम में अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित नाम में २०,००० रु० के मूल्य के हिस्सों से अधिक हो जाते हैं तो उन अधिक खरीदे हुए हिस्सों को उसके नाम नहीं रजिस्टर किया जावेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि २६ मार्च १९४० के उपरान्त कोई भी व्यक्ति कुल मिलाकर २०,००० रु० के हिस्सों से अधिक नहीं खरीद सकेगा। किन्तु इतना होने पर भी रिजर्व बैंक के हिस्सेदारों की संख्या कम होती जा रही है और क्रमशः हिस्से कुछ हाथों में जा रहे हैं।

रिजर्व बैंक ऐक्ट में इस बात का भी विधान है कि यदि बैंक का केन्द्रीय बोर्ड चाहे तो गवर्नर जनरल तथा केन्द्रीय धारा सभा की अनुमति से बैंक की हिरा पूंजी को घटा बढ़ा सकता है।

रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार बैंक को बम्बई, कलकत्ता, देहली, मद्रास और रंगून में अपने आधिकार खोलने होने और लन्दन में एक ब्रांच स्थापित करनी होगी। बैंक ने ऊपर लिखे स्थानों पर अपने आधिकार स्थापित कर दिये थे। ऐक्ट के अनुसार बैंक को यह भी अधिकार है कि वह गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा लेकर भारत में किसी स्थान पर भी अपनी ब्रांच या एजेंसी स्थापित कर सकता है। बैंक ने कानपुर, कर्नाची तथा लाहौर में अपनी ब्रांचें स्थापित कर दी हैं तथा जहाँ जहाँ इम्पेरियल बैंक की ब्रांचें हैं वहाँ इम्पेरियल बैंक को अपना एजेंट बना दिया है। कुछ काल में जापान द्वारा बर्मा पर अधिकार होने पर रंगून का दफ्तर बन्द कर दिया गया और फिर स्थापित नहीं किया गया।

प्रबन्ध—बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथों में सौंपा गया है। उसमें १६ डायरेक्टर होते हैं। यह १६ डायरेक्टर नीचे लिखे अनुसार नियुक्त होते हैं—(१) एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नरों को गवर्नर जनरल नियुक्त करता है गवर्नर जनरल उनकी नियुक्ति करते समय इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति करता है।

(२) ४ डायरेक्टरों को गवर्नर मनोनीत करता है। यह डायरेक्टर उन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो कि साधारणतः बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं पा सकते। (उदाहरण के लिए कृषि इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले डायरेक्टर)

(३) ८ डायरेक्टर मिल-मिल रजिस्ट्रारों के हिस्सेदारों द्वारा चुने जावेंगे। बम्बई, कलकत्ता और देहली में से प्रत्येक को २ डायरेक्टर चुनने का अधिकार है और रंगून तथा मदरास को एक एक डायरेक्टर ही चुनने का अधिकार है।

(४) गवर्नर जनरल एक सरकारी कर्मचारी को बोर्ड में मनोनीत करेगा।

गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नरों को वेतन मिलता है और वे बैंक के वेतन भोगी डायरेक्टर होते हैं। वे पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं किन्तु ५ वर्ष समाप्त हो जाने पर वे फिर नियुक्त किये जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी डायरेक्टर गवर्नर जनरल की इच्छानुसार अपने पद पर रहता है। डिप्टी गवर्नर तथा सरकारी कर्मचारी डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में भाग ले सकते हैं उसकी मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु वोट नहीं दे सकते। गवर्नर की अनुपस्थिति में एक डिप्टी गवर्नर वोट दे सकता है यदि गवर्नर जनरल की लिखित आज्ञा प्राप्त कर ले। अन्य दूसरे सभी डायरेक्टर केवल पाँच वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभा का सदस्य, कोई वेतन भोगी सरकारी या देशी राज्य का कर्मचारी, किसी बैंक का नौकर या कर्मचारी, किसी बैंक का डायरेक्टर (सहकारी बैंक के डायरेक्टरों को छोड़कर) रिजर्व बैंक का डायरेक्टर या स्थानीय बोर्ड (Local Boards) का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जो कि केन्द्रीय बोर्ड का डायरेक्टर या स्थानीय बोर्ड का सदस्य

चुना गया हो या मनोनीत किया गया हो यदि रिज़र्व बैंक के ५००० रु० के हिस्सों का ६ महीने के अन्दर रजिस्टर्ड स्वामी नहीं बन जाता तो वह डायरेक्टर या सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई डायरेक्टर बिना मवनर से छुट्टी प्राप्त किये तीन लगातार मीटिंगों में अनुपस्थिति हा जाता है तो वह बैंक का डायरेक्टर नहीं रहता।

स्थानीय बोर्ड और उनका कार्य—प्रत्येक रजिस्टर का एक स्थानीय बोर्ड होगा। स्थानीय बोर्ड का संगठन इस प्रकार होगा—(१) उस रजिस्टर के हिस्सेदार अपने में से पाँच सदस्य चुनते हैं। (२) केन्द्रीय बोर्ड उस रजिस्टर के हिस्सेदारों में से अधिक से अधिक तीन सदस्यों को मनोनीत करता है। केन्द्रीय बोर्ड को अधिकार इस लिए दिया गया है कि जिससे कृषि सहकारी बैंक, तथा अन्य ऐसे हितों का स्थानीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो सके।

स्थानीय बोर्ड के दो कार्य होते हैं। एक तो वे अपने में से केन्द्रीय बोर्ड के लिये डायरेक्टर चुनते हैं और दूसरे वे केन्द्रीय बोर्ड उन बातों पर अपनी राय देते हैं कि जो उसकी सम्मति के लिये भेजी जाती हैं। स्थानीय बोर्ड के अधिकार बहुत ही सीमित हैं और उनका कोई महत्व नहीं है।

रिज़र्व बैंक के कार्य

रिज़र्व बैंक के व्यापारिक कार्य—रिज़र्व बैंक नीचे लिखे व्यापारिक कार्य कर सकता है।

(१) रिज़र्व बैंक बिना सूद की डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। रिज़र्व बैंक पर सूद न दे सकने का प्रतिबंध इस कारण लगाया गया कि वह व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा न कर सकें।

(२) रिज़र्व बैंक ऐसे बिलों (Bills) को वांछान्वित व्यापारिक व्यवहारों (Commercial Transactions) के कारण उत्पन्न हुए हों, जिन पर दो अन्धे हस्ताक्षर हों उनमें से एक हस्ताक्षर कितो सिड्डल (Schedule) बैंक का होना आवश्यक है, और जिनके चलन की अवधि ६० दिन से अधिक न हो, और जो भारत पर काटे गए हों और जिनका मुग्तान भारत में होना चाहता हो खरीद या बँच सकता है अथवा उन्हें पुनः मुग्तान करता है।

इसका परिणाम यह होगा कि रिज़र्व बैंक रुपयों में काटे गए लिखे गये आयात बिल (Rupee Import Bills) को मुग्तान करेगा जब कि इस

प्रकार के विलों का आयात व्यापार (Import Trade) में चलन होने लगेगा ।

यदि इस प्रकार के विल या प्रामिसरी नोट कृषि के धंधे के लिए लिखे गए हों या फसलों की बिक्री का प्रबंध करने के लिए काटे गए हों तो उनके चलन की अवधि अधिक से अधिक ६ महीने हो सकती है । इन विलों पर भी दो अच्छे हस्ताक्षरों की आवश्यकता है और उसमें से एक हस्ताक्षर था तो किसी शिडल बैंक अथवा प्रान्तीय सरकारी बैंक का होना चाहिए । इस प्रकार के विलों को रिज़र्व बैंक पुनः भुना सकता है ।

(३) रिज़र्व बैंक ऐसे विलों को जो कि यूनाइटेड किंगडम में अथवा वहाँ किसी स्थान पर काटे गए हों और जिनकी पकने की अवधि ६० दिन से अधिक न हो खरीद, बेच और भुना सकता है । किन्तु यह कार्य वह किसी शिडल बैंक के द्वारा ही कर सकता है ।

(४) भारत में शिडल बैंकों से स्टर्लिंग खरीदने और उन्हें स्टर्लिंग बेचने का भी काम रिज़र्व बैंक कर सकता है ।

(५) रिज़र्व बैंक देशी राज्यों, स्थानीय शासन संस्थाओं (म्युनिस्पैलटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि), शिडल बैंकों, प्रान्तीय सहकारी बैंकों को ऋण दे सकता है किन्तु इस प्रकार का ऋण अधिक से अधिक ६० दिन के लिए दिया जा सकता है । किन्तु स्टॉक, कोष (Funds) या सिक्यूरिटी (अचल सम्पत्ति को छोड़ कर) की जमानत पर ही मिल सकता है । जो भी सिक्यूरिटी ट्रस्टी सिक्यूरिटी है उस सिक्यूरिटी के विरुद्ध रिज़र्व बैंक ऋण दे सकता है । इसके अतिरिक्त सोना या चाँदी अथवा उन विलों की जमानत पर भी ऋण दिया जा सकता है कि जिन्हें रिज़र्व बैंक खरीद या भुना सकता है । किसी शिडल बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के प्रामिसरी नोट पर भी रिज़र्व बैंक ऋण दे सकता है यदि वह वास्तव में व्यापारिक व्यवहारों (Commercial Transaction) के लिए लिया जावे ।

(६) रिज़र्व बैंक केन्द्रिय तथा प्रान्तीय सरकारों को तीन महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता ।

(७) रिज़र्व बैंक यूनाइटेड किंगडम की उन सिक्यूरिटियों की खरीद बिक्री कर सकता है जो कि खरीदने की तारीख से १० वर्षों के अन्दर पक जावे । भारत सरकार या प्रान्तीय सरकार की किसी प्रकार की सिक्यूरिटी

चाहे उसके पन्ने की अवधि कितनी ही क्यों न हो रिजर्व बैंक खरीद या बेच सकता है। देशी राज्यों अथवा स्थानीय शासन संस्थाओं में से केवल उनकी ही सिम्बूरियो रिजर्व बैंक खरीद या बेच सकता है। इनकी गवरनर जनरल बैंक के बोर्ड की विचारण पर स्वीकृति दे।

(८) रिजर्व बैंक अपनी पूँजी से अधिक ऋण नहीं ले सकता। और वह भी एक महीने से अधिक के लिए नहीं। ऋण केवल किसी सिङ्गल बैंक से अथवा किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक (Central Bank) से लिया जा सकता है।

(९) कुछ दशाओं में बैंक को सीधे खुले बाजार में ६० दिन के बिन मुनामे, तथा ३० दिन के लिए ऋण देने का अधिकार दे दिया गया है अर्थात् बैंक कुछ दशाओं में बिना किसी सिङ्गल बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के हस्ताक्षरों के ही ऋण दे सकता है या बिलों को भुना सकता है। इसे बैंक की खुले बाजार की क्रिया (Open Market Operations) कहते हैं।

वह व्यापार कार्य जो कि बैंक नहीं कर सकता

(१) बैंक किसी व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य को नहीं कर सकता। अर्थात् व्यापार तथा व्यवसाय में दिलचस्पी नहीं ले सकता और न आर्थिक सहायता दे सकता है।

(२) वह अपने हिस्सों या अन्य किसी बैंक या कंपनी के हिस्से नहीं खरीद सकता और न उन हिस्सों की जमानत पर ऋण ही दे सकता है।

(३) वह किसी अचल सम्पत्ति को देहन रखकर ऋण नहीं दे सकता और न अचल सम्पत्ति को खरोद ही सकता है। केवल अपने काम के लिए जो भी इमारत इत्यादि की आवश्यकता हो उसे अवश्य खरीद सकता है।

(४) बैंक अरक्षित (Unsecured) ऋण नहीं दे सकता।

(५) वह मुहूर्ती जमा (Deposits) का चालू खाते (Current Account) पर कोई मुद्द नहीं दे सकता।

(६) वह ऐसे बिलों को न काट सकता है और न स्वीकार ही कर सकता है कि जिनका माँगने पर मुगवान न हो।

ऊपर लिखे व्यापारिक कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक को भारत के

केन्द्रीय बैंक (Central Bank) होने के नाते और बहुत से महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए गए हैं। वे नीचे लिखे हैं।

कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) को निकालने का एकाधिकार

रिज़र्व बैंक को कागज़ी मुद्रा निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। रिज़र्व बैंक की स्थापना के उपरान्त सरकार का कागज़ी मुद्रा निकालने का अधिकार समाप्त हो गया। रिज़र्व बैंक के नोट कानूनी माध्य (Legal Tender) हैं और गवर्नर जनरल उनकी गारंटी करता है। भारत सरकार के पुराने नोट रिज़र्व बैंक ने ले लिए फिर उन्हें अपने नोटों के रूप में चलाया। जनवरी १९३८ में सबसे पहले रिज़र्व बैंक के नोट निकाले गए। रिज़र्व बैंक पर अपने नोटों को रुपयों में बदलने का कानूनी उत्तरदायित्व है। रिज़र्व बैंक पाँच रुपये, दस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पाँच सौ रुपये, एक हजार रुपये, और दस हजार रुपये के नोट निकाल सकता है।

कागज़ी मुद्रा निकालने का काम बैंक का नोट विभाग (Issue Department) करता है। नोट विभाग (Issue Department) को बैंकिंग विभाग (Banking Department) से सर्वथा पृथक् रखा जाता है। भारत में यह विभाजन अनावश्यक है। यह विभाजन बैंक आव इङ्गलैंड के आधार पर किया गया था। किन्तु बैंक आव इङ्गलैंड में यह विभाजन इस लिए आवश्यक था क्योंकि वहाँ नोट विभाग में होने वाला लाभ तो सरकार को जाता था और बैंकिंग विभाग का लाभ हिस्सेदारों को मिलता था। किन्तु भारत में तो कानून द्वारा निर्धारित (४ प्रतिशत) से अधिक लाभ सरकार को मिलता है इस कारण यह विभाजन अनावश्यक है। इस विभाजन से हानि यह है कि बैंक की लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) दो डुकड़ों में विभक्त हो जाता है।

जहाँ तक कागज़ी मुद्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कोष (Reserves) रखने का प्रश्न है रिज़र्व बैंक ऐक्ट के अनुसार ४० प्रतिशत सोने के सिक्के, सोने के पाटों अथवा स्टर्लिंग के रूप में होना चाहिए और शेष रुपयों तथा सरकारी सिक्यूरिटियों तथा स्वीकृत व्यापारिक पत्रों (Eligible Paper) के रूप में होना चाहिये।

सरकार का बैंकिंग कार्य—नोट निकालने के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक सरकार के बैंकर का कार्य भी करता है। वह सरकार की ओर से रुपये का

भुगतान करता है और सरकार का रुग्ण स्वीकार करता है। सरकार की विदेशी देनी को सुझाना पड़ता है। सरकारी रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है तथा अन्य बैंकिंग कार्य करने पड़ने हैं। जब सरकार व्यय सेती है तो इन व्ययों को रिज़र्व बैंक ही निकालता है और वही उनका प्रबन्ध करता है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का नकद व्यय बैंक के पास ही बिना सूची डिपॉजिट के रूप में रहता है। बैंक को यह कार्य मुफ्त में नहीं करने पड़ते।

रिज़र्व बैंक का यह भी कार्य है कि वह रुपये की विनिमय दर (Exchange Rates) को स्थिर रखे। इसी उद्देश्य को लेकर रिज़र्व बैंक को कानून द्वारा विवश कर दिया गया है कि वह अधिक से अधिक १ शि० ६५/४ पे० प्रति रुपये के दिसाय से स्टर्लिङ्ग खरीदेगा और कम से कम १ शि० ५४/४ पे० प्रति रुपये के दिसाय से स्टर्लिङ्ग बेचेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी के पास स्टर्लिङ्ग है और वह उनके रुपये करना चाहता है तो वह रिज़र्व बैंक को ऊपर लिखी दर पर स्टर्लिङ्ग बैंक सकता है। रिज़र्व बैंक को उसके स्टर्लिङ्ग खरीदने होंगे और यदि किसी व्यक्ति को स्टर्लिङ्ग की आवश्यकता है तो उपरोक्त दर पर स्टर्लिङ्ग खरीद सकता है। रिज़र्व बैंक को उसे स्टर्लिङ्ग बेचने होंगे।

रिज़र्व बैंक की अन्य विशेषताएँ :—यह तो हम ऊपर ही कह आये हैं कि रिज़र्व बैंक की प्रथम विशेषता यह है कि वह दो विभागों में विभक्त है (१) नोट विभाग (Issue Department) और वृत्तरा बैंकिंग विभाग (Banking Department) इन दोनों विभागों के सम्बन्ध में आगे लिखेंगे। इस विशेषता के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक की नीचे लिखी विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं।

✓(१) कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department).

रिज़र्व बैंक ऐक्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक को बाधित रूप से एक कृषि साख विभाग स्थापित करना पड़ा है। इस विभाग के नीचे निम्ने कार्य हैं : कृषि साख के सम्बन्ध में सौज करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर कृषि साख के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए कृषि साख के विशेषज्ञों को नियुक्त करना। जब कभी भारत सरकार, प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों को कृषि साख के सम्बन्ध में कुछ परामर्श लेना होता है तो वे रिज़र्व बैंक के कृषि साख विभाग, रिज़र्व बैंक तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्धों को निर्धारित

करता है और रिज़र्व बैंक की कृषि साख नीति (Agricultural Credit Policy) को निर्धारित करता है। रिज़र्व बैंक और सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) का आपस में क्या सम्बन्ध है इसका विवेचन हम सहकारी बैंकों के परिच्छेद में कर चुके हैं।

(२) रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल बैंक का सम्बन्ध—

रिज़र्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक को अपना एक मात्र एजेंट (Sole Agent) बना दिया है। रिज़र्व बैंक ऐक्ट में इसका विधान है। जो समझौता हुआ है उसके अनुसार १५ वर्षों के लिए इम्पीरियल बैंक को रिज़र्व बैंक का एक मात्र एजेंट बना दिया गया है। जहाँ जहाँ इम्पीरियल बैंक की शाखा है और रिज़र्व बैंक की शाखा नहीं है वहाँ वहाँ इम्पीरियल बैंक रिज़र्व बैंक के एजेंट का कार्य करता है।

इस सेवा के उपलक्ष्य में रिज़र्व बैंक इम्पीरियल बैंक को नीचे लिखे अनुसार कमीशन देगा। पहले दस वर्षों में २५० करोड़ रुपये तक एक प्रतिशत का मोलहवा भाग अर्थात् सौ रुपये पर एक आना और २५० करोड़ रुपये के उपरान्त शेष पर एक प्रतिशत का बचीसवां भाग कमीशन दिया जावेगा अर्थात् सौ रुपये पर दो पैसा। इम्पीरियल बैंक रिज़र्व बैंक के एजेंट की हैसियत से जितना सरकारी काम करेगा उस पर यह कमीशन दिया जावेगा। दस वर्षों के उपरान्त हम कार्य के करने में इम्पीरियल बैंक का जो व्यय होगा वह दिया जावेगा। इन अवधि के उपरान्त पांच वर्षों के लिए समझौता होगा और कोई भी पक्ष पांच वर्ष की सूचना देकर समझौते को भंग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यदि इम्पीरियल बैंक की जितनी शाखाएँ रिज़र्व बैंक ऐक्ट के लागू होने पर खुली हुई थीं कम से कम उतनी शाखाएँ खोले रखता है तो पहले पांच वर्षों में ६ लाख वार्षिक दूसरे पांच वर्षों में ६ लाख वार्षिक और तीसरे पांच वर्षों में ४ लाख वार्षिक रुपये रिज़र्व बैंक इम्पीरियल बैंक को देगा।

शिड्यूल बैंकों की डिपॉजिट—जिस बैंक की चुकता पूँजी (Paid up Capital) और सुरक्षित कोष (Reserves) पांच लाख रुपये से अधिक हो वह रिज़र्व बैंक ऐक्ट की दूसरी शिड्यूल में सम्मिलित किया जा सकता है अर्थात् शिड्यूल बैंक बन सकता है। रिज़र्व बैंक साख (Credit) पर नियन्त्रण स्थापित कर सके इस उद्देश्य से प्रत्येक शिड्यूल बैंक को अपनी

चालू जमा (Current Deposits) का पाँच प्रतिशत और मुदती जमा (Fixed Deposits) का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। यदि कोई सिङ्गल बैंक इस शर्त को पूरा न करे तो उसको दब देना पड़ता है। निर्धारित प्रतिशत से जिस बैंक का रिजर्व बैंक के पास कम हो रहा है उसका कमी पर प्रचलित रिजर्व-बैंक रेट से प्रतिशत अधिक सूर देना पड़ेगा। और यदि सिङ्गल-बैंक अगला लेखा (Return) भेजने के दिन तक उस कमी का पूरा न कर सके तो बैंक रेट से कमी पर पाँच प्रतिशत अधिक सूर देना होगा। यदि उसके आगे लेखा भेजने के दिन तक यह कमी पूरी न हो तो रिजर्व बैंक प्रति दिन ५०० रु० जुर्माना कर सकता है और उस बैंक को और अधिक जनता से डिमाजिट लेने की मनाही कर सकता है। प्रत्येक सिङ्गल बैंक को प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक को एक लेखा (Return) भेजना पड़ता है जिसमें नीचे लिखी बातों का उल्लेख रहता है। (१) बैंक की चालू जमा (Current Deposit) और मुदती जमा (Fixed Deposit) (२) बैंक के पास कितने मूल्य के नोट हैं। (३) बैंक के पास कितने दाये और छाटे सिक्के हैं। (४) बैंक ने कितना ऋण दिया है और कितने मूल्य के बिल भुनाये हैं। (५) बैंक का कितना रुपया रिजर्व बैंक में जमा है। इस लेखे का न भेजने पर प्रति दिन १०० रु० के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है।

✓ **रिजर्व बैंक का लाभ और रक्षित कोष :**—रिजर्व बैंक ऐक्ट में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि रिजर्व बैंक अपने हिस्सेदारों को अधिक से अधिक ५ प्रतिशत लाभ दे सकता है किन्तु लाभ कितना बाँटा जावेगा इसका निर्णय गवर्नर जनरल करेगा। आरम्भ में सरकार ने ३३ प्रतिशत लाभ बाँटने की अनुमात दी थी किन्तु १९४३ से रिजर्व बैंक अपने हिस्सेदारों को ८ प्रतिशत लाभ बाँटता है। हिस्सेदारों के बाँटने के उपरान्त जो भी लाभ शेष रहता है वह सरकार को दे दिया जाता है। ऐक्ट में यह विधान था कि जब तक रक्षित कोष (Reserve Fund) बूँजी के बराबर न हो जावे तब तक कम से कम ५० लाख रुपया रक्षित कोष में प्रति वर्ष रक्खा जावेगा। यदि लाभ इतना न हो तो हिस्सेदारों को बाँटने के उपरान्त जो भी लाभ शेष बचे उस रक्षित कोष में रख दिया जावे। जब रक्षित कोष बूँजी के बराबर हो जावे तो सारा शेष लाभ सरकार को दे दिया जावे। १९३६ के पूर्व ही रिजर्व बैंक का रक्षित कोष पाँच करोड़ रुपये हो गया था अतएव उसके उपरान्त हिस्सेदारों को लाभ बाँटने के उपरान्त शेष लाभ सरकार को चला जाता है।

रिज़र्व बैंक की लेनी-देनी का लेखा (Balance-Sheet) यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि रिज़र्व बैंक के दो भाग हैं एक नोट विभाग दूसरा बैंकिंग विभाग । दोनों का लेनी-देनी का लेखा पृथक् होता है । हम यहां रिज़र्व बैंक की लेनी-देनी के लेखे का अध्ययन करेंगे ।

नीचे हम १६ मई १९५० को प्रकाशित रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया-देनो का लेखा देते हैं।

नोट विभाग (Issue Department)

देनी (Liabilities)

निकाले हुए नोट	रु०
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट.....	१७,१६,९६,०००
नोट जो चलन में हैं ..	११,८७,८०,२८,०००
कुल नोट...	<u>२९,०४,९७,२४,०००</u>

लेनी (Assets)

(क) खोने के सिक्के तथा स्वर्ण पाट	रु०
(क) जो भारत में हैं...	<u>४०,०१,७१,०००</u>
(ख) जो भारत के बाहर हैं	
विदेशी सिक्कुरिटी.....	<u>६५०,२४,२८,०००</u>
'क' का जोड़....	<u>६९०,१६,०९,०००</u>
(ख) रुपये के सिक्के...	
भारत सरकार की रुपये की	
सिक्कुरिटी.....	<u>५४,५३,९७,०००</u>
अन्तरिक (Internal) बिल	
तथा अन्य व्यापारिक पत्र (Commercial.....	<u>४६०,२७,१८,०००</u>
Paper)	
	<u>१२,०४,९७,२४,०००</u>

(रसूर्य और विदेशी सिक्कुरिटी का निकाले हुए नोटों का प्रतिशत ५७.२८३%)

बैंकिंग विभाग (Banking Department)

(२५)

देनी (Liabilities)

₹

बुद्धता पैजी (Capital Paid up).....	५०,०००,०००
रक्षित कोष (Reserve Fund).....	५०,०००,०००
डिपॉजिट (जमा)	
(क) सरकारी	१२८,०४,०४,०००
(१) भारत सरकार (केन्द्रीय)	२१,५१,१०,०००
(२) अन्य सरकारों (भारतीय)	५३,६६,३०,०००
(ख) बैंकों की जमा.....	५६,५६,६५,०००
(ग) अन्य डिपॉजिट	४०२,७४,०००
देय विपन्न (Bills Payable)	१६,५२,१६,०००
अन्य देनी (Other Liabilities)	जोड़ २६२,६७,२६,०००

₹

नोट.....	१७,८६,६६,०००
रुपये के सिक्के	१२,६१,०००
छोटे सिक्के	२,७८,०००
मुनाये हुये बिल (Bills Discounted)	
(क) प्रान्तरिक (Internal) बिल	१,३४,५०,०००
(ख) विदेशी बिल	
(ग) सरकारी हुन्डियाँ (Govt. of India Treasury Bills)	१,६१,६३,०००
कोष जो विदेशों में है	१६६,३५,७२,०००
(Balances held abroad)	
सरकार को दिया गया ऋण	१५२,००,०००
विनियोग (Investments)	५८,८१,५७,०००
अन्य ऋण.....	१०,३२,१७,०००
अन्य देनी या सम्पत्ति.....	५,४७,३५,०००
(Other Assets)	जोड़ २६२,६७,२६,०००

रिज़र्व बैंक और द्रव्य बाजार (Money Market) रिज़र्व बैंक का मुख्य कार्य देश के हित में साख्त (Credit) का नियंत्रण करना है। इस कार्य को भली प्रकार कर सकने के लिये यह आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक का साख्त (Credit) तथा करसी या मुद्रा (Currency) पर भी पूरा नियंत्रण स्थापित हो जावे। यह पहले के अध्यायों में बता चुके हैं कि साख्त पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि करसी या मुद्रा पर भी नियंत्रण स्थापित किया जावे क्योंकि मुद्रा के आधार पर ही साख्त का विस्तार होता है। यदि केवल करसी या मुद्रा (Currency) से व्यापारिक कारबार होता तब तो मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित कर लेने मात्र से साख्त (Credit) पर भी स्वतः नियंत्रण स्थापित हो जाता। परन्तु यदि इसके विपरीत यदि चेक या धनादेश (Cheques) का व्यापारिक कार्यों में बहुत अधिक प्रयोग होता है जैसा कि व्यापारिक दृष्टि से उन्नत देशों में आजकल हो रहा है तब केवल मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने से साख्त (Credit) पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि केवल मुद्रा या करसी पर नियंत्रण स्थापित हो जाने से बैंकों की जमा या डिपॉजिट अथवा बैंक द्रव्य (Bank Money) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अस्तु एक ऐसे देश में जहाँ कि एक बैंक का व्यवहार अधिक होता है केन्द्रीय बैंक (Central Bank) को बैंकों की जमा या डिपॉजिट पर भी नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता।

भारत में क्रय-शक्ति (Purchasing Power) के तीन मुख्य रूप हैं। रुपये का सिक्का, कागजी मुद्रा अर्थात् करसी नोट तथा बैंकों की जमा या बैंक डिपॉजिट। इनमें रुपये का सिक्का अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, उसका व्यवहार अपेक्षा कृति कम ही है। अतएव भुगतान करने के मुख्य साधन या तो करसी नोट हैं या वे बैंक डिपॉजिट (जमा) हैं जिन पर चेक काटे जा सकते हैं। इनमें भी चेकों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। यद्यपि आज यह कहना कठिन है कि भारत में करसी नोटों के चलन से चेकों का चलन अधिक है फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों बराबर का महत्व रखते हैं और शीघ्र ही वह समय आने वाला है जबकि भारत में भी चेकों का चलन करसी नोटों से बहुत अधिक बढ़ जावेगा।

यही कारण है कि रिज़र्व बैंक को करसी पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है अर्थात् रिज़र्व बैंक को कागजी मुद्रा अर्थात् करसी

नोट निकालने का अधिकार प्राप्त है। रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व करंसी नोट निकालने का कार्य तो सरकार करती थी और कुछ सीमा तक साख (Credit) का नियंत्रण इम्पीरियल बैंक के हाथ में था। भारतीय द्रव्य बाज़ार की यही दुर्बलता थी जो कि रिज़र्व बैंक की स्थापना के उपरान्त दूर हो गई। रिज़र्व बैंक को कानून द्वारा शिष्टूल बैंकों के बैलेंस को रखने का अधिकार दे दिया गया। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के पास सरकारी कोष (Funds) भी रहता है तथा उसको सरकार का बैंकर होने का भी गौरव प्राप्त है। इन सुविधाओं से रिज़र्व बैंक को साख (Credit) पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुत सुविधा होती है। इन अधिकारों और सुविधाओं के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ऐक्ट में रिज़र्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सीधे जनता से व्यवहार करने की आज्ञा दे दी गई है। ऐक्ट की धारा १८ के अनुसार यदि भारत के व्यापार व्यवसाय और कृषि के हितों में यह आवश्यक प्रतीत हो तो रिज़र्व बैंक सीधे बिलों को भुना सकता है और ऋण दे सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिज़र्व बैंक बिना शिष्टूल बैंक या प्रान्तीय सरकारी बैंक की दलाली या मध्य-स्तता के खुले बाज़ार (Open Market) कारबार कर सकता है। यह अधिकार रिज़र्व बैंक साधारणतः काम में नहीं लावेगा। यह असाधारण अवसरों पर ही काम में लाया जा सकता है।

रिज़र्व बैंक और साख का नियंत्रण—रिज़र्व बैंक साख (Credit) का नियंत्रण करने में कहीं तक सफल हुआ है इसके निर्याय में एक कठिनाई यह है कि यद्यपि रिज़र्व बैंक को स्थापित हुए इतने वर्ष हो गए किन्तु अभी तक उसकी साख नियंत्रण शक्ति की परीक्षा होने का अभी अवसर नहीं आया। क्योंकि जब से रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई है तब से अभी तक द्रव्य बाज़ार में द्रव्य (Money) का टोटा नहीं पड़ा, द्रव्य की बहुतायत ही रही अतएव द्रव्य-बाज़ार की रिज़र्व बैंक की सहायता/की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अतएव हम केवल सैद्धान्तिक रूप से ही इस बात की विवेचना कर सकते हैं कि रिज़र्व बैंक साख (Credit) का नियंत्रण करने में कहीं तक सफल होगा।

भारतीय द्रव्य बाज़ार की कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जो कि अन्य देशों में नहीं पाई जाती और उनसे यह संदेह होने लगता है कि क्या रिज़र्व बैंक वास्तव में साख का नियंत्रण करने में सफल होगा। पहली विशेषता तो यह है कि इम्पीरियल बैंक का भारतीय द्रव्य बाज़ार में अत्याधिक प्रभाव है किन्तु

जैसा हम आगे देखेंगे इंग्लैंड बैंक के इस अव्यविक प्रभाव से रिजर्व बैंक का प्रभाव कम नहीं होता। इंग्लैंड बैंक की भारतीय द्रव्य बाजार (Indian Money Market) में विशेष परिस्थिति के कारण साल के नियंत्रण की यहाँ एक नई पद्धति का आविर्भाव हुआ जो रिजर्व बैंक और द्रव्य बाजार के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

भारतीय द्रव्य बाजार की दूसरी विशेषता है कि यहाँ विनिमय बैंको (एक्सचेंज बैंको) का एक ऐसा प्रभावशाली समूह है कि जो यदि चाहे तो रिजर्व बैंक की साल नीति (Credit Policy) को अक्षम कर दे सकता है क्योंकि उनकी लन्दन द्रव्य बाजार में सीधी पहुँच है किन्तु अब जैसी राजनैतिक स्थिति है एक्सचेंज बैंको का यह साहस नहीं हो सकता है कि वे रिजर्व बैंक की भारतीय हितों की दृष्टि से निर्धारित नीति के विरुद्ध कार्य करेंगे क्योंकि ऐसा करने से उनका विरुद्ध सरकार का कार्यवाही करना पड़ सकती है अतः एक्सचेंज बैंको तथा रिजर्व बैंक में संपर्क होने की सम्भावना नहीं है। यों भी रिजर्व बैंक तथा एक्सचेंज बैंको का संपर्क तभी खड़ा हो सकता है कि जब रिजर्व बैंक साल को कम करने का प्रयत्न करे किन्तु भारत की स्थिति यह है कि यहाँ साल का विस्तार करने की ही अधिक आवश्यकता है।

कुछ विद्वानों का यह मत है कि भारत जैसे देश में जहाँ कि द्रव्य बाजार असंगठित है रिजर्व बैंक का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। किन्तु भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ कि द्रव्य बाजार संगठित नहीं है वहाँ के अनुभव ने हमें यह यत्न दिला है कि ऐसी कोई सम्भावना नहीं है। अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में वहाँ के केन्द्रीय बैंको (Central Banks) का द्रव्य बाजार पर पूरा प्रभाव पड़ता है।

भारत में भी रिजर्व बैंक का द्रव्य बाजार पर प्रभाव अनुभव होता है यद्यपि अभी तक ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ कि जब उसकी साल नियंत्रण की क्षमता की परीक्षा हो सकती। भारतीय द्रव्य बाजार पर रिजर्व बैंक का प्रभाव इसी से ज्ञात होता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व बाजार में जो मौसमी द्रव्य की कमी पड़ती थी और बैंक की मदद का दर बहुत अधिक घटती बढ़ती थी वह रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद दूर हो गई और वर्ष भर बैंक रेट एक समान रहती है। यही नहीं कि रिजर्व बैंक की स्थापना के उपरान्त बैंक रेट कम हो गई साथ ही उसमें घटाव भी बहुत कम हो गई। यह नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट हो जावेगा।

सितम्बर १९२६ मार्च १९३०	वैक रेट	इम्पीरियल बैंक हुंघी रेट	कलकत्ता बाजार रेट	बम्बई बाजार रेट
सितम्बर १९२६ मार्च १९३०	५%	५	११	६
सितम्बर १९३६ मार्च १९४०	७	७	११	६.६
...	३	३	६.७	६
...	३	३.६	६.७	६.६

उपर की तालिका से सूद की भिन्न दरों में कमी ही नहीं आई बरन् उनका वापसी अन्तर भी कम हो गया । इसका सम्भवतः एक कारण रिज़र्व बैंक की स्थापना है । रिज़र्व बैंक की स्थापना से भारत में बैंकों की प्रोत्साहन मिला है, बैंकिंग पद्धति में सुधार हुआ है और रिज़र्व बैंक के नियन्त्रण और नेतृत्व के फल स्वरूप बैंकिंग की इस देश में उन्नति हुई है । सर्व-साधारण का शिङ्खल बैंकों पर अधिक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण देश में बैंक का अधिक प्रचलन हुआ है । रिज़र्व बैंक सरकारी हुटियों (Treasury Bills) के बाज़ार का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहा है । यदि यह इसमें सफल हुआ तो रिज़र्व बैंक का व्यापारिक बैंकों पर अधिकारिक नियन्त्रण स्थापित हो जावेगा ।

रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल बैंक—यह पूछा जा सकता है कि इम्पीरियल बैंक का भारतीय इम्प्य बाज़ार में इतना अधिक प्रभाव होने से रिज़र्व बैंक की प्रतिष्ठा को आपात पहुँच सकता है और उसके सफलता पूर्वक कार्य करने में बाधा उपस्थित हो सकती है । यदि इन दोनों महान प्रभावशाली संस्थाओं के परस्पर सम्बन्ध अच्छे न होते तब ऐसी सम्भावना हो सकती थी किन्तु माग्यवश ऐसी कोई भी सम्भावना नहीं है । दोनों बैंकों के आपसी सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और दोनों ही अपने कर्तव्यों और कार्यों को मसी प्रकार समझते हैं । यदि रिज़र्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर साख (Credit) का निर्माण करता है तो इम्पीरियल बैंक उसका थोक व्यापारी (Wholesale Dealer) बन कर उसे व्यापारिक बैंकों को बेचता है और व्यापारिक बैंक उसे जनता के हाथ बेचते हैं । यद्यपि शिङ्खल बैंक रिज़र्व बैंक से सीधे श्रृण ले सकते हैं किन्तु दो कारणों से वे इम्पीरियल बैंक के पास आर्थिक सहायता के लिए जाना अधिक पसंद करते हैं । पहला कारण तो यह है कि इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का बहुत पुराना सम्बन्ध स्थापित है दूसरे रिज़र्व बैंक से श्रृण तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने में इम्पीरियल बैंक की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक हैं । इम्पीरियल बैंक श्रृण अथवा आर्थिक सहायता देने में कानूनी बंधनों से इतना अधिक जकड़ा नहीं है जितना कि रिज़र्व बैंक । यदि इम्पीरियल बैंक को किसी व्यापारिक बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी है ऐसा विश्वास हो जावे तो वह श्रृण देने में अधिक उदार हो सकता है ।

रिज़र्व बैंक और बाज़ार मार्केट—अभी तक हमने रिज़र्व बैंक का

संगठित द्रव्य बाज़ार पर किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है इसका उल्लेख किया। वह स्पष्ट है कि रिज़र्व बैंक का बाज़ार मार्केट पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता। जब तक कि देशी बैंकर तथा साहूकार अपनी व्यापार पद्धति को नहीं बदलते तब तक रिज़र्व बैंक उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता और न वे रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में ही आ सकते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि रिज़र्व बैंक के पास बाज़ार मार्केट को सीधे प्रभावित करने के अधिकार नहीं हैं तो वह बाज़ार मार्केट पर विलकुल प्रभाव नहीं डाल सकता। यह सभी जानते हैं कि देशी बैंकों को जो कि बाज़ार मार्केट में कारवार करते हैं परिस्थिति से विवश होकर इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण या आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है। वे अपने बिलों को इन बैंकों से मुनाते हैं और स्वीकृत सिस्चूरिटियों की ज़मानत पर ऋण लेते हैं। जहाँ तक उन्हें अपने बाज़ार की परिस्थितियों से विवश होकर संगठित द्रव्य बाज़ार में सहायता के लिये आना पड़ता है वे रिज़र्व बैंक के अप्रत्यक्ष प्रभाव में आते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों में जो इम्पीरियल हुंडी रेट और बाज़ार रेट में जो समानता दृष्टिगोचर होती है वह इस बात को बतलाती है कि दोनों बाज़ारों में सम्बन्ध बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि रिज़र्व बैंक का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है।

साख के नियंत्रण के उपाय—यह तो हम केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के अध्याय में बता आये हैं कि साख (Credit) का नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक दो उपाय काम में लाता है। एक तो बट्टा-दर (Discount rate) को घटा बढ़ा कर केन्द्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है दूसरे खुले बाज़ार में व्यवहार (Open Market Operations) करके। हम यहाँ रिज़र्व बैंक के सम्बन्ध में इन दोनों उपायों का उल्लेख करेंगे।

बट्टा-दर (Discount Rate)—बट्टा-दर प्रभावशाली है अथवा नहीं यह केवल उसके स्तर (Level) से ही नहीं जाना जा सकता बल्कि इसका निर्णय करने में हमें यह भी देखना चाहिये कि रिज़र्व बैंक की दृष्टि में कौन से व्यापारिक पत्र (Commercial Papers) मुनाने के तथा ऋण के आधार स्वरूप स्वीकार किये जाने के योग्य हैं और उन व्यापारिक पत्रों (Commercial Papers) का द्रव्य बाज़ार में क्या महत्व है।

जहाँ तक बड़ा दर (Discount Rate) का प्रश्न है कि रिजर्व बैंक की बड़ा दर जब से वह स्थापित हुआ है २ प्रतिशत रही है इस कारण यह कह सकना फठिन है कि रिजर्व बैंक को बड़ा दर कहीं तक प्रभावशाली है ।

जहाँ तक रिजर्व बैंक को कुछ व्यापारिक पत्रों (Commercial Papers) को धुनाने और उनके आधार पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त है उसका हम दो दृष्टियों से अध्ययन कर सकते हैं । पहला तो यह कि रिजर्व बैंक इस अधिकार का उपयोग साख्त का नियन्त्रण करने के लिए कर सकता है । दूसरे यह कि रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की आड़े समय में केवल उन्हीं व्यापारिक पत्रों (अर्थात् बिलों और डिस्क्यूंटिबिलिटी) को स्वीकार करके उनकी आर्थिक सहायता कर सकता है । व्यापारिक बैंकों को आड़े समय में आर्थिक सहायता करने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है । यह इस प्रकार है ।

यद्यपि रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक कुछ डिस्क्यूंटिबिलिटी (जिनके सम्बन्ध में पहले कह आये हैं) के विरुद्ध व्यापारिक बैंक को साख्त देकर उनकी सहायता कर सकता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह किसी भी बैंक को जो स्वीकार योग्य व्यापारिक पत्र तथा डिस्क्यूंटिबिलिटी दे सके उसे ऋण देने या आर्थिक सहायता करने पर विवश है । रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को आर्थिक सहायता देते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि उस बैंक ने अपना क्या ठीक जगह लगाया है अथवा नहीं, क्या वह आवश्यकता से अधिक साख्त देकर तो डिपॉजिट आकर्षित नहीं करता है ? क्या वह उस समय भी जब बाजार में द्रव्यकोष (Funds) होता है तब भी रिजर्व बैंक से सहायता चाहता है और क्या वह सट्टे (Speculation) के लिए साख्त देता रहा है । कहने का तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक किसी बैंक की आर्थिक सहायता स्वीकार योग्य बिल या डिस्क्यूंटिबिलिटी लेकर तभी करेगा जब उसे विश्वास होगा कि सहायता माँगने वाले बैंक ने बैंकिंग के सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं की है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

खुले बाजार व्यवहार (Open Market Operations)—बड़ा दर को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक को खुले बाजार के व्यवहार करने का भी अधिकार दे दिया गया है । वह हम केन्द्रीय बैंक के अध्याय में बतला आये हैं कि खुले बाजार के व्यवहारों से क्या तात्पर्य है । संक्षेप में खुले बाजार के व्यवहारों से अर्थ यह है कि रिजर्व बैंक सरकारी

सिक्क्यूरिटियों को खरीद और बेंच कर व्यापारिक बचके नकद कोष (Cash Balances) में वृद्धि या कमी करता है और इस प्रकार वह व्यापारिक बैंकों को अप्रत्यक्ष रूप से साख का अधिक निर्माण करने या साख को कम करने पर विवश करता है। रिज़र्व बैंक खुले बाज़ार में किस प्रकार की सिक्क्यूरिटियों (प्रतिभूति) की खरीद बिक्री कर सकता है उनका ऐक्ट में उल्लेख कर दिया गया है।

अन्य उपाय—ऊपर लिखे दो मुख्य उपायों के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक को जनता से सीधा कारबार करने का भी अधिकार है। किन्तु इस अधिकार को रिज़र्व बैंक विशेष अवस्था में ही काम में ला सकता है। जनता सीधे अपने धिलों को रिज़र्व बैंक से मुना सकती और स्वीकार योग्य सिक्क्यूरिटी पर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। इस अधिकार के फल स्वरूप रिज़र्व बैंक का व्यापारिक बैंकों पर बहुत अधिक प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध आचरण करते हैं तो रिज़र्व बैंक उस अधिकार का उपयोग कर सकता है। अतएव व्यापारिक बैंक का रिज़र्व बैंक की नीति के विरुद्ध आचरण करने का कभी साहस ही नहीं हो सकता।

अन्य उपायों में साख की राशनिंग करना तथा सदस्य बैंकों या शिड्यूल बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का इस देश में अधिक महत्व नहीं है क्योंकि व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक से अधिक श्रृण नहीं लेते। विज्ञापित (Publicity) का संयुक्त राज्य अमेरिका में साख को नियंत्रित करने में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है किन्तु भारत में इसका अधिक उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक से अधिकतर श्रृण नहीं लेते। हाँ, रिज़र्व बैंक का नैतिक प्रभाव अवश्य कारगर हो सकता है। जैसे जैसे रिज़र्व बैंक भारत के व्यापारिक बैंकों के अधिक सम्पर्क में आता जावेगा वह अपना नैतिक प्रभाव उनके कारबार पर डालने में सफल होगा और व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक की साख सम्बन्धी नीति को स्वतः स्वीकार कर लेंगे।

रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

कुछ समय से भारतवर्ष में यह विवाद चल रहा था कि रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए अथवा नहीं। अन्त में सरकार ने रिज़र्व बैंक के

राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया और ३ सितम्बर १९४८ को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी बिल पास होने पर यह विवाद समाप्त हो गया ।

१ जनवरी १९४९ से रिजर्व बैंक की नवीन व्यवस्था हो गई । भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के सारे हिस्से ११८ रुपये १० आना प्रति हिस्से के हिसार से खरीद लिए और इस प्रकार रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक हो गया ।

बैंक की व्यवस्था और प्रबन्ध पहले की ही भाँति केन्द्रीय तथा स्थानीय बोर्ड करेंगे । केन्द्रीय बोर्ड का संगठन इस प्रकार का होगा :—

(अ) एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी ।

(क) चार डायरेक्टर चारों स्थानीय बोर्डों में से केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी ।

(ख) ६ डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जावेंगे ।

(ग) एक सरकारी कर्मचारी सरकार मनोनीत करेगी ।

स्थानीय बोर्डों में प्रत्येक में तीन सदस्य होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी । स्थानीय बोर्ड चार होंगे ।

केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की सलाह से बैंक को उचित परामर्श देगी जो कि बैंक के हित में हो ।

रिजर्व बैंक ऐक्ट की धारा ३३ में संशोधन कर दिया गया है । अब रिजर्व बैंक उन देशों की सिक्यूरिटिया में भी अपना रुपया जमा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष (International Monetary Fund) के सदस्य हैं । रिजर्व बैंक उस देश में भुगतान किए जाने वाले व्यापारिक बिलों को भी जिनकी मियाद ९० दिन से अधिक न हो खरीद करेगा । रिजर्व बैंक उन देशों के केन्द्रीय बैंकों (Central Banks) में भी रुपया जमा कर सकेगा ।

पिछले वर्षों से ससार भर में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है कि केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे । ब्रिटेन ने बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो कि ससार में सबसे अधिक पुराना केन्द्रीय बैंक था राष्ट्रीयकरण कर लिया । योरोप के बहुत से देशों ने अपने अपने केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है । भारतवर्ष में भी इसी आन्दोलन की प्रतिक्रिया हुई है ।

अध्याय—१६

पोस्ट आफिस, ऋण कार्यालय फंड (Loan Offices)

निधि, तथा चिट फंड

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक—पोस्ट आफिस भी भारत में सेविंग्स बैंक का कारबार करते हैं और इस प्रकार वे भी द्रव्य बाजार के एक अंग हैं। पोस्ट आफिस निम्नलिखित बैंकिंग कार्य करते हैं। वे सेविंग्स बैंक का काम करते हैं, कैश सर्टिफिकेट बेचते हैं, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट देते हैं, सरकारी सिक्यूरिटियों की खरीद और बिक्री करते हैं तथा जीवन बीमा करते हैं।

सभी हेड पोस्ट आफिसों में, सब पोस्ट आफिसों में तथा बहुत से बांच पोस्ट आफिसों में सेविंग्स बैंक का काम होता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों, मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों में मितव्ययिता की भावना जागृत करना है। किन्तु पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंकों में अधिकांश मध्यम श्रेणी के ही व्यक्ति अपनी बचत जमा करते हैं। इनमें अधिकतर सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, वकील, डाक्टर, अध्यापक तथा अन्य पेशे वाले लोग ही अपना रुपया जमा करते हैं।

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में अधिक से अधिक पांच हजार रुपये जमा किये जा सकते हैं। पहले यह नियम था कि एक वर्ष में कोई ७५० रु० से अधिक जमा नहीं कर सकता था किन्तु अब यह बंधन हटा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ५ हजार रुपये तक एक बार में जमा कर सकता है। कम से कम २ रुपये जमा किये जा सकते हैं। सेविंग्स बैंक में अब दो सौ रुपये से कम पर १३ प्रतिशत और २०० रु० से ऊपर २ प्रतिशत सूद दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति रुपया जमा कर सकता है। रुपया एक सप्ताह में केवल एक बार निकाला जा सकता है।

भारतवर्ष में पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक की स्थापना १८८२ में हुई। तब से उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा जमा किया हुआ रुपया बराबर बढ़ता ही गया। पहिले महायुद्ध के आरम्भ होने पर (१९१४-१५) अवश्य लोगों में घबड़ाहट फैल गई और लोगो ने करोड़ों रुपया निकाल लिया परन्तु शीघ्र ही

लोगों में विश्वास फिर लौट आया और डिपॉजिट बढ़ने लगी। १९१०-११ में आर्थिक मंदी के कारण जितना रुपया जमा हुआ उससे अधिक हराया निकाला गया किन्तु फिर डिपॉजिट की वृद्धि होने लगी। ११ मार्च १९१२ में २७८ करोड़ जमा करने वाले थे और ७७५ करोड़ रुपये की डिपॉजिट थी। अब दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ और फ्रांस का पतन हो गया तो जनता में फिर पवराहट फैली और लोगों ने अपना रुपया निकालना आरम्भ कर दिया किन्तु शीघ्र लोगों में विश्वास लौट आया और डिपॉजिटों में वृद्धि होने लगी।

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में सुधारः—केन्द्रीय बैंकिंग जीव कमेटी की सम्मति थी कि अधिकतम जमा करने की सीमा पाँच हजार से बढ़ा कर दस हजार रुपये कर देनी चाहिये। कुछ चुने हुए पोस्ट ऑफिसों में सेविंग्स बैंक हिसाब से चेक द्वारा हराया निकालने की सुविधा प्रदान करना चाहिए और अमशः अधिकाधिक पोस्ट ऑफिसों में इस प्रकार की सुविधा दे देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेविंग्स बैंक हिसाब को सयुक्त नामों में खोलने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। रुपया जमा करने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर दें कि जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उसका मालिक हो। इससे यह झकड़ नहीं रहेगा कि रुपया जमा करने वाले का उत्तराधिकारी अपने अधिकार को प्रमाणित करे। ऊपर लिखे सुधारों की आवश्यकता तो केन्द्रीय बैंकिंग जीव कमेटी ने बतलाई भी किन्तु हम यहाँ नीचे अन्य सुधारों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझते हैं :—

(१) उन पोस्ट ऑफिसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए कि जहाँ सेविंग्स बैंक हिसाब खोला जा सके। यदि इस प्रकार के पोस्ट ऑफिसों को पूरे सप्ताह भर खोलना सामंदायक न हो तो बर्हों वे केवल सप्ताह में १ बार खोले जावें।

(२) स्कूल के अध्यापकों का इन पोस्ट ऑफिसों के चलाने के लिए उपयोग किया जावे।

(३) सप्ताह में कम से कम दो बार रुपया निकालने की सुविधा दी जावे और यदि सम्भव हो तो तीन बार रुपया निकाला जा सके। चेक द्वारा रुपया निकालने की सुविधा देना आवश्यक है।

(४) हिसाब हिन्दी में अथवा जमा करने वाले की इच्छानुसार प्रांतीय भाषा में रक्खा जावे।

(५) औद्योगिक केन्द्रों में जहाँ मजदूर रहते हों वहाँ कुछ पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक ऐसे स्थापित किये जावें कि जहाँ सेविंग्स बैंक का काम सायंकाल को हो सके और मजदूर तथा छोटे दूकानदार उनका उपयोग कर सकें ।

यदि इस प्रकार पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में आवश्यक सुधार हो जावें तो वे सर्वसाधारण में मितव्ययिता की भावना जागृत कर सकते हैं और उनका अधिकाधिक उपयोग हो सकता है । अभी उसकी कार्य-पद्धति में कुछ ऐसे दोष हैं कि जिसके कारण उसका अधिक उपयोग नहीं होता ।

पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट तथा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट:—

पिछले महायुद्ध (१९१४-१९) से पोस्ट आफिसों ने कैश सर्टिफिकेट निकालना आरम्भ किये हैं । इन सर्टिफिकेटों को निकालने का उद्देश्य यह है कि जनता में बचता बचाने की प्रवृत्ति बढ़े । कैश सर्टिफिकेटों में अधिकतर मध्यम श्रेणी के पेशेवर लोग तथा सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारी अपनी बचत को लगाते हैं । कारण यह है कि इनमें सूद अच्छा मिलता है और जोखिम बिलकुल नहीं है । मध्यम श्रेणी के लोग अधिकतर पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेटों तथा नव प्रचारित नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों में ही अपना बचता लगाते हैं । यह सर्टिफिकेट पाँच वर्ष के होते हैं और कोई व्यक्ति १०,००० इज़ार रुपये से अधिक के सर्टिफिकेट नहीं रख सकता । कैश सर्टिफिकेट १० रु० से लेकर १ इज़ार रुपये तक के होते हैं । जब पाँच वर्ष के उपरान्त सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसकी जो रकम मिलती है उसमें और उस सर्टिफिकेट के खरीदने में जो मूल्य देना पड़ता है उसका अन्तर ही सूद होता है । इस पर आय-कर नहीं देना पड़ता । १९३६ के पूर्व समय समय पर सर्टिफिकेटों की कीमत में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता रहा है कि सूद की दर घटती गई । आरम्भ में ६ प्रतिशत सूद मिलता था किन्तु १९३६ से सूद की दर २½ प्रतिशत चक्र व्याज की दर से रह गई है । यह सर्टिफिकेट समय पूरा होने से पहले भी भुनाए जा सकते हैं किन्तु खरीदने के एक वर्ष के अन्दर भुनाने पर कोई सूद नहीं मिलता । दूसरे वर्ष से सूद की दर बढ़ती जाती है किन्तु पूरा सूद तभी मिलता है जब कि पाँच वर्ष समाप्त हो जावें ।

सर्टिफिकेटों का आकर्षण सूद की दर के अनुसार कम होता या बढ़ता रहा है । दूसरे महायुद्ध के पूर्व कैश सर्टिफिकेटों का मध्यम श्रेणी की जनता को बहुत आकर्षण था क्योंकि सूद अच्छा मिलता था और उन पर आय-

कर (Income-Tax) नहीं लिया जाता था। ३१ मार्च १९३६ को कैश सर्टिफिकेटों का मूल्य ६० करोड़ रुपये था। ३१ मार्च १९४३ को केवल १५ करोड़ रुपये के कैश सर्टिफिकेट रह गए। इसका कारण यह था कि बहुत से लोग युद्ध के कारण मयभूत हो गए कि कहीं रुपया डूब न जावे। वित्तीय वैकिंग जॉब कमेटी ने कैश सर्टिफिकेटों को अधिक आकर्षिक बनाने के लिए इस बात की सिफारिश की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कि सर्टिफिकेट सरीदे इस बात का अधिकार दिया जावे कि वह अपने मरने पर वह हराया किसको मिले उसका नाम धोषित कर दे।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट—नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट द्वितीय महायुद्ध के समय निकाले गए थे। यह बारह वर्षों के लिए होते हैं। सर्टिफिकेट सरीदने वाला उन्हें कभी भी भुना सकता है किन्तु पहले १ वर्षों में कोई सुद नहीं मिलती और उसके उपरान्त क्रमशः सुद की दर बढ़ती जाती है। १२ वर्ष पूरे हो जाने पर आरम्भ में लगाया हुआ रुपया क्योटा हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति १००० रुपया के कैश सर्टिफिकेट लेता है तो १२ वर्ष के उपरान्त उसको १५०० मिलेंगे। एक व्यक्ति २५ हजार रुपये से अधिक के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट नहीं सरीद सकता। इन पर भी आय-कर नहीं लिया जाता। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेटों पर सुद की दर अच्छी है तथा जोखिम बिलकुल नहीं है इस कारण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उनकी ओर अधिक आकर्षित होता है। यदि सरीदने वाले को यह सुविधा दे दी जावे कि वह अपना उत्तराधिकारी धोषित कर सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरान्त रुपया दिया जावे तो यह और भी अधिक प्रचलित हो सकते हैं।

इन कार्यों के अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस जनता के लिए सरकारी सिक्यूरिटीयों (प्रतिभूति) को सरीदने और बेचने का काम भी करता है। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस कोई फीस नहीं लेता। किन्तु एक वर्ष में पोस्ट ऑफिस किसी एक व्यक्ति के लिए ५००० ६० से अधिक की सिक्यूरिटी नहीं सरीदेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो सिक्यूरिटी स्वयं ले सकता है। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल की सहायता में छोड़ सकता है। उसकी सिक्यूरिटीयों को सुरक्षित रखने के लिए पोस्ट ऑफिस कुछ नहीं लेता।

इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस सरकारी कर्मचारियों 'युनिशैलिटो', जिला बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का जीवन बीमा भी करता है।

ऋण कार्यालय (Loan Offices)—ऋण कार्यालय बंगाल की एक विशेष संस्था है। यह देशी बैंकरो तथा मिश्रित पूँजी वाले बैंको (Joint Stock Banks) के बीच की संस्था है। भारत के अन्य प्रान्तों में जब १८६०-७० के आसपास मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंको की स्थापना हुई तब बंगाल में इन बैंको का उदय हुआ। पहले ऋण कार्यालय (Loan Office) १८६५ में स्थापित हुआ। इनकी रजिस्ट्री कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत होती है। यह अधिकतर बंगालियों द्वारा स्थापित किए गए हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं। इनकी संख्या लगभग १००० है तथा उनकी कार्य-शील पूँजी ६-१० करोड़ रुपये हैं। इनकी चुकता पूँजी (Paid up capital) बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसे ऋण यह हैं जिनकी चुकता पूँजी एक लाख से अधिक हो। यह अधिकतर डिपॉजिटों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वे ऋण पत्र अर्थात् डिबेंचर नहीं निकालते और जो नये हैं उनका रक्षित कोष (Reserve Fund) भी बहुत कम है। यह मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों से डिपॉजिट लेते हैं। यह एक वर्ष से ७ वर्षों तक के लिए डिपॉजिट लेते हैं और ४ से ८ प्रतिशत तक सूद देते हैं। अधिकतर डिपॉजिट ५ वर्षों के लिए होती हैं।

यह ऋण कार्यालय मुख्यतः ज़मींदारों तथा उन किसानों को जिनका भूमि पर अधिकार है भूमि वंधक रखकर ऋण देते हैं। एक प्रकार से यह भूमि वंधक बैंक (Land Mortgage Banks) हैं। इसके अतिरिक्त यह जेवर रखकर भी ऋण दे देते हैं। परन्तु यह व्यापार या बन्धों के लिए बहुत कम ऋण देते हैं। इनमें से कुछ व्यापार में भी अपना रुपया लगाते हैं। पुरानी कम्पनियाँ सुरक्षित ऋण पर १२ से १८ प्रतिशत सूद लेती हैं तथा अरक्षित ऋण (Unsecured debt) पर इससे भी अधिक सूद लिया जाता है। नई कम्पनियाँ तो बहुत सूद लेती हैं। यह कम्पनियाँ डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए दलाल रखती हैं और अत्यधिक सूद देती हैं। इनका प्रबन्ध ठीक नहीं है और वे अपना रुपया बहुत जोखिम के साथ लगाती हैं। यही कारण है कि अभी हाल के संकट में बहुत से बंगाली बैंक ब्रूच गए क्योंकि वस्तुतः वे ऋण कार्यालय ही के थे।

निधि या चिट-फ़ंडः—निधियाँ मदरास प्रान्त में पाई जाती हैं। आरम्भ में यह पारस्परिक ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में काम करती थीं किन्तु क्रमशः वे अर्द्ध बैंकिंग संस्था बन गईं। इस समय मदरास प्रान्त में २२८

निधियाँ काम कर रही हैं। वे कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर की गई हैं। वे या तो डिपॉजिट लेती हैं अथवा हिस्सा पूँजी के रूप में मासिक किरतों में रुपया स्वीकार करती हैं जो कि निकाला जा सकता है। उनका मुख्य उद्देश्य सदस्यों में बचत की भावना जागृत करना है, उनके पुराने ऋण को चुकाना तथा महाजन के चंगुल से निकालना तथा उनको उत्तम जमानत पर सभी कार्यों के लिए ऋण देना है। यदि निधि के पास अधिक रुपया होता है जिसकी सदस्यों के लिए कोई जरूरत नहीं है तो बाहर वालों को भी ऋण दे दिया जाता है। निधियों में डिपॉजिट आकर्षित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वे अधिकतर रुपया हिस्सा पूँजी (Share-capital) के द्वारा प्राप्त करती हैं। निधियाँ सूद की दर पर ऋण देती हैं। साधारणतः वे ३½ प्रतिशत पर सदस्यों को ऋण देती हैं परन्तु समय पर न चुकाये जाने वाले ऋण पर वे अधिक सूद लेती हैं और उससे उनका पूँज लाभ होता है। मदरास बैंकिंग कमेटी का कथन था कि अधिकतर निधियों का संचालन और प्रबन्ध बहुत अच्छा था।

चिट-फंड—चिट फंड थोड़े से लोगों का एक संगठन मात्र होता है जो एक दूसरे को रुपया उधार देने तथा बचत की भावना को जाग्रत करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह अधिकतर मदरास प्रान्त में पाई जाती है। इनकी ठीक ठीक संख्या तो किसी को शायद नहीं किन्तु यह कई हजार होंगी। इसका विधान इस प्रकार होता है। कुछ लोग आपस में यह ठय कर लेते हैं कि वे एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर अपने में से एक को दे दिया करेंगे। सदस्यों द्वारा पहली बार दिया हुआ रुपया चिट फंड को स्थापित करने वाले को उसकी सेवाओं के उपलब्ध में मिल जाता है। इसके उपरान्त प्रत्येक बार का रुपया या तो बारी बारी से प्रत्येक सदस्य को मिलता रहता है अथवा लाटरी डाल ली जाती है। उदाहरण के लिए १०२ आदमी एक चिट फंड स्थापित करते हैं और प्रत्येक प्रति मास दस रुपये फंड को देता है तो पहले महीने का रुपया तो चिट फंड के संस्थापक को मिल जावेगा और दूसरे महीने से १००० रु० या तो बारी बारी से प्रत्येक सदस्य को मिलता रहेगा या लाटरी डाल दी जावेगी। जिस सदस्य को १००० रु० मिल गया उसको तब तक दुबारा रुपया नहीं मिल सकता जब तक बाकी सब सदस्यों को एक बार १००० रु० न मिल जावे। इससे एक लाभ यह होता है कि प्रत्येक सदस्य को एक मुश्त १००० रु० मिल जाते हैं जबकि उसक लिए सम्भवत इतना रुपया एक साथ इकट्ठा करना कठिन हो जाता।

किन्तु कभी-कभी चिट फंड स्थापित करने वाले धोखा देते हैं और वैश्यानी करते हैं तथा अन्य सदस्यों का रुपया मारा जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि इनका प्रबन्ध ठीक हो । केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी का मत था कि निधियो तथा चिट-फंडों की ठीक व्यवस्था हो इसके लिए एक कानून बना दिया जावे जिसके अन्तर्गत उनकी रजिस्ट्री हो ।

अध्याय—२०

उद्योग-धंधों के लिए पूँजी (Capital) का प्रबन्ध

उद्योग-धंधों के लिये दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता है । एक तो **स्थिर सम्पत्ति (Fixed assets)** जैसे भूमि, इमारतों, यंत्रों तथा मशीनों और अन्य स्थायी दीर्घ काल तक काम आने वाली वस्तुओं को मोल लेने के लिए तथा दूसरी चल सम्पत्ति (**Floating assets**) जैसे कच्चा माल, तथा अन्य आवश्यक सामग्री मोल लेने, मजदूरों तथा कर्मचारियों को वेतन देने तथा कच्चे माल को उसके माल में परिवर्तित करने में जो व्यय होता है उसके लिए तथा तैयार माल की बिक्री में होने वाले व्यय के लिए आवश्यक होती है । **अचल पूँजी (Block capital)** की आवश्यकता नये कारखानों तथा धंधों की होती है तथा उन पुराने कारखानों की होती है जो अपना विस्तार करना चाहते हैं । अचल पूँजी स्थायी रूप से धंधे में लगी रहती है किन्तु चल सम्पत्ति (**Floating assets**) की व्यवस्था करने के लिए **कार्यशील पूँजी (Working Capital)** की आवश्यकता होती है वह स्थायी होती है क्योंकि माल के बिक्र जाने पर कारखाने के पास यथेष्ट कार्यशील पूँजी हाथ में आ जाती है परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाजार भाव के कारण अथवा अन्य किसी कारण यह माल नहीं बिक सका अथवा नहीं बेचा गया अतः कारखाने को कच्चे माल के मोल लेने तथा अन्य व्यय करने के लिए कामा चाहिए । अतः प्रत्येक कारखाने या धंधे में दो प्रकार की पूँजी आवश्यक होती है । (१) अचल पूँजी (**Block capital**) दूसरी कार्यशील पूँजी (**Working capital**)

वांछारण्यता उद्योग के लिए पूँजी की व्यवस्था नीचे लिखे अनुसार होती है .—

अचल पूँजी—(Block capital)—अचल पूँजी को एकत्रित करने के लिए तीन उपाय हैं । **हिस्से (Shares)** बेचकर पूँजी एकत्रित करना **डिविडर** बेच कर तथा **सुरक्षित कोष (Reserve fund)** लगा करके । नये कारखानों या धंधों को ता **हिस्से** बेच कर ही अचल पूँजी की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

क्योंकि जब तक कि धंधे के पास जमीन, इमारत, अथवा मशीनों के रूप में कुछ स्थायी सम्पत्ति न हो तब तक वह ऋण पत्र (डिबेंचर) किस की ज़मानत पर निकलेगा। हाँ, किसी कारखाने के पास जब स्थायी सम्पत्ति यथेष्ट होती है और वह कारखाना सफलतापूर्वक चलता है तथा लाभ खींचता है उस दशा में यदि कारखाने के संचालक कारखाने का विस्तार करना चाहते हैं तो उन्हें अधिक अचल पूँजी की आवश्यकता होगी। अब यदि वे नये हिस्से निकालते हैं तो नवीन हिस्सेदार मो लाम में हिस्सा बटावेंगे अतएव संचालक कारखाने की स्थायी सम्पत्ति की ज़मानत पर डिबेंचर निकालते हैं और उन्हें कम सूद पर लम्बे समय (२० या ३० वर्षों के लिए) के लिये ऋण के रूप में पूँजी मिल जाती है। जो कारखाने या धंधे बहुत सफल हुए हैं तथा यथेष्ट पुराने हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है वे प्रति वर्ष होने वाले लाभ में से यथेष्ट रकम सुरक्षित कोष (Reserve fund) में जमा करते जाते हैं और जब कभी उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखाने का विस्तार करना होता है तो वह सुरक्षित कोष (Reserve fund) में से रकमा लेकर मशीनें खरीदते, इमारतों का निर्माण कराते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुराने कारखाने या धंधे नये हिस्से भी बेचते हैं। अस्तु ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब कोई धंधा या कारखाना स्थापित होता है तब तो अचल पूँजी (Block-capital) की व्यवस्था करने का एक मात्र साधन हिस्से बेचना है किन्तु पुराने और सफल कारखाने यदि अपने विस्तार के लिए अचल पूँजी चाहते हैं तो वे नये हिस्से बेच कर, ऋण पत्र (डिबेंचर) निकाल कर अथवा सुरक्षित कोष (Reserve fund) में से रकमा लेकर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

औद्योगिक प्रधान देशों में कारखाने कार्यशील पूँजी (Working Capital) का कुछ अंश तो हिस्से बेचकर ही प्राप्त करते हैं परन्तु व्यापारिक बैंकों पर कार्यशील पूँजी के लिए निर्भर रहते हैं। कारखाना अपने पक्के माल अथवा कच्चे माल इत्यादि की ज़मानत पर थोड़े समय के लिये व्यापारिक बैंकों से ऋण ले लेते हैं और जब तैयार माल बिक जाता है तो ऋण चुका दिया जाता है। जिन कारखानों ने बहुत अधिक सुरक्षित कोष जमा कर लिया हो वे उसका उपयोग भी कार्यशील पूँजी के लिये करते हैं। परन्तु अन्य देशों में कारखाने तथा धंधे मुख्यतः व्यापारिक बैंकों पर कार्यशील पूँजी के लिये निर्भर रहते हैं।

भारत में उद्योग धंधों के लिए पूँजी की व्यवस्था—भारत में भी अचल पूँजी के बिना हिस्से बेच कर ही पूँजी की व्यवस्था की जाती है किन्तु भारत में उद्योग धंधों को पर्याप्त पूँजी नहीं मिलती। केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी के सामने गवाहियाँ देते हुए भारतीय पूँजी-पतियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उद्योग धंधों को पूँजी इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई होती है। धंधों को पूँजी की जो कठिनाई उठानी पड़ती है उसके नीचे लिखे कारण मुख्य हैं,—

(१) भारतवर्षे ज़ूफ़ि प्रधान देश है, अतएव गाँवों में रहने वाले लोग अधिकतर अपनी बचत को सोने चाँदी के आभूषण तथा भूमि खरीदने में और खेतों का सुधार करने में और अपने गाँव वालों को कर्ज देने में लगाते हैं। मध्यम श्रेणी के वे लोग भी जो कि शहरों में रहते हैं जिनमें छोटे व्यापारी तथा भिन्न भिन्न पेशों के लोग भी सम्मिलित हैं वे अपनी बचत को भूमि, मकान, सरकारी ऋण, म्यूनिसिपल ऋण तथा कैश सर्जिफिकेट और नेशनल सेविंग सर्जिफिकेट में लगाना पसन्द करते हैं। वे व्यवसाय की ओर रुख उठाना नहीं चाहते। बड़े बड़े शहरों तथा व्यापारिक केन्द्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी बचत को उद्योग धंधों में न लगा कर सरकारी सिक्यूरिटियों में लगाते हैं। जहाँ गाँवों का तथा कस्बों का प्रश्न है वहाँ एक कारण तो यह है कि वे धंधों की ओर रुख उठाना नहीं चाहते दूसरे वहाँ बैंक इत्यादि भी नहीं हैं कि भिन्नके द्वारा वे कंपनियों के हिस्सों को खरीद सकें। बड़े बड़े शहरों में भी लोग जो उद्योग धंधों में अपनी बचत नहीं लगाते उसका एक कारण यह है कि वहाँ कंपनियों के हिस्सों की खरीद किसी की कोई विशेष सुविधा नहीं है केवल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में शेयर बाज़ार (Stock Exchange) है। बैंक इत्यादि कंपनियों के शेयरों पर आसानी से ऋण नहीं देते इस कारण भी लोग अपना रुपया शेयरों (हिस्सों) में रचना से हिचकते थे। इसके अतिरिक्त उससे पूर्व भारत सरकार की नीति उद्योग धंधों का अधिक प्रोत्साहन न देने की थी इस कारण भा लोग अपनी बचत को उद्योग धंधों में नहीं लगाते थे। भारतीयों का उद्योग धंधों की ओर आकर्षित न होने के केवल यही कारण नहीं थे, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि कंपनियों के मैनेजिंग एजेंट जो कंपनियों के सर्वेक्षक हैं वे कंपनियाँ यदि सफल हो जाती हैं तो उनका अधिकांश लाभ अपनी जेब में रख लेते हैं, हिस्सेदारों को बहुत कम लाभ मिलता है और कभी-कभी तो हिस्सेदारों को बहुत घोसा दिया

जाता है। भारत में कंपनियों का संगठन इस प्रकार का होता है कि हिस्सेदारों का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं होता। मैनेजिंग एजेंट ही उनके वास्तविक स्वामी तथा कर्ता-धर्ता होते हैं। ऐसी दशा में कोई कंपनियों के हिस्सों में अपना रुपया क्यों लगाना चाहेगा। यही कारण थे कि भारत में अधिकतर लोग अपनी बचत को उद्योग धंधों में नहीं लगाते थे। किन्तु १९४० के उपरान्त द्वितीय महायुद्ध के फल स्वरूप लोगों का ध्यान इधर गया है और वे उद्योग धंधों में भी अपनी पूँजी लगाने लगे हैं।

अन्य देशों में यदि कोई व्यवसायी अथवा व्यावसायिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति किसी धंधे की योजना तैयार करता है और कंपनी स्थापित करता है तो यदि योजना अच्छी होती है और उसके सफल होने की सम्भावना होती है तो जनता उसके हिस्से खरीद लेती है, यही नहीं वहाँ के बैंक नई कंपनियों के हिस्सों का अभिगोपन (Underwriting) कर देते हैं। किसी-किसी देश में बैंकों के अतिरिक्त पेशेवर अभिगोपक (Underwriter) हैं जो नई कंपनियों के हिस्सों का अभिगोपन करते हैं। अभिगोपन (Underwriting) का अर्थ यह है कि बैंक या अभिगोपक इस बात की ज़िम्मेदारी ले लेता है कि यदि उस कंपनी के हिस्से नहीं बिके तो वह शेष सब हिस्से खरीद लेगा। इस कार्य के लिए वह थोड़ा कमीशन लेते हैं। यह बैंक तथा अभिगोपक (Underwriter) उस कंपनी की योजना की जाँच पड़ताल करके ही इस ज़िम्मेदारी को लेते हैं। बैंक तो इसके लिए विशेषज्ञ रखते हैं जो नवीन योजनाओं की छानबीन करते हैं। अतएव जब कोई प्रतिष्ठित बैंक अथवा अभिगोपक (Underwriter) नई कंपनी के हिस्सों के न बिकने पर उनको स्वयं मोल लेने की ज़िम्मेदारी ले लेता है तो जनता में उसके प्रति विश्वास जम जाता है और उसके हिस्से बिक जाते हैं। यदि कुछ शेष रह जाते हैं तो बैंक उसको खरीद लेते हैं। फिर आगे क्रमशः उन हिस्सों को जनता को बँच देते हैं। किन्तु भारतवर्ष में न तो बैंक ही उस कार्य को करते हैं और न पेशेवर अभिगोपक (Underwriter) ही हैं। अस्तु यहाँ जब तक किसी नई कंपनी के पीछे कोई बड़ा पूँजीपति या व्यवसायी न हो तब तक उसको पूँजी ही नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए यदि बिरला ब्रदर्स किसी नई कंपनी को स्थापित करते हैं तो पहले तो वे तथा उनके अन्य मित्र ही उसके हिस्से खरीदते हैं और शेष हिस्से वे जनता को बँच देते हैं। उनकी प्रसिद्ध-द्रव्य बाज़ार में साख होने के कारण बहुधा तो उस कंपनी के हिस्से बिक जाते हैं अन्यथा वे स्वयं उनको

खरीद कर बेंचने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि यही कंपनी को स्थापित करते हैं और उसके विशेष हिस्से अपने अधिकार में रखते हैं अतएव वे अपने को उसका प्रयत्नक अर्थात् मैनेजिंग एजेंट नियुक्त कर लेते हैं और उस प्रकार वे उसके सर्वेसर्वा बन जाते हैं। आज देश में स्थिति यह है कि यदि ताता एण्ड-सन्स, गिरला ब्रदर्स, डालमिया इत्यादि प्रसिद्ध पूँजीपतियों की मैनेजिंग एजेंसी में कोई नई कंपनी स्थापित होती है तब तो उसको पूँजी मिल जाती है अन्यथा यदि कोई साधारण व्यक्ति जिसमें व्यावसायिक योग्यता है यदि कोई कंपनी स्थापित करता है तो उसका पूँजी ही नहीं मिल पाती।

ऋण पत्र या डिबेंचर निकालने में कठिनाई :—दिरते बेंचकर प्रारम्भिक पूँजी इकट्ठा करने में जो यहाँ कठिनाई उपस्थित होती है उसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। किन्तु कपनियाँ स्थापित हो जाने और सफलता पूर्वक चलने के उपरान्त भी यदि किसी कारखाने का विस्तार करने के लिए लम्बे समय के लिए पूँजी की आवश्यकता हो तो डिबेंचरों को बेंचकर पूँजी या सफलता भी यहाँ कठिन है। भारत में डिबेंचरों में भी अनजाना अपना दायरा नहीं लगाती और न कपनियाँ ही डिबेंचर निकालना पसंद करती हैं। सब तो यह है कि भारतवर्ष में डिबेंचर प्रचलित ही नहीं हैं। इसके पीछे लिये मुख्य कारण हैं :—

(१) जो कंपनी ऋण पत्र या डिबेंचर निकालती है उसकी सात (Credit) बैंक की दृष्टि में गिर जाती है क्योंकि जो ऋण पत्र या डिबेंचर खरीदते हैं उनका कंपनी की सम्पत्ति पर पहला ग्रहणाधिकार (Lien) होता है। यदि किसी कंपनी ने ऋण पत्र या डिबेंचर निकाले हैं तो उसको बैंकों के ऋण मिलना कठिन हो जाता है। यही नहीं उनको कच्चा माल भी बाजार पर मिलना कठिन हो जाता है। भारत-में डिबेंचर निकालना आर्थिक नियंत्रिता का चिह्न माना जाता है इस कारण साधारणतः कपनियाँ डिबेंचर नहीं निकालती।

(२) भारतवर्ष में डिबेंचरों के अभिगोपन (Underwriting) की प्रथा नहीं है अतएव डिबेंचर बिक ही जायेंगे उसका निश्चय नहीं रहता। अन्य देशों में कपनियों के डिबेंचरों को बैंकों के ग्राहक उनकी सहाय पर खरीद लेते हैं। इस प्रकार अधिकतर डिबेंचर तो बैंकों के द्वारा ही बिक जाते हैं, शेष जनता को बेंच दिए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ डिबेंचरों का अभिगोपन कम खर्चों में और आसानी से हो जाता है। भारतवर्ष सर्वसाधारण को

अपनी बचत उद्योग धंधों में लगाने के लिए न तो उचित परामर्श ही मिलने की कोई सुविधा है और न उनको कुछ जानकारी ही है ।

(३) भारत में जो मो कुछ थोड़ी सी अच्छी कम्पनियों ने डिबेंचर निकाले हैं वे कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में हैं इसलिए यहां डिबेंचरों की बाज़ार में खरीद बिक्री स्वतंत्रतापूर्वक नहीं होती । अतएव लोग उनको खरीदने से हिचकते हैं । उदाहरण के लिए ताता स्टील कंपनी ने जब डिबेंचर निकाले तो महाराजा ग्वालियर ने सारे के सारे खरीद लिये । इस कारण डिबेंचरों का कोई बाज़ार स्थापित न हो सका ।

(४) भारतीय बैंक अपना अपना डिबेंचरों में नहीं लगाते और न डिबेंचरों की ज़ामात पर आसानी से अपने ग्राहकों को ऋण ही देते हैं । अन्य देशों में बीमा कम्पनियां अपने कोष को डिबेंचरों में लगाती हैं किन्तु भारतवर्ष में बीमा कंपनियां भी डिबेंचरों में अपना धन नहीं लगाती ।

(५) भारतवर्ष में जितने सूद पर डिबेंचर बेंचे जा सकते हैं उससे कम सूद पर बैंकों से ऋण मिल सकता है अथवा जनता से डिपॉज़िट मिल सकती है इस कारण भी कंपनियां डिबेंचर नहीं निकालती ।

ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि जहां तक अचल पूंजी (Block capital) का प्रश्न है वह तो यहां हिस्सों को बेंच कर ही प्राप्त की जाती है किन्तु हिस्से भी तभी बिक सकते हैं जब कि कंपनी के पीछे कोई प्रसिद्ध पूंजीपति मैनेजिंग एजेंट अर्थात् प्रबंधक के रूप में हो । मैनेजिंग एजेंट तथा उसके मित्र कंपनी के यथेष्ट हिस्से स्वयं खरीद लेते हैं । इसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ हुआ कि अचल पूंजी के लिए भी यहां धंधे परोक्ष रूप से प्रबंधक अर्थात् मैनेजिंग एजेंटों पर निर्भर हैं ।

कार्यशील पूंजी (Working capital) :—भारतवर्ष में धंधों की कार्यशील पूंजी चार स्थानों से प्राप्त होती है (१) जनता से डिपॉज़िट लेकर, (२) मैनेजिंग एजेंटों से ऋण ले कर अथवा मैनेजिंग एजेंटों तथा अनेक मित्रों से डिपॉज़िट लेकर (३) देशी बैंकरो से ऋण ले कर (४) और मिश्रित पूंजी वाले बैंकों से ऋण लेकर । अब हम प्रत्येक के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिखेंगे ।

जनता की डिपॉज़िट :—यह पद्धति अहमदाबाद और बम्बई में बहुत अधिक प्रचलित है । यों तो अन्य केन्द्रों में भी कारखाने डिपॉज़िट स्वीकार करते हैं परन्तु अहमदाबाद और बम्बई में जनता से डिपॉज़िट लेने का अधिक प्रचार

है। नीचे दी हुई तालिका से यह स्पष्ट हो जावेगा कि बम्बई तथा अहमदाबाद में डिपाजिटों के द्वारा कितनी पूँजी प्राप्त की जाती है।

	बम्बई	अहमदाबाद
	कुल पूँजी का प्रतिशत	कुल पूँजी का प्रतिशत
१. मैनेजिंग एजेंटों से लिया हुआ ऋण	२१%	२४%
२. बैंकों से लिया हुआ ऋण	६%	४%
३. जनता से ली हुई डिपाजिट (जमा)	११%	१६%
४. हिस्सा पूँजी (Share capital)	४६%	१२%
५. डिबेंचर	१०%	१%

जनता से डिपाजिट साधारणतः एक वर्ष के लिए ली जाती है किन्तु कोई कोई मिल ७ वर्षों के लिए भी डिपाजिट लेती है। जहाँ तक सूद का प्रश्न है मिलें बैंकों से कुछ ही अधिक सूद देती हैं अतएव जहाँ तक सूद देने का प्रश्न है मिलें कम सूद पर ही डिपाजिट पा जाती है। जितना सूद उन्हें बैंकों तथा मैनेजिंग एजेंट या देशी बैंकों को ऋण पर देना पड़ता है उससे तो कम ही पर उन्हें डिपाजिट मिल जाती है। किन्तु डिपाजिटों पर कितना सूद देना होगा यह मिल की आर्थिक स्थिति तथा उसके मैनेजिंग एजेंट अर्थात् प्रबंध की साह पर निर्भर होता है। मिलों में अपना रुपया जमा करने की प्रथा इस कारण प्रचलित है कि आरम्भ में बैंक नहीं थे अधिकांश पूँजीपति जो कि मिलों के प्रबंधक बने साहुकारी का काम करते थे। इस कारण मिलों में जनता रुपया जमा करती रही। अब भी जब कि बैंक इत्यादि मौजूद हैं तब भी मैनेजिंग एजेंट के परिचित मित्र जाति विरादरी के लोग तथा अन्य व्यक्ति तिनका उनमें विश्वास है अपना रुपया मिलों में जमा करते हैं। बम्बई में तो यह प्रथा कुछ कम हो गई है किन्तु अहमदाबाद में यह अधिक प्रचल है।

किन्तु इस प्रथा के कुछ दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि यदि कभी आर्थिक मदी (Depression) आई और मिलों के काम कम हुए तो जमा करने वालों में पचराहट पैल जाती है और वे सभी मिलों में से फिर चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों न हो अपनी डिपाजिट निकाल लेते हैं। १९२५, २६ तथा १९२६ में बम्बई तथा अहमदाबाद में यही हुआ। मिलों को ऋण लेकर जमा करने वालों को उनका रुपया वापस करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अब किसी मिल की आर्थिक स्थिति निर्भल हो जाती है, उसे

हानि होती है अथवा उसके मैनेजिंग एजेंट की वाज़ा़र में किसी कारण से साख़ गिर जाती है तो रुपया जमा करने वाले अपना रुपया निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मिल को उस समय अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है और उसी समय उसको रुपया वापस करना पड़ता है। ऐसी दशा में मिल की स्थिति डवाडोल हो उठती है। यही कारण है कि जनता की डिपॉज़िट को “अच्छे समय का मित्र” कहा गया है। जब तक मिलों की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है तब तक डिपॉज़िट आती रहती हैं और तब भी कोई आर्थिक संकट आया कि जमा करने वाले अपना रुपया वापस निकाल लेते हैं। इसके अतिरिक्त इनका एक दोष यह भी है कि आवश्यकता से अधिक डिपॉज़िट आने पर उन्हें अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता नहीं तो फिर डिपॉज़िटों का आना ही समाप्त हो सकता है। अतः मिल उस समय उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाती।

व्यापारिक बैंक तथा उद्योग धंधे—यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि भारत में बैंक उद्योग धंधों को अधिक आर्थिक सहायता नहीं देते। अन्य देशों में बैंक अपनी पूँजी (Capital) तथा सुरक्षित फंड (Reserve fund) को कम्पनियों के डिबेंचरों को खरीदने में लगाते हैं किन्तु भारत में वे ऐसा नहीं करते। क्योंकि भारतीय बैंक रूढ़िवादी हैं। यही नहीं भारतीय बैंक कम्पनियों की हिस्सा पूँजी (Share capital) का अभिगोपन (Underwriting) भी नहीं करते। अतएव जहाँ तक अचल पूँजी (Block capital) का प्रश्न है उद्योग धंधों को बैंकों से कोई सहायता नहीं मिलती।

जहाँ तक कार्यशील पूँजी (Working capital) का प्रश्न है इन्जीनियरिंग तथा अन्य बैंक व्यापारिक कारखानों के कच्चे माल तथा तैयार माल की ज़मानत पर ऋण देते हैं किन्तु उसमें भी ३० प्रतिशत छूट रखते हैं अर्थात् मिल जितना माल बंधक रूप में उनके पास रखता है उसका अधिक से अधिक ७० प्रतिशत वे ऋण देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मिलों को अन्य स्थानों से ऋण लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। बैंक उनकी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को भी पूरा नहीं करते।

बैंकों से ऋण लेने में केवल यही कठिनाई नहीं है कि भारतीय बैंक तरल सम्पत्ति (Liquid assets) की ज़मानत के बिना ऋण देते ही नहीं जब कि

अन्य देशों में बैंक कम्पनी की आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत साख पर श्रृणु दे देते हैं।

इस रियल बैंक को कानून के अन्तर्गत श्रृणु लेने वाली कम्पनियों से शामिलरी नोट पर दो हस्ताक्षरों की करवाना पड़ता है। इसका फल यह हुआ कि वह कम्पनी के डायरेक्टर के अतिरिक्त उस कम्पनी के प्रबन्धक अर्थात् मैनेजिंग एजेन्ट के बिना हस्ताक्षरों के श्रृणु नहीं देते। अन्य व्यापारिक बैंकों ने भी इसी परिपाटी को अपना लिया है अस्तु जिस कम्पनी का कोई मैनेजिंग एजेन्ट नहीं होता केवल संचालक बोर्ड (Board of Directors) ही उसका प्रबन्ध करते हैं उन्हें बैंक आर्थिक सहायता अर्थात् श्रृणु नहीं देते। बैंकों की इस शोध पूर्ण प्रणाली के कारण कम्पनियों को मैनेजिंग एजेन्ट रखना अनिवार्य हो बन गया है।

यहाँ तक अपना तैयार माल या कच्चा माल बंधक रूप में रख कर श्रृणु लेने का प्रश्न है अच्छी मिलें इसे अधिक पसन्द नहीं करती बबोकि देना करने से उनका साख तथा प्रतिष्ठा को धक्का खगता है और उन्हें अन्य स्थानों से श्रृणु मिलने में अड़चन हावी है।

देशी बैंकों से प्राप्त श्रृणु—भारत में कारखानों तथा मिल्नों को बहुधा देशी बैंकों (Indigenous bankers) के पास आर्थिक सहायता के लिए जाना पड़ता है। किन्तु देशी बैंकों के पास वे ही कारखानों या मिलें आर्थिक सहायता क लिये जाती है जिनकी पूँजी उनकी आवश्यकता से कम है और उन्हें डिपॉजिट या बैंकों से श्रृणु नहीं मिलता या जिनके मैनेजिंग एजेन्ट प्रविष्ट व्यवसायी नहीं हैं या स्वयं श्रृणु दे सकें। देशी बैंक बहुत अधिक सूद लेते हैं इस कारण उनसे श्रृणु लेना बहुत अधिक खर्चीला होता है।

मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता—यह तो हम ऊपर ही कह आये हैं कि भारतवर्ष में धन के लिये पूँजी की उचित व्यवस्था नहीं है। न तो यहाँ संगठित पूँजी का बाजार (Capital market) है और न यहाँ औद्योगिक बैंक हैं। अतएव मैनेजिंग एजेन्टों को अपने ही आधीन कारखानों के लिए आवश्यकता पड़ने पर पूँजी या प्रबन्ध करना पड़ता है। मैनेजिंग एजेन्ट बहुत बड़े बड़े पूँजीपति होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं अपने कारखानों को श्रृणु देते हैं अथवा अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से

अणु दिलवाते हैं। किन्तु एक मैनेजिंग एजेन्ट के प्रबन्ध में केवल दो चार कारखाने ही नहीं होते वरन् बहुत होते हैं इस कारण कभी-कभी मैनेजिंग एजेन्टों को भी अपने कारखानों के लिये पूँजी की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है फिर भी भारतीय धन्धों को जो भी कहीं से पूँजी मिलती है वह बहुत कुछ मैनेजिंग एजेन्टों के प्रभाव, साख, तथा सहायता से ही मिलती है। यही कारण है कि भारतवर्ष में मैनेजिंग एजेन्ट प्रणाली का उदय हुआ। आज एक प्रकार से मैनेजिंग एजेन्टों का भारतीय धन्धों पर एकाधिपत्य स्थापित है। भारतीय उद्योग धन्धों के विकास में मैनेजिंग एजेन्टों का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान लेना आवश्यक है।

मैनेजिंग एजेन्ट—मैनेजिंग एजेन्ट बड़े-बड़े पूँजीपति या उनकी फर्में होती हैं। कभी-कभी यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना कर भी मैनेजिंग एजेन्ट का काम करते हैं। मैनेजिंग एजेन्ट नीचे लिखे मुख्य काम करते हैं :—

(१) वे कंपनियों की स्थापना करते हैं, वे कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में जो भी प्रारम्भिक छान-बीन होती है करते हैं, साधन जुटाते हैं और कंपनी की स्थापना करते हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई मैनेजिंग एजेन्ट यह समझता है कि हिमालय की नराई के समीप किसी केन्द्र में कागज़ का कारखाना खुल सकता है तो वे सब छान-बीन करके कि लकड़ी या घास किस मूल्य पर मिल सकेगी, शक्ति के उत्पन्न करने में क्या व्यय होगा, मज़दूरों की कमी तो नहीं रहेगी और मज़दूरी कितनी देनी होगी तथा माल की बिक्री के लिए गमनागमन के साधनों की क्या व्यवस्था है इत्यादि बातों की छान-बीन करके जंगल का ठेका इत्यादि लेकर कारखाने के लिये भूमि इत्यादि खरीद कर फिर कंपनी की रजिस्ट्री करा लेगा। अतएव किसी कंपनी के स्थापित करने में जितनी भी प्रारम्भिक कार्यवाही तथा व्यय करना पड़ता है वह सब मैनेजिंग एजेन्ट करते हैं।

(२) मैनेजिंग एजेन्ट एक प्रकार से पूँजी के अभिगोपन (Capital underwriting) का भी काम करते हैं। वे कंपनी के यथेष्ट हिस्से स्वयं खरीद लेते हैं तथा उनके मित्र और सम्बन्धी भी यथेष्ट हिस्से खरीदते हैं। यही नहीं जनता को जो हिस्से बँचे जाते हैं वे भी मैनेजिंग एजेन्ट के नाम से ही बिकते हैं यदि मैनेजिंग एजेन्ट की प्रसिद्धि अच्छी है जो शेय हिस्से शीघ्र बिक जाते हैं। कार्यशील पूँजी की व्यवस्था भी मैनेजिंग एजेन्ट ही करता है।

(३) मैनेजिंग एजेंट अपने मित्रों को ही कम्पनी डाइरेक्टर बना देते हैं और कुछ डाइरेक्टर वे स्वयं मनोनीत करते हैं। बात यह है कि मैनेजिंग एजेंट तथा उनके मित्रों के पास यदि २५ या ३० प्रतिशत भी हिस्से हुए तो वे जो चाहें वह कर सकते हैं क्योंकि हिस्सेदार जो कि भारतवर्ष में पैसे हुए हैं वे तो कभी साधारण वार्षिक सभा में आते नहीं इस कारण मैनेजिंग एजेंट तथा उनके मित्र कम्पनी के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। इस प्रकार कम्पनी के डाइरेक्टर वस्तुतः मैनेजिंग एजेंट के ही आश्रित होते हैं। मैनेजिंग एजेंट १० वर्षों के लिए उस कम्पनी के प्रबन्ध करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। कम्पनी की इस सेवा के उपलब्ध में यह कई हजार रुपये चापिस भुगतान लेते हैं तथा १० प्रतिशत या उसके सममग लाभ लेते हैं। मैनेजिंग एजेंट को डाइरेक्टर चाहें तो २० वर्षों के लिए फिर मैनेजिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कम्पनी के डाइरेक्टर मैनेजिंग एजेंट के ही आदमी होते हैं इस कारण वास्तव में मैनेजिंग एजेंसी स्थायी होती है, उन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता। अपने सम्बन्धियों को ऊँचे पदी पर नौकर रखकर तथा कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल की बिक्री पर लाभ उठाकर मैनेजिंग एजेंट कुछ लाभ कमाते हैं और इसके बदले वे कम्पनी का प्रबन्ध देखते हैं, उसे चलाते हैं।

मैनेजिंग एजेंटों की सहायता से जहाँ इस देश में बहुत घबों की स्थापना हुई है वहाँ इस प्रणाली में एक दोष भी है। शिक्षित भारतीय जिनमें व्यावसायिक योग्यता हो कम्पनी स्थापित नहीं कर सकते। बिला मैनेजिंग एजेंट के कोई नया पंथा स्थापित नहीं हो सकता। भारत जैसे विशाल देश में जितने प्राशन प्रगम हैं यदि घबों की स्थापना केवल थोड़े से यूजीपतियों के हाथ में ही रही तो एक तो देश की औद्योगिक उन्नति की गति धीमी रहेगी दूसरे यह देश के हित में भी न होगा कि घबों पर थोड़े से उद्योगपतियों का एकाधिपत्य स्थापित हो जावे। मैनेजिंग एजेंट वर्तमान में एक दोष यह भी है कि यह जमें उद्योगपतियों की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्रों के अधिकार में जाती है अर्थात् मैनेजिंग एजेंट के उत्तराधिकारी ही मैनेजिंग एजेंट होते हैं इससे मलिन्य में कम्पनियों का प्रबन्ध अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है।

यही कारण है कि अर्थशास्त्र के विद्वानों का यह मत था कि उद्योग पंथों के लिए पूँजी की व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक अर्थ प्रबन्धक कारपोरेशन

(Industrial Finance Corporation) की स्थापना की जावे । केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने भी इस मत का समर्थन किया था । बंगाल तथा संयुक्तप्रान्तीय सरकारों ने छोटे-छोटे धंधों को आर्थिक सहायता देने के लिए कारपोरेशनों की स्थापना की थी किन्तु यह दोनों संस्थाएँ केवल छोटे धंधों को ही पूँजी देने की व्यवस्था करती थीं फिर उनके साधन इतने कम थे कि वे विशेष लाभदायक न हो सकीं । इर्ष की बात है कि भारत सरकार एक बहुत बड़ी संस्था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन के नाम से स्थापित करने जा रही है । उसका बिल तैयार हो गया है । शीघ्र ऐक्ट बनाकर भारत सरकार उसकी स्थापना कर देगी । इस कारपोरेशन से नवीन धंधों को पूँजी की कुछ सुविधा हो जावेगी । प्रस्तावित औद्योगिक अर्थ प्रबन्धक कारपोरेशन (Industrial Finance Corporation) का विधान इस प्रकार है ।

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन

इस कारपोरेशन की स्थापना १ जुलाई १९४८ को हुई । इसका उद्देश्य उन सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पनियों तथा सहकारी समितियों को माध्यमिक तथा लम्बे काल के लिए आर्थिक सहायता देना है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिणत करने, खनिज सम्बन्धी कार्य करने, तथा विद्युत या अन्य प्रकार की शक्ति को उत्पन्न करने का कार्य करें ।

इस कारपोरेशन का प्रबन्ध १२ डायरेक्टरों का एक बोर्ड करता है । इसमें ४ डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं । केन्द्रीय सरकार ३ साधारण डायरेक्टर मनोनीत करती है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर मनोनीत करती है । इनके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक के दो डायरेक्टर, शिष्टल बैंकों के दो डायरेक्टर, नीमा कंपनी, इनवैस्टमेंट ट्रस्ट इत्यादि के दो डायरेक्टर, तथा सहकारी बैंकों के दो डायरेक्टर होंगे ।

कारपोरेशन की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) दस करोड़ रुपए है जो कि बीस हजार हिस्सों में बंटी हुई है । प्रत्येक हिस्सा पाँच हजार रुपए का है । इन हिस्सों में से अभी केवल दस हजार हिस्से जिनका मूल्य पाँच करोड़ रुपए है बचे गए हैं । अर्थात् कारपोरेशन की चुकता पूँजी (Paid up Capital) केवल पाँच करोड़ रुपए है । आगे चल कर जब कभी आवश्यकता होगी शेष हिस्से बेचे जावेंगे । इस पाँच करोड़ रुपए की पूँजी इस प्रकार इकट्ठी हुई है । (१) केन्द्रीय सरकार

को एक करोड़ रुपए के मूल्य के दो हजार हिस्से, (२) रिजर्व बैंकों को एक करोड़ रुपए के दो हजार हिस्से, (३) सिव्जन बैंकों को एक करोड़ २५ लाख रुपए के दो हजार पाँच सौ हिस्से (४) बीमा कम्पनियों तथा इनवेस्टमेंट ट्रस्टों को एक करोड़ २५ लाख रुपए के दो हजार पाँच सौ हिस्से तथा सहाकारी बैंकों को पचास लाख रुपए के एक हजार हिस्से दिए गए। केन्द्रीय सरकार ने ७६ हिस्से जो कि सहाकारी बैंकों ने नहीं खरीदे और अधिक खरीद लिए।

कारपोरेशन को विधान के अनुसार अपनी शुद्धता पूँजी और रक्षित कोष के पाँच गुने मूल्य के बाँड निकालने का अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में जब कारपोरेशन की शुद्धता पूँजी दस करोड़ रुपए हो जावेगी और रक्षित कोष शुद्धता पूँजी के बराबर हो जावेगी तो कारपोरेशन १०० करोड़ रुपए का ऋण ले सकेगी।

कारपोरेशन उद्योग धन्यों के लिए अचल लेनी (Fixed Assets) अर्थात् मशीन इमारत इत्यादि को प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देगी। चालू व्यय के लिए वह ऋण नहीं देगी। थोड़े समय के लिए चालू व्यय के लिए उद्योग धन्यों को पूर्ववत् व्यापारिक बैंक ही ऋण देंगे। कारपोरेशन व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा न करके केवल लम्बे तथा माध्यमिक काल के लिए उद्योग धन्यों को आर्थिक सहायता देगी।

(१) कारपोरेशन को अधिकार होगा कि यदि कोई कंपनी खुले द्रव्य बाजार में कोई ऋण लेना चाहे तो कारपोरेशन उस ऋण की अदायगी की गारंटी कर दे जिससे कि कम्पनी को वह ऋण आसानी से मिल जावे। किन्तु इस प्रकार का ऋण पच्चीस वर्षों से अधिक के लिए नहीं होगा। (२) कारपोरेशन किसी कम्पनी के हिस्सों (Shares), ऋण पत्रों (Debentures) अथवा बाँडों का अभिगोपन (Underwrite) करके उस कंपनी को लम्बे समय के लिए पूँजी इकट्ठा करने में सहायता दे। (३) कारपोरेशन किसी कम्पनी को सीधे ऋण देकर अथवा उसके ऋण पत्रों को खरीद कर भी कंपनी की आर्थिक सहायता कर सकती है। किन्तु इस प्रकार का ऋण २५ वर्षों से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए।

व्यवहार में कारपोरेशन नई कम्पनियों द्वारा निकाले गए हिस्सों का अभिगोपन (Underwriting) करेगी। जब कोई व्यवसायी अपनी योजना को कारपोरेशन के सामने रखेगा तो कारपोरेशन उसको अपने

विशेषज्ञों को देगी। यदि कारपोरेशन के विशेषज्ञ उस योजना का समर्थन करेंगे तो कारपोरेशन उस कम्पनी के हिस्सों का अभिमोपन कर देगी। इसका परिणाम यह होगा कि जनता में उस नवीन कम्पनी की सफलता में विश्वास बढ़ेगा और अधिक सम्भावना इस बात की होगी कि उसके सब हिस्से बिक जायें। यदि कुछ हिस्से नहीं बिके तो कारपोरेशन स्वयं खरीद लेगी। कारपोरेशन शीघ्र ही उन हिस्सों को फिर जनता को बेच देगी। किसी भी दशा में कारपोरेशन सात वर्षों से अधिक किसी हिस्से को अपने पास नहीं रख सकती। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि कारपोरेशन किसी कम्पनी के हिस्से खरीद कर अपने पास नहीं रख सकती। कारपोरेशन किसी कम्पनी के हिस्सों को छींचे खरीद नहीं सकती। किसी एक कम्पनी को पचास लाख रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती।

कारपोरेशन किसी कम्पनी को उसकी अचल लेनी (Fixed Assets) की जमानत पर ही ऋण दे सकती है अथवा उसको दिए हुए ऋण की गारंटी कर सकती है। किन्तु ऋण देते समय बंधक रखी हुई लेनी (Asset) का मूल्य ही एकमात्र आधार नहीं होगा। उस कम्पनी के लाभ कमाने की सम्भावना, उस कम्पनी का भविष्य, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका उत्पादन व्यवस्था, उस योजना की उपादेयता उसके प्रबन्धकों की योग्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पादन के अन्य साधनों की प्राप्ति, धन्ये का स्थान और सबसे अधिक धन्ये का राष्ट्र के लिए महत्त्व इत्यादि बातों को आर्थिक सहायता देने के समय ध्यान में रखा जावेगा।

किसी कम्पनी को साख देने से पूर्व कारपोरेशन उस कारखाने की जाँच अपने कर्मचारियों से करा लेगा जो कि उस योजना के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। जब उनकी रिपोर्ट से यह श्रात होगा कि योजना ठीक है तभी ऋण दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त उस कम्पनी का प्रबंध ठीक हो तथा उसको दिए हुए ऋण का ठीक-ठीक उपयोग हो इस उद्देश्य से उस कम्पनी के डायरेक्टरों तथा मैनेजिंग एजेंसी के साभोदारों को व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के दिए गए ऋण की गारंटी करनी होगी। कारपोरेशन उस कम्पनी के बोर्ड में अपने दो डायरेक्टर मनोनीत करेगी। कारपोरेशन उन कम्पनियों के लाभ को ६ प्रतिशत पर सीमित कर देती है जिन्होंने कारपोरेशन से ऋण लिया है। कारपोरेशन की सहमति से लाभ को बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रकार के कारपोरेशन की देश के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता थी

न्योक्ति औद्योगिक उन्नति के लिए पूँजी की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है और इसी कारण बन्धों को स्थापित करने का काम बड़े-बड़े पूँजीपति ही करते हैं। किन्तु केवल एक कारपोरेशन से भारत जैसे विशाल देश के श्रम उद्योग बन्धों तथा छोटे-छोटे वर्कशापों तथा कारखानों की स्थापना के लिए पूँजी का प्रबन्ध नहीं हो सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय कारपोरेशन स्थापित होने चाहिए।

एक वर्ष के कार्यकाल में कारपोरेशन से १५६ कम्पनियों ने आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में पृष्ठ-ताछ की। ६५ कम्पनियों ने आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना की। वे लगभग १० करोड़ ३३ लाख रुपये की सहायता चाहती थीं इनमें से २१ के प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुए और उनको ३ करोड़ ४२ लाख रुपये का श्रृण देना स्वीकार किया गया। ३३ प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए गए। कारपोरेशन ने ५ से ५३ प्रतिशत अक्षद पर श्रृण दिया। जो श्रृण पहले बड़े दिया गया उसका ग्योरा इस प्रकार है।

रुपये

१—रुपये के कारखानों के लिए यंत्र बनाने के कारखाने	४१ लाख
२—आयल पेंसिन	१० लाख
३—रासायनिक पदार्थ	५६ लाख ५० हजार
४—शीशे और चीनी मिट्टी के कारखाने	६० लाख
५—सीमेंट	४० लाख
६—इलेक्ट्रिक इंजिनियरिंग	२६ लाख
७—तेल की मिलें	१ लाख ७५ हजार
८—विद्युत शक्ति	३ लाख
९—खनिज सम्बन्धी बन्धे	३० लाख
१०—लोहा और स्टील	१५ लाख ५० हजार
११—सूती वस्त्र	४० लाख
१२—ऊनी वस्त्र	५ लाख
१३—अनिका वर्गीकरण नहीं हुआ	११.५० लाख

कुल ३ करोड़ ४२ लाख २५ हजार

गृह-उद्योग धंधों (Cottage industries) तथा छोटे कारखानों और मध्यम श्रेणी के धंधों को पूँजी की कठिनाई

गृह-उद्योग-धंधों की स्थिति तो अत्यन्त दयनीय है। कारीगर कुछ महाजन व्यवसायियों का कीतदास बन जाता है और महाजन उनका शोषण करता है। पूँजी के प्रबन्ध में गृह-उद्योग धंधों की स्थिति इस प्रकार है। कुछ महाजन होते हैं जो किसी धंधे विशेष का कारबार करते हैं। उदाहरण के लिए हम दरी बनाने या कपड़ा बुनने का धन्धा लेते हैं। कारीगर महाजन से सूत उधार ले जाता है किन्तु शर्त यह होती है कि जो माल वह तैयार करेगा वह उसी महाजन को देना होगा। होता वास्तव में यह है कि महाजन व्यवसायी कारीगर को सूत देते समय यह भी बतला देता है कि उसे किस प्रकार का समान तैयार करना होगा। जब कारीगर माल तैयार करके लाता है तो महाजन व्यवसायी उनको कम से कम मूल्य पर माल ले लेता है और सूत की अधिक से अधिक कीमत काट कर उसे मज़दूरी दे देता है। बेचारा कारीगर एक प्रकार से महाजन व्यवसायी का दास बन जाता है और उसे कम से कम मज़दूरी मिलती है। पिछले कुछ वर्षों से प्रान्तों में औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है जो कारीगरों को साख (Credit) देती हैं उनको उचित मूल्य पर कच्चा माल देती हैं तथा उनके माल बेचने का प्रबन्ध करती हैं। किन्तु अभी तक यह औद्योगिक सहकारी समितियाँ (Industrial Cooperative Societies) इनी-गिनी ही हैं और गृह-उद्योग धंधों के लिए पूँजी का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है। गृह-उद्योग धंधों में लगे हुए कारीगरों का शोषण होता है। व्यापारिक बैंक इन धंधों को कोई आर्थिक सहायता नहीं देते।

गृह-उद्योग धंधों के अतिरिक्त मध्य श्रेणी के धंधों के लिए भी देश में पूँजी के प्रबन्ध की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए चावल, आटा तथा तेल की मिलें, दियासलाई, शीशा, सिगरेट, लाख, चमड़ा के कारखानों, कपास के पेंच, प्रेस, दरी तथा मोझे के कारखाने, तथा रेसमी कपड़े के कारखानों और रासायनिक पदार्थों को तैयार करने के कारखानों को भी पूँजी का टोटा रहता है। बैंक इन धंधों को कार्यशील पूँजी (Working Capital) नहीं देते इसका कारण यह कि इन कारखानों तथा धंधों को स्थापित करने वाले व्यक्ति मध्यम श्रेणी के होते हैं अर्थात् न तो वे ऐसे माल की ज़मानत दे सकते हैं कि जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही बैंक

जा सके और न वे ऐसे किसी प्रतिद्ध व्यवसायी के हस्ताक्षरों को जानात ही दे सकते हैं कि जिसको बैंक स्वीकार करें अस्तु इन धन्वों को बैंकों से कों मा आर्थिक सहायता नहीं मिलनी। आवश्यकता पड़ने पर यह लोग देशों बैंकरो तथा साहूकारों से ऊँचे दर पर ऋण लेते हैं।

प्रान्तीय बैंकिंग कॉन्फेरेण्डों ने इन धन्वों का तथा गृह उद्योग धन्वों का अध्ययन किया था। कॉन्फेरेण्डों का मत था कि छोटे कारखानों तथा मध्य श्रेणी के धंधों के लिए पूँजी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बैंकिंग कॉन्फेरेण्डों का यह भी मत था कि गृह-उद्योग धंधों को भी बैंक आर्थिक सहायता नहीं देते। हाथ कपों से सूती कण्डा तैयार करने का धंधा, रेशमी और ऊनी कपड़े बनाने का धंधा, बोड़ी तथा चिहट का धंधा, चटाई बनाने का धंधा, गुड़ बनाने का धंधा, तेल पेरने का धंधा, रस्सी बनाने का धंधा, दरी बुनने का धंधा, लिलौने बनाने का धंधा, धो दूध का धंधा, मुर्गी पालने का धंधा, तथा लकड़ी का धंधा इत्यादि अन्य गृह-उद्योग धंधे जो देश भर में फैले हुए हैं महाजनो पर अवलम्बित हैं जो उन्हें कच्चा माल उपहार देते हैं तथा उन्हें जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा नक़्दा भी दे देते हैं और उनके तैयार माव्र को बहुत थोड़े मूल्य पर खराद लेते हैं। इस प्रकार बेचारे कारीगर का देश भयकर शोषण होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अधिकांश कारीगर महाजन व्यवसायियों का जीवन भर ऋणी रहता है। वह कभी भी महाजन व्यवसायी का ऋण नहीं चुदा पाता अतएव उसका जीवन भर शोषण होता है। इसका फल यह होता कि इन धंधों की स्थिति दयनीय है।

आवश्यकता इस बात की है कि छोटे कारखानों, मध्यम श्रेणी के धन्वों के लिए तो प्रान्तीय औद्योगिक अर्थ प्रबन्धक कारखानेयन स्थापित किये जावें कि जो इन धन्वों को आर्थिक सहायता दें तथा गृह उद्योग धन्वों के लिए औद्योगिक सहायता समितियाँ स्थापित की जावें। सभी धन्वों की पूँजी की समस्या हल हो सकती है। बड़े बड़े कारखानों तथा धन्वों के लिये पूँजी की व्यवस्था प्रस्तावित भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रबन्धक सच करेगा।

अध्याय—२१

भारतीय समाशोधन गृह अर्थात् क्लियरिंग

हाउस (Clearing House)

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि किसी भी देश में जब व्यापारिक बैंकों की स्थापना हो जाती है तो क्लियरिंग हाउस की आवश्यकता पड़ती है। बिना समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) के बैंकिंग व्यवसाय की उन्नति एक स्थान पर जाकर रुक जाती है। क्लियरिंग हाउस से होने वाले अनेकों लाभों को यहाँ गिनना आवश्यक नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि क्लियरिंग हाउस की स्थापना बैंक के कर्मचारियों को एक दूसरे से चेक तथा ड्राफ्ट इत्यादि का रुपया वसूल करने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता, और न इन पुकों का भुगतान ही नकद रुपयों में करना पड़ता है जिससे मार्ग में रुपयों के लुट जाने का भय नहीं रहता और इसकी स्थापना से बैंकों को अधिक नकद को (Cash Balances) नहीं रखना पड़ता। क्लियरिंग हाउस की स्थापना से बैंक कम नकदी रखकर भी अपना काम चला सकते हैं। यह एक ऐसा लाभ है जिससे बैंकों की कार्य क्षमता बढ़ती है।

भारतवर्ष में नीचे लिखे स्थानों पर क्लियरिंग हाउस स्थापित हैं—सुके और सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं :—बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, देहली, मद्रास, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, कालीघाट, कोयम्बटूर, देहरादून, जालंधर, लखनऊ, लायलपुर, मदुरा, मंगलौर, नागपुर, पटना, शिमला तथा बंगलौर हिन्दुस्तान में तथा लाहौर, कराँची, और रावलपिंडी पाकिस्तान में।

ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष में अभी क्लियरिंग हाउस की सुविधा बहुत थोड़े से स्थानों पर है। यह बैंकिंग व्यवसाय के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। आज अधिकांश बड़े शहरों में यथेष्ट बैंक हैं परन्तु वहाँ क्लियरिंग हाउस स्थापित नहीं हुए हैं। रिजर्व बैंक को इस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिये। बनारस, मेरठ, धरौली, जवेलपुर, जमशेदपुर, सूरत, पुना, जैसे व्यापारिक नगरों में इतने अधिक बैंक होते हुए भी क्लियरिंग हाउस न होना किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता।

सदस्यता—प्रत्येक स्थान की क्लियरिंग एसोसियेशन एक स्वतंत्र संस्था होती है और उसके अपने नियम होते हैं। अन्तु कुछ क्लियरिंग हाउस को छोड़कर अधिकांश स्थानों की क्लियरिंग एसोसियेशनों ने यह नियम बना दिया है कि जिन बैंक की चुकता पूँजी (Paid up capital) पाँच लाख रुपये हो वही उसका सदस्य हो सकता है। कलकत्ता तथा कुछ अन्य क्लियरिंग हाउसों का नियम यह है कि जिन बैंकों की चुकता पूँजी १० लाख रुपये हो वही उसके सदस्य हो सकते हैं। केवल यह शर्त पूरी हो जाने मात्र से ही कोई बैंक क्लियरिंग हाउस का सदस्य नहीं बन जाता। बैंक को क्लियरिंग हाउस के मंत्री को एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है जिसका प्रस्ताव और समर्पण क्लियरिंग हाउस के सदस्य ही कर सकते हैं और जब तीन चौदाई सदस्य उस बैंक के पत्र में अपना मत दें तभी वह बैंक सदस्य बन सकता है। इस नियम का परिणाम यह हुआ कि जिन व्यापारिक केन्द्रों में ऐक्सचेंज बैंक का प्रभाव तथा बहुमत था वहाँ भारतीय बैंकों को सदस्य बनने में बड़ी कठिनाई हुई। होना यह चाहिये कि सदस्यता के नियम तलिक सरल बना दिये जायें। जो भी पिछले बैंक हो उन्हें क्लियरिंग हाउस का सदस्य स्वीकार कर लिया जावे।

उप-सदस्य—जो बैंक ऊपर की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अर्थात् जिनकी चुकता पूँजी २० लाख या ५ लाख से कम है और उनकी प्रांच उस केन्द्र में है जहाँ क्लियरिंग हाउस है तो वे उप-सदस्य बनने की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बैंकों को एक प्रार्थना पत्र किसी सदस्य बैंक के द्वारा क्लियरिंग एसोसियेशन के मंत्री को देना होता है। जिस सदस्य बैंक के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसे प्रवेश कर्ता बैंक (Sponsor Bank) कहते हैं। प्रवेश कर्ता बैंक (Sponsor Bank) को प्रार्थना करने वाले बैंक की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है तब वह उप-सदस्य बना लिया जाता है।

प्रयुक्त—क्लियरिंग हाउस का प्रबन्ध एक प्रबन्धकारिणी समिति करती है जिस पर एक सदस्य रिज़र्व बैंक का (यदि वहाँ रिज़र्व बैंक की प्रांच हो) एक सदस्य इम्पीरियल बैंक का तथा ऐक्सचेंज बैंक और मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (Joint Stock Banks) के निर्धारित प्रतिनिधि होते हैं। बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्रों के ऐक्सचेंज बैंकों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव है।

निरीक्षक बैंक—(Supervising Bank) जहाँ रिज़र्व बैंक की ब्रांच है वहाँ तो रिज़र्व बैंक ही क्लियरिंग हाउस के निरीक्षक बैंक का काम करता है और जहाँ रिज़र्व बैंक की ब्रांच नहीं होती वहाँ इम्पीरियल बैंक यह काम करता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित रकम जमा करनी पड़ती है। कलकत्ता और बम्बई को छोड़कर अन्य स्थानों पर दिन भर में केवल एक बार निष्कासन (Clearing) होता है किन्तु बम्बई और कलकत्ता में दिन में दो बार निष्कासन होता है। अब हम नीचे कलकत्ता में निष्कासन (Clearing) किस प्रकार होता है उसका संक्षिप्त विवरण देंगे।

कलकत्ता क्लियरिंग हाउस—कलकत्ता के सदस्य तथा उप-सदस्य बैंकों के सब चेक, बिल, तथा प्रलेखों (Documents) का निष्कासन (Clearing) क्लियरिंग हाउस द्वारा होता है। किसी उप-सदस्य बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने चेक या बिल इत्यादि सीधे क्लियरिंग हाउस को दे सके। उप-सदस्य के चेक इत्यादि उसके प्रवेश कर्त्ता बैंक (Sponsor-Bank) के द्वारा ही क्लियरिंग हाउस को दिये जा सकते हैं। होता यह है कि प्रवेश कर्त्ता बैंक का प्रतिनिधि अपने बैंक के रजिस्टर में ही उप-सदस्य के चेक इत्यादि चढ़ा लेता है।

प्रत्येक सदस्य बैंक को क्लियरिंग हाउस में एक प्रतिनिधि रखना पड़ता है और उसे एक रजिस्टर देना पड़ता है जिसमें उन सब चेकों, बिलों और प्रलेखों (Documents) को वह दर्ज कर लेता है जो उसे अन्य बैंकों से प्राप्त होते हैं अथवा वह अन्य बैंकों को देता है।

प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि एक पृथक् स्लिप पर उन सब चेकों, बिलों और प्रलेखों (Documents) का व्योरा तथा रकम लिख लेता है जो कि वह अन्य सदस्य बैंकों को देता है और उस रकम को वह सदस्य बैंकों के नाम रजिस्टर में लिख लेता है। तदुपरान्त प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि दूसरे सदस्य बैंकों के प्रतिनिधियों को उन पर लिखे गए चेकों और बिलों इत्यादि का बंडल तथा उनके व्योरे की स्लिप दे देता है और वे अपने रजिस्टर में उनको दर्ज कर लेते हैं। स्लिपों को बिलों, चेकों तथा प्रलेखों से मिलाकर प्रत्येक प्रतिनिधि अपने रजिस्टर के दोनों कालमों को जोड़ लेता है। इससे उस यह ज्ञात हो जाता है कि उसको अन्य सदस्य बैंकों को कुल कितना देना है और उनसे कुल कितना लेना है तथा उसके बैंक को अन्त में

कितना देना या लेना है। इतना कर चुकने के उपरान्त वह रजिस्टर को क्लियरिंग हाउस के निरीक्षक को सौंप देता है।

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कलकत्ते में प्रति दिन दो साधारण निष्कासन (Clearing) होते हैं परन्तु एक विशेष निष्कासन सायंकाल को और होता है जिनमें वापस किए हुये चेक, बिल तथा प्रलेखों का निष्कासन (Clearing) होता है और जिस बैंक के चेक इत्यादि वापस कर दिये जाते हैं उसको उसनी रकम देनी पड़ती है।

कलकत्ते में जो बहुत से छोटे बैंक हैं और जिन्हें क्लियरिंग हाउस का सदस्य होने का गौरव प्राप्त नहीं है उन्होंने एक नई संस्था को जन्म दिया है जिसे मैट्रोपॉलिटन बैंकिंग एसोसियेशन कहते हैं। यह संस्था उन बैंकों के चेकों बिलों तथा प्रलेखों के निष्कासन (Clearing) की व्यवस्था करती है। उसमें दिन में केवल एक बार निष्कासन होता है।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में निष्कासन की व्यवस्था बहुत असतोषजनक है और भविष्य में सभी केन्द्रों में क्लियरिंग हाउसों की स्थापना होना आवश्यक है। यही नहीं क्लियरिंग हाउस के सदस्य होने के लिए जो कड़ी शर्तें रख दी गई हैं उन्हें भी नरम करने की ज़रूरत है।

अध्याय—२२

भारतीय द्रव्य-बाज़ार (Indian Money Market) *N*

भारतीय द्रव्य-बाज़ार के भिन्न विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध का न होना—भारतीय द्रव्य-बाज़ार को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—पहला योरोपियन या केन्द्रीय भाग कहलाता है और दूसरा भारतीय या बाज़ार भाग कहलाता है। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक तथा ऐक्सचेंज बैंक (विनिमय बैंक) योरोपियन या केन्द्रीय भाग के अन्तर्गत हैं और साहूकार, देशी बैंकर, ऋण कार्यालय, चिट फंड तथा निधी भारतीय बाज़ार भाग के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंक तथा सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) की स्थिति इन दोनों के बीच की है। भारतीय द्रव्य-बाज़ार के इन विभिन्न भागों में अपूर्ण सम्बन्ध है क्योंकि भारतीय बैंकिंग का संगठन अच्छा नहीं है और न एक दूसरे से वे अच्छी तरह सम्बद्ध ही हैं। १९३५ तक अर्थात् रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व तो उनको आपस में मिलाने वाला कोई केन्द्रीय बैंक भी नहीं था। द्रव्य-बाज़ार का केन्द्रीय भाग सरकार की मुद्रा नीति (Currency Policy) से बहुत अधिक प्रभावित रहता है और उसके द्वारा सरकार बैंक रेट (Bank Rate) पर भी प्रभाव डालती रही है। यही कारण है कि भारतीय द्रव्य-बाज़ार दोषपूर्ण है और संसार की अन्य उन्नत द्रव्य-बाज़ारों की समता नहीं कर सकता।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank) के अभाव में १९३५ तक इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य करता था। व्यवहार में अन्य बैंक उसके पास अपनी नकदी रखते थे। यह भारत सरकार की सिक्यूरिटियों पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देता था। यद्यपि बैंकों के लिए यह एक बड़ी सुविधा थी किन्तु अधिक ऊँचा खूद लेने के कारण व्यापारिक बैंकों के लिए उनका लाभ कम हो जाता था। पहले भारत सरकार से और अब रिज़र्व बैंक से इम्पीरियल बैंक को जो विशेष सुविधायें मिली हुई हैं उनके कारण मिश्रित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) उसे अपना अनुचित प्रतिद्वन्दी ही मानते आये हैं न कि मित्र और सहायक और इसी कारण मिश्रित पूँजी वाले बैंकों तथा इम्पीरियल बैंक में कभी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका।

भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंक एक्मजेंट बैंको (विनिमय बैंको) को भी अपना प्रबल प्रतिस्पर्धी और विरोधी मानते हैं क्योंकि विनिमय बैंको के साधन बहुत अधिक हैं वे कम सुद पर यथेष्ट डिपॉजिट प्राप्त कर लेते हैं और वे दन्तरगाहों तथा भीतरी व्यापारिक केन्द्रों में देश के आन्दकनी व्यापार को भी इथिया लेना चाहते हैं ।

प्रान्तीय सहकारी बैंक (Provincial Co-operative Banks) इम्पीरियल बैंक के पास थोड़ी सी चालू जमा (Current Deposit) रखते हैं और इम्पीरियल बैंक उन्हें नकद ऋण (Cash Credit) तथा प्रोवर ड्राफ्ट (प्रिविक्चर) देता है । सेन्ट्रल सहकारी बैंक भी इम्पीरियल बैंक या कुछ बड़े मिश्रित पूँजी वाले बैंको से चालू खाता (Current Account) रखते हैं किन्तु प्रारम्भिक सहकारी समिति या केवल सहकारी बैंको से ही सम्बन्ध रखती हैं, इम्पीरियल बैंक या मिश्रित पूँजी वाले बैंको से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता ।

सहकारी बैंको (Co-operative Banks) का देशी बैंकरो तथा महाजनो और साहूकारो से कनिक भी सम्बन्ध नहीं होता । मिश्रित पूँजी वाले बैंको की यह शिकायत है कि सहकारी बैंक भी उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं । उनका कहना है कि सहकारी बैंक वह कारबार भी करने लगे हैं जिसका सहकारिता आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है । उदाहरण के लिए सहकारी बैंक चालू खाता (Current Account) रखते हैं, रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं तथा विला को खरीदते और मुनाते हैं । देशी बैंकर भी सहकारी बैंको के विरुद्ध यही शिकायत करते हैं ।

देशी बैंकरो और महाजनो में अधिक अनिष्ट सम्बन्ध नहीं है । यह दोनों अधिकतर इम्पीरियल बैंक में अपना खाता नहीं रखते । इम्पीरियल बैंक से तो देशी बैंकर अपने बिल या हुडियाँ मुना लेते हैं किन्तु रिजर्व बैंक से तो उनका कनिक भी सम्बन्ध नहीं है । जब कारबार अधिक होता है तो विन देशी बैंकरो का नाम स्वीकृत सूची पर होता है उनकी हुडियों को इम्पीरियल बैंक या मिश्रित पूँजी वाले बैंक मुना देते हैं या दो देशी बैंकरो के हस्ताक्षरों सहित प्राथिमिकी नोट पर कृण्य दे देते हैं । इस प्रकार देशी बैंकरो का बहुत बड़े समय के सम्बन्ध इम्पीरियल बैंक या मिश्रित पूँजी वाले बैंको से सम्बन्ध स्थापित होता है । भी अब देशी बैंकरो का सम्बन्ध उनसे स्थापित नहीं होता । केवल

स्वीकृत देशी बैंकरो को ही यह सुविधा दी जाती है और उनके लिए भी अधिक से अधिक कितने मूल्य की हुन्डिया भुनाई जा सकती है यह निश्चित कर दिया जाता है ।

द्रव्य-बाजारों में सूद की दर—संसार के सभी उन्नतिशील-राष्ट्रों में लम्बे समय के लिए लगाये हुए रुपये पर थोड़े समय के लिए लगाये हुए रुपये से अधिक सूद मिलता है । उदाहरण के लिए इंग्लैंड अथवा संयुक्तराज्य अमेरिका में सरकारी ऋण तथा प्रथम श्रेणी की कंपनियों के डिबेंचरों (ऋण पत्र) पर जो सूद मिलता है वह तीन महीने के बिलों पर दिये जाने वाले सूद से अधिक होता है । किन्तु भारतवर्ष में इसका उलटा रहा है । उन्नीसवीं शताब्दी की पिछली ३० वर्षों में थोड़े समय की सूद की दर लम्बे समय की सूद की दर से एक प्रतिशत अधिक थी किन्तु बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में और विशेषकर पहले महायुद्ध के उपरान्त थोड़े समय की सूद की दर तथा लम्बे समय के सूद की दर का यह भेद कम हो गया है । इसका मुख्य कारण यह है कि थोड़े समय के लिए सबसे अधिक ऋण खेती के धन्धे के लिए आवश्यक होता है और खेती का धन्धा इस देश में अत्यन्त पिछड़ा और असंगठित है । अतएव जो भी ऋण किसानों को दिया जाता है बहुधा वह बसूल जल्दी नहीं होता उसकी अवधि बढ़ानी ही पड़ती है । अतएव वह लम्बे समय के लिए ही ऋण बन जाता है और खेती के धन्धे को दिए जाने वाले ऋण के बूब जाने का बहुत भय रहता है जबकि सरकारी ऋण में लम्बे समय के लिए रुपये लगाने में इस प्रकार की कोई जोखिम नहीं रहती । यही कारण है कि इस प्रकार के थोड़े समय के लिए हुए ऋण पर सूद पर बहुत अधिक लिया जाता रहा है । किसानों से अधिक सूद मिलने के कारण गाँवों में थोड़े समय के लिये अन्य कार्यों के लिए दिए हुए ऋण पर भी ऊँचा सूद लिया जाता है । और गाँवों में थोड़े समय के लिए जब सूद की दर ऊँची रहती है तो उसका प्रभाव संगठित द्रव्य-बाजार पर भी बिना पड़े नहीं रहता । यही कारण है कि भारतीय द्रव्य-बाजार में थोड़े समय की सूद की दर अधिक समय के लिए लगाये हुए रुपये पर मिलने वाले सूद की दर से ऊँची रही है । यहाँ एक बात और ध्यान में रखने की है । यहाँ कंपनियों के डिबेंचर इत्यादि तो अधिक प्रचलित हैं नहीं केवल भारत सरकार के लम्बे समय के लिए हुए ऋण पर मिलने वाले सूद की दर से ही हम तुलना कर सकते हैं । किन्तु वास्तव में भारत सरकार के ऋण पर मिलने वाले सूद को हम लम्बे समय की सूद की दर नहीं कह

सकते क्योंकि सरकारी ऋण अर्थात् सरकारी सिक्युरिटी प्रत्येक समय देवी जा सकती है । उनके लिये सदैव बाजार में माँग रहती है । फिर भी यह तो मानना ही होगा कि भारत में थोड़े समय के लिये लिए जाने वाले ऋण पर सूद की दर ऊँची रही है और उसके कारणों के सम्बन्ध में हमने ऊपर लिखा है । इसके विपरीत भारतवर्ष में जो विदेशी पूँजी आई वह लम्बे समय के लिये लगाई गई । विदेशी पूँजीपतियों ने भारत में अपनी पूँजी को अधिक लम्बे समय के लिए लगाना पसन्द किया क्योंकि यहाँ लम्बे समय के लिए रेलों, धरो, तथा सरकारी ऋण में लगाई जाने वाली पूँजी अधिक सुरक्षित थी परन्तु थोड़े समय के लिए रोती के धबड़े में लगने वाली पूँजी को बहुत जोखिम उठाना पड़ती थी । यही कारण था कि लम्बे समय के लिए विदेशी पूँजी कम सूद पर प्राप्त हो सकती थी । किन्तु वही विदेशी पूँजी अधिक सूद मिलने पर भी थोड़े समय के ऋण के रूप में गाँवों के लिये प्राप्त नहीं थी ।

भारतवर्ष में केवल १८९१-९२ में, १९२१-२२, में और १९२६-२७ में ही ऐसा अवसर आया जब थोड़े समय की सूद की दर (Short term interest rate) अधिक लम्बे समय की सूद की (Long term rate) दर से नीचे गिर गई । १८९१-९२ में थोड़े समय की सूद की दर के गिरने का कारण यह था कि रुपये की विनिमय दर (Exchange rates) के गिरने से देश में चाँदी का आयात (Import) बहुत अधिक हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों के पास आवश्यकता से बहुत अधिक नकदी (Cash) इकट्ठा हो गई इस कारण कम समय की सूद की दर नीचे गिर गई । १९२१-२२ में थोड़े समय के सूद की दर के नीचे गिरने का कारण यह था कि सरकार ने सड़क के खर्चों का चलाने के लिये अस्थायी कागजी मुद्रा (Paper Currency) छाप दी थी । इस कारण थोड़े समय की सूद की दर नीचे गिर गई । ऊपर सरकार ने बहुत से युद्ध ऋण निकाल कर जनता की बचत को लड़ाई के लिये खींच कर लम्बे समय की सूद की दर को ऊँचा कर दिया । और १९२६-२७ में जो थोड़े समय की सूद की दर लम्बे समय की सूद की दर की तुलना में गिर गई उसका कारण वह महान् आर्थिक मन्दी (Economic Depression) थी जो १९२६ में आई ।

हैंक डिपॉजिटों पर सूद की दर— डिपॉजिटों पर सूद की दर निर्धारित
 ने समय बैंकों को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है । एक तो यह कि वे

कितना कोष आकर्षित करना चाहते हैं और कितना कोष लाभदायक ढंग से लगा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से बैंक चालू जमा (Current Deposits) पर सूद नहीं दे सकते क्योंकि चालू खाते (Current Account) में रुपया जमा करने वाले लोग सुविधा की दृष्टि से ही चालू खाता रखते हैं न कि सूद पाने के लिए। सूद प्राप्त करने के लिये जो रुपया उनकी आवश्यकताओं से अधिक है वह मुहती जमा (Fixed Deposit) में जमा किया जाता है। अस्तु यदि चालू जमा पर यदि थोड़ा सूद दे भी दिया जावे तो भी चालू जमा (Current Deposits) अधिक नहीं बढ़ जावेगी। किन्तु चालू जमा पर सूद देने का बैंकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें अधिक सूद कमाने के लिए रुपये को कहीं न कहीं लगाना ही पड़ता है फिर चाहे कुछ जोखिम ही क्यों न उठानी पड़े। इसका परिणाम बुरा होता है। यही कारण है कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में चालू खाते पर सूद नहीं दिया जाता। किन्तु भारतवर्ष में इम्पीरियल बैंक को छोड़ कर सभी बैंक चालू खाते पर सूद देते हैं। १९३० तक भारतीय व्यापारिक बैंक चालू खाते पर २½ प्रतिशत तक सूद देते थे। किन्तु यही उनकी निर्वलता थी क्योंकि भारत में प्रथम श्रेणी के विलो तथा याचना द्रव्य (Call money) का बाजार अभी निर्मित नहीं हुआ है इस कारण बैंकों को जिस सौनी (Assets) में अपना रुपया लगाना पड़ता है वह शीघ्र ही नकदी में परिणत नहीं की जा सकती। परन्तु क्रमशः भारतीय बैंकों ने चालू जमा पर सूद की दर को कम करना आरम्भ कर दिया। १९२१ में वे १ प्रतिशत सूद देते थे बाद को घटाकर उन्होंने चालू खाते पर ½ प्रतिशत सूद कर दिया और दूसरे संसार व्यापी महायुद्ध के समय जब कि देश में रुपये की बहुतायत थी उन्होंने सूद घटा कर ¼ प्रतिशत कर दिया। आशा है कि भारतवर्ष में भी बैंक चालू जमा पर सूद देना बन्द कर देंगे।

मुहती जमा (Fixed Deposit) पर सूद की दर—मुहती जमा पर बैंक जो सूद देते हैं उसपर ही मुहती जमा का अधिक होना या कम होना निर्भर रहता है। यदि सूद अधिक दिया जाता है तो मुहती जमा अधिक आती है और यदि सूद की दर कम कर दी जाती है तो मुहती जमा घट जाती है क्योंकि मुहती जमा वही करता है जिसे उस रुपये की कुछ समय के लिए आवश्यकता नहीं होती या वह उस पर सूद कमाना चाहता है। यदि मुहती जमा पर सूद बहुत कम हो जावे तो मुहती जमा चालू जमा में परिणत हो

सहती है क्योंकि यदि मुहती जमा पर सूद बहुत कम हो जावेगा तो लोग अपने रुपये को उस पर लम्बे समय के लिए अटकाने रहना पसन्द नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त बैंक मुहती जमा पर सूद की दर निर्धारित करते समय यह भी देख लेते हैं कि वे अपने ग्राहकों से कितना सूद ले सकते हैं। अस्तु मुहती जमा पर सूद की दर दो बातों पर निर्भर रहती है। एक तो इस बात पर कि अन्य सिन्क्यूरिटियों में रुपया लगाने पर कितना सूद मिल सकता है दूसरे द्रव्य-बाजार में थोड़े समय के लिए श्रृणु देने में कितना सूद मिल सकता है। जहाँ तक रुपया जमा करने वालों का प्रश्न है उसके लिए बैंक में रुपया जमा करने के अतिरिक्त दूसरा सीधा रास्ता यह है कि वह भारत सरकार की सिन्क्यूरिटी में अपनी रुपया लगा दें। अस्तु सरकार अपने श्रृणु जिस सूद की दर पर निकालती है उसका मुहती जमा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि दोनों में बहुत भेद भी है। भारतवर्ष में अधिकतर मुहती जमा १ महीने या उससे अधिक समय के लिए ली जाती है। अधिकतर डिपॉजिट एक वर्ष के लिए होती है। बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्रों में ६ महीने से कम की भी मुहती डिपॉजिट ले ली जाती है।

बैंक दिये हुए कर्जों पर कितना सूद लेंगे यह अन्य देशों में जहाँ द्रव्य-बाजार पूर्ण रूप से संगठित है बैंक-रेट (Bank rate) पर निर्भर रहती है। यदि केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की सूद की दर जिस पर वह अन्य बैंकों को कर्ज देता है ऊँची हो जाती है तो अन्य बैंक भी अपने कर्ज-दारों से और ऊँची दर से सूद लेते हैं और यदि केन्द्रीय बैंक की सूद की दर घटती है तो अन्य बैंक भी कर्ज पर सूद की दर घटा देते हैं। अन्य बैंक जब किसी को श्रृणु देते हैं तो जो उस समय केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की सूद की दर (Bank rate) होती है उससे एक निश्चित फीस की अधिक सूद लेते हैं। उन देशों में यह बैंक मुहती जमा पर जो सूद देते हैं वह कुछ निश्चित प्रतिशत 'बैंक रेट' से कम होता है। इस प्रकार उन देशों में जहाँ द्रव्य-बाजार संगठित है वहाँ मुहती जमा पर दिये जाने वाले तथा कर्ज पर लिया जाने वाले सूद की दर वहाँ के केन्द्रीय बैंक (Central Bank) की बैंक-रेट पर निर्भर रहता है और उससे सम्बन्धित होता है।

किन्तु भारतवर्ष में स्थिति दूसरी ही है। यहाँ सूद की दर का कोई नियम नहीं है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक बैंक की सूद की दर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर केवल एक ही बैंक है तो वह अपने

एकाधिकार का पूरा लाभ उठाता है और अधिक से अधिक सूद लेता है और यदि कोई दूसरा बैंक वहाँ अपनी जान्च खोल देता है तो सूद की दर गिर जाती है। यह नहीं कि मिल मिल स्थानों में सूद की दर भिन्न होती है प्रत्येक बैंक का कारबार भी बहुत भिन्न होता है इस कारण उनकी सूद की दर में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। भारतवर्ष में कुछ बैंक ऐसे हैं जो कर्ज पर बहुत उचित सूद लेते हैं फिर भी वे यथेष्ट लाभ कमाते हैं। किन्तु यदि दूसरे बैंक उसी सूद की दर पर ऋण दें तो उन्हें बहुत घाटा सहन करना पड़े। भारतवर्ष में बैंकों की सूद की दर में दुगुने से अधिक का अन्तर पाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में बैंकों की सूद की दर में बहुत भिन्नता पाई जाती है।

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अभी उद्योग-धंधों का पूरी तरह से विस्तार नहीं हुआ है और जहाँ द्रव्य-बाजार अभी पूर्ण रूप से संगठित नहीं है भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सूद की दर भिन्न होना कुछ सीमा तक अनिवार्य है। किन्तु यहाँ बैंकों में अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा के कारण जो सूद की भिन्नता पाई जाती है वह भारतीय बैंकिंग का एक बड़ा दोष है। कुछ बैंक केवल इसलिए अधिक सूद देते हैं जिससे वे डिपॉजिट प्राप्त करने में सफल हों। इसका फल यह होता है कि उन्हें अपना रुपया ऐसी जगह लगाना पड़ता है जो बहुत सुरक्षित नहीं होती और उनकी स्थिति कमजोर रहती है। तनिक से संकट में इस प्रकार के बैंक डूब जाते हैं और सभी बैंकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी देशों में अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि डिपॉजिटों पर दिये जाने वाले सूद की दर में अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा न तो किसी एक बैंक के ही लिए लाभप्रद होती है और न बैंकिंग संस्थान (Banking System) के लिए ही लाभदायक सिद्ध होती है। अन्य देशों में बैंक स्वयं मिल कर डिपॉजिट पर सूद की दर क्या हो यह निश्चित कर लेते हैं। किन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार सूद की दर का नियंत्रण नहीं किया जाता। आवश्यकता इस बात की है कि भारतवर्ष में भी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया जावे और कम से कम एक वर्ष की मुहती अमा की सूद की दर निश्चित कर दी जावे।

विनियोग (Investments) पर मिलने वाले सूद की दरें—
आधुनिक द्रव्य-बाजार में दो प्रकार की सूद की दर पाई जाती हैं। वे सूद की दरें जो खुले बाजार में प्रचलित होती हैं और जिन्हें हम खुले बाजार की दरें (Open market rate) कहते हैं और दूसरी वे सूद की दरें जो

ग्राहकों से ऋण देने पर ली जाती है। ग्राहकों से जो सूद लिया जाता है उसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु खुले बाज़ार की दरों के बारे में हमें प्रामाणिक आंकड़े मिलते हैं। ग्राहकों से लिये जाने वाले सूद की दरों में बहुत भिन्नता होती है। यदि किसी एक प्रदेश में सूद की दर बहुत ऊँची है तो दूसरे प्रदेश में सूद की दर नीची होती है। बात यह है कि जहाँ तक ग्राहकों से लिए जाने वाले सूद की दर का प्रश्न है वह स्थानीय कारणों पर निर्भर रहती है अतएव सूद की दर का भिन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए बैंकों को किसी प्रदेश में डिपॉजिट कम मिलती है तो वे वहाँ ऋण अधिक सूद लेकर ही देंगे और जहाँ डिपॉजिट बहुत अधिक मिलती है वहाँ कम सूद लेकर भी उस रुपये को लगाने का प्रयत्न करेंगे। जिस स्थान या प्रदेश का देश के केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है वहाँ सूद की दर कुछ कम रहती है। अतएव कहने का तात्पर्य यह है कि ग्राहकों से लिए जाने वाले सूद की दर स्थानीय कारणों पर निर्भर रहती है और उन्हीं कारणों से उसमें भिन्नता पाई जाती है।

खुले बाज़ार की दरें (Open Market rates)—(१) अभियाचन ऋण (Demand Loan) पर इम्पीरियल बैंक जो सूद लेता है वह देश में अल्पकालीन पूँजी (Short-term capital) पर कितनी आय हो सकती है इसको बतलाता है। इम्पीरियल बैंक की अभियाचना ऋण की दर हमें यह बतलाती है कि अल्प काल के लिए पूँजी लगाने से हमें कितनी आय हो सकती है। इम्पीरियल बैंक की अभियाचन ऋण की दर अल्प कालीन पूँजी पर होने वाली आय को नापने का र्वंश है। यह दर नक़द साख (Cash credits) तथा साधारण ऋणों पर लिए जाने की सूद की दरों का भी प्रतिनिधित्व करती है।

(२) इम्पीरियल बैंक हुडी रेट वह सूद की दर है जिस पर इम्पीरियल बैंक प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों को मुनाता है। २६२५ तक इम्पीरियल बैंक केवल ३ महीने की अवधि के बिलों को ही मुना सकता था। किन्तु व्यवहार में उन बिलों की पकने की अवधि केवल ६० या ६१ दिन होती थी।

हुडी रेट यर्षा इम्पीरियल बैंक की अभियाचन ऋण (Demand Loan) की सूद की दर के साथ-साथ घटती बढ़ती है किन्तु कभी कभी

इम्पीरियल बैंक की हुंडी दर उसकी अभियाचन ऋण की दर से ऊंची हो जाती है और कभी नीचे गिर जाती है।

(३) याचना द्रव्य रेट (Call money rate) उस सूद की दर को कहते हैं जो कि २४ घंटे के लिए दिए हुए ऋण पर लिया जाता है। याचना द्रव्य को (Call money) बैंक जिस समय चाहे वापस मांग सकता है और लेने वाला उसे जब चाहे वापस दे सकता है। भारतवर्ष में बैंक इस प्रकार ऋण केवल उन्हीं व्यक्तियों को देता है जो उसके जाने धूके होते हैं और जिनकी साख बहुत अच्छी होती है। बैंक इस प्रकार के ऋण के लिए कोई जमानत नहीं लेते केवल ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत साख पर दे देते हैं।

भारतवर्ष में याचना द्रव्य (Call money) अधिकतर केवल सोने चांदी के बाज़ार और शेयर बाज़ार में कारबार करने के लिए लिया जाता है। परन्तु बम्बई में बड़े व्यापारी साधारण व्यापार के लिये भी याचना द्रव्य लेते हैं क्योंकि उन्हें कम सूद पर रुपया मिल जाता है।

याचना द्रव्य की दर इम्पीरियल बैंक की अभियाचन ऋण की दर (Demand Loan rate) के अनुसार बढ़ती बढ़ती है। कभी-कभी याचना द्रव्य की दर बहुचो ऊंची चढ़ जाती है यहां तक कि इम्पीरियल बैंक की अभियाचन ऋण की दर (Demand Loan rate) के बराबर पहुँच जाती है। जब कारवार की बहुत तेजी होती है तो कभी-कभी याचना द्रव्य ऊंची दर पर भी नहीं मिलता और मदी के समय उसकी सूद की दर बहुत गिर जाती है। इन अवसरों पर याचना द्रव्य की सूद की दर का इम्पीरियल बैंक के अभियाचन ऋण की दर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

(४) बाज़ार बिल रेट या बाज़ार हुंडी रेट भारतीय द्रव्य बाज़ार (Money market) में सब से ऊँची सूद की दर होती है। यह सूद की दर उन बिलों पर ली जाती है जो आफ छोटे व्यापारियों के लिये भुनाते हैं। बाज़ार बिल रेट कलकत्ता की अपेक्षा बम्बई में कम रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि बम्बई में आफों (Shroffs) का बैंकों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुसंगठित द्रव्य-बाज़ारों की भांति भारतीय द्रव्य-बाज़ार में प्रचलित सूद की दरों का एक दूसरे से कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है। यदि बाज़ार में कारवार की तेजी हुई

और रुपये की मांग अधिक हुई और रुपया कम हुआ। दो सूद की दरें ऊंची चढ़ जाती हैं और यदि कारबार मंदा हुआ तो सूद फिर जाता है। किन्तु बाज़ार में प्रचलित सूद की दरों का आपस में कोई निश्चित और घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता। इसका कारण यह है कि भारतीय बैंकों में इस बात की भावना नहीं है कि उनके स्वार्थ एक हैं। रिज़र्व बैंक अभी तक इतना अधिक प्रभाव डाली नहीं है कि द्रव्य-बाज़ार पर अपना पूरा प्रभाव डाल सके और पूँजी (Capital) के एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता पूर्वक पहुँचाने में सफल रहे।

बैंकों की उन्नति और द्रव्य-बाज़ार को अधिक सगठित बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सूद की दरों के सम्बन्ध में बैंक एक आपसी समझौता कर लें तथा एक परम्परा बना लें। इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि बैंकों में आपस में अस्वरूपकर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जायेगी। उदाहरण के लिए लंदन में बैंकों ने यह निश्चय कर लिया है कि अल्पकालीन डिपॉजिट पर बैंक रेट से २ प्रतिशत सूद कम दिया जावे। बैंक रेट तथा डिपॉजिटों पर दिये जाने वाले सूद की दर का सम्बन्ध जोड़ देने से एक लाभ यह होगा कि बैंक डिपॉजिटों को खींचने के लिए अत्यस्थकर होइ नहीं कर सकेंगे।

भारतीय द्रव्य-बाज़ार में अस्थिरता तथा अधिक उतार-चढ़ाव का होना—भारतीय द्रव्य-बाज़ार का एक बड़ा दोष यह रहा है कि उसमें स्थिरता नहीं रहती। बैंक रेट में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते हैं। १९१२ के पूर्व अर्थात् आर्थिक मंदी (Economic Depression) के अधिक गहरे हो जाने के पूर्व जब व्यापार मंदा होता तब तो बैंक रेट ३ प्रतिशत पर रहती और तेज़ी के मौलम में ७ और ८ प्रतिशत तक चढ़ जाती। इस अस्थिरता के कारण व्यापार का नीतिम बंद जाता है तथा व्यापारियों को बहुत आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उद्योग-धंधों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था क्योंकि वे भी बहुत कुछ थोड़े समय के लिए प्राप्त किए श्रम पर निर्भर रहते थे। जन कारबार की तेज़ी होती और बैंक रेट ऊंची हो जाती तो देश के भीतरी व्यापार तथा खेती के लिए पूँजी मिलने में बहुत कठिनाई होने लगती थी क्योंकि बन्दरगाहों में भी उस समय पूँजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और वहाँ के व्यापार में अधिक सूद देने की गुंजाइश रहती थी। अतएव बैंक उस समय अपना रुपया बन्दरगाहों को भेज देते थे तथा देश के भीतरी व्यापार तथा खेती के लिए द्रव्य (money)

का टोटा पड़ जाता था। इसका कारण यह था कि जब कारबार की तेजी होती तो देश में द्रव्य का टोटा पड़ जाता था। कारण यह था कि भारतवर्ष के खेतिहर देश होने के कारण जब खेती की पैदावार की फसल के समय खरीद होती तो बहुत अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ती थी और जो भी करंसी (मुद्रा) देश में साधारणतः होती वह इस कार्य के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। किन्तु गरमियों तथा वर्षा के मौसम में जब कारबार मंदा रहता था तो वही करंसी आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती थी।

१९२१ में इम्पीरियल बैंक के स्थापित होने से पूर्व सरकार पृथक् और स्वतंत्र खजाने रखती थी जो चलन में से बहुत अधिक द्रव्य (Money) को खींच कर रख लेती थी। कारण यह था कि मालमुजारी के रूप में किसान जो द्रव्य देते थे वह इन खजानों में जाकर बन्द हो जाता था और यह उस समय होता था जब बाज़ार में द्रव्य की बहुत अधिक मांग होती थी। इस कारण बाज़ार में द्रव्य का बेहद टोटा पड़ जाता था। १९२१ के उपरान्त वह रूपया इम्पीरियल बैंक के पास आने लगा और वह इसको व्यापारियों को दे देता था अस्तु १९२१ के उपरान्त इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ। फिर भी भारत सरकार तथा भारत मंत्रो पृथक् और स्वतंत्र रूप से बैंकिंग का कारबार करते थे जिसके कारण द्रव्य-बाज़ार में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी। बात यह थी कि भारत सरकार तो मुद्रा (Currency) का नियंत्रण करती थी और इम्पीरियल बैंक कुछ हद तक साख (Credit) का नियंत्रण करता था। इस दोहरे नियंत्रण का फल यह होता था कि मुद्रा नीति (Currency policy) और साख नीति (Credit need) में कभी साम्य स्थापित नहीं हो पाता था। यदि उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होती तो अधिक साख (Credit) की आवश्यकता होती थी परन्तु अधिक साख का निर्माण तभी हो सकता है जब अधिक द्रव्य (Money) हो, परन्तु यदि उस समय सरकार अधिक नोट छाप कर द्रव्य राशि को न बढ़ाती तो बैंकों को साख कम करनी पड़ती थी। इस प्रकार उस समय देश में मुद्रा (Currency) तथा साख का कोई ठीक प्रबन्ध न था। कारण यह था कि साख का ठीक नियंत्रण तो था नहीं किन्तु जो कुछ भी नियंत्रण था वह इम्पीरियल बैंक के हाथ में था किन्तु साख मुद्रा (Currency) पर निर्भर रहती है किन्तु मुद्रा का नियंत्रण सरकार के हाथ में था।

रिज़र्व बैंक की स्थापना से द्रव्य-बाज़ार (Money Market) का यह

दोष दूर हो गया। अब रिज़र्व बैंक के अधिकार में दोनों ही कार्य हैं। वह कागज़ी मुद्रा (Paper Currency) तथा साख्त (Credit) दोनों का ही नियन्त्रण करता है अस्तु अब रिज़र्व बैंक द्रव्य की अधिक मांग होने पर अधिक नोट निकाल कर द्रव्य की कमी को दूर कर सकता है। आशा है कि भविष्य में जो वसतों की खरीद के समय देश में द्रव्य का टोटा पड़ जाता था अब वह दूर हो जावेगा।

भारतीय द्रव्य-बाज़ार में व्यापारिक विलों का प्रभाव—भारतीय द्रव्य बाज़ार का एक मुख्य दोष यह है कि यहाँ व्यापारिक विलों की बहुत कमी है। भारतीय बैंकों की लेनी (Asset) में विल बहुत कम होते हैं जबकि विदेशों में बैंक अपने कोष (Funds) का बहुत बड़ा भाग इनमें लगाते हैं। भारतीय निमित्त पैंडी वाले बैंक तथा इम्पीरियल बैंक की अपनी कुल डिपॉजिटों का केवल ३ से ६ प्रतिशत रुपया विलों के मुनाने में लगाते हैं। इसी से यह दृष्ट हो जाता है कि भारतीय द्रव्य-बाज़ार में विलों का नितान्त अभाव है। इसके नीचे लिखे मुख्य कारण हैं :-

(१) भारत में बैंक अपना रुपया सरकारी सिक्कूरिटियों अर्थात् परम प्रतिभूति (Gild edged Securities) में लगाना अधिक पसंद करते हैं। इसके दो कारण हैं एक तो भारत में बैंकिंग अभी अधिक उन्नत अवस्था में नहीं है इस कारण बैंक अपना रुपया ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो शीघ्र ही नकदी में परिणत किया जा सके और दूसरे सरकारी सिक्कूरिटियों पर सूद अच्छा मिलता था। किन्तु अब नितना सूद विलों के मुनाने से मिलता है उससे अधिक परम प्रातभूति (Gild edged Securities) अर्थात् सरकारी सिक्कूरिटियों पर नहीं मिलता। अतएव जैसे जैसे सर्वसाधारण का बैंकों पर अधिक विश्वास जमता जावेगा वैसे वैसे बैंक सरकारी सिक्कूरिटियों में कम रुपया लगाने लेंगे।

(२) जब जब बैंकों को श्रृण की आवश्यकता होती है तब-तब वे इम्पीरियल बैंक से सरकारी सिक्कूरिटियों की जमानत पर श्रृण लेना पसंद करते हैं और अपने विलों को इम्पीरियल बैंक से पुनः भुनाना (Rediscount) पसंद नहीं करते। इसके नीचे लिखे कारण हैं :-

(क) इम्पीरियल बैंक केवल उन्हा विलों को पुनः भुनाना है जिन्हें वह ठीक समझता है और पसंद करता है। किन्तु वह किस प्रकार के विलों को पसंद करेगा इसका उसने कोई मानदण्ड (Standard) कायम नहीं किया है

जिसके अनुसार अन्य बैंक यह जान सकें कि वह किन बिलों को पसंद करेगा। अतएव बैंकों को सदैव यह खतरा रहता है कि कहीं उनके बिलों को इम्पीरियल बैंक अस्वीकार न कर दे।

(ख) भारतीय द्रव्य-बाजार में यह प्रचलित धारणा है कि बिलों का पुनः भुनाना आर्थिक निर्बलता का सूचक है अतएव भारतीय बैंक बिलों को पुनः इम्पीरियल बैंक से भुनाने में इस कारण हिचकते हैं कि इससे उनकी साख पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(ग) इम्पीरियल बैंक अन्य बैंकों के लिये बट्टा दर (Discount Rate) में कोई रियायत नहीं करता। वह उनसे भी वही सूद लेता है जो वह देशी बैंकों से लेता है।

(घ) क्योंकि इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रतिद्वन्दी है इस कारण वे उसे यह नहीं बतलाना चाहते कि उनके पास कितने और कैसे बिल हैं।

(ङ) भारत में बिलों या हुंडियों पर हस्ताक्षर करने वालों की आर्थिक स्थिति या साख कैसी है यह जानने की सुविधा नहीं है। इंग्लैंड तथा अमेरिका में ऐसी एजेंसियाँ हैं जो किसी भी व्यापारी या व्यवसायी की आर्थिक स्थिति और साख के सम्बन्ध में थोड़ी सी फीस लेकर ठीक जानकारी दे देती हैं।

(च) भारत में हुंडियों तथा बिलों का उपयोग बहुधा ऋण देने और लेने में किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि 'क' 'ख' से २ हजार ऋण लेना चाहता है तो 'क' 'ख' पर हुंडी या बिल लिख देगा और 'ख' उसको स्वीकार कर लेगा। अब 'क' उस हुंडी या बिल को भुना कर रुपया प्राप्त कर लेगा। इन हुंडियों को देखने मात्र से यह कोई नहीं बता सकता कि वह केवल कर्ज लेने के उद्देश्य से लिखा गया है अथवा व्यापारिक हुंडी है। क्योंकि हुंडी के साथ न तो रेल की बिल्टी होती है और न अन्य प्रकार के कोई कामकाज पत्र होते हैं।

(छ) भारत में मुहत्ती हुंडी का चलन लगभग समाप्त हो गया क्योंकि उस पर स्टाम्प खूबी का खर्चा अधिक होता है। वह केवल बंगाल में तथा बम्बई और शिफारपुर में ही अधिक प्रचलित है। अब मुहत्ती हुंडी का स्थान दर्शनी हुंडी ने ले लिया है किन्तु उनसे बहुत थोड़े दिनों की ही साख मिल

पाती है। यहाँ दुदियों के चलन में एक कठिनाई यह है कि उनके सकारने में बहुत सी शर्तें होती हैं। यहाँ नहीं दुदियों का कोई निश्चित रूप भी नहीं है। न तो उनकी लिपि और भाषा ही एक होती है और भिन्न भिन्न स्थानों पर निकराने और सकारने (Acceptance and payment) के नियम भी भिन्न होते हैं।

(६) भारत में बिल या दुदियों के अभाव का एक कारण यह भी है कि बैंक नकद साख (Cash Credit) अधिक देते हैं। नकद साख बैंकों तथा कर्ज लेने वालों दोनों के ही लिए लाभदायक सिद्ध होती है। कर्ज लेने वालों का लाभ तो यह है कि जितनी साख का वह उपयोग करते हैं उतने पर ही उन्हें खुद देना पड़ता है और बैंक का लाभ यह होता है कि बैंक हमारा जरूरी चाहे वापस मांग सकता है। यदि कर्जदार की आर्थिक स्थिति पिछड़ी मालूम पड़े तो बैंक मुख्यतः उससे अपना वापस ले सकता है। किन्तु बिल नकद साख से बिल दोनों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। क्योंकि कर्ज लेने वालों को बिलों की अवधि तक एक निश्चित राशि की साख (Credit) मिल जावेगी और यदि पुनः भुनाने की सुविधा हो तो बैंकों को एक अत्यन्त तरल लेनी (Liquid Asset) में अपना धन लगाने का अवसर मिल जावेगा। फिर कर्जदार को यह भी लाभ होगा कि वह नकद साख पर जितना खुद देता है उससे कम पर बिल को भुना सकेगा।

(७) भारतीय द्रव्य बाजार में बिलों या दुदियों का चलन न होने का एक यह भी कारण है कि भारत सरकार बहुत अधिक राशि में सरकारी दुदियाँ (Treasury Bills) बेचती है। बैंक इन सरकारी दुदियों को बहुत बड़ी राशि में खरीदते हैं क्योंकि वे बहुत सुरक्षित होते हैं और निश्चित समय पर उनका मुगलान हो जाता है और वे तरल भी होते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक उन्हें खरीदने के लिए सदैव तैयार रहता है।

फिरी सेंट्रल बैंकिंग जॉब कमेटी तथा सभी बैंकिंग विभागों की राय है कि जब तक देश में व्यापारिक बिलों का चलन और उपयोग नहीं बढ़ता और भारत में सक्रिय रहा बाजार (Discount Market) का उदय नहीं होता तब तक भारतीय बैंक सख्त और उन्नत नहीं हो सकते। रिजर्व बैंक ही इस देश में दुदियों और बिलों के चलन और उपयोग को बढ़ा सकता है और देश में बड़ा बाजार (Discount Market) स्थापित कर सकता है। रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह अन्य बैंकों को अपने बिलों

को पुनः भुनाने (Rediscount) की सभी सुविधायें दे, उन्हें यह निश्चित रूप से बतला दिया जाय कि किस प्रकार के बिल या हुंडियों को यह पसंद करेगा । रिजर्व बैंक को चाहिये कि वह देशी बैंकरो (Indigenous Bankers) को बड़ा गृह (Discount Houses) का काम करने के लिए प्रोत्साहित करे । देशी बैंकर व्यापारियों के बिलों या हुंडियों को भुनावे और यदि उन्हें अधिक कोष (Funds) की आवश्यकता हो, तो वे रिजर्व बैंक से उन बिलों या हुंडियों को पुनः भुना लें । रिजर्व बैंक को देशी बैंकरो को अपने बिलों को पुनः भुनाने की सभी सुविधायें देना चाहिये । इससे एक लाभ यह भी होगा कि देशी बैंकरो तथा द्रव्य-बाजार का सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा । यदि देश में प्रमाणित भंडारों तथा गोदामों की व्यवस्था हो जावे जिनका प्रबंध विश्वसनीय हो तो हुंडियों और बिलों का चलन अधिक बढ़ सकता है क्योंकि इन गुदामों और भंडारों की रसीद के साथ जो बिल या हुंडी होगी उसके व्यापारिक बिल या हुंडी होने में तनिक भी संदेह नहीं रहेगा और बैंक उन हुंडियों को भुनाने से नहीं हिचकेंगे । जो कुछ भी हो बैंकिंग की उन्नति के लिए बिलों और हुंडियों के चलन की बहुत आवश्यकता है ।

अध्याय—२३

भारत में बैंकिंग सम्बन्धी कानून

१९३६ तक भारत में बैंक सम्बन्धी कोई विशेष कानून नहीं था। बैंक की अन्य मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों (Joint Stock Companies) की भाँति (१९१३ के कंपनी ऐक्ट के अन्तर्गत) रजिस्टर होते ये और बैंकों के लिए भी वही नियम थे जो अन्य कंपनियों के लिए लागू थे। १९१३ के कंपनी ऐक्ट में बैंकों तथा अन्य कंपनियों के बीच में केवल दो बातों में भेद किया गया था। एक अन्तर तो यह था कि १० व्यक्तियों से अधिक साझेदारों वाली जर्ने बैंकिंग कारबार नहीं कर सकती और बैंकों की लेनी-देनी का हिसा (Balance Sheet) एक निर्धारित ढंग से बनाया जावेगा जिसमें मुद्रित ऋण (Secured Debts) तथा अरक्षित ऋण (Unsecured Debts) अलग अलग दिखाताना आवश्यक था।

किन्तु इस कानून के द्वारा बैंकों का ठोक नियंत्रण नहीं किया जा सका था। सभी देशों में बैंकिंग का कारबार विशेष महत्त्व का सम्का जाता है क्योंकि वे जनता की डिपॉजिट अकॉम्प्लिश करते हैं और देश के आर्थिक जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक देश में बैंकों का नियंत्रण करने के लिए विशेष बैंकिंग कानून आवश्यक समझा गया। भारतवर्ष में बैंकिंग सम्बन्धी विशेष कानून का न होना सब को सतर्कता था और विशेषकर जब १९१३ और १४ में भारतवर्ष में बैंकों का सकल उपरिप्लव हुआ और बहुत से बैंक डूब गए उस समय से सब का विश्वास टूट हो गया कि देश में विशेष और स्वतंत्र बैंकिंग कानून के बन आने से शक्तिमान और अच्छे बैंकों के उदय होने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि हमें यह न भूल जाना चाहिये कि चाहे कैसा ही अच्छा बैंकिंग कानून क्यों न बनाया जावे वह जुर्र प्रवर्ध, हानि और बैंकों के डूबने को नहीं रोक सकता। बैंक या बैंकर को केवल कानूनों द्वारा उत्तम नहीं किया जा सकता। यही नहीं यदि बैंकों के लिए बहुत समझा चौड़ा कानून बना दिया जावे तो उनकी उन्नति में रुकावट होती है। बैंकों पर बहुत अधिक न्ययन लगा देना उनकी उन्नति को रोकना है। बैंकों को जहाँ तक हो सके

स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए । हाँ रिज़र्व बैंक के नियंत्रण की बैंकों की उन्नति के लिए अवश्य आवश्यकता है । इतना सब होते हुए बैंकिंग कानून की इसलिये आवश्यकता है कि जिससे बेईमानी, धोखे और कुप्रवच को कुछ हद तक रोका जा सके । यही कारण था कि सेन्ट्रल बैंकिंग जाँच कमेटी ने एक स्वतंत्र बैंक कानून की आवश्यकता बतलाई ।

उस समय भारत सरकार ने यद्यपि स्वतंत्र बैंक कानून तो नहीं बनाया परन्तु १९३६ के कंपनी ऐक्ट में बैंकों के लिए कुछ विशेष नियम बना दिये जो नीचे लिखे हैं ।

(१) बैंकिंग कंपनी की कंपनी ऐक्ट में इस प्रकार परिभाषा की गई— बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जिसका मुख्य कारवार जनता के रुपये को ऐसी डिपॉजिटों के रूप में स्वीकार करना है जो चेक, ड्राफ्ट या आशा के द्वारा निकाली जा सकें । इसके अतिरिक्त वह नीचे लिखे कार्य भी कर सकती हैं : (क) रुपया कर्ज लेना और देना, बिलों और हुंडियों, प्रामिसरी नोट, कंपनियों के हिस्सों, डिबेंचरों, रेलवे रसीद, तथा सोने चाँदी की खरीद-विक्री करना और द्रव्य और लिक्विडिटी को वसूल करना और एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना । (ख) सरकार, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तथा व्यक्तियों के एजेंट का काम करना । लेकिन बैंक किसी कंपनी का मैनेजिंग एजेंट नहीं हो सकता । (ग) सरकार तथा व्यक्तियों के लिए ऋण दिलाना तथा ऋण को निकालना । (घ) सरकारी तथा म्युनिसिपल ऋण का अभिगोपन (Underwriting) करना तथा कंपनियों के हिस्सों या डिबेंचरों का अभिगोपन करना । (ङ) किसी व्यापारी कारवार को आर्थिक सहायता देना । (च) चल अथवा अचल सम्पत्ति की खरीद-विक्री करना । (छ) किसी का ट्रस्टी बनना । (ज) किसी दूसरी कंपनी के हिस्से खरीदना या प्राप्त करना जिसके उद्देश्य उसके ही समान हों । (झ) उन संस्थाओं और कोषों (Funds) को स्थापित करना जो कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए हों । (ञ) कंपनी के लिए आवश्यक इमारतों को खरीदना ।

कोई भी बैंकिंग कंपनी ऊपर लिखे कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कर सकती और भविष्य में कोई बैंकिंग कंपनी रजिस्टर नहीं की जा सकती जिसके उद्देश्य डिपॉजिट लेने तथा ऊपर के कार्यों तक सीमित न हों ।

किसी भी बैंकिंग कंपनी का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेंट नहीं कर सकते । भविष्य में कोई भी बैंकिंग कंपनी जो रजिस्टर की जा चुकी हो उक्त समय तक

कार्य नहीं कर सकती जब तक उसकी चुकता पूँजी कम से कम ५०,००० रुपये हो ।

प्रत्येक बैंकिंग कंपनी उस समय तक जब तक उसका रक्षित कोष (Reserve Fund) उसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) के बराबर नहीं हो जाता लाभ का कम से कम २० प्रतिशत रक्षित कोष में जमा करेगी और शेष लाभ ही हिस्सेदारों में बाँट सकेगी । रक्षित कोष या तो सरकारी अथवा ट्रस्ट रिकॉर्डियों में लगाया जावेगा अथवा किसी अन्य शिष्ट बैंक में जमा कर दिया जावेगा ।

प्रत्येक बैंक (शिष्ट बैंकों को छोड़ कर) को रिज़र्व बैंक के पास अपनी चालू जमा (Current Deposit) का ५ प्रतिशत तथा मुहती जमा (Fixed Deposit) का १३ प्रतिशत जमा करना होगा और प्रत्येक महीने रजिस्ट्रार को एक लेखा भेजना होगा जिसमें पिछले महीने के प्रत्येक शुक्रवार को उसकी कितनी देनी (Liability) थी तथा उसके पास कितना नकद कोष (Cash Reserve) था यह पताना होगा ।

जो भी व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी का श्रुषी हो अथवा आगे चल कर उसका कर्जदार हो जावे उसका आडिटर (आय-व्यय निरीक्षक) नहीं बनाया जा सकता । बैंकिंग कंपनी को अपने लेनी देनी के लेखे (Balance Sheet) में बैंक के डायरेक्टरो, मैनेजरो तथा कंपनी के अन्य कर्मचारियों पर कितना श्रुय है यह अलहदा दिसलाना होगा ।

रिज़र्व बैंक का र्थक ऐक्ट बनाये जाने का प्रस्ताव—नवम्बर १९३६ में रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा और उसमें बैंक ऐक्ट बनाये जाने की आवश्यकता बतलाई । साथ ही बैंक ऐक्ट में किन बातों का समावेश होना चाहिए उसका एक लेख बना कर भेजा । रिज़र्व बैंक का कहना यह था कि अधिकांश बैंकों की पूँजी और रक्षित कोष बहुत कम है तथा वे डिपॉजिटरो के हितों की चिन्ता नहीं करते इस कारण सरकार को एक कानून बना ॥ डिपॉजिटरो के हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

रिज़र्व बैंक का प्रस्तावित बैंक बिल इस प्रकार था—बैंक को परिभाषा अधिक निश्चित और सीमित कर देनी चाहिए और कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कार्य नहीं करती उसे अपने नाम के आगे बैंक शब्द जोड़ने का अधिकार न होगा । जो कंपनी बैंकिंग कार्य करती है वह अपने नाम

के साथ बैंक शब्द अवश्य जोड़ेगी। कोई भी बैंक उन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कारवार नहीं करेगी जिनका बिल में समावेश है।

कोई भी बैंक उस समय तक बैंकिंग कार्य न कर सकेगा जब तक उसकी चुकता पूँजी और रक्षित कोष (Reserve) कम से कम एक लाख रुपये न हो और यदि बैंक नीचे लिखे स्थान में से किसी में कारवार करता है अर्थात् ब्रांच खोलता है तो उसको प्रत्येक स्थान के लिए नीचे लिखे अनुसार पूँजी रखनी होगी :—यम्बाई और कलकत्ते के लिए ५ लाख, प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए जिसकी आबादी एक लाख से अधिक हो कम से कम २ लाख रुपये। यदि बैंक उस प्रान्त या राज्य के बाहर ब्रांच खोलना चाहता है जिसमें उसका हेड आफिस है तो उसकी चुकता पूँजी (Paid up Capital) और रक्षित कोष कम से कम २० लाख रुपये होना चाहिए। अर्थात् यदि किसी बैंक की चुकता पूँजी और रक्षित कोष २० लाख रुपये से अधिक है तो वह भारतवर्ष भर में जहाँ चाहे ब्रांचें खोल सकता है।

किसी बैंक की विक्रित पूँजी (Subscribed capital) उसकी अधिकृत पूँजी (Authorised capital) की आधी से कम और चुकता पूँजी (Paid up capital) विक्रित पूँजी से आधी से कम न होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised capital) ४ करोड़ रुपये है तो कम से कम २ करोड़ रुपये उसकी विक्रित पूँजी होनी चाहिए और १ करोड़ रुपये उसकी चुकता पूँजी होनी चाहिए।

प्रत्येक बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी चालू जमा और मुहती जमा का ३० प्रतिशत या नक़्द कोष (Cash Reserve) के रूप में अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत सिक्कूरिटियों के रूप में रखना होगा। प्रत्येक बैंक को प्रत्येक वर्ष १ फरवरी के पहले रिज़र्व बैंक में अपनी कुल डिपॉजिटों का लेखा तथा बैंक के पास कितनी देनी (Assets) है उसका लेखा भेजना होगा। कुल देनी (Liabilities) की ७५ प्रतिशत देनी (Assets) वह होगी जिन्हें रिज़र्व बैंक स्वीकार करे।

किन्तु भारत सरकार ने उस समय बैंक ऐक्ट बनाना अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार का कहना था कि युद्ध समाप्त हो जाने के उपरान्त ही इस प्रकार का कानून बनाना उचित होगा। किन्तु १९४१ और १९४२ में नये बैंकों की एक बाढ़ सी आ गई बहुत से नये बैंक स्थापित हुए। उनमें से बहुतों की अधिकृत पूँजी (Authorised capital) तो बहुत अधिक

भी किन्तु चुकता पूँजी बहुत कम थी। साथ ही बहुत से बैंकों ने पूर्वाधिकार वाले हिस्से (Preferential Shares) साधारण हिस्से (Ordinary Shares) तथा विलम्बित हिस्से (Deferred Shares) निकाले और पूर्वाधिकार वाले हिस्सों को मत देने का अधिकार ही नहीं दिया और विलम्बित हिस्सों (Deferred Shares) का मूल्य बहुत थोड़ा रक्खा एक या दो रुपया और उनको भी मत का अधिकार उतना ही दे दिया जितना साधारण हिस्से वाले को या जिनका मूल्य बहुत अधिक था। सच तो यह था कि यह युक्ति कुछ लोगों ने बैंक में बहुत कम पूँजी लगा कर बैंक को अपने हाथ में रखने के लिए निवाली थी। उदाहरण के लिए यदि एक बैंक स्थापित किया जाता है और उसकी विक्षिप्त पूँजी (Subscribed capital) केवल एक करोड़ रुपया है इसमें २० हजार पूर्वाधिकार वाले हिस्से (Preferential Shares) हैं जिनका मूल्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो पूरा चुका दिया गया है। ७५ हजार साधारण हिस्से हैं जिनका मूल्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो पूरा चुका दिया गया है और केवल २ लाख विलम्बित हिस्से (Deferred Shares) जिनका मूल्य प्रति हिस्सा २½ रु० है और जिन पर प्रति हिस्सा केवल १ रुपया चुकाया गया है। अब बैंक को स्थापित करने वाले चतुर व्यवसायी विधान में यह नियम बना दें कि पूर्वाधिकार वाले हिस्सों को मतदान का कोई अधिकार न होगा अथवा एक हिस्से का एक वोट होगा और प्रत्येक साधारण हिस्से का एक वोट होगा और प्रत्येक विलम्बित हिस्से का भी एक वोट होगा और वे सब विलम्बित हिस्से खरीद लेते हैं और उन पर प्रति हिस्से के हिसाब से एक रुपया चुका देते हैं तो वे केवल २ लाख रुपये लगा कर २ लाख वोट प्राप्त कर लेंगे और साधारण हिस्सेदार और पूर्वाधिकार वाले हिस्सेदार ६५ लाख रुपये लगाकर भी कुल ६५ हजार वोटों के अधिकारी होंगे। इस प्रकार बैंक उन लोगों के जिन्होंने चालाकी से विलम्बित हिस्से खरीद लिए हैं अधिकार में चला जावेगा।

जब रिजर्व बैंक ने देखा कि नवीन स्थापित बैंकों में यह दोष बड़ी मात्रा में पाया जाता है तो रिजर्व बैंक ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। भारत सरकार ने १९४३ में कम्पनी ऐक्ट में संशोधन कर दिया और उसके अनुसार यह निश्चित हो गया कि जिस कम्पनी के नाम के साथ बैंकिंग या बैंकर लगा है उसको बैंकिंग कम्पनी स्वीकार किया जावेगा फिर चाहे उसका मुख्य कार्य ऐसा डिपॉजिट लेना जो कि चेक से निकाली जा सके हो।

या ■ हो। उसके साथ ही सरकार ने यह भी नियम बना दिया कि प्रत्येक बैंक की विक्रित पूँजी (Subscribed capital) कम से कम अधिकृत पूँजी (Authorised capital) की आधी होगी और चुकता पूँजी (Paid-up capital) विक्रित पूँजी की कम से कम आधी होगी। और बैंक या तो केवल साधारण हिस्से (Ordinary Shares) ही रखें या यदि भिन्न प्रकार के हिस्से रखें तो उनके मतदान का अधिकार उनकी पूँजी के अनुपात में ही होगा। उदाहरण के लिए ऊपर जिस कल्पित बैंक का हमने उल्लेख किया है यदि उसमें पूर्वाधिकार वाले हिस्सेदारों को २० हजार, साधारण हिस्सेदारों को ७५ हजार तथा विलम्बित हिस्सेदारों को केवल २ हजार मत देने का अधिकार होगा।

इतना सब कुछ होने पर भी युद्ध काल में नये बैंकों की स्थापना इस तेजी से हुई और उनमें कुछ ऐसे दोष दृष्टिगोचर होने लगे कि भारत सरकार को स्वतंत्र बैंक कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा और १९४५ में भारत सरकार ने एक बिल धारा सभा में उपस्थित किया। यह प्रस्तावित बैंक कानून रिज़र्व बैंक के प्रस्तावित बैंक बिल के अनुसार ही है केवल उसमें इतना ही अन्तर है कि इस प्रस्तावित कानून में बैंक की परिभाषा इस प्रकार की गई है—बैंक वह है जो अभिवाचन डिपॉजिट या जमा (Demand Deposit) स्वीकार करे। कोई भी बैंक अपने डायरेक्टरों को अथवा उस फर्म या कम्पनी को जिसका साझेदार, डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट बैंक का कोई डायरेक्टर हो अरक्षित ऋण (Unsecured loan) नहीं दे सकता। इस प्रस्तावित बैंक कानून के अनुसार प्रत्येक बैंक को जो अपने जन्म प्रान्त के बाहर कारबार करे कम से कम २० लाख रुपये की चुकता पूँजी और रक्षित कोष रखना आवश्यक है। बम्बई या कलकत्ता में ब्रांच खोलने के लिए ५ लाख, प्रत्येक ऐसे स्थान पर जिसकी आवादी १ लाख से ऊपर हो २ लाख और प्रत्येक दूसरी ब्रांचों के लिए प्रति ब्रांच के हिसाब से १० हजार रुपये की पूँजी और रक्षित कोष आवश्यक होगा। कोई भी बैंक एक लाख की पूँजी और रक्षित कोष के बिना बैंक कार्य नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कानून में प्रत्येक बैंक को अपनी कुल डिपॉजिट का २५ प्रतिशत रिज़र्व बैंक के पास नकद कोष (Cash Reserve) अथवा सरकारी और ट्रस्ट सिक्यूरिटियों के रूप में रखना अनिवार्य होगा।

इस बिल में उन कार्यों का भी उल्लेख किया गया था जो एक बैंक

कर सकता था। यह इसलिये किया गया था कि जिससे रुपये जमा करने वालों की अमानत (जमा) की सुरक्षा हो। बिज का उद्देश्य यह था कि व्यापारिक बैंक अपना धन उद्योग पंथों में लम्बे समय के लिये न लगावें। उनके लिये औद्योगिक बैंकों की स्थापना आवश्यक है। जर्मनी, इटली और नैलजियम में जिस प्रकार व्यापारिक कारबार करने के साथ-साथ स्थायी अथवा अर्ध स्थायी रूप से उद्योग पंथों में पूँजी लगाने की परिपाटी चल रही है उसे भारत में न बनाने देना ही इस धारा का उद्देश्य था।

विल में दो धारों इस आशय की भी थी कि बैंक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार की व्यापारिक जोखिम को अपने ऊपर नहीं लेंगे और इस उद्देश्य से वे बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापार में नहीं करेंगे। *Faust Harrison Sal. Walker.*

विल में एक धारा इस आशय की भी थी कि जो बैंक भारत या प्रिटेन के बाहर स्थापित हुए हैं और वे भारत में अपना कारबार करते हैं। उन्हें रिज़र्व बैंक के पास रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित अमानत (जमा) रखनी होगी। इसके द्वारा उन भारतीयों को जो विदेशी बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं योही सुरक्षा देने का प्रयत्न किया गया था।

इस विल के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे प्रत्येक महीने अपने कारबार का लेखा और उन्होंने अपनी पूँजी कहाँ लगाई इसका धोरा रिज़र्व बैंक को देंगे जिससे रिज़र्व बैंक उनकी गति-विधि से पूरी तरह से परिचित हो सके।

विल के अनुसार रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों की जाँच करने का भी अधिकार प्राप्त था।

किन्तु १९४४ का यह बैंकिंग विल व्यवस्थापिका सभा के मंग हो जाने के कारण व्यवस्थापिका सभा के सामने उपस्थित न किया जा सका।

अन्त में ११ अप्रैल १९४६ को उत्कालीन अर्थ सदस्य सर रोल्डस ने पुराने विल का संशोधन करके फिर व्यवस्थापिका सभा के सामने उपस्थित किया जो सेलेक्ट कमेटी के मुखर्द कर दिया गया। यह विल १९४४ के विल के आधार पर ही बनाया गया था। इसमें केवल कुछ संशोधन किये गये थे। इस नये विल के अनुसार रिज़र्व बैंकों को किसी भी बैंक के हिसाब सभा कारबार की जाँच करने का अधिकार था। यह विल विदेशी बैंकों पर

भी लागू होता तथा इसके अनुसार एक विशेष प्रकार की लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) निर्धारित कर दिया गया तथा रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों से सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। बैंकों को बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने की मनाही कर दी गई। बिना पूर्व आशा लिए कोई दो बैंक का जहाँ तक पूँजी के संगठन का प्रश्न था वह पूर्ववत् ही रहता गया।

किन्तु यह बिल भी शीघ्र पास न हो सका। इस बीच में आवश्यकता पड़ने के कारण सरकार ने १९४६ में एक आर्डिनैस बनाकर रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों की जाँच का अधिकार दे दिया। साथ ही रिज़र्व बैंक को यह भी अधिकार दे दिया गया कि यदि उसकी जाँच का परिणाम यह निकले कि बैंक का कार्य ठीक नहीं है तो रिज़र्व बैंक उस बैंक को आगे जमा न लेने की आज्ञा दे सकता है और उसको शिथिल बैंक की श्रेणी से निकाल सकता है। रिज़र्व बैंक ने इस अधिकार का प्रयोग किया और इंटर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, आर्यन बैंक तथा ज्वाला बैंक इत्यादि को आगे बिपाज़िट न लेने की आज्ञा दे दी।

एक दूसरे आर्डिनैस से भारतीय बैंकों को बेयरर प्रामिसरी नोट निकालने की मनाही कर दी गई। वास्तव यह भी कि यदि कोई बैंक बेयरर प्रामिसरी नोट निकाले तो वे बिना किसी अद्वचन के एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकेंगे और उनका चलन बैंक नोटों के अनुसार होने लगेगा।

एक तीसरा विधान यह बनाया गया कि कोई बैंक बिना रिज़र्व बैंक की आज्ञा प्राप्त किए कोई नई शाखा नहीं खोल सकेगा और न स्थापित शाखा के स्थान को ही बदल सकेगा। रिज़र्व बैंक उस बैंक की आर्थिक स्थिति, प्रबंध, उस बैंक का पुराना इतिहास, लाभ की आशा तथा जनहित को ध्यान में रखकर किसी बैंक की स्थापित जाँच को रद्द करने तथा उसके स्थान परिवर्तन की आज्ञा देगा अथवा नहीं देगा।

बैंकिंग बिल १९४८ :—१९४६ का बैंक बिल भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा में न लाया जा सका क्योंकि अगस्त १९४७ में भारत स्वतंत्र हो गया अतएव उस बिल में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अस्तु पुराने बिल को सरकार ने वापस ले लिया और १९४८ में एक नया बिल व्यवस्थापिका समा के

सामने उपस्थित किया गया। १९४८ के दिन को मुख्य बातें नीचे निम्न अनुसार हैं।

(१) बैंक की एक निश्चित परिमाणा स्वीकार कर ली गई है। किन्तु भी प्रकार की उम परिमाणा के अनुसार जो भी सहाय्य प्रदान देने के लिए अपना विनियोग (Investment) के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु (डिपॉजिट) स्वीकार करे वह बैंक की श्रेणी में गिनी जावेगी।

(२) जो बैंक नहीं है उन्हें चालू वसा स्वीकार करने की मनाही कर दी गई है।

(३) कोई बैंकिंग कम्पनी किसी अन्य प्रकार का व्यापार अपना करार नहीं कर सकता। इस प्रकार बैंकिंग कारखाने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की जोरिम बैंकों पर नहीं रहेगी।

(४) १९४५ के दिन में जो न्यूनतम पूँजी का विधान किया गया था उसको इस दिन में बेते या बेसा ही स्वीकार कर लिया गया।

(५) बैंक के हिस्सेदारों को लाभ समिति कर दिया गया है।

(६) जो बैंक भारत के बाहर स्थापित हुए हैं उन पर भी यह कानून लागू होगा।

(७) बैंकों का अपनी लेनी देनी का लेखा (बैलेंस शीट) एक विशेष फार्म के अनुसार तैयार करना होगा। रिज़र्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यह प्रत्येक बैंक से समय समय पर उनके कारखाने के ब्रांचे माँग सके।

(८) जब भी रिज़र्व बैंक को आवश्यकता होगी वह किसी भी बैंक के हिसाब की जाँच कर सकता है।

(९) केन्द्रीय सरकार को इस कानून के अनुसार यह अधिकार प्राप्त हो गया कि यदि उसको प्रतीत हो कि कोई बैंक रुपया जमा करने वालों के हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वह जा भी कार्यवाही उस बैंक के विरुद्ध करना चाहे कर सके।

(१०) बिल में इस बात का प्रस्ताव कर दिया गया है कि रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जावे।

(११) यदि कोई बैंक दिवालिया हो जावे तो उसका कारखाना सभेदने में अधिक गतिमान लगे उसका प्रबन्ध भी बिल में कर दिया गया है।

(१२) इम्पीरियल बैंक आव इंडिया पर भी इस कानून की कुछ रायें लागू होगी ।

(१३) रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों के संकट के समय उनकी सहायता कर सके इसके लिए कानून द्वारा उसे विशेष अधिकार दे दिए गए हैं ।

अन्ततः यह विल व्यवस्थापिका सभा में स्वीकार किया जाकर कानून बन गया । बहुत वर्षों के प्रयत्नों के बाद पहली बार भारत में बैंक सम्बन्धी कानून बना । आशा है कि इस कानून के प्रभाव से तथा रिज़र्व बैंक की देख-भाल, नियंत्रण तथा नेतृत्व के कारण देश में बैंक अधिक कार्यशील और सुसंगठित बन सकेंगे ।

अध्याय—२४

द्वितीय महायुद्ध तथा देश के विभाजन का भारतीय बैंकिंग पर प्रभाव

(१) द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर पहला प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ नये बैंकों की बाढ़ सी आ गई, अनेक नये बैंक स्थापित हुए और पुराने बैंकों ने तेजी से अपनी ब्रांचों को बढ़ाया। इसका कारण यह था कि युद्ध काल में धंधों को खड़ा करने के लिए मशीन तथा यन्त्र तो विदेशों से आ नहीं सकते थे जो फैक्टरियाँ स्थापित की जा सकती थीं और न इमारतें इत्यादि बनाने की सुविधा थी। किन्तु बैंक स्थापित करने में इन चीजों की आवश्यकता न थी। उसके लिए केवल अल्पकालीन कोष (Short-term Funds) की आवश्यकता थी और वह युद्ध काल में इस देश में बहुतायत से उपलब्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक बड़े पूँजीपति या व्यवसायी ने अपना बैंक खड़ा कर दिया। आज ऐसा कोई प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी नहीं है जिसने इस समय एक बैंक स्थापित नहीं किया। यदि भारत सरकार नई मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के स्थापित होने पर रोक न लगा देती तो सम्भवतः भारत में अनाप्त-अनाप्त बैंकों की वृद्धि होती। फिर भी जहाँ १९१९ के जून में इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंकों को मिला कर सब शिङ्गल बैंकों की संख्या ११ थी वह १९४४ में बढ़ कर ७६ हो गई और उनकी ब्रांचों की संख्या १९१२ से बढ़कर २१४१ हो गई और १९४७ में ६४ या ६५ हो गई। १९१६ के अन्त तक सब शिङ्गल बैंकों की ब्रांचों की संख्या बढ़कर १५१९ हो गई। इनमें ४४५ ब्रांचें इम्पीरियल बैंक की थी, ७८० ब्रांचें पाँच बड़े बैंकों की थी और अन्य शिङ्गल बैंकों की शाखों की संख्या २२०७ थी।

बैंकों की इस कल्पनासीत वृद्धि के होने पर प्रति ब्रांच बड़े बैंकों में १५ लाख रुपये और साधारण और छोटे बैंकों में ३ लाख रुपये से डिपॉजिटों का औसत कम नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध काल में बैंकों की डिपॉजिट भी बेहद बढ़ गई। इम्पीरियल बैंक विनिमय बैंकों और भारतीय मिश्रित पूँजी वाले बैंकों की स्थिति १९४१ तक लगभग पूर्ववत् ही रही परन्तु जापान के युद्ध में सम्मिलित होते ही विनिमय बैंकों (एक्स्चेंज बैंकों)

की अनुपातिक डिपाज़िट गिरने लगीं। जहाँ युद्ध के पूर्व एक्सचेंज बैंकों की डिपाज़िट कुल बैंकों की डिपाज़िटों का २६.५ प्रतिशत थीं गिरकर १९४२ में २५ प्रतिशत और १९४३ में २० प्रतिशत से भी कम हो गईं। उसी समय इम्पीरियल बैंक ने निदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का कार्य तेज़ी से आरम्भ कर दिया था और उसकी ऊँची साख तथा अधिक विस्तार होने के कारण जो एक्सचेंज बैंकों को हानि हुई वह इम्पीरियल बैंक के लिए लाभदायक प्रमाणित हुई। एक्सचेंज बैंकों की डिपाज़िटों का अनुपात कम हुआ किन्तु इम्पीरियल बैंक की डिपाज़िटों का अनुपात १९४२ में बढ़ कर ३७ प्रतिशत हो गया किन्तु बहुत से नवीन बैंक स्थापित हो जाने के कारण १९४३ में इम्पीरियल बैंक की डिपाज़िटों का अनुपात गिर कर ३० प्रतिशत से भी नीचे हो गया। १९४३ में भारतीय मिश्रित बैंकों की डिपाज़िटों का अनुपात तेज़ी से बढ़ गया। जहाँ १९३६ में उनकी डिपाज़िटों का अनुपात केवल ३८ प्रतिशत था वहाँ १९४३ में वह बढ़ कर ४६ प्रतिशत हो गया। भारतीय मिश्रित बैंकों में भी १९४२ तक 'बड़े पाँच' के पास ही भारतीय बैंकों की अधिकांश डिपाज़िट थीं वहाँ १९३६ में बड़े पाँच की डिपाज़िटों का अनुपात कुल भारतीय बैंकों की डिपाज़िटों का ७० प्रतिशत था १९४२ में वह बढ़कर ८० प्रतिशत हो गया। किन्तु १९४३ में बहुत से नये बैंकों के स्थापित हो जाने के कारण यह गिरकर ६० प्रतिशत रह गया और 'बड़े सात' की डिपाज़िटों का अनुपात ७५ प्रतिशत से घटकर ६१ प्रतिशत रह गया।

युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि बैंकों की डिपाज़िट में कल्पनातीत वृद्धि हुई। इम्पीरियल बैंक, एक्सचेंज बैंक तथा अन्य शिखर बैंकों की कुल डिपाज़िट युद्ध आरम्भ होने के समय २३८ करोड़ रुपये थीं। १९४४ में वही बढ़ कर ७८२ करोड़ रुपये हो गई। और जनवरी १९४८ में वही बढ़कर १०८० करोड़ रुपये के लगभग हो गई। यह ध्यान में रखने की बात है कि १९३६ से १९३६ तक केवल २० करोड़ रुपये की बैंकों की डिपाज़िट में वृद्धि हुई थी। जहाँ एक ओर बैंकों की डिपाज़िट में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी वहाँ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंकों की डिपाज़िट तथा कैश सर्टिफिकेट में कमी हो गई। १९२८ में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपाज़िट तथा कैश सर्टिफिकेट की रकम १४० करोड़ थी वह घट कर १९४१ में १०२ करोड़; १९४२ में ३८ करोड़ और १९४३ में १०८ करोड़ हो गई। बैंकों की डिपाज़िटों की वृद्धि का कारण तो यह था कि युद्ध के व्यय के कारण मुद्रा (Currency) का

देश में बहुत विस्तार हुआ था। रिजर्व बैंक तथा सरकार ने अनाप-शनाप नोट छापे। बैंकों की डिपॉजिटों की वृद्धि का एक कारण था कि बैंकों ने नये क्षेत्रों में प्रवेश किया था तथा शाखाओं का बहुत विस्तार हुआ था। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक तथा कैश मर्चण्टाइजेटों की रकम के घटने का कारण यह था कि बेहद महंगाई के कारण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति कुछ बचा नहीं सकता वरन् उसे अपनी पुरानी बचत को भी खर्च करना पड़ता था।

बैंकों की डिपॉजिटों के सम्बन्ध में एक और आश्चर्यजनक बात हुई। मुद्रा प्रारम्भ होने के पूर्व मुद्रती जमा (Fixed Deposits) का कुल डिपॉजिटों का अनुपात ५० प्रतिशत था अर्थात् मुद्रती जमा आधी थी किन्तु मुद्रा काल में वे २५ प्रतिशत रह गईं। हुआ यह कि मुद्रा काल में मुद्रती जमा तो बहुत कम बढ़ी किन्तु चालू जमा (Current Deposit) बहुत अधिक बढ़ गई। इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह था कि मुद्रा की दर बहुत गिर गई थी। १९३१ के उपरान्त मुद्रा की दर गिरती ही चली जा रही थी इस कारण सर्वसाधारण को एक वर्ष के लिए रुपया अटकाने में कोई लाभ नहीं दिखता था। वह चालू खाते में जमा करना पसंद करती थी। किन्तु यह प्रभाव मुद्रा के पहले से ही काम कर रहा था। दूसरा कारण यह था कि सर्वसाधारण की मनो-बहुत लंबी होने के कारण अपनी बचत को जमीन, इमारतें, सोना-चाँदी, कंपनियों के हिस्सों में लगाने से हिचकती थी। वह अपनी बचत को तरल रूप (Liquid Form) में रखना चाहती थी कि जब आवश्यक आवे तभी अपनी बचत का इन चीजों के खरीदने में उपयोग कर सके। तीसरा कारण चालू जमा की अत्यधिक वृद्धि का यह था कि मुद्रा काल में मर्यादित तथा अन्य साधन न मिलने के कारण नये कारखाने तो स्थापित हो नहीं सकते थे कि जिनमें व्यवसायी तथा व्यापारी अपने बढ़ते हुए लाभ को लगा सकते अवश्यतः वे उस धन को अपने कारखानों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) को बढ़ाने में लगाते थे जिससे वे उसी कारखाने से अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें।

मुद्रा का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि बैंकों की चुकता पूँजी या परिदत्त पूँजी (Paid up Capital) और रक्षित कोष उनकी डिपॉजिटों की तुलना में बहुत घट गई। इम्पीरियल बैंक की पूँजी और रक्षित कोष उसकी डिपॉजिटों की तुलना में जहाँ १९३६ में १२.८८ प्रतिशत था वह घटकर ४.५ प्रतिशत रह गया, पाँच बड़ों की परिदत्त पूँजी और रक्षित कोष ६.३ प्रतिशत से घट कर

४५ प्रतिशत रह गई। इसका फल यह हुआ कि बहुत से बैंकों ने अपनी पूँजी (Capital) को बढ़ाया।

युद्ध का चौथा प्रभाव यह हुआ कि उद्योग-धन्धों और व्यापार के लिए जो ऋण की माँग थी वह कम हो गई किन्तु सरकार ने एक के बाद दूसरे ऋण निकालने आरम्भ किए। १९३६ में जहाँ बैंक अपनी कुल डिपॉजिटों का ५८ प्रतिशत ऋण, नकद साख तथा विलों के रूप में धन्धों और व्यापार में लगाते थे वहाँ १९४५ में उन्होंने अपनी डिपॉजिटों का कुल २० प्रतिशत इस रूप में लगाया। जैसे-जैसे युद्ध चलता गया उद्योग-धन्धों को बैंकों से उधार लेने की आवश्यकता कम होती गई। उनके लाभ को व्यवसायी चालू खाते में रखते थे और उसी को कार्यशील पूँजी (Working Capital) के रूप में लाते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बैंकों ने अपने कोष (Funds) को सरकारी सिक्यूरिटियों में आधिकाधिक लगाना आरम्भ कर दिया। यहाँ नहीं बैंकों ने नकद कोष (Cash Reserve) भी अधिक रखना आरम्भ कर दिया। शिड्डल बैंक १५ प्रतिशत, इम्पीरियल बैंक १५ से २५ प्रतिशत, बड़े पाँच १८ प्रतिशत, और वे बैंक जो शिड्डल बैंक नहीं हैं वे १९ प्रतिशत नकद कोष रखने लगे। वृद्धि के बाद से युद्ध काल में बैंकों की सरल लेनी (Liquid Assets) का अनुपात बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों को अपने रुपये पर सूद की कम आय होने लगी इस कारण उन्होंने भा डिपॉजिटों पर सूद कम कर दिया।

युद्ध का पाँचवाँ प्रभाव यह पड़ा कि बैंकों में कुछ खराबियाँ और उनकी कार्य पद्धति में कुछ कमी दृष्टिगोचर होने लगी। अतएव रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया और भारत सरकार ने कंपनी ऐक्ट में कुछ सुधार किए (देखा अध्याय २३) तथा एक बैंक कानून का निश्चय किया।

युद्ध का छठा प्रभाव यह पड़ा कि बैंकों की वृद्धि होने के कारण बैंक कर्मचारियों का टोटा बढ़ गया। नये बैंकों ने पुराने बैंकों के कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया और प्रत्येक बैंक को यह आवश्यकता अनुभव होने लगी कि युवकों को अपरेंटिस रखकर उनको बैंक कार्य सिखाने का प्रबन्ध किया जावे।

अन्तिम प्रभाव यह हुआ कि भारतीय बैंक यह अनुभव करने लगे कि अखिल भारतीय बैंक संघोर्सियेशन स्थापित की जावे जो अस्वस्थकर होड़ को रोके तथा बैंकों में सद्भावना और परस्पर सम्बन्ध स्थापित करे। साथ ही

ऊँचे दर्जे की बैंकिंग परम्परा का निर्माण करे तथा बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच में एक कड़ी का काम दे। यह एंथ्रोसियेशन भारतीय बैंकों की कठिनाइयों तथा माँगों को सरकार के सामने रख सकेगी और उनका प्रतिनिधित्व कर सकेगी। यही कारण था कि बम्बई के बैंकों ने उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया।

यद्यपि मुद्रा के पल स्वरूप भारत में बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ किन्तु उस बाढ़ में बहुत से निर्मल बैंक भी स्थापित किए गए और वे डिपॉजिट लेने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा करने लगे। विशेष कर बंगाल और पंजाब में इस प्रकार के बहुत से छोटे छोटे बैंक स्थापित हुए। १९४७ में इनमें से पचास से अधिक बैंक बंद हुए। भविष्य में बैंकों को सफल और मुदद बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि छोटे बैंक दूसरे बैंकों से मिल जावें। देश में इस समय बैंकिंग सम्मिश्रण (Banking Amalgamation) की आवश्यकता है तभी बैंकिंग व्यवसाय उन्नति कर सकेगा।

देश के स्वतंत्र होने तथा विभाजन का प्रभाव—१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया किन्तु साथ ही उसका विभाजन भी हो गया। उसके पल स्वरूप जो पंजाब, सीमा प्रान्त तथा सिंध इत्यादि में इत्याकांड हुआ उसमें उत्तर पश्चिम भारत में पैले हुए बैंकों की बहुत अधिक हानि हुई है। वहाँ का व्यापार तथा व्यवसाय चौपट हो गया और बैंकों का जो रूपया लगा हुआ था वह बहुत कुछ हूब गया। अभी यह कह सकना कठिन है कि कितनी हानि हुई है किन्तु यह कहना होगा कि बैंकों ने इस हानि को सहन कर लिया है और उनमें से अधिकांश की स्थिति अच्छी है। हाँ इसका एक प्रभाव श्रवश्य हुआ है पंजाब तथा पाकिस्तान में बहुत से बैंक अपने हेड ऑफिसों को वहाँ से हटाकर भारत में ले आये हैं। साथ ही बहुत से बैंक सम्भवतः वहाँ अपनी ब्रांचों को भी बन्द कर दें।

इम्पीरियल बैंक तथा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—कुछ दिनों से देश में रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) की माँग हो रही थी। अभी हाल में भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्री चेन्नी महोदय ने भारतीय पार्लियामेंट में यह घोषणा की थी कि सरकार रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करेगी।

अध्याय—२५

बैंकों की कार्य पद्धति और उनके नियम

बैंकर और उसके ग्राहक

बैंक की परिभाषा—यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में बैंक या बैंकर की परिभाषा वहाँ के कानूनों में भिन्न है और यह कह सकना कठिन है कि कौन सी परिभाषा सही है फिर भी हम साधारण तौर से यह कह सकते हैं कि बैंक या बैंकर वह है जो ऐसी अभिव्यक्ति जमा (Demand Deposit) स्वीकार करता है जो चेक द्वारा निकाली जा सके।

बैंक के ग्राहक (Customer) की परिभाषा—अभी तक बैंक के ग्राहक की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है किन्तु इस विषय के विद्वानों का मत है कि बैंक के ग्राहक होने के लिये व्यक्ति को दो शर्तें पूरी करनी होंगी (१) कुछ समय तक बैंक से व्यवहार करता रहा हो (२) उसका बैंक से कारबार बैंकिंग सम्बन्धी हो। आजकल पहली शर्त को आवश्यक नहीं माना जाता परन्तु दूसरी शर्त आवश्यक है अर्थात् वही व्यक्ति बैंक का ग्राहक माना जावेगा जो बैंक से बैंकिंग सम्बन्धी कारबार करता हो। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कभी-कभी बैंक में जाकर सौ रुपये के नोट भुना लाता है अपने चेक या बैंक ड्राफ्ट का नकद रुपया ले आता है अथवा अपने जेवर इत्यादि को बैंक की रक्षा में रख देता है तो वह बैंक का ग्राहक नहीं कहलावेगा क्योंकि यह कार्य बैंक के नियमित कार्य नहीं हैं। अधिकांश विद्वान अब यही मानते हैं कि बैंक का ग्राहक होने के लिए जमा खाता (Deposit Account) खोलना आवश्यक है।

बैंकर तथा ग्राहक का सम्बन्ध -बैंकर अपने ग्राहक का कर्जदार होता है और ग्राहक बैंकर का लेनदार (Creditor) होता है क्योंकि ग्राहक अपना रुपया बैंक में जमा करता है। बैंकर जमा किये हुए रुपये का ट्रस्टी नहीं होता और न वह अपने ग्राहक का उस रुपये के सम्बन्ध में एजेंट ही होता है जब तक कि ग्राहक उसे विशेष रूप से अपने रुपये का ट्रस्टी या एजेंट नहीं बना देता। जब ग्राहक अपना रुपया बैंक में जमा कर देता है तो उसका उस रुपये

पर कोई अधिकार नहीं रहता। बैंक उस रुपये का जित्त प्रकार भी चाहे उपयोग कर सकता है। हाँ, बैंक को यह ज़िम्मेदारी अवश्य होती है कि ग्राहक जब उस रुपये को माँगे तो वापस करे। अस्तु बैंकर, ग्राहक का ट्रस्टी या एजेंट न होकर केवल कर्जदार (Debtor) ही होता है।

रुपये को वापस करने की माँग आवश्यक है—बैंक और साधारण कर्जदार के कर्ज में भेद इतना ही है कि जहाँ साधारण कर्जदार के विरुद्ध कर्ज की अवधि समाप्त हो जाने पर लेनदार (Creditor) बिना उससे कर्ज की प्रदायगी की माँग किये ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है वहाँ बैंक का ग्राहक ऐसा नहीं कर सकता। जब तक कि ग्राहक अपना रुपया बैंक से नहीं माँगता तब तक बैंक उसको अपनी ओर से रुपया नहीं अदा कर सकता।

दिये हुए रुपये का नियोजन (Appropriation)—यदि किसी ग्राहक के एक बैंक में बहुत से खाते (Accounts) हैं तो वह बैंक में रुपया भेजते समय इस बात का उल्लेख कर सकता है कि वह रुपया किस खाते में जमा किया जावे या वह इस बात का उल्लेख कर सकता है कि वह रुपया किसी बिल, हुंडा या चेक विशेष का भुगतान करने के लिये रक्खा जावे। यदि ग्राहक ने उस रुपये का किस प्रकार उपयोग किया जावे इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया तब तो बैंक को उसकी आज्ञा माननी ही होगी और उसी खाते में उस रुपये को जमा करना होगा जिसमें ग्राहक रुपया जमा करना चाहता है अथवा उसी हुंडा या चेक के भुगतान के लिये उस रुपये को रखना होगा जिसका ग्राहक ने उल्लेख किया है। किन्तु यदि ग्राहक ने ऐसा कुछ नहीं किया तो बैंक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह उस रुपये को उस श्रेणी को जो बैंक का ग्राहक पर हो बसूल करने में इस्तेमाल कर ले। यहाँ तक कि जो कर्जा अत्यधिक पुराना होने के कारण कानूनन बसूल नहीं किया जा सकता उसको भी बैंक इस रुपये से चुका ले सकता है।

जहाँ तक अचले खातू खाते (Current Account) का धरन है नियम यह है कि उस खाते में नामे (Debit) की ओर जो पहली रकम होगी वह जमा (Credit) की ओर की पहली रकम को चुकावेगी या कम करेगी। किन्तु यह नियम केवल खातू खाते के लिए है।

बैंकर अपने ग्राहक के चेकों का भुगतान करने के लिए बाध्य है—बैंक का यह पहला उत्तरदायित्व है कि वह अपने ग्राहक के काटे हुए

चेकों का भुगतान करे जब तक कि उसके खाते में रुपया है अथवा जब तक कि उसके दिये हुए ओवर ड्राफ्ट की रकम समाप्त नहीं हो गई हो। हाँ, यदि चेक ६ महीने से अधिक पुराना हो या उसमें कोई दोष हो (देखो अध्याय १) या ग्राहक ने ही उसका भुगतान रोक दिया तभी बैंक उसका भुगतान करने से इनकार कर सकता है। यदि ग्राहक ने कुछ चेक तथा बैंक ड्राफ्ट अपने खाते में जमा करने के लिए भेजे हैं तो बैंक उस समय तक उन्हें उसके खाते में जमा करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि उसको उनका रुपया वसूल न हो जावे। यदि कोई बैंक अपने ग्राहक का चेक बिना उचित कारण के अस्वीकार कर देता है तो ग्राहक उनसे अपनी साल गिरने के उपलब्ध में इर्जाना वसूल कर सकता है।

यदि किसी ग्राहक के एक ही स्थिति में दो खाते हों और एक में नाभे बाकी (Debit Balance) हो और दूसरे में जमा बाकी (Credit Balance) हो तो बैंक ग्राहक को नोटिस देकर उन दोनों खातों का प्रतिसाद (Set off) कर सकता है अर्थात् एक खाते की कमी को दूसरे खाते से पूरा कर सकता है। (इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिये कि एक जज ने तो यहाँ तक निर्णय दिया है कि बिना ग्राहक की अनुमति के बैंक ऐसा नहीं कर सकता।)

बैंक का ग्रहणाधिकार (Lien)—यदि कोई ग्राहक बैंक के पास अपनी सिक्यूरिटियाँ जमा कर देता है तो बैंक को उन पर ग्रहणाधिकार (Lien) प्राप्त हो जाता है। ग्रहणाधिकार का अर्थ यह है कि यदि वह ग्राहक बैंक का कर्जदार है तो बैंक उन सिक्यूरिटियों को जमानत के रूप में अपने पास रख सकता है और यदि ग्राहक उस कर्ज को अदा न करे तो उन सिक्यूरिटियों को बिक्र कर अपना कर्ज वसूल कर सकता है। किन्तु यह अधिकार बैंक को तभी प्राप्त होता है जब उसको वे सिक्यूरिटियाँ बैंकर की इशियत से मिली हों। उदाहरण के लिए यदि ग्राहक भूल से अपने मूल्यवान कागज़ पत्र, चेक, बिल, या अन्य मूल्यवान ज़ेवर इत्यादि बैंकर के पास छोड़ जाता है या सिक्यूरिटियों को बैंकर के हाथ में एक नये ऋण की जमानत के रूप में देता है जो बैंक अस्वीकार कर देता है या उन सिक्यूरिटियों को वह किसी विशेष उद्देश्य से बैंक के पास जमा करता है तो बैंक उन पर अपना ग्रहणाधिकार (Lien) स्थापित नहीं कर सकता। यदि ग्राहक और बैंकर के बीच में ऐसा कोई समझौता हो गया हो कि बैंक उन सिक्यूरिटियों पर

प्रहणाधिकार स्थापित नहीं करेगा तो भी बैंक अपने इस अधिकार से वंचित रहेगा। नहीं तो बैंक के पास जो चेक, बिल, शेयर, वारंट आदि प्राइम के हिसाब में जमा करने के लिए आते हैं वह उन पर अपना प्रहणाधिकार स्थापित कर सकता है और उनको वसूल करके अपने उम रुपये को जो कि बैंक का प्राइम पर कर्ज के रूप में है और प्राइम नहीं चुकाता वसूल कर सकता है।

बैंक का कर्तव्य है कि वह अपने प्राइम की आर्थिक स्थिति को गुप्त रखे—बैंक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि बिना उचित कारण के वह प्राइम के खाते (Account) को किसी को न बतावे। बैंक प्राइम के खाते को ठीक प्रकट कर सकता है जब कि कानून द्वारा वह ऐसा करने के लिए विवश हो या बैंक के हित में आवश्यक हो (उदाहरण के लिए बैंक यदि प्राइम पर कर्ज अदा न करने के कारण मुकदमा चलावे) अथवा प्राइम की सहमति से उसने ऐसा किया हो। आगकल व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में बैंक एक दूसरे को गोपनीय सम्मति देते हैं। यह इतना अधिक प्रचलित है कि यह उनका अधिकार माना जाने लगा है।

अदालत की आज्ञा (Garnishee order)—यदि अदालत बैंक को आज्ञा दे कि किसी प्राइम विशेष को अपने खाते में से रुपया न निकालने दे तो बैंक उस आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

खाते को बन्द करना—कोई भी प्राइम अपने खाते में से सारे रुपये को निकाल कर खाते को बन्द कर सकता है। किन्तु बैंक प्राइम को बिना पूर्व सूचना दिये उसके खाते बन्द नहीं कर सकता। बैंक यदि किसी प्राइम के हिसाब को बन्द करना चाहे तो उसे प्राइम को सूचित कर देना चाहिए कि वह अपना रुपया निकाल ले और भविष्य में उसका रुपया जमा नहीं किया जावेगा। किन्तु नीचे लिखी दशाओं में बैंक प्राइम के हिसाब को रोक देने के लिए बाध्य है। (क) यदि प्राइम मर जावे, पागल हो जावे या दिवालिया हो जावे। या यदि प्राइम कम्पनी है तो उसके टूटने का नोटिस मिलने पर बैंक उसका खाता रोक देगा (ख) यदि अदालत की इस आशय की आज्ञा मिले तो बैंक प्राइम के खाते का रोक देगा।

पास बुक की प्रविष्टि (Entry)—यदि पास बुक में प्राइम के पक्ष में मूल से बैंक ने कोई रकम जमा कर दी है तो वह यह साबित कर

सकता है कि वह रुपया मूल से जमा हो गया और उसको सही कर सकता है। किन्तु यदि बैंक ने मूल से ग्राहक के खाते में उसके पक्ष में कुछ रुपया जमा कर दिया है और यदि ग्राहक ने उस प्रविष्टि (Entry) के भरोसे चेक काट दिया तो बैंक को उसका भुगतान करना ही होगा। उस दशा में बैंक उस प्रविष्टि से बँध जावेगा। किन्तु यदि इस बीच में ग्राहक के खाते की स्थिति नहीं बदली तो बैंक उस मूल का सुधार कर सकता है।

ग्राहकों के खाते (Accounts)—नये ग्राहक का खाता खोलने से पूर्व बैंक को उसके बारे में संतोषजनक जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए अन्यथा उसे जोखिम उठानी पड़ सकती है और वह दोषी ठहराया जा सकता है। यदि बैंक ने नये ग्राहक के बारे में संतोषजनक जाँच पड़ताल कर ली है तो फिर ग्राहक ने जो रुपया जमा किया हो वह कैसा है और कहाँ से आया है उसके बारे में बैंक को कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राहक दो प्रकार के होते हैं :—(१) वैयक्तिक खाता (Personal Account) (२) अवैयक्तिक खाता (Impersonal Account)। अवैयक्तिक खाते कम्पनियों, संस्थाओं तथा म्युनिसिपल बोर्ड इत्यादि के होते हैं। हम यहाँ दोनों प्रकार के खातों के बारे में लिखेंगे।

वैयक्तिक खाते—जब कोई व्यक्ति हिसाब खोलता है तो उसके हस्ताक्षरों के नमूने बैंक लेता है। यदि ग्राहक अपने खाते पर चेक काटने तथा चेकों, हुंडियों या बिलों इत्यादि पर बेचान (Emborsement) का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहता है तो बैंक उससे अपने फार्म पर इस आशय का लिखित आदेश ले लेता है। यदि ग्राहक अपना कोई एजेंट नियुक्त करता है तो उसके क्या अधिकार होंगे वह लिख देना आवश्यक है। यदि ग्राहक ने उसके अधिकारों का स्पष्टीकरण नहीं किया है तो वह उन सब अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो बैंकिंग सम्बन्धी कारबार में होते हैं।

नाबालिग (Minor)—बैंक नाबालिग को बिना जोखिम के खाता खोलने दे सकता है किन्तु यदि नाबालिग को मूल से बैंक ने उसका जितना रुपया जमा है उससे अधिक निकाल लेने दिया तो बैंक उससे वसूल नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक कि बैंक नाबालिग को ओवर-ड्राफ्ट नहीं देता तब तक कोई जोखिम नहीं होती। किन्तु बैंक अधिकतर नाबालिगों का खाता उनके माता-पिता के नाम से खोलते हैं। नाबालिग किसी का एजेंट बन सकता है।

विवाहिता स्त्री—विवाहिता स्त्री चालू खाता खोल सकती है और वह चेक काट सकती है। लेकिन यदि किसी बैंकर ने किसी स्त्री को कर्ज़ दे दिया है तो रोक उसको जेल नहीं भिजवा सकता केवल उसकी व्यक्तिगत वृत्त, आयदाद या स्त्री धन को कुर्क करवा सकता है। किन्तु स्त्रियों की सम्पत्ति में बहुत कानूनी उलझने होती हैं इस कारण बैंक उन्हें अधिकतर श्रृंखला नहीं देते। यदि विवाहिता स्त्री ने कोई कर्ज़ लिया है तो उसका पति उसके लिए जिम्मेदार न होगा।

संयुक्त खाता (Joint Account)—दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में चालू खाता खोला जा सकता है जो साम्प्रदायिक न हो लेकिन बैंकर को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह उन व्यक्तियों से एक लिखित आदेश प्राप्त कर ले कि उस खाते का संचालन किस प्रकार होगा। किस प्रकार बिल, हुडी या चेक इत्यादि का बेचान (Endorsement) होगा और यदि उनमें से किसी का मृत्यु हो जावे तो बाकी किसको दी जावेगा।

जब तक संयुक्त खाता खोलने वाले सब व्यक्ति किसी एक को चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं दे देते तब तक चेक, बिल तथा अन्य सभी पत्रों पर सब के हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हो जावे तो जो शेष व्यक्ति जीवित रह गए हैं बाकी रुपये के अधिकारी वे लोग होते हैं। किन्तु जहाँ तक उस मरे हुए व्यक्ति के हिस्से का प्रश्न है यह सबेरे हुए लोग मरे हुए व्यक्ति के ट्रस्टी होते हैं। अतएव बैंक के लिए यह आवश्यक है कि खाता खोलते समय ही इस सम्बन्ध में निश्चित आदेश ले लें कि मरने पर रुपये किसको दिया जावे। साथ ही बैंक का सभी व्यक्तियों से इस बात की लिखित स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि यदि बैंक ओवर ट्राफ्ट देगा तो वे सभी सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप से उसके देनदार होंगे। यदि बैंक ऐसा नहीं करेगा तो वे लोग उसके सम्मिलित रूप से ही देनदार होंगे और यदि उनमें एक मर गया तो मरे हुए व्यक्ति की सम्पत्ति से बैंक अपना क़ायम बसूल नहीं कर सकेगा। केवल वचे हुए व्यक्ति उसके देनदार रहेंगे।

दिवालिया—जैसे ही कि बैंकर को ज्ञात हो कि किसी ग्राहक ने दिवालिया घोषित किये जाने की अदालत में शर्यना की है अथवा उसने अपने लेनदारों (Creditors) को उनके रुपये का चुकाना बंद कर दिया है अथवा वह ऐसा करने जा रहा है तो बैंक को उससे तुरन्त ब्यवहार बंद कर देना चाहिए। दिवालिया की सारी सम्पत्ति पर क्रायसियल रिजिस्टर का अधिकार होता है जिसका

प्रबंध वह उस दिवालिये के लेनदारों (Creditors) के लाभ के लिए करता है। जिसको अदालत ने ऋणमुक्त-दिवालिया (Discharged Bankrupt) घोषित नहीं कर दिया उसका खाता खोलने में बहुत जोखिम है। इस कारण बैंक उन दिवालियों का जो अदालत से ऋणमुक्त नहीं घोषित किए गए हैं खाता नहीं खोलते।

साझेदारी (Partnership)—प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह फर्म के नाम में खाता खोले और फर्म के लिए चेकों, बिलों को काटे, उन पर बेचान करे और हुंडियों और बिलों को स्वीकार करे। जो कुछ वह फर्म के नाम से करता है फर्म उससे बंध जाती है अर्थात् फर्म उसकी जिम्मेदार हो जाती है फिर चाहे अन्य साझेदारों ने उसको यह अधिकार न भी दिया हो। हाँ, उस व्यक्ति या बैंक इत्यादि के लिए फर्म उत्तरदायी नहीं होगी जो वह जानता हो कि उस साझेदार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अस्तु बैंकर एक साझेदार की प्रार्थना पर ही फर्म के नाम खाता खोल सकता है किन्तु व्यवहार में बैंकर को ऐसा कभी भी न करना चाहिए कि वह एक साझेदार की प्रार्थना पर फर्म के नाम खाता खोल दे या ऐसे चेकों का भुगतान करे जिन पर केवल एक साझेदार के हस्ताक्षर हों। ऐसा वह तभी कर सकता है जब वह अन्य सभी साझेदारों से इस आशय का लिखित आदेश ले ले। जब किसी फर्म के नाम हिसाब खोला जावे तो बैंक को सभी साझेदारों से लिखित आदेश ले लेना चाहिए कि वे उस बैंक में हिसाब खोलना चाहते हैं। हिसाब का संचालन किस प्रकार होगा, कौन हस्ताक्षर करेगा इत्यादि बातों का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए और इस बात का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए कि सब साझेदार सम्मिलित रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से बैंक द्वारा फर्म को दिए गए ऋण के लिये जिम्मेदार होंगे। यदि फर्म ऋण की जमानत स्वरूप अपनी कोई सम्पत्ति गिरवी रखे तो उसके प्रलेख (Document) पर सब साझेदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

बैंक को एक फर्म का खाता किसी एक साझेदार के नाम में खोलना चाहिए। फर्म का हिसाब फर्म के नाम में ही खोलना चाहिए और न बैंकर को किसी ऐसे चेक को लेना चाहिए जो फर्म के नाम काटा गया हो और कोई साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करना चाहता हो जब तक कि सब साझेदारों की अनुमति न हो। लेकिन यदि कोई साझेदार फर्म के खाते पर अपने पक्ष में चेक काटता है तो बैंक को पूछूँ ताछूँ करने की आवश्यकता नहीं है।

जब कोई साम्प्रदायिक कर्म से अलग होता है तो भविष्य में कर्म जो कार-
 चार करती है उसका दायित्व (Liability) उस पर न होगा। किन्तु यदि
 उन्होंने कर्म से अलगहदा होने की सूचना बैंक को नहीं दी है तो भविष्य में
 भी बैंक कर्म को जो श्रृण देगा उसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। ऐसी दशा में
 जब बैंक को यह सूचना मिले कि कोई साम्प्रदायिक कर्म से हटा रहा है तो
 उसको पहले साते बन्द कर देना चाहिए और एक नया खाता खोलना चाहिए
 नहीं तो अलगहदा होने वाला साम्प्रदायिक कर्म द्वारा कर्म को उस समय के दिए
 हुए कर्ज के दायित्व से मुक्त हो जावेगा जब कि वह कर्म का साम्प्रदायिक था।
 कर्म के टूटने पर भी बैंक को यही करना चाहिए।

कम्पनियों—जब किसी निमित्त पूंजी वाली कम्पनी (Joint Stock
 Company) के नाम में खाता खोला जावे तो बैंक को उस प्रस्ताव की
 नकल माँगनी चाहिए जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने उस बैंक को कम्पनी
 का बैंकर नियुक्त करते समय स्वीकार किया हो। उस प्रस्ताव में इस बात का
 भी स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है कि कम्पनी के खाते का संचालन कौन
 करेगा। उस प्रस्ताव के साथ बैंक को कम्पनी की रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र,
 तथा कारबार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र भी भेजना चाहिए। बैंक इनको
 देखकर वापस कर देगा। इन कागजों के अतिरिक्त बैंक को "कम्पनी का
 स्मारक पत्र" (Memorandum of Association) तथा कम्पनी की
 नियमावली (Articles of Association) तथा आवश्यक निरीक्षक
 (आडिटर) द्वारा प्रमाणित लेनी-देनी का लेखा (Balance Sheet) और
 माँग लेना चाहिए।

बैंक को कम्पनी का स्मारक पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए जिससे उसे
 यह शक्त हो जावे कि कम्पनी के कारबार का क्या स्वरूप है और कम्पनी तथा
 उसके डायरेक्टर्स (संचालकों) को क्या क्या अधिकार हैं। कम्पनी की नियमा-
 वली को भी बैंक को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए विशेषकर कम्पनी के हिसाब
 खोलने, चेक, ड्रड्री, प्रॉमिसरी नोटों, तथा अन्य प्रलेखों (Documents)
 पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं। बैंक को यह जान लेना
 चाहिए कि इस सम्बन्ध में बोर्ड की मीटिंग में ही निर्णय हो सकता है अथवा
 संचालन बोर्ड (Board of Directors) को यह अधिकार किसी
 एक डायरेक्टर को दे देने का अधिकार प्राप्त है।

जब भी कम्पनी बैंक से श्रृण लेना चाहे तो बैंक को इस आशय के

संचालन बोर्ड (Board of Directors) के प्रस्ताव की प्रमाणित नकल माँगनी चाहिए जिसमें ओवर ड्राफ्ट या ऋण लेने का अधिकार दिया गया हो और जमाबंदी का जमा करने तथा तत्सम्बन्धी प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रदान दिया गया हो। बैंक को यह भी देख लेना चाहिए कि यह प्रस्ताव कम्पनी के स्मारक पत्र तथा नियमावली के अनुसार है या नहीं। बैंक को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि ऋण किस कार्य के लिए लिया जा रहा है और यदि उस रुपये को कोई डायरेक्टर गवन कर ले तो भी कम्पनी बैंक से लिए देनदार होगी।

कम्पनियाँ जो व्यापार नहीं करती—कुछ ऐसी कम्पनियाँ भी होती हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता वरन् विज्ञान, साहित्य, धर्म तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होता है। उनके सदस्यों को उस कम्पनी से होने वाला लाभ नहीं बाँटा जा सकता। ऐसी कम्पनियों का खाता खोलने से यही सब काम करना होगा जो व्यापारिक कम्पनियों के साथ करने पड़ते हैं। केवल इन कम्पनियों को कारबार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता। यदि ऐसी कम्पनी ऋण लेना चाहे तो बैंक को यह पता लगा लेना चाहिए कि उस कम्पनी के अधिकार ऋण लेने के सम्बन्ध में क्या है।

भुगतान करने वाला बैंकर (Paying Banker)—भुगतान करने वाले बैंक का यह पहला कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहक के चेकों का भुगतान करे किन्तु बैंक नीचे लिखी शर्तों के पूरा होने पर ही चेक का भुगतान करेगा। (१) ग्राहक का बैंक में चालू खाता या कोई अन्य ऐसा खाता होना चाहिए जिस पर वह चेक काटने की आज्ञा देता है (२) खाते में चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रुपया होना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो ओवर ड्राफ्ट का प्रवन्ध होना चाहिए (३) चेक को उसका पाने वाला (Holder) या उसका एजेंट बैंक के कारबार के घंटों में उपस्थित करे (४) चेक ठीक प्रकार से लिखा या काटा गया हो (५) और कोई कानूनी कारण उस चेक को अस्वीकार करने का न हो।

यदि चेक पर चेक काटने वाले (Drawer) के हस्ताक्षर हों, उसके भुगतान की तारीख अगली न हो अर्थात् उसके भुगतान का समय हो गया हो, और वह बहुत पुराना (Stale) न हो गया हो, यदि शब्दों और अंकों में रकम एक समान हो, यदि वह आर्डर चेक है तो उस पर ठीक बेचान हुआ हो, और यदि उसमें कोई परिवर्तन हुआ हो तो उस पर काटने वाले (Drawer) के हस्ताक्षर हों तो चेक को ठीक माना जावेगा।

नीचे लिखे कारण होने पर बैंक चेक का भुगतान करना रोक देगा :—

(१) जब ग्राहक ने उसका भुगतान रोक दिया हो।

(२) यदि बैंक को शक हो जावे कि भुगतान के लिए चेक उपस्थित करने वाला चेक का सही मालिक नहीं है।

(३) यदि ग्राहक के दिवालिया हो जाने, मर जाने, या पागल हो जाने की खबर बैंक को लग गई हो। यदि कम्पनी हो और उसके टूटने का नोटिस दे दिया गया हो।

(४) जब ग्राहक ने अपने हिसाब में जो कुछ भी बाकी हो उसको किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया हो और उसकी सूचना बैंक को हो।

(५) यदि बैंकर को यह मालूम हो जावे कि ग्राहक ट्रस्ट के रुपये को अपने लाभ के लिए लेना चाहता है।

(६) जब अदालत की आज्ञा (Garnishee order) हो कि ग्राहक अपने खाते से रुपये न निकाले।

जब बैंकर चेक का भुगतान नहीं करता और उसे वापस करता है तो उसके साथ एक रसिद लगाकर उसका कारण लिख देता है (देखो अध्याय १)

बैंकर की जोखिम—चेक का भुगतान करने में बैंक का दो मुख्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। (१) ग्राहक के हस्ताक्षरों का जाली होना (२) रकम को बढ़ा देना या अन्य कोई परिवर्तन कर देना।

बैंकर के पास अपने ग्राहक के हस्ताक्षर होते हैं इस कारण यदि हस्ताक्षरों में तनिक भी अन्तर हो तो उसे चेक का भुगतान न करना चाहिये। यदि जाल बनाने वाला ऐसी हाशियारी से जाल बनावे कि बैंकर यह जान न सके कि यह जाली हस्ताक्षर है और वह चेक का भुगतान कर दे तो भी बैंकर उसका रुपये ग्राहक के हिसाब में से कम नहीं कर सकता। यह हानि बैंकर को ही उठानी होगी। परन्तु हाँ यदि ग्राहक को यह मालूम है कि एक जाली चेक बैंक के सामने उपस्थित किया जा रहा है और वह उसकी सूचना बैंक को नहीं देता तो अवश्य वह उसका निम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए एक ग्राहक की पत्नी अपने पति के जाली हस्ताक्षर करके बैंक से चेक का भुगतान ले लेती थी और अन्त में उसने आत्म हत्या कर ली। मुकदमों का पैशला यह हुआ कि ग्राहक को यह हानि उठानी होगी। बैंक वह रुपये ग्राहक के खाते से कम कर लेगा।

यदि चेक में कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ती हो तब तो कोई हानि नहीं परन्तु यदि रकम बढ़ा दी गई हो और बैंक असावधानी से उसका भुगतान कर दे तो ग्राहक उसका देनदार न होगा। किन्तु यदि ग्राहक ने ही चेक में रकम ऐसी असावधानी से लिखी हो जिससे उसको बढ़ाया जा सकता हो तो ग्राहक उस हानि के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को चेक को ध्यानपूर्वक देखकर उसी के अनुसार उसका भुगतान करना चाहिए। यदि चेक रेखांकित है तो उस चेक का भुगतान किसी बैंक के द्वारा ही करना चाहिए। यदि उस चेक पर विशेष रेखांकन (Special Crossing) है तो भुगतान उसी बैंक को करना चाहिए जिसका नाम उसमें दिया हो।

चेकों का रुपया वसूल करने वाला बैंक—(Collectg Banker)
यदि वसूल करने वाला बैंक अपने ग्राहक के बिना रेखांकित किये हुए चेक का रुपया वसूल करता है और बाद को यह ज्ञात होता है कि उस चेक पर जाली बेचान (Forged Endorsement) है या बैंक का ग्राहक उसका वास्तविक स्वामी नहीं है अर्थात् चेक चुराया हुआ है तो वसूल करने वाले बैंक को उस चेक के असली मालिक को रुपया देना होगा। हाँ बैंक अपने ग्राहक से हानि की पूर्ति कर सकता है।

किन्तु यदि चेक रेखांकित (Crossed) है और बैंक के पास पहुँचने से पहले वह रेखांकित कर दिया गया है साथ ही बैंक किसी ग्राहक के लिए उसका भुगतान बिना यह जाने कि उसका ग्राहक उस चेक का वास्तविक स्वामी नहीं है ले लेता है तो वसूल करने वाले बैंक से उस चेक का असली मालिक रुपया वसूल नहीं कर सकता।

यदि किसी रेखांकित चेक पर यह लिखा हो कि रुपया पाने वाले के हिसाब में जमा करो (Account Payee only) तो वसूल करने वाले बैंक को ग्राहक के हिसाब में ही जमा करना चाहिए।

शकताओं को मली भांति पूरा कर सकें। प्रारम्भिक अवस्था में स्थानीय इकाई बैंको (Unit Banks) के द्वारा उस क्षेत्र में जनता को बैंकों से कारबार करने का अभ्यास पड़ता है बाद में फिर बड़े बैंक वहाँ अपनी शाखा स्थापित कर सकते हैं। अतएव भारत की निरासता को देखते हुए स्थानीय इकाई बैंक का यहाँ स्थान है। साथ ही हमें यह न भूलना चाहिए कि मिश्रित बैंक वाले व्यापारिक बैंक किसी भी देश में उद्योग यह धर्मों को, साधारण किसानों को, शीकरी या अन्य पेशा करने वाले लोगों को, छोटे छोटे ठेकेदारों को लाभ नहीं दे सकते। इनका छोटे स्थानीय बैंक ही लाभ दे सकते हैं।

कुछ देशों में व्यापारिक कारबार के साथ-साथ बैंक उद्योग-धर्मों का भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, इसे मिश्रित बैंकिंग कहते हैं। जर्मनी और जापान में मिश्रित बैंकिंग प्रचलन था और उससे वहाँ के धर्मों को खूब प्रोत्साहन मिला। परन्तु यह भी निरुत्पत्ता का एक कारण बन जाता है। क्योंकि व्यापारिक बैंकों को थोड़े समय के लिए डिपॉजिट मिलती है और उस रुपये को धर्मों में लम्बे समय के लिए पैसा देना जोखिम को मोल लेना है। अब तो यह है कि प्रत्येक देश में औद्योगिक उन्नति के प्रारम्भिक काल में मिश्रित बैंकों का प्राधान्य रहा। जब स्थानीय-धर्म विकसित और उन्नत हो गए और जन-साधारण उन्नत धर्मों की स्थापना करने लगे तब व्यापारिक बैंक उद्योग-धर्मों से हटकर शुद्ध व्यापारिक कारबार करने लगे। अब अधिकांश देशों में मिश्रित बैंक कमियाँ शुद्ध व्यापारिक बैंक ही बनते जा रहे हैं।

भारतवर्ष में प्रारम्भ में कुछ मिश्रित बैंकों की प्रवृत्ति रही परन्तु बहुत जल्दी ही भारतीय बैंकों ने इन बैंकों की प्रवृत्ति को अपनाकर शुद्ध व्यापारिक बैंकिंग कारबार को ही प्राथमिकता दी और आज देश में बैंक शुद्ध व्यापारिक कारबार ही करते हैं। अतएव जहाँ तक मिश्रित बैंकों से होने वाली निरुत्पत्ता का प्रश्न है इस देश के बैंकों में यह नहीं पाई जाती।

परन्तु निम्नलिखित दिनों में भारतवर्ष में एक नई और कुछ अर्थों में अस्वस्थकर प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। दूसरे महायुद्ध के समय प्रत्येक बड़े व्यवसायी और उसके सहयोगियों ने बैंक स्थापित करना आरम्भ कर दिए। आज देश में कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है जिसका एक बैंक न हो। बिड़ला, टाटा, बजाज, सिंदिया, सेकसिया, ताटा सभी बड़े उद्योगपतियों ने अपने बैंक स्थापित कर सकते हैं। यह स्थिति स्वस्थकर नहीं है। आज देश में

क्रमशः सभी धन्धों और बैंकिंग पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों का प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा है यह आर्थिक शक्ति जो कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ रही है वह देश की राजनैतिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए बाधक सिद्ध होगी।

(३) विनियोग (Investment):—बैंकों की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण उनकी गलत विनियोग नीति होती है। जब बैंक भूल से गलत कारखानों में अथवा जोखिम के कारखानों में रुपया लगा देते हैं तो आर्थिक संकट के समय उनकी स्थिति डबाडोल हो जाती है और वे असफल हो जाते हैं। भारतवर्ष में धन को तरल लेनी (Liquid Assets) में लगाने की सुविधायें अधिक नहीं हैं। अधिकतर सरकारी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) में ही रुपया लगाना पड़ता है। जिन देशों में औद्योगिक उन्नति नहीं हुई है उन देशों में ऋण देने का क्षेत्र सीमित होता है। भारतवर्ष में जो भी बैंक असफल हुए हैं यदि उनका इतिहास देखा जावे तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि उन बैंकों ने अपना रुपया जोखिम की जगह फँसा दिया था। गलत विनियोग (Investment) ही उनकी असफलता का मुख्य कारण था।

(४) आर्थिक संकट के कारण असफलता :—जब देश में आर्थिक संकट आता है मुद्रा (Currency) का संकोचन (Deflation) होता है तथा वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है तो मुहड़ बैंकों की स्थिति भी कठिन हो जाती है। ऐसी दशा में जिस बैंक में भी तनिक सी कमज़ोरी होती है वही घराशायी हो जाता है। प्रथम योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त योरोपीय देशों में जो आर्थिक संकट उपस्थित हुआ उसके फल स्वरूप उन देशों में बहुत से बैंक असफल हो गए। यद्यपि भारतवर्ष में भी कुछ बैंक असफल हुए परन्तु यहाँ स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी जितनी कि योरोपीय देशों की बिगड़ गई।

बैंकों की असफलता और केन्द्रीय बैंक :—जिस देश में केन्द्रीय बैंक प्रभावशाली होता है उसका नेतृत्व अच्छा होता है और वह बैंकिंग की मुहड़ परम्परायें स्थापित कर देता है वहाँ बैंकों की असफलता कम होती है। सीमाभ्युदय भारतवर्ष में रिज़र्व बैंक की स्थापना हो चुकी है, उसको बैंकों के कार्य के निरीक्षण के अधिकार प्राप्त हैं। वह एक सजग प्रहरी की भाँति बैंकों के कार्यों को देखता रहता है और

उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। साथ ही भारत सरकार ने एक बैंक कानून भी बना दिया है जिससे बैंकिंग जगत् में अन्धखी परम्परायें स्थापित होगी। आशा है कि भविष्य में भारतीय बैंक रिजर्व बैंक के नेतृत्व में सुदृढ़ और बलवान बनेंगे।

अब हम भारतीय बैंकों की असफलता का संक्षिप्त इतिहास लिखेंगे। इससे यह ज्ञात होगा कि जो बैंक भारत में असफल हुए उसका मुख्य कारण क्या था।

भारतवर्ष में यों तो हफ्ता हुआ बैंक टूटते रहे किन्तु १९११-१४ में बैंकों के धरायायी होने की एक बाढ़ सी आ गई। अनेक बैंकों ने अपना कारबार बन्द कर दिया और बहुतों का रुपया डूब गया।

यदि ध्यान पूर्वक देखा जावे तो यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि असफल होने वाले बैंकों में नये बैंक ही अधिक थे। १९११-१४ से आज तक पितने बैंक इस देश में असफल हुए हैं उनमें दो तिहाई बैंक ग्यारह वर्ष से कम के थे। जो बैंक पुराने होते जाते हैं उनमें असफल बैंकों का प्रविशित घटता जाता है।

भारतीय बैंकों का असफलता के इतिहास से हमें एक बात और देखने को मिलती है कि अधिकतर वे ही बैंक धरायायी होते हैं जो बहुत नगण्य हैं, जिनकी पूँजी बहुत कम है। जो भी बैंक इस देश में बन्द हुए हैं उनमें से अधिकांश की चुकता पूँजी एक लाख रुपए थे। ऐसे बहुत कम बैंक बन्द हुए जिनकी पूँजी पाँच लाख से अधिक थी।

अब हम यहां कुछ प्रतिनिधि बैंकों की असफलता के कारण लिखेंगे :—

(१) बैंक कानून का न होना, जनता का बैंकिंग के सम्बन्ध में अनजान होना और प्रयन्धकों का ईमानदार न होना :—बहुत से बैंकों की असफलता का कारण यह था कि कुछ भेईमान व्यापारियों ने बैंक कानून न होने के कारण मनमाने ढंग से बैंक स्थापित किए और जनता को खूब ठगा। यह बैंक वास्तव में बहुत छोटे थे उनकी चुकता पूँजी दो तीन लाख से अधिक नहीं थी किन्तु वे बड़े-बड़े अज्ञानों में छपवाते कि हमारी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) कई करोड़ है। साधारण जनता अधिकृत पूँजी और चुकता पूँजी में कोई भेद नहीं समझती थी। वह समझती थी कि इस बैंक की पूँजी कई करोड़ रुपए है

जबकि उसकी वास्तविक चुकता पूँजी (Paid up Capital) केवल लाख दो लाख रुपए ही थी। किसी किसी बैंक की चुकता पूँजी तो केवल कुछ हजार ही होती थी। यह बैंक विज्ञापन करने कि हमारी शाखायें देश भर में फैली हुई हैं और कुछ ने तो यहाँ तक सूचित किया कि हम लंदन पैरिस इत्यादि नगरों में ब्रांच खोल रहे हैं। भोली और अनभिज्ञ जनता यह समझ कर कि यह बहुत बड़े बैंक हैं उनमें अपना रुपया जमा कर देती और कुछ समय बाद यह बैंक अपना कारबार बंद कर देते। १९४० के उपरान्त जो इस देश में नये बैंकों की स्थापना की एक बाढ़ सी आई उसमें भी बहुत से छोटे-छोटे बैंक स्थापित हुए और १९४५—४६ में बहुत से ऐसे बैंक विशेष कर बंगाल के बैंक धराशायी हो गए। इन बैंकों की पूँजी बहुत कम थी, उन्होंने जल्दी-जल्दी दूर-दूर स्थानों में तथा सुदूर प्रान्तों में अपनी ब्रांच स्थापित कर दी और दलाल रख कर ऊँचा सूद देकर मोली जनता से जमा लेना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बहुत जल्दी धराशायी हो गए और बहुत से लोगों का रुपया डूब गया। इस प्रकार के बैंकों में पूना बैंक, अमृतसर नेशनल बैंक, पायनियर बैंक, हिन्दुस्तान बैंक मुल्तान, काठियावाड़ अहमदाबाद कारपोरेशन, ब्रिटिश इंडिया बैंक, बाम्बे बैंकिंग कारपोरेशन, पायनियर बैंक बाम्बे, क्रेडिट बैंक आब इंडिया, बंगाल नेशनल बैंक आब इंडिया, आर्यन बैंक, मैट्रोपॉलिटन बैंक कलकत्ता इत्यादि मुख्य हैं। इस प्रकार के बैंक मुख्यतः पंजाब और बंगाल में अधिक स्थापित हुए। १९४६ के आस पास तो बंगाल में लगभग ६० छोटे-छोटे बैंक बंद हो गए।

(२) लम्बे समय के लिए उद्योग-धन्धों में रुपया लगाना :—कुछ अच्छे और बड़े बैंक इस कारण नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपना रुपया लम्बे समय के लिए कारखानों में लगा दिया। जब तक उन धंधों की आर्थिक स्थिति अच्छी रही उन्हें लाभ होता रहा तब तक सब ठीक रहा परन्तु जब आर्थिक संकट आया धन्धों को हानि होने लगी तो इन बैंकों की स्थिति खराब हो गई और वे धराशायी हो गए। इन बैंकों में लाहौर का प्यूपिल्स बैंक, अमृतसर बैंक लाहौर, ताता औद्योगिक बैंक, बैंक आब वर्मा, नाथ बैंक कलकत्ता, तथा ज्वाला बैंक आगरा मुख्य हैं।

(३) सट्टे की जोखिम :—कुछ बैंक सोने चाँदी तथा अन्य वस्तुओं के सट्टे में फँस कर अपना विनाश करते हैं। बैंक का कारबार करने वाला यदि सट्टे में हाथ डाले तो उस बैंक का विनाश अवश्यम्भावी है। इंडियन स्पीरी बैंक, एलाइंस बैंक आब शिमला इस श्रेणी में आते हैं।

(४) दुर्भाग्य वश असफल होना :- कभी कभी अन्धे बैंक दुर्भाग्य वश कठिन परिस्थिति में पँस जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। एलाइस बैंक शिमला और ट्रावकोर नेशनल किनलन बैंक दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति में पँस गए ।

अभी हाल में बंगाल में नाथ बैंक जैसे बड़े बैंक तथा अन्य प्रभावशाली बैंकों के उध्वंस होने से एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई । प्रिन्सिपल बैंक नेतृत्व में बंगाल में बैंकों के एकीकरण (Amalgamation) का आन्दोलन चल रहा है । भविष्य में भारत में बैंकों का एकीकरण हो जाने पर ही पाड़े से सवाल और मुद्दों बैंक देश की सेवा कर सकेंगे । वास्तविकता इस बात की है कि जहाँ तक हो सके बैंकों का एकीकरण शीघ्र हो जाने काय की स्थिति में बहुत छोटे बैंकों के लिए बहुत सी बटिनाइयाँ उपस्थित होती हैं अतएव उनका एकीकरण हो जाना आवश्यक है ।
